



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]
No. 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 1994/आषाढ़ 4, 1916
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1994/ASADHA 4, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-Section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का.आ. 1405.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की
उपधारा (1) के खंड (viii) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स क्रेडिट कैपिटल वेंचर फण्ड (इण्डिया)
लि., 62, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 को कर-
निर्धारण वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए उक्त फंड के प्रयोजनार्थ
एक कम्पनी के रूप में अनुमोदित करती है।

2. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि यह कम्पनी आयकर
अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के उपबंधों के अनुरूप होगी
और उनका अनुपालन करेगी।

[अधिसूचना सं. 9552/फा.सं. 204/7/94-आयकर नि.-II)]

अजय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1405.—In exercise of the powers conferred by clause
(viii) of sub-section (1) of section 36 of Income-tax Act, 1961,
the Central Government hereby approves M/s. Credit Capital

Venture Fund (India) Limited, 62, Basant Lok, Vasant Vihar,
New Delhi-110057 as a company for the purpose of said
clause for assessment years 1995-96 and 1996-97.

2. The approval is subject to the condition that the com-
pany will conform to and comply with the provisions under
section 36(1)(viii) of Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 9552/F. No. 204/7/94-ITA.II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का. आ. 1406.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की
उपधारा (1) के खंड (viii) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स इण्ड बैंक हाऊसिंग लि., 178, कोडमबक्कम
हार्ड रोड, नुतुयामबक्कम, गदाम को कर-निर्धारण वर्ष 1994-95, 1995-
96 और 1996-97 के लिए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अनुमोदित करती
है।

2. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि यह कम्पनी आयकर
अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के उपबंधों के अनुरूप होगी
यदि उनका अनुपालन करेगी।

[अधिसूचना सं. 9553/फा. सं. 204/5/93-आयकर नि.-II)]

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1406.—In exercise of the powers conferred by clause
(viii) of sub section (1) of Section 36 of Income-tax Act, 1961,
the Central Government hereby approves M/s. Ind Bank

Housing Limited, 178, Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Madras for the purpose of said clause for assessment years 1994-95, 1995-96 and 1996-97.

2. The approval is subject to the condition that the company will conform to and comply with the provisions under section 36(1)(viii) of Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 9553/F. No. 204/5/93-ITA.II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का. प्रा. 1407.—सर्वे साधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दी गई संस्था/एम्प्लोयर्स असोसिएशन और इसके नीचे दिए गए उसके कार्यक्रम की सविन्य, पर्यावरण तथा वन संरक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा जो कि आयकर नियमावली 1962 के नियम 6-क क ग के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारी हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35-ग ग ख के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

संस्था/एम्प्लोयर्स असोसिएशन का नाम

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति-517501

कार्यक्रम

1. श्री वेंकटेश्वर अनाभिवृद्धि योजना
2. श्री वेंकटेश्वर तपोवन योजना

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए दोनों ही अनुमोदन अर्थात् (i) धारा 35 ग ग ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था/एम्प्लोयर्स असोसिएशन के लिए तथा (ii) धारा 35 ग ग ख की उपधारा (1) के अन्तर्गत उक्त कार्यक्रमों के लिए, निम्नलिखित बातों के अधीन रहते हुए दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1996 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे :—

1. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में बनों के संरक्षण एवं विकास तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के निमित्त उसके द्वारा प्राप्त किए गए वानों का प्रयोग से लेखा-जोखा रखेगा।
2. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति ऊपर उल्लिखित कार्यक्रमों की प्रत्येक वित्त वर्ष की प्रगति रिपोर्टों को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
3. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक कुल आय एवं व्यय को दर्शाने वाले लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों तथा प्रत्येक कार्यक्रम की अलग-अलग स्थिति को दर्शाने वाले तुलन-पत्र की एक प्रति निर्धारित प्राधिकारी के पास भेजेगा।
4. उक्त अनुमोदन निर्धारित प्राधिकारी की निरन्तर संतुष्टि के अधीन है और उसे, यदि आवश्यक समझा जाए, तो पूर्व-व्याप्ति से वापस लिया जा सकता है।

[अधिसूचना सं. 9554 /फा.सं. 203/11/94-आयकर नि.-II]

अजय कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1407.—It is notified for general information that the Institution/Association mentioned below and its programme given hereunder, have been approved by the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi being the prescribed authority under the rule 6-AAC of the Income-tax Rules, 1962, for the purposes of Section 35CCB of Income-tax Act, 1961.

Name of the Institution/Association

Tirumala Tirupati Devasthanams,
Tirupati-517501.
Programmes

1. Sri Venkateswara Vanabhibridhi Scheme.
2. Sri Venkateswara Tapovan Scheme.

Both the approvals accorded by the Prescribed Authority namely (i) to the Institution/Association under sub-section (2) of Section 35-CCB and (ii) to the programmes under sub-section (1) of Section 35-CCB are valid for a period of three years with effect from 1-4-1993 to 31-3-1996, subject to the following conditions :—

1. Tirumala Tirupati Devasthanams Tirupati shall maintain a separate account of the donations received by it for conservation and development of forests and maintenance of ecological balance in the area as mentioned above.
2. The Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati shall furnish progress reports of the programmes mentioned above to the prescribed authority for every financial year by the 30th June each year.
3. The Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati shall submit to the prescribed authority by the 30th June every year, a copy of the audited annual accounts showing the total income and expenditure and balance sheet showing the position of each of the programmes separately.
4. The approval is subject to the continued satisfaction of prescribed authority and may be withdrawn with retrospective effect, if considered necessary.

[Notification No. 9554/F. No. 203/11/94-ITA.II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का.प्रा. 1408.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यैसर्से विदर्भ हाउसिंग डेवलपमेंट फार्मिनेस कम्पनी लि. प्रथम तल, अमर पैलेस, वेस्ट सेंट्रल रोड, धन्तली, नागपुर-440012 को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि कम्पनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के प्रावधानों के अनुरूप होगी और उनका अनुपालन करेगी।

[अधिसूचना सं. 9551/फा.सं. 204/34/92-आयकर नि.-II]

अजय कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1408.—In exercise of the powers conferred by clause (viii) of sub-section (1) of Section 36 of Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby approves M/s. Vidarbha Housing Development Finance Company Limited, 1st Floor, Amar Palace, West Central Road, Dhantoli, Nagpur-440012 for the purpose of said clause for assessment years 1991-92 to 1994-95.

2. The approval is subject to the condition that the company will conform to and comply with the provisions under section 36(1)(viii) of Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 9551/F. No. 204/34/92-ITA.II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का.प्रा. 1409.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने

हृष्ट केन्द्रीय सरकार एतद्वारा म. दीवान हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लि., वार्डेन हाउस, वृन्गी मजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, बम्बई-400023 को कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ एक कंपनी के रूप में अनुमोदित करती है।

2 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि उक्त कंपनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुरूप होगी और उसके उपबंधों का अनुपालन करेगी।

[प्रतिस्मृचना सं. 9549/फा. म. 204/22/92-आ.कर नि. II])
अजय कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1409.—In exercise of the powers conferred by clause (viii) of sub-section (1) of Section 36 of Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby approves M/s. Dewan Housing Development Finance Limited, Warden House, 2nd Floor, Sir P. M. Road, Fort, Bombay-400023 as a company for the purpose of said clause for assessment years 1993-94 to 1995-96.

2. The approval is subject to the condition that the company will conform to and comply with the provisions under section 36(1)(viii) of Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 9549/F. No. 204/22/92-ITA.II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का. आ. 1410.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (i) के खंड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, जिसमें जो. एल. एफ. एल. हाउसिंग फाइनेंस लि., प्रथम तल, ह.सुभाई चैम्बर, टाउन हास जे पीछे, गेलोस मि, अहमदाबाद-380006 को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए अनुमोदित करती है।

2 यह अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि कम्पनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के प्रावधानों के अनुरूप होगी और उनका अनुपालन करेगी।

[प्रतिस्मृचना सं. 9550/फा.सं. 204/17/93-आयकर नि.-II])

अजय कुमार, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 24th May, 1994

S.O. 1411.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column 1 of the Table below, being gazetted officer of Government, to be Estate Officer for the purpose of the said Act who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of Public premises specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
Deputy Manager (Finance) Security Paper Mill Hoshangabad	Premises under administrative control of the General Manager, Security Paper Mill, Hoshangabad, including the land acquired for the railway siding of the Mill.

[No. F.4/6/94-CY. I(SPM)]

V.K. VELUKUTTY, Dy. Manager (C&C)

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1410.—In exercise of the powers conferred by clause (viii) of sub-section (1) of Section 36 of Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby approves M/s. GLFL Housing Finance Limited, 1st Floor, Hasubhai Chambers, Opp. Town Hall, Ellis Bridge, Ahmedabad-380006 for the purpose of said clause for assessment year 1994-95.

2. The approval is subject to the condition that the company will conform to and comply with the provisions under section 36(1)(viii) of Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 9550/F. No. 204/17/93-ITA. II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1994

का. आ. 1411.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (यथाधिकृत अधिकारियों की वेदखानों) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम I में उल्लिखित अधिकारी को, सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संघर्ष अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के कॉलम 2 में समन्वय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के संरक्ष से सभी अधिकारी अंतर्गत की स्थानीय सोमाओं के अंतर्गत रहने हुए उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत संघर्ष अधिकारियों पर प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों को निष्पादित करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थान की श्रेणियाँ और अधिकारिता की स्थानीय सोमाएँ
1	2
उप-प्रबन्धक (वित्त) प्रतिभूति कागज मिल, होशंगाबाद	महाप्रबन्धक के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्थान, प्रतिभूति कागज मिल, होशंगाबाद, जिसमें मिल का, रेलवे साइडिंग के लिए अधिगृहीत भूमि शामिल है।

[सं. फा. 4/6/94-करो-1 (एस. पी. एम.)]
वी. के. वेलुकट्टी, उप-प्रबन्धक (सी. एण्ड सी.)

[Notification No. 9550/F. No. 204/17/93-ITA.II]

(बैंकिंग प्रभाग)			1	2	3
नई दिल्ली, 6 जून, 1994			देना बैंक	श्री बी. गोविन्दराजन संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय प्राथमिक कार्य विभाग नई दिल्ली	श्री वाई. पी. सेठी
का. भा. 1412 - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रयोग 'उपबंध स्कीम') 1970 के खण्ड 3 के उप खण्ड (ज) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कॉलम (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक नियुक्त करती है:-			बैंक ऑफ महाराष्ट्र	श्रीमती गानी ए. जाधव संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय प्राथमिक कार्य विभाग नई दिल्ली	श्री. मोना शर्मा
सारणी			इंडियन बैंक	श्री सुधीर भार्गव निदेशक वित्त मंत्रालय प्राथमिक कार्य विभाग बैंकिंग प्रभाग नई दिल्ली।	श्री के. श्रीनिवासन
1	2	3	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	श्री डी. सी. गुप्ता. संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय. व्यय विभाग नई दिल्ली	श्री एस. एन. मुखर्जी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	श्री गजेन्द्र हस्तिव्या संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय प्राथमिक कार्य विभाग नई दिल्ली	श्री के. श्रीनिवासन	यूको बैंक	श्री वाई. पा. सेठी निदेशक वित्त मंत्रालय प्राथमिक कार्य विभाग बैंकिंग प्रभाग नई दिल्ली।	श्री एन. एन. मुखर्जी

[सं. एक. 9/94--वी. प्रो. I (i)]
के. के. मंगल, अवर सचिव

[सं. एक. 9/9/94--घो. प्रो. I (i)]

के. के. मंगल, भवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 6th June, 1994

S.O.1412.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

1	2	3
United Bank of India	Sh. D.C. Gupta, Joint Secretary Ministry of Finance, Deptt. of expenditure, New Delhi.	Sh. N.N. Mookerjee

1	2	3
Central Bank of India	Sh. Gajendra Haldea, Joint Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, New Delhi.	Sh. K. Srinivasan
Dena Bank	Sh. V. Govindarajan, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.	Sh. Y.P. Sethi
Bank of Maharashtra	Smt. Rani A. Jadhav, Joint Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs New Delhi	Kum. Mona Sharma
Indian Bank	Sh. S. J. Bhargava, Director, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi.	Sh. K. Srinivasan
UCO Bank	Sh. Y.P. Sethi, Director, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi.	Sh. N.N. Mookerjee

[No. F.9/94-BO-I(i)]
K.K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 1994

का. आ. 1413 --राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण) उपबंध स्कीम, 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में निविष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (3) में निविष्ट व्यक्तियों के स्थान पर काम (1) में निविष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों का निदेशक नियुक्त करती है :-

सारणी

1	2	3
ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स सीमित प्रबंधात्मक वित्तीय सलाहकार वित्त मंत्रालय, व्यवसाय विभाग, नई दिल्ली।	सीमती प्रतीता कपूर	

1	2	3
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	श्री सी. मकरूप संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यवसाय विभाग, नई दिल्ली।	श्री पी. एन. राममूर्ति
विजया बैंक	श्री एस. के. बत्रा अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली।	श्री सुश्री भार्गव

[संख्या एक. 9/94 वी.ओ. I (ii)]
के. के. मंगल, अवर सचिव

New Delhi, the 6 June, 1994.

S.O. 1413 :—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

(1)	(2)	(3)
Oriental Bank of Commerce	Mrs. Aruna Makhan, Financial Advisor, Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure, New Delhi.	Mrs. Anita Kapoor
Punjab & Sind Bank	Sh. D. Swarup, Joint Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure, New Delhi.	Sh. P.N. Ramamoorthy
Vijaya Bank	Sh. S.K. Batra, Under Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi.	Sh. Sudhir Bhargava

[No. F. 9/94-BOI(ii)]
K.K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 1994

का.आ. 1414 —भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंधी बैंक) अधिनियम 1959 (1959 का 38) की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री के.के. मंगल, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली को श्री वाई.पी. सेठी के स्थान पर स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं. एफ 9/94-बी.ओ. I (iii)]

एम.एस. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 6th June, 1994

S.O. 1414.—In pursuance of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government, hereby nominates Shri K. K. Mangal, Under Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi, as a Director of State Bank of Hyderabad vice Shri Y. P. Sethi.

[No. F. 9/94-BO.I(iii)]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 1994

का.आ. 1415 —भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एन.एन. मुखर्जी, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली को श्री ए.के. जैन के स्थान पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं. 9/94-बी.ओ. I (iv)]

के.के. मंगल, अवर सचिव

New Delhi, the 6th June, 1994

S.O. 1415.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (e) of sub-section (1) of section 6 of Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri N. N. Mookerjee, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of the Board of Directors of the Export-Import Bank of India vice Shri A. K. Jain.

[No. 9/94-B.O.I(iv)]

K. K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1993

का. आ. 1416.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 53(2) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है:—

1 जुलाई, 1992 से 30 जून, 1993 तक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य-प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट

भाग एक—आर्थिक समीक्षा

1. नीतिगत गतिविधियाँ एवं स्वरूप

1.1 आर्थिक स्थिरीकरण और कार्य के पुनः आरंभ की दिशा में उत्साहजनक प्रगति वर्ष 1992-93 (जुलाई-जून) की प्रमुख विशेषताएँ रही। जुलाई 1991 से किए गए व्यापक सुधारात्मक उपायों के परिणाम परिलक्षित होने लगे, जैसे मुद्रास्फीति में कमी, सकल देशी उत्पाद में सुधार और विदेशी भुगतान की स्थिति में स्थायित्व।

1.2 नई आर्थिक नीति का विशेष जोर उत्पादकता और प्रणाली की कार्यक्षमता सुधारने के एक साधन के रूप में अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश का सृजन करने पर रहा है। इसी दिशा में 1992-93 के दौरान विशेष रूप से राज-कोषीय, मौद्रिक, वित्तीय दर और व्यापार नीति के क्षेत्रों में सुधारात्मक प्रक्रिया को और अधिक व्यापक और गहन बनाया गया।

राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया

1.3 जुलाई 1991 से राजकोषीय क्षेत्र में अनेक नीतिगत मामलों में पहल की गयी। इसका उद्देश्य सकल देशी उत्पाद संदर्भ में संघ सरकार राजकोषीय घाटा कम करना था। सकल देशी उत्पाद में सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 1990-91 में 8.41 प्रतिशत था; इस स्तर से उसे घटाकर 1991-92 में 5.96 प्रतिशत पर लाया गया। आगे चलकर उसमें फिर कमी आयी और वह 1992-93 में 5.70 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। यह आशा की जाती है कि बजट अनुमानों के अनुसार 1993-94 में यह अनुपात 4.71 प्रतिशत हो जाएगा। सकल राजकोषीय घाटे के रूप में केन्द्र का राजस्व घाटा उच्च स्तर पर बना रहा। 1992-93 में वह 45.5 प्रतिशत था, तथा 1993 में 48.0 प्रतिशत हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप राजस्व खाने की संसाधन की कमी अधिक लागत की उधार निधियों द्वारा पूरी की गयी। 1992-93 में व्याज भ्रदायगी की राशि राजस्व प्राप्तियाँ 41.5 प्रतिशत रही तथा आशा की जाती है कि 1993-94 में यह राशि बढ़कर 8.45 प्रतिशत हो जाएगी। सकल राजकोषीय घाटे तथा सरकार की उधार

राशियों में कमी लाना आवश्यक होगा ताकि व्याज भ्रदायगी की राशियाँ साथ ही घाटे के मौद्रिकरण के हिस्से को कम किया जा सके। तथापि, 1993-94 की प्रथम तिमाही में इसमें कमी नहीं लाई जा सकी, जबकि इसी तिमाही के दौरान परंपरागत बजट घाटे में तीव्र वृद्धि हुई। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार को दिए गए ऋण में भी काफी बढ़ोतरी हुई।

1.4 वर्तमान राजकोषीय स्थिति प्रत्याशित स्तर से कम उत्पादन और कर तथा शुल्क वरों में कमी इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रभावित करती है। प्राप्तियाँ व्यय से कम हैं, हालांकि उर्वरक और निर्यात अर्थ सहायता तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए योजनेतर अनुदान और ऋण घटाए गए थे और कुल व्यय में पूंजी परिव्यय का हिस्सा कम हो गया।

1.5 कर सुधार समिति (अध्यक्ष : प्रोफेसर राजा जे. चेलय्या) की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की पूष्ट भूमि में कर नीतियाँ निर्धारित की गयीं। परोक्ष कर सीमा शुल्क टेरिफ और उत्पाद शुल्क के संबंध में किए गए सुधारों से काफी राजस्व हानि हुई। इस हानि का काफी बड़ा भाग केन्द्र सरकार ने वहन किया। प्रत्यक्ष करों के संबंध में की गयी पहल से अतिरिक्त राजस्व के रूप में प्राप्तियाँ लगभग नगण्य रही। राजकोषीय असंतुलन, जैसे कि तीव्र गति से बढ़ते हुए राजस्व घाटे में प्रतिबिम्बित हुआ है, सुधारात्मक प्रक्रिया सफल कार्यान्वयन में गंभीर समस्याएँ पैदा करता है।

मौद्रिक नीति साध्य और साधन

1.6 वर्ष 1992-93 के दौरान मौद्रिक नीति निर्धारण में निम्नलिखित बातें निहित थीं : (i) आर्थिक कार्यक्रमों के पुनराारंभ में व्यवधान पड़नाये बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मौद्रिक विस्तार में कमी लाना; (ii) सकल राजकोषीय घाटे को कम करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप मुद्राकृत घाटे (केन्द्र को रिजर्व बैंक का निवल ऋण) को कम करना; (iii) विदेशी भुगतान के घाटे की समस्या हल करने के लिए नियति को बढ़ावा देना।

1.7 वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के प्रारंभिक महीनों की मौद्रिक नीति को मुख्यतः पांच प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम संबंधित प्रणाली में क्रमशः व्याज दरें कम करने के लिए सजग प्रयास किए गए क्योंकि मुद्रास्फीति की दरें छटी हैं तथा समष्टि आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। उधार दर विन्यास को क्रमशः युक्तिसंगत बनाने के अवसर का भी लाभ उठाया गया। द्वितीय चूंकि समष्टि आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, इसलिए आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के पिछले कम स्तर की ओर तेजी से अग्रसर होना उपयुक्त नीति सम्मत प्रतिसाद समझा गया। उधार देने योग्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों और संस्थाओं को दिए जाने वाले पुनर्वित्त की और अधिक उदारतापूर्वक बढ़ाने के लिए उपाय किए गए। तृतीय, वर्ष 1992-93 इस बात के लिए विशेष उल्लेखनीय रहा कि

मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधनों से अप्रत्यक्ष साधनों की ओर सतर्क प्रवास किए गए और मौद्रिक नियंत्रण के प्रभावी साधन के रूप में खुले बाजार के कार्यकलाप के साधन विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस नीति से एक भाग के रूप में सक्रिय गौण प्रतिभूति बाजार के लिए सुविधाजनक उचित संस्थागत ढांचे को विकसित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। चतुर्थ, कृषि और लघु उद्योग, मशोले और बड़े उद्योगों सहित प्राथमिकता प्राप्त करने और निर्यात जैसे क्षेत्रों के ऋण की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए गए। अंततः वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास के एक भाग के रूप में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कार्य पद्धति सुधारने के उपायों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

1.8 वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के प्रारंभिक चरण के दौरान किए गए प्रमुख मौद्रिक ऋण नीति संबंधी उपाय और उनका औचित्य नीचे प्रस्तुत है :

(क) ब्याज दरें

(i) उधार दरें

1.9 मुद्रास्फीति की उच्च दर तथा समष्टि-आर्थिक स्थिति में समग्र गिरावट के परिणामस्वरूप 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की न्यूनतम उधार दरें बढ़ाकर 9 अक्टूबर, 1991 से 20.0 कर दी गई। मुद्रास्फीति का दबाव कम होते ही न्यूनतम दर चार चरणों में प्रत्येक चरण के साथ एक प्रतिशत घटाई गयी अर्थात् 24 जून, 1993 से 20.0 प्रतिशत से 16.0 प्रतिशत तक घटाई गयी। इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान उधार दरों के बिन्यास को युक्ति संगत बनाया गया ताकि अब 1991 के छः श्रेणियों के बजाय केवल तीन श्रेणियां ही रहें। (परिशिष्ट सारणियां 1.1 और 1.2)

(ii) जमा दरें

1.10 मुद्रास्फीति की दर में गिरावट और उधार दरों में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप, बैंकों के अधिकतम जमा दरों में कमी संभव हो सकी। यह कमी दो चरणों में की गयी ताकि बैंक अपनी अर्थक्षमता बनाए रख सकें दिनांक 9 अक्टूबर, 1992 से प्रभावी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 46 और उससे अधिक दिनों के देशी मीयादी जमाराशि की दरें अधिकतम 13.0 प्रतिशत से घटाकर अधिकतम 12.0 प्रतिशत तथा पहली मार्च 1993 से अधिकतम 11.0 प्रतिशत प्रति वर्ष तक घटा दी गयी। देशी वचत जमाराशियों की ब्याज दरें 24 अप्रैल, 1992 में 5.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया था; इन दरों को फिर घटाकर पहली जुलाई 1993 से 5.0 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार 2 लाख रुपए से अधिक की सीमा के लिए मीयादी जमाराशि की अधिकतम दर, वचत जमाराशियों की दर और मीयादी जमाराशि की अधिकतम दर, वचत जमाराशियों की दर और उधार दर घटाकर उस स्तर पर लायी गयी जो 13 अप्रैल, 1991 में ब्याज दरें बढ़ाए जाने से पहले का स्तर था (परिशिष्ट सारणी 1.3)

1.11 अनिवासी विदेशी रुपया खाता जमाराशि (अनिवासी) योजना के अंतर्गत वचत खातों की ब्याज दर 9 अक्टूबर 1992 से एक प्रतिशत बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गयी। अनिवासी खातों की मीयादी जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों को देशी जमाराशियों की ब्याज दरों के अनुरूप युक्तिसंगत किया गया। 9 अक्टूबर 1992 से प्रभावी अनिवासी विदेशी रुपया खातों की 46 दिन से तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि की मीयादी जमाराशियों के लिए अधिकतम 13.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की एकल चरणीय ब्याज दर निर्धारित की गयी। देशी मीयादी जमाराशियों की ब्याज दरों में की गयी कमी के अनुरूप यह दर भी 8 अप्रैल, 1993, से एक प्रतिशत घटाकर अधिकतम 12.0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गयी।

(iii) जमा प्रमाण पत्र

1.12 बैंक प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर संग्रहण जुटा सकें इसलिए अनुसूचित बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे ब्याज दर संबंधी अधिकतम सीमा के बिना जमा प्रमाण पत्र जारी करें। जमा प्रमाणपत्र के लिए व्यवस्थित बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए उनके निर्गम पर सीमाएं निर्धारित कर दी गयी हैं। 13 अप्रैल, 1993 में लागू की गयी नई सीमाएं इस प्रकार हैं—वर्ष 1991-92 में बकाया कुल जमाराशियों के पाक्षिक औसत के 10 प्रतिशत के बराबर जमा प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं। इस निर्धारण से 20,552 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार मीयादी जमाराशि का काफी बड़ा भाग ब्याज दर नियंत्रण से मुक्त है।

(ख) आरक्षित निधि की अपेक्षा संबंधी उपाय

1.13 वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के अनेक प्रयोजनों में से एक प्रमुख प्रयोजन बैंकिंग प्रणाली पर प्रभावी कर में कमी करना है क्योंकि यह कर अत्यधिक आरक्षित निधि की अपेक्षा का स्रोतक है। अप्रैल, 1992 से सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) और आरक्षित निधि अनुपात (सी आर आर) दोनों के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे हैं। इससे वस्तुतः बैंकों की जमाराशियों में जो वृद्धि पूर्वकल्पित थी उसमें काफी कमी आयी, अर्थात् 1991-92 में वह 63.5 प्रतिशत थी जबकि 1992-93 की प्रथम छमाही में घटकर 45.0 प्रतिशत और दूसरी छमाही में और घटकर लगभग 25.0 प्रतिशत पर आ गयी। वर्ष 1993-94 की प्रथम छमाही में नकद आरक्षित अनुपात में किए गए समायोजन के साथ वृद्धिशील आरक्षित अनुपात लगभग 0.5 प्रतिशत होगी।

(i) सांविधिक चलनिधि अनुपात

1.14 वर्ष 1992-93 के संघ के बजट में दशान्ग ग सकल राजकोषीय घाटों को संशोधित करने के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की बकाया निवल मांग और मीयादी देयताओं के आधार स्तर तक सांविधिक चलनिधि अनुपात 3 अप्रैल, 1992 को

38.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया तथापि 3 अप्रैल 1992 को निबल मांग और मीयादी देयताओं का जो स्तर था उसमें यदि वृद्धि होती है तो सांविधिक चलनिधि अनुपात तदनुसार 30 प्रतिशत के स्तर पर रहेगा।

अक्तूबर 1992 में सांविधिक चलनिधि अनुपात का निर्धारित आधार स्तर 35.50 प्रतिशत से घटाकर 37.75 प्रतिशत कर दिया गया। यह कमी 3 चरणों में क्रमशः प्रथम चरण 9 जनवरी 1993, द्वितीय चरण 6 फरवरी 1993 और तृतीय चरण 6 मार्च 1993 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से की गयी तथा प्रत्येक चरण में से 0.25 प्रतिशत अंक की कमी की गयी। सांविधिक चलनिधि अनुपात में इस प्रकार की कमी करने से यह अनुमान लगाया गया था कि बैंकों की ऋण देने योग्य संसाधनों में लगभग 1,650 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। 1993-94 में सकल राजकोषीय घाटे को और अधिक संयत बनाने के साथ ही सांविधिक चलनिधि अनुपात का आधार स्तर एक प्रतिशत कम कर के 37.75 प्रतिशत से 36.75 प्रतिशत तक घटाया गया। यह कमी चार चरणों में की गयी। प्रत्येक चरण में 0.25 प्रतिशत की कमी की गयी जो 21 अगस्त, 1993, 18 सितम्बर 1993, 16 अक्तूबर 1993 और 13 नवंबर 1993 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से की गयी। इस उपाय के साथ ही यह आशा की जाती है कि बैंकों के ऋण देने योग्य संसाधन 2150 करोड़ रुपए से कुछ अधिक हो जायेंगे। इस कमी और वृद्धिशील सांविधिक चलनिधि अनुपात में भी कमी आयेगी अर्थात् 3 अप्रैल 1992 को यह 38.5 प्रतिशत के स्तर पर था। इस स्तर से घटकर यह अनुपात मार्च 1994 के अंत तक 35.4 प्रतिशत पर आ जाएगा।

(ii) नकदी आरक्षित अनुपात

1.15 मुद्रास्फीति की दर में गिरावट, राजकोषीय घाटे में कमी और वित्तीय क्षेत्र में किए गए मुधारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता से रिजर्व बैंक 1992-93 और 1993-94 के दौरान वर्तमान नकदी आरक्षित अनुपात में पर्याप्त कमी चरणबद्ध ढंग से करने के लिए प्रेरित हुआ। तदनुसार, 17 अप्रैल 1992 से वृद्धिशील 10 प्रतिशत का नकदी आरक्षित अनुपात समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 3 मई 1991 के स्तर तथा 17 अप्रैल 1992 के स्तर के बीच 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी आरक्षित अनुपात के अंतर्गत रोक रखी गयी 3,848 करोड़ रुपए की नकदी शेष राशि का एक तिहाई भाग (1,280 करोड़ रुपए) 3 समान किस्तों में जारी किया गया। यह राशि 17 अक्तूबर 1992, 14 नवंबर 1992 और 12 दिसंबर 1992 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े में जारी की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रचलित नकदी आरक्षित अनुपात में लगभग 0.6 प्रतिशत की कमी होगी। इसी के साथ-साथ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का आधार-नकदी आरक्षित अनुपात जुलाई 1989 से अपरिवर्तित था; इसमें यह आधार-अनुपात एक प्रतिशत कम किया गया। अर्थात् इस 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया जो

इससे 5 प्रतिशत प्रतिचरण के अनुसार दो चरणों में कम किया गया। यह कमी 17 अप्रैल 1993 और 15 मई 1993 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े में की गयी। नकदी आरक्षित अनुपात के विभाजन को कम करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अब तक यह छूट दी गयी थी कि वह नकदी आरक्षित अनुपात बनाए रखने के लिए जमा प्रमाणपत्रों के भाग को शामिल न करे। अब यह छूट वापस ले ली गई। 17 अप्रैल 1993 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से 2 मई 1992 से पहले की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा जारी की गयी ऋण जमाराशियां अब नकदी आरक्षित अनुपात के अधीन होंगी। इसकी सीमा 1989-90 में पाक्षिक औसत बकाया कुल जमाराशियों के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। इसलिए जमा प्रमाणपत्रों की संपूर्ण बकाया राशि नकदी आरक्षित अनुपात की अपेक्षा के लिए गिनी जाएगी। यद्यपि इससे नकदी आरक्षित अनुपात के लिए निर्धारित राशि 520 करोड़ रुपए बढ़ी—तथापि नकदी आरक्षित अनुपात में की गयी कमी से बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों में लगभग 2,360 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस उपाय से बैंकों की लाभप्रदता मजबूत होने से अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को बैंक ऋण की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

1.16 जैसाकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था, पात्र नकदी शेष राशि पर ब्याज अदा करने से अपेक्षित मौद्रिक प्रभाव हासिल करने में नकदी आरक्षित अनुपात की प्रभावकारिता कम होती है और इसलिए यह बेहतर होगा कि नकदी आरक्षित अनुपात के लिए निर्धारित राशि को कम किया जाए और इन बकाया राशियों पर ब्याज अदा न किया जाए, बजाए इसके कि नकदी आरक्षित अनुपात की राशि उच्च स्तर पर निर्धारित कर के उसकी नकदी शेष राशियों पर ब्याज अदा किया जाए। 23 मार्च 1990 को निबल मांग और मीयादी देयताओं का जो स्तर था उस स्तर से अधिक वृद्धि के आधार पर पात्र नकदी शेष राशियों पर देय ब्याज की दर 2 मई 1992 से 5.0 प्रतिशत से घटाकर 3.0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई तथा 17 अक्तूबर 1992 से 10 प्रतिशत की वृद्धिशील नकदी आरक्षित अनुपात के अंतर्गत रखे गए पात्र नकदी शेष राशियों पर भी ब्याज दिया जाता है। 23 मार्च 1990 को निबल जमा और मांग देयताओं पर आधारित पात्र नकदी जमाराशियों पर 10.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करना जारी है।

1.17 आलोच्य वर्ष के दौरान तीन अनिवारी जमा योजनाएं प्रारंभ करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि रही।

योजनाएं इस प्रकार हैं :

(i) अनिवारी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना (एन आर एन आर),

(ii) विदेशी मुद्रा (सामान्य अप्रत्यावर्तनीय) जमा योजना (एफ सी ओ एन) और

(iii) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना । ये योजनाएं आरक्षित निधि की अपेक्षाओं से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं । यह आशा की जाती है कि ये योजनाएं पहले की विदेशी मुद्रा अनिवासी और अनिवासी विदेशी योजनाओं की तुलना में अधिक आकर्षक होंगी ।*

(ग) निर्यात ऋण

1.18 निर्यात क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए ।

(i) निर्यात क्षेत्र को ऋण की आपूर्ति

1.19 नवंबर 1942 में यह शर्त लगायी गयी थी कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक जून 1993 के अंत तक अपने निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें । यदि यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जाता तो विशिष्ट नीति की शर्तें लागू होंगी जिसमें आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं बढ़ाना और पुनर्वातन सुविधाएं वापस लेना शामिल होगा ।

(ii) निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

1.20 निर्यात संवर्धन परिवेश की सहायता करने की आवश्यकता को महत्व देने हुए यह महसूस किया गया कि निर्यात ऋण पर कम ब्याज दरों के रूप में कुछ राहत प्रदान करना समीचीन है । तदनुसार 9 अक्टूबर 1992 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्यात ऋण (रूपया) संबंधी ब्याज दरें सभी स्तरों पर 1 प्रतिशत घटायी गयी । इसके अतिरिक्त 1 मार्च 1993 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले निर्यात ऋण (रूपया) को सभी स्तरों पर पुनः 1 प्रतिशत कम किया गया (परिशिष्ट सारणी 1.4) । इस प्रकार निर्यात ऋण पर मूल उधार दर 2 मार्च 1992 को 15.0 प्रतिशत थी जिसे घटाकर 9 अक्टूबर 1992 को 14.0 प्रतिशत कर दिया गया उसे और घटाकर 1 मार्च 1993 से 13.0 प्रतिशत कर दिया गया । साथ ही 24 जून 1993 से 2 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम राशि पर न्यूनतम उधार दर में उधार कमी 1 प्रतिशत अर्थात् 16

प्रतिशत होने के कारण तदनुसार 90 दिनों में अधिक और 6 महीनों तक और 6 महीनों से अधिक अवधि के मीयादी बिलों के संबंध में ब्याज दर भी क्रमशः 17 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत और 22 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दी गयी ।

(iii) निर्यात ऋण से प्राप्त ब्याज—आय पर कर

1.21 वर्ष 1993-94 संघ के बजट में यह घोषित किया गया था कि निर्यात क्षेत्र के भार को कम करने की दृष्टि से 1 अप्रैल 1993 को यह इसके बाद किसी भी बैंकिंग कंपनी द्वारा निर्यात ऋण के रूप में किसी भी निर्यातक को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर उपचित अथवा प्रोद्भूत ब्याज कर से मुक्त होंगे । इससे निर्यात ऋण से संबंधित प्रचलित ब्याज दर लगभग 1/2 प्रतिशत कम होगी ।

(iv) विदेशों में निर्यात बिलों की भुनाई

1.22 विदेशों में निर्यात बिलों की भुनाई करने के लिए बैंकों को अनुमति देने का प्रश्न काफी समय से बैंक के विचार-धीन रहा है । निर्यात ऋण के विन्यास में संबंधित समिति ने भी इस बात की सिफारिश की है कि बैंकों को विदेशों में निर्यात बिलों की भुनाई की अनुमति दी जाए । निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल 1993 में यह घोषणा की गयी थी कि भारत में स्थित प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशों में निर्यात बिल भुनाने की अनुमति दी जाए जिसकी दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों से संबद्ध होगी ।

(5) निर्यात ऋण पुनर्वित्त

1.23 रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं उदारता से प्रदान करता रहा है । इस प्रकार की पुनर्वित्त सीमाओं में काफी तेजी से वृद्धि के साथ-साथ इनमें सामंजस्य लाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक समझे गये । 31 अक्टूबर 1992 से निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं इस प्रकार थी : (क) निर्यात ऋण में वर्ष 1988-89 के मासिक औसत स्तर से अधिक तथा वर्ष 1989-90 के मासिक औसत स्तर तक हुई वृद्धि का 60 प्रतिशत + वर्ष 1989-90 में बकाया निर्यात ऋण मासिक औसत स्तर के बाद हुई वृद्धि के 110 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान किया गया, जबकि अब तक यह पुनर्वित्त 125 प्रतिशत होता था, और (ख) अमेरिकी डालर में व्यक्त पोत-लदान के बाद निर्यात ऋण पर दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदत्त इस प्रकार के 120 प्रतिशत के बराबर निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं के लिए बैंक पात्र हैं । तब तक यह पुनर्वित्त 133 1/3 प्रतिशत था ।

1.24 निर्यात ऋण पुनर्वित्त में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई । 4 मार्च 1993 को यह पुनर्वित्त कुल निर्यात

*इसके अतिरिक्त आरक्षित निधि की अपेक्षाओं से अनेक योजनाओं को छूट प्राप्त है । यह योजनाएं इस प्रकार हैं (i) विदेशी मुद्रा अर्जकों के विदेशी मुद्रा खातों की जमाराशियां (ईईएफसी), (ii) भारतीय निर्यातकों द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खातों की जमाराशियां, (iii) निवासी विदेशी मुद्रा खाता (आर.एफ.सी.), जिन्हें भारत के बैंकों में लौटनेवाले भारतीयों ने खोला है, (iv) एयर इंडिया के विमानचालकों द्वारा भारत में स्थित बैंकों में खोले गए निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी), (v) विदेश में स्थित निर्यातकों के साथ परस्पर व्यापार व्यवस्था करने वाले भारतीय निर्यातकों द्वारा खोले गए एस्क्रो खाते ।

ऋण का 61.2 प्रतिशत रहा जो कि एक ऐतिहासिक उच्च स्तर था। अतः यह महसूस किया गया कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त को संयत करना आवश्यक है। तदनुसार, 15 मई 1993 से 1988-89 के मासिक औसत स्तर से अधिक तथा 1989-90 के मासिक औसत स्तर तक कि वृद्धि का 60 प्रतिशत निर्यात ऋण + 1989-90 में बकाया निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर के बाद की वृद्धि का 100 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान किया गया है। अब तक यह पुनर्वित्त 110 प्रतिशत था। अमेरिकी डालर में व्यक्त पोत-लदानोत्तर निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा इस प्रकार दिये गये बकाया ऋण के 100 प्रतिशत के बराबर निर्यात पुनर्वित्त के लिए बैंक पात्र होंगे। अब तक यह पुनर्वित्त 120 प्रतिशत था। फिर भी निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं में 1150 करोड़ रुपये से अधिक कमी को सांविधिक चलनिधि और नकदी आरक्षित अनुपात संबंधी अपेक्षाएं घटाने के कारण पूरे हो जायेंगी और इससे बैंकों के ऋण देने योग्य संसाधन बढ़ेंगे। 1993-94 के दौरान बैंकों के पास निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत निर्यात ऋण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। क्योंकि निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर प्रभावी व्याज रिजर्व बैंक के पास रखे जाने-वाले नकदी जमा राशि पर देय व्याज से उच्चतर है इसलिए उपायों का पैकेज इस तरह से तैयार किया गया है कि इससे बैंकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

(घ) सामान्य ऋण संबंधी उपाय

1.25 उद्योग और कृषि को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए 18 जनवरी 1993 को कुछ विशेष उपाय किये गये। (1) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अतिरिक्त संसाधन

1.26 चूंकि कृषि उत्पादन की संभावनाओं में काफी सुधार आया है इसलिए इस क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण समर्थन देने की आवश्यकता है जबकि रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को प्रदान की गयी 2 सामान्य ऋण प्रणालियों की सीमाएं 1989-90 से अपरिवर्तित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यदि हाल ही के वर्षों में कृषि के कार्य में काम आने वाली निविष्टियों की कीमतों में हुई बड़ोदारी के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को अल्पावधि कृषि कार्यों के लिए सामान्य ऋण प्रणाली की राशि 400 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2,700 करोड़ रुपये से 3,100 करोड़ रुपये कर दी है। इससे नाबार्ड 1993 के रबी के मौसम के दौरान अल्पावधि कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए अधिक ऋण प्रदान कर सकेगा। अप्रैल 1993 में 93-94 की प्रथम छमाही के लिए घोषित ऋण नीति में रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड की अल्पावधि मौसमी कृषि कार्यों के लिए दी जाने वाली सामान्य ऋण सहायता को और 200 करोड़ रुपये बढ़ाकर 3,100 करोड़ रुपये से 3,300 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) को विशेष पुनर्वित्त सुविधा

1.27 पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1993 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा के रूप में 400 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की। यह सुविधा 14.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित व्याज दर से दी गयी। इसके अतिरिक्त इस बैंक के स्वयं के संसाधनों में से 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4 एच) (बी) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत 14.0 प्रतिशत की निश्चित व्याज दर से अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गयी। विल भुनाई के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्य वाहनों और मशीनों के विनिर्माता किराया खरीद और पट्टेधारी कंपनियां तथा सड़क परिवहन निगमों को भी पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध होगी।

(3) ऋण सम्बन्धी अनुशासन और मानदंड

1.28 रिजर्व बैंक ने अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त की गणना करने के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील दी है। 18 जनवरी से अगले 12 महीनों के दौरान चुकौती के लिए देय मीयादी ऋण की किस्तों के केवल दो तिहाई भाग को चालू देयताओं के रूप में माना जाएगा और शेष एक तिहाई भाग अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त की गणना करने के प्रयोजन के लिए चालू देयताओं के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस उपाय से उधारकर्ता की अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त की पात्रता बढ़ेगी जो उनके द्वारा महसूस की गयी चलनिधि संबंधी समस्याएं बहुत कुछ हद तक दूर हो जायेंगी बैंक के संसाधनों पर पड़ने वाले दबावों को कम करने के लिए और उधार कर्ताओं को कुछ और राहत प्रदान करने के लिए अप्रैल 1993 में यह निश्चय किया गया है कि इस प्रकार के अगले 12 महीनों के भीतर देय मीयादी ऋण की किस्तों का केवल एक तिहाई भाग अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त की गणना के प्रयोजन के लिए वर्तमान देयताओं के मद्दे के रूप में समझा जाएगा। इस प्रकार अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त के अंतर्गत आनेवाले उधारकर्ताओं को ऋण की उपलब्धता में 3,000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की बढ़ोतरी होगी।

(4) लघु उद्योगों का वित्त-पोषण करने के लिए माप-दण्ड पैकेज

1.29 समस्त औद्योगिक, उत्पादन, निर्यात और रोजगार में लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान को देखते हुए 7 अप्रैल, 1993 को क्रेडिट नीति के उपायों का एक विशेष

पैकेज घोषित हुआ ऐसा करते समय श्री पी. आर. नायक की अध्यक्षता में गठित लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत क्रेडिट की पर्याप्तता की जांच सम्बन्धी समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 7 अप्रैल, 1993 में उपायों का एक पैकेज घोषित हुआ ताकि लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके।

1.30 इसके लिए एक सरल सा फार्मुला तैयार किया गया है, इसके अन्तर्गत लघु उद्योग इकाइयों के वार्षिक प्रतिफल का न्यूनतम 20 प्रतिशत, उन लघु उद्योग इकाइयों की कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी निधि आधारित क्रेडिट आवश्यकताएं 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं। इसके बदले में लघु उद्योग इकाइयों को अपने वार्षिक प्रतिलाभ का 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लाना होगा। लघु उद्योग इकाइयों की शिकायतों का निवारण करने के लिए संस्थागत संरचना का सूत्रपात किया जा रहा है।

(5) कुछ क्षेत्रों को ऋण देने पर प्रतिबंध

1.31 8 अप्रैल, 1993 से शेयरों और डिबेंचरों बांडों के बदले मिलने वाले कर्ज के लिए न्यूनतम मार्जिन 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है और अलग-अलग बैंकों से मिलने वाले क्रेडिट की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी गई। शेयर की कीमतों में तेजी से कमी आने से उधार लेने वालों के सामने आ रही कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की जमानत के बदले अग्रिम धन देने के लिए 5 लाख रुपये की विद्यमान सीमा, जो जनवरी 1988 में निर्धारित की गई थी, लागू बनी रहेगी।

(6) विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

1.32 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले कुल अग्रिमों का निर्धारित लक्ष्य अर्थात् 15 प्रतिशत के मुकाबले विदेशी बैंकों ने मार्च 1992 तक 8 प्रतिशत से भी कम को वर प्राप्त की है। इन बैंकों से कहा गया है कि वे लक्ष्य में इस कमी को जून 1993 तक ठीक कर लें। इस बात का ध्यान रखते हुए कि विदेशी बैंकों का प्राथमिक शाखा नेटवर्क नहीं है, यह भी निर्णय लिया गया है कि विदेशी बैंकों द्वारा उधार दिए जाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को परिभाषा को विस्तृत किया गया है ताकि इस लक्ष्य में नियोजित व्यवस्था का भी शामिल किया जाए, परिणामस्वरूप यह लक्ष्य 32 प्रतिशत हो गया। यह 1 जुलाई, 1993 से लागू किया गया है और विदेशी बैंकों को यह लक्ष्य मार्च 1994 के अंत तक प्राप्त कर लेना चाहिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए इस समय लक्ष्य के अंतर्गत विदेशी बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों और निर्धारित क्रेडिट दोनों में से

प्रत्येक के लिए शुद्ध बैंक क्रेडिट के 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों के सर्वाधिक में इस उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए कमी के बराबर की धनराशि को 10 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज की दर पर लघु उद्योग विकास बैंक में धन जमा करके किया जाना होगा।

(इ) विदेशी मुद्रा जमा राशियां जुटाना

1.33 विदेशी मुद्रा-अनिवासी खाता स्कीम पर अत्यधिक निर्भरता रखने की परिपाटी अभी हाल ही के वर्षों में चिन्ता का विषय बनकर सामने आई है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिए जा रहे ब्याज दर विभेदकों और विनिमय दर सम्बन्धी संरक्षण को देखते हुए इस स्कीम के तहत उधार लेना बहुत महंगा है। भारतीय रिजर्व बैंक पर विनिमय में होने वाली हानि का जो बोझ पड़ता है, वह विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अन्तर्गत निधियों जुटाने की लागत का अभिन्न तत्व है। वर्ष 1990-1991 और 1991-1992 के भुगतान संकट के दौरान हुए अनुभव से भी यही सामने आया कि विदेशी मुद्रा अनिवासी से खाता स्कीम परिवर्तनशील हो सकती है; यह तथ्य इसी से स्पष्ट है कि वर्ष 1991-92 में इस खाते से 1.6 बिलियन डालर की राशि बाहर गई। यही वजह है कि हाल ही के कुछ समय के दौरान मौजूदा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के पुनर्विन्वास और ऐसी नई स्कीमों लाए जाने संबंधी प्रयास किए गए हैं जिनसे (i) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना पर निर्भरता को कम किया जा सके; (ii) विनिमय जोखिम कवर को एक वाणिज्यिक संकल्पना बनाया जा सके; और (iii) मौजूदा विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत जमा राशियों के परिवर्तनशील घटक को कम किया जा सके।

1.34 अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) जमा योजना तथा विदेशी मुद्रा (सामान्य) अप्रत्यावर्तनीय जमा योजना जैसी नई योजनाएं प्रारम्भ की गई, ताकि किसी एक योजना के प्रति जितने जमाकर्ताओं को आकृष्ट किया जा सकता है उसके मुकाबले विभिन्न श्रेणियों के कहीं अधिक जमाकर्ताओं को अलग-अलग विशेषताओं से युक्त योजनाएं चलाकर आकृष्ट किया जा सके।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना

1.35 अप्रैल 1993 में विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना मानक एक नई योजना शुरू की गई जो 15 मई 1993 से लागू कर दी गई। यह योजना मौजूदा योजना जैसी ही है, पर इसमें एक बड़ा अंतर भी है। इस योजना में जमा-दरें वही होंगी जो मौजूदा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के लिए निर्धारित की गई हों तथा निधियों को विदेशी मुद्रा में मुक्त रूप से वापस ले जाया जा सकेगा, लेकिन रिजर्व बैंक नई योजना के अन्तर्गत जमा राशियों के लिए बैंकों को विनिमय दर सम्बन्धी

कोई गारंटी नहीं देगा और इस तरह विनिमय-जोखिम स्वयं बैंकों को ही उठाना होगा। बैंक विनिमय-जोखिम को खेल मके, इसके लिए नई योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशियाँ प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के परिकलन के लिए निवल मांग और मीमादीय देयताओं का हिस्सा नहीं मानी जायेंगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जुटाये गये संसाधनों पर उधार-दर संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे तथा प्राथमिकता संबंधी क्षेत्र के उधार तय किये जाने संबंधी प्रयोजन के लिए ऐसे उधारों को निवल बैंक ऋण का अंश नहीं माना जाएगा। विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना को भी जारी रखा जा रहा है किन्तु ऐसा जमाराशियों को केवल एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की अवधियों के लिए ही स्वीकार किया जा सकेगा।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार

1.36 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में 'वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति' (अध्यक्ष : श्री एम० नरसिंहम) की सिफारिशों के संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी थी। पिछले डेढ़ वर्ष के समय के दौरान क्रियान्वित किये गये राजकोषीय और मौद्रिक नीति संबंधी उपायों में न केवल अल्पकालिक स्थिरीकरण आवश्यकताओं की झलक मिलती है, बल्कि वे राजकोषीय और वित्तीय क्षेत्रों के लिए जरूरी सुधारों की तरफ भी इशारा करते हैं। जहाँ तक वित्तीय क्षेत्र का संबंध है, सुधार संबंधी नीतियाँ को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी में समग्र मौद्रिक नीति से जुड़े मुद्दे आते हैं, ये मुद्दे हैं प्रारक्षित निधि की अपेक्षाएँ, व्याज दरें, पुनर्वित्तपोषण सुविधाएँ और आन्तरिक ऋण प्रबंधन लिखतों का प्रवर्तन। दूसरे, कुछ "संस्थागत" मुद्दे भी हैं, जैसे पूंजी-पर्याप्तता और विवेकशीलता सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित करते हुए बैंकों और संस्थाओं को मजबूत बनाना, परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण, तुलन-पत्रों को लुटिहीन बनाना और बैंकों का पुनः पूंजीकरण और अंतिम, बैंकों और वित्तीय ढांचे की प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बन्धी मुद्दे भी हैं ताकि निजी क्षेत्र में नए बैंकों का विलयन और समांमेलन की तथा नए बैंकों के प्रवेश की अनुमति देकर बड़े पैमाने पर क़िफायत की जा सके।

1.37 प्रारक्षित निधि—अपेक्षाओं के क्षेत्र में, सकल राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने की स्पष्ट घोषणा की गयी है ताकि क्रमिक रूप से कमी लाते हुए अगले तीन वर्ष में सांविधिक चलनिधि अनुपात 25 प्रतिशत किया जा सके और अगले चार वर्ष में प्रारक्षित नकदी अनुपात 10 प्रतिशत किया जा सके। जिस हद तक सकल राजकोषीय घाटे की स्थिति ठीक-ठाक बनी उस हद तक इस मध्य-कालिक उद्देश्य पर अमल करते रहना असम्भव नहीं होना चाहिए।

1.38 वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित व्याज दरों के ढांचे का स्वरूप काफी जटिल रहा है; अब इसे बदलकर अधिक आसान ढांचा बना दिया गया है। उधार दरों को

तीन श्रेणियों में बांट कर युक्ति संगत बनाया गया है, जिनमें से एक श्रेणी न्यूनतम दर की है। जमाराशियों पर व्याज की दरों की अधिकतम सीमा एक ही रखी गई है और जमा प्रमाणपत्रों, जो वृद्धिशील सावधि जमाराशियों का अब एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर दरों का निर्धारण बाजार में मुक्त रूप से होता है। बैंकों की व्याज दरों में परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय लेते हुए ऐसे निर्णयों का बैंकों की अर्थक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। निधियों की लागत और निधियों को चुकौती के बीच रहने वाले अंतर से बैंकों को मिलने वाला लाभान्श इतना पर्याप्त तो होना ही चाहिए कि बैंकों द्वारा दी जा रही सेवाओं पर आने वाली लागत, स्थापनाव्यय और शाखा विस्तार और कार्यकलापों पर आने वाले खर्चों को वहन किया जा सके। कर्जों पर ली जाने वाली व्याज दरों में कोई भी अधोगामी समायोजन केवल तभी संभव हो सकेगा जब जमाराशि पर दिए जाने वाले व्याज की दर को भी कम किया जाए, और ऐसा कर सकना भी न केवल अपेक्षित मध्यावधि मुद्रास्फीति दर पर बल्कि वैकल्पिक वित्तीय परिसम्पत्तियों पर प्राप्त होने वाले प्रतिलाभों पर भी निर्भर करता है। इसे एक ओर रखा जाए, तो भी प्रणाली को अधिक प्रभावी करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों की लागत और निधियों पर होने वाले प्रतिलाभ का अंतर गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों का कार्य भर न बन कर रह जाए।

1.39 नीलामी के आधार पर कई नई लिखतों का सूत्रपात करने से सरकारी प्रतिभूतियों पर दी जानेवाली व्याज दर वृद्धिशील रूप से मार्केट दर से सम्बद्ध हो रही है और अब कई विकल्पों की सीमा के भीतर है, जहाँ पर कि दर में किया गया परिवर्तन निवेशकों में प्रतिक्रिया जागृत करेगा।

1.40 पुनर्वित्त—पोषण के उपकरण का अनिवार्यतः प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि सर्वोच्च महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् निर्यात क्षेत्र को ऋण की आपूर्ति होती हो। जिन सीमाओं तक ऐसे पुनर्वित्त-पोषण की मात्रा बढ़ने दी जा सकती है वे साफ-साफ तय की हुई होती हैं और जहाँ कुल निर्यात पुनर्वित्त कुल पुनर्वित्त का एक बड़ा अंश बना चला आ रहा है, वहाँ ऐसे रियायती पुनर्वित्त की असीमित वृद्धि से मौद्रिक नियंत्रण की हालत बिगड़ सकती है; यह एक ऐसा ताकिक आधार है जिसकी मदद से इस प्रकार के रियायती पुनर्वित्त-पोषण की व्यवस्था में तेजी से हो रही वृद्धि को समय-समय पर संयमित किया जा सकता है।

आन्तरिक ऋण प्रबंधन नीति

1.41 मौद्रिक नीति पर अमल किये जाने की सामर्थ्य एक बड़ी सीमा तक सरकारी ऋण के मौद्रिकीकरण की सीमा पर निर्भर करती है। जहाँ सरकार के आन्तरिक ऋण की मात्रा राजकोषीय नीति का 5 परिणाम होती है, वहीं

एक सक्रिय ऋण प्रबंधन नीति का लक्ष्य सरकारी प्रतिभूतियों की संरचना, उनके परिपक्वता बिन्यास और उनसे होने वाली आमदनी को विवेकसम्मत ढंग से प्रभावित करना होता है और इसमें रिजर्व बैंक पर अनिवार्य निर्भरता में कमी लाकर तथा मुद्रा आपूर्ति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करके मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता में वृद्धि लाई जा सकती है।

1.42 स्मरण रहे कि मुद्रा प्रणाली (1985) के कार्य-चालन की समीक्षा के लिए गठित चक्रवर्ती समिति ने यह परिकल्पना की थी कि ऋण मुद्रीकरण के विस्तार को कम करने के लिए, सर्वप्रथम सरकार की उधार जरूरतें खुले बाजार से पूरी की जानी चाहिए इसका मुनिश्चयन बाजार समाशोधन ब्याज दर प्रणाली विकसित करके किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप, अन्य बातों के साथ, सक्रिय मुद्रा लिखत के रूप में खजाना बिलों का विकास जरूरी होगा। यह काम ऐसे बिलों की आय में उर्ध्वमुखी संशोधन करके किया जा सकता है। इस प्रकार, न केवल संस्थागत निवेश तथा बैंक बल्कि अन्य कम्पनी निकाय, स्थानीय सरकारी एजेंसियां, न्यास तथा अलग-अलग व्यक्ति भी खजाना बिलों तथा दिनांकित प्रतिभूतियों के एक बड़े बाजार का हिस्सा हो सकते हैं। सर्वप्रथम, इसका परिणाम यह होगा कि रिजर्व बैंक द्वारा इन लिखतों की धारण राशियों में पर्याप्त कमी आयेगी जिससे सरकार को रिजर्व बैंक के ऋण में तदनुरूप गिरावट होगी और इसके परिणामस्वरूप आरक्षित मुद्रा में कमी होगी। इससे मुद्रा और पूंजी बाजार के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और फलस्वरूप वित्तीय प्रणाली को संपूर्ण कार्यक्षमता में सुधार आयेगा। चक्रवर्ती समिति के अनुसरण में, परिपक्वता स्वरूप को नया रूप देने के लिए उपाय किये गये और सरकारी ऋण लिखतों के संबंध में ब्याज दर ढांचे को भी दूरदर्शी बनाया गया। बाद में नरसिंहम समिति ने यह राय दी कि सरकारी ऋणों पर ब्याज दरों को धीरे-धीरे बाजार से संबद्ध किया जाये और इससे सांविधिक चलनिधि अनुपात कम करने में सुविधा होगी। तथापि, एक सक्रिय आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति अपने आप ही सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी नहीं कर सकती। सांविधिक चलनिधि अनुपात राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण के नियमन पर निर्भर है। सकल राजकोषीय घाटे की नियमन व्यवस्था के अन्तर्गत, एक सक्रिय आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति मुद्रा नीति के साथ ऋण प्रबंधन नीति का एकीकरण करती है तथापि, सांविधिक चलनिधि अनुपात में की गयी कोई कमी सरकार के उधार कार्यक्रम में कमी के अनुरूप होनी चाहिए।

1.43 1992-93 में तथा 1993-94 के शुरू में, नियंत्रण के अप्रत्यक्ष तरीकों पर आधारित मुद्रानीति को बढ़ावा मिला और सरकारी प्रतिभूति बाजार विकसित करने के लिए प्राथमिक कदम उठाये गये हैं। हाल ही की अवधि में, इस क्षेत्र में कई सुधारात्मक उपाय शुरू किये गये जिसमें 364 दिवसीय तथा 91 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी तथा पुनः खरीद योजना

शामिल हैं। निश्चय ही ये उपाय निधियों के उपयोग में राजकोषीय अनुशासन का अंग हैं और इनसे निवेशकों को लचीलापन भी प्रदान होता है।

1.44 10 वर्षीय प्रतिभूति पर 13.5 प्रतिशत की कूपन दरें जब लगभग 16 प्रतिशत वाली बैंकों की उधार दर के भारित औसत के आसपास होती हैं तब उनसे यह पता चलता है कि इस प्रणाली में ब्याज दरों का एक संभावित संगम है।

भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम

1.45 एक संस्थागत आधारभूत संरचना के विकास की जरूरत है ताकि सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों के लिए एक सक्रिय गौण बाजार उपलब्ध हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। उक्त प्रस्तावित संस्था अपने चलनिधि प्रबंध के एक अंग के रूप में खजाना बिलों की तरह अल्पावधि मुद्रा बाजार परिसंपत्तियां भी रख सकता है। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की प्रारंभिक चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपये की होगी तथा उक्त निगम का स्वामित्व व्यापक आधार वाला होगा जिसमें रिजर्व बैंक, वाणिज्य और सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां शामिल होंगी।

(ख) वाणिज्य बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

1.46 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में पूंजी-पर्याप्तता निर्धारण के लिए जोखिम परिसंपत्ति भार प्रणाली शुरू करने और आय निर्धारण एवं इसके उपबंध के लिए नये नियमों का विस्तृत व्यौरा दिया गया था। अन्तरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले अखिल भारतीय स्तर के बैंकों के यथासंभव 8 प्रतिशत का जोखिम परिसंपत्ति अनुपात की पूंजी रखनी होगी और किसी भी स्थिति में 31 मार्च 1994 तक इसे प्राप्त करना होगा। भारत स्थित विदेशी बैंकों को यह मानदंड मार्च 1993 में प्राप्त करना था। अन्य बैंकों को 4 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता का मानदंड 31 मार्च, 1993 तक तथा 8 प्रतिशत का मानदंड 31 मार्च, 1996 तक प्राप्त करना है।

1.47 तथापि, यह पाया गया कि इन मानदंडों को कार्यान्वित करने में बैंकों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रिजर्व बैंक तथा वाणिज्य बैंकों का एक अनौपचारिक दल इस मामले पर विचार करने के लिए गठित किया गया। दल ने सुझाव दिया कि परिकल्पित उपायों को अमल में लाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से और अधिक समय दिये जाने की जरूरत है। तदनुसार, 31 मार्च, 1993 तथा 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले दो लेखा वर्षों के लिए कुछ छूट दी गई। यह छूट किसी खाते को "पिछले बकाया" की अवस्थिति, कृषि प्रयोजन के लिए मंजूर अग्रिमों को अनुपयोज्य परिसंपत्तियों

के रूप में मानने, उधारकर्ता/गारंटीकर्ता के निवल मूल्य अथवा प्रतिभूति मूल्य, खोई हुई परिसंपत्तियों का स्वरूप निर्धारण, संघीय अग्रिमों के बारे में तथा अनुपयोज्य परिसंपत्तियों की व्यवस्था धरणबद्ध रूप में करने और निवेश राशियों में मूल्यहास के लिए दी गई थी। व्याहारिक दृष्टिकोण से, यह महसूस किया गया कि 25,000 रुपये और उससे कम की राशि के बारे में कुल बकाया राशि के 2.5 प्रतिशत तक सकल व्यवस्था करना बेहतर होगा, न कि छोटे खातों की काफी बड़ी संख्या में एक-एक मामले का मूल्यांकन करना। दी गई अन्य प्रमुख रियायतों में 1992-93 के दौरान अनुपयोज्य परिसंपत्तियों के लिए की गई व्यवस्था घटिया परिसंपत्तियों, शंकास्पद परिसंपत्तियों के संबंध में और 25,000 रुपये तथा इससे कम की परिसंपत्तियों के मामले में कुल व्यवस्था के 50 प्रतिशत से घटाकर मार्च, 1993 से 30 प्रतिशत कर दी गई। तथापि, घाटा परिसंपत्तियों के लिए पूरी राशि मार्च, 1993 तक प्रदान करनी होगी।

1.48 इन छूटों के बावजूद नये मापवण्ड बैंकों के तुलन-पत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। इसलिए वर्ष 1993-94 के बजट में सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे यह समस्या फिलहाल कुछ समय के लिए सुलझ जाएगी। इनमें से कुछ बैंक अपने इक्विटी संसाधन या तो पूंजी बाजार से या फिर कर्ज निम्नलिखित जारी करके जुटाने में समर्थ हो सकेंगे।

1.49 जहां बैंकों के संसाधनों की मजबूत बनाये जाने संबंधी उपाय किए जा रहे हैं, वहीं बैंकों की बकाया राशियों की वसूली में विलम्ब होने सम्बन्धी मुद्दा बैंकों की वर्तमान नकदी-प्रवाह की स्थिति से जुड़े हुए पहलुओं को देखते हुए गम्भीर चिन्ता का विषय बना रहा। चूंकि बैंकों की बकाया राशियों की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर भी शीघ्र वसूलियां हो सकने में कोई मदद नहीं मिली इसलिए लोकसभा ने 10 अगस्त 1993, को बिल पाम किया। इस संदर्भ में संसद ने 10 अगस्त 1993, को "बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए विशेष वसूली अधिकरण का गठन करने के लिए, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993" नामक एक नया अधिनियम पारित किया।

(घ) निजी क्षेत्र के बैंक

1.50 बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश की अनुमति देकर ज्यादा बड़ी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत के मान्यता दिए जाने के पक्ष में बराबर बढ़ोतरी हुई है। तदनुसार रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नये बैंकों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जिनका ब्योरा इस रिपोर्ट के भाग-II में दिया गया है। निजी क्षेत्र के किसी भी नए बैंक की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी और उसे विवेकसम्मत मानदण्ड तथा 8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता का पालन शुरू से ही करना होगा। कई

आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तीन वित्तीय संस्थाओं भारतीय युनिट ट्रस्ट, आवास विकास वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम लिमि. के आवेदन पत्र सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिये गये हैं। निजी क्षेत्र के इन बैंकों द्वारा शीघ्र ही काम शुरू कर देने की आशा है।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

1.51 यह सुनिश्चित करने के लिए कि विवेकसम्मत विनियमनों का पालन किया जा रहा है एक सुदृढ़ पर्यवेक्षण प्रणाली आवश्यक हो गई है। रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और विनिर्देशों का अनुपालन कराए जाने पर जोर देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों अर्थात् बैंकों वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के भीतर ही भीतर विवेकसम्मत आंतरिक नियंत्रण और जोखिम आंकलन प्रणाली का होना भी आवश्यक है। रिजर्व बैंक के भीतर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना की रूपरेखा बहुत प्रागे तैयार कर ली गई है तथा इस बोर्ड के शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा है यह बोर्ड पूर्णरूप से केवल पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य करेगा और इसे ऋण प्रबंधन, परिसम्पत्ति वर्गीकरण, आय के स्रोतों को पड़ना, धन व्यवस्था पूंजी पर्याप्तता और कोष परिचालनों के क्षेत्र से जुड़े विनियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

(ङ) वित्तीय प्रणाली के अन्य संभागों में सुधार

1.52 सुधार प्रक्रिया को बृहत्कार बनाए जाने की आवश्यकता महसूस करते हुए हाल ही के कुछ समय के दौरान वित्तीय प्रणाली के अन्य संभागों की ओर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। मराठे समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के सुधार के लिए आधार तैयार किया है, जबकि शाहू समिति ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सुधार संबंधी रूपरेखा तैयार की है। इन दोनों रिपोर्टों पर कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है और इस संबंध में किए गए उपायों का ब्योरा इस रिपोर्ट के भाग-II में दिया गया है। बीमा क्षेत्र को हाल ही तक सुधार प्रक्रिया के दायरे के भीतर नहीं लाया गया था; तथापि श्री आर०एन० मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार सम्बन्धी समिति गठित की गई है।

विदेशी क्षेत्र सम्बन्धी नीतियां

(क) विनिमय दर नीति

1.53 व्यापार, उद्योग, विदेशी निवेश और स्वर्ण का आयात करने के कार्यक्षेत्रों में उदारीकरण के अन्य उपायों के साथ-साथ मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का सूत्रपात किया गया। एक अस्थायी दर बंदोबस्त के तौर पर उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली ने रुपये

के विदेशी मूल्य को स्थिर बनाये रखने तथा लेनदेनों की बढ़ी हुई मात्रा के लिए एक सीमित अंतः बैंकों विदेशी मुद्रा बाजार तैयार करने का काम किया। तथापि इसमें एक दोहरी विनिमय दर प्रणाली की व्यवस्था थी, किन्तु एक अन्य तत्व जो इसमें मौजूद था, वह निर्यातों पर कर निर्यात प्राप्तियों की अभ्यर्पण दरों के आपसी अंतर के फलस्वरूप आया था। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली को और ज्यादा लम्बे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था क्योंकि इसकी वजह से कुछ आयातों के बीच राजकीय सहायता प्राप्त विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ता था और जिसका हर हाल में नतीजा यही निकलता कि संसाधनों के आबंटन की स्थिति गड़बड़ा जाती थी। इस प्रणाली के चालू रहते हुए ऐसे संकेत मिले थे कि मुद्रा प्रेषण अपनी सामान्य दिशा बदल कर पूंजीगत खाते की ओर मुड़ जाते थे। क्योंकि कुछ अनिवासी रुपया जमा खातों में जमा की जाने वाली राशियों के बाजार विनिमय दर पर पूर्ण परिवर्तन की अनुमति होती थी, जबकि चालू अंतरणों के रूप में किए जाने वाले मुद्रा-प्रेषण केवल 60 प्रतिशत की हद तक ही बाजार विनिमय दर पर परिवर्तित किए जा सकते थे। आधिकारिक विनिमय दर में निम्नगामी समायोजन दिसम्बर, 1992 के गुरु में हुआ था तथा दोहरी दरों को अंतिम तौर पर आपस में मिलाकर इस व्यवस्था को 1 मार्च, 1993 से लागू कर दिया गया।

1.54 विनिमय दरों का एकीकरण चालू खाते की परिवर्तनीयता की दिशा में प्रगति किए जाने संबंधी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भुगतान संतुलन संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश के अनुरूप है (देखें बॉक्स-I) मुक्त रूप से परिवर्तनीय विनिमय दर की प्रणाली विदेशी मुद्रा नियंत्रण के विन्यास के दायरे में अभी भी बैसी ही चल रही है। जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती रहती है उसे बैंकिंग क्षेत्र के हवाले कर दिया जाता है जिससे जायज प्रयोजनों के लिए उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा की मांग पूरी की जाती है। इन लेनदेनों को विनिमय की जिस दर पर सम्पन्न किया जाता है वह बाजार में निर्धारित होते हैं।

बॉक्स-I

भुगतान संतुलन संबंधी उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार द्वारा डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित भुगतान संतुलन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1992 में तथा अंतिम रिपोर्ट अप्रैल, 1993 में प्रस्तुत की। समिति ने भारत के भुगतान संतुलन के विभिन्न पहलुओं में सम्बन्धित विस्तृत सिफारिशों की तथा समिति की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को हाल ही के कुछ समय के दौरान लिए गए नीति निर्णयों में आधार बनाया गया है।

एक वास्तविक विनिमय दर का पक्ष लेते हुए समिति ने सिफारिश की कि पूर्ण-परिवर्तनीयता की दिशा में विनिमय दर का एकीकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस सिफारिश के अनुसरण में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च, 1993 से लागू कर दी गई।

समिति ने यह सिफारिश भी की कि आयातों और अन्य भुगतान सम्बन्धी अपेक्षाओं पर लगने वाले तीन माह के समय के उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर प्रारक्षित निधि के लक्ष्य तय करते रहना चाहिए। समिति की नजर में प्रारक्षित निधि को न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं आने दिया जाना चाहिए। समिति ने यह सिफारिश भी की कि स्वर्ण को विदेशी मुद्रा संसाधनों में परिवर्तित किए जाने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए; हालांकि, फिलहाल कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें इस विकल्प का प्रयोग किए जाने की जरूरत पड़ी हो। इसके साथ ही, समिति ने यह सिफारिश की कि आकस्मिक खर्चों की पूर्ति के लिए ग्रन्थ सूचना पर स्वर्ण को मुद्रा संसाधनों में बदलने के लिए स्वर्ण का कुछ हिस्सा अनग रखा जाना चाहिए।

जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, समिति ने सुझाव दिया कि विदेशी सहायता का 100 प्रतिशत राज्यों को सभी क्षेत्रों के लिये दे दिया जाना चाहिए। समिति का मानना था कि पांच वर्ष में कम अवधि वाले वाणिज्यिक उधारों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए तथा विदेशी उधारों की सार्वजनिक गारण्टी दिये जाने जैसे एक सतर्क दृष्टिकोण का पक्ष लिया। समिति ने सुझाव दिया कि विदेशी वाणिज्यिक उधारों के संक्षिप्तकरणों के मामले में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर की वार्षिक सीमा निर्धारित की जाए। साथ ही समिति का यह निष्कर्ष था कि भारत में ऋण-प्रबंधन के लिए ऋण इक्विटी परिवर्तन का विकल्प कोई उपयोगी विकल्प नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि प्रयोग के तौर पर स्वर्ण बांड जारी किये जा सकते हैं।

अनिवासी भारतीय उधारों की परिवर्तनीयता और लागत कम किये जाने के लिए समिति ने सिफारिश की कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता जमा राशियों के मामले में न्यूनतम परिपक्वता अवधि एक वर्ष हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्याज दरों और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता दरों के बीच अन्तराल को ऋमिक रूप से कम किया जाए। समिति इस बात के पक्ष में भी थी कि अनिवासी भारतीय को मध्यावधि निवेशों के प्रति आकृष्ट करने के लिए अनिवासी भारतीय ब्राण्डों के बाजार विकसित करने चाहिए।

समिति का मानना था कि मध्यावधि ऋण की अनुमति केवल व्यापार से जुड़े प्रयोजनों के लिए ही दी जानी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश भी की कि अल्पावधि ऋण के लिए एक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की जाए ताकि किसी समय विशेष पर बकाया अल्पावधि ऋण को मात्रा का पता लगाया जा सके। विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए समिति इस बात के पक्ष में थी कि लाभांश के देश में बाहर जाने, विदेशी राष्ट्रों द्वारा विनिवेश और उनके रोजगार से सम्बन्धित मौजूदा नीति और प्रथाओं को कानूनी रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय "निवेश कानून" बनाया जाना चाहिए।

मध्यावधि के लिए समिति का मानना था कि निर्यात में न्यूनतम 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि डालरों में सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति का विचार था कि, सकल देशी उत्पाद का 1.6 प्रतिशत चालू खाता घाटा, निवल पूंजीगत प्राप्तियों के एक वाजिब स्तर के माध्यम से बनाये रखा जा सकता है।

1.55 प्राधिकृत व्यापारियों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे उन्हें बेची गई विदेशी मुद्रा का कोई भी अंश भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपे। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मर्जी से बाजार में विदेशी मुद्रा खरीदने/बेचने के लिए उतर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राम तौर पर विदेशी मुद्रा की बिक्री, भारत सरकार के ऋण चुकोती जैसी अनुमोदित प्रयोजनों के लिए और एक्जिम स्क्रिप्सों के पूर्ण मूल्य तथा निर्यातकों को जारी किए गए कुछ अन्य लाइसेंसों के 40 प्रतिशत अंश की पूर्ति के लिए अवस्थांतरण व्यवस्था के रूप में की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेनदेनों के लिए प्रमुख मुद्रा अमरीकी डालर है। भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी विनिमय दर पर लेन-देन करता है, जो चालू बाजार दर की 5 प्रतिशत के मार्जिन के बीच-बीच हो। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी खरीद और बिक्री दरों के अतिरिक्त एक ऐसी संदर्भ दर (रेफरेंस रेट) की घोषणा भी करता है जो बम्बई स्थित कुछ चुनिंदा बैंकों के प्रतिदिन 12 बजे की दरों के आधार पर तय किया जाता है। यह संदर्भ दर विशेष आहरण अधिकार संबंधी लेनदेनों तथा एणियाई समाशोधन संघ के माध्यम से किए गए लेनदेनों पर लागू होती है।

1.56 एकीकृत विनिमय दर में निर्यात आमदनियों में वृद्धि लाने के लिए समुचित कीमत-प्रोत्साहन की व्यवस्था है। मात्राजन्य, नियन्त्रण, क्रमिक रूप से हटा लिए जाने के फलस्वरूप मूल्य परिवर्तन के प्रति मांग और पूर्ति की संवेदनशीलता में सुधार आयेगा तथा विनिमय दर से, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा के प्रभावी आयात में मदद मिलेगी। विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तनों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा विनिमय के नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों को भी शामिल किया गया है; इनका व्यौरा रिपोर्ट के भाग-II में दिया गया है। व्यापार नीति में संशोधनों के फलस्वरूप मात्राजन्य नियन्त्रण पर्याप्त रूप से युक्ति-संगत बन गए हैं और लाइसेंसिकरण की आवश्यकता वास्तव में नहीं रह गई है। मूल्य विनियन्त्रण सम्बन्धी उपाय भी एक बड़ी मात्रा में अमल में लाए गए हैं, विशेषतया उर्वरक, स्टील, और सीमेन्ट जैसे प्रमुख संरचनात्मक निवेशों में, बाजार में तंगी आ जाने पर बड़ी मात्रा में आयातों के लिए विदेशी मुद्रा बाजार की उपलब्धता से अनावश्यक खलबली से बचने के लिए प्रारंभिक स्तरों पर सहायक हो सकता है। जैसे-जैसे विदेशी मुद्रा बाजार का दायरा, लिखतों के उप-बाजारों सहित, बढ़ता चला जाएगा और जैसे-जैसे उसका मुद्रा और पूंजी बाजार के साथ जुड़ाव होता चला जाएगा, मुक्त विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली की बुनियादी शर्तें पूरी होती जाएंगी।

1.57 एकीकृत विनिमय दर प्रणाली का आरम्भिक अनुभव उत्साहजनक रहा। एकीकृत विनिमय दर प्रणाली के क्रिया-न्वयन के शुरूआती महीनों में बाजार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अत्यधिक मात्रा में हो गयी थी जिसके पीछे ये कारण थे कि निर्यात से हुई आय, वर्तमान और—पिछले संभव धन संचयों और धन प्रेषणों को तेजी से स्वदेश भेजा गया, लेनदेन नाजायज तरीके से होने की बजाय वैकिंग प्रणाली के माध्यम से होने लगा और आयात सम्बन्धी मांग कमजोर पड़ी।

इसके परिणाम स्वरूप रुपया स्थिर रह और कई मौकों पर यह मजबूत भी हुआ। प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा बिक्री किए जाने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों का महत्वपूर्ण संचय हुआ।

(ख) विदेशी ऋण प्रबंधन कार्यनीति

1.58 अस्सी के दशक के दौरान विदेशी वित्त व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए वित्त व्यवस्था के अधिक महंगे तथा अधिक परिवर्तनशील स्रोतों का सहारा लेना पड़ा। सातवीं योजना अवधि के दौरान (1985-90) वित्त व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता के साथ-साथ वाणिज्यिक उधारों और अनिवासी जमा राशियों ने एक समान भूमिका निभाई। वर्ष 1990-91 के उत्तरार्ध और 1991-92 के पूर्वार्ध में हुए भुगतान संकट से यह प्रकट हो गया कि साख की समस्या को देखते हुए वित्त-व्यवस्था का ऐसा प्रतिरूप वर्दीष्ट करने योग्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू खाते के जो घाटे सामान्य रूप से वित्त-पोषण किए जाने योग्य थे वे अर्थश्रम नहीं रहे और सामान्य पूंजी प्रवाह भी बिगड़ गया। यह स्पष्ट हो गया है कि ऋण प्रबंधन कार्यनीति की आवश्यकता है जो कि पूंजी खाते का पुनःसंरचना करेगी जिसमें संरचनागत रूप परिवर्तन कर रही अर्थव्यवस्था की विदेशी वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यकताओं में अनुकूलता लाई जा सके। तदनुसार परिवर्तनशीलता को कम करने समग्र और सापेक्षिक लागत प्रतिक्रियों पर आधारित उधार लेने के चार्ट तैयार करने और इस प्रकार के उधारों में छिपी हुई लागतों जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए जा रहे विनिमय जोखिम का बोझा भी शामिल है, को समाप्त करने के कदम उठाए गए।

1.59 अन्तर्राष्ट्रीय दर-निर्धारक एजेंसियों द्वारा देश का वर्तमान दर निर्धारण निम्न स्तर पर कर देने से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार तक पहुंचने में बाधा आई है, जिसकी वजह से देश की लागत और मोटादा ढांचे को देखते हुए वाणिज्यिक उधारों का पुनर्विन्वास करना पड़ा। जिन देनदारियों में शासकीय गारंटी तथा एक वर्ष से 12 वर्ष तक या 12 वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि शामिल होती है उनके लिए सीमा बांध दी गई है। ऐसे ही कंप अल्पावधि ऋणों पर भी लगाया गया है और अल्पविधि ऋण के ओवर हैंग को

समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किया गए हैं, मध्यावधि में, जैसा कि भुगतान संतुलन संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने पाया है, ऐसे उपायों से विदेशी उधारों की परिपक्वता अवधि में वृद्धि होगी, रियायती और गैर-रियायती उधारों के बीच पुनः संतुलन स्थापित होगा तथा इनसे यह सुनिश्चित होगा कि ऋण चुकौती के जरिए चालू प्राप्ति का अपेक्षाकृत पहले निपटान किया जाना नाजायज नहीं है।

(ग) विदेशी निवेश नीति

1.60 वर्ष 1990-92 के दौरान विदेशी भुगतानों सम्बन्धी संकट के पश्चात विदेशी विन के ऋणोत्तर आगमों के सृजन के पक्ष में जोर दिया जाने की दिशा में बढोत्तरी हुई है। इससे पहले तकनीकी स्थानांतरण से न जुड़े हुए विदेशी निवेशों को सामान्यतया कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि विशिष्ट फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों को सन्निकट रूप से प्राप्त कर लिया गया है तथा यह कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण विदेशी निवेश के आगम में अक्सर रुकावट आती है। औद्योगिक और विदेशी निवेश नीतियों में जलाई 1991 में आमूलचूल उदारीकरण किया गया जिसका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष में विदेशी निवेश को आकृष्ट करने और उसका उपयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाए जाने की दिशा में कई अन्य उपाय किए जाते देखे गए। इन उपायों में विनियम दरों में लाई स्थिरता वित्तीय क्षेत्र में हो रहे मुधारों व्यापार नीति उदारीकरण और टैरिफ तथा उत्पाद शुल्कों में कमी करना शामिल है।

1.61 विदेशी निवेश के लिए बाजार सुलभ वातावरण विकसित करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विदेशी संस्थागत निवेशकों अर्थात् पेंशन फण्डों, म्यूचुअल फण्डों, परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनियों, निवेशकर्ता ट्रस्टों, नामित कंपनियों और निगमित या संस्थागत संविभाग प्रबंधकों को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इसमें हिस्सा लिया जाना उम्हें शर्तों के अधीन है जो सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य है। विनिवेश के सम्बन्ध में उन पर लॉक-इन पीरियड की कोई बन्दिश नहीं है। निवेश की कोई सीमा नहीं है तथा दीर्घावधि (एक वर्ष से अधिक) पूंजीगत प्राप्ति पर 10 प्रतिशत और अल्पावधि पूंजीगत प्राप्ति पर 30 प्रतिशत की रियायती कर दर की सुविधा उन्हें मिलती है। लाभांश और ब्याज से होने वाली आय पर 20 प्रतिशत की दर अन्य देशों में विद्यमान कर दरों के समान ही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हिस्सा लेने पर नियन्त्रण रखने सम्बन्धी दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा तैयार कर लिये गये हैं, इन दिशानिर्देशों का उल्लेख खण्ड II में किया गया है।

1.62 भारत सरकार ने रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिये अपनी बचतबद्धता को पूरा करने की दृष्टि से 8 जनवरी 1993 को एक अध्यादेश पारित किया जिसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में कुछ संशोधन किए गए। बाद में इसके स्थान पर विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1993 लाया गया। इन संशोधनों को 8 फरवरी, 1993 से लागू माना गया है तथा ये संशोधन प्रमुखतः भारत स्थित "फैरा कंपनियों" के कार्यकलापों में सम्बन्ध रखते हैं और नए उपबन्धों (धारा 28-अ और 73-आ) में माल के लीज अथवा किराये पर निर्यात किए जाने तथा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उनका बेहतर ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए बेहतर विनियमन की व्यवस्था की गई है। फैरा में किए गए प्रमुख परिवर्तन इस रिपोर्ट के भाग II में दिए गए हैं।

(घ) व्यापार नीति

1.63 व्यापार नीति का पुनर्विचार उस सुधार कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बना हुआ है जिस पर जुलाई 1991 से काम चल रहा है। जहाँ निर्यातकों को आयात लाइसेंसों का उदार रूप से दिया जाना पिछले दो वर्षों से निर्यात संवर्धन का एक साधन बना हुआ था, वहीं इस पर अमल किए जाने में नीति का स्वेच्छिक रूप से प्रयोग करने संबंधी प्रशासनिक बाधाएं और उसके दुरुपयोग जैसे तत्व भी शामिल थे। अतः मार्च 1992 में घोषित एक्जिम नीति, 1992-97 के जरिये कुछ कार्यविधियों को हटाया गया और कुछ को आसान बनाया गया और नीति समायोजनों की एक श्रृंखला का प्रारूप तैयार किया गया ताकि व्यापार क्षेत्र बृहदाकार प्रतिस्पर्धी दक्षता प्राप्त कर सके और यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का समुन्नत अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने में मदद दे सके। 1 अप्रैल 1993 से लागू संशोधन, इस प्रक्रिया में स्तर-दर-स्तर स्थिति दर्शाते हैं।

1.64 मशीनगत उपायों पर दो तरफ से जोर दिया गया है। एक तरफ सुधारों की संरचना इस प्रकार तैयार की गई कि उससे निर्यात प्रोत्साहनों तक सुगमता से पहुंच के जरिए, बृहदाकार निर्यात कार्यानीति को सम्बल मिल सके। इस प्रकार, हाल ही में किए गए संशोधनों में, अर्थव्यवस्था में कृषि और उसमें जुड़ी हुई गतिविधियों और सेवाओं जैसे क्षेत्रों को आयातों के मामले में बेहतर सुविधाएं प्रदान की गईं। कृषि, जलचरपालन, पशुपालन, फूलों की खेती, बागवानी मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन, रेशमीकट पालन में लगी इकाइयों को ई ओ यू/ई पी जैड योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क-मुक्त आयातों का लाभ उठाने की अनुमति है, यदि वे मूल्य की दृष्टि से आने उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत का ही निर्यात करते हों। पूंजीगत माल वर्गीकरण का विस्तार इस प्रकार किया गया कि उसमें कृषि और उसमें जुड़ी हुई गतिविधियों में सम्बन्धित मर्दों को शामिल किया जा सके। ये मर्द अब तक निपिद्ध माल-सूची में शामिल थीं। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना की आवधिक रूप से समीक्षा

और उसमें संशोधन इस प्रकार किया जाता है, कि पूंजीगत माल का आयात अधिक तीव्रतापूर्वक हो सके। सेवा क्षेत्र के लिए एक नई याजना शुरू की गई, ताकि व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित पूंजीगत माल के आयातों में गिरावट मिले।

1.65 व्यापार नीति संबंधी सुधार में जिस अन्य मुद्दी को सुलझाया गया है वह है मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को क्रमिक रूप से हटाया जाना। लाइसेंसिकरण को संकल्पना को गुंथित/मुक्त बनाया गया और उसे सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए चालू किया गया। पूंजीगत माल, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, पुर्जों, स्पेयर पार्ट्स के आयात सम्बन्धी वास्तविक उपभोक्ता शर्तों को हटा दिये जाने के फलस्वरूप, आयातों का क्रिया जाना अब बिना किसी भेदभाव के कुछ मौजूदा लाइसेंसों पर ही होता है। गुणवत्ता संबंधी जो नियंत्रण शेष बचा रहता है, वह है निर्यातों और आयातों दोनों ही के लिए एक निपिद्ध सूची; इस सूची की निपिद्ध मदें अथवा वे मदें दी गई हैं जिनके लिए लाइसेंसिकरण अथवा एजेंसी माध्यम के निर्यात व आयात किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से निर्यात व आयात करने की आमतौर पर अनुमति नहीं होगी। 1 अप्रैल, 1993 के दिन से लागू किए गये हालिया संशोधनों के अन्तर्गत एक्सपोर्ट हाउसों, ट्रेडिंग हाउसों और स्टार ट्रेडिंग हाउसों को मान्यता दिए जाने संबंधी मानक और साथ ही, अनुमत प्रोत्साहनों की मात्रा का सम्बन्ध निम्नलिखित विदेशी मुद्रा आरामदती में होने की बजाए अब निर्यातों के पोत परदेन्त निःशुल्क (एफओबी) मूल्य से है। निपिद्ध वस्तुओं की आयात सूची को अपने आप में ही अगस्त 1992 में छोटा बना दिया गया। निर्यात के लिए निपिद्ध वस्तुओं की सूची में से 144 प्रविष्टियों को 1 अप्रैल 1993 से निकाल दिया गया है। मात्रात्मक नियंत्रणों को मुक्त किया जाना, टेरिफ में की गयी कमी और परिवर्तनशील विनिमय दर के साथ मिलकर, निर्यातों और आयातों की मूल्य संकेतकों के प्रति संवेदनशीलता को सुधारने का काम करेगा। व्यापार नीति में जिन सुधारों की परिकल्पना की गयी है, जब उन्हें पूरी तरह से अमल में लाया जायेगा तो राजकोषीय तथा अन्य प्रोत्साहन, भुगतानों पर नियंत्रणों और अन्ततः शेष बचे विवेक सम्मत उपायों को क्रमबद्ध रूप से हटाये जाने के फलस्वरूप उन सुधारों से पूर्ण परिवर्तनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता के मध्यावधि लक्ष्यों को प्राप्त करने का आधार तैयार होगा।

पूंजी बाजार

1.66 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) को भारत में पूंजी बाजार की नियामक एजेंसी बना दिया गया है। सेबी ने कई दिशानिर्देश/विनियम प्रकाशित किये हैं; ये दिशानिर्देश/विनियम बाजार से जुटाई गई निधियों से सम्बद्ध नए शेयर निर्गमों से सम्बन्धित घोषणा और निवेशकों की संरक्षा के लिए कम्पनियों और विकास वित्त संस्थाओं

के लिए अलग-अलग प्रकाशित किये गये हैं। सेबी ने शेयरों के परोक्ष लेनदेन, म्युचुअल फंडों, संविभाग प्रबन्धकों और मर्चेन्ट बैंकों के कार्यकलापों के लिए भी विनियम जारी किए हैं। सेबी के विकास वित्त संस्थाओं के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों के अंशदान की अब आवश्यकता नहीं रह गई है और हामीदारी की अनिवार्यता भी नहीं होगी। इन संस्थाओं के संबंध में, शेयरों का मूल्य निर्धारण मुक्त रूप से किये जाने की अनुमति है बशर्ते तीन वर्ष के रिकार्ड में स्थिरता हो और तीन वर्षों से अधिक के डिबेंचरों और बांडों के लिए ऋण योग्यता निर्धारण अनिवार्य किया गया हो। कंपनियों द्वारा आम जनता के लिये जारी किए जाने वाले निर्गमों के संबंध में सेबी ने जहां अपने दिशानिर्देशों में निर्गमों के मूल्य मुक्त रूप से निर्धारित किए जाने की व्यवस्था की है, वहीं प्रवर्तकों द्वारा निजी तौर पर कोटा दिये जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और हामीदारी को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने भी विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। शेयर बाजारों में निर्गमित सदस्यता को सुविधाजनक बनाने के लिहाज से एक अधिसूचना भी जारी की गई है।

1.67 आशा की जाती है कि पूंजी बाजार के सुधार के क्षेत्र में किये गए उपायों से शेयर बाजार और अधिक कारगर ढंग से काम करेंगे और निवेशकों को सुरक्षा मिलेगी। चूंकि गार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलने वाली बजट आदिकारिक सहायता में कमी भी गिरावट आ सकती है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि बचत राशियां जुटाए जाने के साधनों के रूप में पूंजी बाजार अपने कार्य प्रभावी ढंग से करें।

शेयर संतुलनकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश

1.68 हाल ही में किया गया एक महत्वपूर्ण उपाय शेयर संतुलनकर्ताओं के इस क्षेत्र में उतरने को प्रोत्साहन दिए जाने से संबंधित है; ये शेयर संतुलनकर्ता दो तरफा कोटेशनों के जरिए प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिये कि शेयर संतुलनकर्ता स्क्रिपों के लिए धन जुटाने की स्थिति में हो तथा शेयरों के मूल्यों में होने वाली भारी घट-बढ़ में कमी ला सकें, रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त 1993 को उनके कार्यकलापों को बैंक द्वारा वित्त पोषित किये जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंक उन शेयर संतुलनकर्ताओं की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को निर्धारित किये जाने के मामले में अपने व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं जो सेबी द्वारा अनुमोदित हों। तथापि, शेयरों, डिबेंचरों/बांडों पर व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए 50 प्रतिशत के मौजूदा न्यूनतम मार्जिन की शर्त बैंकों द्वारा शेयर संतुलनकर्ताओं को दिये जाने वाले अग्रिमों पर लागू नहीं होगी।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति परिचालनों के संबंध में जानकारीरामन समिति

1.69 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में, प्रतिभूतियों के लेनदेनों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई घोर अनियमितताओं की समूची घटना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। जानकारीरामन समिति की पहली तीन रिपोर्टों में प्रस्तुत निष्कर्ष तथा इसकी सिफारिशों और साथ ही संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किये गये तात्कालिक सुधारात्मक उपाय भी पिछली रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट मार्च 1993 में और छठी (अंतिम) रिपोर्ट अप्रैल 1993 में प्रस्तुत की। जहां चौथी और पांचवीं रिपोर्ट में कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं विशेष के बारे में चर्चा की गई थी, अंतिम रिपोर्ट में समग्र निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्टों में 32 बैंकों और संस्थाओं के बारे में ऐसे विस्तृत निष्कर्ष दिए गए हैं। जिनमें गंभीर स्वरूप की अनियमितताएं बरती गई हैं। इन निष्कर्षों में दलालों, वित्तीय संस्थाएं, और बैंकों के बीच सांठ-गांठ के और इस तथ्य को उजागर किया गया है कि रिपोर्ट में वर्णित बैंक और उनकी सहायक संस्थाएं सविभागीय प्रबंधन सेवाओं, हाजिर वायदा लेनदेन और बैंक रसीदों को जारी करने संबंधी विशानिर्देशों का जान-बूझकर उल्लंघन करने में लगी हुई थीं ताकि दलाल/वित्तीय कंपनियां शेयर बाजार में बड़े लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में धन हासिल कर सकें।

1.70 इन रिपोर्टों में ऐसे चार प्रमुख कारणों की पहचान की गई है जिनसे अनियमितताओं संबंधी यह आपराधिक कृत्य संभव हो सका : (i) बैंक रसीदों का अनुचित और अंधाधुंध प्रयोग; (ii) दलालों द्वारा अपने निजी खातों से भारी लेनदेन किया जाना और लेनदेन की स्थिति को आगे के लिए टालना; (iii) बैंकों द्वारा निवेशों का आवधिक रूप से मिलान न किया जाना और (iv) कई बैंकों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पूर्णतः असफल रहना। समिति ने पाया कि इन अनियमितताओं के फलस्वरूप बैंकों के निवेश सविभाग की हालत नाजुक और कमजोर हो गई है। समिति के अंतिम अनुमान के अनुसार बैंकों द्वारा किये हुए निवेशों के मूल्य को समाविष्ट करते हुए, बैंकों की कुल मिलाकर 4,024 करोड़ रुपये की राशि का घोटाला हुआ है। जिसके लिए उनके पास कोई प्रतिभूतियां, एस० जी० एल० अंतरण फार्म या बैंक रसीदें अथवा जहां उनके पास ऐसी प्रतिभूतियां हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जारीकर्ता बैंक को पर्याप्त समर्थन नहीं है और प्रतिभूतियों सहित अन्य दस्तावेज जारी/भरी पाई गई हैं।

1.71 समिति ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि बैंकों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपर्याप्त हैं और पर्यवेक्षण तंत्र में कमजोरियां हैं। विशेषतौर पर बड़ी मात्रा में पायी जाने वाली अनियमितताओं को ढूंढ निकालने में रिजर्व बैंक की ओर से हुए विलंब के पीछे जो प्रमुख कारण हैं, वे हैं—अनियमित आचरणों के हर तरफ फैले होने के

प्रति अनभिज्ञता अथवा उसे न जान पाना, विदेशी बैंकों द्वारा प्रयुक्त अधुनातन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग प्रणालियों की विशेषीकृत जानकारी का न होना, एक अच्छी बाजार आसूचना प्रणाली का अभाव, निरीक्षणों के दौरान ज्यादा-से-ज्यादा शाखाओं को कवर किए जाने संबंधी एक नियम के कारण पर्यवेक्षण प्रणाली के संसाधनों का जरूरत से ज्यादा होना और निरीक्षणों के दौरान खजाने के कार्यकलापों को पर्याप्त महत्व न देना। बाहरी लेखा परीक्षकों की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा कि लेखा परीक्षक सभी लेनदेनों की जांच नहीं करते हैं और इस बात को अपनी इयूटी में मानकर नहीं चलते हैं कि रिजर्व बैंक के विशानिर्देशों के उल्लंघनों की जांच की जाए इसके अतिरिक्त समिति ने पाया कि यदि विभिन्न नियंत्रण एजेंसियों के बीच और अधिक पारस्परिक सन्वय होता तो संभव है कि अनियमितताएं पहले ही पकड़ में आ जातीं।

1.72 समिति की पहली तीन रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुसरण में, भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के सेट को पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही शामिल किया जा चुका है। बाद की तीन रिपोर्टों में सुझाये गये सुधारात्मक उपाय नीचे दिये गए हैं :

- (i) बैंकों से कहा गया है कि वे अपने आंतरिक लेखा-परीक्षक विभागों की पर्याप्तता के बारे में समीक्षा का काम तत्काल शुरू कर दें।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण प्रणाली में परिवर्तन करके उसमें बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण और अधिक विस्तार से किये जाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही, कुछ बैंकों के प्रतिभूतियों के लेनदेनों के सत्यापनों के लिए चाटर्ड अकाउंटेंटों की अनुभवी फर्मों को नियुक्त किया जाए।
- (iii) प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए या किसी बैंक द्वारा किये गए लेनदेनों पर, दलालों के माध्यम से किए गए कुल लेनदेनों के पांच प्रतिशत की सीमा लगा दी गई है।
- (iv) बैंकों से कहा गया है कि वे प्रतिभूति लेनदेन किए जाने के लिए पर्याप्त प्रणालियां तैयार करें ताकि जानकारीरामन समिति द्वारा बताये गये स्वरूप की अनियमितताएं फिर से न हों।
- (v) बैंक जिन प्रतिभूतियों का कारोबार आमतौर पर करते हैं, उन सभी के लिए एक केन्द्रीय निक्षेपागार स्थापित किया जायेगा। यह कार्रवाई सार्वजनिक क्षेत्र के बाण्डों और म्युचुअल फण्डों के यूनितों संबंधी नाडकर्णी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है।
- (vi) रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय निरीक्षणों के दौरान रिजर्व बैंक के प्रमुख और महत्वपूर्ण

अनुदेशों/निर्देशों के साथ-साथ अनुपालन संबंधी पहलू की भी जांच करेंगे और निर्धारित अंतराल पर बैंकों के अनुपालन, प्रमाणपत्रों की निगरानी भी करेंगे।

(vii) बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद और बंगलूर स्थित लोक ऋण कार्यालयों में सहायक सामान्य खाते (एस जी एल) के लेनदेनों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

(viii) सांविधिक लेखा परीक्षकों से अपेक्षित होगा कि वे वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के बाद इस बात का भी मत्यापन करें कि बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण अनुदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ix) सेवा नियुक्त वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए उन्हें कुछ बैंकों में हुई अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए विशेष अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

(x) रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को एक विस्तृत परिपत्र यह कहते हुए जारी किया गया कि वे अपने निवेश लेनदेनों को उपयुक्त रूप से विनियमित करें। वित्तीय संस्थाओं से यह कहा गया कि वे वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों की भावना का कड़ाई से पालन करें। इन संस्थाओं से यह भी कहा गया कि वे अपने-अपने निदेशक मण्डल के सम्मुख एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करें जिसमें उनकी संस्था में अपनायी जा रही नीतियों, कार्य-प्रणालियों आदि का ब्यौरा दिया गया हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेनदेनों संबंधी कार्यवाही का किया जाना और उनके हिसाब का रखा जाना सुस्पष्ट और सही ढंग से होता है।

(xi) अन्य उपायों में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेटलमेंट एण्ड डिपॉजिटरी (ई सी एस डी) का स्थापित किया जाना शामिल है। रिजर्व बैंक में एक दल गठित किया जायेगा जो स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बाण्डों और यूनिटों के कारोबार के क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित किये जाने के कार्य के प्रति मार्गदर्शन देगा और उसका समन्वय करेगा।

1.73 जिन बैंकों में गम्भीर अनियमितताएँ बरती गई थीं, और जिनके बारे में जानकारीरामन समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास

आपराधिक शिकायतें दर्ज कराए जाने के लिये कहा है और साथ ही साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ गलती करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिये कहा है।

1.74 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना का उल्लेख किया गया था जो अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच करेगी ताकि जिम्मेदारियाँ तय की जा सकें; साथ ही, समिति इस प्रणाली में भविष्य में सुधार लाये जाने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाएगी। इस संयुक्त संसदीय समिति ने सरकार, रिजर्व बैंक एवं बैंकों के पदाधिकारियों तथा दलालों सहित कई व्यक्तियों से पूछताछ की है। आशा है कि संयुक्त संसदीय समिति शीघ्र ही संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

II. वास्तविक अर्थव्यवस्था : कार्य निष्पादन और समस्याएं

1. समष्टि आर्थिक परिवृश्य

2.1 वर्ष 1992-93 के दौरान वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि में वर्ष 1991-92 के 1.2 प्रतिशत की अल्प वृद्धि से अनुमानित 4.2 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार हुआ (सारणी 2.1)। इस सुधार के बावजूद, वर्ष 1992-93 के दौरान हुई वृद्धि, अस्सी के दशक की 5.4 प्रतिशत वार्षिक और सातवीं योजना 1985-90 में 5.8 प्रतिशत वार्षिक की प्रवृत्ति दर के मुकाबले फिर भी कम है (परिशिष्ट सारणी II.1)। यह सुधार मुख्यतः कृषि क्षेत्र में किये गये ठोस कार्य निष्पादन के कारण संभव हुआ। पिछले वर्ष के 2.5 प्रतिशत तक की गिरावट की तुलना में 1992-93 के दौरान यह अनुमानित 5.1 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि निश्चित करती है। वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में हुई गिरावट के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष के 1.3 प्रतिशत की वृद्धि को एक सुधार ही माना गया; तथापि यह सुधार आशा से बहुत ही कम है।

सारणी : 2.1 समष्टि आर्थिक संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	1992-93*	1991-92	1990-91
1	2	3	4
1. वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर	4.2	1.2	5.2
2. सकल देशी बचत दर	22.5	23.8	23.7
3. कुल सकल निवेश दर	24.8	24.8	27.1
4. निवल देशी बचत दर	14.2	15.2	15.2
5. निवल कुल निवेश दर	16.6	16.3	19.1

*अग्रिम

टिप्पणी : सकल/निवल बचत और निवेश दरें सकल देशी उत्पाद/निवल देशी उत्पाद के संबंध में वर्तमान बाजार कीमतों के अनुपात हैं।

2.2 सकल देशी बचत की दर 1990-91 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 23.7 प्रतिशत थी जो 1991-92 में बढ़कर 23.8 प्रतिशत हो गयी, इसके बारे में अनुमान है कि देशी क्षेत्र की वित्तीय परिसंपत्तियों की बचत में तेजी से गिरावट आने के कारण 1991-92 के 9.1 प्रतिशत की तुलना में उसके 1992-93 में 7.7 प्रतिशत हो जाने से 1992-93 के दौरान, गिरकर यह दर 22.5 प्रतिशत तक हो जायेगी। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की सकल बचत दर वर्ष 1991-92 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 2.00 प्रतिशत हो जायेगी, जो सरकारी प्रशासन की सुधारी हुई बचत को परिलक्षित करता है।

साधणी : 2.2 क्षेत्र-वार सकल देशी बचत दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	1992-93*	1991-92*	1990-91*
1. घरेलू क्षेत्र	17.7	19.4	19.9
1.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7.7	9.1	8.6
1.2 भौतिक परिसंपत्तियाँ	10.0	10.3	11.3
2. सार्वजनिक क्षेत्र	2.0	1.7	1.1
3. निजी कंपनी क्षेत्र	2.8	2.7	2.7
कुल घरेलू बचत	22.5	23.8	23.7

*अनंतिम

निजी कंपनी क्षेत्र की सकल बचत दर 1991-92 के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 2.8 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है (सारणी 2.2)। विदेशी संसाधनों के निवल आगमन के 1992-93 में बढ़कर लगभग 2.2 प्रतिशत हो जाने की आशा है। यह वर्ष 1990-91 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3.5 प्रतिशत था जो वर्ष 1991-92 में तेजी से गिरकर 1.4 प्रतिशत रह गया। कुल सकल निवेश दर वर्ष 1992-93 में पिछले वर्ष की तरह 24.8 प्रतिशत होने का अनुमान है (सारणी 2.1 और परिशिष्ट सारणी II-2)।

2. उत्पादन—प्रवृत्तियाँ

कृषि

2.3 कृषि उत्पादन में वर्ष 1992-93 में 5.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर तीव्र सुधार की आशा है। वर्ष 1992-93 में कुल खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष 1991-92 के 167.1 मिलियन मीटरी टन के मुकाबले कहीं अधिक अर्थात् 180.3 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है जिसका मुख्य कारण है, मोटे अनाज और दालों का अधिक उत्पादन। वर्ष 1992 में खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन पिछले खरीफ मौसम से 91.4 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में उच्चतर अर्थात् 103.2 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है। यद्यपि यह निर्धारित लक्ष्य 103.3 मिलियन

मीटरी टन से काफी नीचे है। पिछले रबी मौसम के 75.6 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 78.0 मिलियन मीटरी टन रहा, परंतु निर्धारित लक्ष्य 79.7 मिलियन मीटरी टन से कम रहा (परिशिष्ट सारणी II.3)।

2.4 अन्य फसलों में, तिलहनों और कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 में तिलहन का उत्पाद पिछले वर्ष के 18.3 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन से 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए, वह 20.6 मिलियन मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया। कपास उत्पादन में वर्ष 1991-92 के 9.8 मिलियन गांठों में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि होकर वह 11.9 मिलियन गांठों के रिकार्ड स्तर का होने की आशा है। गन्ना और जूट और भेस्ता दोनों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम होगा (परिशिष्ट सारणी II.3)।

2.5 उच्चतर कृषि उत्पादन ने, न केवल अत्यावश्यक पण्यों की उपलब्धता में सुधार किया अपितु साथ ही मुद्रा-स्फीति की दर में गिरावट लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, निकासी और भण्डार

2.6 खाद्यान्न के उच्चतर उत्पादन और उन्हें लाभकारी कीमतों के दिये जाने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों ने वर्ष 1992-93 के दौरान अधिक खरीद की और वह वर्ष 1991-92 से 0.8 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 19.0 मिलियन मीटरी टन हो गयी। परंतु खाद्यान्नों की निकासी पिछले वर्ष के 19.2 मिलियन मीटरी टन की तुलना में घटकर 17.1 मिलियन मीटरी टन हो गयी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आंशिक रूप से कम आवंटित और अंशतः निम्नतर कीमतों के लिए विकल्प उपलब्ध होने के कारण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का भण्डार एक वर्ष पहले की (12.2 मिलियन मीटरी टन) तुलना में मार्च के अंत में 14.7 मिलियन मीटरी टन का उच्चतर भंडार रहा (परिशिष्ट सारणी II.4)। अच्छी फसल और सरकारी खरीद के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण 30 जुलाई 1993 तक रबी में गेहूँ की सरकारी खरीद 1993 में 12.8 मिलियन मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर रही। गेहूँ और चावल दोनों के भण्डार में महत्वपूर्ण सुधार होने के कारण, जून 1993 के अंत तक इनका भंडार निर्धारित मानदण्डों से अधिक रहा।

उद्योग

2.7 औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 1992-93 में माधारण पुनर्स्थान देखा गया, औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की अपरिर्वतित स्थिति की तुलना में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। उत्पादन में यह पुनर्स्थान रसायन और रसायनिक

उत्पाद, परिवहन उपकरण और कुछ कृषि आधारित उद्योगों में ठोस रूप से परिलक्षित हुआ। वर्ष 1992 के प्रारंभ में लिये गये विभिन्न नीतिगत उपायों ने औद्योगिक उत्पादन में चिरस्थायी सुधार के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे आयात दबाव उपायों में छूट, कंपनी क्षेत्र जिस कर प्रणाली का सामना कर रहा है उसमें टिकाऊ-पन और ऋण का अपेक्षाकृत आमानी से उपलब्ध होना।

2.8 वर्ष 1992-93 में वृद्धि की दर ग्रस्सी के दशक के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि दर (7.7 प्रतिशत) से और सातवीं योजना अवधि के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत से बहुत ही नीचे रही। कुछ धीमा पुनरुत्थान, आधारभूत उद्योगों के मंद कार्यानिष्पादन को ज्यादातर परिलक्षित करता है। पिछले वर्ष इसकी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत थी जबकि 1992-93 में यह 2.5 प्रतिशत रही। विनिर्माण क्षेत्र

2.9 विभिन्न क्षेत्रों के बीच, विनिर्माण क्षेत्र में विपरीत प्रवृत्ति देखी गयी, वर्ष 1991-92 में 1.5 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले वर्ष 1992-93 में 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गयी। वर्ष 1992-93 के दहाई स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र के अलग-अलग आंकड़े (परिशिष्ट सारणी 11.6) यह दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष में आठ औद्योगिक समूहों में (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 42.38 प्रतिशत भारांक) तीन औद्योगिक समूहों (17.08 प्रतिशत भारांक के साथ) की तुलना में त्वरित वृद्धि देखी गयी। पुनरुत्थान वाले प्रमुख औद्योगिक समूह हैं, खाद्य और खाद्य उत्पाद, रसायन और रसायनिक उत्पाद, परिवहन उपकरण, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, सूती वस्त्र उत्पाद, रबर, प्लास्टिक और पेट्रोलियम पदार्थ। वर्ष 1991-92 में आयातों पर लगाये गये प्रतिबंधों को वापस लिये जाने के कारण कुछ उद्योग समूहों का पुनरुत्थान देखा गया। रसायन जैसे कुछ उद्योग समूहों का पुनरुत्थान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे माल की कीमतों में गिरावट, अत्यधिक आने, कम ब्याज भार और निर्यातों को रुपये के निम्नगामी समायोजन से प्राप्त बढ़ावे के कारण हुआ। गैर-धात्विक खनिज उत्पाद में गिरावट देखी गई और आठ समूहों में (औ०उ०मु० 31.73 प्रतिशत भारांक) अंशतः कच्चे माल का अभाव और कम या मिश्रित मांग के कारण गिरावट देखी गयी।

आधारभूत उद्योग

2.10 वर्ष 1992-93 के दौरान आधारभूत उद्योग का कार्य निष्पादन धीमा रहा, पिछले वर्ष 6.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में इस वर्ष इसमें वृद्धि 2.5 प्रतिशत रही। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों में निम्नतर वृद्धि दर देखी गयी। विशेष रूप से क्रूड पेट्रोलियम उत्पाद में 11.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी (परिशिष्ट 11.7)।

2.11 पिछले वर्ष के बिजली उत्पादन के 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 1992-93 में 4.9 प्रतिशत

की अल्प वृद्धि देखी गयी, जिसका मुख्य कारण पन बिजली का निम्नतर उत्पादन है। पिछले वर्ष के कोयले के उत्पादन के 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 1992-93 में 3.9 प्रतिशत तक की तीव्र गिरावट का मुख्यतः कारण है, सिंगरेनी कोयलाखान कंपनी लिमिटेड के उत्पादन में रखे गये लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कमी आना। तथापि, वर्ष 1992-93 में कोयले का कुल लदान अधिक रहा और यद्यपि कोयले का कुल गर्तमुख भंडार इष्टतम भंडार स्तर से दुगुने से ज्यादा बढ़ा (लगभग 20 मिलियन मीटरी टन) सीमेंट और इस्पात उद्योगों पर मांग में मंदी के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा। बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में पिछले वर्ष में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में वृद्धि की 3.9 प्रतिशत दर देखी गयी। सीमेंट के उत्पादन में 1991-92 के 10.9 प्रतिशत की तुलना में 0.2 प्रतिशत की तीव्र गिरावट होने के कारण हैं—सरकारी निकासी में कटीती, सीमेंट की कीमतों और स्टॉक को बनाये रखने में गिरावट।

2.12 क्रूड पेट्रोलियम उत्पादन में निरंतर गिरावट आना एक गंभीर चिंता का विषय है। क्रूड पेट्रोलियम के उत्पादन में पिछले वर्ष के दौरान 8.1 प्रतिशत की गिरावट की तुलना, वर्ष 1992-93 के दौरान 11.2 प्रतिशत की सर्वाधिक गिरावट आयी। पर्याप्त तेल भंडार के बावजूदा क्रूड तेल उत्पादन में गिरावट आयी (उत्पादन की तुलना में भंडार का अनुपात हमारे देश में 26:1 है जबकि अमरीका में 10.1:1 और पश्चिमी यूरोप का 9.0:1 है)। इसका मुख्य कारण निवारक रखरखाव के लिए अप्रतटीय ढांचे को बंद रखना और पूर्वोत्तर में तेल उत्पादन में बाधा। तथापि, तेल उत्पादन में गिरावट आने के संगठनात्मक कारण भी हैं, जैसे तेल खोज क्षेत्र में कम निवेश और तेल के लिए ड्रिलिंग कार्य में धीमी गति और तेल कंपनियों द्वारा अतिरिक्त निवेश योग्य निधियां जुटाने का अभाव। तथापि पेट्रोलियम रिफाइनरी के उत्पादन में पिछले वर्ष के 0.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 4.0 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई।

III. सरकारी वित्त

वर्ष 1992-93 में केन्द्र सरकार की बजट संबंधी गतिविधियां

3.1 वर्ष 1991-92 के दौरान शुरू किया गया राज-कोषीय समायोजन वर्ष 1992-93 के दौरान जारी रखा गया और ऐसा करने हुए, सकल देशी उत्पाद से जुड़े केन्द्र सरकार के घाटे के प्रमुख तत्वों को ध्यान में रखते हुए, हाल ही के कुछ समय के दौरान ऊंचे पैमाने पर चल रहे उक्त घाटे में बराबर कमी लायी गयी (सारणी 3.1)। सकल राजकोषीय घाटे में कमी लाते हुए उसे समुचित स्तर तक ले आने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान विशिष्ट उपाय किये गये ताकि ग्रस्सी के दशक के बाद के वर्षों के दौरान खर्चों में वृद्धि के लगभग 16 प्रतिशत के औसतन स्तर से घटाकर लगभग 12 प्रतिशत पर सीमित रखा जा

सके तथा साथ ही ऋणोत्तर वित्त जुटाया जा सके। इसके फलस्वरूप, वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों में सकल राजकोषीय घाटे को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 5.22 प्रतिशत के बराबर रखा गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यही प्रतिशत 5.96 पर था और वर्ष 1990-91 में 8.41; अस्सी के दशक के बाद वाले पांच वर्षों के दौरान

सकल राजकोषीय घाटे और सकल देशी उत्पाद के बीच औसतन 8.22 प्रतिशत का अनुपात रहा। नवीनतम संकेत ये हैं कि सकल राजकोषीय घाटे और सकल देशी उत्पाद के बीच वर्ष 1992-93 के दौरान अनुपात 5.70 प्रतिशत का रहेगा जिसका कारण होगा आय का अनुमान से कम होना, विशेषतः वर्ष की अंतिम तिमाही में।

सारणी 3.1 : चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार के घाटे का परिकलन

(प्रतिशत)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	निवल राजकोषीय घाटा	निवल प्राथमिक घाटा	मुद्रांकन घाटा	परंपरागत घाटा	राजस्व घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1980-81 से 1984-85 (औसत)	6.26	3.73	2.99	2.21	1.19	1.11
1985-86 से 1989-90 (औसत)	8.22	3.40	3.80	2.29	2.07	2.58
1990-91	8.41	(5.70)\$	3.32	2.78	2.14	3.50
1991-92	5.96	4.05	1.47	0.90	1.12	2.67
1992-93 (सं०अ०)	5.22	3.70	0.85	0.77	1.02	2.38
	(5.70)			(0.61)@	(1.81)@	
1993-94 (ब०अ०)	4.71	3.43	0.44	0.55	0.55	2.25

सं०अ० : संशोधित अनुमान

ब०अ० : बजट अनुमान

नवीनतम अनुमान

रिजर्व बैंक के अधिलेखों के अनुसार वास्तविक

3.2 सकल राजकोषीय घाटे और सकल देशी उत्पाद के बीच अनुपात में कमी लाये जाने के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण (मुद्रांकन घाटे) और सकल देशी उत्पाद के बीच अनुपात में, वर्ष 1993-94 के बजट के अनुसार, वर्ष 1992-93 में और कमी लाते हुए उसे वर्ष 1991-92 के 0.90 प्रतिशत की तुलना में 0.77 प्रतिशत तक ले आया गया है, यही अनुपात अस्सी के दशक के बाद के पांच वर्षों में औसतन 2.29 प्रतिशत था। इसके फलस्वरूप, सकल राजकोषीय घाटे के मुद्रांकन को वर्ष 1992-93 (संशोधित अनुमान) में 15 प्रतिशत से नीचे स्तर तक सीमित रखा गया जबकि वर्ष 1991-92 में यह 15.2 प्रतिशत और वर्ष 1990-91 में 33 प्रतिशत रहा था, अस्सी के दशक के बाद के पांच वर्षों में सकल राजकोषीय घाटे का मुद्रांकन औसतन लगभग 28 प्रतिशत था। पिछले दो वर्षों के दौरान मुद्रांकन के स्तर में कमी, अन्य बातों के साथ-साथ, आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति की बढ़ती हुई सक्रियता के कारण आयी है। पिछले कुछ समय के दौरान, केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण की मात्रा का

स्तर ऊंचा रहने संबंधी जो प्रवृत्ति देखने में आ रही थी वह वर्ष 1992-93 के दौरान कुछ कम देखने में आई, हालांकि वर्ष के शुरू के महीनों के दौरान यह प्रवृत्ति वैसी ही ऊंची थी, फिर भी वर्ष के अन्त तक आते-आते इसमें तेजी से गिरावट आ गयी थी। इस बात को इस तथ्य से भी जाना जा सकता है कि प्रत्येक तिमाही के पाक्षिक औसत, समूचे वर्ष के औसत के इर्द-गिर्द ही बने रहे तथा यह कि समूचे वित्तीय वर्ष के पाक्षिक औसत और 31 मार्च 1993 के आंकड़े के बीच का अंतर, पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक कम था (सारणी 3.2)। केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक का औसत निवल ऋण 1992-93 की पहली तिमाही में 5,986 करोड़ रुपये था जो भारी वृद्धि लेते हुए, वर्ष 1993-94 की पहली तिमाही में 10,097 करोड़ रुपये हो गया (सारणी 3.2)। रिजर्व बैंक ने अपने संविभाग (पोर्टफोलियो) से दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्रियां पुनः खरीद करारों (रिपोम) के अंतर्गत की और यदि ये बिक्रियां नहीं की गयीं होतीं तो केन्द्र सरकार का उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण बेहद ऊंचे स्तर पर होता। इससे भी अधिक चिन्ता का विषय तो यह है कि

जुलाई 1993 में केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण, जुलाई 1992 के 8,249 करोड़ रुपये के साप्ताहिक औसत की तुलना में 17,404 करोड़ रुपये था।

सारणी : 3.2 : केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण का पाक्षिक औसत

(करोड़ रुपये में)

राजकोषीय वर्ष	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5
पहली तिमाही (अप्रैल-जून)	10,097	5,986	6,104	5,841
दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर)	17,019\$	7,264	10,454	8,185
तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर)		7,016	11,865	11,938
चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)		7,087	13,606	15,130
31 मार्च		4,257	5,508	14,746
राजकोषीय वर्ष औसत*		6,718	10,209	10,337

*यह केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण के सभी पाक्षिक आंकड़ों का औसत और सरकारी खातों के बंद होने के बाद 31 मार्च का आंकड़ा है।

\$ 20 अगस्त 1992 तक

3.3 राजस्व घाटे की 16,700 रुपये का संशोधित अनुमान 2,818 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से आगे निकल गया। इस स्थिति के बिगड़ने के पीछे प्रमुख कारण थे: राजस्व-प्राप्तियों और सकल देशी उत्पाद के बीच के अनुपात में लगभग ठहराव आ जाना, व्याज-अदायगियों में वृद्धि (500 करोड़ रुपये की) आर्थिक सहायता में वृद्धि (1,621 करोड़ रुपये की), पेंशन भुगतानों में वृद्धि (305 करोड़ रुपये की), प्रतिभूतियों से संबंधित खर्च 285 करोड़ रुपये की ओर साथ ही, पंचवर्षीय योजना के प्रयोजनों के लिए बढ़े हुए प्रावधान (2,181 करोड़ रुपये)। व्याज भुगतानों में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण थे 364 दिवसीय खजाना बिलों का भुनाया जाना। यह एक ऐसी लिखत थी जिसके अन्तर्गत 1992-93 में संसाधनों का बड़े पैमाने पर लेनदेन हुआ, तथा विनिमय दर समायोजन के कारण विदेशी कर्ज चुकौती पर और अधिक लागत आना। जहां तक आर्थिक सहायता का संबंध है, उच्चतर वसूली मूल्यों के झटके को झेलने के लिए निर्गम मूल्यों के बढ़ाये जाने में विलम्ब के फलस्वरूप खाद्यान्न संबंधी सहायता की राशि 300 करोड़ रुपये की आबंटित राशि से आगे निकल गयी। उर्वरक संबंधी सहायता में 800 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसका प्रभाव यूरिया के मूल्य में कमी तथा उच्चतर निवेश लागतों में नजर आया। इसके अलावा, 340 करोड़ रुपये

की एकमुश्त सहायता किसानों को फॉस्फेट और पोटाश के उर्वरक खरीदने के लिए दी गयी जिनके मूल्यों पर से अगस्त 1992 में नियंत्रण हटा लिया गया था। फिर भी उर्वरक हमदाद के मामले में यह सुनिश्चित करने की समस्या है कि विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बीच की मूल्य सापेक्षताएं उर्वरकों के प्रयोग के इष्टतम मिश्रण में बाधक नहीं बनतीं। निर्यात सहायता के लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान नकद प्रतिपूर्ति सहायता संबंधी विचाराधीन दावों के निपटारे तथा संभावित निर्यातों पर लाभ बनाये रखने के लिए किया गया था। पेंशन भुगतानों में वृद्धि रक्षा-पेंशनभोगियों को दी गयी तदर्थ एकमुश्त वृद्धि के कारण हुई थी। प्रमुखतः इन्हीं खर्चों के फलस्वरूप राजस्व घाटा सकल राजकोषीय घाटे के एक बड़े अंश के रूप में सामने आया जबकि अस्सी के दशक में यह प्रवृत्ति नहीं पायी जाती थी (सारणी 3.3)।

सारणी 3.3 : सकल राजकोषीय घाटे का विश्लेषण

(प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व घाटा	पूँजीगत लागत	निवल उधार	विनिवेश	सकल राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5	6
					(2+3+4+5)
1980-81 से 1984-85 (औसत)	17.0	42.3	40.7	--	100.0
1985-86 से 1989-90 (औसत)	31.5	34.2	34.3	--	100.0
1990-91	41.6	27.2	31.2	--	100.0
1991-92	44.8	31.4	32.2	8.4	100.0
1992-93 (मं०अ०)	45.5	34.9	29.1	9.5	100.0
1993-94 (ब०अ०)	47.7	34.7	27.1	9.5	100.0

मं०अ०—संशोधित अनुमान

ब०अ०—बजट अनुमान

3.4 एक चिन्ता का विषय वर्ष के अन्त का उच्च बजट घाटा रहा जो भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार 12,757 करोड़ रुपये था; यह घाटा 5,389 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के दुगने से अधिक तो था ही, यह 7,202 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से भी कहीं अधिक था। राजकोषीय वर्ष का औसत भी 11,811 करोड़ रुपये के ऊंचे अंक को छू गया। वर्ष 1993-94 की पहली तिमाही में यह औसत 10,056 करोड़ रुपये पर था (सारणी 3.4)। जुलाई 1993 में, बजट घाटे ने जुलाई 1992 के 14,213 करोड़ रुपये के साप्ताहिक औसत की तुलना में 20,909 करोड़ रुपये का भारी उछाल लिया। संकेत तो ये मिल रहे हैं कि 1992-93 में सकल राजकोषीय घाटे और सकल देशी उत्पाद के

बीच का अनुपात 5.22 प्रतिशत के संशोधित अनुमानों की तुलना में अन्ततः और बढ़ेगा और यह लगभग 5.9 प्रतिशत तक जा सकता है। निवल उधार को देखते हुए निवल प्राथमिक घाटे, जिसकी परिभाषा निवल राजकोपीय घाटे में से निवल ब्याज भुगतानों को घटाकर निकालने वाली राशि के रूप में की गयी है (बॉक्स II देखें) में भी वृद्धि होगी और यह राशि सकल देशी उत्पाद के 0.85 प्रतिशत के संशोधित अनुमानों के मुकाबले उच्चतर होगी।

सारणी 3.4 : भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार बजट घाटे का केन्द्र सरकार का पाक्षिक औसत

(करोड़ रुपये में)

राजकोपीय वर्ष	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5
पहली तिमाही (अप्रैल-जून)	10,056	8,082	7,337	6,187
दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर)	21,065†	13,157	12,137	10,068
तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर)		11,835	13,622	12,803
चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)		14,647	14,114	14,554
31 मार्च		12,757	6,492	11,490
राजकोपीय वर्ष औसत*		11,811	11,508	10,818

*यह केन्द्र सरकार के बजट घाटे के सर्वा पखवाइयें तथा 31 मार्च तक सरकारी खातों के बन्द होने के बाद के आंकड़े का औसत है।

†20 अगस्त 1993 तक।

बॉक्स-II

प्राथमिक घाटा

सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे की मात्र विधियों में जिस एक विधि को हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण समझा गया है वह है प्राथमिक घाटा। यह संकल्पना, जिसे गैर-ब्याज घाटे के रूप में भी जाना जाता है, सरकारी बजट की विवेकसम्मत नीति के प्रभाव को मापने में काम आती है और इसका उपयोग सरकारी घाटों के औचित्य के मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है।

जिस सकल राजकोपीय घाटे में खर्च के खाते में निवला उधार शामिल होते हैं, आमतौर पर उसका प्रयोग किया जाता है और उसे सकल राजकोपीय घाटा कहा जाता है।

जो प्राथमिक घाटा सकल राजकोपीय घाटे में निकल कर आता है इसके बारे में एक जैसी धारणा नहीं है। एक धारणा यह है कि प्राथमिक घाटा सकल राजकोपीय घाटे में से सरकारों के ब्याज भुगतानों को निकाल कर होना चाहिए। एक अन्य धारणा यह है कि यह निवल ब्याज भुगतानों को निकालने के बाद सकल राजकोपीय घाटे के समान है। जिस राजकोपीय घाटे में सरकार के निवल उधार (जिसकी परिभाषा सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों में से ऋणों की वसूलियों की राशि निकाल देने के बाद की राशि के रूप में की गई है) शामिल नहीं होते उसे निवल राजकोपीय घाटे के रूप में जाना जाता है। जब निवल राजकोपीय घाटे से निवल ब्याज भुगतान (ब्याज भुगतान घटा ब्याज प्राप्तियां) को घटाने के बाद जो बचा रहता है वह निवल प्राथमिक घाटा कहलाता है। यह एक ऐसी संकल्पना है जो ऋण की सकल देशी उत्पाद अनुपात की तुलना में ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत है।

संदर्भ :—वर्ल्ड बैंक (1988) वर्ल्ड डेवेलपमेंट रिपोर्ट, पृ० 56,

मारियो I ब्वेजर एण्ड ग्रॉडियाने चीम्टी (1991), 'दि मेजरमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स—एनलिटिकल एण्ड मैथोडोलोजिकल इश्यूज', जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, दिसम्बर

केन्द्र सरकार का बजट : 1993-94

3.5 एक परिष्कृत व्यापक आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में तैयार किये गये 1993-94 के बजट में जहां विन्यास संबंधी चल रहे समायोजन की रफ्तार को और तेज किया जाना जारी रखा गया, वहीं इसमें प्रगति पर बल दिये जाने संबंधी प्रयासों को भी स्थान दिया गया। तदनुसार, बजट में और अधिक सुदृढ़ औद्योगिक चेतना तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी कई उपायों को स्थान दिया गया। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के सुधार, निर्यात संवर्धन एवं वित्तिय दूर के प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण उपाय घोषित किये गये। केन्द्र सरकार का, करों और शुल्कों की 1992-93 की दरों पर परिकल्पित बजट घाटा, 1993-94 में 333 करोड़ रुपये आंका गया है। बजट में घोषित करों और शुल्कों में दी गयी रियायतों के कारण होने वाले 4,522 करोड़ रुपये के घाटे को हिमाव में लेने के बाद, जिसमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 3,981 करोड़ रुपये होगा। बजट घाटा 4,314 करोड़* रुपये होने का अनुमान लगाया गया। बजट में यह भी कहा गया कि राजस्व घाटे तथा सकल राजकोपीय घाटे में गिरावट सकल देशी उत्पाद के अंशों के रूप में आपूर्ति (सारणी 3.1 एवं परिशिष्ट सारणी 3.1 एवं 3.5)

*बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद, वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों में कुछ और संशोधनों/परिवर्तनों की घोषणा 1 मई, 1993 को की, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, वैयक्तिक आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाना तथा कुछ विशिष्ट सर्वोपरि आयों एवं आयकारी शुल्क में कमी किया जाना शामिल है। आशा है कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार को निम्न राजस्व की 125 करोड़ रुपये की और 25 राज्यों को 304 करोड़ रुपये की हानि होगी।

3.6 वजट के अनुसार, राजकोषीय स्थिति को अनिवार्यतः सही करना होगा और इसके लिए गैर योजनागत व्यय के ब्याजितर घटकों में कमी लानी होगी तथा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी ईक्विटी धारिताओं का निवेश वापस लेना होगा। अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ, जिन विशिष्ट क्षेत्रों में खर्च में कमी लायी जा सकती है, वे हैं वर्ष 1993-94 में जो भी अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देय हो, उसके भुगतान के लिये कोई प्रावधान न किया जाए, कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना—1990 के अन्तर्गत बैंकों को किये जाने वाले भुगतानों में पर्याप्त कटौती को जाए, उर्वरक और निर्यात सहायता में विशिष्ट कटौतियां भी जाएं तथा राज्यों को दिये जाने वाले गैर योजनागत अनुदानों में कमी लाई जाए।

3.7 वर्ष 1993-94 के वजट में ध्यान देने योग्य एक पहलू यह है कि इसमें योजनागत व्यय में 4278 करोड़ रुपये (11.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जिसमें से 3607 करोड़ रुपये (18.4 प्रतिशत) केन्द्र सरकार के योजना परिव्यय के कारण होगा और शेष 671 करोड़ रुपये (3.9 प्रतिशत) राज्यों और मध्य राज्य क्षेत्रों की योजनाओं की सहायता राशि के रूप में दिये जाएंगे। राजकोषीय बाधाओं के कम होने और सुद्रास्फीति में तन्मी आ जाने के फलस्वरूप पर्याप्त रूप से उच्चतर योजना-परिव्यय की व्यवस्था करने में केन्द्र सरकार की मदद मिली है। योजना-परिव्यय के लिए वजट सहायता को निम्नतर स्तर पर (18.4 प्रतिशत) रखा गया है, जो केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वजट के आंतरिक और बाह्य संसाधनों को बढ़ाकर दी गई 35.3 प्रतिशत की सहायता से कम ही है।

राज्यों के वजट परिचालन: 1993-94

3.8 वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों* के समेकित वजट परिचालनों में आंतरिक असंतुलन देखने में आते रहे, जैसा कि प्रमुख घाटा-संकेतकों, (अर्थात् समग्र परम्परागत घाटा, राजस्व घाटा और सकल राजस्व घाटा) से सिद्ध होता है। कुल 3,128 करोड़ रुपये (कराधान की 1992-93 की दरों पर) परिकल्पित यह समग्र परम्परागत घाटा 1992-93 की स्थिति (1,256 करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है। तरह राज्यों द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी उपायों से मिलने वाले 1,030 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकार के वजट में नए कर प्रस्तावों से राज्यों के हिस्से के रूप में 542 करोड़ रुपये** की राजस्व हानि के समायोजन के बाद भी लगभग 2,640 करोड़ रुपये का समग्र अंतराल बना रहेगा।

वर्ष 1993-94 के दौरान राजस्व खाने में होने वाला घाटा पिछले वर्ष के 4,117 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे की तुलना में बढ़कर 4,524 करोड़ रुपये हो जायेगा। राजस्व खाने की जो स्थिति 1987-88 से बराबर देखने में आ रही है उसके फलस्वरूप राज्यों का सकल राजकोषीय

घाटा 1987-88 के 11,219 करोड़ रुपये से बढ़कर 1993-94 में अनुमानित: 23,707 करोड़ रुपये हो जायेगा।

3.9 राजस्व घाटे के निरन्तर बने रहने का परिणाम यह हुआ है कि पूंजीगत परिव्यय और निवल उधार के लिए उपलब्ध संसाधन कम होते चले गए हैं, जैसा कि सकल राजकोषीय घाटे के विश्लेषण में जाहिर है (सारणी 3.5)। इसके अलावा राज्यों के बढ़ते हुए सकल राजकोषीय घाटे के फलस्वरूप राज्यों के वकाया कर्ज में भी वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप वजट में दर्शाए अनुसार सभी राज्यों के वकाया कर्ज, मार्च 1994 के अंत में 1,58,144 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँच जाएंगे, जबकि मार्च 1993 के अंत में ये कर्ज 1,40,079 करोड़ रुपये थे (परिशिष्ट सारणी 3.7)। कर्ज के इस ऊँचे स्तर की वजह से राज्यों पर ब्याज का भार बढ़ा है जिसके फलस्वरूप अपनी राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा अंश अलग से बचाकर रखना जरूरी है। सकल ब्याज भुगतानों और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अनुपात 1992-93 के 14.7 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 के दौरान 16.0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। 80 के दशक के दौरान यह अनुपात औसतन केवल 9.6 प्रतिशत रहा था। कर-रहित राजस्व में ठहराव तथा ब्याज-रहित राजस्व व्यय के सकल देशी उत्पाद के अनुपातों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण प्राथमिक राजस्व अधिशेष (अर्थात् राजस्व घाटा, निवल ब्याज भुगतान घटाकर) ठहराव सा आया है। इसके फलस्वरूप, प्राथमिक राजस्व अधिशेष में से निवल राजस्व भुगतानों का वित्त-पोषण 1993-94 में केवल 62.2 प्रतिशत हो पाने की आशा है, जबकि 80 के दशक के बाद के पांच वर्षों में यह 77 प्रतिशत रहा था।

सारणी 35 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का विश्लेषण

(प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार	जोड़
1	2	3	4	5
1980-81 से 1984-85 (औसत)				
1985-86 से 1989-90 (औसत)				
1990-91				
1991-92				
1992-93 (सं०अ०)				
1993-94 (सं०अ०)				
(1990-91 से 1993-94 तक का औसत)				

*अधिशेष दर्शाता है।

*समेकित वजट परिचालन 25 राज्यों से सम्बन्धित है, जिनमें से 11 राज्यों के वजट लेखा अनुदान वजट पर निर्भर है।

**दिनांक 1 मई 1993 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित वजट के बाद की कर रियायतों से होने वाली 20.4 करोड़ की राजस्व हानि में राज्यों के हिस्से को छोड़कर।

3.10 जैसा कि 1993-94 के दौरान बजट प्रावधान किया गया, गैर-विकासात्मक व्यय में तेजी से उछाल आयेगा, जो 1992-93 के दौरान के कुल संवितरण 26.7 प्रतिशत (32,729 करोड़ रुपये) की तुलना में 29.3 प्रतिशत हो जायेगा। गैर-विकासात्मक व्यय पर होने वाले संवितरणों में वृद्धि, विशेषतया व्याज भुगतानों, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशनों पर होने वाले व्यय के मुकाबले राज्यों द्वारा अपने संसाधन जुटाने संबंधी प्रयासों में विगत वर्षों में कोई अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। यह बात राज्यों के अपने समग्र घाटे से साबित हो जाती है (यह घाटा केन्द्र द्वारा राज्यों को अंतरित संसाधनों में से निकाले गए राज्यों के बजट परिचालनों में संसाधन अंतर और राज्यों द्वारा केन्द्र को की गई ऋण चुकौतियों और व्याज भुगतानों का छोटक है) जो 1980-81 से सकल देशी उत्पाद के लगभग 6 प्रतिशत पर ठहरा हुआ है।

3.11 राज्यों के कुल संसाधन अंतराल (सकल राजकोषीय घाटा) का वित्त-पोषण संबंधी ढांचा यह दर्शाता है कि इस अंतराल के लगभग 43 प्रतिशत का वित्त-पोषण अनुमानतः केन्द्र सरकार से ऋण लेकर किया जाना है; यह वित्त-पोषण 1992-93 के दौरान 46 प्रतिशत था और 80 के दशक के दौरान औसतन 53 प्रतिशत रहा था।

3.12 केन्द्र सरकार से राज्यों को 1993-94 के दौरान कुल प्राप्तियों के एक हिस्से के रूप में मिलने वाला संसाधनों का निवल अंश कुल प्राप्तियों के लगभग 34 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है; यह अंश 1992-93 में 35 प्रतिशत था। 80 के दशक के दौरान भी यह हिस्सा औसतन लगभग 34 प्रतिशत रहा था। केन्द्र सरकार की वित्त-पोषण संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए, राज्यों को एक बड़े पैमाने पर पर्याप्त प्राथमिक राजस्व अधिशेष चालू खर्च में कमी करते हुए और कर आदि दरों और उनके आधार में परिवर्तन लाते हुए राज्य में बढ़ोतरी करके और निधि के पुनर्विनियोजन द्वारा करनी होगी।

राज्यों के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट

3.13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 23 राज्यों को मिलने वाली रिजर्व बैंक की सामान्य और विशेष अर्थोपाय सीमाएं क्रमशः 744.8 करोड़ रुपये, 266.0 करोड़ रुपये पर बनी रहीं। यह नियम कि ओवरड्राफ्टों की चुकौती अधिकतम 7 क्रमिक कार्य दिवसों के भीतर हो जानी चाहिये, ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम 1985 के अनुसार लागू बना रहा। 1992-93 के दौरान छह राज्य ऐसे थे जो उपर्युक्त नियम का पालन 11 विभिन्न अवसरों पर नहीं कर सके। अतः, रिजर्व बैंक को इन राज्य सरकारों की ओर से उक्त 11 अवसरों पर भुगतानों को रोकना पड़ा। इसके ठीक विपरीत 1991-92 के दौरान, सभी राज्यों ने, ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम का पालन किया।

केन्द्र और राज्यों की संयुक्त बजट स्थिति

3.14 केन्द्र सरकार और राज्यों की संयुक्त राजकोषीय स्थिति दर्शाने वाले, सकल राजकोषीय घाटा परम्परागत घाटा और राजस्व घाटा नामक तीनों प्रमुख घाटा-संकेतकों में पायी गयी प्रवृत्तियां यह बताती हैं कि अस्मी के दशक के आखरी वर्षों में सकल राजकोषीय घाटे और सकल देशी उत्पाद के अनुपात के जो स्तर थे उनमें हाल के वर्षों में स्पष्ट तौर पर कमी आने के बावजूद, राजस्व खाते में पाया जाने वाला बड़ा अंतर मोटे तौर पर अभी भी वैसा ही बना हुआ है (सारणी 3.6)।

सारणी 3.6 सकल देशी उत्पादन के समानुपात के रूप में केन्द्र और राज्य सरकारों के घाटे के मापदण्ड

(प्रतिशत)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	परम्परागत घाटा	राजस्व घाटा
1985-86 से 1989-90 (औसत)	9.5	2.2	2.8
1990-91	10.1	2.1	4.5
1991-92	7.5	1.1	3.6
1992-93 (सं०अ०)	6.8	1.2	3.0
1993-94 (ब०अ०)	6.7	0.9	2.8

*अंतर सरकारी लेनदेनों को घटाकर

**केन्द्र और राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे में से, केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये निवल उधार घटाकर।

सं०अ०—तथोक्ति अनुमान।

ब०अ०—बजट अनुमान।

3.15 बजट में किए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 1992-93 में संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा सकल देशी उत्पाद का 6.8 प्रतिशत रहेगा, जबकि 1991-92 में यह 7.5 प्रतिशत था और 80 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान यह घाटा औसतन 9.5 प्रतिशत रहा था। यदि नवीनतम संकेतकों को लेकर चलें तो वास्तविक प्रतिफल सारणी 3.6 में प्रस्तुत अनुमान की अपेक्षा लगभग 0.47 प्रतिशत अंक उच्चतर रहेगा। वर्ष 1992-93 में सकल देशी उत्पाद का 3.0 प्रतिशत का संयुक्त राजस्व घाटे का आंकड़ा वर्ष 1985-86 से 1989-90 की अवधि के दौरान के औसतन 2.8 प्रतिशत के आंकड़े की तुलना में ऊंचा है, लेकिन यहां भी लगता था कि कहीं कुछ छूट गया है। राजस्व घाटा सरकारी वित्त पोषणों में पाई जाने वाली अस्तनिहित समस्या को प्रतिबिम्बित करता है, अर्थात् सकल देशी उत्पाद के समानुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों और खर्चों में लगभग अपरिवर्तनीयता रही, जो वर्ष 1992-93 में क्रमशः 21 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के आसपास रखी गई है—अस्मी के दशक के उत्तरार्ध के औसत के समान रही।

राजस्व व्यय के विकासार्थक घटक के हिस्से को प्रस्ती के दशक के अंतिम वर्षों के 55 प्रतिशत की तुलना में घटाकर वर्ष 1992-93 में 52 प्रतिशत करने से यह समस्या और बड़ गई है।

3.16 वर्ष 1993-94 के बजट अनुमान में सकल देशी उत्पाद के समानुपात सकल राजकोपीय घाटे, राजस्व घाटे और परम्परागत घाटे में कटौती दर्शाई गई है। बाजार से लिए गए उधार: केन्द्र सरकार

3.17 केन्द्र सरकार ने सकल राजकोपीय घाटे के प्रति चिन्तित होते हुए 1991-92 के बाद से बाजार से उधार लिए जाने वाले अपने कार्यक्रम में निरन्तर कमी की है। इसके फलस्वरूप, वर्ष 1991-92 में बाजार से लिए गए 7,501 करोड़ रुपए के निवल उधारों की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे उधारों की 3,670 करोड़ रुपये के निम्न स्तर पर सीमित रखा गया है, जबकि सकल बाजार उधार, वर्ष 1991-92 के 8,919 करोड़ रुपये के मुकाबले 4,821 करोड़ रुपये तक सीमित रखे गए (परिशिष्ट सारणी III.11) बाजार से सम्बन्धित लेनदेनों के प्रति रख किए जाने संबंधी कार्यनीति के एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार की तरफ से पहली बार 1992-93 में दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी का काम हाथ में लिया। नीलामियों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों पर होने वाली अधिकतम आय 5-वर्षीय प्रतिभूति के लिए 12 प्रतिशत और 10-वर्षीय प्रतिभूति के लिए 12.75 प्रतिशत के बीच रही (परिशिष्ट सारणी III.12)। यद्यपि, आरम्भ में रिजर्व बैंक ने कुल प्राप्तियों के 2/5वें हिस्से से कुछ अधिक का अभिदान किया, फिर भी इन प्रतिभूतियों का अधिकांश भाग 1992-93 के दौरान बाजार में बेचा गया।

3.18 वर्ष 1993-94 के बजट अनुमानों में बाजार से लिए जाने वाले केन्द्र सरकार के सकल और निवल उधार क्रमशः 4,848 करोड़ रुपये और 3,700 करोड़ रुपये पर आकलित किए गए, जो वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों से कुछ ही अधिक थे।

3.19 राजकोपीय वर्ष 1993-94 के दौरान (जुलाई के अन्त तक) केन्द्र सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों की अब तक तीन नीलामियाँ 3 जून, 15 जून और 27 जुलाई 1993 को करके 3,000 करोड़ रुपए जटाए हैं। पांच-वर्षीय, नौ वर्षीय और सात-वर्षीय प्रतिभूतियों के लिए अधिकतम आय क्रमशः 13.00 प्रतिशत, 13.40 प्रतिशत और 13.25 प्रतिशत हुई थी।

राज्य सरकारें

3.20 भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा बाजार से कुल 3,471 करोड़ रुपए के निवल उधार लिए गए।

राज्य सरकार ऋणों पर 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए कूपन दर 13.00 प्रतिशत निर्धारित की गई है, इसकी तुलना में, वर्ष 1991-92 के दौरान बाजार से लिए गए उधारों की निवल राशि कुल मिलाकर 3,364 करोड़ रुपये थी।

3.21 भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार, राजकोपीय वर्ष 1993-94 के दौरान (जुलाई 1993 के अंत तक) राज्य सरकारों ने 13.50 प्रतिशत की कूपन दर वाले 10 वर्षीय ऋण जारी किये हैं जिनका पहला हिस्सा 18 मई 1993 को जारी किया गया और उससे उन्होंने 1748 करोड़ रुपये जुटाये। 12 जुलाई 1993 को किये गये दूसरे हिस्से से उन्होंने 2,006 करोड़ रुपये की राशि जुटाई।

स्वर्ण बांड स्कीम, 1993

3.22 स्वर्ण बांड स्कीम, 1993 सार्वजनिक अभिदान के लिए 15 मार्च 1993 को आरंभ की गयी तथा 14 जून 1993 को इसे बंद कर दिया गया। इस अवधि के दौरान इस स्कीम के जरिये 41.12 मीटरी टन सोना जुटाया गया। स्वर्ण की यह मात्रा उस मात्रा से कहीं अधिक है जिसका अनुमान इस स्कीम के अंतर्गत लगाया गया था। देशी बाजार मूल्य (29 जून, 1993 के दिन) पर इसका मूल्य लगभग 1,807 करोड़ रुपये (अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर 1,558 करोड़ रुपये) आका गया है। केन्द्र सरकार के वर्ष 1993-94 के बजट में यह संभावना है कि इस योजना अंतर्गत केवल 300 करोड़ रुपये मूल्य का स्वर्ण (जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर लगभग 8 मीटरी टन के बराबर बैठगा) जुटाया जा सकेगा।

IV. मुद्रा और मूल्य प्रवृत्तियाँ

मौद्रिक और बैंकिंग प्रवृत्तियाँ

4.1 वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान मुद्रा का विस्तार पिछले वर्ष में दर्ज की गई असाधारण वृद्धि की तुलना में काफी कम था। केन्द्र को निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण में परिकल्पित वृद्धि से कम वृद्धि और भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में साधारण वृद्धि ने आर्णक्षत मुद्रा की वृद्धि की दर को संयत किया जिसके कारण 1992-93 के दौरान व्यापक मुद्रा में गिरावट आयी। जनता के पास की मुद्रा और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमा राशियाँ दोनों में मंद गति से वृद्धि हुई। मियादी जमा राशियों में वृद्धि अधिक थी जो इस बात का संकेत है कि बचत के अन्य माध्यमों के बजाय इस साधन को अधिक पसंद किया गया, इसका आंशिक कारण यह भी था कि प्रतिभूति लेनदेन में अनियमितताओं के कारण अस्थिरता थी। सकल देशी उत्पाद से संबंधित राजकोपीय घाटे को स्थिर रखने के साथ ही मुद्रा विस्तार में संयमन रहा और सपदा क्षेत्र के मुधरे हुए कार्यनिष्पादन ने 1992-93 के दौरान मुद्रास्फीति की दर में उल्लेखनीय गिरावट लायी।

मौद्रिक गतिविधियां

4.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को उनकी वास्तविक ऋण आवश्यकताओं से वंचित किये बिना मुद्रा विस्तार की दर को सीमित कर मुद्रा नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता था। एम 3 और एम 1 दोनों ने गिरावट में वृद्धि दिखायी (सारणी 4.1)। तदनुसार, एम 3 का विस्तार वर्ष के दौरान 14.2 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष के 19.4 प्रतिशत विस्तार की दर से कम था (परिशिष्ट सारणी-4.1) और 1980-81 से 1990-91 तक के दशक में औसत वृद्धि की दर करीबन 17 प्रतिशत थी।

4.3 1992-93 में संकीर्ण मुद्रा एम 1 का विस्तार (8,440 करोड़ रुपये या 7.3 प्रतिशत) वस्तुतः न केवल 1991-92 की तुलना में (21,946 करोड़ रुपये या 23.6 प्रतिशत) कम था बल्कि पिछले ग्यारह वर्षों की तुलना में भी सबसे कम था। जनता के पास मुद्रा और मांग जमा-

राशियां दोनों मंद गति से बढ़ीं। जनता के पास की मुद्रा में पिछले वर्ष के 15.2 प्रतिशत की तुलना में 1992-93 में 12.1 प्रतिशत का अधिक विस्तार हुआ। मांग जमा-राशियों में पिछले वर्ष के 34.9 प्रतिशत की तुलना में काफी कम 0.8 प्रतिशत का विस्तार हुआ। मीयादी जमा-राशियों में 1991-92 के 17.2 प्रतिशत के बदले 18.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा-राशियां भी पिछले वर्ष के 211 करोड़ रुपये से बढ़कर 618 करोड़ हो गईं। वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान सूचना देने के लिए नियत गुरुवारों को इन जमा-राशियों में वृद्धि हुई क्योंकि वित्तीय संस्थाओं ने प्रतिभूतियों के तैयार बायदा लेनदेनों पर कड़ प्रतिबंध होने से निधियों की मांग कम होने के कारण अपनी निधियों को रिजर्व बैंक के पास रखा। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद नीलामी प्रारंभ होने के पश्चात वर्ष की अंतिम तिमाही में इसमें सुधार हुआ।

सारणी 4.1 : व्यापक मुद्रा (एम 3) में घटबढ़ : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये में)

	1992-93	1991-92	अग्रिम-जून	
			1993-94	1992-93
1	2	3	4	5
संकीर्ण मुद्रा एम 1	8,440 (7.3)	21,946 (23.6)	8,347 (6.8)	7,051 (6.1)
व्यापक मुद्रा एम 3	45,181 (14.2)	51,653 (19.4)	13,391 (5.1)	19,152 (6.1)
जनता के पास मुद्रा	7,414 (12.1)	8,050 (15.2)	6,088 (8.9)	2,763 (4.5)
कुल जमा-राशियां	37,152	43,392	9,171	11,690
जिसमें से विदेशी मुद्रा	(14.5)	(20.5)	(3.1)	(4.6)
जमा-राशियां *	5,843 (20.7)	5,632 (24.8)	1,124 (3.3)	5,069 (17.9)
1. सभी विदेशी मुद्रा जमा-राशियां	5,061 (24.8)	4,824 (30.9)	499 (2.0)	4,291 (21.0)
2. अन्निवासी (विदेशी)	782 (10.0)	808 (11.5)	625 (7.3)	778 (9.9)
मांग जमा-राशियां	408 (0.8)	13,685 (34.9)	-- 873 (-- 1.6)	-- 711 (-- 1.3)
मीयादी जमा-राशियां	36,744 (18.1)	29,707 (17.2)	10,044 (4.2)	12,40 (6.1)
सरकार को निवल बैंक ऋण	17,826 (11.3)	18,070 (12.9)	13,654 (7.8)	6,442 (4.1)
सरकार को भारी बैंक का निवल ऋण	4,423 (4.7)	5,168 (5.8)	7,303 (7.4)	2,320 (2.5)
जिसमें से केन्द्र बैंक	4,257 (4.6)	5,508 (6.3)	9,201 (9.5)	3,913 (4.2)

1	2	3	4	5
वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	28,380	16,225	3,916	8,811
निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	(15.1)	(9.4)	(1.8)	(4.7)
बैंकिंग क्षेत्र की निवल	3,809	11,291	1,681	84.9
	(17.4)	(106.7)	(6.5)	(3.9)
मुद्रांतर देयताएं	4,925	--5,984	875	-3,319
	(9.4)	(--10.3)	(1.5)	(--6.3)
भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्रांतर देयताएं	641	393	--270	-2,205
	(2.3)	(1.5)	(--1.0)	(-8.0)

टिप्पणी :--कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में घटबढ़ दर्शाते हैं ।

अ--अनंतिम

--*केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित ।

4.4 स्त्रोतों की ओर देखें तो, सरकार के निवल बैंक ऋण की वृद्धि में दूसरे क्रमिक वर्ष में गिरावट आयी । केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण विस्तार, जो मुद्राकृत घाटे को नियंत्रित करता है, 1990-91 में 14,745 करोड़ रुपये (20.5 प्रतिशत) और 1991-92 में 5,508 करोड़ रुपये (6.3 प्रतिशत) की तुलना में 1992-93 में 4,257 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत) पर स्थित था । वर्ष में वास्तविक उत्पादन उच्चतम सीमा से न्यूनतर था (सारणी 4.2) ।

4.5 सरकारी क्षेत्र के ऋणों में जहां कमी आयी वहीं वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों के ऋणों में बढ़ि हुई । ऐसा इसलिए हुआ कि रिजर्व बैंक ने उद्योग तथा कृषि के लिए समाधानों में वृद्धि कर दी, सांविधिक चलनिधि अनुपात को घटा दिया, वृद्धिशील आरक्षित नकदी अनुपात हटा लिया और बैंकों को रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता में बढ़ि कर दी । वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋण का विस्तार 1991-92 के 16,255 करोड़ रुपये (9.4 प्रतिशत) की तुलना में बढ़ाकर 28,380 करोड़ रुपये (15.1 प्रतिशत) तक कर दिया गया ।

4.6 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जिसमें 1991-92 में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी, वर्ष के अधिकांश भाग में उसमें कमी आयी । मार्च 1993 में, विनिमय दरों के एकीकरण के कारण, बाजार दरों पर, इन परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात इन परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई । 1992-93 के दौरान रिजर्व बैंक की निवल मुद्रांतर देयताओं में 641 करोड़ रुपये की

भारी वृद्धि हुई । तथापि, वर्ष के अधिकांश समय में रिजर्व बैंक की निवल मुद्रांतर परिसंपत्तियों में गिरावट का अनुभव हुआ जिससे, अन्य बातों के साथ साथ विदेशी परिसंपत्तियों की हानि हुई और केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के लाभ का काफी बड़ा हिस्सा अंतरित करना पड़ा । विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के एकीकरण से और 5 मार्च 1993 से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने के कारण इस प्रवृत्ति में बदलाव आया ।

आरक्षित मुद्रा और रिजर्व बैंक की निवल देशी परिसंपत्तियां

4.7 केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में साधारण वृद्धि होने के बावजूद आरक्षित मुद्रा का विस्तार 11,438 करोड़ रुपये हुआ जो 1991-92 के 11,726 करोड़ रुपये के करीब था (परिशिष्ट सारणी 4.2) । पिछले वर्ष की तुलना में रिजर्व बैंक की निवल घरेलू परिसंपत्तियों में 1991-92 के 871 करोड़ रुपये (1.1 प्रतिशत) की तुलना में 7,629 करोड़ रुपये (9.5 प्रतिशत) की भारी वृद्धि हुई । फिर भी, 1992-93 के लिये निर्धारित निवल घरेलू परिसंपत्तियों के विस्तार की अधिकतम सीमा को पूरा किया गया । (सारणी 4.2) ।

4.8 हालांकि पिछले ग्यारह वर्ष के दौरान प्रवृत्ति की दर की तुलना में 1992-93 में मुद्रा का विस्तार निम्नतर था, फिर भी वह सांकेतिक लक्ष्य और वास्तविक कीमत तथा उत्पाद गतिविधियों की तुलना में उच्च था । इसलिए, मुद्रा और कीमत को स्थिर बनाये रखना सर्वोपरि हो गया ।

सारणी : 4. 2 : निचल देशी आस्तियों और वास्तविक कार्यनिष्पादन के संबंध में उच्चतम सीमा

(करोड़ रुपये)

सद	31 मार्च	31 मार्च 1992 की तुलना में				31 मार्च	वास्तविक कार्यनिष्पादन : 31 मार्च 1992 की				31 मार्च
	1992 को	निर्धारित विस्तार				1993 की	तुलना में विस्तार				1993 की
	वकाया	26 जून	18 सितंबर	दिसंबर	31 मार्च	निर्धारित	26 जून	18 सितंबर	25 दिसंबर	31 मार्च	वास्तविक
		1992	1992	1992	1993	वकाया राशि	1992	1992	1992	1993	वकाया (घ)
							(घ)	(घ)	(घ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 आरक्षित मुद्रा	99,505	7,100	5,900	10,900	13,700	1,13,200 (13.8)	6,068	5,627	4,710	11,438	1,10,943 (11.5)
निवल देशी	80,667	10,900	9,300	13,600	16,200	97,871	5,219	5,533	7,473	7,629	88,296
परिसंपत्तियां	92,798	9,246	7,373	13,389	12,131	(20.1)					(9.5)
सरकार को	94,016	7,300	7,500	7,400	5,800	99,200	2,320	3,836	223	4,433	98,449
भारतीय रिजर्व						(5.5)					(4.7)
बैंक का ऋण											
जिममें से केन्द्र	92,266	7,400	7,600	7,000	6,100	97,666	3,913	5,513	1,450*	4,257*	96,523*
को ऋण					5,400@	@[6.6]					(4.6)
अन्यों पर भारतीय	12,362	3,700	2,100	6,500	10,700	23,100	683 --	1,006	1,903	3,713	16,105
रिजर्व बैंक के दावे						[86.8]					[30.3]
	5,102						570	227	3,166	4,783	9,885
	7,260						93	-1,233	-1,263	-1,040	6,220
जिममें से (i)	25,711	25,100	-2,236	-2,703	-5,347	547	26,258
बैंकों पर											
(ii) वाणिज्यिक	18,838	--3,800	--3,400	--2,700	--2,500	16,300	849	94	-2,763	3,809	22,647
क्षेत्र पर अन्य मदें						[--13.5]					[20.2]
(निवल)											
निवल विदेशी											
परिसंपत्तियां											
2 सांकेतिक स्वल्प	1,58,263	9,400	10,600	11,400	10,400	1,68,700	6,412	10,921	12,175	17,826	1,76,989
केन्द्र सरकार को											
निवल बैंक ऋण											
(अधिकतम)											
व्यापक मुद्रा	3,17,481	9,600	11,700	25,200	32,700	3,47,800	19,452	24,223	34,125	45,184	3,62,665
(एम 3)		(3.0)	(3.7)	(8.0)	(10.4)	(10.4)					[14.2]

(@निम्नलिखित घटकों के समावेशों का निम्न अर्थात् विनियम दर्शों में परिवर्तन, स्वर्ण का सूत्र, आरक्षित आरक्षणार्थ और न्यूनतम निम्न अंशों का आरक्षण राशियाँ ।

अ-प्रतंसिम ।

(a) 31 मार्च 1993 को वर्ष की समाप्ति पर लब्ध ।

*प्रारम्भित परिसंरुति के कारण बड़े दुग्ध कोड़े के विप्रे अंतर्गच्छीय मुद्रा कोष को किये गये अभिधान पर खर्च किये गये 752 करोड़ रुपये को मिलाकर (211.95 मिलियन विशेष आहूरण अधिकारों के समकक्ष) आकड़े दिये गये हैं ।

टिप्पणी : 1. जन, मितम्बर और विगम्बर के लिए भारतीय गिर्य जैक को प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर उच्चतम सीमा का अनुपालन निर्धारित करने हेतु 31 मार्च के लिए अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार तक (और मिलाकर) चार शुक्रवारों का मासार्ण योगत लिया गया था। (सरकारी खातों को खोल करने के पश्चात् और 31 मार्च के अंतिम चार शुक्रवारों के श्रकड़ों को लेकर अंतिम निकाला गया।

2. बड़े कोष्ठकों में दिये गये आकड़े वित्तीय वर्ष के दौरान जी वृद्धि की दरें बताते हैं।

3. लघु कोष्ठक में दिये गये आकृष्टे प्रतिशत वसति है ।

4. 1991-92 के अन्तिम आंकड़ों पर लक्ष्य आधारित हैं ।

1993-94 की प्रथम तिमाही के दौरान प्रवृत्तियां

4.9 पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि में 19,452 करोड़ रुपये (6.1 प्रतिशत) की तुलना में व्यापक मुद्रा (एम 3) 18,391 करोड़ रुपये (5.1 प्रतिशत) से बढ़ जाने से वित्तीय वर्ष 1993-94 की प्रथम तिमाही में मुद्रा विस्तार की गति धीमी थी। करीबन 12.00 प्रतिशत की निर्धारित वृद्धि की तुलना में एम 3 में विस्तार की गति इस वर्ष की पहली तिमाही में कुछ अधिक रही। जनता के पास मुद्रा पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही के 2,763 करोड़ रुपये (4.5 प्रतिशत) की तुलना में तीव्र गति से बढ़कर 6,088 करोड़ रुपये (8.9 प्रतिशत) हो गई। पिछले वर्ष के 11,690 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत) की तुलना में कुल जमाराशियों के 9,171 करोड़ रुपये (3.1 प्रतिशत) हो जाने से वृद्धि सामान्य थी। वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक ऋण में तीव्र गिरावट आयी जो पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि में 8,811 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत) के आधे से कम 3,916 करोड़ रुपये (1.8 प्रतिशत) थी। केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में तेजी से विस्तार हुआ। वह 9,201 करोड़ रुपये (9.5 प्रतिशत) तक पहुँच गया। इससे वास्तविक चलनिधि प्रभाव नियंत्रित नहीं होता क्योंकि करीब-करीब पूरी तिमाही में मततः पुनः खरीद के आधार पर रिजर्व बैंक के संविभाग से सरकारी प्रतिभूतियों की पर्याप्त बिक्री की गई। यदि पुनः खरीद लेनदेनों के भारित औसत पर विचार किया जाता है तो संपूर्ण तिमाही में केन्द्र की भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण विस्तार में 1992-93 की पहली तिमाही में 3,913 करोड़ रुपये या 4.2 प्रतिशत की तुलना में करीबन 17,524 करोड़ रुपये अर्थात् 18.2 प्रतिशत वृद्धि होगी। बैंकिंग प्रणाली के निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी पिछले वर्ष की तदनुगुणी तिमाही में 849 करोड़ रुपये की न्यूनतर वृद्धि की तुलना में 1,681 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि हुई। तथापि, आरक्षित मुद्रा वृद्धि में गिरावट आयी। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में 6,068 करोड़ रुपये (6.1 प्रतिशत) की तुलना में 3,833 करोड़ रुपये (3.5 प्रतिशत) की बहुत कम वृद्धि, आरक्षित नकदी की न्यूनतर आवश्यकताएं, अंशतः आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती और अंशतः वाणिज्यिक ऋण की मांग में कमी, दर्शाती हैं, जिसकी वजह से बैंकों ने पुनर्वित्त सुविधाओं का अपेक्षाकृत कम उपयोग किया।

कुछ मौद्रिक संबंध

4.10 1992-93 के दौरान आय वेग अनुपातों (मुद्रा को छोड़कर) में कमी थी जो, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्रा की मांग में और विशेषतः बैंक की जमाराशियों (परिशिष्ट सारणी 4.3) में वृद्धि दर्शाती है। औसत और बिल्दवार आधार दोनों में वर्धमान मुद्रा गुणकों ने कुछ वृद्धि दर्ज की है। इसने प्रभावी आरक्षित नकदी अपेक्षाओं में 1397 GI/94-5

कटौती और आर्थिक इकाइयों द्वारा प्रदर्शित मुद्रा में जमाराशियों के लिए संपेक्ष अधिमान का प्रभाव मुख्यतया दर्शाया (परिशिष्ट सारणी 4.4)।

बैंकिंग प्रवृत्तियां

4.11 कुल जमाराशियों और विशेषतः मांग जमाराशियों की वृद्धि में कमी और बैंक ऋण में पर्याप्त वृद्धि राजकोपीय वर्ष (20 मार्च 1992 से 19 मार्च 1993 तक) के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनों की विशेषता थी।

4.12 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की वृद्धि पिछले वर्ष के 38,216 करोड़ रुपये (19.8 प्रतिशत) के स्तर से 37,814 करोड़ रुपये (16.4 प्रतिशत) प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट सारणी 4.5)। इस क्षेत्र में प्रारंभिक कार्यकारी अनुमान की अधिकतम सीमा 1992-93 में सर्वाधिक थी क्योंकि ये कार्यकारी अनुमान अस्सी के दशक में तैयार किये गये थे (सारणी 4.3)।

सारणी 4.3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक

सकल जमाराशियों की वृद्धि

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कार्यकारी अनुमान		वास्तविक उपनिधि	
	राशि	वृद्धि (प्रतिशत)	राशि	वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1982-83	7,000	16.0	7,625	17.4
1983-84	8,000	15.7	9,238	18.0
1984-85	9,600	15.8	11,648	19.2
1985-86	11,500	16.2	13,160	18.2
1986-87	15,000	17.5	17,320	20.3
1987-88	18,500	18.1	15,321	14.9
1988-89	20,500	17.4	22,105	18.7
1989-90	24,000	17.3	26,809	19.1
1990-91	27,500	16.6	25,583	15.3
1991-92	29,500	15.4	38,216	19.8
1992-93	27,000	11.7	37,814	16.4

4.13 वर्ष 1991-92 में क्रिशाशील दो विशेष घटक, अर्थात् विकास वाण्डों के कारण प्राप्त जमाराशियां और मध्यस्थ एजमियों द्वारा रखी गयी मार्जिन मुद्रा जमाराशियां वर्ष 1992-93 में न होने के कारण सकल जमाराशियों में बड़ी मात्रा में गिरावट आयी और विशेष कर 1992-93 के दौरान मांग जमाराशियों पर अधिक असर हुआ। फिर भी सावधिक जमाराशियों में वर्ष के दौरान सभी परिपक्वता अग्रविधानी मीमादी जमाराशियों पर वास्तविक निश्चित ब्याज-दर प्रस्तावित किये जाने, बैंक-जमाराशियों से प्राप्त ब्याज-आय पर स्त्रोत पर कर-कटौती को हटाये जाने और

प्रतिभूति बाजार की अनियमितताओं के संदर्भ में बैंक-जमा-राशियों में हुई वृद्धि के कारण भारी वृद्धि परिलक्षित हुई।

4.14 26,390 करोड़ रुपये (21.0 प्रतिशत) की वृद्धि होने के कारण बैंक ऋण में विस्तार तीव्र रूप से ढाई गुना से भी अधिक हुआ। पूर्ववर्ती वर्ष में 9291 करोड़ रुपये (8.00 प्रतिशत) की असाधारण रूप से निम्न वृद्धि दर्ज हुई। आरक्षित निधि अपेक्षाओं में बड़ी छूट के जगह बैंकों के स्त्रोतों के विमोचन और औद्योगिक तथा कृषि विस्तार में अधिक जोर लाने हेतु चयनित क्षेत्रों की जनवरी 1993 में 1,000 करोड़ रुपये के विमोचन के कारण यह संभव हो सका। वर्ष 1991-92 के दौरान की 164 करोड़ रुपये (3.6 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि की तुलना में खाद्य ऋण में 2,073 करोड़ रुपये (44.4 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि हुई जो खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि के तत्काल बाद बड़ी खरीद खरीद तथा खरीद मूल्यों में वृद्धि के रूप में प्रतिबिम्बित हुई। खाद्य ऋण विस्तार पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक था (1991-92 के 9,127 करोड़ रु० या 8.2 प्रतिशत की तुलना में 24,317 करोड़ रु०

या 20.1 प्रतिशत)। हालांकि यह मर्यादित औद्योगिक पुनरुज्जीवन द्वारा पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ अन्य घटक भी इसमें क्रियाशील थे: न्यूनतम उधार दर को कम करने के साथ-साथ ऋण की लागत में कटौती, मांग मंदी का सामना कर रहे क्षेत्रों में श्टाक बनवाना, सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बड़ी हुई मांग और निर्यात ऋण में अधिकतम वृद्धि तथा नीतिगत उपाय जैसे, वृद्धिशील ऋण खाद्य ऋण-जमा अनुपात के घटने को हटाना, सांविधिक जलनिधि अनुपात में घट, और उधारकर्ताओं के उत्पादन के मौजूदा स्तर की पूर्ति के लिए आवश्यक मानक मानदण्डों के 20 प्रतिशत तक स्टॉक और प्राप्य के मानदण्ड का सुलभीकरण। परिणामस्वरूप, संविभाग में निवेशों में ऋण में अंतरण हुआ। सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश में गिरावट दर्ज हुई। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पिछले वर्ष के 12,729 करोड़ रु० से सीमान्त रूप में बढ़कर 13,218 करोड़ रु० हुआ; जबकि अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में निवेश ने पिछले वर्ष के 2,402 करोड़ रु० की तुलना में निम्न वृद्धि अर्थात् 2,242 करोड़ रु० दर्ज की।

सारणी 4.4 : बैंकिंग परिवर्तन—वृद्धि दरें

परिवर्तन	(प्रतिशत)						
	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89	1993-94	1992-93
						(अप्रैल-जून) @	
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल जमाराशियां	16.4	19.8	15.3	19.1	18.7	3.2	5.3
मग्न जमाराशियां	3.0	35.8	15.0	23.6	15.3	-1.6	0.4
सीमादी जमाराशियां	19.6	16.5	14.4	18.2	19.4	1.2	6.5
बैंक ऋण	21.0	8.0	14.6	19.8	20.1	2.3	6.4
खाद्य ऋण	44.4	3.6	124.6	160.9	64.9	42.0	9.2
खाद्येतर ऋण	20.1	8.2	12.4	18.5	22.8	0.5	6.3
निवेश	17.1	20.2	16.6	17.8	17.5	5.8	4.8

टिप्पणी: घनात्मक वृद्धि के मामले में कोई चिह्न नहीं दिया गया है।

@अनंतिम।

4.15 सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में कतिपय नीतिगत अभिक्रमों के अनुसरण में, वर्ष 1992-93 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों की संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। वाणिज्यिक बैंकों ने नीलामी पर ओजार बेचे जाने के संबंध में अनुकूल प्रतिक्रिया दी।

4.16 ऋण में तीव्र वृद्धि और जमाराशियों में गिरावट के साथ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष के 54.4 प्रतिशत की तुलना में 56.6 प्रतिशत तक बढ़ा।

4.17 कुल जमाराशियां 6,147 करोड़ रुपये या 2.2 प्रतिशत (4,503 करोड़ रुपये या 1.9 प्रतिशत)

और बैंक ऋण 4,518 करोड़ रुपये या 2.9 प्रतिशत (4,079 करोड़ रुपये या 3.1 प्रतिशत) की वृद्धि सहित हाल ही के वर्षों में मार्च के अंतिम शुक्रवार और मार्च के आखिरी दिन के बीच कुल जमाराशियां और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण, दोनों में, उभार की प्रवृत्ति दिखायी दी। पिछले वर्ष के अनुसार ही, अप्रैल 1993 के परवर्ती रिपोर्टिंग सप्ताहों में जमाराशियों में इस प्रकार की बड़ी वृद्धि कम होती दिखाई दी। (परिशिष्ट सारणी 4.6)

जमाराशि से इतर संसाधन

4.18 1992-93 के दौरान सकल जमाराशि वृद्धि में गिरावट के साथ, बैंकों द्वारा जमाराशि से इतर संसाधनों

के उपयोग ने 1991-92 की गिरावट के तीव्र विरोध में 1992-93 में विशेष रूप से ऊर्ध्व प्रवृत्ति दर्शायी (परिशिष्ट सारणी 4.7)। समग्र आधार पर वर्ष 1991-92 के दौरान अतिरिक्त जमाराशि में इतर संसाधनों का उपयोग 1,889 करोड़ रु० से बढ़ा तथा बैंकों द्वारा ऐसे संसाधनों का उपयोग 457 करोड़ रु० से घटा था।

पहली तिमाही की प्रवृत्तियाँ : 1993-94

4.19 वित्तीय वर्ष 1993-94 (अप्रैल-जून), की पहली तिमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियाँ तथा बैंक ऋण दोनों में धीमी वृद्धि हुई। सकल जमाराशियों में 8,664 करोड़ रु० (3.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो 1992-93 की तुलनीय तिमाही में हुई 12,256 करोड़ रु० (5.3 प्रतिशत) की वृद्धि से अधिक थी। बैंक-ऋण का विस्तार पिछली तदनुरूपी अवधि के 8,052 करोड़ रु० (6.4 प्रतिशत) से 3,534 करोड़ रु० (2.3 प्रतिशत) तक निम्न रहा। फिर भी गेहूँ उगाही प्रक्रिया में सुधार के कारण खाद्य ऋण में 2,833 करोड़ रु० (42.0 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खाद्येतर ऋण का विस्तार 701 करोड़ रु० (0.5 प्रतिशत) रहा जो 1992-93 की तुलनीय अवधि में हुई 7,621 करोड़ (6.3 प्रतिशत) की वृद्धि से बहुत ही कम था। सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान दर्ज 4,291 करोड़ रु० (4.8 प्रतिशत) से उच्चतर अर्थात् 6,137 करोड़ रु० (5.8 प्रतिशत) थी। पिछले वर्ष की तुलना में 1993-94 की पहली तिमाही में खाद्येतर ऋण के विस्तार में हुई प्रत्यक्ष गिरावट के लिए कई घटक जिम्मेदार हैं। पहले, कठोर पूर्वोपाय मानदंडों और पूँजी जोखिम-आस्तियाँ अनुपात लागू करने की दृष्टि से उधार देने के संबंध में बैंक सावधानी बरतने लगे हैं। दूसरी बात, बैंकों ने मार्च 1993 में बढ़े खाते खाली गयी बड़ी राशि का उत्तरदायित्व लिया। तीसरी बात, कई बड़े उधारकर्ताओं ने वाणिज्यिक पत्र का आश्रय लेना बढ़ाया है। चौथी बात, ऐसी कई कंपनियाँ, जिन्होंने 1992-93 में पूँजी बाजार से बड़ी राशियाँ प्राप्त की थी, निधियों से परिपूर्ण है और उन्होंने बैंकों के अपने उधारों को कम कर दिया है। पाँचवीं बात, मार्ज-जनिक क्षेत्र के कुछ बड़े यूनिटों, विशेषकर व्यापारिक गति-विधियों से सम्बद्ध यूनिटों ने बैंक के अपने उधारों को कम कर दिया है। छठी बात, अप्रैल-जून तिमाही सामान्यतः ऋण में संदी की अवधि है, क्योंकि उस समय ऋण का मौसमी अंतर्वाह होता है हालांकि 1993-94 की प्रथम तिमाही में खाद्येतर ऋण विस्तार 1992-93 के तुलनीय विस्तार की तुलना में काफी धीमा दिखाई देता है; यह 1991-92 और 1990-91 के विस्तार के अनुरूप है

(सारणी 4.5)।

सारणी 4.5 पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में खाद्येतर ऋण विस्तार

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
करोड़ रु०	791	7,621	149	648
प्रतिशत	0.5	6.3	0.1	0.7

ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

4.20 वित्तीय वर्ष 1992-93 (अप्रैल-मार्च) के सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि खाद्येतर सकल बैंक ऋण में 18,993 करोड़ रु० की वृद्धि हुई, जब कि 1991-92 के तदनुरूपी अवधि के दौरान 7,822 करोड़ रु० की कम वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी 4.8)। वृद्धिशील ऋण के उद्योग-वार व्यूरे यह दर्शाते हैं कि मुख्यतः सभी इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात, रसायन समूह, रत्न और आभूषण, निर्माण और पेट्रोलियम में बहुत अधिक ऋण विस्तार हुआ है, जबकि बिजली (उत्पादन और संचारण) चमड़ा और चमड़े की बस्तुओं को दिये ऋण की वृद्धि में कमी आयी (परिशिष्ट सारणी 4-9)।

रिजर्व बैंक पुनर्वित्त

4.21 निर्यात क्षेत्र को बैंक ऋण का बहिर्वाह 1992-93 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। वृद्धि का क्रम 40.6 प्रतिशत रहा। 19 मार्च 1993 और 25 जून 1993 के बीच इसमें 12.9 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। 20 मार्च 1992 के अंत और 19 मार्च 1993 के बीच कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं 85.9 प्रतिशत से बढ़ीं और कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं; 19 मार्च 1993 को बकाया निर्यात ऋण के 69.2 प्रतिशत के समरूप थीं। भाग-1 में उल्लिखित पुनर्वित्त फार्मूला में समायोजन के बावजूद भी 19 मार्च 1993 और 25 जून 1993 के बीच कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं और 7.9 प्रतिशत में बढ़ीं। 19 मार्च 1993 तथा 23 जुलाई 1993 के बीच जहां बैंकों के बकाये निर्यात में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं उनके निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमायें 11.2 प्रतिशत बढ़ीं।

4.22 अक्टूबर 1992 में लागू नयी पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियाँ पुनर्वित्त सुविधा के अधीन, 25 जून 1993 को पुनर्वित्त की कोई बकाया राशि नहीं थी।

सारणी 4. 6 निर्यात शुण पुनर्वित्त

(करोड़ रुपये)

निम्न दिनांक को	भारतीय रुपयों में मूल्यवर्गित निर्यात शुण का पुनर्वित्त पोषण			अमरीकी डालरों में मूल्यवर्गित निर्यात शुण का पुनर्वित्त पोषण					
	बकाया निर्यात शुण	बकाया निर्यात पुनर्वित्त सीमाएं	स्तंभ (2) से स्तंभ (3) का अनुपात	बकाया निर्यात शुण	बकाया निर्यात पुनर्वित्त सीमाएं	स्तंभ (5) से स्तंभ (6) का अनुपात	बकाया निर्यात शुण	बकाया निर्यात पुनर्वित्त सीमाएं	स्तंभ (8) से स्तंभ (9) का अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 मार्च 1992	10,672	5,564	52.1	23	30	130.4	10,695	5,594	52.3
26 जून 1992	11,852	6,939	58.5	16.8	224	133.3	12,020	7,163	59.6
11 अगस्त 1992	11,565	6,647	51.5	745	993	133.3	12,310	7,640	62.1
19 मई 1993	11,228	5,834	52.0	3,810	4,568	119.9	15,038	10,402	69.2
25 जून 1993	12,298	6,548	53.2	4,679	4,679	100.0	16,977	11,227	66.1
6 अगस्त 1993	12,364	6,580	53.2	4,945	4,945	100.0	17,309	11,525	66.6

अल्पावधिमुद्रा बाजार की प्रवृत्तियां

भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि०

4.23 वर्ष 1992-93 के दौरान मांग और सूचना पर देय उधार को छोड़कर मुद्रा बाजार के अन्य सभी भागों में भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि० का लेनदेन पिछले वर्ष के उनके संबंधित स्तरों की तुलना में निम्नतम रहा। मांग और सूचना मुद्रा बाजार में इनका संचित वार्षिक लेनदेन 4,57,013 करोड़ रु० रहा और यह 10 प्रतिशत से थोड़े अधिक का हिस्सा रहा। इसके विपरीत पिछले वर्ष उक्त लेनदेन 2,94,373 करोड़ रु० दर्ज हुआ था। इसके परिणाम-स्वरूप भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि० द्वारा उधार की दैनिक औसत वर्ष 1991-92 के 799 करोड़ रु० की तुलना में बढ़कर वर्ष 1992-93 में 1,243 करोड़ रु० हो गयी।

4.24 भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड ने अप्रैल 1992 में केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में अपना लेनदेन आरंभ किया और मार्च 1993 के अंत तक संचयी लेनदेन 18,645 करोड़ रु० हुआ, परन्तु इन लेनदेनों का अत्यधिक हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पुनर्खरीद से संबंधित था। अन्य के साथ संचयी लेनदेन केवल 2,713 करोड़ रु० का था। वाणिज्यिक बिल लेनदेन काफी घट गया और 1991-92 के 6,995 करोड़ रु० की तुलना में 1992-93 में 786 करोड़ रु० तक संचयी लेनदेन में तीव्र गिरावट आयी, बिल भुनाई/पुनर्भुनाई सुविधा के अनियमित उपयोग को नियंत्रित करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 1992 में की गयी कार्रवाई के अनुसरण से बिल प्रणाली का आश्रय लेने की घटती हुई प्रवृत्ति का यह परिणाम था।

जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र आदि जैसे अन्य मुद्रा बाजार लिखतों में भी लेनदेन घीमा था।

मांग मुद्रा बाजार

4.25 वर्ष 1992-93 के दौरान मांग मुद्रा दरें सामान्यतः सुलभ थीं, जो बैंकिंग प्रणाली में सापेक्षतः स्वस्थ चलनिधियों में प्रतिबिंबित हुईं। आरक्षित अपेक्षाओं में भारी घट के कारण भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि० की मासिक भारांकित औसत उधार दर अप्रैल 1992 के 29.36 प्रतिशत और मई 1992 के 23.99 प्रतिशत से घटकर जून 1992 में 14.75 प्रतिशत हो गयीं। जुलाई 1992 से मांग मुद्रा बाजार सुलभ रहा और मार्च 1993 के अंतिम मप्ताह तक दरें सामान्यतः 9.00 से 12.00 प्रतिशत के बीच रहीं, जब निधियों की मांग में वर्ष के अंत की वृद्धि के कारण दरें स्थिर थीं। मांग मुद्रा बाजार बाद वाले महीनों में सुलभ रहा और भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि० की मासिक भारांकित औसत उधार दरें मई और जून 1993 के दौरान क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 6.1 रहीं प्रतिशत रहीं।

4.26 32 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पखवाड़े के दैनिक औसत पर उधार, 10 जुलाई 1992 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 10,387 करोड़ रुपये थे जो घटकर 25 जून 1993 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 8,520 करोड़ रु० हो गये। परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये, पखवाड़े के दैनिक औसत उधार, 10 जुलाई, 1992 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 7,434 करोड़ रु० से घटकर 25 जून 1993 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 6,354 करोड़ रु० के हो गये।

जमा प्रमाण-पत्र और वाणिज्यिक पत्र

4.27 11 जून 1993 को 50 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि 11,744 करोड़ रु० थी। इसकी तुलना में 52 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 26 जून 1992 को उक्त राशि 6,990 करोड़ रु० थी। मार्च के अंत में बकाया जमा प्रमाणपत्र, सीमाओं के कुल 67.0 प्रतिशत थे (परिशिष्ट सारणी IV.15)। 3 महीनों की परिपक्वता—अवधि वाले जमा प्रमाणपत्रों के लिए विशिष्ट ब्याज—दरें जून 1992 में 15 से 16 प्रतिशत के बीच थीं जो मार्च 1993 में 14.5 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत की सीमा तक नीचे आयीं। एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले जमा प्रमाणपत्रों की विशिष्ट ब्याज-दर भी जून 1992 के 15.0-16.5 प्रतिशत से थोड़ी सी घटकर मार्च 1993 में 14.5—16.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुई। छः अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं; अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और निर्यात-आयात बैंक को भी एक वर्ष से अधिक और तीन वर्षों तक की परिपक्वता अवधि वाले 3,750 करोड़ रु० की सकल राशि के जमा प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी गयी है। ऐसे जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि 25 जून 1993 को 2,040 करोड़ रु० थी जिसे 14.5 प्रतिशत और 17.0 प्रतिशत के बीच की सीमा में ब्याज दरें प्रस्तावित थीं।

4.28 वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि 30 जून 1992 को 14 कंपनियों द्वारा जारी 198 करोड़ रु० से बढ़कर जुलाई 1993 के अंत को 57 कंपनियों द्वारा जारी 1,454 करोड़ रु० हो गयी जो वाणिज्यिक पत्र की बकाया राशि के चरम स्तर पर थी। 1992-93 वर्ष के दौरान जारी किये गये अधिकतम वाणिज्यिक पत्रों को प्रतिवर्ष 15.5 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत की सीमा तक प्रभावी ब्याज दरें दी गयीं। फिर भी बाव वाले महीनों में जारी वाणिज्यिक पत्रों की प्रभावी ब्याज दरों में भारी गिरावट आयी और जुलाई 1993 में जारी वाणिज्यिक पत्रों को 12.0 प्रतिशत से 13.5 प्रतिशत तक की सीमा में प्रभावी ब्याज दरें दी गयीं। अधिकांश वाणिज्यिक पत्रों को बैंकों द्वारा रखा गया था।

बिल पुनर्भुनाई बाजार :

4.29 बिल भुनाई/पुनर्भुनाई बाजारों की गतिविधियां उल्लेखनीय रूप से कम हुईं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्भुनाई वाणिज्यिक बिलों की बकाया राशि मार्च 1992 के अंत के 3,874 करोड़ रु० से घटकर मार्च 1993 के अंत में 779 करोड़ रु० हो गयी, जो आगे मई 1993 के अंत में 679 करोड़ रु० तक नीचे आयी।

आंतरिक ऋण प्रबंधन परिचालन :

4.30 वर्ष 1992-93 में आंतरिक ऋण प्रबंधन परिचालनों को क्रियाशील बनाने हेतु कई नीतिगत परिवर्तन किये गये और यह स्वीकार किया गया कि अधिक कारगर संसाधन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के संसाधनों का पूर्वकथ अधिकार कम करने की आवश्यकता होगी। अप्रैल 1992 की मौद्रिक नीति में भारत सरकार सप्टा दिनांकित प्रतिभूतियों और दीर्घवधि खजाना बिलों का समावेश करने के संबंध में बाजार उन्मुखता आरंभ कर आंतरिक ऋण प्रबंधन के लिये एक नया दृष्टिकोण घोषित किया। विविध परिपक्वताओं के खजाना बिलों सहित केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए नीचामी प्रणाली लागू की गयी। इसे 1992-93 के, सरकार के उधार कार्यक्रम में समग्र कटौती द्वारा सुनभ किया जाना था।

दर्शाती है कि आय की वक्र रेखा धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी बनती जा रही है। (देखें बाक्स 3 और सारणी 4.7)।

सारणी 4.7 सरकारी प्रतिभूतियों का कूपन दरें

(प्रतिवर्ष प्रतिशत)

परिपक्वता अवधि	1993-94†	1992-93*	1991-92†
1	2	3	4
3 वर्ष	12.75@	—	—
5 वर्ष	13.00	12.00	10.75
6 वर्ष	—	12.30	—
7 वर्ष	13.25	12.60	—
8 वर्ष	—	12.70	—
9 वर्ष	13.40	—	—
10 वर्ष	13.50@@	12.75	11.00
15 वर्ष	—	13.00	12.50

†नियत कूपन दरें।

*3 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए 12.75 प्रतिशत को छोड़कर नीचामियों से उभरी दरें।

@364 दिनों के खजाना बिलों के रूपांतरण में जारी किये गये सरकारी स्टॉक पर नियत कूपन दर।

@@राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर नियत कूपन दर।

बाक्स 3

आय—वक्र

आय वक्र के आकार से उन प्रतिभूतियों की आय के बीच के संबंध का पता चलता है जो केवल अपनी परिपक्वता अवधि में भिन्नता रखती हैं। सामान्य धारणा है कि आय-वक्र एक बिन्दु तक ऊपर उठेगा फिर वह सपाट हो जायेगा। आय-वक्र इस प्रकार होगा।

कम से कम तीन प्रतियोगी सिद्धांत हैं जो व्याज-दरों के ढांचे की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, अर्थात्,

आशावादी, नकदी वरीयतावादी तथा वरीयता पसंदगी सिद्धांत ।

आशावादी सिद्धांत के अनुसार, वक्र के आकार की व्याख्या भावी व्याज दरों के बारे में निवेशकों की आशा से की जा सकती है । यदि भविष्य में, अल्पावधि दरों के अपेक्षाकृत कम होने की आशा है तो अल्पावधि दर दीर्घावधि दर से नीचे होगी । इसी प्रकार, यदि यह आशा हो कि दरें भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक होंगी तो दीर्घावधि दरें चालू अल्पावधि दर से आगे निकल जायेंगी । हम सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता जे० आर० हिक्स (1939) एफ० लुज (1940) तथा बी० मलकील (1966) थे ।

कीन्स का नकदी वरीयता सिद्धांत, जिसे जे० आर० हिक्स ने (1939) प्रस्तुत किया था, इस तथ्य को स्वीकार करता है कि आय-वक्र का आकार आशाओं से प्रभावित होता है । फिर भी, अल्पावधि हिस्से के शेयर, विणेशकर अनिश्चितता की दुनिया में, अधिकांश निवेशक पसंद करेंगे क्योंकि दीर्घावधि शेयर की अपेक्षा उनका नकदी मूल्य ज्यादा है । यदि दीर्घावधि लिखतों के लिए कोई प्रीमियम नहीं है तो निवेशक अल्पावधि प्रतिभूतियां रखना पसंद करेंगे ताकि वे अपने संविभाग के अंकित मूल्य में संभावित घट-बढ़ का कम कर सकें ।

जे० कुलबर्टसन (1957) तथा एफ० मोडिलियानी और आर० मुण (1966) जैसे आलोचकों ने आशावादी सिद्धांत के बारे में यह उल्लेख किया कि निवेशकों के सभी वर्ग के लिए नकदी वरीयता ही मुख्य बात नहीं हो सकती । उनकी राय में, बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां तथा यहां तक कि सेवानिवृत्त लोग भी व्याज दर में संभावित घट-बढ़ से बचने के लिए अल्पावधि प्रतिभूतियों की अपेक्षा दीर्घावधि प्रतिभूतियों में निवेश करना पसंद करते हैं । दूसरी और, वाणिज्य बैंकों अथवा कंपनी के निवेशक नकदी को पसंद कर सकते हैं और इसलिए वे अल्पावधि शेयरों में निवेश करेंगे । इस प्रकार, निवेशक वरीयता पसंद करते हैं और प्रतिभूति बाजार के अलग-अलग हिस्से होने की संभावना रहती है जिससे उनसे होने वाली आय प्रत्येक बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है ।

संदर्भ: कुलबर्टन जे० (1957) द टर्म स्ट्रक्चर आफ इंटरैस्ट रेट्स, क्वार्टर्ली जर्नल आफ इकोनामिक्स, नवंबर, हिक्स, जे० आर (1939), बैल्यू एण्ड कैपिटल, लंदन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लुज, एफ (1940), "द स्ट्रक्चर आफ इंटरैस्ट रेट्स", क्वार्टर्ली जर्नल आफ इकोनामिक्स, नवंबर, मलकील, बी, (1966) द टर्म स्ट्रक्चर आफ इंटरैस्ट रेट्स, प्रिस्टन, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, एण्ड मेडिग्लियानी, एफ० एण्ड मुण, आर (1960), "इन्वेंशनम् इन इंटरैस्ट रेट पालिसी," अमेरिकन इकोनामिक रिव्यू, मई ।

4.31 पुनः स्थापित आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति का एक मुख्य लक्षण सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को धारकों के लिये आकर्षक बनाना था । दूसरी बात, व्याज दरें समग्र सीमा के भीतर अनुमत थीं, ताकि बाजार के अनुकूल हो सकें । वर्ष 1991-92 में अधिकतम कूपन दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक दो स्तरों में बढ़ा जबकि अधिकतम परिपक्वता अवधि 20 वर्षों से घटकर 15 वर्ष हो गयी । 1992-93 में अधिकतम कूपन दर 15 वर्षों के लिए 13.0 प्रतिशत था । अधिकतम आय/कूपन दरों पर 5 वर्षों के लिए 12.0 प्रतिशत से लेकर 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए 12.75 प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां 10 वर्षों की अल्प परिपक्वता अवधि के लिए नीलाम की गईं । 1993-94 में 10 वर्षों के लिए अधिकतम परिपक्वता अवधि की और कटौती सहित अधिकतम कूपन दर 13.5 प्रतिशत बढ़ाई गई थी ।

182 दिवसीय खजाना बिल

4.32 182 दिवसीय खजाना बिलों की बकाया राशि मार्च 1992 के अंत में 3,986 करोड़ रुपए हुई, जो अक्टूबर के मध्य में पूर्णतः चुकाई गयी और 16 अप्रैल 1992 के बाद कोई नया 182 दिवसीय खजाना बिल जारी नहीं किया गया ।

364 दिवसीय खजाना बिल

4.33 364 दिवसीय खजाना बिलों के रूप में एक नया लिखत अप्रैल 1992 के अंत में आरंभ किया गया । पाक्षिक आधार पर इन बिलों की नीलामी एक नियमित लक्षण बन गया । इन नीलामियों ने निवेशकों से अच्छा प्रतिभाव पाया जो अंशतः लिखत के मापेक्ष आकर्षकता का परिणाम था, तथा अंशतः 1992-93 के आरंभ में प्रतिभूतियों के लेनदेन में उभरकर आयी अनियमितताओं के कारण सरकारी प्रतिभूति बाजार पर हावी अनिश्चितताओं के सामने निवेशकों को सुरक्षा प्रदान किये जाने का परिणाम था । 364 दिवसीय खजाना बिलों के जगह सकल उधारों की राशि 1992-93 में 8,777 करोड़ रु० हुई । नीलामियों में निर्धारित अधिकतम मूल्यों पर आवश्यक आय दरें 10.96 प्रतिवर्ष और 11.42 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच की सीमा में रहीं । चूंकि 182 दिवसीय खजाना बिलों की कुल बकाया राशि मार्च 1992 के अंत में 3,986 करोड़ रु० थी और उनकी अवधि समाप्त हो गयी, अतः 500 करोड़ रु० की कुल बजट राशि के मकाबले 4,791 करोड़ रु० की राशि, जो दीर्घ दिनांकित खजाना बिलों की शुद्ध चकोतियों की राशि है, सरकार जुटा सकती थी । यह उल्लेखनीय है कि इन दीर्घ दिनांकित बिलों का पूरा अभिदान बाजार द्वारा था और इसका कोई हिस्सा रिजर्व बैंक द्वारा धारित नहीं था । राजकोषीय वर्ष 1993-94 से 6 अगस्त 1993 तक के दौरान 364 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी में 3,378 करोड़ रु० जमा किये गये (पारिशिष्ट सारणी 4.16) ।

4.34 वर्ष 1993-94 में अवधि समाप्ति के कारण 364 दिवसीय खजाना बिलों की राशि बहुत बड़ी थी और तीव्र नकदी वृद्धि की अंतर्भूत समस्या के निराकरण के लिए सरकार ने 19 अप्रैल, 1993 को 1993-94 में अवधि-समाप्त 364 दिवसीय खजाना बिलों के परिवर्तन से 12.75 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 1996 की बिक्री का प्रस्ताव रखा। कुल 8,777 करोड़ रु० (अंकित मूल्य) के परिवर्तन के लिये योग्य बिलों के लिए निवेशकों द्वारा परिवर्तन के लिए 7,123 करोड़ रु० (अंकित मूल्य) प्रस्तुत किये गये जो पात्र बिलों के 81.2 प्रतिशत थे। इससे वर्ष 1993-94 में अवधि समाप्त 364 दिवसीय खजाना बिलों की राशि 1,654 करोड़ रु० अंकित मूल्य हुई। 12.75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति, 1996 में परिवर्तित कुल राशि 6,946 करोड़ रु० थी।

91 दिवसीय खजाना बिल

4.35 सक्रिय ऋण प्रबंधन परिचालनों की वषा में दूसरा चरण था पूर्वनिर्धारित राशि परंतु रिजर्व बैंक के सहभाग सहित, 91 दिवसीय खजाना बिलों को जारी करने के लिए नीलामी योजना का लागू किया जाना। अधिकतम आय ऐसे बिलों पर असीमित प्रतिभूतियों के सीधे विक्रय पर प्रति वर्ष 4.6 प्रतिशत के निर्धारित रियायती दर से उल्लेखनीय रूप से उच्चतर थी। मार्च 1993 के अंत में 91 दिवसीय खजाना बिलों की बकाया राशि 1,350 करोड़ रु० थी जिसमें से 1,147 करोड़ रु० भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और 203 करोड़ रु० अन्यो द्वारा रखे गये। वि० 21 अगस्त, 1993 को कुल बकाया राशि 2,625 करोड़ रु० थी, जिसमें से केवल 27 करोड़ रु० रिजर्व बैंक द्वारा रखे गये और 2,598 करोड़ रु० अन्यो द्वारा। इस प्रकार हाल ही में बाजारों द्वारा 91 दिवसीय खजाना बिलों का समावेशन अत्यधिक बढ़ा (परिशिष्ट सारणी 4.17)।

सरकारी विनांकित प्रतिभूतियां

4.36 पहली बार, 1992-93 में केन्द्रीय सरकार ने 4,821 करोड़ रु० के अपने सारे कुल बाजार उधार नीलाम प्रणाली के माध्यम से वसूल किये। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारंभ में 2,214 करोड़ रु० का अभिदान दिया, बाद में रिजर्व बैंक ने इन प्रतिभूतियों का काफी बड़ा हिस्सा बाजार में बेच दिया। 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 14 अगस्त, 1993 तक 3,000 करोड़ रुपये का सकल बाजार उधार बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारंभिक रूप में केवल 435 करोड़ रुपये का अभिदान किया। (परिशिष्ट सारणी 4.19)। नीलाम प्रणाली प्रारंभ से केन्द्रीय सरकार के ऋणों की कूपन दरें अधिकतम आय में व्यक्त हुईं, जिन दरों पर नीलामियों में प्रतियोगी बोलियां स्वीकार की गयीं। ऐसी कूपन दरें तुलनीय परिपक्वता-अवधि के लिए पिछले वर्ष में निर्धारित, पूर्वनिश्चित कूपन दरों से अधिक आकर्षक रही। कूपन दरों में सुधार परिपक्वता अवधि को कम किये जाने के ऊपर था। फिर भी राज्य सरकारों

तथा अन्य निकायों द्वारा लिये उधारों के लिए दरें निर्धारित रखना जारी रखा गया है। राजकोपीय वर्ष 1993-94 के दौरान जारी पहले दो निर्गमों की श्रृंखला में 3754 करोड़ रुपये की (सकल) राशि राज्य सरकार ने जुटाई। वर्ष 1992-93 में 15 वर्षीय राज्य सरकार प्रतिभूति के लिए उच्चतम दर 13.0 प्रतिशत थी। यह दर, 10 वर्षीय राज्य सरकार प्रतिभूति के लिए 1993-94 में 13.5 तक बढ़ायी गयी। प्रचलित निर्धारित दर से ऐसा कवर मिला जिसके भीतर नीलाम प्रणाली परिचालित हुई। कूपन दरें, जो पिछले तीन वर्षों में प्रतिभूतियों (केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों की) पर लागू रहीं।

4.37 रिजर्व बैंक ने पाक्षिक पूरक अवधि के भीतर बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि चलनिधि को एक समान करने के लिए केन्द्र सरकार की विनांकित प्रतिभूतियों के लिए समय-समय पर पुनः क्रय करारों की नीलामी आयोजित की। पहली नीलामी 10 दिसम्बर, 1992 को हुई और 20 अगस्त, 1993 तक 38 ऐसी नीलामियां आयोजित की गयीं। यह खुले बाजार की गतिविधियों को विकसित करने की ओर एक और उपाय है। प्रारंभ में, पुनः क्रय की नीलामियां एक या दो दिन की अल्पावधि अवधि के लिये थीं और उसके बाद 14 दिवस तक की पुनः क्रय की नीलामियों की श्रृंखला की गयी। 14 दिनों से अधिक अवधि के लिए आरक्षित अपेक्षा प्रणाली की स्थिति में अलग-अलग अवधियों के लिए पुनः क्रय की नीलामी के चलनिधि प्रभाव को 14 दिन से अधिक अवधि पर कुल बिक्री के औसत से मूल्यांकित किया जाए।

4.38 प्रतिभूतियों के लेन-देन में दो अन्य परिवर्तन हुए। पहले का संबंध स्विच कोटे से था। वार्षिक स्विच कोटे के आवंटन की प्रणाली 1973 से प्रचलन में थी जो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों, संस्थाओं के निवेशों के संबंध में आय बढ़ाने के लिए है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक ऋण की खरीदी की जमानत पर दूसरे ऋण की बिक्री हेतु प्रत्येक बैंक, संस्था के लिए वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया था। स्विच कोटा सुविधा की समीक्षा की जाने के बाद 1 अप्रैल, 1992 में यह प्रणाली समाप्त की गयी क्योंकि कुल मौद्रिक राशियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं था और मौद्रिक नीति के एक हथियार के रूप में खुले बाजार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुकूल नहीं थी। दूसरी, रिजर्व बैंक की बिक्री, खरीद सूची से संबंधित थी। बैंक अब केवल उन्हीं चुनिंदा प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए प्रस्तावित करता है जिन्हें वह अपना प्रस्ताव सूची में सूचीबद्ध करने के बजाए निवेश सविभाग की सभी विनांकित प्रतिभूतियों में लेने की इच्छा रखता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि रिजर्व बैंक कम से कम कुछ प्रतिभूतियों के लिए संपूर्ण चलनिधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपनी खरीद सूची में नकदी के लिए कतिपय प्रतिभूतियां रखे।

मूल्य प्रवृत्तियाँ

4.39 निरंतर आधार पर मुद्रास्फीति की दर में अत्यधिक गिरावट 1992-93 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है। मार्च 1993 के अंत में थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में 7.0 प्रतिशत पर अत्यधिक रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर समीक्षाधीन वर्ष में दर्ज की गयी दर (सारणी 4.8) से लगभग दुगुनी थी। इसके लिए अनेक तत्वों ने योगदान दिया, सकल देशी उत्पाद के संबंध में केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे में कटौती, मुद्रा-विस्तार में संयत और आपूर्ति की स्थिति में सुधार। अनुकूल मानसून के कारण भरपूर खरीफ फसल हुई। रबी उत्पाद में भी सुधार हुआ है। खाद्यान्नों तथा संबद्ध उत्पादों के आयात से खाद्यान्न के मूल्यों पर दबाव कम हो गया। फिर से उभरी औद्योगिक गतिविधि अस्सी के दशक की

स्थिति की तुलना में सामान्य रही जो मुद्रास्फीति संबंधी संभावनाओं को मंद करने में सहायक सिद्ध हुई।

4.40 बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर 'सभी पण्यों' के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार: 1981-82 = 100) के माध्यम से मापी गई मुद्रास्फीति की दर 1992-93 में 7.00 प्रतिशत थी जो अगस्त 1989 से अब तक कम थी। वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर अक्टूबर 1990 से जुलाई 1992 के अंत तक प्रत्येक महीने में 10 प्रतिशत से अधिक थी और अगस्त 1991 में 16.4 प्रतिशत पर सर्वाधिक रही। यह दर केवल नवम्बर 1992 से लगातार कम होकर इकाई अंक में रह गयी। औसत आधार पर, मुद्रास्फीति दर 1992-93 में 10.0 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के 13.7 प्रतिशत से बहुत कम थी (परिशिष्ट सारणी 4.21)।

सारणी 4.8 थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (बिंदु दर बिंदु 12 महीने की अवधि की वृद्धि)

(प्रतिशत)

के अंत में	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	7.0	13.6	11.4	9.0	5.9	9.6
मई	7.2	12.9	12.3	8.4	7.2	9.3
जून	6.1 अ	12.3	12.3	9.4	6.5	9.5
जुलाई	5.8 अ	10.4	14.5	9.3	6.4	8.3
अगस्त	6.2 अ*	9.2	16.4	7.6	8.9	6.3
सितम्बर		10.2	15.9	7.9	9.0	6.9
अक्तूबर		10.2	14.3	10.1	7.6	7.3
नवम्बर		8.5	14.6	11.1	7.5	7.0
दिसम्बर		8.4	14.3	12.6	7.7	4.4
जनवरी		7.6	12.9	13.5	8.1	5.6
फरवरी		7.4	13.2	13.2	8.7	5.3
मार्च		7.0	13.6	12.1	9.1	5.7

अ--अनंतिस

* 14 अगस्त, 1993 तक

4.41 वर्ष की उल्लेखनीय बात यह थी कि सार्वजनिक उपभोग के आवश्यक पण्यों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव में तेज गिरावट आयी। ऐसा लगता है कि 'प्राथमिक वस्तुओं' का भारित योगदान 14.4 प्रतिशत पर अत्यधिक है (परिशिष्ट सारणी 4.22)। फिर भी, इस परिणाम के लिए अत्यधिक योगदान खाद्य पदार्थों के कुल भार में लगभग आधा भार 8.397 प्रतिशत, फल और सब्जी, दूध, अंडा, मछली एवं मांस और चाय का रहा। सामान्य मूल्य स्तर के लिए बाकी खाद्य पदार्थों (ज्यादातर अनाज) का भारित योगदान वस्तुतः नगण्य था।

4.42 सामान्य मूल्य स्तर के लिए ईंधन, पावर, बिजली तथा चिकनाई के पदार्थ समूह का भारित योगदान 1991-92

के 10.2 प्रतिशत की तुलना में 1992-93 के दौरान 22.6 प्रतिशत था। इसका कारण पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद के (पिछले वर्ष के 9.2 प्रतिशत की तुलना में 18.8 प्रतिशत) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों और विभिन्न राज्य सरकारों, विद्युत बोर्डों द्वारा (पिछले वर्ष के 13.7 प्रतिशत की तुलना में 9.8 प्रतिशत) विद्युत प्रणाली में की गयी तीव्र वृद्धि है। सामान्य मूल्य स्तर के लिए विनिर्मित उत्पाद समूह का भारित योगदान 63.0 प्रतिशत पर सर्वाधिक रहा। इस वृद्धि का मुख्य कारण चीनी, खांडमारी और गुड़, उर्वरक, सूती वस्त्र, लोहा और इस्पात के मूल्यों में तीव्र वृद्धि है। खाद्य तेलों और सीमेंट के मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आयी।

4.43 वर्ष 1992-93 में मुद्रास्फीति दर में गिरावट औद्योगिक श्रमिकों, शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों और कृषि मजदूरों के सभी तीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के उतार चढ़ाव में प्रतिबिंबित हुआ था। अत्यंत उल्लेखनीय बात यह थी कि कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने पिछले वर्ष के 21.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में बिन्दु दर बिन्दु आधार पर केवल 0.7 प्रतिशत की अत्यल्प वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक श्रमिकों और शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की दरों में क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो पिछले वर्ष दर्ज की गयी दरों से आधी थीं। औद्योगिक श्रमिकों और शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की अधिक भारिता वर्ष की इसकी विकास दर में प्रतिबिंबित हुई थी। (परिशिष्ट सारणी 4.22)।

1993-94 की पहली तिमाही के दौरान प्रवृत्तियाँ

4.44 1992-93 की वार्षिक मुद्रास्फीति दर में देखी गयी समग्र गिरावट की प्रवृत्ति 1993-94 की प्रथम तिमाही के दौरान भी थी। सामान्य थोक मूल्य सूचकांक ने 2.4 प्रतिशत की अल्प वृद्धि दर्ज की जो 1992-93 की तुलनीय अवधि में दर्ज की गयी 3.2 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी। मूल्य स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को दो प्रमुख वस्तु समूहों अर्थात् 'प्राथमिक वस्तुओं' तथा 'विनिर्मित उत्पादों' के सूचकांकों में सामान्य स्थिति द्वारा स्पष्ट किया गया था, इस अवधि के दौरान प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांकों में गिरावट अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तथापि, 'ईंधन' समूह ने एक वर्ष पूर्व की तुलनीय तिमाही के 0.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि रिकार्ड की, सामान्य मूल्य वृद्धि के लिए पिछले वर्ष के 0.9 प्रतिशत के नगण्य अंश की तुलना में इसका योगदान 16.3 प्रतिशत की सीमा तक था। थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति का कारण खाद्य पदार्थों का अधिक स्टॉक, 1993-94 में अत्यधिक खाद्यान्न की खरीद, और चालू वर्ष में अनुकूल मानसून भी हो सकते हैं, जिन्होंने मुद्रास्फीति की संभावनाओं को मन्द कर दिया है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने 1993-94 की प्रथम तिमाही के दौरान 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 1992-93 की तदनुसूची अवधि में दर्ज 3.1 प्रतिशत से कम थी।

4.45 चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 (14 अगस्त 1993 तक) के दौरान थोक मूल्य सूचकांक ने बिन्दुवार आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 6.2 प्रतिशत दर्ज की जो पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि में दर्ज की गई 9.3 प्रतिशत से काफी कम थी।

बुनियादी कीमतें

4.46 वर्ष 1992-93 के दौरान बुनियादी बाजार से संबंधित दूरगामी स्वरूप की अनेक नीति संबंधी घोषणाएं 1397 GI/94-6

की गयी। स्मरण रहे कि 1992-93 के केन्द्रीय बजट में स्वर्ण आयात संबंधी नीति की घोषणा की गयी जिसके अंतर्गत नाममात्र भुगतान शुल्क की अदायगी पर अनिवार्य भारतीय और विदेशों से वापस आ रहे भारतीय पांच किलोग्राम तक स्वर्ण का आयात कर सकते हैं। 8 फरवरी, 1993 को सरकार ने चांदी से संबंधित एक उद्घोषित नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत प्रति किलोग्राम 500 रुपये सीमा-शुल्क की अदायगी पर भारतीय मूल के भारत में आने वाले यात्री अथवा भारतीय पारपत्र के धारक 100 किलोग्राम तक चांदी का आयात कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया गया था, 18 फरवरी 1993 को स्वर्ण बांड योजना 1993 की घोषणा की गयी थी और यह 14 जून 1993 तक तीन महीने के लिए सार्वजनिक अभिदान के लिए खली रखी गयी थी और 41.12 मीटरी टन स्वर्ण जुटाया गया था। नीति संबंधी इन उपायों से सोने और चांदी के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा। देश में स्वर्ण के मूल्य में पिछले वर्षों में जो बढ़ोतरी का रुख था, वह 1992-93 के दौरान उलट गया। स्वर्ण के औसत वार्षिक मूल्य में वर्ष की समाप्ति तथा मासिक औसत दोनों के आधार पर पिछले वर्ष के 25 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि की तुलना में 1992-93 में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। (परिशिष्ट सारणी 4.24 से 4.25) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वर्ण के मूल्य गिरावट की प्रवृत्तियां दर्शाते हुए देशी और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण के मूल्यों में बीच 1991-92 में 51.3 प्रतिशत का अंतर था, 1992-93 में आधे से भी अधिक गिरकर 23.2 प्रतिशत रहा और फरवरी 1993 में 16.5 प्रतिशत का न्यूनतम अंतर दर्ज किया।

4.47 वर्ष के दौरान, विशेषकर फरवरी, 1993 में चांदी के आयातों को अनुमति देने वाली नीति संबंधी घोषणा के बावजूद चांदी के देशी मूल्य में तीव्र गिरावट आयी। 1992-93 में वर्ष की समाप्ति के आधार पर चांदी के मूल्य में 31.7 प्रतिशत और औसत आधार पर 3.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के देशी और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में औसत वार्षिक अंतर 1991-92 के 124.2 प्रतिशत से पर्याप्त रूप से घटकर 1992-93 में 88.7 प्रतिशत रहा। मासिक आधार पर, यह अंतर जो अप्रैल 1992 में 110 प्रतिशत था, तीव्रता से गिरकर मार्च 1993 में 50 प्रतिशत रह गया।

1993-94 की पहली तिमाही के दौरान प्रवृत्तियाँ

4.48 अप्रैल और मई 1993 के दौरान मौसमी मांग में वृद्धि, स्वर्ण बांड योजना 1993 के अभिदान के लिए मांग और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उछाल के कारण स्वर्ण का मूल्य स्थिर रहा। 14 जून 1993 को स्वर्ण बांड योजना की समाप्ति और स्वर्ण के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण जून 1993 के अंत तक स्वर्ण के देशी मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति आयी। तथापि जुलाई 1993 में यह फिर से पलट गई। सोने के मूल्य में अंतर, जो बढ़कर

अप्रैल 1993 में 25.7 हो गया था, गिरकर मई 1993 में 22.2 प्रतिशत, जून 1993 में 19.1 प्रतिशत और जुलाई 1993 में 15.3 प्रतिशत आ गया। चांदी का मूल्य जो देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अप्रैल तथा मई 1993 के दौरान बढ़ गया था, जून 1993 में तुरंत पड़ गया। तथापि, जुलाई 1993 में देशी और अंतर्राष्ट्रीय कीमत-लागत के अंतर के 27.6 प्रतिशत तक गिर जाने के फल-स्वरूप उसमें भारी तेजी आयी।

V. पूंजी बाजार की गतिविधियाँ

5.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राथमिक बाजार ने नये पूंजी निर्गमों की संख्या और राशि दोनों ही की गति-विधियों में एक उछाल देखा। फिर भी, गौण बाजार ने सामान्यतः गिरावट की स्थितियाँ महसूस कीं। मीयादी पूंजीगत वित्तपोषण में भी भारी वृद्धि हुई।

मीयादी वित्तपोषण और निवेश संस्थाओं के कार्यकलाप

5.2 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1992-93 (अप्रैल-मार्च) के लिए दी गयी 29,809 करोड़ रुपये की मंजूरीयों (अंतर-संस्थागत प्रवाहों का निवल) ने पिछले वर्ष के 24.5 प्रतिशत की तुलना में 34.9 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्शायी (परिशिष्ट सारणी 5.1)। उक्त अवधि के दौरान संवितरण पिछले वर्ष के 34.6 प्रतिशत की तुलना में 34.8 प्रतिशत बढ़ गये। निवेश संस्थाओं (भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम) ने 1992-93 (अप्रैल-मार्च) के दौरान अपनी मंजूरीयों और संवितरणों में पर्याप्त वृद्धि अनुभव की। अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाएं इस संबंध में समन्वय की समस्या का सामना करती रही हैं क्योंकि गारंटीकृत बांडों के माध्यम से उनके रियायती संग्राहनों में कमी की गयी है और रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन प्रवर्तनों का आवंटन समाप्त कर दिया गया है। इस स्थिति के होने हुए, वित्तीय संस्थाओं को अपने संसाधनों के लिए बाजार में पहुंचने की अधिकाधिक आवश्यकता हुई है। इसके अनुक्रम में वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों को एक नया स्वरूप देना होगा।

कंपनी निवेश पूर्वानुमान

5.3 रिजर्व बैंक, डॉ सी० रंगराजन द्वारा विकसित पद्धति के अनुसार कंपनी निवेश के पूर्वानुमान (वित्तीय वर्ष के आधार पर) बनाता रहा है जो कुल मिलाकर सही सिद्ध हुए हैं। निजी कंपनी क्षेत्र के निवेश के पूर्वानुमान के संबंध में नवीनतम अध्ययन ने यह अनुमान लगाया गया है कि 1992-93 के दौरान अंकित रूप में कुल 25,335 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया होगा। बिल पुनर्मुनाई योजना के अन्तर्गत 436 करोड़ रुपये की और तकनीकी विकास निधि योजना के अंतर्गत 23 करोड़ रुपये की सहायता को सम्मिलित करते हुए पूंजीगत व्यय 25,794 करोड़ रुपये होगा जिससे 1991-92 के दौरान हुई 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में उक्त वर्ष के दौरान 29.7 प्रतिशत की वृद्धि निर्विष्ट होती है। वास्तविक रूप में अर्थात् 1980-81

के मूल्यों पर, कुल निवेश 1992-93 में 11,051 करोड़ रुपये रहा जिससे 1991-92 में हुई 4.3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। 1992-93 के दौरान कुल मिलाकर निजी कंपनी क्षेत्र (संयुक्त क्षेत्र को मिलाकर) में 1,175 परियोजनाओं को प्रमुख मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम) द्वारा सहायता मंजूर की गयी। नयी परियोजनाओं को 29.1 प्रतिशत का सबसे बड़ा भाग (259 परियोजनाओं के लिए 7,521 करोड़ रुपये) मिला। 1992-93 के दौरान उद्योगवार वितरण के स्वरूप में सुस्पष्ट व्यतिक्रम था। सभी परियोजनाओं की कुल लागत में रसायनों और पेट्रो-रसायनों का अंश 27.8 प्रतिशत पर (142 परियोजनाओं के लिए 7,186 करोड़ रुपये) सबसे अधिक रहा एवं इसके बाद जूट को छोड़कर वस्त्र उद्योग का स्थान था जिसका अंश 16.6 प्रतिशत (212 परियोजनाओं के लिए 4,295 करोड़ रुपये) रहा। धातुओं और धातुओं से बनी वस्तुओं का स्थान तीसरा रहा जिसका अंश 16.1 प्रतिशत (135 परियोजनाओं के लिए 4,161 करोड़ रुपये) था। पिछले वर्ष में धातुओं और धातुओं से बनी वस्तुओं का अंश 39.0 प्रतिशत था जिनके बाद रसायनों और पेट्रो-रसायनों (10.0 प्रतिशत) तथा जूट को छोड़कर वस्त्र उद्योग (9.6 प्रतिशत) का स्थान रहा।

नया निर्गम बाजार

5.4 पूंजी निर्गम नियंत्रक के पद को 29 मई, 1992 से समाप्त करने के कारण सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों ने प्रस्ताव प्रलेखों की मंजूरी की मांग भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) से की। पूंजी निर्गम नियंत्रक (अप्रैल-मई 1992) और सेबी (जून 1992-मार्च 1993) दोनों के द्वारा अनुमोदित कुल राशि (प्रीमियम और बोनस शेयरों सहित सहमतियाँ एवं अभिस्वीकृतियाँ) गैर-सरकारी कंपनियों के लिए 20,841 करोड़ रुपये और सरकारी कंपनियों के लिए 380 करोड़ रुपये थी (परिशिष्ट सारणी 5.2)।

5.5 1992-93 के दौरान गैर-सरकारी सार्वजनिक सीमित कंपनियों द्वारा नये निर्गमों के संबंध में प्राथमिक पूंजी बाजार ने 1991-92 में हुई 33.5 प्रतिशत की तुलना 244.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की (परिशिष्ट सारणी 5.3)। इस उछाल के लिए प्रमुख रूप से 29 मई, 1992 से पूंजी निर्गम नियंत्रण की समाप्ति और नीतिगत सामान्य स्थिति को कारण माना जा सकता है। 1992-93 के दौरान कुल पूंजीगत निर्गम, इक्विटी शेयरों और डिबेंचरों के बीच प्रायः समान रूप से विभाजित थे। नये पूंजीगत निर्गमों में अपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गमों और अधिकार निर्गमों की प्रधानता रही।

5.6 वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय विशेषता थी, कुल नये पूंजीगत निर्गमों के 45.3 प्रतिशत के समकक्ष

8,973 करोड़ रुपये की रिकार्ड राशि के लिए 34 बृहत् निर्गम (प्रत्येक 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक का निर्गम) जारी करना, जबकि पिछले वर्ष में ये 34.5 प्रतिशत बनाते हुए 1,985 करोड़ रुपये (9 बृहत् निर्गम) के जारी किये गये थे।

5.7 वर्ष 1992-93 ने उच्च प्रीमियम से युक्त ईक्विटी निर्गमों का आधिक्य भी, विशेषकर अधिकार निर्गमों के रूप में देखा। प्रीमियम सहित 324 ईक्विटी निर्गम जारी हुए थे जबकि 1991-92 में इस प्रकार के 58 निर्गम जारी किये गये थे। 5,184 करोड़ रुपये का कुल प्रीमियम कुल ईक्विटी निर्गमों का 51.9 प्रतिशत बना जबकि 1991-92 के दौरान यह 227 करोड़ रुपये अथवा 13.1 प्रतिशत था। 1993-94 की पहली तिमाही में ईक्विटी शेयरों के माध्यम से नये निर्गमों की 2,287 करोड़ रुपये की राशि 1992-93 की तदनुसूची तिमाही की तुलना में 23.7 प्रतिशत बढ़ गई और यह वृद्धि प्रमुखतः प्रीमियम के कारण थी।

5.8 पूंजी बाजार में एक और महत्वपूर्ण गतिविधि थी, नये निर्गमों के लिए अधिक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु विशेष लक्षणों से युक्त नवीन संकर लिखत जैसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों से संबद्ध वारंट, शून्य-श्याज वाले परिवर्तनीय बांड, वारंटों के साथ संबद्ध ईक्विटी, वारंटों के साथ संबद्ध जमानती प्रीमियम नोट और सघन भुनाई बांड प्रचलित करना। 1992-93 के लिए उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इस प्रकार से संकर/नवीन लिखतों के माध्यम से 4,703 करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये जबकि 1991-92 में यह राशि 198 करोड़ रुपये थी। 1992-93 में एक और विशेषता थी—निर्गमों का समूहन। सितम्बर—नवंबर 1992 के दौरान कुल 8,518 करोड़ रुपये के 317 निर्गम जारी किये गये जो कुल पूंजीगत निर्गमों का 43.0 प्रतिशत बने थे।

5.9 हाल ही की अवधि में प्राथमिक निर्गमों का पूर्णतः अभिदान किये जाने के संबंध में कठिनाई रही है तथा ऐसी समस्याएं रही हैं जहां बड़े पैमाने पर हामीदारों पर निर्भर रहना पड़ा जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं के साथ इन निर्गमों को बढ़ते पर लेने की व्यवस्था की। इन विषयों पर भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

ईक्विटी मूल्य

5.10 पिछले वर्ष के दौरान जो अश्रुतपूर्व उल्लावकता विद्यमान थी उसके असमान शेयर बाजार 1992-93 के अधिकतर भाग के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति के अधीन रहे। वर्ष 1992 में मार्च के अंत में और अप्रैल के प्रारंभ में ईक्विटी मूल्य जिस उच्च स्तर पर पहुंच गये थे वह लेनदेनों में अनियमितताओं, जिनमें बैंक, वित्तीय संस्थाएं और शेयर दलाल संबद्ध थे, प्रकाश में आने के बाद स्थिर नहीं रह

सका। उसके बाद शेयर बाजारों ने अगस्त 1992 के मध्य तक शेयर मूल्यों में निरंतर गिरावट महसूस की। सितम्बर 1992 में स्थिति में अल्प सुधार होने के बाव ईक्विटियों में पुनः अधोमुखी प्रवृत्ति आयी जो जनवरी 1993 तक रही। शेयरों के मूल्यों में फरवरी 1993 में बढ़ि हुई परन्तु वह कम समय के लिए ही रही। सामान्य शेयर मूल्यों (आधार: 1980-81=100) के भारतीय रिजर्व बैंक अखिल भारतीय सूचकांक (साप्ताहिक) जो 28 मार्च 1992 को समाप्त सप्ताह में 1485.4 थे, कम होकर 29 अगस्त 1992 को समाप्त सप्ताह में 1,134.2 रहे तथा मार्च 1993 के अंत तक उनकी अंतिम स्थिति 892.1 रही (परिणित सारणी 5.4)। बंबई शेयर बाजार सूचकांक (1978-79=100) ने भी ऐसी ही प्रवृत्ति दर्शायी है (ग्राफ 6)।

5.11 1992-93 के लिए 1,142.1 पर स्थित रिजर्व बैंक के औसत सूचकांक ने 1991-92 के दौरान 55.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 47.1 प्रतिशत का लाभ दर्शाया। फिर भी, बिन्दुवार आधार पर उक्त सूचकांक ने 28 मार्च 1992 का समाप्त सप्ताह में विद्यमान 1,485.4 से 27 मार्च 1993 को समाप्त सप्ताह में स्थित 892.1 तक 39.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जबकि पिछले वर्ष में 181.4 प्रतिशत का पर्याप्त लाभ हुआ था। उद्योग-वार विश्लेषण से यह विदित होता है कि केवल अल्पमिनियम समूह के शेयरों के अपवाद को छोड़कर जिनमें 6.5 प्रतिशत का लाभ हुआ, सभी उद्योग समूहों को भारी हानि हुई। 66.2 प्रतिशत की अधिकतम हानि सीमेंट समूह के शेयरों को उठानी पड़ी तथा उसके बाद का स्थान रबड़ उत्पादों (63.6 प्रतिशत) एवं मानव निर्मित रेशों (59.2 प्रतिशत) का रहा।

5.12 बम्बई शेयर बाजार के संबंध में उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि सभी प्रमुख निर्देशकों अर्थात्—बाजार के आलत, बाजार पूंजीकरण और कीमत-कमाई अनुपात ने वर्ष 1992-93 के दौरान गौण बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। 1992-93 के दौरान 3,807 करोड़ रुपये का औसत मासिक आवर्त पिछले वर्ष (5,981 करोड़ रुपये) की तुलना में 36.3 प्रतिशत कम था। मार्च 1993 की समाप्ति पर बाजार पूंजीकरण संबंधी बंबई शेयर बाजार के आंकड़े कुल 2,10,952 करोड़ रुपये (अनंतिम) थे जो 12 महीने पहले के 3,23,363 करोड़ रुपये की तुलना में 34.8 प्रतिशत कम थे। कीमत-कमाई अनुपात से सितम्बर 1992 और फरवरी 1993 में अल्पकालीन उछालों को छोड़कर अप्रैल 1992 से निरंतर गिरावट देखी गई। औसत कीमत—कमाई अनुपात (बंबई शेयर बाजार) के अस्थिर सूचकांकों में सम्मिलित 30 स्क्रिप्सों के लिए परिकलित (आधार: 1978-79=100) जो अप्रैल 1992 में 52.6 था, मार्च 1993 में 29.3 तक कम हो गया। मार्च 1993 के स्तर पर भी उक्त कीमत—कमाई अनुपात

अन्य देशों के कई बाजारों में विद्यमान कीमत—कमाई अनुपात की तुलना में अधिक माना जाता है।*

5.13 घट-बढ़ के गणक के आधार पर नापी गई शेयर मूल्यों की अस्थिरता पिछले वर्ष की तुलना में 1992-93 के दौरान कम थी। सूचकांक के घट-बढ़ का गुणक 1991-92 में विद्यमान 27.0 प्रतिशत के मुकाबले 1992-93 के दौरान 16.2 प्रतिशत पर पर्याप्त रूप से कम था। सूचकांक में वियोजन (उच्च और निम्न के बीच का अंतर) पिछले वर्ष में विद्यमान 948.5 की तुलना में 764.8 पर निम्नतर था।

5.14 1993-94 की पहली तिमाही के दौरान प्रतिभूति बाजार की गतिविधियों में लगातार गिरावट रही। जून 1993 की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक सूचकांक मार्च 1993 की समाप्ति पर विद्यमान 892.1 के मुकाबले 850.6 रहे। बंबई शेयर बाजार के संवेदनशील सूचकांक ने भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्शायी।

विदेशी संस्थागत निवेशक

5.15 देश में विदेशी संस्थागत निवेश के अधिक आगमन को आकर्षित करने के लिए वर्ष के दौरान उठाये गये अनेक कदम खंड-1 में दर्शाये गये हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 1993 तक 56 विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति प्रदान की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशों को और अधिक आकर्षित करने के लिए 1993-94 के बजट में कर-प्रोत्साहन रखे गये। अल्पावधि पूंजीगत अभिलाष कर 30 प्रतिशत तक घटा दिया गया जबकि लाभांश आय पर 20 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। इनके कारण भारतीय बाजार का स्थान विश्व के कई देशों के साथ तुल्य स्थिति में होगा।

भारतीय ओवर द काउन्टर एक्सचेंज

5.16 ओटीसी एक्सचेंज ने 6 अक्टूबर 1992 से अपने कार्यकलाप प्रारंभ किये। मार्च 1993 के अंत तक भारतीय ओटीसी एक्सचेंज के पास 7 स्क्रिप सूचीबद्ध किये गये थे। चूंकि भारतीय ओटीसी एक्सचेंज का मासिक आवर्त जो अक्टूबर 1992 में 17 लाख रुपये था, जून 1993 के दौरान बढ़कर 106 लाख रुपये हो गया, अतः भारतीय ओटीसी एक्सचेंज ने अपने व्यापार के लाभ, निवेशकों को अन्य एक्सचेंजों के पास वर्तमान में सूचीबद्ध शेयरों के लिए देने का निर्णय किया है। जून 1993 की समाप्ति पर भारतीय ओटीसी एक्सचेंज के पास 8 स्क्रिप सूचीबद्ध थे। यह अनुमान है कि 25 अनुमत प्रतिभूतियों के संबंध में व्यापार बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। भारतीय ओटीसी एक्सचेंज ने अनिवार्य शेयर संतुलनकर्ता के रूप में मूलभूत संरचना पट्टेदारी और वित्तीय सेवाओं (आई एल एण्ड एफ एस) के साथ

ऋण लिखतों में व्यापार 20 मई, 1993 से प्रारंभ किया है। भारतीय ओटीसी एक्सचेंज द्वारा दिल्ली और मद्रास में शुरू करके कलकत्ता और अन्य महानगरीय क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय पटल खोलने की प्रक्रिया जारी है।

भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लि०

5.17 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार, भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि० तथा मूलभूत संरचना पट्टेदारी और वित्तीय सेवाएं (आई एल एण्ड एफ एस) द्वारा प्रवर्तित भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लि० कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में 27 नवम्बर 1992 को नियमित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लि० को भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक तौर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 26 अप्रैल 1993 में मान्यता प्रदान की गयी। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लि० का मुख्य उद्देश्य स्वचालित स्क्रीन-प्राधारित व्यापार और स्वचालित व्यापारोत्तर समाशोधन और निपटान सुविधाओं के माध्यम से निवेशकों को विस्तृत राष्ट्र-व्यापी प्रतिभूति व्यापार सुविधा सुनिश्चित करना है। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लि० कंपनी व्यापार वाले सदस्यों को व्यापारी नेटवर्क, कंप्यूटरीकृत व्यापार और अल्पकालीन निपटान चक्रों के साथ प्रोत्साहित करता रहेगा। उसका दो खंडों में कार्य करने का प्रस्ताव है, जिनमें से एक खंड थोक ऋण लिखतों के संबंध में और दूसरा खंड पूंजी बाजार लिखतों के संबंध में कार्य करेगा। भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि० द्वारा स्थापित की जाने हेतु प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और निपटान प्रणाली (ई सी डी एस) अपेक्षित समाशोधन और निपटान प्रणालियां उपलब्ध करायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड

5.18 1992-93 के दौरान 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बांडों/डिबेंचरों के माध्यम से 6,291 करोड़ रुपये की राशि जुटानी थी, परन्तु अंतिम जानकारी के अनुसार 1991-92 में जुटाए गये 5,211 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 1,062 करोड़ रुपये ही जुटाये गये (सारणी 5.1)। प्रतिभूतियों से संबंधित अनियमितताओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के बाजार में विद्यमान प्रमुख दुर्बलताएं भली-भांति उजागर हुईं। उक्त निर्गम अनिवार्यतः पुनः खरीद परिचालनों (रेपों) के तंत्र के माध्यम से बहुत ही अल्पकालीन मुद्रा बाजार निधियों पर निर्भर होते हैं और चूंकि एक बार प्रतिभूतियों से संबंधित अनियमितताओं के प्रकाश में आने के बाद यह बाजार उपलब्ध नहीं था, अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बांड जारी करना वास्तव में संभव नहीं था। 1993-94 के लिए

* 1991 की समाप्ति पर कीमत—कमाई अनुपात फ्रांस में 12.70, अमेरिका में 21.70 रहा।

जर्मनी में 15.10, युनाइटेड किंगडम में 15.20 और संयुक्त राज्य

संघ के बजट में यह निर्दिष्ट किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बांडों/डिबेंचरों के माध्यम से 6,882 करोड़ रुपये जुटावेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के बाजार को सामान्य बनाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। बांडों के उचित और समय पर निर्गम की गतिविधि, पर्याप्त नकदी की व्यवस्था तथा व्यापार की एक सुस्पष्ट प्रणाली जिससे 1993-94 के दौरान वे अपने संसाधनों को मांग पूरी कर सकें।

सारणी 5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1985-86 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान बांडों का निर्गम

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कर मुक्त बांड	कर योग्य बांड	कुल (2+3)
1	2	3	4
1985-86	--	353.7	353.7
1986-87	898.0	776.1	1,674.1
1987-88	1,737.3	946.9	2,684.2
1988-89	2,080.0	417.7	2,497.7
1989-90	2,597.0	1,132.0	3,729.0
1990-91	2,345.0	3,118.1	5,463.1
1991-92	2,368.6	2,842.2	5,210.8
1992-93	10.5	1,052.0	1,062.5

स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों से प्राप्त विवरणियाँ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का विनिवेश

5.19 भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम सुधार के पैकेज के एक भाग के रूप में 1991-92 के दौरान विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। यह प्रक्रिया 1992-93 में जारी रही। 1991-92 के दौरान 31 सार्वजनिक उद्यमों में कुल पूंजी के 5 से 20 प्रतिशत तक के समान ईक्विटियों का विनिवेश दो चरणों में दिसम्बर 1991 और फरवरी 1992 में किया गया। उक्त वर्ष के दौरान विनिवेश से की गयी वसूली की राशि कुल 3,038 करोड़ रुपये थी।

5.20 वर्ष 1992-93 के लिए संघ के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश का 3,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य के मुकाबले 1,866 करोड़ रुपये की राशि दो भागों में अक्तूबर 1992 और दिसम्बर 1992 में वसूल की गयी। मार्च 1993 के दौरान तीसरे अंश में प्राप्त सभी बोलियाँ इस कारण से अस्वीकृत की गईं कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मंदर्भ मुक्तियों से कम थीं। 1993-94 के लिए संघ के बजट में विनिवेश के माध्यम से 3,500 करोड़ रुपये की वसूली करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश के संबंध में गठित समिति द्वारा दिये गये सुझाव

के अनुसार कार्य योजनाएं बनाना आवश्यक होगा। (बाक्स IV देखें)।

सारणी 5.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का विनिवेश

वर्ष	विक्रीत शेयरों की संख्या	कुल वसूली (करोड़ रु.)	औसत वसूली (करोड़ रु.)
1	2	3	3
1991-92			
1. पहला भाग	51.62	1,427	2765
2. दूसरा भाग	35.59	1,611	45.25
1992-93			
1. पहला भाग	12.87	682	53.00
2. दूसरा भाग	31.06	1,184	38.10

बाक्स IV

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों के विनिवेश के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट

डॉ० सी० रंगराजन की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश के संबंध में गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1993 में प्रस्तुत की। उक्त समिति के विचारार्थ विषय थे: (क) 1992-93 के दौरान विनिवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के चयन हेतु मानदंड बनाना, (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के इस प्रकार के उद्यमों के संबंध में विनिवेश की जाने वाली ईक्विटी के प्रतिशत संबंधी सीमाओं के विषय में परामर्श देना, (ग) लक्ष्य-ग्राहकों के संबंध में सुझाव देना, (घ) विनिवेश की कार्य-प्रणाली सुझाना, (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ईक्विटी शेयरों के मूल्य-निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित करना, और (च) अन्य संगत सिफारिशें करना। उक्त रिपोर्ट की कुछ प्रमुख सिफारिशें यहां प्रस्तुत की जाती हैं।

यद्यपि उक्त रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत किये जाने तक 1992-93 समाप्त हो चुका था, तथापि समिति ने 1992-93 के दौरान विद्यमान विनिवेश की स्थिति और अपनानी गयी नीतियों को ध्यान में रखा। यह मामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि किसी पब्लिक इश्यू को जनसामान्य को ओकर किया जाना एक सर्वाधिक वांछनीय कदम होगा, हालांकि यदि समय और बाजार की परिस्थितियों के कारण ऐसा किया जाना संभव न हो सके तो पब्लिक इश्यू जारी किये जाने जैसा ही कोई बोलो लगाने संबंधी तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

समिति ने यह पाया कि सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की ईक्विटी में विनिवेश के लक्ष्यों को मोटे तौर पर निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। समिति की राय में, विनिवेश के स्तर की सीमाएं मध्यावधि में प्रत्येक उद्यम में सरकार के स्वामित्व के लक्ष्य-स्तर से प्राप्त की गयी है। उसने स्वामित्व के निम्नलिखित लक्ष्य-स्तरों पर विचार किया। सार्वजनिक

क्षेत्र के लिए आरक्षित यूनितों के संबंध में 51 प्रतिशत जिससे प्रबंधन पर नियंत्रण रखा जा सके; और प्रधान हिस्से वाले उद्यमों अथवा कार्यनीतिगत कारणों से अलग पहचान की आवश्यकता के अपवादात्मक मामलों में 26 प्रतिशत। समिति ने महसूस किया कि सरकार उत्कृष्ट भविष्य और उच्च संवृद्धि संभावना से युक्त उद्यमों में कुल ईक्विटी के 26 प्रतिशत से अधिक वृद्धि धारण करें। उसने सिफारिश की कि ईक्विटी आधार के वांछनीय स्तर एवं सरकार के स्वामित्व के लक्ष्यित स्तर का निर्णय ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाए जैसे विस्तार, आधुनिकीकरण, तकनीकी सहयोग के लिए अखिरत निवेश योजनाओं का अनुमान, अतिरिक्त ऋण अथवा विस्तारित ईक्विटी के माध्यम से इस प्रकार के विस्तार के वित्तपोषण का स्वरूप, वर्तमान ऋण-ईक्विटी संरचना और इन दोनों घटकों में से किसी भी एक घटक की वृद्धि के लिए गुंजाइश एवं पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए परिवर्तनीय बांड जारी करने की संभाव्यता। समिति ने देय, प्राप्य बड़ी बकाया राशियों, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए सभी तौर-तरीकों और लेखा-प्रक्रियाओं के निपटान एवं सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के लिए एक वाणिज्यिक बैंकर की नियुक्ति की भी सिफारिश की।

समिति ने सिफारिश की कि यदि एक समुचित समयावधि के दौरान, एक सामान्य कारोबारी माहौल में एक उल्लेखनीय बाजार मूल्य एक बार स्थापित हो जाए तथा कोई सार्वजनिक उद्यम तैयारी संबंधी कार्य एक बार पूरा कर ले तो निर्धारित मूल्य पद्धति का अपनाया जाना ही सर्वाधिक उपयोगी होगा। यह भी सिफारिश की गयी है कि प्रत्येक उद्यम के लिए विनिवेश की योजना और कार्यान्वयन अलग से किया जाना चाहिए तथा विक्रय की कार्य-प्रणाली बनाने के लिए एक वाणिज्यिक बैंकर नियुक्त किया जाना चाहिए। निर्गम के समय और मध्यवर्ती के चयन सहित एक उद्यम विशिष्ट दृष्टिकोण का समिति ने समर्थन किया। यह भी सिफारिश की गयी कि सरकार द्वारा प्राप्तियों का 10 प्रतिशत अलग रखा जाए और वह सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों को उनके विस्तार, युक्तिकरण की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रियायती शर्तों पर उधार दिया जाए।

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ईक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के संबंध में समिति ने महसूस किया कि बट्टागत नकद प्रवाह सर्वाधिक संगत होगा, यद्यपि इसे कार्यान्वित करना सबसे कठिन है। उसने सिफारिश की कि आय-उत्पादन न करने वाली आस्तियों की बिक्री और श्रम-शक्ति का युक्तिकरण करने के लिए गुंजाइश और सीमाओं का सुनिश्चित निर्धारण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति ने यह चेतावनी दी कि भावी लाभप्रदता को प्रभावित करने वाली नीतियों (जैसे प्रतिफल की गारंटीकृत दर) का विस्तार केवल निवेशकों के प्रति शेयरों की त्वरित आकर्षणशीलता की अपेक्षा आर्थिक कुशलता पर ऐसे आपवासनों के निहितार्थों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही किया जाए। उसने यह भी सिफारिश की कि जहां भी सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से

विनिवेश किया जाता है, वहां कीमत का निर्धारण निर्गम को बाव के प्रस्ताव के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक सफलता के रूप में प्रक्षेपित करने की आवश्यकता के सूक्ष्म मूल्यांकन के साथ और साथ ही न्यून कीमत-निर्धारण की आलोचना से बचते हुए करना आवश्यक होगा।

लक्ष्य-ग्राहकों के संबंध में समिति ने सिफारिश की कि बाजार मूल्य पर बड़े सहित खरीदे जा सकने वाले शेयरों की संख्या पर उच्चतम सीमा के साथ उनमें जनसाधारण, पारस्परिक निधियों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को तथा विशेष परिस्थितियों में अन्य स्टैकहोल्डरों की एक आरक्षित श्रेणी को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन करने के बाद और हमारी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय पुनर्संरचना, स्वामित्व के विविधीकरण के मसले और मध्यावधि कंपनी योजना जैसे क्षेत्रों में विनिवेश के लिए तैयारी के उपाय करने में सार्वजनिक उद्यमों और सरकार का मार्गदर्शन करने हेतु सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश संबंधी एक स्थायी समिति स्थापित करने की सिफारिश की।

समिति ने विनिवेश की प्राप्तियों के भाग का उपयोग न केवल राष्ट्रीय नशीकरण निधि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 10 प्रतिशत के प्रोत्साहन, और सरकारी ऋण में कटौती हेतु, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, स्वास्थ्य और रोजगार का उत्पादन जैसे सामाजिक क्षेत्रों को संसाधनों के निवेश के लिए भी करने की सिफारिश की।

शेयर संतुलनकर्ताओं (मार्केट मेकर्स) के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

5.21 कुछ प्रमुख शेयर बाजारों शेयर संतुलनकर्ताओं के प्रवर्तन के बारे में खंड 1 में उल्लेख किया गया है। जो शेयर संतुलनकर्ता प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के लिए द्विपक्षवर्ती भाव (कोटेशन) प्रस्तुत करते हैं वे स्क्रिपों को नकदी प्रदान करते हैं और शेयर मूल्यों की गतिविधियों में अस्थिरता को कम करने में सहायता करते हैं। शेयर संतुलनकर्ताओं का अनुमोदन भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा संबंधित शेयर बाजारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अपने कार्य-कलापों को करने के लिए शेयर संतुलनकर्ताओं को बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता अपेक्षित होगी। रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं।

(i) सेबी द्वारा जिन शेयर संतुलनकर्ताओं का अनुमोदन किया गया है वे अग्रिम प्रदान करने हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संपर्क करने के लिए पात्र होंगे।

- (ii) शेयर संतुलनकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करते समय अनुसूचित वाणिज्य बैंक कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में अपने वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करें।
- (iii) शेयर संतुलनकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करते समय बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर सामान्य विवेकपूर्ण मार्जन निर्धारित करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि शेयरों, डिबेंचरों बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋणों पर 50 प्रतिशत का वर्तमान न्यूनतम मार्जिन, शेयर संतुलनकर्ताओं को दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों के विषय में लागू नहीं होंगे।
- (iv) इस प्रकार के अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज दर उधार ली गई राशि पर निर्भर होगी। बैंक 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं पर ब्याज-दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं जो वर्तमान में न्यूनतम 16 प्रतिशत हैं।
- (v) शेयर संतुलनकर्ताओं को दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए बैंक उस स्क्रिप को छोड़कर जिममें शेयर संतुलन कार्य किये जा रहे हों, अन्य स्क्रिपों को समर्थक ऋणाधाय के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।
- (vi) शेयर संतुलनकर्ताओं को ऋण सीमाओं का निर्धारण, बैंकों द्वारा शेयर संतुलन कार्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
- (vii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयर संतुलन के लिए प्रदत्त अग्रिमों का विपथन, शेयर संतुलन के प्रयोजन के लिए निर्धारित स्क्रिप को छोड़कर अन्य स्क्रिपों में निवेश के लिए न किया जाए। इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त अनुवर्तन और निगरानी का तंत्र अनिवार्यतः विकसित किया जाए।
- (viii) वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत यह शर्त रखी गयी है कि एकल उधारकर्ता को आकस्मिक व्यय और निजी स्वरूप की आवश्यकताओं के लिए अथवा अधिकारों या शेयरों, डिबेंचरों के नये निर्गमों हेतु अभिदान के लिए अथवा वर्तमान शेयरों, डिबेंचरों, बांडों की जमानत पर गौण बाजार संबंधी खरीद के लिए ऋण प्रदान किये जा सकते हैं जो 5 लाख रुपये से अधिक न हों। 5 लाख रुपये की यह उच्चतम सीमा शेयर संतुलनकर्ताओं पर लागू नहीं होगी।

5.22 सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर संतुलनकर्ता (मार्केट मेकर) से यह अपेक्षा होगी कि वह कम से कम पांच स्क्रिपों के लिए बाजार बनाये, प्रारंभ में ऐसे स्क्रिपों के लिए जो

बंबई शेयर बाजार राष्ट्रीय सूचकांक में सम्मिलित नहीं हैं प्रत्येक शेयर संतुलनकर्ता से यह अपेक्षित होगा कि वह प्रत्येक स्क्रिप में कम से कम 30,000 शेयर अर्जित करें।

गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र की जमाराशियों की वृद्धि संबंधी प्रवृत्तियां

5.23 सूचना देने वाली 12,817 गैर-बैंकिंग कंपनियों की कुल जमाराशियों में संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं और केवल 1991-92 तक ही उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लिए 10,166 कंपनियों द्वारा सूचित 11,730 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में मार्च 1992 की समाप्ति तक उक्त जमाराशियां 8,298 करोड़ रुपये बढ़कर 53,559 करोड़ रुपये हो गयीं। मार्च 1992 की समाप्ति पर, सूचना देने वाली कंपनियों की कुल विनियमित जमाराशियों में 9,269 करोड़ रुपये के प्रसाधारण स्तर के साथ 1,362 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि छूट-प्राप्त जमाराशियों में पिछले वर्ष में हुई 10,581 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की तुलना में 6,936 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। सूचना देने वाली कंपनियों की छूट-प्राप्त जमाराशियां मार्च 1992 के अंत तक 44,290 करोड़ रुपये थी। सूचना देने वाली कंपनियों की कुल जमा राशियों में से एक ओर जहां गैर-वित्तीय कंपनियों का प्रतिशत 52.8 था, वहीं दूसरी ओर वित्तीय कंपनियों का प्रतिशत 41.5 रहा। विविध और अवशिष्ट गैर-वित्तीय कंपनियों का अल्प अंश दोनों को मिलाकर 5.7 प्रतिशत रहा (परिशिष्ट सारणी 5.5)। 20 मार्च 1992 की स्थिति के अनुसार वित्तीय कंपनियों की विनियमित जमाराशियां सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों के 4.0 प्रतिशत के मगलक्ष थीं।

VI. बाह्य क्षेत्र की गतिविधियां

6.1 भुगतान संतुलन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया 1992-93 के दौरान भी जारी रखी गयी। उदारीकृत विदेशी मुद्रा विनियम दर प्रबंधन प्रणाली में स्वतः संतुलन व्यवस्था मूर्तरूप होने और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतों से विशिष्ट वित्तपोषण की वजह से 1992-93 में देश के अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित भण्डार में 612 मिलियन अमरीकी डालर जमा हो गये। मार्च 1993 के अंत तक बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां 6,434 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गयी थीं। कृषि क्षेत्र में भारी सुधार के वावजूद संरचनात्मक सुधारों के प्रोत्साहन में तेजी लाने के लिए संपदा क्षेत्रों की प्रतिक्रिया आशा से कहीं कम रही। देश में सामाजिक उपद्रवों और विशेषकर बम्बई में जो मोटे तौर पर भारत के विदेशी व्यापार संबंधी लगभग 60 प्रतिशत यातायात सेवाओं के लिए उत्तरदायी है, से वित्तीय वर्ष की, दूसरी छमाही में आयातों और निर्यातों में सामान्यता होने वाली मौसमी वृद्धि में रुकावट आयी। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के घटकों के साथ किए गए बाह्य लेनदेनों में छापी अनिश्चितता और औद्योगिक राष्ट्रों में लगातार बनीं

रही मंदी के परिप्रेक्ष्य में व्यापार विविधीकरण में आयी बाधा, ऐसी बाह्य विपरीत गतिविधियां थीं जिनका बाह्य क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा।

भुगतान संतुलन

6.2 अब वर्ष 1990-91 तक के प्राथमिक भुगतान संतुलन संबंधी अंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 1991-92 के लिए अंतिम प्राक्कलन उपलब्ध है जो वास्तविक आंकड़ों के करीब ही हैं। वास्तविक आंकड़ों की उपलब्धता के अंतर को पूरा करने के लिए वर्ष 1992-93 के लिए उपलब्ध सूचना के आधार पर त्वरित आंकड़े तैयार किए गए हैं (सारणी 6.1, 6.2 और परिशिष्ट सारणी 6:1)।

6.3 वर्ष 1990-91 से 1992-93 के भुगतान संतुलन के आंकड़े उस फॉर्मेट में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आयातों

के वर्ष में, रक्षा संबंधी आयातों का मूल्य आयातों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और जिन ऋणों से ऐसे आयातों का वित्त पोषण होता है, उन्हें पूंजीगत खाते में दर्शाया जाता है। सामान्य मुद्रा क्षेत्र से लिए गये रक्षा संबंधी ऋण पर जब-जब भी ब्याज भुगतान किये जाते हैं उन्हें श्रद्धा खाते में निवेश आय भुगतान शीर्षक के अंतर्गत तथा वाणिज्य उधारों के परिपोषण के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख चुकौतियों को पूंजीगत खाते में दर्शाया जाता है। रुपया भुगतान क्षेत्र के मामले में, ऋण की किसी प्रमुख चुकौती पर किए जाने वाले ब्याज भुगतान को आपस में मिला दिया जाता है और उसे पूंजीगत खाते में 'रुपया ऋण सेवा' नामक मद के अंतर्गत अलग दर्शाया जाता है। यह भुगतान संतुलन संबंधित उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष: डा० सी० रंगराजन) की सिफारिशों के अनुरूप है।

सारणी 6.1 भारत का समग्र भुगतान संतुलन

मद	अमरीकी मिलियन डालर			करोड़ रुपए		
	1992-93 (त्वरित आंकड़े)	1991-92 (अंतिम प्राक्कलन)	1990-91	1992-93 (त्वरित आंकड़े)	1991-92 (अंतिम प्राक्कलन)	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
क. चालू लेखा						
1. निर्यात, पोतपर्यंत निःशुल्क	18,789	18,223	18,477	54,418	44,923	33,153
2. आयात, लागत बीमा भाड़ा	22,895	20,347	27,914	65,945	50,159	40,086
3. व्यापार शेष	-1,106	-2,124	-9,437	-11,527	-5,236	-16,933
4. चालू खाता शेष*						
ख. कुल पूंजीगत लेखा	-4,921	-2,135	-9,857	-13,533	-5,186	-17,686
अ०मु०को० और वि० आ० अधि० आबंटन						
ग. आरक्षित निधि और मौद्रिक	5,649	5,710	8,579	16,096	15,031	15,393
स्वर्ण (अव/घट-...)	-728	-3575	1278	-2563	-9845	2293

*भूलचूक को हिसाब में लेने के बाद। परिशिष्ट सारणी 6.1 भी देखें।

सारणी 6.2 चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू खाता जनदेन

(प्रतिशत)

मद	1992-93*	1991-92*	1990-91	7वीं पंचवर्षीय योजना (वार्षिक औसत)	छठी पंचवर्षीय योजना (वार्षिक औसत)
1	2	3	4	5	6
1. निर्यात	7.7	7.3	6.2	5.1	5.0
2. आयात	9.3	8.2	9.4	8.3	8.4
3. व्यापार घाटा	1.6	0.9	3.2	3.2	3.4
4. श्रद्धा प्राप्तियां +	3.3	3.3	2.5	2.9	3.6
5. श्रद्धा भुगतान	3.8	3.3	2.6	1.9	1.5
6. श्रद्धा (निवल) (4-5) +	-0.5	0.0	-0.1	0.9	2.1
7. चालू खाता घाटा (3-6) +	2.1	0.9	3.3	2.2	1.3

* हमने ऐसे आधिकारिक अनुमानों को शामिल किया है जो चालू खाता प्राप्तियों के एक अंश के रूप में माने गये हैं।

टिप्पणी : छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े हाल के वर्षों से पूर्णतः मेल नहीं खाते।

6.4 वर्ष 1992-93 के दौरान, निर्यात की धीमी गति और आयात मांग में हुई मामूली वृद्धि के फलस्वरूप 4,016 मिलियन अमरीकी डालर (11,527 करोड़ रुपये) का पण्य व्यापार घाटा हुआ। जहाँ वर्ष के दौरान व्यापार घाटे में 2 बिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि हुई वहाँ यह वर्ष 1991-92 के दौरान अनिवार्य रूप से आयातों के संकुचित स्तर को दर्शाता है। अदृश्य लेखे में गिरावट दर्ज की गई। इतफाक से पर्यटक मौसम की शुरुआत में ही उपद्रवों के प्रभाव की वजह से पर्यटकों के आगमन की वृद्धि दर में (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रों सहित) भी 2.2 प्रतिशत की गिरावट आयी। यद्यपि रायल्टी, तकनीकी शुल्क आदि के लेखे में जावक प्रेषणों में लगातार वृद्धि हुई, फिर भी व्याज भुगतानों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति में गिरावट आयी। मुख्यतया अनिवासी भारतीयों से प्राप्त होने वाले प्रेषणों की निजी अन्तरण प्राप्तियां लगभग पिछले वर्ष की भांति ही रही, जबकि ऐसे अंतरण, जो आधिकारिक तथा बाजार की मिश्रित दरों की 40:60 की औसत पर अन्यथा परिवर्तित कर दिए जाते, विनिमय बाजार दर के पूर्ण लागू होने के लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजी लेखे में प्रेषणों की कतिपय विविधता का संकेत देते हैं। अदृश्य लेखे (आधिकारिक अंतरणों सहित) से वर्ष 815 मिलियन अमरीकी डालर (3,104 करोड़ रुपये) की निवल आमद हुई। वर्ष 1992-93 के लिए चालू लेखा घाटा (जिसमें अनिवासी भारतीय जमाराशियां और आधिकारिक अन्तरण पर प्रोद्भूत व्याज भी शामिल है) 4,921 मिलियन अमरीकी डालर (14,631) करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1991-92 में यह 2,135 मिलियन अमरीकी डालर (5,186 करोड़ रुपये) या सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत था। वर्ष 1990-91 में चालू लेखा घाटा 9,679 मिलियन अमरीकी डालर (17,366 करोड़ रुपये) या सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत और जो अपेक्षाकृत बहुत अधिक था। (परिशिष्ट सारणी 6.1)।

6.5 विदेश से लोट रहे भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के व्यक्तियों के लिए बैंगेज विनियमों में उदारीकरण, जो संघ के 1992-93 के बजट में लागू किया गया था, के कारण 1992-93 के दौरान लगभग 132 मीटरी टन स्वर्ण का आगम का अनुमान लगाया गया था, जिसका मूल्य लगभग 1.4 बिलियन अमरीकी डालर होगा। फरवरी, 1993 में इसी प्रकार का उदारीकरण चांदी के आयात के लिए भी बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1992-93 के दौरान देश के अंदर लगभग 650 किलोग्राम चांदी लायी गयी थी। तथापि, 1992-93 के लिए भुगतान संतुलन के आंकड़ों में सोना-चांदी के इस आगम को या आयात अथवा निजी अन्तरण रमोदों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया था।

6.6 पूंजी लेखे में, ऋण देने वाले देशों द्वारा विशिष्ट रूप से वित्तपोषण करने के वावजूद भी गत वर्ष की तुलना में विदेशी सहायता के निवल आगमन में एक बिलियन अमरीकी

डालर से भी अधिक की गिरावट हुई। देश के माख निर्धारण को देखते हुए वाणिज्यिक बाजारों में प्रवेश करने के प्रयास भी नहीं किए गए। वाणिज्यिक उधार राशियों के संवितरण अधिकांशतया व्यापार सापेक्ष ऋणों के रूप में ही हुए। एफ सी एन आर ए स्कीम के अंतर्गत निवल बहिर्गमन की प्रवृत्ति का रुख बिल्कल बदल गया और अक्टूबर, 1992 से निवल आगमन राशियों का प्राप्त होता आरम्भ हो गया। एफ सी बी ओ डी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली एक बहुत बड़ी राशि वर्ष के प्रथम चार महीनों में योजना के समाप्त कर दिये जाने पर आनी बंद हो गयी और बाद के महीनों में उनके आहरण आरंभ हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जो आपाती व्यवस्था संबंधी समझौता किया उसके अंतर्गत अमरीकी डालरों की खरीदारियों के रूप में किये गए आहरण इस प्रकार थे—जलाई 1992 में, 663 मिलियन अमरीकी डालर (1,717 करोड़ रुपये), दिसम्बर, 1992 में 643 मिलियन अमरीकी डालर (1,685 करोड़ रुपये) (इस राशि में से 295 मिलियन अमरीकी डालर या वि० आ० अ० 212 मिलियन, कोष में आरक्षण के रूप में रखे गए, क्योंकि कोटे की 9वीं सामान्य समीक्षा के अधीन कोटा बढ़ाने की दृष्टि से यह राशि भारत के कोटे अभिदान के रूप में थी) फरवरी, 1993 में 319 मिलियन अमरीकी डालर और जून, 1993 में 325 मिलियन अमरीकी डालर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1992-93 में की गयी निवल खरीदारियां की राशि 1,288 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गयीं जबकि गत वर्ष यह राशि 781 मिलियन अमरीकी डालर थी।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

6.7 भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (जिनमें रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां, रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा सरकार द्वारा धारित विशेष आहरण अधिकार शेष राशियां शामिल हैं) मार्च, 1992 के अंत में 9,220 मिलियन अमरीकी डालर (23,850 करोड़ रुपये से बढ़कर) 9,832 मिलियन अमरीकी डालर (30,744 करोड़ रुपये) हो गयी जो 612 मिलियन अमरीकी डालर (6,894 करोड़ रुपये) की वृद्धि दर्शाता है (परिशिष्ट सारणी 7.3)। सोने के पुनर्मूल्यांकन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए लेन-देनों को छोड़कर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 1991-92 के दौरान 2,794 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में 1992-93 के दौरान 525 मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आयी। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 715 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। स्वर्ण के पुनर्मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए लेन-देनों को छोड़कर, अप्रैल-जून 1993 के दौरान आरक्षित निधियों में 4 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां

6.8 बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां मार्च, 1991 के अंत के 2,236 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर

मार्च, 1992 के अंत में 5,631 मिलियन अमरीकी डालर हो गयीं और ये मार्च, 1993 के अंत में और बढ़कर 6,434 मिलियन अमरीकी डालर हो गयीं। इस प्रकार इन आस्तियों में 1991-92 के दौरान 3,395 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में 1992-93 के दौरान 803 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई (ग्राफ 7)। उदारीकृत विदेशी मुद्रा विनिमय दर बंधन प्रणाली के अंतर्गत दोहरी विनिमय दर प्रणाली की संतुलन व्यवस्था, प्राधिकृत विक्रेताओं से विदेशी मुद्रा की खरीदारियां और इनकी बिक्रियां करने के बीच व्यापक अनुरूपता के रूप में परिलक्षित होती थी। सहायता प्राप्तियों में भारी गिरावट आने और भारी कर्ज भुगतानों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा आस्तियों के भण्डार से निवल बहिर्गमन हुआ। भारत और रूस महासंघ के बीच 5 मई, 1992 को समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर के अंतर्गत रूस के वनेशतोग बैंक को तकनीकी ऋण के रूप में 165 मिलियन अमरीकी डालर (3 मिलियन अमरीकी डालर के पुर्नभुगतान का निवल) उपलब्ध कराए गए जिसमें से 88 मिलियन अमरीकी डालर की राशि उन देयताओं में समायोजित की जाएगी जो रुपये में रूस को देय है और

77 मिलियन अमरीकी डालर की शेष राशि भारत को वापस की जानी है। 826 मिलियन अमरीकी डालर (सहायता प्राप्तियों के रूप में) असाधारण वित्तपोषण के आगमन से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1,063 मिलियन अमरीकी डालर के किए गए आहरणों की निवल प्राप्तियों से, विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारी वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता स्कीम के अंतर्गत निवल बहिर्गमनों में ठहराव आया। वर्ष 1992-93 के प्रथम चार महीनों में एफ सी बी ओ डी स्कीम के अंतर्गत भारी आगमनों को बाद वाले महीनों में आहरणों के द्वारा प्रति-संतुलित किया गया ताकि वर्ष के अंत तक 350 मिलियन अमरीकी डालर का निवल आगमन हो सके। विशेष घटकों को छोड़कर (सारणी 6.3) यदि तुलनात्मक आधार पर विवेचना की जाए तो विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1,539 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में 1,711 मिलियन डालर की गिरावट दर्ज की गई होती। मार्च, 1993 के अंत और जून, 1993 के अंत के बीच की अवधि में विदेशी मुद्रा आस्तियों में 119 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई और जून, 1993 के अंत में वे 6,553 अमरीकी डालर पर पहुंची।

सारणी 6.3 विदेशी मुद्रा आस्तियों के लेनदेन को प्रभावित करने वाले घटक

मद	मिलियन अमरीकी डालर		करोड़ रुपये	
	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
प्राधिकृत व्यापारियों से किए गए लेनदेन	128	1,855	735	5,215
निवल सहायता प्राप्तियां	-976	-3	-2,234	-164
रूस को दिया गया तकनीकी ऋण	-165	--	-429	--
ग्रन्थ	-698	-313	961	211
विशेष घटक	2,514	1,856	6,529	4,928
असाधारण वित्तपोषण	826	1,000	2,183	2,477
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गए लेनदेन	1,063	790	2,754	1,793
एफ सी बी ओ डी स्कीम	350	304	881	742
एफ. सी. एस. आर. ए. स्कीम	86	-1,611	223	-3,641
भारत विकास बॉण्ड	189	1,373	488	3,557
विदेशी मुद्रा आस्तियों में परिवर्तन	803	3,395	5,562	10,190
विशेष घटकों को छोड़ कर विदेशी मुद्रा आस्तियों में परिवर्तन	1,711	1,539	-967	5,262

विशेष आहरण अधिकार

6.9 विशेष आहरण अधिकारों की (वि० आ० आ०) धारिताओं में गत वर्ष के 10 मिलियन वि० आ० की गिरावट की तुलना में राजकोषीय वर्ष 1992-93 के दौरान 53 मिलियन वि० आ० आ० की गिरावट आयी। वर्ष 1992-93 में आयी गिरावट, 225 मिलियन मूल्य के वि० आ० आ० के निवल अर्जन, 446 मिलियन वि० आ० आ० के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से आहरण, 54 मिलियन वि० आ० आ० की पुनः खरीदारियां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 227 मिलियन वि० आ० आ० (व्याज सहायता को छोड़कर) के प्रभार/

व्याज की अदायगी, 231 मिलियन वि० आ० आ० मूल्य के वि० आ० आ० की बिक्री और भारत के कोटे में वृद्धि करने के एवज में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 212 मिलियन वि० आ० आ० के भुगतान का संयुक्त परिणाम थी। अप्रैल—जून 1993 के दौरान, वि० आ० आ० धारिता में 169 मिलियन वि० आ० आ० की वृद्धि हुई।

स्वर्ण

6.10 मार्च 1993 के अंत में रिजर्व बैंक की 354 टन स्वर्ण की धारिताओं का मूल्य 3,380 मिलियन अमरीकी डालर (10,549 करोड़ रुपये) आंका गया। इसमें विदेश

में रखी स्वर्ण धारिताओं पर व्याज की प्राप्ति के रूप में स्वर्ण स्टाक का 2.5 मिलियन अमरीकी डालर (6.75 करोड़ रुपये) के मूल्य का 0.25 टन अतिरिक्त स्वर्ण भी शामिल है। दिसम्बर 1992 से मार्च 1993 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार से 29.4 मिलियन अमरीकी डालर (82.57 करोड़ रुपये) मूल्य के 3.07 टन की खरीदारियों की वजह से बैंक की स्वर्ण धारिताओं में वृद्धि हुई। स्वर्ण के अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य में वृद्धि होने की वजह से अप्रैल—जून 1993 के दौरान स्वर्ण धारिताओं के मूल्य में 427 मिलियन अमरीकी डालर तक की ओर वृद्धि हुई।

पण्य व्यापार

6.11 कुल मिलाकर वर्ष के दौरान पण्य व्यापार संबंधी गतिविधियों अपेक्षाकृत कम संतोषजनक रही। वर्ष 1992-93 की प्रथम छमाही के दौरान व्यापार में जो मामूली सुधार आया वह वर्ष की दूसरी छमाही में बम्बई में उपद्रव होने के फलस्वरूप व्यापार न होने और विश्व में कम मांग की वजह से अधिकांशतया प्रतिसंतुलन रहा। वर्ष 1992-93 के दौरान अमरीकी डालर मूल्यों के रूप में 18,421 मिलियन अमरीकी डालर के कुल निर्यातों में केवल 3.1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। दूसरी ओर, वर्ष के दौरान 11.9 प्रतिशत आयातों की वृद्धि हुई जो बढ़कर 21,726 मिलियन अमरीकी डालर हो गए (परिशिष्ट सारणी VI.5)।

सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार

6.12 सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातों, जिनका विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, में लचीलापन आया। सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातों में वर्ष के प्रारंभ से लेकर अक्टूबर 1992 तक की अवधि से ही वृद्धि के आसार नजर आये। अगले दो महीनों में इसमें गिरावट आयी तथा वह स्थिति मौसमी प्रवृत्ति से भिन्न थी। (गत 3 वर्ष के दौरान किये गये निर्यातों की मासिक औसत के रूप में मूल्यांकन)। तथापि, जनवरी 1993 तक सामान्य मुद्रा निर्यातों की मौसमी प्रवृत्ति में पुनः वृद्धि होनी शुरू हुई जो वर्ष के अंतिम माह तक अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच गयी। वर्ष 1992 में 4.2 प्रतिशत के विषय व्यापार की वृद्धि की मात्रा के परिप्रेक्ष्य की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातों से अमरीकी डालर के रूप में 10.4 प्रतिशत दर की वृद्धि हुई जो संतोषजनक थी। व्यापारिक वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में निरंतर शिथिलता के कारण सामान्य मुद्रा क्षेत्र को किये जाने वाले निर्यातों की मात्रा 7-8 प्रतिशत के बीच हो सकती है।

6.13 रुपया भुगतान क्षेत्र के निर्यातों में वर्ष के दौरान 1,118 मिलियन अमरीकी डालर अथवा अमरीकी डालर के रूप में 62.2 प्रतिशत तक की कमी आयी जो समय निर्यात वृद्धि को लगातार प्रभावित करती रही। इन निर्यातों में गिरावट लगातार तीसरे वर्ष भी बनी रही। पूर्व सोवियत रूस के साथ व्यापार समाप्त हो जाने, जो भारत के लिये एक महत्वपूर्ण बाजार था, की वजह से सामान्य मुद्रा क्षेत्र और रुपया भुगतान क्षेत्र के बीच निर्यातों तथा आयातों के स्त्रोत दोनों के लक्ष्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ (ग्राफ 8)।

6.14 वर्ष की प्रथम छमाही में 1990-91 और 1991-92 के संकुचन से आयातों में जो पुनः उछाल आया वह बहुत सुदृढ़ था और इस प्रकार अप्रैल—सितम्बर 1992 के दौरान आयात वृद्धि अमरीकी डालर के रूप में 22.3 प्रतिशत थी। वर्ष की दूसरी छमाही में आयातों की गति स्पष्ट रूप से धीमी रही, जिसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष भर में समग्र आयात वृद्धि अमरीकी डालर के रूप में केवल 11.9 प्रतिशत थी जो वर्ष 1991-92 में आयातों के घटे हुए स्तर से जितनी वृद्धि की आशा की गयी थी उससे भी अपेक्षाकृत काफी कम रही। पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के निर्यातों में पिछले वर्ष में 22.2 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद अमरीकी डालर के रूप में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बाह्य गतिविधियों के प्रभाव और टैरिफ में प्रत्याशित परिवर्तनों की वजह से वर्ष के बावजूद छमाही में कुछ आयातों को स्थगित कर दिये जाने से वर्ष के दौरान पेट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों से इतर पदार्थों के आयातों से मौसमी प्रवृत्ति में परिवर्तन आया, जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 1992 और जनवरी 1993 के बीच की अवधि के दौरान अधोमुखी विपरीत—मौसमी प्रवृत्ति परिलक्षित हुई (ग्राफ 9)।

6.15 पेट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों के आयात गत वर्ष के 5.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1992-93 में 6.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। कच्चे पेट्रोलियम के आयातों की मात्रा में वर्ष 1991-92 में 24.0 मिलियन टन से 1992-93 में 29.2 मिलियन टन की वृद्धि हो जाने से घरेलू उत्पादन में अनिवार्य रूप से कमी होती रही। रखरखाव संबंधी सुविधाएं उपलब्ध न होने पर कुछ तेल शोधक कारखानों के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 के 9.4 मिलियन टन की तुलना में 1992-93 के दौरान 11.1 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों में भी वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में सुधार की स्थिति बने रहने से पेट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों की आयात बिल में भी व्यापक बचत रही। तथापि, पेट्रोल उत्पादों के आयात मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई।

6.16 वर्ष 1992-93 के दौरान सीमा शुल्क के आधार पर 3,305 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा पूर्व प्रत्याशित घाटे से अपेक्षाकृत कम था (परिशिष्ट

सारणी VI.5)। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयातों की गति को बनाये रखने के लिये किये गये उपायों से समीक्षाधीन वर्ष और इन वर्षों में, व्यापार शेष की तुलनात्मक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लगातार दूसरे वर्ष भी पेट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों से इतर पदार्थों के शेष आधिक्य रहे जो पेट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों से इतर पदार्थों के आयातों की स्पष्ट वृद्धि को परिलक्षित करता है। वर्ष के दौरान पेट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों के घाटे में और वृद्धि, अर्थात् 675 मिलियन अमरीकी डालर, हुई।

6.17 गत दो वर्षों के दौरान हुई गतिविधियों के परिणामस्वरूप व्यापार की दिशा में परिवर्तन आया। वर्ष 1989-90 और 1992-93 के बीच की अवधि के दौरान जहाँ भारत के निर्यातों के प्रमुख बाजारों, जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अमरीकी, जापान और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, (ओ पी ई सी) के अंश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वहाँ दूसरी ओर, रुपया भुगतान क्षेत्र के अंश में भारी गिरावट की भार को अन्य देशों को सहन करना पड़ा। आयातों के संसाधनों के मामले में भी ऐसी ही प्रवृत्ति परिलक्षित हुई, यद्यपि भारत के आयातों में ओ पी ई सी के अंश में तीन वर्ष की अवधि के दौरान वृद्धि हुई (ग्राफ 10)। विदेशी सहायता

6.18 वर्ष 1992-93 के दौरान विदेशी सहायता के आगम में काफी गिरावट आई। ऋणों और अनुदानों का सकल उपयोग 3,737 मिलियन अमरीकी डालर (11,454 करोड़ रुपये) पर 1991-92 के 4,689 मिलियन अमरीकी डालर (11,615 करोड़ रुपये) से 952 मिलियन अमरीकी डालर (161 करोड़ रुपये) कम था वर्ष 1992-93 के दौरान ऋण परिशोधन भुगतान 1,581 मिलियन अमरीकी डालर (4,846 करोड़ रुपये) पर वर्ष 1991-92 के समान ही थे। वर्ष 1992-93 के दौरान विदेशी सहायता के निवल आगम में 2,156 मिलियन अमरीकी डालर (6,608 करोड़ रुपये) की तुलना में 1,059 मिलियन अमरीकी डालर (1,357 करोड़ रुपये) पर गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी 6.9)। विदेशी क्षेत्र में संरचनात्मक समायोजन के प्रभाव को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दाता देशों से विशिष्ट वित्तीयन द्वारा प्रदान की गई सहायता से कम किया जा सका। 1992-93 में ऐसी अपवादात्मक वित्तीयन की राशि 826 मिलियन अमरीकी डालर थी जिसमें विश्व बैंक के 452 मिलियन अमरीकी डालर, एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर, जापान से 134 मिलियन अमरीकी डालर, जर्मनी से 62 मिलियन अमरीकी डालर और अन्य स्रोतों से 28 मिलियन अमरीकी डालर शामिल है। 1993-94 के लिए; भारत सहायता संघ ने 2.2 बिलियन अमरीकी डालर के शीघ्र संवितरण के साथ भारत को 7.4 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिया। अनिवासी जमाराशियाँ में वृद्धि

6.19 अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के लिए अंतिम आंकड़े 39 मिलियन अमरीकी डालर (111 करोड़ रुपये) अनुमानित ब्याज के

अंश को छोड़कर की वृद्धि दर्शाता है जबकि 1991-92 में 27 मिलियन अमरीकी डालर (44 करोड़ रुपये) के अन्तरण थे। 1991-92 में 1,611 मिलियन अमरीकी डालर (3,605 करोड़ रुपये) की बड़ी राशि के बहिर्गमन की तुलना में 1992-93 में विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता के अन्तर्गत 86 मिलियन अमरीकी डालर (223 करोड़ रुपये) की राशि का आगम हुआ (परिशिष्ट सारणी 6.10)। 1 मार्च 1993 के अंत में अनिवासी (विदेशी) रुपया और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों के अंतर्गत बकाया जमाराशियाँ 8,171 मिलियन अमरीकी डालर या 25,634 करोड़ रुपये थीं जिसमें अनिवासी (वि०) रुपया खाते में 2884 मिलियन अमरीकी डालर (9,062 करोड़ रुपये) और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते के अंतर्गत 5,287 मिलियन (16,572 करोड़ रुपये) शामिल है। जून 1993 के अंत में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता और अनिवासी (विदेशी) रुपया खाते के अधीन बकाया शेष राशियाँ क्रमशः 5,167 मिलियन अमरीकी डालर अथवा 16,136 करोड़ रुपये और 2,900 मिलियन अमरीकी डालर अथवा 9,090 करोड़ रुपये हो गयी। विदेशी मुद्रा (सामान्य गैर—प्रत्यावर्तनीय) स्कीम के अंतर्गत 1991-92 के 5 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 1992-93 में 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का आगम हुआ। अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) जमाराशि स्कीम के अंतर्गत बड़ी राशि के आगम के संकेत हैं। 1992-93 के दौरान अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) जमाराशि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध आंशिक सूचना लगभग 600 मिलियन अमरीकी डालर (1,912 करोड़ रुपये) की राशि के आगम का संकेत देती है। नई चालू की गई अतिवारी स्कीम, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) स्कीम के निष्पादन का पूरा दृश्य अभी सामने नहीं आया है क्योंकि इसे हाल ही में अर्थात् 15 मई 1993 से आरम्भ किया गया है।

6.20 विदेशी मुद्रा (बी० एण्ड ओ०) जमा स्कीम को 31 जलाई 1992 से रद्द कर दिया गया है। उस समय, स्कीम में 2,232 मिलियन अमरीकी डालर की जमाराशियाँ बकाया थीं। स्कीम रद्द किये जाने से बाद के महीनों में काफी मात्रा में राशियाँ आहरित की गईं। मार्च 1993 के अंत में योजना के अंतर्गत बकाया जमा राशियाँ 1,044 मिलियन अमरीकी डालर और जून 1993 के अंत में 932 मिलियन अमरीकी डालर थीं।

ब्याज दरें अनिवासी जमाराशियाँ

6.21 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ब्याज दरों में गिरावट की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, 1992-93 में सभी प्राधिकृत मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता के अंतर्गत जमा राशियों पर ब्याज की दरों को पांच बार और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (जुलाई 1993 के अंत तक) तीन बार संशोधित किया गया (परिशिष्ट सारणी 6.11)। 46 दिन और 3 वर्ष के बीच की परिपक्वता वाली सभी मीयादी जमाराशियों के लिए 9 अक्टूबर 1992 से अनिवासी (विदेशी) रुपया खाते पर ब्याज दरों को संशोधित कर दिया गया और 13 प्रतिशत का कैप ब्याज निर्धारित किया गया। धरेल जमाराशियों की ब्याज दरों के अनुसार अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता पर ब्याज दरों की यक्षित्यवत बनाते

के उद्देश्य से 8 अप्रैल, 1993 से कैप को कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

विदेशी ऋण

6.22 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, विदेशी ऋण आंकड़ों से संबंधित नीति बल और कृतिक बल ने विदेशी ऋण की नयी परिभाषा और वर्गीकरण की निफारिश की है। नया वर्गीकरण विस्तृत है और इसमें वर्तमान में शामिल घटकों के अलावा, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता स्कीम परिवर्तनीय डिबेंचर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक संगहीत ऋण के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित शेष और 1971 से पहले के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों* के संबंध में विनिमय समायोजन शामिल है। इसमें पट्टे के लेन-देन और रुपया सकल ऋण में मुख्य ऋण—आंकड़ों में शामिल नहीं होंगे (रुपया-रुबल ऋण ज्ञापन मदों के रूप में दिखाया गया है)। अल्पावधि ऋण के अंतर्गत, छह महीने की परिपक्वता वाली अवधि के सभी ऋणों को शामिल नहीं किया गया। दल ने यह निफारिश भी की कि ऋण आंकड़ों की और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता की दृष्टि से गैर-नागरिक ऋणों के आंकड़ों का खुलासा किया जाए। परिशिष्ट सारणी 6.12 में नई परिभाषा और वर्गीकरण के आधार पर भारत के विदेशी ऋण को दर्शाया गया है। भारत का दीर्घावधि ऋण, मार्च 1990 के अंत में 56 बिलियन (96,475 करोड़ रुपये) अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च 1993 के अंत में 69 बिलियन अमरीकी डालर (2,13,555 करोड़ रुपये) हो गया। इसी अवधि में अल्पावधि ऋण 5.5 बिलियन (9,465 करोड़ रुपये) से घटकर 4.5 बिलियन (13,909 करोड़ रुपये) अमरीकी डालर रह गए। कुल ऋण, जिसमें मेमो मदों के रूप में दिय गये ऋण भी शामिल हैं, की राशि मार्च 1993 के अंत में 85 बिलियन (2,66,214 करोड़ रुपये) अमरीकी डालर थी।

6.23 वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के संबंध में कुल ऋण जिसमें मेमो मदों के अंतर्गत ऋणों को शामिल नहीं किया गया है, मार्च के अंत में 1990 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1993 के अंत में 32.4 प्रतिशत हो गए। यदि मेमो मदों को शामिल किया जाता है तो सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण स्टाक मार्च 1990 के अंत के 28.3 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 1993 को 37.9 प्रतिशत पर पहुंच जायेगा। ऋण चुकौती अनुपात (अर्थात् आधिकारिक अंतरणों को छोड़कर माल और सेवाओं के निर्यात के लिए ऋण चुकौती भुगतानों जिनमें सुरक्षा से संबंधित ऋण सेवा भुगतान भी शामिल हैं का अनुपात) 1991-92 के 26.2 प्रतिशत से मामूली सा गिरकर 1992-93 में 26.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। सुरक्षा से संबंधित ऋण सेवा भुगतानों सहित, ऋण सेवा अनुपात ने 1991-92 के 31.6 प्रतिशत से 1992-93 में 30.8 प्रतिशत तक की कमी दर्शायी।

रुपया-रुबल ऋण

6.24 वर्ष 1993 के आरंभ में हुए समझौते के अनुसार 1 अप्रैल, 1992 को बकाया ऋण की मूल राशि भारतीय रुपये में परिवर्तित करनी होगी और उसे भारतीय रुपये में निम्नानुसार चुकाना होगा:

- (i) 1 अप्रैल 1992 को बकाया ऋण को 1 जनवरी 1990 (19.9 रुपया प्रति रुबल) को प्रचलित रुपया-रुबल विनिमय दर के अनुसार (25 नवम्बर, 1978 को प्रोटोकाल के प्रावधानों के अनुसार) रुपये में परिवर्तित किया जायेगा।
- (ii) 1 अप्रैल 1992 (31.8 रुपया प्रति रुबल) को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार भी ऋण को रुपये में परिवर्तित किया जायेगा।

6.25 दोनों राशियों के बीच के अंतर की राशि को 1 अप्रैल, 1993 से आरंभ करके 45 वर्ष की अवधि में बिना ब्याज के समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। 1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्ष के लिए रुपये के मूल्य में किसी घट-बढ़ के लिए कोई संरक्षण नहीं है। तत्पश्चात् हर पांच वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि विशेष आहरण अधिकार की तुलना में वार्षिक औसत आधार पर प्रतिवर्ष रुपये का मूल्य ह्रास तीन प्रतिशत से अधिक हो तो इस कारण से देय भुगतान विशेष आहरण अधिकार के रुपया मूल्य पर अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से किया जा सकता है।

6.26.1 जनवरी, 1990 को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किये गये ऋण की चुकौती ब्याज सहित प्रत्येक ऋण समझौते की भुगतान सूची के अनुसार की जायेगी। 1 अप्रैल, 1992 के बाद किसी भी दिन विशेष आहरण अधिकार की तुलना में रुपये का मूल्य रुपये के आधार मूल्य की तुलना में, जो 1 अप्रैल, 1992 को 35.3637 रुपये था तीन प्रतिशत से अधिक या कम होता है तो 1 अप्रैल, 1992 के बाद किसी भी दिन भुगतान किय गए मूलधन और ब्याज की राशि को उक्त परिवर्तन के साथ अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

6.27 इस समझौते से देश को यह लाभ है कि 1 जनवरी, 1990 से 1 अप्रैल, 1992 के बीच रुबल की तुलना में रुपये के विनिमय मूल्य में घट-बढ़ स्वरूप हुई ऋण की वृद्धि को प्रोटोकाल के अनुसार बिना ब्याज के 45 वर्ष में चुकाना होगा।

रुपए की विनिमय दर

6.28 1 मार्च, 1992 को उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (एल० ई० आर० एम० एम०) के अंतर्गत शुरू किये गये वुहरे विनिमय दर समझौते ने एक व्यवस्थित संक्रमण ला दिया और अब उतार-चढ़ाव से निकालकर बाजार निर्धारित प्रणाली में हम आ गये हैं। उदारीकृत विनिमय

*नवापि तकनीकी समस्याओं को बजह से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के समूह ऋणों के अंतर्गत शेषों का पुनर्मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के 1971 के पूर्व के ऋणों के संबंध में विनिमय समायोजन नहीं किया गया है।

दर प्रबंधन प्रणाली के परिचालन के 12 महीने की अवधि के दौरान 4 दिसम्बर 1992 को हुए 1.12 प्रतिशत के निम्न-गामी समायोजन को छोड़कर आधिकारिक रूप से निर्धारित विनिमय दर में स्थिरता रही। आधिकारिक विनिमय दर प्राधिकृत व्यापारियों को समर्पित चालू प्राप्तियों के 40 प्रतिशत के बीच रही और बचले में रिजर्व बैंक उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्यों की चुकौती

हेतु भी यही दर रही। बाजार परिचालकों के माध्यम से उतनी ही मात्रा में लेनदेन किये गए जिसके परिणामस्वरूप बाजार निर्धारित विनिमय दर स्थिर रही। आधिकारिक और बाजार दरों के बीच का अंतर कम रहा, किन्तु फरवरी 1993 का महीना अपवाद रहा जब सट्टा गतिविधियों से अंतर—बैंक विनिमय बाजार में कुछ खलबली रही (सारणी 6.4 और ग्राफ 11 और 12)।

सारणी 6.4: आधिकारिक और बाजार विनिमय दरों के बीच अंतर

(रुपया प्रति अमरीकी डालर)

महीना	आधिकारिक दर	बाजार दर	अंतर	भारत दर
1	2	3	4	5
मार्च 1992	25.8901	29.4551	13.77	28.0291
अप्रैल "	25.8900	30.9253	19.45	28.9112
मई "	25.8900	30.3407	17.19	28.5604
जून "	25.8900	30.2361	16.75	28.4977
जुलाई "	25.8900	30.2524	16.85	28.5074
अगस्त "	25.8900	30.0885	16.22	28.4091
सितम्बर "	25.8900	30.0584	16.10	28.3710
अक्टूबर "	25.8900	30.0471	16.06	28.3843
नवम्बर "	25.8900	30.0824	16.19	28.4054
दिसम्बर "	26.1540	30.7005	17.38	28.8819
जनवरी 1993	26.1986	30.8833	17.88	29.0094
फरवरी "	26.1986	32.6456	24.61	30.0668

6.29 संक्रमणकाल में एक प्रणाली के रूप में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली ने बड़ी हुई विदेशी मुद्रा के लेनदेनों को बाजार में अंतरित करने की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के मामले में अच्छा योगदान दिया। इससे उत्पन्न स्थिरता मुद्रा, स्फीति की दर में महत्वपूर्ण गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत स्थिति ने उस स्थिति के सरल रूपांतरण में सहायता दी जिसके अंतर्गत विनिमय दरों को एकीकृत (1 मार्च 1993 से प्रभावों) किया गया और रुपये का बाह्य मूल्य बाजार की शक्तियों से निर्धारित होता है। दुहरी दर प्रणाली को एकीकृत करने से भुगतान संतुलन के समायोजन में अस्थाई मुद्रा दर ने विनिमय दर प्रणाली को महत्वपूर्ण लोच प्रदान किया।

6.30 एकीकृत विनिमय दर व्यवस्था नियंत्रण के समग्र ऋण के भीतर कार्य करती है। सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से किये जाते हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक को सौंपना आवश्यक नहीं होता। जहाँ विदेशी मुद्रा के लेनदेन बाजार दरों पर किये जाते हैं वहीं रिजर्व बैंक की अपनी विनिमय दर बाजार की परिस्थितियों को दर्शाती है और बाजार दरों से 5 प्रतिशत कम या अधिक हो सकती है। अपने विवेकानुसार अनुमोदित उद्देश्यों हेतु अमरीकी

डालर की हाज़िर खरीद और मुद्रा की बिक्री कर सकेगा तथा इस रूप में उसे अब जरूरत नहीं कि वह विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री करे। तथापि, वर्तमान में, रिजर्व बैंक, भारत सरकार के ऋणों के भुगतानों के लिए और अस्थाई व्यवस्था के रूप में एक्सिम स्क्रिप्सों में पूर्ण मूल्य हेतु और निर्यातकों को जारी अन्य लाइसेंसों के मूल्य के 40 प्रतिशत के भुगतानों के लिए विदेशी मुद्रा बेचता है। अपने विवेकानुसार वह बाजार में विदेशी मुद्राओं की मध्यवर्ती खरीद/बिक्री भी करेगा। प्राधिकृत व्यापारियों के साथ लेनदेनों के लिए अपनी खरीद और बिक्री दरों के अतिरिक्त, रिजर्व बैंक अपनी संदर्भ दर बैंक आधार पर घोषित करता है जो बंबई में कुछ चुनिंदा बैंकों के मध्याह्न की दरों पर आधारित होती है। विशेष आह्वान अधिकार रुपया विनिमय दर और रणियन समाशोधन संघ के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों के लिए लागू विनिमय दर इस संदर्भ दर पर आधारित होती है। दो से छह महीने की अवधि के लिए प्राधिकृत व्यापारियों के साथ डालरों में अवला-बदली का कारबार भी बैंक करता है।

6.31 मुक्त अस्थायी बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली का अनुभव संतोषजनक रहा। यदि अपवादों को

छोड़ दें, तो रुपये की विनिमय दर में उल्लेखनीय स्थिरता रही।
वास्तव में, रुपये में, 1 मार्च 1993 को विनिमय दरों के

एकीकरण के बाद से कई बार मजबूती आयी (सारणी
6.5 और ग्राफ 13)।

सारणी 6.5: भा० वि० मु० व्या० संघ* (संक्रितिक) विनिमय दरें—साप्ताहिक औसत
(मार्च 1992 से जून 1993)

(रुपये प्रति अमरीकी डालर)

समाप्त सप्ताह	रुपये/अमरीकी डालर (औसत)		समाप्त सप्ताह	रुपये/अमरीकी डालर (औसत)	
1992	अक्टूबर		30	30.0955	
मार्च	6	29.1996	नवम्बर	6	30.0680
	13	29.1783		13	30.1024
	20	30.5031		20	30.0969
	27	31.2645		27	30.0590
अप्रैल	3	31.3251	दिसम्बर	4	30.4113
	10	31.1614		11	30.7930
	17	31.0768		18	30.6286
	24	30.7611		25	30.7588
मई	1	30.6185	1993		
	8	30.1046	जनवरी	1	30.8072
	15	30.1963		8	30.7901
	22	30.0617		15	30.7626
	29	30.6775		22	30.8139
जून	5	30.5022		29	31.2650
	12	30.2587	फरवरी	5	31.8733
	19	30.0239		12	32.9878
	26	29.9792		19	32.8364
जुलाई	3	30.4159		26	32.9244
	10	30.4110	मार्च	5	31.8706 (31.86)
	17	30.3472		12	31.5610 (31.56)
	24	30.1708		19	31.4634 (31.46)
	31	30.1097		26	31.4482 (31.45)
अगस्त	7	30.0327	अप्रैल	2	31.2257 (31.23)
	14	30.0417		9	31.2256 (31.23)
	21	30.0580		16	31.3211 (31.32)
	28	30.2231		23	31.3195 (31.32)
सितम्बर	4	30.1092		30	31.3617 (31.37)
	11	30.0436	मई	7	31.3197 (31.32)
	18	30.0571		14	31.3034 (31.32)
	25	30.0454		21	31.3209 (31.32)
अक्टूबर	2	30.0312		28	31.3382 (31.34)
	9	30.1008	जून	4	31.3714 (31.37)
	16	30.0264		11	31.4209 (31.42)
	23	30.0364		18	31.4643 (31.46)
				25	31.3854 (31.39)

टिप्पणी: सधु कंष्टकों में आंकड़े सांख्यिकी संवर्षों के संदर्भ में हैं।

* भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियां

6.32 उत्पादन और व्यापार की मात्रा में वृद्धि के रूप में प्रकट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति वर्ष 1992 में सुधार दर्शाती है। विश्व की उत्पादन वृद्धि जो 1991 में 1 प्रतिशत से भी कम थी सुधारकर 1992 में 1.8 प्रतिशत पर पहुंच गयी। इस सुधार में औद्योगिक और विकासशील देशों दोनों ने योगदान दिया। औद्योगिक देशों में वृद्धि दर 1991 के 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 1992 में 1.5 प्रतिशत हो गई और विकासशील देशों में (केन्द्रीय यूरोप और भूतपूर्व सोवियत संघ) के देशों को छोड़कर 4.2 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत हो गई। विकासशील देशों की वृद्धि में योगदान एशिया, मध्य-पूर्व और यूरोप के देशों से मिला। केन्द्रीय यूरोप और भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थ व्यवस्थाओं में तीसरे वर्ष लगातार उत्पादन में गिरावट आयी और यह गिरावट 1991 के 10.1 प्रतिशत की तुलना में 15.5 प्रतिशत पर अधिक गंभीर रही।

6.33 वर्ष 1991 के 2.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1992 में विश्व के व्यापार (भूतपूर्व सोवियत संघ के राज्यों के बीच के व्यापार को छोड़कर) की मात्रा में 4.2 की वृद्धि हुई। तथापि, यह व्यापक तौर पर माना गया कि विश्व व्यापार की भावी वृद्धि उरुग्वे दौर की वार्ता की सफलता पर निर्भर करती है।

6.34 सितंबर 1992 से यूरोपीयन मौद्रिक प्रणाली की विनिमय दर प्रणाली में संकट के कारण विदेशी मुद्रा और वित्तीय बाजार की गतिविधियां काफी प्रभावित हुईं। यूरोपीय मौद्रिक प्रणाली में संकट के दो प्रमुख मुद्दों, पौण्ड, स्टर्लिंग और इटालियन लीरा को विनिमय दर प्रणाली से निलंबित किया गया। इस खलबली का परिणाम यह हुआ कि कई नये समीकरण बने और तीन नाजिक मुद्दों का चलन यूरोपीय मुद्रा संघ के साथ अधिकीकृत किया गया जिससे मुद्रा और पूंजी के प्रवाह तथा व्यापार और व्यापार संबंधी लेनदेनों में कई उछाल आये।

6.35 11 नवम्बर, 1992 से लागू अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करार की शर्तों में तीसरा संशोधन और कोटा की नौवीं सामान्य समीक्षा जो कि वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसके साथ ही, आठवीं समीक्षा के अंतर्गत कुल आई०एम०एफ० कोटा एसडीआर 90.1 बिलियन से बढ़कर नौवीं समीक्षा के अंतर्गत एस०डी०आर० 135.2 बिलियन हो गये। आई०एम०एफ० में बाद में सदस्यता के कारण कुल कोटा बढ़कर लगभग 145 बिलियन हो गया। भारत के कोटे में 38.4 प्रतिशत एस०डी०आर० 2,207.7 मिलियन से बढ़कर एसडीआर 3,055.5 मिलियन हो गया। आई०एम०एफ० ने अपनी ऋण उपलब्धता नीति के अंतर्गत नई सीमाओं की भी घोषणा की जो मुद्रा कोष की विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत भारत के लिए पूर्ण उपलब्धता में वृद्धि का द्योतक है।

6.36 कम आय वाले देशों पर प्रभाव डालने वाला एक और महत्वपूर्ण तथा बर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा (इएसएफ) के अंतर्गत संसाधनों के वायदों के लिए निर्धारित तिथि एक वर्ष बढ़ाकर नवंबर 1993 के अंत तक करने का आई०एम०एफ० का जुलाई, 1992 का निर्णय था। कम आय वाले देशों को सहायता पहुंचाने के लिए यह एक रियायती सुविधा है। इस निर्णय से इस तथ्य का पता चलता है कि कम आय वाले देशों के लिए बाहरी परिस्थितियां अनिश्चित हो रहेंगी। मुद्रा इस समय बर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा के संचालित उत्तराधिकारी के विकल्पों और परिचालनगत तौर-तरीकों की जांच कर रहा है जिसके नवंबर, 1993 के बाद प्रभावी होने की संभावना है।

6.37 केन्द्रीय यूरोप और भूतपूर्व सोवियत संघ के इसके पूर्व के केन्द्रीय रूप से योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं अब बाजार की अर्थव्यवस्थाएं बनने की राह में विभिन्न स्तरों पर हैं। आई०एम०एफ० ने सर्वांगीण रूपांतरण सुविधा नामक एक नयी सुविधा स्थापित की है ताकि सदस्यों को उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं में सभी रुकावटों को दूर करने में सहायता दे सके।

VII. मूल्योन्त और संभावनाएं

7.1 1992-93 के दौरान अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण सकारात्मक विशेषताएं—कृषि की सुदृढ़ वृद्धि, मौद्रिक विस्तार में संतुलन और मुद्रा स्फीति दर में उल्लेखनीय कमी तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का सुधार—उत्साहवर्धक लक्षण हैं एवं समष्टि—अर्थशास्त्रीय स्थिरता और प्रणाली की सुधरी कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लक्ष्य से नीतिगत प्रयास जारी रखने और उन्हें सघन बनाने के लिए आधार प्रदान करती है। तथापि, समायोजन की प्रक्रिया में कई गंभीर मसले उभरकर सामने आये जिनके संबंध में अनुकूल और सुदृढ़ नीतिगत प्रत्युत्तर की आवश्यकता है।

कृषि संबंधी संभावनाएं

7.2 हाल की अवधि में अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि एक भजवत कृषि निष्पादन के चारों ओर निर्मित है जो अभी भी अधिकतर मौसम की स्थितियों पर निर्भर है। अस्सी के दशक में कृषि में निवेश में कमी ने कृषि उत्पादन में दीर्घावधि की दूरगामी वृद्धि को प्रभावित किया है। फिर भी, पिछले दो वर्षों में यह मान्यता बढ़ रही है, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख में भली भांति प्रतिबिंबित है कि उत्पादकता और रोजगार में सुधार लाने के लिए कृषि और अन्य ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों में निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1993 के प्रारंभ में संसद में प्रस्तुत कृषि नीति संकल्प का प्रारूप, 1993-94 का बजट और व्यापार नीति में अप्रैल, 1993 से लागू किये गये आशोधन और खाद्यान्नों की सरकारी खरीद की कीमतों में बढ़ोतरी—इन सभी के द्वारा ऐसे उपाय किये गये हैं जो कृषि की वृद्धि पर विशेष रूप से बल दे सकते हैं। 1993-94 में अनुकूल

मौसम की स्थितियों में हुई कृषि की वृद्धि कृषि की निरंतर प्रगति को दर्शाती है। चालू वर्ष के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून बहुत ही अनुकूल रहा है तथा 35 मौसमी प्रभागों में से 26 उप-प्रभागों में अब तक हुई वर्षा 11 अगस्त 1993 तक सामान्य अधिक रही जबकि पिछले वर्ष में ऐसा 25 उप-प्रभागों में थी। जून 1993 की समाप्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के खाद्यान्नों के लगभग 26 मिलियन टन के स्टॉक मानदंडों से अधिक ही हैं और मांग की तुलना में सुविधाजनक आपूर्ति की स्थिति के होते हुए प्रणाली अब यह सुनिश्चित करने की स्थिति में है कि आपूर्ति संबंधी किसी भी झटके के कारण अचानक मुद्रास्फीति नहीं बढ़े।

उद्योग

7.3 आयात संबंधी प्रतिबंधों में रियायतें देने तथा ऋण संबंधी नियंत्रणों के और व्याज-दरों में कमी करने के श्रावजद 1992-93 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में सुधार निराशाजनक रहा। यद्यपि, 1992-93 की अंतिम तिमाही में गड़बड़ी न होती तो उक्त वृद्धि कुछ अधिक रहती। मंद औद्योगिक वृद्धि ने अवश्य मंद वास्तविक देशी मांग और निर्यात की अनुमान से कम वृद्धि को प्रतिबिंबित किया है। हमें यह पहचानना ही होगा कि औद्योगिक क्षेत्र के कुछ खंडों को संक्रमण की प्रक्रिया के दौरान कतिपय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सकल राजकोपीय घाटा कम करने के प्रयास से, जिसका अर्थ सरकारी खर्चों में कमी है, कुछ वस्तुओं की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इन क्षेत्रों को मांग के स्वरूप में परिवर्तन के अनुरूप अपने आपको समायोजित करना होगा। देशी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर भी कुछ दबाव आ सकता है क्योंकि इन वस्तुओं के आयातों को खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है और इन वस्तुओं पर आयात टैरिफ में बड़ी मात्रा में निम्न-गामी संशोधन किया गया है। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र किम सीमा तक अपने-आपको नयी स्थिति के अनुरूप समायोजित कर सकता है, यह भी आयातित कच्चे माल, घटक और तैयार माल पर टैरिफ की संबंधित दरों पर निर्भर होगा।

7.4 औद्योगिक उत्पादन से संबंधित समग्र आर्थिक परिदृश्य में उत्साहवर्धक तत्व है सुधरा हुआ कृषि उत्पादन का संभावित सकारात्मक प्रभाव। ग्रामीण आर्थिक वृद्धि होगी जिससे औद्योगिक उपभोग वस्तुओं के लिए देशी अंतिम मांग में तेजी आएगी। इस प्रकार, चूंकि 1993-94 में कृषि क्षेत्र पुनर्स्थापन के सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है, अतः सरकार की व्यय नीतियों के पुनरीक्षण को देखते हुए वास्तविक सकल निवेश और वास्तविक देशी मांग में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए। यह अनुमान है कि निजी कंपनियों क्षेत्र का निवेश 1993-94 में वास्तविक तौर पर लगभग 13.3 प्रतिशत अधिक (सांकेतिक और पर 21.6 प्रतिशत) होगा।

1993-94 के लिए मंच के वजट में भी 1993-94 केन्द्रीय योजना परिव्ययों में वृद्धि की घोषणा की गयी है। योजना परिव्यय में सांकेतिक तौर पर 28 प्रतिशत की वृद्धि अस्सी के दशक से लेकर किसी भी एक वर्ष के लिए अधिकतम दर की वृद्धि है। परिव्यय के श्रावटन में ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अनिर्दिष्ट, मुद्रास्फीति की दर, जिसे पिछले राजकोपीय वर्ष में इकाई अंक के भीतर सीमित रखा गया है और लचीलापन जिसके साथ विनिमय दर और विदेश निवेश नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है, से भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। अनुमान है कि अर्थव्यवस्था में किये जा रहे संरचनात्मक समायोजन के परिणामस्वरूप उत्पादन के संबंध में आयात की सघनता अपेक्षाकृत कम होगी। अतः, पूँति और मांग दोनों के द्वारा अधिक सक्रिय बनाये गये औद्योगिक क्षेत्र में 1993-94 में लगभग 4.5 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। तथापि, 1993-94 में औद्योगिक वृद्धि अस्सी के दशक में विद्यमान 8 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से लगातार तीसरे वर्ष के लिए काफी कम होगी।

समग्र सकल देशी उत्पाद वृद्धि

7.5 इस प्रकार, 1993-94 के लिए संभावनाएं समग्र आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के साथ स्पष्ट रूप से बेहतर प्रतीत होती हैं। कृषि में बनाये रखी गई वृद्धि और उद्योग में सुधार के साथ 1993-94 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगभग 5 प्रतिशत होगी।

वचन दर और उत्पादकता

7.6 1980 के दशक के दौरान वास्तविक कुल निवेश सकल घरेलू उत्पाद अनुपात लगभग 21 प्रतिशत था जबकि औसत वास्तविक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी। इस प्रकार, 3.6 का वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (ग्राइ सी ओ ग्रार) प्राप्त किया गया। 1990-91 से 1992-93 तक की तीन वर्षीय अवधि में कुल निवेश सकल देशी उत्पाद अनुपात लगभग 23 प्रतिशत था जबकि वास्तविक वृद्धि केवल 3.5 प्रतिशत तक ही रही। इस प्रकार, 6.6 का वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात प्राप्त किया गया। जहां निम्न वास्तविक आय वृद्धि के एक वर्ष में एक उच्च वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात को समझा जा सकता है, वहीं अनेक वर्षों के दौरान निरंतर उच्च वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात चिंताजनक है। हमें अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता मिद्ध होती है। एक ओर जहां वचन निवेश अनुपात को बढ़ाने के लिए गुंजाइश है, वहीं दूसरी ओर उत्पादकता और प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण के प्रादुर्भाव से इस संबंध में सहायता मिलेगी। एक अन्य महत्वपूर्ण

तत्व जिसका अंततः उत्पादकता पर प्रभाव पड़ सकता है, वह है सकल देशी उत्पाद के सापेक्ष रूप में सकल राजकोषीय घाटे का संतुलन। इसका यह अर्थ होगा कि जब तक जोखिम के लिए समायोजित निवेशों पर प्रतिफल की प्रभावी दरों को पर्याप्त माना जाता है तब तक मार्बेजनिज और नीजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियां “अंतः प्रवाही” घटना के हिताधिकारी होंगी। इसके कंपनी क्षेत्र का हित होना चाहिए और उसकी निवेश योजनाओं के वित्तपोषण में सहायता मिलनी चाहिए। फिर भी, अलग-अलग इकाइयों को निधियों के प्रवाह का निर्धारण इकाई की प्रतिस्पर्धात्मक कुशलता और उसकी कारबार युक्तियों के अनुसरण में विश्वसनीयता के आधार पर किया जाएगा।

राजकोषीय उद्विकास : मुद्दे

7.7 1992-93 में राजकोषीय स्थिति में सुधार जिस रूप में प्रारंभ में आयोजित किया गया था उससे अपेक्षाकृत अल्पतर पाया गया। सकल देशी उत्पाद के 5 प्रतिशत के सकल राजकोषीय घाटे के मुकाबले, जिसकी बजट में व्यवस्था की गयी, वास्तविक घाटा 5.7 प्रतिशत हुआ। यद्यपि मुद्राकृत घाटा परिकल्पना से निम्नतर था, तथापि उसका ठहराव केवल अस्थायी था क्योंकि बहुत अल्पावधि पुनः खरीद कार्यों का मुद्रा विस्तार पर केवल अस्थायी प्रभाव ही रहा। 1993-94 के प्रारंभिक महीनों में केन्द्र सरकार के बजट घाटे में अत्यंत तेज वृद्धि हुई जो 20 अगस्त 1993 तक 21,065 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। केन्द्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण 16,245 करोड़ रुपये था। फिर भी, परम्परागत बजट घाटा प्राथमिक मुद्रा विस्तार की सीमा को अधिक बताता है क्योंकि उसमें नीलाम किये गये 91-दिवसीय खजाना बिल सम्मिलित हैं जो प्रमुखतः भारतीय रिजर्व बैंक से बाहर धारित हैं और अधिकाधिक कुल 91-दिवसीय खजाना बिलों का उल्लेखनीय अनुपात बन रहे हैं। केन्द्र को रिजर्व बैंक का निवल ऋण जो परम्परागत घाटे से निम्नतर है, फिर भी अधिक रहा। 20 अगस्त 1993 को यह 16,245 करोड़ रुपये था। इन प्रवृत्तियों को शीघ्र ही ठीक करने की आवश्यकता है, अन्यथा विस्तृत मौद्रिक विस्तार होगा जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में तेजी से वृद्धि होगी तथा वित्तीय क्षेत्र में स्थिरीकरण की पुनः व्यवस्था और संरचनागत सुधार के सुदृढीकरण का कार्यक्रम निष्प्रभावी होगा जिसका पिछले दो वर्षों के दौरान परिश्रमपूर्वक अनुसरण किया गया है।

7.8 केन्द्र के राजकोषीय कार्यक्रमों में गैर-अनिवार्य राजस्व व्ययों जैसे-आर्थिक सहायता और प्रशासनिक सेवाएं आदि में कटौतियां करने, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उर्वरक सहायता से विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की कीमतों में आपसी तालमेल में कोई अन्तर न आये ताकि उर्वरकों का मिले जुले उपयोग में प्रतिकूल प्रभाव न आये। साथ ही सरकार को चाहिये कि ब्याज-रहित राजस्व प्राप्तियों एवं कर राजस्व में सुधार करने पर अधिक ध्यान देना होगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह कुल व्यय में पूंजी परिव्यय का हिस्सा बढ़ाये जिसमें उच्च वृद्धि की संभावना बन सके। केन्द्र सरकार की ओर से विश्वसनीय राजकोषीय कार्य न केवल अपना स्वयं का घाटा ठीक करने के लिए बल्कि उन राज्यों के लिए मिसाल कायम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसके वित्त भी गड़बड़ी की प्रवृत्तियां दर्शा रहे हैं। राज्य सरकारों के राजस्व खाते 1987-88 से घाटे में रहे हैं। अतः, राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे गैर-योजना व्यय, विशेषकर प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय कम करें, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता प्रभारों का ऊर्ध्वमुखी संशोधन करते हुए करेतर आय बढ़ायें तथा राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों की लाभप्रदता निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करें।

वित्तीय प्रणाली में सुधार

7.9 वित्तीय प्रणाली के कार्यचालन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए कई उपाय किये गये। विशेषतः वाणिज्य बैंक एक समयबद्ध संरचनात्मक स्वरूप परिवर्तन की प्रक्रिया के अधीन हैं। उक्त सुधार कार्यक्रम प्राथमिक तौर पर वित्तीय क्षेत्र को अधिक सक्षम, कुशल और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए तैयार किया गया है। नीति इस बात पर बल देती है कि समग्र रूप में वित्तीय प्रणाली की परिचालन और आवंटनगत कुशलता में सुधार लाया जाए। उसके कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले कई बाह्य और संरचनात्मक तत्वों का सुधार करके इसे प्राप्त करना अपेक्षित है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐसी स्वायत्त कारबार इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो अपने कार्यनिष्पादन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हों। वित्तीय क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के अन्तर्गत बाह्य प्रतिबंधों को मुक्त बनाने, ऋण हानियों और पूंजी पर्याप्तता के विषय में प्रावधानीकरण से संबंधित उचित विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करने, लेखाविधि और सूचना की प्रक्रियाओं में सुस्पष्टता लागू करने, बैंकों की पुनःसंरचना और उनका पुनःपूँजीकरण करने तथा निजी सहभागियों के प्रवेश के माध्यम से बाजार के प्रतियोगी तत्व को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र का समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए विधायी परिवर्तन करने पर भी विचार किया जा रहा है।

7.10 वाणिज्य बैंकों के खातों में अधिकतर सुस्पष्टता लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किये जा चुके हैं। उनकी वित्तीय शक्ति और समग्र उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए यह एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। बैंकों द्वारा 1992-93 के अपने खातों पर ये नये नियम लागू किये जा रहे हैं और इनके प्रत्येक बैंक की वित्तीय स्थिति का एक अधिक सही चित्र प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उक्त मानदंड इस प्रकार बनाये गये हैं कि वे दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिकाधिक सक्षम रहें। जहां उक्त मानदंड 31 मार्च

1993 को समाप्त लेखा-वर्ष से लागू होंगे, वही बैंकों को अपेक्षित प्रावधान 31 मार्च 1994 तक करने की अनुमति दी गयी है। यह अनुमान है कि 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग 13 बैंक नये मानदंडों के अनुसार प्रावधान करने के बाद 3,500 करोड़ रुपये की कुल हानि दर्शाएंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें निर्धारित पूंजीगत पर्याप्तता के मानदंड पूरे करने होंगे। इस पृष्ठभूमि के आधार पर अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने की एक योजना बनायी गयी है। तदनुसार, सरकार ने 1993-94 के बजट में राष्ट्रीयकृत बैंकों का पुनः पूंजीकरण करने के लिए 5,700 करोड़ रुपये की पूंजी का आभिवान करने हेतु प्रावधान किया है। यह राशि बैंकों के बीच इस प्रकार आवंटित की जाएगी जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक मार्च 1993 की समाप्ति पर 4 प्रतिशत का न्यूनतम पूंजी-जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) प्राप्त करें और अपनी पूंजी को भी अधुण रखें। प्राप्तकर्ता बैंकों से यह अपेक्षा होगी कि वे सरकार के पूंजी आभिवान का निवेश सरकारी बांडों में करें। बैंकों को लाभप्रदता और आमदनी अनुपातों, ऋण की गुणवत्ता और वसूलियों, कंप्यूटरीकरण, ग्राहक सेवा, नकदी और निवेश प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट समयबद्ध वायदे भी करने होंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों का पुनः पूंजीकरण और सुदृढीकरण ठीकाऊ आधार पर हो। वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के अलावा, सुस्पष्ट (क्लीन्ड-अप) तुलन-पत्रों से कुछ बैंक, जब भी उचित विधायी परिवर्तन लागू होंगे तब अतिरिक्त ईक्विटी जुटाने के लिए पूंजी बाजार से संपर्क कर सकेंगे।

7.11 पूंजी-पर्याप्तता के प्रति जोखिम वाले दृष्टिकोण के अनेक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि उच्चतर जोखिम वाली संस्थाएं पूंजीगत निधियों का उच्चतर स्तर बनाये रखें। ऐसा दृष्टिकोण जो न्यूनतम पूंजी के निर्धारण में किसी बैंक की तुलन-पत्रगत ऋण-जोखिमों को सम्मिलित करता है, बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हों और अपने तुलन-पत्र की संरचना अधिक विवेकपूर्ण तरीके से करें। इसके लिए अलग-अलग बैंक प्रबंधन से यह अपेक्षा होगी कि वे परिसंपत्तियों और निवेशों की विभिन्न श्रेणियों की जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से संसाधन जुटाने के संदर्भ में और विभिन्न श्रेणियों में निधियों के निवेश के लिए भी उचित जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियां अपनाएं।

7.12 वर्षों से भारतीय बैंकों की एक विशेषता निम्न-स्तर की लाभप्रदता रही है। इसके परिणामस्वरूप, आरक्षित निधियों का निर्माण अत्यंत निम्न स्तरों पर रहा है और फलस्वरूप स्वाधिकृत निधियों का सुदृढीकरण बार-बार अतिरिक्त पूंजी से निवेश कर करना पड़ा है। सरकार ने 31 मार्च 1993 तक 4,000 करोड़ रुपये का अंशदान किया है। पूंजी निवेश के इस कार्यक्रम का स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अर्थक्षमता को पुनः कायम करने के कार्यक्रम

का एक भाग होने के बजाय, हानियों को गोरनीय रखने का औपचारिक प्रयास अधिक रहा।

7.13 अब अपनायी जा रही पुनः पूंजीकरण स्कीम केवल बैंकिंग प्रणाली को वित्तीय रूप से सुदृढ और सक्षम बनाने की ओर ये आरंभिक कदम है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी का आभिवान बैंकिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए, जो एक मध्यावधि बहुमुखी प्रक्रिया है, उसका केवल एक भाग है। चूंकि लेखाविधि के मानदंड कड़े हैं और न्यूनतम पूंजी स्तर में वृद्धि हुई है, अतः एक समूह के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजीगत कमी 1994-95 तक उल्लेखनीय रहेगी। न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंकों को सरकार अथवा पूंजी बाजारों से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। फिर भी, तुलन-पत्र के आकार में निरंतर वृद्धि केवल प्रति-धारित आमदनी के आधार पर ही संभव होगी जो समग्र आमदनी का एक कार्य है। इसके समान ही, भावी निजी निवेशक इस आश्वासन की अपेक्षा करेंगे कि अर्जन और लाभांश की वृद्धि पर्याप्त रूप में आकर्षक होगी। अतः, बढ़ी हुई लाभप्रदता, जैसी कि वह नये लेखाविधि मानदंडों द्वारा मापी गयी है, अनिवार्य होगी। इस प्रकार की बढ़ी हुई लाभप्रदता गैर-निधि आधारित आय के अधिकतर उत्पादन लागतों (विशेषकर, ऊपरी लागत) में कमी, एवं ऋण वसूली में सुधार को संबद्ध करेंगी। सरकार द्वारा बाजार स्तर से नीचे निधियों के पूर्वक्रय में कमी से बैंकों को उनकी जमा और सामान्य उधार व्याज दरों के बीच का मार्जिन कम करने और प्रमुख ग्राहकों को उधार देने में उनकी प्रति-स्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य परिसंपत्तियां अनुविधाजनक रूप से उच्च स्तरों पर हैं। उक्त अनुपयोज्य परिसंपत्तियां, जो इस प्रकार के अभिमानों में धारित प्रतिभूति और/या गारंटियों को देखते हुए वसूली योग्य मानी गयी हैं, कुल अनुपयोज्य परिसंपत्तियों का काफी बड़ा अंश बनती हैं। अतः, बैंक प्रबंधन को दो बिन्दुओं की कार्यनीति अपनानी होगी: पहले, इस प्रकार की अनुपयोज्य परिसंपत्तियों की त्वरित वसूली के लिए प्रयास करना और दूसरे, यह सुनिश्चित करना कि वृद्धिशील अनुपयोज्य परिसंपत्तियों को पर्याप्त रूप में निम्न स्तर पर रखा जाए। इस संदर्भ में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं हेतु विशेष वसूली प्राधिकरण बनाने के लिए एक नया अधिनियम संसद ने पारित किया है। इस प्रकार के प्राधिकरणों की शीघ्र स्थापना से बैंकों के लिए उनको देय ऋणों की त्वरित वसूली में सहायता मिलनी चाहिए।

7.14 1992-93 और 1993-94 में न्यूनतम प्रावधानों में वृद्धि के बाद भी बैंकों के पास अनुपयोज्य परिसंपत्तियां रहेंगी। जब तक ये अवशेष परिसंपत्तियां बहियों में रहेंगी तब तक बैंकों के लिए अपेक्षित स्तर तक अपनी लाभप्रदता को बढ़ाना कठिन होगा। भारतीय परिवेश में एक केन्द्रीयकृत राष्ट्रव्यापी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि (ए आरएफ) की जो कमियां पायी गयी हैं, वे हैं भारत जैसे

विशाल देश में एक नयी संस्था के लिए भौगोलिक पहुंच का अभाव एवं वे संस्थाएं जो वाणिज्य बैंकों को उनकी वसूली के दायित्वों से मुक्त करती हैं जिससे लाभप्रद खातों से वसूली करने का उनका संकल्प कमजोर पड़ सकता है और लाभप्रद खातों को रण होने में प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रश्न भी है कि न्यूनतम प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं द्वारा अपेक्षित सीमा की तुलना में परिसंपत्ति सविभाग के एक बृहत्तर भाग के मूल्यहासन से बनी पूंजी की कमी का वित्तपोषण कैसे किया जाए। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की समस्या का निराकरण किसी एक समाधान से नहीं हो सकता। इसके बजाय, अलग-अलग बैंकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहल करना संभवतः आवश्यक होगा।

7.15 एक ओर जहां पूंजी-पर्याप्तता और अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधानीकरण की आवश्यकता पूरी करने के लिए बैंकों की संसाधनगत अपेक्षाएं अत्यधिक होगी, वहीं दूसरी ओर इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि अधिकतर सुस्पष्टता अपने-आप में किसी भी रूप में बैंकों की शोध-क्षमता में कमी का कारण नहीं बनती, बहुत करके इन प्रश्नों पर ठीक-ठीक ध्यान देने से बैंकों का समग्र स्थिति में सुधार की ओर प्रगति हो सकेगी। दूसरे शब्दों में, अपेक्षाकृत कठोरतापूर्वक विवेकपूर्ण मानदंडों के कार्यान्वयन की ओर गतिशील होता जमाकर्तियों को अपनी जमाशायियों की सुरक्षा के विषय में चिंता का कारण किसी भी तरह नहीं बन सकता, उल्टे ये सभी उपाय जमाकर्तियों के हितों की रक्षा करेंगे।

7.16 बैंकों के लिए इस बात की भी आवश्यकता होगी कि वे अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यनीतियों को विशेष रूप से ऋण प्रबंधन और निवेश प्रबंधन के संदर्भ में मजबूत करें। उपयुक्त कीमत निर्धारण प्रतिविधियों के अतिरिक्त, ऋण मूल्यांकन, ऋण निगरानी और जोखिम परिसंपत्तियों/निवेशों के प्रबंधन की ओर उन्मुख नीतियों में उचित परिवर्तन करने होंगे। ब्याज-दर जोखिम, परिपक्वता जोखिम और विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए कार्यनीतियां बनानी होंगी जो आने वाले समय में अधिकतर महत्व प्राप्त करेंगी। देयता प्रबंधन पर अब तक की अपेक्षा और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कारबार और सेवाओं का विशेषकर कम लागत, व्यर्थ के कार्यकलाप जो लाभप्रद नहीं हैं, को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्मतर अवलोकन करना होगा। उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कंप्यूटर और संचार की प्रौद्योगिकियों के विस्तृत प्रयोग-सहित नवीन तकनीकी प्रक्रियाओं परिचालनों की सुधरी प्रक्रिया आदि के बारे में विचार करना होगा। अलाभकारी शाखाएं बंद करने शाखाओं का स्थान बदलने, कारबार को मिलाने, आदि-सहित शाखा नेटवर्क के युक्तिकरण पर भी अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह एक तथ्य है कि कुछ बैंकों में उनके कारबार की मात्रा की तुलना में स्टाफ बहुत ही

अधिक संख्या में है तथा इस प्रकार के बैंकों की सक्षमता को पुनः कायम रखने के लिए स्टाफ-स्तर का औचित्यस्थापन एक पूर्वपिक्षा है।

निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना

7.17 निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जनवरी 1993 में निर्धारित किये गये थे। एक ओर जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महत्व और उनकी भूमिका की पहचान की गयी थी, वहीं दूसरी ओर अधिकतर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करने की भी बड़ी हुई आवश्यकता थी जिससे बैंकिंग प्रणाली में अधिकतर उत्पादकता और कार्य-कुशलता आ सकती है। अतः, उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि नये प्रवेश करने वाले बैंक वित्तीय रूप से सक्षम हैं और तकनीकी रूप से सुदृढ़ हैं तथा ऋण का केन्द्रीकरण, आर्थिक शक्ति का एकाधिकारीकरण, औद्योगिक समूहों के साथ प्रतिधारण, आदि नहीं हैं। एक ओर जहां कई प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं, वहीं यह संभाव्य पाया गया है कि पहले वित्तीय संस्थाओं में प्राप्त आवेदनपत्रों पर इन संस्थाओं के पिछले रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाए। "सैद्धान्तिक रूप में" अनुमोदन तीन संस्थाओं को नयी बैंकिंग कंपनियां प्रारंभ करने के लिए कुछ नियमों और शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है जिनके बारे में अनुमान है कि इन कंपनियों की शोयर्धारिता अधिक व्यापक होंगी। ये बैंक ग्रामीण, अर्ध-गहरी और शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलेंगे, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करेंगे और प्रारंभ से ही जोखिम वाली परिसंपत्तियों के 8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करेंगे।

7.18 अन्य संभावित प्रवेशकों में बैंकेतर वित्तीय कंपनियों के कार्यकलाप बैंकिंग गतिविधियों के सबसे निकट हैं तथा निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने में दूसरों की तुलना में उनकी स्थिति अधिक अनुकूल है। फिर भी, मूल संस्था और उनकी सहायक संस्था के बीच संबंधों में पर्याप्त दूसरी स्थापित करने के लिए सुपरिभाषित मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता है। चूंकि यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है, अतः यह वांछनीय है कि प्रारंभ में ही भलीभांति स्वीकृत आधारभूत नियमावली निर्धारित की जाए।

बैंकेतर वित्तीय कंपनियों में सुधार

7.19 एक ओर जहां बैंकेतर वित्तीय कंपनियों ने विविध प्रकार की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने में उपयोगी भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी ओर यह आवश्यक है कि संगठित वित्तीय प्रणाली की मुख्यधारा से जुड़े के लिए इन कंपनियों का पर्याप्त मात्रा में समायोजन किया जाए। इसके लिए कार्यकलापों की बृहत्तर सुस्पष्टता और पूर्णतर प्रकटीकरण की अपेक्षा होगी। आवश्यकता तो भली भांति समेकित नियंत्रक ढांचा बनाने की है जिसमें (क) विद्योप रूप से, संपत्ति अधिकार, दिवालियापन कानून, लेखाविधि सूचना के प्रकटीकरण आदि से संबंधित कार्य करने के लिए, एक उपयुक्त

कानूनी संरचना तथा संविदाजात कानूनी बाध्यताएं लागू करने के लिए तंत्र, और (ख) विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत और एक निगरानी तंत्र सम्मिलित हो जो किसी भी संभव प्रणालीगत संकट के विरुद्ध रक्षोपाय की व्यवस्था करता है।

7.20 रिजर्व बैंक ने सिद्धांत के रूप में शाह कार्यकारी दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। फिर भी, कुछ सिफारिशों को समग्र नीतिगत ढांचे के योग्य होने के लिए आशोधित करना होगा, जबकि कुछ अन्य सिफारिशों में विधायी परिवर्तन आवश्यक होंगे। तदनुसार, उक्त उपायों को एक चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है जिससे संक्रमण काल की कठिनाइयों को न्यूनतम बनाते हुए उक्त कंपनियों के पास प्रत्येक चरण में निदेशों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय हो। पूंजी-पर्याप्ता, आय की मान्यता और प्रावधानीकरण से संबंधित सिफारिशें बनायी जा रही हैं तथा शीघ्र ही उन्हें लागू किया जाएगा। वर्तमान में वित्तीय कंपनियों का अत्यधिक श्रेणीकरण किया जाता है जिसके साथ विपुल विभिन्नता से युक्त नियंत्रक ढांचा संबद्ध है। वर्तमान ढांचा वित्तीय कंपनियों के अलग-अलग समूहों के लिए भिन्न-भिन्न है तथा इसे एकल प्रभावी ढांचे के रूप में प्रयोजनात्मक तौर पर एकीकृत किया जा सकता है। शाह कार्यकारी दल द्वारा परिकल्पित रूप में स्व-नियंत्रक संगठनों (एसआरओ) की भूमिका एक ऐसा विचार है जिसका आगे अनुसरण किया जाना चाहिए। वित्तीय उदारीकरण की गति बढ़ाने और वित्तीय बाजार को और सघन और विस्तृत बनाये जाने के साथ ही स्व-नियंत्रित संगठनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो यह देखेंगे कि अलग-अलग सदस्य नियंत्रक प्राधिकारियों के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हैं और विवेकसम्मत आधार पर कार्य करते हैं। वर्तमान नियंत्रक दृष्टिकोण प्रथमः जमाराशियों की मात्रा को सीमित करने तथा जमाराशियों के स्वीकरण की शर्तें निर्धारित करने पर आधारित है। शाह कार्यकारी दल ने यह सही सुझाव दिया है कि इस नियंत्रक दृष्टिकोण में क्षेयता से परिसंपत्ति की ओर परिवर्तन हो। यह बैंकों के लिए लागू की जा रही पूंजी पर्याप्ता के मानकों और बैंकेतर वित्तीय कंपनियों पर उनकी प्रयोज्यता के बिलकुल योग्य होगा। वास्तव में, शाह कार्यकारी दल ने सभी पंजीकृत बैंकेतर वित्तीय कंपनियों के लिए अनिवार्य मास्त्र-निर्धारण की जो सिफारिश की उस पर उक्त कार्यकारी दल द्वारा परिकल्पित रूप में निर्धारित समय-सीमा की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय-सीमा के अंदर विचार किया जाना चाहिए। निवेशकों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों में यह एक उपाय होगा। प्रभावी और व्यवहार्य विनियमों के साथ में परम्परा से हटकर किये गये परिवर्तन और पर्यवेक्षण से बैंकेतर वित्तीय कंपनियों के सुदृढ़ और सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वित्तीय प्रणाली की अर्थक्षमता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

7.21 हाल ही में, रिजर्व बैंक ने अंतर कम्पनी जमाराशियों के लिए कतिपय दूरदर्शी मापदंड लागू किये हैं।

जो कम्पनियां अविवेकपूर्ण जोखिम उठाती रही हैं उनके प्रणालीबद्ध तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं इसलिए इस प्रकार के मानदंडों का अभाव एक गंभीर कमी थी। यह तर्क करना अनुचित है कि चूंकि अंतर-कम्पनी जमाराशियां कम्पनियों द्वारा रखी गयी निवेशराशियां हैं इसलिए विवेकपूर्ण मानदंडों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चय ही ये कुछ कम्पनियों के अविवेकपूर्ण तरीके हैं जो बड़ी प्रणालीबद्ध जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसके अनतिरिक्त, अंतर कम्पनी जमाराशियों का विनियमन व्यापक सर्वेक्षण के बाद लागू किया गया है और केवल कुछ ही कम्पनियों को बड़े समायोजन करने होंगे और यहां भी रिजर्व बैंक समायोजन के उदार चरणबद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहा है।

7.22 जिन कम्पनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां 50 लाख रुपये से अधिक हैं उन सभी कम्पनियों के लिए जुलाई 1993 के अंत तक पंजीकरण की प्रणाली लागू की गयी है। व्यवसाय का विस्तार करते समय ऐसी वित्तीय कम्पनियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को संतोषजनक ढंग से पूरा करना विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए यह इन सभी कम्पनियों के हित में होगा कि वे पंजीकरण की अपेक्षाओं को तेजी से पूरा करें।

7.23 इस समय बैंकेतर वित्तीय और बैंकेतर गैर-वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों की ब्याज दरें विनियमित की जाती हैं। जब तक बैंक की जमा-दरों को विनियमित किया जाता है तब तक इन ब्याज-दरों को विनियमित करने की आवश्यकता होगी। इसके अनतिरिक्त, जब तक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली को अनिवार्य नहीं किया जाता जब तक कम्पनी-जमाराशियों का नियंत्रण आवश्यक होगा। कम्पनियों की जमा-दरों की व्यापकता की सीमा तक यह आवश्यक है कि वित्तीय और गैर-वित्तीय कम्पनियों पर वही नियंत्रित ब्याज दर लागू की जाये।

ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी प्रणाली

7.24 नीति निर्धारण में अन्य एक और ध्रांति का सामना करना पड़ रहा है और वह है ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी प्रणाली। देश के बहुत बड़े भाग में सरकारी ऋण संस्थाएं वित्त की कमी और प्रबंधकीय कमजोरी से पीड़ित हैं। वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिक प्रशासनिक व्यय, अत्यधिक प्रतिदेय और अर्थक्षमहीन ब्याज दर विन्यास के कारण ग्रामीण ऋण क्षेत्र में काफी हानि उठानी पड़ी है। तथापि, सक्षम कृषि आधार को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण ऋण की आपूर्ति उत्पादक कार्यकलाप के समर्थन हेतु उपयुक्त स्तर पर बनाये रखी जाय। यह विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर कृषि की वृद्धि दर के कारण ही बनी रही। इस प्रकार की सुपुर्दगी प्रणाली के लिए अपेक्षित संस्थागत व्यवस्था का शीघ्र विकास करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, ऋण की वसूली के लिए कानूनी उपबंधों का पूरक समर्थन भी आवश्यक है। कृषि और ग्रामीण ऋण में बैंकों की

विगत हानियों को भी समायोजित करने की आवश्यकता है जो वर्तमान संस्थाओं का सुदृढ़ पुनः पूंजीकरण और उनकी उधार नीतियों से सम्बन्धित बाधाएं दूर करके किया जा सकता है।

7.25 कृषि ऋण अन्य क्षेत्रों के ऋण से अपेक्षाकृत कम हैं इसलिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं इन ऋणों को अनाकर्षक मानती हैं क्योंकि निधियों की लागत और इस प्रकार के ऋण के लिए निर्धारित व्याज दर के बीच पर्याप्त मार्जिन है। उधार दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक भाग के रूप में यह स्वीकार किया गया है कि अब दो स्तरीय विन्यास की आवश्यकता है इन में से एक दर बाजार द्वारा निर्धारित होगी और दूसरी दर रियायती दर होगी जो प्रमुख उधारकर्ताओं पर प्रभावित की जाने वाली दर 2 से 3 प्रतिशत कम होगी। इससे छोटे ऋणों के लिए व्याज दर में कुछ वृद्धि मिहित है परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात छोटे उधारकर्ताओं के लिए व्याज दर कम रखना नहीं है बल्कि इन उधारकर्ताओं को पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करना है। स्पष्ट है कि इसके लिए व्याज दर थोड़ी-सी उच्चतर होगी। इसका उद्देश्य अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्र को कुछ उच्चतर व्याज दर पर ऋण की प्रभावी आपूर्ति बढ़ाना है। क्योंकि छोटे उधारकर्ताओं को विकल्प के रूप में अत्यधिक उच्च व्याज दर पर अनौपचारिक स्त्रोतों का बड़े पैमाने पर आश्रय लेना पड़ता है। सहकारी ऋण विन्यास के लिए इस समय निर्धारित व्याज दरें स्पष्टतः अर्थक्षम नहीं हैं क्योंकि निधियों की लागत उस पर मिलने वाले प्रतिलाभ से कहीं ज्यादा है। इस संबंध में एक विचार यह था कि सहकारी ऋण विन्यास जमा/उधार दर नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो ताकि ये व्याज दरें वास्तविक स्तरों पर निर्धारित की जा सकें।

7.26 ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को व्यापक बनाते समय बैंक स्वयं-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं को ऋण प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार के संगठन ग्रामीण गरीबों की ऋण सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं का पता लगाने और उन्हें पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। ऋण सुपुर्दगी की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास पुनर्गठित ऋण वसूली प्रणाली से अनुपूरित होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना ग्रामीण ऋण प्रणाली को बनाये रखना असंभव हो जायेगा। अपनी वसूली व्यवस्था में सुधार लाते समय वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्थाएं वसूली मददगारों को स्थानीय रूप से नियुक्त करने पर सोच सकती हैं जो ऋण की वसूली में सहायता दे सकेंगे।

बैंकों में कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली

7.27 बैंकिंग के कतिपय क्षेत्रों में पहले से ही कम्प्यूटरीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रिजर्व बैंक के अधिकतर प्रमुख केन्द्रों में सहायक सामान्य खाता बही का कम्प्यूटरीकरण

पहले ही किया जा चुका है। महानगरीय केन्द्रों में चेक समाशोधन से सम्बन्धित सभी कार्यकलाप कम्प्यूटर द्वारा किये जाते हैं। सम्प्रेषण की "बैंक नेट" प्रणाली के अंतर्गत संदेश भेजने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है जिसमें "बैंक नेट" से सम्बद्ध स्थानों के बीच निधि अंतरण अनुदेश भी दिये जा सकते हैं। इस नेटवर्क की और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत देशों के उस समूह में भी शामिल हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय "स्विफ्ट" नेटवर्क के सदस्य हैं। वाणिज्य बैंक अपने-अपने कार्यालयीन स्तर पर "बैंक आफिस-कार्य" लेखांकन तथा कार्यालयीन व्यवस्था सम्बन्धी अन्य कार्यकलापों के लिए अधिकाधिक कम्प्यूटर लगा रहे हैं। परन्तु कम्प्यूटर लगाने का यह कार्य महानगरीय तथा प्रमुख शहरी केन्द्रों की अपेक्षाकृत बड़ी शाखाओं में ही किया गया है। ऐसी संख्या सीमित है। इस प्रकार की गयी प्रगति बैंकिंग उद्योग को कम्प्यूटरीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

7.28 बैंकों में कम्प्यूटरीकरण की गति ऐसी होनी चाहिए जो ग्राहक सेवा के वर्तमान स्तर को सुधार सके, निर्णय लेने में सहायक हो सके, बैंकों की उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार ला सके। इसलिए बैंकिंग उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि वह संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करे और कम्प्यूटरीकरण के लिए सुपरिभाषित और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करे। कार्यक्षमता और ग्राहक सेवा में सुधार लाने के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अगले दो-तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 400 शाखाएं पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत की जानी हैं। त्रुटि ग्रन्थव्यवस्था नियमों/विनियमों से उत्तरोत्तर मुक्त हो रही है और वित्तीय क्षेत्र में किये जा रहे सुधारों से बाजार की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है इसलिए संसाधन प्रबंधन की दृष्टिगत आयोजना सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण आवश्यक है। प्रतिभूति के लेन-देन में बरती गयी अनियमितताओं के कारण प्रभावी बाजार प्रामुखता और आधुनिक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता बड़ी ही स्पष्टता के साथ उभर कर सामने आयी है। इन्हीं अनियमितताओं ने बड़े पैमाने पर सूचना के अंतर्गलों और अभावों को उजागर किया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में लेन-देन

7.29 प्रतिभूतियों के लेनदेन में बरती गई अनियमितताओं के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में गौण बाजार के कार्यकलाप लगभग रुक से गये थे। इस धारणा को मणक्त अभिव्यक्ति दी गयी कि पुनःखरीद सुविधा का पुनरारंभ करने से सरकारी क्षेत्र के बांडों का गौण बाजार पुनः सक्रिय करने में गतिशीलता आ सकती है। सरकारी क्षेत्र के बांडों का जिम तरह आबंटन हुआ और इस बांडों के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि निधियों के आवर्तन पर वस्तुतः पूर्ण आश्रय तथा बाद की अत्यधिक अनियमितताएं जिस तरह बढ़ती गयीं उसमें सरकारी क्षेत्र

के बांडों का बाजार पूरी तरह धाराशाही हो गया। अतः, यह आवश्यक है कि इन बांडों का अर्थक्षम और स्थायी बाजार का पुनर्गठन करने का प्रयास करते समय इस अनुभव से भी कुछ सीखा जाए। इसी संदर्भ में, इन बांडों की बिना किसी पर्याप्त समाशोधन और निपटान प्रणाली से पुनः खरीद को फिर से प्रारंभ करना जोखिम भरा काम होगा। उचित अभिलेखन/भुगतान प्रणाली के बिना मात्र संपादित प्रतिभूतियों से समर्थित पुनः खरीद प्रणाली से ठीक वैसे ही समस्याएं उत्पन्न होंगी जो प्रणाली भंग हो जाने के परिणाम-स्वरूप हुई थीं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शेयर बाजार में जब निर्बाध रूप से व्यापार होने लगेगा तब पुनः खरीद अनावश्यक हो जायेगी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि समाशोधन और निपटान संबंधी उचित प्रक्रिया विद्यमान है, यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रारंभिक अभिवान अधिक-से-अधिक संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है ताकि एक या दो अभिधारकों के पास गलत तरीके से राशि के जमाव को ढाला जा सके। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए फिर यह आवश्यक है कि वे केवल वह राशि जुटाएँ जिससे उनकी 12-24 महीने की आवश्यकताएं पूरी होती हों। इन बांडों की परिपक्वता अवधि कम करने की ओर भी सोचा जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गौण बाजार में इन बांडों के लिए पर्याप्त अर्थसुलभता रहती है, बाजार संतुलनकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जहां भारतीय मित्टिकाटा और वित्त गृह लिमिटेड और प्रस्तावित भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम जैसी संस्थाएं संभवतः कुछ गहराई के साथ बाजार के लिए बाजार संतुलन कार्यकलापों का विकास कर सकती हैं वहीं अनेक बाजार संतुलन कर्ताओं की भी आवश्यकता होगी। बांड जारी करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शेयर बाजार के संतुलन कर्ता द्वारा निपटान के लिए कुछ राशि अर्थात् 10 से 15 प्रतिशत तक राशि रखी जा सकती है ताकि बाजार संतुलनकर्ता इन बांडों के लिए दो तरह की दरें प्रस्तावित कर सकें। जहां नाडकर्णी समिति ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के गौण बाजार के लिए समाशोधन, निपटान और निक्षेपन (ईसीएलडी) की इलेक्ट्रानिकी प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की है, वहीं यह संकेत मिले हैं कि व्यापार की इस प्रकार की प्रणाली के परिचालन के लिए समय लगेगा। रिजर्व बैंक इस बात पर बड़ी सक्रियता से विचार कर रहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रचलित सहायक सामान्य खाता बड़ी प्रणाली को उन संस्थागत बड़े निवेशकों (जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड इत्यादि) द्वारा उन बांडों के व्यापार पर लागू की जायगी जिन्हें सहायक सामान्य खाता बड़ी संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आशा की जाती है कि यह योजना आगामी कुछ महीने में प्रारंभ हो जायेगी। प्रारंभ में ऐसे बांडों के नये निर्गमों को एस०जी०एल० प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किया जायगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं कि व्यापार और अदायगी का निपटान साथ-साथ किये

जा रहे हैं ताकि इन बांडों के विक्रेता और क्रेता दोनों की जोखिम समाप्त की जा सके।

प्रतिभूति लेनदेनों में अनियमितताओं के निहितार्थ

7.30 जानकीरामन समिति ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेनदेन सम्बन्धी कार्यकलापों में बरती गयी अनियमितताओं की जांच पूरी करी। समिति ने प्रस्तुत छः रिपोर्टों में अनियमितताओं का व्यापक स्वरूप और काम में लाये गये तरीकों को बड़े ही स्पष्ट रूप से उजागर किया है। दलालों/वित्तीय कंपनियों और बैंकों (उनकी कतिपय सहायक संस्थाएं) के बीच विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं और निधियों के प्रबंधन से संबंधित रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के खुले उल्लंघन के तरीकों को भी समिति ने बड़े ही स्पष्टता से उजागर किया है। जहां ये रहस्योद्घाटन और परवर्ती जांच वित्तीय प्रणाली में वर्ष 1992-93 की एक मात्र सबसे बड़ी घटना रही है वहीं मुद्रा और प्रतिभूति बाजार की कार्य-पद्धति को सामान्य बनाना और वित्तीय प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने की त्वरित आवश्यकता थी। परिचालन संबंधी प्रचलित तौर-तरीके, विनियामक विन्यास और बाजार-रखेज की काफी आलोचनात्मक समीक्षा की गयी। पूंजी बाजार सहित वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंगों के बीच परस्पर उल्लेखनीय संबंध उजागर हुए और अलग-अलग प्रबंध तंत्रों और विनियामक प्राधिकारियों, दोनों, के लिए इसमें सीख थी।

7.31 इन अनियमितताओं ने मजबूत और पर्यवेक्षण की सजग प्रणाली की आवश्यकता को उजागर किया है। संपूर्ण सदाशय के बावजूद आंतरिक नियंत्रण और लेखा-परीक्षा व्यवस्था तथा पर्यवेक्षण प्रणाली ने दुरुभिमंथि और प्रवंचनात्मक स्वरूप के वित्तीय कार्यकलापों को नहीं पहचाना। निरंतर बाजार की गतिविधियों पर समन्वित निगरानी रखने की व्यवस्था भी कमजोर साबित हुई।

7.32 वर्तमान पर्यवेक्षण तंत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रश्न उठाये गए हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बावजूद बैंक के पदाधिकारियों तथा ओरों ने उनका खुलकर उल्लंघन किया और यह तथ्य इस बात की ज़रूरत की तरफ इशारा करता है कि जैसे ही कोई उल्लंघन होता दिखाई दे तत्काल कड़ी निवारक कार्रवाई की जाए। यह बात निहायत आवश्यक हो जाती है पर्यवेक्षण सभी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन किया जाए और ऐसा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जाएगी और उच्चस्तरीय पेशेवर मानक बनाए रखे जाएं। नियामक की भूमिका पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा है जिसमें आम जनता यह सुवृद्ध विश्वास लेकर चलती है कि नियामक वर्ग एक ऐसी प्रणाली को अपनाएगा जिसमें काम शीघ्र और प्रभावी ढंग से हो और जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों का शब्दः निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा। जहां नियामकों को आम तौर पर निगरानी बनाये रखनी होती है, वहीं अनिय-

ने साफ तौर पर ये दिखा दिया है कि नियामकों के लिए विनियमों के उल्लंघनों को पूर्णतः समाप्त कर सकना संभव नहीं है, हालांकि एक समुचित तंत्र एक शक्तिशाली निवारक व्यवस्था की भूमिका अदा करेगा। अनियमितताओं के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करके, प्रबंध तंत्र में परिवर्तन लाकर गलती करने वाली संस्थाओं पर दंड आरोपित किये जाने के प्रस्ताव के जरिए प्रणाली में जिम्मेदार ठहराए जाने संबंधी एक बेहतर तत्व कायम किया जा सकेगा।

7.33 इन अनियमितताओं से एक और भी बात सामने आई है और यह है कि जो कानूनी तंत्र वित्तीय क्षेत्र की मदद करता है, उसे मजबूत बनाए जाने के उद्देश्य से विधायी परिवर्तनों का लाया जाना आवश्यक है। आपसी करारों के अमल में लाई जाने संबंधी प्रणाली के पेचीदा होने की वजह से प्रतिभूतियों में हुई अनियमितताओं से संबंधित विवादों का शीघ्र और संतोषजनक हल ढूंढ निकालने के प्रयासों में अड़चन आई है। एक साफ-सुथरे कानूनी तंत्र का निर्माण और उसका प्रवर्तन एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में निर्णायक साबित होगा जिसमें आपसी करारों की शर्तों का बाकायदा पालन हो। इस प्रकार प्रतिभूति बाजार के समुचित विकास में एक स्वतंत्रपूर्ण कानूनी प्रबंध तंत्र को एक अनिवार्य तत्व के रूप में जाना जाता है।

7.34 धोखाधड़ी का तुरंत पता लगाने के ऐसे तंत्र की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके साथ उसके उचित कार्यान्वयन का भी तंत्र हो। इस संबंध में अन्य देशों में विद्यमान विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं तथा भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रयोज्यता का अध्ययन किया गया है। उपयुक्त तंत्र के संबंध में शीघ्र की निर्णय लिया जाएगा।

7.35 आय निर्धारण और लेखा-विधि-प्रकटीकरण मानदंडों की मूल प्रणाली लागू करने के द्वारा परिचालनों में अधिकतर गुम्फटता लाने पर बल दिया जा रहा है ताकि परिचालनों में छिपाव और कारबार के वनावटीपन को दूर किया जा सके। सांविधिक बाह्य लेखा परीक्षाओं के मानक कठोर बनाये जा रहे हैं। कारोबार में नियमों के अनुसार लेनदेन किये जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की लेखा-परीक्षा और विश्लेषण आधिकारिक रूप में करना होगा।

7.36 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किये जा रहे वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, पर्यवेक्षण की एक एकल समेकित प्रणाली विकसित करेगा जिसमें पर्यवेक्षण कार्य के विभाजन और वित्तीय प्रणाली की देखरेख करने वाले विभिन्न प्राधिकरणों के बीच अपर्याप्त समन्वय की संबंधित समस्या से बचा जा सके। उक्त बोर्ड, नियंत्रण के ढांचे के साथ बैंकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रभावी पर्यवेक्षण की भूमिका पर ध्यान आकर्षित करने में भी मदद करेगा।

7.37 अन्य चिंता जो अनियमित प्रतिभूतियों के लेनदेनों के संदर्भ में उभरी वह वित्तीय प्रणाली और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में मुख्यस्थित गड़बड़ी की संभावना थी। प्रति पार्टी जोखिम का उचित निर्धारण और ऋण बाजार की सुचारु कार्य पद्धति ने महत्व प्राप्त किया है। प्रणालीजन्य जोखिम को कैसे रोका जाए यह एक मुख्य चुनौती है जिसका विनियम को अब सामना करना है। बैंकों के निवेश परिचालनों और निधियों के प्रवाह के लिए विनियामक सावधानी अब निर्दिष्ट की गई है और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं तथा आदेश दिये गये हैं कि बैंकों की अपनी नीति हो एवं परिचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत हों जिन्हें उनके बोर्डों ने यथोचित रूप में अनुमोदित किया हो। बाजार आयोजना को मजबूत करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है और बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे अत्यधिक सतर्कता बरती जा सके और नाजुक संविभाग परिचालनों पर गलत निगरानी रखने में मदद मिल सके।

7.38 यह सभी के हित में है कि अनिश्चितता की इस भावना को दूर कर दिया जाए कि वित्तीय प्रणाली को मजबूत नहीं बनाया जा सकता और कोई ऐसी प्रभावी तथा उद्देश्यपरक प्रणाली को अपनाने का इरादा ही नहीं है जो हमारे विकासोन्मुख प्रयासों से जुड़ा सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों में सहायक हो सकती है। प्रत्येक बैंक को चाहिए कि वह इस दिशा में कार्रवाई शुरू करे, भले ही एक अधिक व्यापक पर्यवेक्षण प्रणाली के निर्माण में नियामक वर्ग अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हो। नीति तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि निधियों का बाजार एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और इसमें बनावटी विभाजन की कलाई गुंजाइश न हो।

विदेशी क्षेत्र के निर्गम

7.39 1992-93 के दौरान भुगतान संतुलन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। जैसा कि लगानार दूसरे वर्ष भी विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के काफी बड़ा संचय से स्पष्ट है। पिछले वर्ष के संदर्भ में जहां 1992-93 में चालू खाते का घाटा बढ़ा है वहीं 1991-92 के चालू खाते के घाटे को तेजी से बढ़ति वाले आयात प्रतिबंधों संबंधी उपायों से उस वर्ष के साथ की गयी तुलना की निष्फल कर देती है। 1989-90 के पिछले "सामान्य" वर्ष की पृष्ठभूमि में दबें तो 1992-93 का चालू खाते का घाटा सकल देशी उत्पाद के सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों अर्थों में कम रहा।

7.40 1993-94 के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति नियंत्रण के योग्य रहेगी। इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान भारी निर्यात हुआ जो अमेरिकी डॉलरों में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। अप्रैल-जून 1993 के दौरान आयात में 1992 की प्रथम तिमाही की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है जबकि अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ ही आयात की मांग भी बढ़ने की आशा की जाती है।

इसके बावजूद समर्थन: आसोजन वर्ष में चालू खाते का घाटा उसी स्तर पर रहने की आशा है जिस स्तर पर 1992-93 में था।

7.41 वर्ष 1993-94 के प्रथम चार महीने के दौरान विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों का संचय बढ़ा है। जुलाई 1993 के अंत में विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियां 6.8 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर थीं। विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों के संयोजन का सुदृढ़ पुनर्गठन हुआ। परिसंपत्तियों के संयोजन के भाग जैसे—विनिमय और विदेशी मुद्रा बैंक तथा अन्य जमा राशि योजना के अंतर्गत शामिल जमा राशियां जुलाई 1992 के अंत के अपने स्तर से काफी कम हुईं। ये सकारात्मक गतिविधियां 1993-94 के दौरान भुगतान संतुलन के प्रबंधन को काफी मृदु बना देंगी।

7.42 अमेरिकी डालर में व्यक्त 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की निर्यात वृद्धि व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूप से कम होगा। अदृश्य अर्जन में कुछ सुधार होने की संभावना है। यह सुधार अनुकूल नीतिगत परिवेश से लाभान्वित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटे में व्यापार संतुलन में सुधार आयेगा। फिर भी, प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा और उद्यत व्यवस्था के अंतर्गत किये गए आहरणों आहरणों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को की जाने वाली चुकौतियां 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान काफी अधिक होंगी और 1995-96 में वह उच्चतम स्तर पर होंगी। इसके अलावा, इंडिया डेवलपमेंट बैंड और उसके मिश्र व्याज की चुकौती 1996-97 में एक साथ एक बार में करनी होगी। इस प्रकार चालू खाते में हुआ सुधार ऋण चुकौती की अपेक्षा से संतुलित हो जायेगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय ऋण स्थिति निर्धारण समष्टिगत आर्थिक आधारभूत बातों में मजबूती के परिणामस्वरूप जहां वाणिज्यिक बाजारों का आश्रय नवीकृत किया जा सकता है वहीं मध्यावधि के दौरान अमाधारण वित्तपोषण की आवश्यकता बनी रहेगी।

7.43 निर्यात की उच्च वृद्धि केवल व्यापक नीतिगत विन्यास के ढांचे के भीतर ही संभव है। यह नीतिगत विन्यास ऐसा होना चाहिए जो प्रोत्साहन की संरचना को सामान्य बनाता हो, संरचनात्मक बाधाओं और प्रक्रियात्मक रुकावटों को दूर करता हो और निर्यात उद्योगों को औद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के शक्तिवर्धक परिणामों से परिचित कराये। लम्बी अवधि के दौरान निर्यात प्रोत्साहनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहनों में विमिश्र होना पड़ेगा तथा उन प्रोत्साहनों की ओर अभिमुख होना पड़ेगा जो मूल्य मकेतक के रूप में दिये जाते हैं। इसी के साथ-साथ, निर्यात मात्रा की संवेदनशीलता और अधिक तीव्र करके मूल्यगत परिणामों की ओर अभिमुख करने के लिए व्याज दर, टैरिफ सुधार और सक्रिय विनिमय दर नीति की जरूरत पड़ेगी। लम्बे अंतराल के दौरान निर्यात को वृद्धिशील उत्पादन और देशी उद्योग के तुलनात्मक लाभ के रूप में देखने की आवश्यकता होगी बजाय इसके कि उसे आर्थिक सहायता देकर बनाये रखा जाये।

7.44 वर्ष 1992-93 के दौरान आयात वृद्धि मामूली अर्थात् 11.9 प्रतिशत रही। परंतु परम्परागत आयात की अधिक मदों को देखते हुए, पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ और उर्वरकों जैसे बड़ी आयात मदों के संबंध में व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता पर उचित जोर देना आवश्यक है। पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ के संरक्षण, उनका इष्टतम उपयोग और ईंधन की स्थानापन्नता की दिशा में समन्वित प्रयास करना ऐसे उपाय हैं जिनकी ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

7.45 हाल ही के वर्षों में परिवहन संबंधी भुगतान, ब्याज, रायल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसी अदृश्य अदायगियां कठोर स्वरूप की हो गयी हैं जिसके कारण अदृश्य खाते में उत्तरोत्तर गिरावट आयी। इस सेवा क्षेत्र की सेवाओं में प्राप्त होने वाली आय को बढ़ाने में श्रम प्रधान सेवाओं से बिलकुल अलग हटकर अधिकाधिक प्रौद्योगिकी विनिष्टियों की ओर अभिमुख होने की आवश्यकता है। सेवाएं विशेष रूप से मूल्य संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और इसलिए उपयुक्त मूल्य से संबंधित नीतियां अत्यधिक संगत हो चुकी हैं। एकीकृत विनिमय दर प्रणाली से निजी अंतरण को गतिशील बनाने में सहायता मिलती है।

7.46 मध्यावधि के दौरान भुगतान संतुलन को बनाये रखने के लिए पूंजी की आपूर्ति प्रणाली की पुनःसंरचना करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आगामी वर्षों में लिये जाने वाले ऋण के स्तरों को चालू खाते की शेष राशि के परिमाणान्तरक आयातों तक सीमित रखने की आवश्यकता है, जैसा कि उच्चस्तरीय समिति ने परिभाषित किया है। विदेशी पूंजी के उपयोग में उत्पादकता देयताओं के संदर्भ में एक मार्गदर्शी मानदंड होगा।

7.47 हाल ही के वर्षों के अनुभव से यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूंजी आपूर्ति प्रणाली की संपूर्ण मात्रा के अतिरिक्त उसके संयोजन पर भी निगरानी रखी जाए। विदेशी वाणिज्यिक उधार, विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋणों को उन स्तरों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें व्यापार से संबद्ध आवश्यकताओं द्वारा अधिकारिक रूप से बताया गया हो। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक ऋण की अवधि संरचना की ओर भी उचित ध्यान देना होगा।

7.48 अनिवामी भारतीयों की जमा राशियों पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी साबित हुई क्योंकि उनमें उतार-चढ़ाव और उधार-लागत अधिक थी। ये दोनों परिवर्तन व्यक्त और अव्यक्त थे। अब इस प्रकार की उधार राशियों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले अंश को कम करने की ओर उल्लेखनीय नीतिगत झुकाव है। यह कमी अंतर्राष्ट्रीय व्याज दरों के स्वरूप द्वारा निर्धारित स्तरों तक ऋणों की अवधि पुनर्निर्धारित करके तथा उधार की लागत घटाकर की जायेगी। जहां अनिवामी भारतीयों के पास विभिन्न विशेषताओं में

युक्त असायोजनाओं के चलाय का शिकल्प है वहाँ "लैकेडिशिया दृष्टिकोण अपनाना गया है। यह आवश्यक है कि इस प्रकार का नीतिगत दृष्टिकोण मध्यावधि तक जारी रहे ताकि पूर्व-परिलक्षित असंतुलनकारी परिणामों को कम किया जा सके। अनिवासी अमाराशियों के लिए समग्र नीति अत्यधिक अस्थिरता और इन योजनाओं की लागत में कमी को ध्यान में रखकर सुनिश्चित की जानी चाहिए। लक्ष्य-समूह को ध्यान में रखकर विभिन्न विशेषताओं से युक्त पांच योजनाएँ तैयार की गयी हैं। ये विशेषताएँ प्रत्यावर्तनीयता, विनिमय जोखिम और आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं तथा व्याज दर निर्धारण से संबंधित हैं। कुछ नई योजनाएँ जैसे अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय जमा योजना काफी सफल रही है। यह आशा की जाती है कि अगले दो या तीन वर्षों में मूलभूत परिवर्तन होगा और गारंटियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जायेगा।

7.49 इस बात की भी आवश्यकता है कि गैर-ऋण आपूर्ति प्रणाली के पक्ष में पूंजी आपूर्ति के संयोजन को बदला जाए, विशेष रूप से सीधे विदेशी निवेश को। भारत की औद्योगिक नीति में और भुगतान संतुलन को समर्थन प्रदान करने में विदेशी निवेश की भूमिका काफी सीमित है। अस्सी के दशक में भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह औसतन 1.6 बिलियन अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष रहा है, जबकि थाईलैण्ड में वार्षिक निवेश लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डालर, इंडोनेशिया में 1 बिलियन अमेरिकी डालर, मलेशिया में 2.7 बिलियन अमेरिकी डालर और चीन में 3 बिलियन डालर रहा है। भारत में विदेशी निवेश का अपेक्षाकृत कम अंश हथारी पहले ही की नीति का ही परिणाम है। कुछ प्रौद्योगिकी जानकारी आसानी से अंतरण तभी होती है जब उनके साथ ईविक्टरी शेयर होते हैं। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि विदेशी निवेश उस समय भी ऋण के मुकाबले लाभकारी है जब कि वह प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम के रूप में कार्य नहीं करता। उससे ऋण में बढ़ोतरी बिना भुगतान संतुलन को समर्थन प्राप्त होता है। नृत्ति लाभोण प्रत्यावर्तन कार्यशीलता से जोड़ा गया है इसलिये विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी के उन्नयन की ओर से जाना है और देशी उद्योग को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। मध्यावधि भुगतान संतुलन के सगायोजन की नीति में तदनुसार विदेशी निवेश को प्रवर्धित भूमिका प्रदान करते हुए महत्व दिया गया है। इसलिये उठाये गये प्रमुख कदम रही दिशा की ओर हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन किये गये हैं। भारत ने बहुपक्षीय निवेश करने के लिए एंजेंसी सम्मेलन में भी हस्ताक्षर किये हैं ताकि विदेशी निवेशकों को संरक्षण मिल सके और उसमें अपनी यह इच्छा भी जाहिर की है कि विदेशी निवेशकों में विश्वास पैदा करने के लिये द्विपक्षीय गारंटियों प्रदान की जायें। महत्वपूर्ण उपाय यह रहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये।

7.50 वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान भुगतान संबंधी आर्थी अत्यधिक कठिनाइयों से सीखे हुए पाठ

जो 1992-93 के दौरान प्रमुख रूप से व्यापक सुधारीकरण के लिए किये गये समन्वित प्रयास नीति को तबे भिरे से अनागे की ओर अभिमुख थे। ये नीतियाँ मध्यावधि के दौरान अर्थक्षम भुगतान संतुलन को हासिल करेंगी। इसी संदर्भ में भुगतान संतुलन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति ने उधार व्यापार क्षेत्र के वातावरण पर विचार किया जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा दर में स्वयं सुधार होता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की ओर उत्तरीतर संक्रमण होता रहता है और मध्यावधि के यही लक्ष्य हैं। भावी विकास के इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तथा गतिशील प्रतिस्पर्धात्मक कार्य-क्षमता और खुलेपन के लाभों से देश को लाभान्वित करने के लिए इस समिति ने पिछले वर्ष की संकीर्ण नीति से मुक्त होकर आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है। यह दृष्टिकोण स्थायी तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। अर्थात् इसके अंतर्गत आयातों को कम किया जाना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। भुगतान संतुलन के लिए मध्यावधि नीति को उच्चस्तरीय समिति के मूल्यांकन की पृष्ठभूमि में विकसित किया जाना चाहिये। समिति का मूल्यांकन यह था कि सकल देशी उत्पाद के 1.6 प्रतिशत के स्तर तक चालू खाते का घाटा सामान्य पूंजी आपूर्ति से ही पूरा किया जाए।

विदेशी मुद्रा विनियमन दर नीति

7.51 हाल ही की अवधि में विदेशी मुद्रा विनियमन दर नीति में आधारभूत परिवर्तन हुआ है और इस नीति के मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि नई नीति के परिचालन के आवश्यक तथ्य तय कर लिये जाए। 2 मार्च, 1993 तक प्रवर्धित दुर्गो विनियमन दर प्रणाली भलीभांति काम करती रही। जुलाई 1992 के दौरान सरकारी विनियमन की तुलना में मुक्त बाजार दर प्रीमियम लगभग 17 प्रतिशत पर लगातार स्थिर बना रहा। फरवरी 1993 का महीना उसका अपवाद रहा जब सट्टेबाजी की आशाओं से इसकी दर में तेजी से वृद्धि हुई। मिश्रित दर (40 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत से घटक पर लागू गई आधिकारिक और बाजार विनियमन दरों का औसत) के मासिक परिवर्तन के विवेक्षण और आधिकारिक विनियमन दर से यह पता चलता है कि आधिकारिक दर की तुलना में मिश्रित दर का प्रीमियम लगभग 9-10 प्रतिशत पर कमोअंश अपरिवर्तित बना रहा। 2 मार्च 1993 में, उक्त विनियमन दर प्रणाली का स्थान एकीकृत विनियमन दर प्रणाली के लिया जिसके अंतर्गत विनियमन दर संवर्धित भाग एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों से पूरी तरह निर्धारित होने लगी। एकाकृत विनियमन दर प्रणाली इसलिये शुक्त की गई ताकि उस पुरी विनियमन दर प्रणाली में उत्पन्न असंगति से निपटा जा सके जिसके अंतर्गत निर्यातकों तथा विदेशी मुद्रा के अन्य अर्जकों को अप्रत्यक्ष रूप से कमिषन आयातों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी।

7.52 नई प्रणाली के अंतर्गत, प्रचलित बाजार दरों पर रिजर्व बैंक ने अपनी खरीद और बिक्री दरों (भाग्य में

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के साथ लेनदेन) की घोषणा की जो पहले की प्रणाली में भिन्न थी जिसके अंतर्गत सबसे पहले रिजर्व बैंक अपनी दर तय करता था और बाजार उसका अनुसरण करते थे। रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार दिया गया था कि वह प्रचलित बाजार दर की 5 प्रतिशत सीमा के भीतर अपनी खरीद एवं बिक्री दरें तय करें, किन्तु आज तक रिजर्व बैंक ने इस लोच का प्रयोग नहीं किया और सामान्यतः वह बाजार में प्रचलित दर के समीप की दरें निर्धारित करता रहा है। एक दिन में रुपये की मानक विनिमय दर के कारण चूँकि बैंकों के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान बाजार दरों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिये रिजर्व बैंक प्रति अमरीकी डालर रुपयों के रूप में "संदर्भ दर" घोषित करता है। 2 अगस्त 1993 के प्रत्यक्ष कोटा प्रणाली शुरू कर दी गई है। उक्त संदर्भ दरमेंबई में स्थित कुछ चुनिंदा बैंकों की 12 बजे की दरों पर आधारित है। विशेष आह्वान अधिकार दर और एजियाई समाधान संघ की मुद्राओं की विनिमय दरें इसी दर पर आधारित हैं।

7.53 नई प्रणाली के अंतर्गत, रिजर्व बैंक की बिक्री दर प्रभावी रूप से लागू नहीं है। बैंक प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विदेशी मुद्रा की खरीद कर रहा है। किन्तु जरूरी नहीं कि बाजार की खरीद दर की तुलना में रिजर्व बैंक की खरीद दर आकर्षक हो। उन दिनों जब बाजार में डालर की ज्यादा आपूर्ति हो जाती है तब बाजार रिजर्व बैंक को उसकी खरीद दर पर अतिरिक्त डालर की बिक्री कर देता है। अधिक-से-अधिक इसे हम सक्रिय हस्तक्षेप कह सकते हैं। रिजर्व बैंक ने (मार्च-जुलाई 1993) 4 माह की अवधि के दौरान 2 बिलियन अमरिकी डालर से ज्यादा की निवल राशि की खरीद की है। 2 मार्च 1993 को बैंक की संदर्भ दर 32.06 रुपये प्रति अमरीकी डालर थी। इस माह में रुपये की संदर्भ दरों का औसत प्रति डालर 31.53 रुपये था। तब से रुपया सुदृढ़ हो गया और प्रति अमरीकी डालर वह 31.30 रुपये तथा 31.40 रुपये के बीच रहा। 1993-94 के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की दिशा चालू खाते में अंतर तथा वित्त की उपलब्धता, सामान्य एवं अपवादवात्मक दोनों, पर मुख्य रूप से निर्भर रहा। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें, घरेलू एवं विश्व अर्थव्यवस्था की अतिविधियों के अलग-अलग प्रभाव पड़े जो इस बात पर निर्भर था कि इनके एक-साथ घटित होने की मात्रा क्या थी। यदि दर्शायी मात्रा से घरेलू वसूली प्रमुख औद्योगिक देशों के साथ तालमेल रखती है तो निर्यात और आयात दोनों बढ़ेंगे तथा इस बात की भी संभावना होगी कि अगले वर्ष में विनिमय दर स्थिर रहे। वास्तव में, अद्यतन अनुमानों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, तथा यू०के० इस संकट से पहले ही निकल चुके हैं और वे वृद्धि दिखा रहे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हमारे, भुगतान संतुलन में, वर्ष के दौरान रुपया वर्तमान स्तर पर स्थिर बना रहेगा।

7.54 उद्देश्यपूर्ण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली शुरू होने तक जो विनिमय दर नीति अपेक्षा की जाती थी वह भूत

रूप से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाये रखने के लिए थी। रिजर्व बैंक ने इसे रुपये की सांकेतिक विनिमय दर निर्धारित करके इस प्रकार तय की थी कि वास्तविक वर्षों में (यर्थात् भारत तथा उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच मुद्रास्फूर्ति के अंतर को हिसाब में लेने के बाद) कम-से-कम स्थिर बहने न पावे। एकीकृत विनिमय दर की प्रणाली के अंतर्गत, विनिमय की दर बाजार में मांग एवं आपूर्ति (विदेशी मुद्रा विनिमय दर) की शक्तियों से निर्धारित होती है। ऐसी स्थिति में, यदि अस्थायी तौर पर मांग की तुलना में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति के ज्यादा हो जाने से रुपया सुदृढ़ हो जाता है तो विदेशी मुद्रा को खरीद करके रिजर्व बैंक के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना संभव होगा ताकि रुपये के मूल्य में अस्थिर उतार-चढ़ाव न हो किन्तु, इसके विपरीत स्थिति होने पर, यदि आधारभूत कारणों से रुपये का मूल्य कम होता है आरक्षित मुद्रा की हानि उठाकर रुपये के सूचा को बचाये रखना बुद्धिमानों का काम नहीं होगा। पूरे विश्व का यही अनुभव है कि आधारभूत कारण तथा किसी मुद्रा के विनिमय मूल्य में स्थायी परिवर्तनों को रोकना बेकार है। किन्तु, देश के विदेशी मुद्रा बाजार में अल्पावधि उतार-चढ़ाव को समर्थन करना संभव होगा। व्यापार तथा विनिमय विनियमन के प्रतिबंधों को करीब-करीब न्यूनतम पर लाने के कारण, इस समय रुपया कमोडिटी चालू खाते की दर पर परिवर्तनीय कहा जा सकता है।

7.55 भाग में विगत समय में स्थिर विनिमय दर बताये रखना वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच निरंतर संतुलन बताये रखने पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। इसमें विनिमय दर स्वयं ही संतुलन की भूमिका भूदा करेगी। फिर भी, विनिमय दर एवं मुद्रा नीति की स्थिति तथा समग्र मूल्य स्थिति के बीच बड़े हुए संबंध होंगे। एक तर्कसंगत स्थिर विनिमय दर बताये रखना एक स्थिर घरेलू मूल्य स्थिति के लिए अपेक्षित होता।

मौद्रिक नीति :

7.56 आर्थिक नीति की एक भुजा के रूप में मौद्रिक नीति कनिष्ठ क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, जिस समय कार्रवाई की जरूरत होती है और जिस समय वास्तव में कार्रवाई की जाती है, इनके बीच समय का अंतर मौद्रिक नीति के मामले में राजकोपीय नीति के मामले की तुलना में कम होता है, जबकि राजकोपीय नीति से निम्न मौद्रिक नीति के परिवर्तन किसी वर्ष के दौरान किसी भी समय आसानी से किये जा सकते हैं। मौद्रिक विनियमन की लिखतों के अंतर्गत तुरन्त आने वाले परिवर्तनकारी तत्वों में बदलाव के बीच का अंतराल, और उत्पाद तथा रोजगार जैसे वास्तविक परिवर्तनकारी तत्वों का प्रभाव मौद्रिक नीति के मामले में अपेक्षाकृत लम्बे समय तक रहता है क्योंकि इसमें आय और व्यय के मुद्रा प्रवाह सीधे-सीधे प्रभावित नहीं होते। मौद्रिक नीति लागू और प्रणाली मुद्रा की उपलब्धता को प्रभावित करने हुए कार्य करती है और उसकी प्रभावशीलता उन सांस्थानिक ढांचे

पर निर्भर करती है जो केंद्रीय बैंक द्वारा दिये गये अनुदेशों को भेजने के लिए उपलब्ध है। अस्सी के दशक में सरकार को रिजर्व बैंक का निम्न ऋण आरक्षित मुद्रा के विस्तार में एक प्रमुख योगदान देनेवाला रहा है और इसलिए मौद्रिक नीति को यथासंभव निम्न विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में अपनी धारण राशियों में अल्पावधि घटबढ़ को हिसाब में लेने के बाद घाटे की राशियों के विस्तारवादी प्रभाव को बेअसर करने के कठिन कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर डालनी होगी। आरक्षित मुद्रा में भारी वृद्धि के कारण बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ी हुई नकदी को निरंतर कम करने रहना होगा। निर्धारित ब्याज दर ढांचे की स्थिति में, बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी को समाहित करने का कार्य मुख्य रूप से नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके किया जाता है। सरकार की उधार जरूरतें उंचे स्तर पर ही बने रहने के कारण, सांविधिक नकदी अनुपात को भी धीरे-धीरे बढ़ाना होगा ताकि इन जरूरतों को बहू पूरा कर सकें।

7.57 मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित रखना तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराते हुए उत्पादन कार्यों का समर्थन करना रिजर्व बैंक की मौद्रिक तथा ऋण नीतियों का आधार बना रहा। 1990-91 के मध्य में जब रिजर्व बैंक को उसके दायित्व के सामान्य अंश में अधिक का बोझ उठाना पड़ा तब भुगतान संतुलन की स्थिति ने संकट का स्वरूप ग्रहण किया। आयात संकुचन तथा मांग परिसीमन को लक्ष्य से रखकर मौद्रिक एवं ऋण नीति संबंधी उपायों के जरिये उसे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। किंतु तब से मौद्रिक नीति की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुए हैं। मुद्रा-स्फीति नियंत्रण के उद्देश्य की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक और कृषि उत्पादन के पुनर्स्थान के लिए उपायों की गुरुत्वात् की गई है। अक्तूबर 1991 में 20 प्रतिशत तक बढ़ाई गई। न्यूनतम उधार दर चार चरणों में कम करके 16 प्रतिशत पर लाई गई। तदनुसार, अधिकतम जमा दर 13 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दी गई उधार दर में किसी प्रकार का समायोजन जमा दर में उसी प्रकार के परिवर्तन के साथ ही करना होगा। अन्यथा, बैंकिंग प्रणाली की अर्थ-क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। जमा राशि की दर तय करने समय, जमाकर्ताओं की धारणा तथा वैकल्पिक वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपलब्ध होने वाली आय को भी ध्यान में रखना होगा। किंतु ब्याज दरों की निरंतर समीक्षा होती रहनी है और हमारी नीति का आशय यह नहीं है कि लम्बे समय तक वास्तविक उधार दरों को काफी उंचे स्तर पर रखा जाए। ब्याज दर नीति का प्रयोग एक लोचदार लिखत के रूप में होना चाहिए और यह काम परिस्थिति की मांग के अनुसार बढ़ा-घटाकर किया जा सकता है।

7.58 ब्याज दर स्तर के अलावा, कतिपय मुद्दे ब्याज दर ढांचे से जुड़े हैं। ब्याज दर का स्तर मौद्रिक नीति की स्थिति से निर्धारित होगा। निर्धारित ब्याज दरों के ढांचे के संबंध में विगत कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार किये गये जो

इस प्रकार हैं: (क) रियायती स्तरों की संख्या में कमी लाते हुए, तथा कतिपय दरों को बढ़ाते हुए, बैंकों की उधार दरों को पर्याप्त तर्कसंगत बनाया गया है जिससे विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता का तत्व कम हो सके, (ख) विनियमित जमा दर ढांचे के स्थान पर एकल निर्धारित ढांचा दिया गया है जिससे 46 दिन और उससे अधिक परिपक्वता अवधि के लिए अधिकतम दर तय कर दी गई है, (ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है, जबकि परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियों की ब्याज दरें कम कर दी गयी हैं, जिससे तुलनात्मक परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियों पर ब्याज की लागू दरें काफी बढ़ गई हैं, और (घ) जमा प्रमाणपत्रों जैसे कई लिखतों के लिए ब्याज दरें बैंक स्वतन्त्र रूप से तय करते हैं। जमा राशियों पर विचार करें, तो जमाकर्ताओं को ब्याज की एक सकारात्मक वास्तविक दर निर्धारित किये जाने की जरूरत है और जमा राशियों पर आय की पर्याप्त दरों के अभाव में संगठित वित्तीय प्रणाली की निधियां असंगठित प्रणाली के पास चली जायेंगी। इस बात पर पर्याप्त मतभेद हैं कि क्या संपूर्ण बचत राशियों के निर्धारण में ब्याज दर एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी तत्व है। इस मतभेद के होते हुए भी, इस बात पर कोई संदेह नहीं कि अंतरणीय बचत राशियों पर ब्याज दरों का प्रभाव पड़ता है। किंतु, विभिन्न प्रकार की दरों वाली आर्थिक सहायता के कारण ही काफी संख्या में उधारकर्ताओं के लिए ब्याज की दरों को तुलनात्मक रूप से उंचे स्तर पर रखना पड़ता है। चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के अनुसार दो प्रकार का ब्याज दर ढांचा अखंड जाने पर रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक लचीली ब्याज दर प्रणाली में अपरिहार्य रूप से रहने की आदत डालनी होगी। निधियों की लागत तथा निधियों पर आय के बीच बैंकों को उपलब्ध अंतर पर्याप्त होना चाहिये ताकि जमा राशियों को एक स्थान से दूसरे तक भेजने की लागत और परिसंपत्तियों के नियोजन पर किये जाने वाले खर्च में सुविधा हो। जब तक आरक्षित जरूरतें पर्याप्त रूप से नीचे नहीं लाई जाती और ब्याज दर रियायती तत्व को घटाया नहीं जाता तब तक जमा और उधार दरों के बीच दूरार अपरिहार्य रूप से बनी रहनी। इस संदर्भ में, इस समय बैंकों को उपलब्ध लगभग 3 प्रतिशत का अंतर तर्कसंगत है। ऐसी स्थिति में, बैंकिंग प्रणाली में काफी संख्या में उधार एवं जमा होते हैं। जहां उधार दर एवं जमा दर के बीच संबंध है, वहीं इसके साफ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि प्रशासनिक तथा अन्य लागत न्यूनतम रखी जाय ताकि इनका अंतर अधिक न होने पाये। सरकारी प्रतिभूतियों पर कृत्रिम न्यून ब्याज दरें अब विगत काल की बात हो गई है। अब सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें स्थानापन्नता के दायरे के करीब हैं, प्रतिभूतियों पर अधिकतम दर 13.5 प्रतिशत है, जबकि अग्रिमों पर भारत औसत उधार दर लगभग 15-16 प्रतिशत है। जोखिम बोध की स्थिति में, यह विश्वसनीय लगता है कि परिसंपत्ति धारण राशियों के प्रति बैंकों की पसंद सांविधिक निर्देशन द्वारा निर्धारित नहीं की

जायेगी वल्कि प्रतिभूतियों और बैंक उधार के मामले में जोखिम-पुरस्कार बोध से इसे तथ किया जायेगा। सरकार की वित्तीय जरूरतों को बाजार से संबंधित दरों पर रखने के लिए किये गये प्रयासों को सुदृढ़ बनाना और सरकारी प्रतिभूतियों के बिये गौण बाजार का विकास करना वित्तीय क्षेत्र सुधार की कार्यभारी का एक अनिवार्य अंग रहा। किन्तु ब्याज दरों को स्वतन्त्र करना क्रमबद्ध रूप में ही होगा। ब्याज दर एक परिवर्तनकारी तत्व है जो केन्द्रीय बैंकिंग की कार्रवाइयों से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होता है। जब तक ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं तब तक यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये दरें बाजार के अनुभव के करीब हों।

7.59 नीति का उद्देश्य आगामी अवधि में निम्न समय पर रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर निर्धारण के तत्व को और कम करना होगा। इस प्रकार, वो लाख रुपये से अधिक के ऋणियों की श्रेणियों के लिये न्यूनतम उधार दर का निर्धारण समाप्त किया जा सकता है और बैंकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपनी प्रमुख दर स्वयं तय करें। फिर, बैंक जमा राशियों पर उच्चतम ब्याज दर का निर्धारण समाप्त किया जा सकता है और बैंक अपनी जमा दरें निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। रिजर्व बैंक से ब्याज दरों के संबंध में सिगनल की आवश्यकता, ब्याज दर नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू बना रहेगा और बैंक अपनी ब्याज दरों में एक को संदर्भ दर के रूप में घोषित कर सकते हैं। एक परम्परा विकसित हो सकती है जिससे बैंक इस संदर्भ दर पर ध्यान दे सकें और संदर्भ दर से नीचे उपर्युक्त अंतर पर अपनी जमा दर निर्धारित कर सकते हैं, वल्कि जबकि उधार दर संदर्भ दर से ऊपर एक निश्चित अतिरिक्त दर हो सकती है। ऐसी प्रणाली एक बार लागू होने पर, आर्थिक गतिविधि के संपूर्ण संगठित क्षेत्र को प्रभावित कर सकेगी।

7.60 वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अंग के रूप में, आरक्षित जरूरतों को कम करने की शुरुआत की जा चुकी है। एक ओर जहां रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित निधि तथा सांविधिक चल निधि के रूप में पहले से ही बैंकों की राशियों के स्तर में कमी करने के लिए बचनबद्ध है, वहीं इस प्रकार की कमी की गति राजकोषीय परिणाम पर निर्भर करेगी। जहां नकदी आरक्षित अनुपात में कमी नितांत रूप से मौद्रिकृत घाटे में कमी पर निर्भर करेगी, वहीं सांविधिक चल निधि अनुपात में कमी सरकार द्वारा लिये गये समग्र उधार में कमी की सीमा तथा उस सीमा पर निर्भर करेगी जिस पर सरकार ब्याज की बाजार संबंधित दरों पर उधार लेती है। कार्यान्वयन के रूप में देखें तो—जैसे ही राजकोषीय षाटा कम होता जाता है, और चूकि घाटे के स्व-मुद्रीकरण से दूर होने की प्रवृत्ति है, मौद्रिक नीति अपने-आप ही लागू होगी। मुद्रा और ऋण का वित्तियमन केन्द्रीय मौद्रिक प्राधिकरण की इस समग्र अनुभव से तथ होगा कि मुद्रा और ऋण के विस्तार का उपयुक्त स्तर क्या होना चाहिये और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था के वास्तविक कारण कैसे काम कर रहे हैं।

7.61 वित्तीय क्षेत्र के सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है भारी आरक्षित जरूरतों वाली बैंकिंग प्रणाली पर लागू दर को कम करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक वर्षों से नकदी आरक्षित जरूरतों को मौद्रिक नियंत्रण के एक शक्तिशाली लिखित के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है और यह लिखित मौद्रिक विस्तार पर एक उच्च सीमा लगाने के लिये एक औजार के रूप में देखा जाता है। हाल के वर्षों में, अनेक देशों में, नकदी आरक्षित जरूरतों को उल्लेखनीय रूप से कम किया गया है। भारतीय संदर्भ में, मध्यावधि योजना यह है कि 1992 में लगभग 16.5 प्रतिशत के प्रचलित अनुपात से नकदी आरक्षित अनुपात का कम करके 1997 तक 10 प्रतिशत किया जाए, किन्तु यदि समायोजन अवधि के दौरान किसी समय में प्राथमिक मुद्रा निर्माण ज्यादा हो जाता है तो रिजर्व बैंक अस्थायी तौर पर मध्यावधि उद्देश्य से अलग हटने में संकोच नहीं करेगा और अतिरिक्त प्राथमिक मुद्रा निर्माण को निष्प्रभावी बनाने के लिए नकदी आरक्षित अनुपात बढ़ा देगा। एक ओर जहां उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, वहीं समायोजन की समय-सारणी को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना होगा। उस सीमा तक जहां रिजर्व बैंक आरक्षित निधियों तथा मौद्रिक वृद्धि के बीच एक सीधे संपर्क पर निर्भर करता है, आरक्षित जरूरतों में किसी प्रकार की गिरावट से मौद्रिक नियंत्रण ढीला हो जायेगा। यदि मौद्रिक नियंत्रण की हानि से बचना हो तो रिजर्व बैंक को अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर चातुर्य की आवश्यकता होगी और प्रतिभूति बाजार को पर्याप्त विकसित होना होगा।

7.62 वित्तीय क्षेत्र सुधार के एक अनिवार्य अंग के रूप में यह परिकल्पना की गई कि बैंकों के लिए निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात मार्च 1996 में समाप्त होने वाले तीन वर्ष में घटाकर 25 प्रतिशत तक लाया जाये। इसका तात्पर्य यह होगा कि प्रतिभूतियों के लिए आबद्ध बाजार अगले कुछ वर्षों में तेजी से सिकुड़ जायेगा। समायोजन प्रक्रिया के एक अंग के रूप में प्रतिभूतियों पर लचीली ब्याज दर के साथ केन्द्र ने एक नीलामी प्रणाली शुरू कर दी है। आगामी अवधि में केन्द्र को अपनी उधार जरूरतों के लिये ब्याज की बाजार निर्धारित दरों की ओर पूरी तरह जाने की जरूरत होगी। किन्तु, राज्यों को ब्याज की बाजार से संबंधित दरों की ओर जाने में अधिक समय की जरूरत होगी, फिर भी, इस समस्या से सुधार की गति में बाधा नहीं आनी चाहिये। एक राज्य निधीयन निगम की स्थापना पर विचार किया जा सकता है जो ब्याज की बाजार संबंधित दरों पर निधि जुटा सकेगा और राज्यों को निर्धारित दरों पर धन देगा। ऐसी संस्था की स्थापना से पूर्व केन्द्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच आर्थिक सहायता के बोलबाले के समग्र प्रभाव की जांच करना आवश्यक होगा। इसे कार्यान्वित किये जाने से पहले केन्द्र और राज्यों के बीच ऐसी व्यवस्था की रूपरेखा पूरी तरह तैयार करना जरूरी होगा। फिर, सरकारी उधार का परिपक्वता ढांचा कम किये जाने में चुकौती की मस्य-सारणियों में अमुचिधा होगी और, इसलिये ऋण पर पुनः

विचार करने के लिए समेकित इकाई निधि की पहले वाली प्रणाली को फिर से चालू करना काफी समय से विचाराधीन है। सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में व्याज की बाजार निर्धारित दरों की ओर मुकाबल में जहां दम है, वहीं समायोजन केवल तभी सफल होगा जब सरकारी उधार की जरूरतें संयमित की जायें। यदि उधार की जरूरतें ज्यादा हैं, तो बाजार-निर्धारित व्याज दर प्रणाली के अंतर्गत व्याज की दर इतनी ऊंची हो जायेगी कि मुधार का संपूर्ण कार्यक्रम प्रतिकूल हो जायेगा क्योंकि इससे व्याज दरों में दोषपूर्ण उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकती है और सकल राजकोपीय असंतुलन बढ़ सकता है। इसलिये यह अनिवार्य है कि उधार जरूरतें तर्कसंगत सीमा के भीतर रखी जायें।

7.63 तीन वर्ष के भीतर सांविधिक चलनिधि अनुपात में 25 प्रतिशत तक कमी करने के चरणबद्ध कार्यक्रम को एक कार्यक्रम में मिला देना चाहिये ताकि तीन वर्ष की अवधि में बजट बाटे का स्व-मुद्रीकरण समाप्त हो जाये। तदनुसार, 91 विधेय बजाना बिलों के कुल निर्माण में नीलाम किये गये बिलों का अनुपात क्रमबद्ध रूप से बढ़ा देना चाहिये ताकि 1996-97 तक तदर्थ खजाना बिलों की प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो जाये। इसके बाद, केन्द्र सरकार को अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम सीमा उपलब्ध हो सकेगी और वित्तीय वर्ष के अंत तक इस सीमा का परिसमापन अपेक्षित हो सकेगा। प्रणाली के इस तरह के सुधारों से मौद्रिक नीति कार्रवाई में स्वतन्त्रता स्थापित होगी।

7.64 प्रायः, मौद्रिक नीति तथा वित्तीय दर नीति पर उसे संपूर्ण वित्तीय नीति के एक अलग एवं सुस्पष्ट अंक के रूप में मानकर चर्चा की जाती है, ये दोनों अंग अनिवार्य रूप से आपस में जुड़े हैं और जैसे ही बाजार आधारित प्रणाली में विकास होता है वैसे ही नीति के एक अलग अंग के रूप में उन्हें देखना अर्थपूर्ण नहीं रह जायेगा। यदि इन दो अंगों में परस्पर तालमेल नहीं स्थापित किया जाता तो नीति का एक अथवा दूसरा अंग काफी हद तक शिथिल हो सकता है।

7.65 प्रत्यक्ष मौद्रिक नियंत्रण के लिखतों के प्रयोग को कम करने और मुद्रा तथा प्रतिभूति बाजारों पर अप्रत्यक्ष मौद्रिक नियंत्रण लिखतों के विकास की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने का मतर्क प्रयास 1992-93 से किया जा रहा है। मौद्रिक और आंतरिक मार्केजिनिक ऋण प्रबंधन नीतियों में समन्वय स्थापित करने की यही जरूरत है ताकि दोनों अंग परस्पर सहयोग कर सकें। मौद्रिक नियंत्रण की एक अकीर्ण विकसित प्रणाली के उद्विकास में सरकारी प्रतिभूतियों का तेजसे प्रमुख तत्व है। खुले बाजार कार्यों को वास्तव में कारगर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक सक्रिय गौण बाजार हो। यदि इस प्रकार के गौण बाजार का विकास करना है तो आवश्य निवेशकर्ताओं के अलावा अन्य निवेशकर्ताओं का होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में ही गैर-प्रायोज्य निवेशकर्ता प्रभावों

हो सकते हैं और गौण बाजार में गहराई आ सकती है तथा ऐसी स्थितियों में ही प्रमुख व्यापारियों की एक प्रणाली विकसित करना संभव होगा। ये व्यापारी नीलामियों के समय संपूर्ण शेयर की हमीदारी देगे और इसके बाद अंतिम निवेशकर्ताओं के लिए इन प्रतिभूतियों तक अपनी पट्टी रखेंगे। अकीर्ण विकसित किसी प्रतिभूति बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी सरकारी प्रतिभूति के किसी प्रारंभिक शेयर में रिजर्व बैंक को कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए किन्तु अपने खुले बाजार कामकाज के एक भाग के रूप में उसे प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री करनी चाहिए जो इस प्रणाली के तकदी के उसके मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। प्रतिभूतियों के एक सक्रिय गौण बाजार के लिए यह जरूरी है कि उसे समृद्ध करने वाली समर्पित संस्थाएं हों। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम, जिसके चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, प्रतिभूतियों के लिए दुतरफे भावों के माध्यम से बाजार निर्माता की भूमिका अदा करने का प्रयत्न करेगा। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम का काम केवल इन प्रतिभूतियों के लिए एक निष्पक्ष भंडार का काम करना ही नहीं होगा बल्कि यह बाजार मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों की सक्रिय खरीद एवं बिक्री भी करेगा। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम प्रतिभूतियों की कुल खरीद बिक्री को प्रोत्साहन देगा जिससे इन प्रतिभूतियों को तकदी उपलब्ध होती रहे। प्रतिभूतियों के गौण बाजार की विकास गति व्याज दरों के पूरी तरह बाजार निर्धारित होने और अपेक्षाकृत अधिक सक्षम समाशोधन एवं निपटान प्रणाली के अस्तित्व में आने पर निर्भर करेगा। इस समय सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के दो प्रकार हैं: पहली, जिसमें राशि की घोषणा पहले से ही कर दी जाती है तथा रिजर्व बैंक अधिकतम मूल्य पर इसमें भाग लेता है और दूसरी, जिसमें राशि की घोषणा पहले से ही नहीं की जाती है और रिजर्व बैंक नीलामियों में हिस्सा नहीं लेता। इस प्रणाली में अलग हटकर एक वास्तविक बाजार-निर्धारित प्रणाली में जाने के लिए प्रमुख व्यापारियों के लिए अपेक्षित है कि वे इस पूरे मुद्दे पर विचार करें और उन्हें रिजर्व बैंक की हस्तक्षेप दरों तथा गौण बाजार में प्रचलित दरों के बीच वित्तीय मध्यस्थता करने की पहल करनी होगी। रिजर्व बैंक दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का एक सक्रिय बाजार विकसित करने का प्रस्ताव करता है। इस संबंध में यह जरूरी है कि संस्थागत विकास, लिखत विकास के लिए साथ-साथ कार्रवाई की जाए और सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में बाजार निर्धारित व्याज दरों का बांका उपयुक्त बनाया जाए। इन सबके अतिरिक्त, सरकार की उधार जरूरतों को सरकारी प्रतिभूति बाजार के आकार एवं गहराई के अनुरूप स्तर तक संयमित करने की जरूरत है।

7.66 हाल की अवधि में, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर भारत में मुद्रारफीति की दर कम होकर लगभग 6 प्रतिशत पर आ गई जबकि एक वर्ष पहले यह 10 प्रतिशत थी।

भी। मुद्रास्फीति में इस गिरावट का अत्यंत स्वागत है। किन्तु, सावधानी का एक शब्द कहना जरूरी है। हाल की अवधि में, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक नकदी की वृद्धि अभूतपूर्व स्तर पर रही है और जब तक आगामी कुछ महीनों में सकल राजकोषीय घाटे में भारी कमी नहीं की जाती तब तक वर्ष के बाद के महीनों में निरंतर अतिरिक्त प्राथमिक नकदी से मुद्रास्फीतिवारी दबाव बढ़ता रहेगा और इससे सुधार की प्रक्रिया अस्थिर हो सकती है। एक ओर जहां रिजर्व बैंक को नियंत्रण के सभी उपलब्ध निबन्धों का प्रयोग करके इस प्रणाली में अतिरिक्त प्राथमिक नकदी को तेजी से कम करने के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए वहीं घाटे को निर्धारित स्तरों पर रखने के लिए राजकोषीय मुद्रास्फीतिक कार्रवाइयों की जरूरत है।

भाग दो-भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन

VIII. परिचय

8.1 लेखा वर्ष 1992-93 के दौरान रिजर्व बैंक की भूमिका अनिवार्यतः वित्तीय और बाह्य क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों का और आगे बढ़ा रही है। मूल्यों में स्थायित्व बनाये रखने के प्रथम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अर्थव्यवस्था के सुधार में समर्थन देने के लिए कुछ पहल की है। इस रिपोर्ट के प्रथम भाग में महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां और भावी संभावनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

8.2 पिछले वर्ष जानकीरामन समिति ने अपनी प्रथम तीन रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। वर्ष 1992-93 में और तीन रिपोर्टें प्रस्तुत की और समिति ने अपनी परिचर्चा पूर्ण की। जानकीरामन समिति के निष्कर्षों और उसकी सिफारिशों के संदर्भ में बैंक ने वित्तीय विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाये जिससे वर्तमान खामियां दूर हो सकें और समूचे वित्तीय क्षेत्र में समग्र गुणात्मक सुधार लाया जा सके। जानकीरामन समिति ने यह सिफारिश की कि अपने कार्यकलापों की जानकारी अनु-पूरित करने के लिए बैंक को चाहिए कि वह बाजार आसूचना को मजबूत करे। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने हाल ही में बाजार आसूचना कक्ष (एमआइसी) की स्थापना की और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में बैंकिंग आसूचना को भी मजबूत किया जा रहा है। संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में यांत्रिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के संबंध में उठाया गया कदम एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है जिसमें रिजर्व बैंक को प्रमुख भूमिका विभानी है। जानकीरामन समिति का यह मन था कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियों के लेनदेन में बरती जा रही अनियमितताओं का शीघ्र पता न लगना एक बहुत बड़ी कमी थी और यह इसलिए हुआ क्योंकि संबंधित प्रतिभूतियों के अभिलेख रखने, उसके समागोहन, उसके निपटान और अंतिम रूप से अदायगी से संबंधित कार्यकलापों में इलेक्ट्रॉनिकी यांत्रिक समागम प्रणाली (ईडीपी) का अभाव था। बैंक ने नवंबर 1992 में इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी समा-

गोहन, निपटान और जमा प्रणाली (ईसीएमडी) लागू की। स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/भारतीय यूनियन ट्रस्ट द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों/यूनितियों के लेन देन के समागोहन और निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली स्थापित करने के कार्य में मार्गदर्शन प्रदान करने और उसके समन्वय करने के लिए आंतरिक दल की स्थापना की गयी थी। भारत सरकार ने परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में (सुधी विमला विश्वनाथन) आंतर-अनुशासनिक दल गठित किया जाय। इस दल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर (जांच) विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह दल जानकीरामन समिति द्वारा पता लगाये गये जोखिम निवेश में निहित निधियों के संबंध में आगे की जाने वाली जांच के विषय में समन्वित कार्रवाई के मानदंड निश्चित करेगा।

8.3 वर्ष 1992-93 रिजर्व बैंक के लिए अत्यंत उल्लेखनीय वर्ष रहा है। उसके परिचालनों के साथ ही उसकी नीतियों में अनेक परिवर्तन उसकी विशेषता रही है। सक्रिय आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति को लागू करने के साथ-ही-साथ मुद्रागत नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधनों से अप्रत्यक्ष साधनों की ओर बढ़कर इसका सुषपात किया गया। आंतरिक ऋण प्रबंधन की नीतियों और परिचालनों को मजबूत करने के लिए बैंक ने पहली अक्टूबर 1992 में स्वतंत्र यूनिट के रूप में आंतरिक ऋण प्रबंधन कक्ष (आईडीएमसी) की स्थापना की। इसी के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम नाम की एक नई संस्था स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया जो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए गौण बाजार के विकास के लिए है। मुद्रा नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधन जैसे नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर कम बल दिया गया तथा मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रचलित अनुपात में कमी की गयी।

8.4 इसके अतिरिक्त स्वर्ण प्रबंधन प्रभाग की स्थापना इस वर्ष की एक और महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रभाग की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक समायोजन में स्वर्ण का संभावित उपयोग तथा जनता से स्वर्ण प्राप्त कर विकास सुनिश्चित करना तथा देश के अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि को मजबूत बनाना है।

8.5 नियंत्रित ऋण विन्यास समिति (अध्यक्षता: श्री जी० मदनम) तथा लघु उद्योग से संबंधित ऋण आवश्यकता समिति (अध्यक्ष: श्री पी०आर० नायक), इन दो समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं और उनकी सिफारिशों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। वित्तीय कंपनियों के सम्बन्ध में गठित कार्य दल (अध्यक्ष: ए०सी० शाह) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और दल की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

8.6 आलोच्य वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक में वित्तिय समितियाँ/आंतरिक दल गठित किये हैं। इन समितियों और दलों को गठित करने का उद्देश्य ऋण सुपुर्दगी की वर्तमान प्रणाली की नये सिरे से व्यापक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करना है। कार्यशील पूंजीगत वित्त में संबंधित वर्तमान मानदण्ड और प्रक्रिया के अनुपालन में व्यापार और उद्योग प्रतिष्ठानों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को उचित महत्व देने हुए एक समिति (अध्यक्ष: श्री राशिद जीलानी) उधार दिये जाने की नकद ऋण प्रणाली की समीक्षा कर रही है जबकि एक अन्य समिति (अध्यक्ष: श्री जे.वी.० गेट्टी) संघीय सहायता व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देने संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा कर रही है। श्रेटी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशों पर बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है। बैंक ने एक आंतरिक दल (अध्यक्ष: सुधी आइ.टी.० वाज) का गठन किया है जो रिजर्व बैंक द्वारा मानदंड और उधार दिये जाने में मुख्यवस्था और साथ ही बैंक ऋण की सीमा (अधिकतम अनुमत बैंक वित्त) की सीमा निश्चित किये जाने की आवश्यकता की जांच करेगा और तत्संबंधी सिफारिशें करेगा।

8.7 जहां तक बैंकिंग उद्योग में कंप्यूटरीकरण का संबंध है, बैंकिंग उद्योग में कंप्यूटरीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की दो समितियों द्वारा 1983 और 1989 में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कंप्यूटरीकरण के स्वरूप और उसके कार्यक्षेत्र पर सुपरिभाषित तथा समयबद्ध कार्यक्रम के लिए व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तावित की गयी है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनः समर्थन किया गया है क्योंकि भारत में स्थित बैंकों को परंपरागत वाणिज्य और सहकारी क्षेत्रों में ग्राहक सेवा, आंतरिक प्रशासन और निर्णयन में सुधार लाने के लिए कंप्यूटर और संप्रेषण के क्षेत्र में उच्चतर प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए तैयार रहना है।

8.8 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बैंक का कार्पोरेट प्लान तैयार करने के लिए आंतरिक कार्य दल गठित करने और इस दल की सहायता करने के लिए मार्च 1992 में बाहरी परामर्शी मैसर्स ए.एफ.० फर्ग्युसन एंड कंपनी का चयन करने संबंधी उल्लेख किया गया था। आंतरिक कार्य दल ने भेमर्स ए.एफ.० फर्ग्युसन एंड कंपनी के मार्गदर्शन तथा बैंक के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों की समीक्षा की और एक दस वर्षीय नीतिगत कार्य योजना (1993-2002) तैयार की। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्यतः आर्थिक नीतियों और विशेषतः मौद्रिक तथा ऋण नीतियों के विकास के संदर्भ में केन्द्रीय बैंक के पुनर्विचार का मुद्दा दिया गया है।

IX. वाणिज्य बैंकों से सम्बन्धित गतिविधियाँ

9.1 बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 1992-93 में हुई गतिविधियों का अवलोकन समग्र वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए करना होगा। इस समय बैंक कहीं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक

वातावरण में काम करने के लिए स्वयं को तैयार होना पड़ेगा, नई चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने की तैयारी में जुटे हैं।

9.2 निजी बैंकों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त— जैसाकि खण्ड 1 में कहा गया है, रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए जनवरी 1993 में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश के संबंध में, 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम प्रवृत्त पूंजी तथा विवेकपूर्ण मानदण्डों एवं पूंजी प्रणाली आदि संबंधी अपेक्षा के अलावा तय किए गए महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं: (क) उनके शेयरों का शेयर बाजार में लिखित कराया जाना; (ख) उनके प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन आदि का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, के उपबन्धों और साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं दी गई सलाहों द्वारा नियंत्रित किया जाना; (ग) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों में संबंधित निदेशों पर ऐसे उधारों की संरचना में किए गए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में तीन वर्ष की आरंभिक अवधि के दौरान नजर रखना; (घ) जैसाकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में प्रावधान है, किसी भी शेयरधारक-विशेष के मताधिकार कुल मताधिकारों के एक प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत रहेंगे (तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को छूट प्रदान की जा सकती है); (ङ) किसी भी नए बैंक को उसकी स्थापना के बाद न्यूनतम तीन वर्ष तक कोई सहायक संस्था अथवा म्यूचुअल फंड खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और (च) बैंक को आधुनिक संरचनात्मक सुविधाओं का प्रयोग करना होगा ताकि अच्छी ग्राहक सेवा उपलब्ध हो सके और साथ ही उसे उच्चाधिकारयुक्त ग्राहक शिकायत कक्ष भी स्थापित करना होगा ताकि ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जा सके।

9.3 वाणिज्य बैंकों का शाखा-विस्तार—अप्रैल 1992 में, वाणिज्यिक बैंकों के शाखा लाइसेंसिकरण की नीति को उदार बनाया गया था। अक्टूबर 1992 में इस नीति को और उदार बनाया गया। बैंकों को प्राधिकार दिया गया था कि वे कार्यालयों का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं तथा नया कारोबार कर सकते हैं। बैंकों को अब यह अनुमति है कि वे अपनी मौजूदा शाखाओं का उसी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, विशेषीकृत शाखाएं जैसे औद्योगिक वित्त/लघु उद्योग/अनिवार्ता भारतीय/खजाना शाखाओं जैसी विशेषीकृत शाखाएं खोल सकें, विस्तार काउंटर खोल सकें, इन काउंटरों पर सुरक्षित जमा खातों की व्यवस्था कर सकें और यदि मौजूदा ग्रामीण शाखाएं कतिपय न्यूनतम औपचारिकताओं के बाद अलाभकारी पाई जाएं तो उन शाखाओं को अनुपंगी कार्यालयों में बदला जा सके। इसके अतिरिक्त बैंकों को इस बात की अज्ञाती दी गई है कि वे बेहतर सेवा

उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपनी किसी शाखा को सरकारी कारोबार जैसा कोई कारोबार सौंप सकें। साथ ही, भावी शाखा-विस्तार और ग्रामीण और ग्रन्थ-शहरी केन्द्रों में लाइसेंस-करण इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित राज्य सरकारों और क्षेत्रीय कार्यदलों ने शहरी, पत्तन नगर और महानगरीय केन्द्रों में बैंक-रहित इलाकों/कम बैंक-शाखाओं वाले इलाकों आदि की पहचान करते हुए क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

9.4 बैंकों का निरीक्षण : बैंकों में प्रतिभूतियों के लेनदेनों में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को देखते हुए बैंकों के निरीक्षण के बारे में रिजर्व बैंक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के निरीक्षण की मौजूदा प्रणाली के दायरे और तत्वों की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष-श्री एस. पद्मनाभन) ने बदलते हुए वातावरण को दृष्टि में रखते हुए निरीक्षण और पर्यवेक्षण की एक नई प्रणाली तैयार किए जाने का सुझाव दिया है। रिजर्व बैंक ने इस तल की सिफारिशों को माना। नई प्रणाली के अंतर्गत, रिजर्व बैंक द्वारा मौके पर किए जाने वाले पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में ये बातें निहित होंगी : (क) वार्षिक वित्तीय निरीक्षण, (ख) सांविधिक लेखापरीक्षाओं द्वारा चुनिंदा मदों की लेखा परीक्षा, (ग) रिजर्व बैंक के वरिष्ठ और अनुभवी कार्यपालकों द्वारा दो वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा का व्यवस्थापन किया जाना, (घ) जनसामान्य को उधार दिए जाने, विकास-सम्बद्ध पहलुओं की पड़ताल का काम रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा मुख्य निरीक्षण अर्थात् वार्षिक वित्तीय निरीक्षण से अलग रखते हुए किया जाना, और (ङ) जब भी आवश्यक हो विशेष निरीक्षण और जांच-पड़ताल किया जाना। मुख्य निरीक्षण अर्थात् वार्षिक वित्तीय निरीक्षण की प्रमुख विशेषता है सम्बन्धित बैंक की वित्तीय मजबूती और कार्यप्रणालियों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच किया जाना। यह योजना निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों-सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू है। यह निर्णय लिया गया है कि चालू वर्ष के दौरान तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य पूरा हो जाने के बाद सांविधिक लेखा परीक्षाओं को कुछ खनिदा बैंकों के विशिष्ट कार्य-क्षेत्रों की जांच का कार्य सौंपा जाए। रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय मुख्यालयों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण किया। जहाँ तक वित्तीय निरीक्षणों का संबंध है, नौ निजी क्षेत्र के बैंकों और नौ विदेशी बैंकों का निरीक्षण किया; वित्तीय वर्ष 1993-94 के पहले तीन महीनों के दौरान वित्तीय निरीक्षण कार्य तीन निजी क्षेत्र के बैंकों और दो विदेशी बैंकों ने सम्पन्न किया गया।

9.5 रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 1992 में गठित कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में बैंक ने विभिन्न बैंकों में बड़े पैमाने पर बकाया चले आ रहे अन्तर शाखा खातों के मिलान कार्य के मद के बारे में सूचित किया। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1993 में बैंकों को सूचित किया

कि वे बड़े मूल्य वाली सभी मदों का दो महीनों के भीतर समायोजन कर लें, केन्द्रीय और स्थानीय मुख्य कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण लागू करें, समायोजन प्रक्रिया का विवेकीकरण करें और प्रविष्टियों का मिलान मासिक अन्तराल पर करते रहें। इन सभी बकाया कार्यों के लिए मार्च 31, 1994 तक समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस प्रकार 1993-94 के बाद से बैंकों को प्रविष्टियाँ छः महीने से अधिक समय तक असमायोजित रखने की अनुमति नहीं होगी।

9.6 अशोध्य कर्जों/हानियों को बट्टे खाते डाले जाने/समझौता संबंधी प्रस्तावों से जुड़े मामलों के संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाने और साथ ही हानि संबंधी मदों की पहचान करने में बैंकों की सहायता किये जाने तथा रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी अनुदेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिहाज से भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग-अलग बैंक के निदेशक मंडलों को अशोध्य कर्जों/हानियों को बट्टे खाते डाले जाने तथा विभिन्न संस्थाओं से जुड़े समझौता-प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में उपयुक्त शक्तिय सौंपे जाने की अनुमति दी है, जिनके प्रयोग के लिए सुरक्षा-उपाय/शर्तें और रिपोर्टिंग पद्धति संबंधित बोर्डों द्वारा तय की जाएगी।

9.7 रिजर्व बैंक ने "बैंकों में धोखाधड़ी और घनाचार" संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री ए. घोष) द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सभी बैंकों को चाहिए कि वे रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर अपने अनुदेश मेन्युअलों की समीक्षा करें और आन्तरिक नियंत्रण, निगरानी एवं सतर्कता तंत्र, विशेषतः रोकथाम विषयक सतर्कता के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और कार्यविधियाँ तय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न प्रणालियों का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। बैंक द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली के तरीके निर्धारित किए जाने के लिए बैंकों और लेखा परीक्षा व्यावसायियों का एक अनुपचारिक दल गठित किया गया है ताकि प्रतिभूति लेनदेनों में अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित करने संबंधी बैंकों के कारोबारी परिचालनों के एक बड़े हिस्से को कवर किया जा सके।

9.8 ऋण स्थगन, सम्मेलन और परिसमापन : फरवरी 1993 केमसन ग्राइलैण्ड के ग्रांड कोर्ट ने बैंक ग्राफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लि. की बम्बई शाखा के कारोबार को भारतीय स्टेट बैंक को बचने संबंधी शर्तों का अनुमोदन किया। भारतीय स्टेट बैंक ने बम्बई शाखा के कारोबार की खरीद 40 करोड़ रुपए पर किए जाने की पेशकश की। इस पेशकश के अनुसार बैंक ग्राफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लि. बम्बई के कारोबार का अभिग्रहण एस. बी. ग्राइ. इन्टरनेशनल बैंक

लि. द्वारा किया जाएगा जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित उसके पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था होगी। यदि किसी कारण से यह सहायक संस्था स्थापित नहीं हो सकी तो इसका अभिग्रहण स्वयं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस पेशकश पर विचार किया है और बम्बई उच्च न्यायालय में उस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए अर्जी दाखिल की है। 3 अगस्त, 1993 को न्यायालय ने अंतिम मुतवाई में विप्री की अनुमति दी है।

9.9 तीन बैंकों ने बैंक आफ कराड लि. की कुछ परिसम्पत्तियों और उसके स्टाफ को अपने पास लेने का अपना इरादा जाहिर किया था। इस बैंक के परिष्कारण संबंधी रिजर्व बैंक की याचिका बम्बई उच्च न्यायालय के विचारधीन है।

9.10 मार्च 31, 1990 की स्थिति के अनुसार, नौ बैंकों की वित्तीय स्थिति असंतोषजनक थी, जिनमें से एक बैंक, अर्थात् पूर्वांचल बैंक लि. का सम्मेलन सरकारी क्षेत्र के एक बैंक, मेसूर बैंक आफ इंडिया के साथ, 29 अगस्त, 1990 को कर दिया गया था। तीन बैंकों—कर्नाटक बैंक लि., बैंक आफ मद्रुरै लि. और सांगली बैंक लि. के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1991 के दौरान किए उसके निरीक्षणों के आधार पर यह पाया गया कि उनकी स्थिति में सुधार आया था क्योंकि उनकी जमाराशियों में कोई गिरावट देखने में नहीं आई, अर्थात् उनकी परिसम्पत्तियों का वसूली योग्य मूल्य उनकी जमाराशियों की देनदारी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था। तथापि उनके प्रावधानों, आंशिक चलनिधियों (कर्नाटक बैंक लि.) तथा प्रावधानों, चलनिधियों और आंशिक प्रदत्त पूंजी (सांगली बैंक लि. और बैंक आफ मद्रुरै लि.) में गिरावट आई। शेष पांच बैंकों—बनारस स्टेट बैंक लि., काशीनाथ मेठ बैंक लि., पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि., लाड कृष्ण बैंक लि. और धनलक्ष्मी बैंक लि. की वित्तीय स्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1991 के दौरान अलग-अलग तारीखों पर किए गए निरीक्षणों के अनुसार असंतोषजनक बनी रही। इन बैंकों के प्रावधानों, चलनिधियों, प्रदत्त पूंजी और आंशिक जमाराशियों में गिरावट पाई गई। इनके कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्हें जारी किये गये निर्देशों/इनमें प्राप्त आवश्यक विवरण के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा नार्नि निर्देशकों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। इन बैंकों का निरीक्षण 1992 की अंतिम तिमाही के दौरान फिर से किया गया है और छह बैंकों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एक ओर जहाँ काशीनाथ मेठ बैंक लि., पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि. तथा लाड कृष्ण बैंक लि. की वित्तीय स्थिति निरंतर असंतोषजनक रही, वहीं बैंक आफ मद्रुरै लि., कर्नाटक बैंक लि. तथा सांगली बैंक लि. की स्थिति में सुधार हुआ और उनकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक रही। दो बैंकों अर्थात् बनारस

स्टेट बैंक लि. और धनलक्ष्मी बैंक लि. की निरीक्षण रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

9.11 स्वर्ण बांड, 1993 और 10 प्रतिशत नाहन बांड, 1993 की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना : भारत सरकार द्वारा 15 मार्च, 1993 से स्वर्ण बांड स्वीप, 1993 शुरू करने और 10 प्रतिशत राहत बांड 1993 प्रचलित करने के परिणामस्वरूप सभी वाणिज्य बैंकों को उपर्युक्त बांडों की जमानत पर अग्रिम इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निर्देशों और शर्तों के आधार पर प्रदान करने के लिए अनुमति दी गयी है।

9.12 औद्योगिक ऋण : औद्योगिक ऋण को मांग को पीछता से पूरा करने के लिए बैंकों को अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से ऋण निगरानी व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किये गये हैं। अधिकतम अनुमत बैंक वित्त के मूल्यांकन हेतु माल सूची और प्राथम राशियों के लिए मानदंडों में अलग हटने के लिए बैंकों को अनुमति दी गयी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण निगरानी व्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक ऋण की मंजूरी के बाद की जांच की सूचना दिये जाने से संबंधित निश्चित सीमा को भी और आगे बढ़ा दिया है।

9.13 औद्योगिक ऋण से संबंधित समिति/कार्यदल : व्यापार तथा उद्योग द्वारा की गयी मांग के अनुसार और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसूप बैंक क्षेत्र की नीतियों में किये जाने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंकिंग प्रणाली द्वारा ऋण देने के लिए औद्योगिक ऋण नीति तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों, मानदंडों आदि के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाय। सर्वप्रथम रिजर्व बैंक के अंतर्गत पर भारतीय बैंक संघ ने बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी सुरक्षा सहैया करने के लिए उधार देने की वर्तमान महती ऋण प्रणाली की समीक्षा और उधार देने की किसी नई प्रणाली की शुरुआत-सहित आवश्यक होने पर आशाघ्न की विकास के लिए एक समिति (अध्यक्ष : श्री रजिंद जोलानी) गठित की। दूसरे संघीय सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत उधार दिये जाने संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा के लिए एक और समिति (अध्यक्ष : श्री जे. बी. गेंद्री) गठित की गयी। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त, 1993 को प्रस्तुत कर दी है तथा उसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है। अंततः कार्यशील पूंजी प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार के लिए मानदंड मार्गदर्शी सिद्धांत आदि निर्धारित करने में रिजर्व बैंक की भूमिका की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक दल (अध्यक्ष : सुश्री आई. टी. ब्राज) गठित किया गया।

9.14 रिजर्व बैंक ने मिनम्बर 1992 में निर्धारित ऋण संरचना की जांच के लिए निर्धारित ऋण संरचना संबंधी समिति

(अध्यक्ष : डा. जी. सुन्दरम) गठित की। समिति ने निधियों की लागत और निर्यात की गयी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर व्याज की लागत के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निर्यात वित्त संबंधी व्याज दर संरचना में संबंधित शिकायतों की जांच की। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 1 मार्च 1993 से निर्यात ऋण पर व्याज दर मपाट रूप से एक प्रतिशत कम कर दी गयी और निर्यात ऋण के मामले में व्याज पर कर को वापस ले लिया गया। इसके अलावा जैसा कि समिति ने सिफारिश की यह निर्णय किया गया था कि विदेशों में आयान बिलों की पुनर्मुतादी की योजना आरंभ की जाए।

9.15 राज्य स्तरीय निर्यात संबंधित समिति: मूलभूत और परिचालनगत समस्याओं का समाधान राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थाओं और कार्यालयों की सहायता से पीछता-पूर्वक करने की दृष्टि से एक 'राज्य-स्तरीय निर्यात संबंधित समिति' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जो पूर्णतः निर्यातों में संबंधित सभी मामलों के कार्य करेगी। राज्य का अग्रणी बैंक बैठकों का संयोजक होगा तथा सदस्यों में अन्य व्यक्तियों के साथ राज्य सरकारों, रिजर्व बैंक, स्थानीय वाणिज्य मंडलों, निर्यात संघों, आयातों एवं निर्यातों के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय, सीमांतकों निर्यात-आयात बैंक और भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (स्थानीय) आदि के अधिकारी शामिल होंगे। उक्त राज्य-स्तरीय निर्यात संबंधित समिति राज्य में निर्यात-वृद्धि की ध्यानपूर्वक निगरानी करेगी। समिति निर्यात ऋण, विदेशी मुद्रा विनियमावली, बीमा आदि से संबंधित परिचालनगत समस्याओं का समाधान करेगी वह बिजली की उपलब्धता, परिवहन आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में निर्यातकों की समस्याओं पर भी चर्चा और विचार करेगी तथा सामान्यतः राज्य में निर्यात संबंधित के लिए प्रयासों का समन्वय करेगी। समिति की बैठकें छमाही अंतरालों पर होंगी।

9.16 रुग्ण औद्योगिक उपक्रम: बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। जो इकाइयाँ वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम होने की सारथ्य रखती हैं उनके संबंध में प्रयोज्य पुनःस्थापन पैकज तैयार किए जाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण पर तन दिया जाता जारी रखा। इस पर अगवर्ती कार्रवाई के रूप में रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक के कार्यविभाजन पर निगरानी रखना चला आ रहा है जिसके लिए बैंकों में प्राप्त प्राथमिक विवरणों की पड़ताल की जाती है। मार्च 1993 से बैंकों की कार्य-निष्पादन रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण का निमाही के स्थान पर छमाही कर दिया गया है ताकि उनका तात्पर्य ऋण/कमजोर औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रस्तुत संबंधित छमाही की वार्षिकीय विवरणियों के साथ बिठाया जा सके।

9.17 एक आंतरिक दल ने रुग्णता को कम-पे-कम किए जाने संबंधी उपाय तलाश करने के लिए चर्चित बैंकों

और वित्तीय संस्थाओं के साथ वार्ता की है। रुग्ण/कमजोर चमड़ा उद्योगों की समस्याओं के अध्ययन के लिए और उपाय सुझाने के वास्ते डिसेम्बर 1992 में एक समिति (अध्यक्ष : श्री एन.जी. बालमुक्कमण्णन) का गठन किया गया है।

9.18 लघु उद्योग की रुग्ण इकाइयों के बारे में मार्च 1992 के अंत का नवीनतम अंकिड़ा ऐसी इकाइयों की संख्या 2,45,575 के नेहद उंचे स्तर पर दर्शाता है। मार्च 1992 में समाप्त वर्ष के दौरान लघु उद्योग की रुग्ण इकाइयों की सूची में जड़ी इकाइयों की संख्या 24,103 थी। लघु उद्योग की रुग्ण इकाइयों के बकाया ऋण की तुलना में अनुमूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण मार्च 1992 के अंत में 3,101 करोड़ रुपये था। रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों में से 2,42,546 का अर्थक्षमता अध्ययन किया गया और 19,210 इकाइयों को अर्थक्षम पाया गया, इनमें से 13,289 इकाइयों को पोषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत रखा गया। गैर-लघु उद्योग रुग्ण इकाइयों की संख्या 75 इकाइयों की बढ़ती हुई तथा कुल संख्या 1,536 हो गई तथा इन पर बकाया बैंक ऋण की राशि पिछले वर्ष के 5,106 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,787 करोड़ रुपये हो गई। इन गैर-लघु उद्योग की रुग्ण इकाइयों में से 1,301 इकाइयों के संदर्भ में अर्थक्षमता संबंधी अध्ययन पूरा किया गया और 567 इकाइयों को अर्थक्षम माना गया जिनमें से 401 इकाइयों को पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया।

9.19 कमजोर गैर-लघु उद्योग इकाइयों में से 63 कम होकर उनकी संख्या 813 तक नीचे आयी जिन पर 2,646 करोड़ रुपए का बैंक ऋण बकाया था। इनमें से अर्थक्षमता संबंधी अध्ययन 623 इकाइयों का पूरा किया गया और 361 इकाइयों को अर्थक्षम माना गया। इनमें से जिन इकाइयों को अर्थक्षम सामर्थ्य वाला पाया गया उनमें से 218 इकाइयों को बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया।

9.20 वित्तीय संस्थाओं को रिजर्व बैंक की सहायता : वर्ष 1992-93 में रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को अपनी सांख्यिक निधियों में से कोई भी सहायता नहीं दे रहा है। इस प्रकार की सहायता के रूप में 155 करोड़ रुपए की एकसम्व मंजूरी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 8 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर 15 वर्ष के लिए दी गई; यह राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि) परिचालन निधि में की गई चुनौती में से दी गई। इसके अनतिरिक्त, एक विशेष पुनर्गत सुविधा के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 400 करोड़ रुपए की राशि पूर्णगत और मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों में निवेश करने के लिए दी गई; यह राशि 14 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर दी गई जिसे दस सभान छमाही हिस्सों में चुकाया जाता है। किन्तु,

1993-94 के लिए, बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घा-वधि परिचालन) निधि में केवल एक करोड़ रुपये दिये। अध्याय XV में इसके व्यौरे दिये गये हैं।

9.21 कुल 11 बड़ी ग्रामिण भारतीय संस्थाओं के संबंध में प्रारम्भ की गई तिमाही सूचना प्रणाली को और व्यापक बनाया गया तथा इनके आंकड़ों का विश्लेषण, नीति निर्धारण के दृष्टिकोण से किया जाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय का लाया जाना आवश्यक समझा जाता है। वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों से जुड़े जिन समग्र नीति-उपायों को रिजर्व बैंक ने लागू किया था, उन्हें जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, उनके सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल ध्यान में लाया जाता है। जो अनुदेश वित्तीय संस्थाओं को उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए हाल ही में दिए गए हैं (क) बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा (ख) ग्राहकों की ओर से संविभागीय प्रबंधन और (ग) अनुमोदित दलालों के माध्यम से किये जाने वाले व्यावसायिक लेन-देनों के लिए कुछ उच्चतर संविधा सीमा का निर्धारण सरकारी क्षेत्र के बाण्डों और म्युचुअल फण्ड की यूनिटों की कारोबार संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री एस. एस. नाडकर्णी) की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एक महत्वपूर्ण सिफारिश इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरेंस सेटलमेंट्स एण्ड डिपॉजिटरी की प्रणाली की स्थापना से संबंधित है जिस पर पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और ऐसी सुविधा के परिचालन संबंधी तौर-तरीकों को प्रस्तुत करने के लिए श्री डब्ल्यू. एस. सराफ की अध्यक्षता में एक कार्य-दल कार्य कर रहा है।

9.22 आवास वित्त : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे आवास वित्त आबंटन के अपने-अपने शरीरों की पिछले वर्ष में उपाजित अपनी वर्तमान जमाराशियों

1.5 प्रतिशत के हिसाब से परिकलित करना जारी रखें। वर्ष 1991-92 के दौरान बैंकों में कुल जमाराशियों में और अधिक मात्रा में हुई वृद्धि को देखते हुए इस आधार पर गणना किया गया समग्र आवास वित्त का लक्ष्य 569 करोड़ रुपये पर उच्चतर था जबकि 1990-91 के लिए समग्र लक्ष्य 365 करोड़ था। अभिनिर्धारित किया गया था। बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अपने आवास वित्त लक्ष्य से आगे जा सकते हैं बशर्ते उनकी संसाधनों संबंधी स्थिति अनुकूल हो। वर्ष 1991-92 के दौरान भू-सम्पत्ति कर्ज पर लगाए गए प्रतिबंध उस सीमा तक लागू नहीं होते, जहां तक ऐसा ऋण लक्ष्य के प्रयोजन के लिए आवास वित्त की परिभाषा में शामिल किया जाता है।

9.23 राष्ट्रीय आवास बैंक की चुकता पूंजी, जिसका अभिवान पूर्णतः रिजर्व बैंक ने किया है, 250 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रही। जैसा कि निर्णय लिया जा चुका है, वर्ष 1992-93 के दौरान रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से

कोई राशि आबंटित नहीं की। 1993-94 में, बैंक ने इस निधि में एक करोड़ रुपया आबंटित किया है जिसे बाद में अध्याय 15 में दिया गया है।

9.24 वा क्षेत्र दृष्टिकोण : सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की समीक्षा किए जाने पर उसके कार्यान्वयन में कुछ कमियां पाई गईं जैसे (क) ग्रामीण रुपरेखा का अद्यतन न होना, (ख) ग्रामीण रुपरेखा में प्रदर्शित अर्थक्षमता के आधार पर ऋण योजनाओं का व्यावहारिक रूप में तैयार न किया जाना, और (ग) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शाखा प्रबंधकों द्वारा सजग प्रयास न किया जाना। रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1992 में नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करते हुए सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा कि वे सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में पाई गई सभी कमियों को दूर करें।

9.25 कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत स्कीम, 1990 : अस्थायी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के अधीन 7,829 करोड़ रुपये की ऋण राहत प्रदान की गई, जिसमें से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2,834 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 795 करोड़ रुपये और सहकारी बैंकों ने 4,200 करोड़ रुपये प्रदान किए। भारत सरकार ने अपने बजटीय आबंटन में से मार्च 1993 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में क्रमशः 1,500 करोड़ रुपये, 1,425 करोड़ रुपये और 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए : 1993-94 में 500 करोड़ रुपये के आबंटन में से 80 करोड़ रुपये भी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के दावों का निपटान करने के लिए प्रदान किए। इनमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2,158.04 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 672 करोड़ रुपये तथा सहकारी बैंकों ने 1,674.13 करोड़ रुपये उपयोग में लाए। रिजर्व बैंक ने भी सहकारी संस्थाओं के ऋण-कर्ताओं के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के 50 प्रतिशत अंश की पूर्ति के लिए नाबांड के माध्यम से 1,676.16 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए।

9.26 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा 1 और 1(क) से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छूट : रिजर्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा 1 और उपधारा 1(क) के परन्तुक से और दो वर्ष की अवधि अर्थात् 31 दिसम्बर 1994 तक के लिए छूट प्रदान की जिसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी जाने वाली प्रारम्भित नकदी निधियां उनकी मांग और मीयादी देयताओं का 3 प्रतिशत कमी रहेंगी। इस छूट के पीछे प्रमुख धारणाएं ये हैं कि अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कमजोर और घाटे में चले आ रहे हैं तथा यह कि वे कमजोर वर्ग वाले लक्ष्य समूह को ऋण दे रहे हैं, हालांकि हाल ही में अपने वृद्धिशील अभिमानों का

40 प्रतिशत अंश लक्ष्येतर समूह को भी दिए जाने की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्विस्थापन का प्रश्न भारत सरकार और रिजर्व बैंक के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

9.27 बैंकों में ग्राहक सेवा सम्बन्धी समिति :—बैंकों में गुणवत्तायुक्त ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित किया जाना आज के समय का एक पर्याप्त महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए हो गया है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में लाए जाने वाले सुधारों को वित्तीय क्षेत्र में लाए जाने वाले समग्र सुधारों का एक हिस्सा बनना के है। रिजर्व बैंक में ग्राहक सेवा से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों पर विचार किए जाने के बाद बैंक ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और बैंकों को अपना कार्यसमय बढ़ाने, कारोबार का समय बढ़ाने, विभिन्न मूल्य वर्गों में बैंक के घाड़ें शुरू करना, छोटे मूल्य वर्ग के नोट स्वीकार करना, कटे-फटे और गन्धे नोट बदलना, ब्याज दर निदेशों ग्रथवा उनमें हुए संशोधनों क सम्पूर्ण पाठ को समाचार पत्र में प्रकाशित कराना, 5000 रुपए तक के स्थानीय चेकों को तत्काल जमा करना और आहरी चेकों की विलम्ब से हुई वसूली पर ब्याज भ्रदा करना और जब लिखतों की प्राप्तियां मकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट या ऋण खाते में जमा करनी हों तब न्यूनतम उधार ब्याज दर लागू करने, जिससे इस प्रकार के ग्राहकों के लिए साम्यिक क्षतिपूर्ति की जा सके, संबंधी दिशानिर्देश जारी किए।

9.28 लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता तथा संबंधित पहलुओं पर विचार करने संबंधी समिति :—लघु औद्योगिक इकाइयों संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री पी.आर. नायक) ने सितम्बर 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि लघु उद्योग क्षेत्र ने कुल मिलाकर कार्यशील पूंजी का एक ऐसा स्तर प्राप्त किया जो इसके आउटपुट का केवल 8.1 प्रतिशत था और इनमें से ग्रामीण उद्योगों तथा अतिलघु उद्योगों को उनके उत्पादन के केवल लगभग 2.7 प्रतिशत तक का कार्यशील पूंजी वित्त ही प्राप्त हो सका। अतः, समिति ने सुझाव दिया कि जिन लघु इकाइयों के लिए ऋण सीमा एक लाख से अधिक नहीं रखी गई हो उनका लघु उद्योगों को मिलने वाले प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण पर पहला हक होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992-93 की पहली छमाही के लिए घोषित मुद्रा नीति में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज का सूत्रपात किया; इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) बैंकों को चाहिए की वे 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऋण दिए जाने में इस प्रकार बढ़ासरी करें कि उससे लघु उद्योग क्षेत्र की सभी जायज जरूरतों की पूर्ति पूर्ण रूप से हो जाए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को चाहिए कि वे अपने वार्षिक ऋण बजट सामान्य जनता (बाटम

अप) के आधार पर तैयार करें और प्रत्येक बैंक द्वारा शाखा स्तर पर तैयार किए गए बजटों में लघु उद्योग इकाइयों के परामर्श से और साथ ही अन्य संबंधित घटकों को दृष्टि में रखते हुए समेकित स्थिति दर्शाएं।

(ख) उनके द्वारा परिकलित वार्षिक कुल बिक्री के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर आकलित 50 लाख रुपये तक की कार्यशील पूंजी सीमाएं नहीं और मौजूदा दोनों ही सीमाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में ऋणता की समस्या पर काबू पाने के लिए, ऋण लघु उद्योग इकाई की परिभाषा को इस प्रकार संशोधित किया गया कि अर्थक्षमता की सामर्थ्य वाली लघु उद्योग इकाइयों की, उनके पुनर्स्थापन संबंधी उपायों में, शुरूआती स्तर पर ही सहायता की जा सके।

(घ) बैंकों को चाहिए कि लघु उद्योग इकाइयों की तकलीफों को दूर करने के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करें। इस प्रयोजन के लिए 'लोकपाल' जैसे प्राधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

9.29 रिपोर्ट के भाग 1 में उल्लिखित इन सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

10 ए सहकारी बैंक

10.1 नये शहरी बैंकों को लाइसेंस देना :—नये शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के संबंध में गठित समिति (अध्यक्ष: श्री एस.एस. मराठे) की सिफारिशों पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी थीं। रिजर्व बैंक ने उक्त समिति की सिफारिशें कतिपय आशोधनों के साथ स्वीकार कर ली हैं। तदनुसार, प्रवेश-बिन्दु और अर्थ-क्षमता और नये मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। नयी नीति इस प्रकार के बैंकों की आवश्यकता-आधारित और स्वस्थ वृद्धि पर बल देती है। तीन वर्ष की समय-सीमा के अन्दर इन शुरूआती अपेक्षाओं और सक्षमता के मानदण्डों का पालन करना होगा। तथापि, बहुत कम विकसित, आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों तथा कम विकसित राज्यों में स्थित नये शहरी सहकारी बैंकों एवं महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के द्वारा स्थापित बैंकों के लिए उक्त प्रवेश-बिन्दु संबंधी मानदण्डों में कुछ रियायतें दी गयी हैं। महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी केन्द्रों में कार्यरत बैंकों को संबंधित उपान्तीय ग्रामीण इलाकों तक अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। वर्तमान लाइसेंस रहित शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने के मानदण्डों में भी ढील दी गयी है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शहरी बैंकों को शामिल करने के मानदण्डों में संशोधन करना प्रस्तावित है।

10.2 कमजोर और अक्षम बैंकों की छटाई अधिक मजबूत इकाइयों के साथ विलयन/समामेलन या परिसमापन

द्वारा करना अपेक्षित होगा। राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में रिजर्व बैंक के साथ समन्वय करते हुए कार्रवाई शुरू करें। राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया जा रहा है कि वे सहकारी संस्थाओं की कार्यपद्धति में स्व-नियंत्रण और दायित्वपूर्ण कार्रवाई के साथ-साथ सच्चा लोकतंत्र और स्वायत्तता लाने के लिए राज्य सहकारी समितियों के कानून में उचित संशोधनों का प्रवर्तन करें। कमजोर शहरी बैंकों के विलयन/समांमेलन को सुसाध्य बनाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा सहकारी समितियों पर लागू है) में उपयुक्त विधायी संशोधन करने का सुझाव दिया जाएगा।

10.3 शाखा लाइसेंसिकरण कार्यक्रम :—1991-94 की तीस-चर्याय अधि के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लाइसेंस प्राप्त बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति दी जा रही है / दिये जाएंगे जो निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हैं: (i) बैंक वित्तीय तौर पर मजबूत हैं, (ii) बैंकों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को निर्धारित स्तर तक ऋण का अभिनियोजन कर दिया है, (iii) बैंकों अतिरिक्त निर्धारित सीमा के अन्दर हैं, और (iv) बैंकों ने निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों में जहां निदेशों के उल्लंघन, यदि कोई हों, बताये गये हैं वहां उनका अनुपालन प्रस्तुत कर दिया है। तदनुसार, शाखा योजना अधि 1991-94 के दौरान 660 शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों में से 363 बैंकों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है और शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक ने जून 1993 के अन्त तक इन बैंकों को 446 केन्द्र आबंधित किये हैं।

10.4 9 जून, 1993 को रिजर्व बैंक ने विस्तार काउंटर खोलने, कार्यालयों का स्थानांतरण करने और शाखाएं बंद करने से संबंधित वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अगे और रियायत लागू कर दी हैं। तथापि, संबंधित बैंकों के निदेशक बोर्डों द्वारा विस्तार काउंटर खोलने, कार्यालयों का स्थानांतरण और शाखाओं के विभाजन संबंधी निर्णयों का अनुमोदन किया जाना चाहिए तथा इसकी सूचना रिजर्व बैंक को भी दी जानी चाहिए और उनके वास्तविक कार्यान्वयन के एक महीने के भीतर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

10.5 कमजोर प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की पुनर्व्यवस्था :—31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार 211 अनाभ्रप्रद/कमजोर बैंक और ऐसे बैंक भी थे जो न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सके थे। उनकी वित्तीय स्थिति में कमी/परिचालन संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

10.6 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 35क के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने चार प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को अन्य बातों के अलावा जमा राशियों के आहरण की अधिकतम राशियों पर एवं विनिविष्ट राशियों से अधिक ऋण और भ्रमि प्रदान करने/नवीकृत करने और खर्चा करने पर प्रतिबंध, लगाते हुए, निदेश जारी किये। इसके अतिरिक्त दो बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के, प्रावधानों के अन्तर्गत जमाकर्ताओं के हित के विपरीत असंतोषजनक कार्य के लिए तथा भारत में बैंकिंग कारबार करने हेतु लाइसेंस निरस्त करने के लिए 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये। छः शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में प्रबंधक वर्गों, अर्थात् निदेशक बोर्डों का अधिक्रमण किया गया है। रिजर्व बैंक की विचारण पर वर्ष 1992-93 के दौरान भारत सरकार द्वारा छः बैंकों को अधिस्थगन के आदेश के अधीन रखा गया और इन सभी बैंकों का अन्व मजबूत हवाइयों के साथ समांमेलन किया गया/समांमेलन करने के लिए अनुमति दी गयी।

10.7 सहकारी क्षेत्र में सुधार :—प्रवेश बिन्दु, अर्थ क्षमता के मानदंड एवं उनके परिचालनों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के अलावा, रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों पर आय निर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित शर्तों पर ही उपयुक्त आशोधनों के साथ शर्तें रखी हैं जिन्हें 1 अप्रैल 1992 को प्रारम्भ हुए लेखा-वर्ष के साथ शुरू, होने वाली तीन वर्ष की अवधि में एक चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित करने हुए 9 फरवरी 1992 को विस्तृत सिद्धान्त जारी किये कि 21 मार्च 1993 को समाप्त लेखा-वर्ष से घटिता आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और खोई हुई आस्तियों के लिए किये गये आवश्यक प्रावधान उनके लाभ-हानि खातों और तुलन-पत्रों में प्रतिबिम्बित हों।

10.8 शहरी सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त :—रिजर्व बैंक ने पांच शहरी सहकारी बैंकों को लघु और अत्यन्त छोटी औद्योगिक इकाइयों को बैंक दर पर दिये जाने वाले उनके भ्रमि के संबंध में पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान 20 प्राथमिक सहकारी बैंकों को कुल 10.64 करोड़ रुपये की ऋण संसाधन मंजूर की गई। 31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार इस सीमा के संबंध में वकाया राशि 7.19 करोड़ रुपये थी।

10.9 सहकारी विकास निधि :—सहकारी बैंकों में प्रबंधन प्रणालियों और कुशलताओं को सुधारने में सहायता प्रदान करने के लिए संघ के बजट में 10 करोड़ रुपये की

प्रारंभिक राजि के साथ लाभांश के आवधिकरण में सहकारी विकास निधि स्थापित करी का प्रस्ताव किया गया है।

10.10 शहरी सहकारी बैंकों में कम्प्यूटीकरण :— शहरी सहकारी बैंकों में कम्प्यूटीकरण के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिश को स्वीकार करने हुए रिजर्व बैंक ने 24 जून, 1993 को सभी शहरी सहकारी बैंकों, विशेषकर 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी रखनेवाले शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने परिचालनों के कम्प्यूटीकरण के लिए उचित कदम उठाएं जिससे बेहतर ग्राहक सेवाएं की जा सकें, लाभप्रदता में वृद्धि की जा सके और उनकी समग्र कार्यकुशलता में सुधार लाया जा सके।

10.11 स्वर्ण बाण्ड, 1998 और 10 प्रतिशत राहत बांड, 1993 की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना :— रिजर्व बैंक ने 2 जून, 1993 को शहरी सहकारी बैंकों को स्वर्ण बाण्ड, 1997 और 10 प्रतिशत राहत बांड, 1993 की जमानत पर अग्रिम प्रदान करने के लिए अनुमति दी। एक ओर जहाँ इस प्रकार के अग्रिमों पर ब्याज दर अग्रिमों के संबंध में समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देशों पर आधारित होगी वहीं दूसरी ओर बैंकों को भी चाहिए कि वे उधारकर्ता की ऋण आवश्यकता की वास्तविकता एवं उधार दी गई निधियों के उचित अंतिम उपयोग के बारे में स्वयं स्पष्ट हो जाएं।

10.12 राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा 1 और 1क से छूट :— भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा 1 और 1क के परन्तु के प्रावधानों से 31 दिसम्बर 1994 तक दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए छूट दी है। तदनुसार, इस प्रकार के बैंकों द्वारा रखी जाने वाली अरक्षित तकदी निधियों उनकी मांग और सीमादी देयताओं से 3.0 प्रतिशत के रूप में जारी रहेंगी।

11. गैर-बैंकिंग वित्तीय और गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा राशि स्वीकरण

11.1 वित्तीय कम्पनियों के संबंध में कार्यकारी दल :— मरसिहम समिति ने यह स्वीकार किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों अनिवार्यतः समग्र वित्तीय क्षेत्र के मुद्दारों की मुख्य धारा के भीतर ही होनी चाहिए। समिति ने अवलोकन किया कि कारबार चलाने हेतु इन कम्पनियों के लिए भी विवेकपूर्ण मानदंड और मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जाएं और संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण के लि

प्रस्तावित गठित की जाने वाली एजेंसी के दायरे के भीतर आर्थिक विवरणों के आधार पर एक दूरस्थ पर्यवेक्षण प्रणाली गठित की जाए। वित्तीय कम्पनियों के लिए सुधार कार्यक्रम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1992 में श्री ए.सी. शाह की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया और दल ने दिसम्बर 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यकारी दल ने वित्तीय कम्पनियों के सुधार के लिए व्यापक ढांचे की व्यवस्था की और कम्पनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को निर्धारित कर मुद्दर बनाने की अपेक्षा की। दल की गठवपूर्ण सिफारिशों नीचे दी गयी हैं :

- (i) वित्तीय कम्पनियों के श्रेणीवार वर्गीकरण को हटाया जाय और सभी वित्तीय कम्पनियों के लिए एक समान विनियमान्वली लागू की जाए।
- (ii) रिजर्व बैंक की नियामक कार्यविधि को 50 लाख रुपये और उससे अधिक की स्वाधिकृत निधियों वाली कम्पनियों तक परिसीमित किया जाए।
- (iii) दल ने नयी वित्तीय कम्पनियों के संबंध में, प्रवेश मानदंड अर्थात् 50 लाख रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि और जमा राशियों को स्वीकार करने के पूर्व की निष्क्रिय अवधि का प्रस्ताव किया है।
- (iv) ऋण केन्द्रण की सीमा, अवांछित क्रियाकलापों में निवेशों को रोकना आदि जैसे विनियामक घटकों को परिसंपत्तियों में दिखाया जाना चाहिए।
- (v) परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की जोखिम तथा तुलनात्मक में न आने वाली मदों के लिए ऋण अंतरण कारकों के आधार पर पूंजी-पर्याप्तता मानकों को निर्धारित किया जा सकता है।
- (vi) जमा राशियों की छूट प्राप्त श्रेणी को हटाया जाए और सभी जमा राशियों को विनियामक ढांचे के अन्तर्गत लाया जाए। बैंकों/संस्थाओं से प्राप्त जमा राशियों और लिये गए उधारों के बीच एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए।
- (vii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को 12 महीने तथा 84 महीनों के बीच की अवधि के लिए जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, जब तक बैंक जमा राशियों पर ब्याज दरें विनियमित की जाती हैं, तब तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा स्वीकृत जमा राशियों पर ब्याज दरें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तावित दरों से 2 या 3 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।

(viii) आय की पहचान, खातों में सुस्पष्टता के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और अशोध्य तथा संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधानों को निर्धारित किया जाए।

11.2 एक स्व-नियामक संगठन का गठन, पांच वर्ष के बाद अनिवार्य ऋण-पात्रता निर्धारण, जमाकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए जन चेतना कार्यक्रम आदि जैसी अन्य कुछ सिफारिशें हैं।

11.3 रिजर्व बैंक ने सिद्धांततः शाह कार्यदल की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया चूंकि यह सुधार प्रक्रिया वित्तीय कंपनियों द्वारा सामंजस्य की अपेक्षा की संभावना रखती है, अतः एक चरणबद्ध रूप में कार्यान्वयन के लिए कुछ उपाय प्रस्तावित किये गये थे। तदनुसार, बैंक ने 12 अप्रैल, 1993 से निदेशों में अनेक परिवर्तन किये जिनका मुख्य सार नीचे दिया गया है।

11.4 उपायों के एक भाग के रूप में पहले चरण में, बैंक ने अप्रैल, 1993 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किये गये निदेशों में कतिपय परिवर्तन किये और बाद में मई 1993 में संशोधन किये। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों की अवधि एक समान रूप में न्यूनतम 12 माह और अधिकतम 84 माह निर्धारित किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए अधिकतम सीमा 120 महीनों से घटाकर 84 महीने कर दी गयी है जबकि अन्य सभी वित्तीय कंपनियों के लिए अवधि की न्यूनतम सीमा 24 महीने से कम करके 12 महीने कर दी गयी है। समयपूर्व आहरण वाली जमाराशियों के संबंध में नियमों का संशोधन जमाराशियों की न्यूनतम अवधि में कमी के अनुकूल किया गया है। इस प्रकार इससे विभिन्न श्रेणियों की कंपनियों की जमाराशियों की परिपक्वता का वायरा समरेखित किया गया है। अंतर कंपनी जमाराशियों/उधार राशियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के निदेशकों और शेयर धारकों से प्राप्त धन और डिवेंचरों को जारी करके जुटाया गया धन अथवा अचल संपत्ति बंधक रखकर प्राप्त किये गये बांडों को बैंक के निदेशों के दायरे में लाया गया है जो अब तक छूट प्राप्त जमाराशियों की कोटि में थे, तथापि, वित्तीय कंपनियों द्वारा स्वीकृत उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के दुगुने तक की सीमा वाली 12 महीने की अवधि तक की अंतर कंपनी जमाराशियों पर ब्याज दर और न्यूनतम अवधि से संबंधित शर्तें लागू नहीं होंगी। किराया खरीद वित्त और उपस्कर पट्टादायी कंपनियों से अपेक्षित है कि वे जमाराशियों के 10 प्रतिशत चल परिसंपत्तियां बनाये रखें। ऋण और निवेश कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपनी जमाराशियों के 5 प्रतिशत की सीमा तक चल परिसंपत्तियां बनाये रखें। इनके बारे में इसके पूर्व कोई चल परिसंपत्तियों की अपेक्षा की शर्त नहीं थी। उपस्कर पट्टादायी और किराया

खरीद वित्तीय कंपनियों के मामले में चल परिसंपत्तियों का आधा अर्थात् जमाराशियों का 5 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों और/अथवा सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों के रूप में बनाये रखा जाए। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को भी उनकी जमाराशियों देयताओं के 10 प्रतिशत की सीमा तक, अनुमोदित प्रतिभूतियों में 70 प्रतिशत निवेशों की सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों और अथवा सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों में न्यूनतम निवेश करना होगा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां, जिन्होंने निर्धारित चलनिधि अनुपात प्राप्त नहीं किया था, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको मार्च 1994 के अंत तक समय दिया गया है। उन अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों—सहित ऐसी सभी वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक में अपना पंजीकरण करवायें जिनकी निवल स्वाधिकृत निधियां 50 लाख रुपये और उससे अधिक हैं। यथा समय पंजीकरण उन कंपनियों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो अपनी गति-विधियां बढ़ा रही हैं।

11.5 कार्यदल की अन्य सिफारिशें चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जाएंगी और यथा पेक्षित वैधानिक परिवर्तनों के बारे में सरकार को सुझाव दिया जाएगा।

11.6 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को जारी निदेश सामान्यतया कतिपय स्कीमों के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करनेवाली अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां उन निदेशों के समूह से नियंत्रित हैं, जिन्हें अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (उनकी जमाराशियों की मात्रा की तुलना में) की निवल स्वाधिकृत निधियां पर्याप्त नहीं हैं। वित्तीय तथा विधि गैर-बैंकिंग कंपनियों को जारी निदेशों से भिन्न ये निदेश यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके जमाराशि देयताओं का कम से कम 10 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों में रखा जाए और जमाराशि देयताओं का अन्य 70 प्रतिशत अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाए। कतिपय अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों ने इन निदेशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। इनमें से कुछ कंपनियां जमाकर्ताओं को अपनी संपूर्ण देयता भी नहीं बर्शाती और इसके स्थान पर वे अपनी राजस्व लागत की पूर्ति के प्रयोजन के लिए जमाराशियों का एक हिस्सा अपने लाभ और हानि लेखे में अंतरित करती हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30 जनवरी 1992 के अपने फैसले में निदेशों की वैधता को मान्य ठहराया। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया था कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों जमाराशियों के किसी अंश को अपनी चालू पूंजीगत लागत की पूर्ति के लिए उपयोग नहीं कर सकती। इस निर्णय के बाद भी यह पाया गया था कि कुछ कंपनियों ने अपने जमाकर्ताओं से प्रक्रिया/अनुरक्षण प्रभारों के नाम पर पर्याप्त धन एकत्र करने की

प्रथा शुरू की है। बैंक ने ऐसे प्रभाव एकत्र करने से इन कंपनियों को मना करते हुए अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को जारी निदेशों को संशोधित किया है। इसमें से एक कंपनी ने इस संशोधनों को चुनौती दी और फिलहाल यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में है।

11.7. चिट फंड अधिनियम, 1982 : जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, इस अधिनियम को अभी तक 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनसमें। फिर यहाँ, चिट फंड अधिनियम की वैधता को चुनौती बिभिन्न न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दी गयी, मामले की सुनवाई नवंबर 1992 में उच्चतम न्यायालय में हुई और न्यायालय ने दिनांक 13 जुलाई, 1993 के अपने फैसले में अधिनियम की वैधता की वैधता को मान्य ठहराया।

11.8. अनियमित निकायों द्वारा जमाराशियों का स्वीकरण : भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45न तथा 58इ में उल्लिखित अनियमित निकायों के बिना कार्रवाई करने के लिए जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपयुक्त अधिकारियों को प्राधिकृत करते हुए अधिसूचनाएं जारी कीं उनकी संख्या 30 पर अपरिवर्तित रही। जिन अनियमित निकायों को जमाना भरना है उनकी कुल संख्या छह थी, संबद्ध उच्च न्यायालय ने एक मामले को संयुक्त कर दिया है।

11.9. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ग द्वारा तथा नियमित व्यक्तियों, फर्मों और अन्य अभिगमित निकायों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले जमाराशियों की अधिकतम संख्या से संबंधित शर्तों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5 फरवरी 1993 के अपने निर्णय में अधिनियम के अध्याय III-ग की संवैधानिक वैधता को मान्य ठहराया।

XII. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम और बीमा क्षेत्र का सुधार

12.1. जुलाई 1980 से प्रचलित किसी बीमाकृत बैंक में 30,000/- रुपये की बीमा रक्का राशि में कमी बढ़ि करके 1 मई 1993 से एक लाख रुपये कर दी गई जो स्वयंशाधीन वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधि थी। यह उस अवधि के दौरान बीमा रक्का राशि की मांगों में बढ़ि करने की प्रतिश्चा स्वरूप था और उन विवेकपूर्ण मानकों के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए जरूरी था जो अब किये जा रहे हैं। बीमा प्रीमियम दर को 1 जुलाई 1993 से प्रत्येक 100 रुपये पर 4 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे वार्षिक कर दिया गया है। 31 मार्च

1993 को बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या 1931 थी जिसमें 80 वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय प्रामाण बैंक और 1,655 सहकारी बैंक शामिल हैं। वर्ष के दौरान मार्च 1993 के अंत में प्राप्त किये गये 105.97 करोड़ रुपये के बीमा प्रीमियम की तुलना में निगम ने मामलों के निपटान के लिए एक वाणिज्यिक बैंक और दो सहकारी बैंकों के संदर्भ में "खते में" भुगतान के रूप में केवल 38.99 करोड़ रुपये प्रदा किये।

12.2. जैसा कि पिछली रिपोर्ट में सूचित किया गया था, निगम ने 1 अप्रैल, 1992 से अपनी छह स्कीमों में से 3 का समापन किया था क्योंकि गारंटीकृत अभिगम शून्य/नगण्य थे, सहभागी संस्थाएं गारंटी शुल्क की प्रदायगी में निरंतर बूक कर रही थीं। इस प्रकार, केवल 3 स्कीम ही परिचालन में हैं, अर्थात् प्रत्येक गारंटी स्कीम, 1971, प्रत्येक गारंटी (सहकारी बैंक) गारंटी स्कीम, 1984 और प्रत्येक गारंटी (लघु उद्योग) गारंटी स्कीम, 1981। इन तीन स्कीमों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए गारंटीकृत अभिगमों की राशि 31 मार्च 1992 तक 43,605.50 करोड़ रुपये थी। लगातार तीसरे वर्ष में भी गारंटी शुल्क की प्राप्तियां गारंटी दावों की प्राप्तियों से कम थी। चालू वर्ष के दौरान 1,143.27 करोड़ रुपये के गारंटी दावों की प्राप्तियों ने 702.78 करोड़ रुपये के गारंटी शुल्क की प्राप्तियों से बहुत आगे बढ़ते हुए 440.49 करोड़ रुपये की कमी को पीछे छोड़ दिया। चूंकि इसके कारण चालू गारंटी स्कीमों की परिचालन संबंधी प्रत्येकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए निगम को 1 अप्रैल 1993 से प्रत्येक गारंटी स्कीम, 1971 की गारंटी शुल्क दर को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत वार्षिक करना पड़ा। तथापि, अन्य दो स्कीमों के लिए दरें 1.5 प्रतिशत वार्षिक पर अपरिवर्तित हैं।

12.3. जैसा कि भाग 1 में उल्लेख किया गया था, बैंकिंग क्षेत्र तथा पूंजी बाजार को सम्मिलित करते हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के क्षेत्र में अनेक पहल की गयी हैं जिनका उद्देश्य चालू संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुकूल अर्थ-व्यवस्था के लिए गठित अधिक कार्यक्षम तथा प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना है। बीमा समग्र वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह जरूरी समझा गया कि इस क्षेत्र में भी इसी प्रकार से सुधारों की अपेक्षा है। अतः, सरकार ने 2 अप्रैल, 1993 को इन मुद्दों पर गंभीर विचार करने और निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए "बीमा क्षेत्र में सुधारों के संबंध में समिति" (अध्यक्ष : श्री आर. एन. महोत्त) गठित की :

(i) बीमा उद्योग की संरचना की जांच करना क्योंकि वर्तमान ढांचे के भीतर ही इसका विकास हुआ है और एक कार्यक्षम और प्रत्यक्ष बीमा उद्योग का निर्माण करने के उद्देश्य से इसकी श्रृंखलाओं एवं कमजीरियों का मूल्यंकन करना ताकि बीमा सेवाएं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और बीमा उत्पादों

में विविधता आये। इसके साथ ही, जनता को यह अच्छी सेवा दे सके और विकास हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रभावी हथियार के रूप में काम कर सकें :

(ii) वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के अन्य भागों और आजकल हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बीमा उद्योग की संरचना और नीति से संबंधित सामान्य ढाँचे में परिवर्तन के लिए सिफारिशें करना ;

(iii) भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय सामान्य बीमा निगम के संबंध में विशेष सुझाव देना जिससे परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश में इन संगठनों की कार्य-पद्धति में सुधार हो और परिवर्तनशील अपेक्षाओं के अनुरूप नियामक प्रणाली को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए सिफारिशें करना ;

(iv) सर्वेक्षकों, बिचौलियों और बीमा क्षेत्र के अन्य सहायकों की भूमिका तथा उनकी कार्य पद्धति की समीक्षा और सिफारिशें करना ;

(v) बीमा क्षेत्र के स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन विकास के लिए अथवा समिति द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों के परिणामस्वरूप, विधान में यथावश्यक परिवर्तन सहित समिति द्वारा संगत समझे जाने वाले अन्य मामलों के बारे में सिफारिशें करना ।

12.4 समिति में आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

XIII. विनियम प्रबंधन और विदेशी मुद्रा नियंत्रण

13.1 1992-93 के दौरान विदेशी विनियम प्रबंधन और नियंत्रण के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं । एक जनवरी 1993 के प्रारम्भ में अध्यादेश जारी कर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया और बाद में उसे निरस्त कर दिनांक 2 अप्रैल 1993 को विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम 1993 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया । तथापि संशोधित अधिनियम जिस दिन अध्यादेश जारी किया गया था उसी दिन अर्थात् 8 जनवरी 1993 से प्रभावी माना गया है । दूसरी घटना 1 मार्च 1993 से बाजार आधारित एकीकृत विनियम दर की शुरुआत है जिसे इस रिपोर्ट के भाग 1 में विस्तृत रूप में दिया गया है ।

13.2 विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1993 : पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की व्यापक समीक्षा करने, उसे सरल बनाने, भारत में विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह और इसी प्रकार विदेशी संयुक्त उद्यमों के रूप में भारतीय कंपनियों द्वारा किये जाने वाले निवेशों में आने वाली रुकावटों को दूर करने के संबंध में सरकार के निश्चय का उल्लेख किया गया था । तबनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में निम्नलिखित व्यापक श्रेणी के संशोधन किये गये :

(i) भारत में 'फैस कंपनियों' के परिचालनों को नियंत्रित करने वाले कुछ उपबंधों में संशोधन किये गये जिसके परिणामस्वरूप फेरा 1973 के अधीन इन कंपनियों पर लगाये गये प्रतिबंध हटा दिये गये । इससे उन फेरा कंपनियों को जिनमें किसी भी प्रकार की विदेशी इन्विस्टी सहभागिता नहीं है या जिनमें 40 प्रतिशत तक विदेशी इन्विस्टी सहभागिता है और जिन पर फेरा 1973 के प्रतिबंधात्मक उपबंध लागू नहीं होते उन्हें फेरा कंपनियों के समकक्ष रखा गया है ।

(ii) रुपये की परिवर्तनीयता की दिशा में पहल के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंध लगाने वाले कई उपबंधों को जिन्हें प्रतिकूल पाया गया उनमें संशोधन किया गया या उन्हें हटा दिया गया । विदेशियों द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा में ही टोटल बिन्हीं का भुगतान करने, अनिवारियों की ओर से भारत की/से यात्रा के लिए रुपये में भुगतान करने पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करने वाले उपबंधों में संशोधन, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं ।

(iii) जिन व्यक्तियों के बारे में यह संदेह हो कि उन्होंने उक्त अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है उन्हें परेशानियों से बचाने की दृष्टि से अधिनियम के लागू किये जाने संबंधी कतिपय उपबंधों में संशोधन किया गया ।

(iv) पट्टे पर या किराये पर माल के निर्यात के लिए बेहतर विनियम बनाने और प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा क्रमशः रिजर्व बैंक को विवरणियाँ प्रस्तुत करने और रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से दो नये उपबंध अर्थात् 18क और 73क प्रारण लागू की गई । उत्तरवर्ती धारा रिजर्व बैंक को अधिकार देती है कि वह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों और कार्यक्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकृत व्यापारियों पर जमाता लगाये ।

13.3 फेरा के अंतर्गत प्रक्रियाओं का सरलीकरण : अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रक्रियाओं और प्रलेखीकरण को सरल बनाने के लिए संशोधन किये गये तथा प्राधिकृत व्यापारियों को प्रेषण के कतिपय अन्य क्षेत्रों जैसे (i) भारत में परिचालनगत विदेशी हवाई जहाज कंपनियों की अधिकृत आय (ii) भारतीय कंपनियों द्वारा रखे गये विदेशी तक-निशियों को भुगतान योग्य पारिश्रमिक (iii) माल के आयात के लिए अभिम प्रेषण और (iv) विविध प्रयोजनों जैसे विज्ञापनों, सदस्यता शुल्कों, परीक्षा शुल्कों और कानूनी व्ययों के लिए प्रेषणों हेतु अधिक प्राधिकार दिये गये । प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा वायदा विनियम बीमा रक्षा के उपबंधों से विनियमों को और उदार बनाया गया और प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकार दिया गया है कि वे विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों में उनके सीधे निवेश पर उनके गैर-धोरण पर उन्हें देय लाभांश के संबंध में और विदेशी मुद्रा

में नामित भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के पास बैंक खाते में रखी हुई बकाया राशि के बारे में निवासियों को वायदा विनियम रक्षा दें। फेरा कंपनियों में विदेशी निवेशकों के शेयरधारकों पर लाभांश के प्रेषणों पर पहले रिजर्व बैंक के प्राधिकार की आवश्यकता थी किंतु अब प्राधिकृत अधिकारियों को सीधे ही लाभांश भेजने की अनुमति दी गई है।

13.4 व्यापारिक संस्थाओं जैसे एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिककी) आदि द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों/सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों, अध्ययन संस्थानों, प्रशिक्षण, उच्चतर शिक्षा और डॉक्टरी चिकित्सा के लिए विदेश की यात्रा सहित व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए विदेश की यात्राओं से संबंधित विनियमों को और उधार बनाया गया और साथ ही साथ प्रक्रिया तथा प्रलेखीकरण को भी सरल बनाया गया। रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना ही इन आवेदन पत्रों को सीधे ही निपटाने के अधिकार प्राधिकृत व्यापारियों को दिये गये हैं।

13.5 निम्न क्षेत्रों में सामान्य अनुमति :—रिजर्व बैंक ने अत्यधिक उदारीकृत परिस्थितियों के अधीन अनिवामी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों को भारत में अप्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश करने की सामान्य अनुमति दी है। भारत में बैंकों में सामान्य अनिवामी रुपया खाता खोलने और बनाए रखने के लिए उदारीकरण से संबंधित मामलों के बारे में निश्चित संदर्भ को कम करने के लिए इन खतों को भी समस्त अनिवामीयों (और न केवल अनिवामी भारतीयों) के नामों से अनुमति दी गई है। नियंत्रण करने की प्रक्रिया को पूर्णतया हटाते हुए इन खातों से संबंधित विनियमों को अत्यधिक सरल बना दिया गया है। विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय खोलने के बारे में पूर्ववर्ती मार्गदर्शी सिद्धांतों को परिचालन के क्षेत्रों के विस्तार के साथ-साथ अत्यधिक उदार बनाया गया है।

13.6 मुद्रा प्रयोजनों के लिए 500 अमरीकी डालर के समकक्ष कुल मूल्य की विदेशी मुद्राएं रखने की सामान्य अनुमति सरकार ने निवासियों को दी है।

13.7 घोषणा से छूट/लौटनेवाले भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सौंपना : भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिकों को देश में स्थायी रूप से अपनी वापसी पर समस्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को जो उन्होंने अनिवामीयों के रूप में प्राप्त की थी रिजर्व बैंक को घोषित करना आवश्यक था। उनके लिए यह भी आवश्यक था कि वे विदेशों में अपने बैंक खातों को बंद कर दें। रिजर्व बैंक की शर्तों के अधीन और उसकी अनुमति से ही विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के अन्य रूपों को रखने की उन्हें अनुमति दी गई थी। जहाँ ऐसे व्यक्ति विदेशों

में विदेशी मुद्रा राशियां रखना जारी रखने के इच्छुक हों, उन्हें बैंक की अनुमति प्राप्त करना होगा। विदेश में कम से कम एक वर्ष की अवधि तक रहने वाले अनिवामीयों को अब देश में स्थायी रूप से रहने के लिए लौटने के पश्चात् रिजर्व बैंक को अपनी विदेशी मुद्रा अस्तित्वा घोषित करने से छूट है और किसी प्रतिबंध के बिना उन्हें उपयोग में लाने की अनुमति दी गई है। इस सुविधा में अपने विदेशी निवेशों को इधर-उधर करना, कानूनी तौर से प्राप्त की गई अपनी विदेशी अस्तित्वा पर अर्जित आय को विदेश में लगाना शामिल है। प्रोत्साहन के रूप में ऐसे व्यक्ति जो अपनी विदेशी मुद्रा निधियां देश में लाते हैं उन्हें भारत में बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों को बनाये रखने और किसी भी विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों के बिना स्वतंत्र रूप से ऐसे खातों की निधियों का उपयोग करने की अनुमति भी दी गई है।

13.8 उदारीकृत बेगेज नियमावली :—सरकार ने 35 बेगेज मर्दा पर लागू सीमा शुल्क को 255 प्रतिशत घटाकर यथामूल्य 150 प्रतिशत कर दिया है। रियायती दरों का लाभ लेने के लिए विदेश में कम से कम कितने समय तक रहना है इसके बारे में कोई निर्धारित शर्त नहीं है और दरों के लिए पात्र माल का कुल मूल्य 1.50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

13.9 घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां :—घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में कई गतिविधियां भी हुईं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा वायदा विनियम रक्षा के उपबंध से संबंधित विनियमों को शिथिल किया गया है। अब उन्हें (i) समस्त वास्तविक निवेशकों को वायदा कवर देने (ii) भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने के बाद आवश्यक परिवर्तनों में जाये बिना एकमुश्त आधार पर लम्बी समयावधियों 180 दिनों से भी अधिक के लिए बीमा रक्षा देने (iii) अनिवामी भारतीय जमाकर्ताओं के पास की विदेशी मुद्रा अनिवामी मुद्राओं के बन्ने किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में पूर्णतः रक्षा विनियम की जिम्मेदारी लेने और (iv) दो विदेशी मुद्रा अनिवामी मुद्राओं के बीच ऐसा विनियम करने की अनुमति दी गई है।

13.10 रुपये पर दबाव कम करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि एक दिवसीय अधिविक्रीत स्थिति प्रत्येक कार्य दिन की समाप्ति पर रुपये में एक मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समकक्ष से अधिक न हो तथापि, इस सीमा के प्रयोजन के लिए उनके निवीयन हेतु ग्राहक क्रयों और विदेशी मुद्रा क्रयों को छोड़ दिया गया है।

13.11 विदेशी निवेश :—वर्ष के दौरान लाभांश प्रत्यावर्तन को संतुलित करने के लिए निर्यात वायित्वों में समाविष्ट

उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्रस्तावों का गैर-प्रशुल्क प्रतिबंधों से मुक्त किया गया था (22 उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के अलावा)। कंप्यूटरों के क्षेत्र में व्यापक प्रौद्योगिकीय प्रगति की विस्तार-सीमाओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक हाईवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम प्रारंभ की गई थी जो 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता पूंजीगत माल के शुल्क मुक्त आयात और कंपनी तथा आयकर से सम्बंधित पांच वर्ष के कर अवकाश का प्रबंध करती है। बिजली निर्माण में एक सौ प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी गई थी। रिजर्व बैंक की अनुमति लिये बिना विदेशी तकनीकविदों की सेवाएं लेने के लिए अब भारतीय फर्म/कंपनियां स्वतंत्र हैं बशर्ते उनकी सेवा की शर्त कतिपय विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हों। कुछ शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारियों का अब अपने निवासी कंपनी ग्राहकों को भारत में सीधे विदेशी निवेश के कारण विदेशी निवेशकों को बेय साभांश की राशि के संबंध में वायदा रक्षा बीमा देने की अनुमति दी गई है। खनन और खनिज निष्कासने के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रों के लिए किया गया धारक्षण हटा दिया गया। नई राष्ट्रीय खनिज नीति में खनन गतिविधियों में लगी भारतीय कंपनियों में 50 प्रतिशत तक और गैर-प्राक्ख खानों के संबंध में, अलग-अलग मामलों में उससे अधिक सीमा तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की व्यवस्था है।

13.12 उवारीकरण के बाद की अवधि के दूसरे वर्ष के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग राशियों, ने विशेषतः भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित, कई गुना वृद्धि दर्ज की। समस्त संस्थाओं के ऐसे अनुमोदन जो 1991 में 950 थे, बढ़कर 1992 में 1,520 हो गये। इनमें विदेशी सहयोग अनुमोदनों, जिनमें विदेशी इक्विटी शामिल है, की कुल संख्या का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है : भारतीय रिजर्व बैंक (7.8 बिलियन रुपये की विदेशी इक्विटी के 251), औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस आई ए) (4.2 बिलियन रुपये की विदेशी इक्विटी के 243) और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) (28.9 बिलियन रुपये की विदेशी इक्विटी के 198)। 1993 के दौरान (जून के अंत तक) उपर्युक्त उल्लिखित सभी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोगों की कुल संख्या 673 थी जिसमें से 333 विदेशी सहयोगों में 39.5 बिलियन रुपये के विदेशी निवेश शामिल हैं।

13.13 पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और उनके संरक्षण तथा प्रत्यावर्तन की भी गारंटी देने के लिए भारत सरकार ने बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एम आई जीए) अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। सरकार ने इस मुद्दे पर द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।

13.14 विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं के लिए प्राथमिक और गौण बाजारों में निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत — विदेशी निवेश हेतु बाजार अनुकूल वातावरण के विकास की निरंतर प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विदेशी संस्थागत

निवेशकों द्वारा पेश निवेदन, पारस्परिक मिश्रणों, परिसंमिल प्रबंधन कम्पनियां, निवेश म्याक्स, नामित कंपनियों और निगमित अथवा संस्थागत संविभाग प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं : विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्राथमिक और गौण बाजारों में क्रय-विक्रय की जाने वाली समस्त प्रतिभूतियों का निवेश करने की अनुमति दी गई है। भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध और ओटीसी एक्सचेंज में शामिल होने के लिए परिभाषित कंपनियों की प्रतिभूतियों में किसी भी प्रकार का निवेश करने के पूर्व विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड में शुरू में पंजीयन लेना होगा। चूंकि विदेशी मुद्रा-नियंत्रण प्रभावी है अतः विदेशी संस्थाएं निवेश प्रारंभिक पंजीयन के अपने आवेदन पत्र के साथ फेरा के अधीन विभिन्न अनुमतिपत्र लेने के लिए विशिष्ट फार्मेट में रिजर्व बैंक को संबोधित दूसरा आवेदनपत्र भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज को दें। प्रारंभिक पंजीयन स्वीकृत करने के पहले एक ही स्थान पर संबंधी द्वार भारतीय रिजर्व बैंक से सामान्य अनुमति ली जायेगी। संबंध से प्रारंभिक पंजीयन चाहने वाले विदेशी निवेश संस्थाओं को प्रतिभूति और एक्सचेंज आयोग अथवा अधिवासी/विदेशी निवेश संस्थाओं के निगमन देश के शेयर बाजार के नियामक संगठन से पंजीयन लेना आवश्यक होगा। भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) का प्रारंभिक पंजीयन पांच वर्ष तक के लिए वैध होगा और उसका नवीकरण किया जा सकेगा।

13.15 मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से सामान्य अनुमति लेने के कारण विदेशी निवेश संस्थाएं (क) नामित बैंक में विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्गीय खातों खोल सकेंगे ; (ख) विशेष अनिवासी रुपया खाता खोल सकेंगे जिसमें सब्सक्त प्राप्ति का जमा की जा सकेंगी ; (ग) विदेशी मुद्रा खातों से रुपया खातों में और इसके विपरीत राशियां अंतरित कर सकेंगे ; (घ) रुपया खातों की बकाया राशि भारत में प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे ; (ङ) अंतरण प्रत्यावर्तनीय राशियां (कर के पश्चात्) रुपया खातों से विदेशी मुद्रा खातों में अंतरित कर सकेंगे ; (च) पूंजी, पूंजीगत आय, साभांश, ब्याज आय आदि को प्रत्यावर्तित कर सकेंगे और (छ) फेरा के अधीन और किसी मंजूरी के बिना विदेशी संस्थागत निवेशकों की धारण राशियों को दर्ज करवा सकेंगे।

13.16 मार्गदर्शी सिद्धांत यह भी बताते हैं कि प्राथमिक/गौण बाजारों में विदेशी निवेश संस्थाओं के प्रवेश को प्रयोजन हेतु निवेश की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अनिर्दिष्ट विदेशी निवेश संस्थाओं द्वारा ऐसे निवेशों के लिए निर्धारित समय बंदी भी न होगी। तथापि प्राथमिक या गौण बाजारों में किसी एक कंपनी में विदेशी निवेश संस्थाओं की कुल धारण राशियां जातीय शेयर पूंजी के 24 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन होंगी। किसी भी कंपनी में एकल विदेशी निवेश संस्थाओं की धारण राशि की कुल निर्गमित पूंजी के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन

होगी और इस प्रयोजन के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक समूह की जमा राशियाँ एकल विदेशी निवेश संस्था की धारण-राशियों के रूप में गिनी जायेंगी।

13.17 मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विनिवेश की अनुमति भारत में शेयर बाजारों के लिए दी जाएगी। विदेशी निवेश संस्थाओं के नमस्त गौण बाजार परिचालन भारतीय शेयर बाजारों में मान्यता प्राप्त विश्वालियों के माध्यम से ही किये जायेंगे। एक पूंजीकृत विदेशी निवेश संस्था सेबे द्वारा अनुमोदित एजेंसी को प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने और प्रतिभूतियों के लेन-देनों का पुष्टीकरण करने, ऋण तथा बिक्री का समायोजन एवं सूचना की रिपोर्टिंग के लिए अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

13.18 विदेशी संस्थागत निवेशकों को फिजियल दीर्घावधि (एक वर्ष से अधिक) पूंजीगत लाभों पर 10 प्रतिशत और अल्पावधि पूंजीगत लाभों पर 30 प्रतिशत रियायती कर दर का भुगतान करना पड़ता है। लाभांश और ब्याज से आय पर 20 प्रतिशत की कर दर भी अन्य देशों में प्रचलित वैसी ही कर दर की तुलना में बेहतर है।

13.19 अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों के लिए प्राथमिक पूंजी बाजार में स्टॉक निवेश सुविधा की शुद्धान्तः प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा स्टॉक निवेश सुविधा इससे पूर्व निवासी भारतीयों को ही उपलब्ध कराई गयी थी तथा अब प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की भी अनुमति दी गयी है कि वे कुछ शर्तों के साथ स्टॉक निवेश भारतीय राष्ट्रकृत/मूल-के अभिवासीयों और ऐसे विदेशी कंपनी निकायों को जारी करें जो प्रमुख रूप से ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व-वाली हों। इस प्रकार, अनिवासी भारतीय और विदेशी कंपनी निकाय प्रत्यक्ष रूप से लाभ सहित शेयरों/डिबेंचरों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

13.20 प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशों में निवेश: पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों को नयी विदेशी मुद्रा/विदेशी जमा राशियाँ रखने की अनुमति दी गयी है, जैसे विदेशी मुद्रा अर्जकों की विदेशी मुद्रा (ईईएफसी), निवासी विदेशी मुद्रा खाता (भार.एफ.सी.)। साथ ही उन्हें यह भी अनुमति दी गयी थी कि वह विदेशी मुद्रा में इस प्रकार के खाते रखें और विवेकपूर्ण मानदंडों के भीतर विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करें। फिर भी, उन्हें इस बात की अनुमति नहीं है कि वे निवेश में रखे गये विदेशी मुद्रा खातों की बकाया राशि निवेश में लगायें। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 अगस्त 1993 से प्राधिकृत अधिकारियों को अपने बहियों के सभी विदेशी मुद्रा खातों में धारित निधियों का निवेश करने की अनुमति दी है। यह निवेश खजाना बिलों और

उन विदेशी बैंकों में रखा गया जमा राशियों से किये जा सकते हैं जिन्हें अल्पावधि देयताओं के लिए स्टैंडर्ड द्वारा ए1+ के रूप में और मुद्रा द्वारा वित्तहीन या पी के रूप में श्रेणीकृत है। उन्हें इस बात की भी अनुमति दी गयी है कि वे ईईएफसी और भार.एफ.सी. खातों की विदेशी मुद्रा जमा राशियों निधियों को उनकी बाल्विक विदेशी मुद्रा जमा राशियों को पूरा करने के लिए उधार दे सकते हैं जैसे कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत निधियाँ जुटाने के मामले में होता है। फिर भी, प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे इस प्रकार का जमा राशियों की अवधि समाप्ति और उनके निवेश को ध्यान में रखा जाता है और उसी के साथ-साथ विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों की अवधि समाप्ति का भी ध्यान रखा जायेगा कि अंतर्गतों की गणना करते समय वे शामिल किये जा सकें और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि अंतर्गतों की कुल सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाता। यह भी सुनिश्चित करना है कि वे अपने निवेश इस ढंग से करें जिससे कि जमा देयताएं अवधि समाप्ति/मांग पर उन्हें सुरक्षित पूरा किया जा सके। खजाना बिलों तथा विदेशों में निवेशित जमा राशियों और ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा खातों में अपने कुछ जमा राशियों में से किये गये निवेशों का विवरण आवधिक रूप से प्रेषित करना आवश्यक है।

13.21 विदेशी मुद्रा विनिमय दर के भाव-प्रत्यक्ष भाव प्रणाली में अंतरण: रिजर्व बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी अभी तक विदेशी मुद्रा में अपने बिक्री/क्रय लेन-देनों के लिए अप्रत्यक्ष भाव प्रणाली का प्रयोग करते आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने दिनांक 28 मई 1993 के अपने आदेश एफ.सं. 4 (4) एफईबी-1193 द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के लिए प्रत्यक्ष भाव प्रणाली में अंतरित करने का निर्णय किया है। तत्सुमार, 2 अगस्त 1993 से रिजर्व बैंक अपनी विनिमय दरें प्रति 100 रुपये के लिए अमरीकी डालर के स्थान पर प्रति अमरीकी डालर के लिए रुपये के रूप में व्यक्त करेगा। इसके साथ ही, प्राधिकृत व्यापारियों के अंतर बैंक तथा व्यापारी भाव भी प्रत्यक्ष भाव प्रणाली में परिवर्तित हो जायेंगे।

13.22 किसी अनिवासी धारक को शामिल किये जाने वाले सामान्य अनुमति: प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को सरल बनाने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने भारतीय कंपनियों को अनिवासी होने के परिणामस्वरूप किसी भी प्रतिभूति के धारक के विदेश के पते को अपने रजिस्टर/बही खातों में दर्ज करने की सामान्य अनुमति प्रदान की है, बशर्त धारक प्रतिभूतियों के आय-लाभांश अथवा बिक्री आय के प्रत्यावर्तन की मांग नहीं करेगा।

13.23 अनिवासी भारतीय अब भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना अपने पास रखी प्रतिभूतियों में अनिवासी भारतीय का नाम शामिल कर किसी अन्य अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय निवासी का नाम शामिल करने हुए अपनी शेयर धारिता को संयुक्त धारिता के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उसमें अनिवासी भारतीय का नाम शामिल कर सकते हैं। साथ ही, अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में स्थित अपने निकट संबंधियों को शेयरों के हस्तांतरण किये जाने के लिए कनिष्ठ शर्तों के साथ सामान्य अनुमति प्रदान की गयी है।

13.24 अनिवासी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता खोलने की सुविधा का विस्तार : विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित नीतियों में हाल में लायी गयी रियायतों और देश में विदेशी निवेशों को आकर्षित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों के विदेश में जन्मे पति/पत्नी को उपलब्ध विभिन्न निवेश योजनाओं के तहत भारतीय कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करने के साथ-साथ उन्हें अनिवासी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान की जाए। तदनुसार, भारत के किसी नागरिक या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति (पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रिक न हो) का कोई पति/पत्नी, अब से भारतीय मूल का व्यक्ति समझा जायेगा।

13.25 भारतीय मुद्रा का निर्यात और आयात : यह निर्णय लिया गया है कि भारत में कोई भी निवासी इस समय लागू 250 रुपये के बजाय अधिकतम 1,000 रुपये तक की राशि भारतीय मुद्रा में भारत से बाहर (नेपाल को छोड़कर) ले जा सकता है और भारत में वापस ला सकता है।

13.26(i) भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के अनिवासीयों द्वारा आवास और भूमि-भवन विकास में निवेश : अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की ओर अधिक प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि जो निजी अथवा सार्वजनिक मर्यादित कंपनियां, भूखंडों के विकास और व्यापार, केन्द्रों तथा टाउनशिप के विकास, शहरी बियासगत सुविधाओं, भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन आदि के व्यवसाय में लगी हैं या लगने की इच्छुक हैं, उन्हें भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के अनिवासीयों को प्रत्यावर्तन के लाभों से युक्त नये निर्गम के सी प्रतिशत तक इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किये जाने की अनुमति दी जाये। तथापि, विदेशी निगमित निकाय इस सुविधा के पात्र नहीं हैं।

(ii) अभी तक भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के व्यक्तियों को रिटायर्गेंट संपत्तियों का अभिग्रहण केवल गैर-प्रत्यावर्तन के आधार पर करने की अनुमति थी। अब ऐसे व्यक्तियों को इसकी अनुमति होगी कि वे अधिकतम दो मकानों तक

आवासीय संपत्तियों में सममूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य निवेशों का प्रत्यावर्तन कर सकेंगे बशर्ते ऐसी परिस्थितियां 26 मई, 1993 को अथवा उसके बाद खरीदी गई हों, तथा संपत्तियों का अंतरण अथवा उनका निपटान खरीद की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक बिक्री के माध्यम से न किया गया हो।

(iii) भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों, भले ही वे भारत के निवासी हों, अथवा नहीं, तथा अनिवासी भारतीयों को भारत में वाणिज्यिक अथवा संपत्ति का अभिग्रहण खरीद, बिक्री के माध्यम से तथा बिक्री द्वारा अंतरण या निपटान कर सकने की सामान्य अनुमति प्रदान की गयी है। मूल निवेश को समकक्ष विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तन करने की अनुमति भी कुछ शर्तों पर दी गई है।

(iv) भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों, भले ही वे भारत के निवासी हों, अथवा नहीं, को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 31(1) के अन्तर्गत यह सामान्य अनुमति भी दी गई है कि वे किसी ऐसे संबंधी में या को उपहार के रूप में भारत में स्थित आवासीय संपत्तियों (दो मकानों तक) का अभिग्रहण, अंतरण अथवा निपटान कर सकते हैं जो भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल का हो सकता है, भले ही भारत का निवासी हो या न हों, बशर्ते उपहार कर, यदि कोई हो तो, उसकी अदायगी की जायेगी। उपर्युक्त सुविधाओं में भारत में स्थित कृषि भूमि/फार्म हाउस/वृक्षारोपण संपत्ति का अभिग्रहण शामिल नहीं होगा।

13.27 चांदी का आयात : भारत सरकार ने 8 फरवरी, 1993 को स्वर्ण आयात की तरह ही देश में चांदी के आयात की अनुमति देने से संबंधित योजना को अधिसूचित किया। अनिवासी भारतीयों और विदेश से लौटे भारतीयों (विदेश में छह मास रहने के पश्चात) को प्रति किलोग्राम 500 रुपये का शुल्क, विदेशी मुद्रा में, भुगतान करने पर व्यक्तिगत मामान के रूप में 100 किलोग्राम चांदी लाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

XIV. बैंक के संगठनात्मक मामले

14.1 मुद्रा तिजोरियां : जून 1993 के अन्त में देश में कार्य कर रही मुद्रा तिजोरियों की संख्या 4,016 थी। 30 जून, 1993 को समाप्त एक वर्ष की अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों की मुद्रा तिजोरियों की संख्या में 26 की ओर वृद्धि हुई जो बढ़कर 2,837 हो गयी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की तिजोरियों की संख्या में 24 और मुद्रा तिजोरियां बढ़ जाने से उनकी संख्या 715 हो गयी। खजानों और उप खजानों द्वारा रखी गयी तिजोरियों की संख्या में एक की वृद्धि हुई और वह 436 हो गई। रिजर्व बैंक तथा जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के पास विद्यमान तिजोरियों

की संख्या क्रमशः 17 और 5 पर अपरिवर्तित रही। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि दो निजी क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही निजीकरण स्थापित कर रखी हैं तथा चार और निजी क्षेत्र के स्थापना में वर्ष 1992-93 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों के पास छः मुद्रा निजीकरणों में काम करना आरंभ किया। इन निजीकरणों के साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रखे गये चार सौ बीससे निक्षेपागारों ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया था।

14.2 मुद्रा प्रबंध: नासिक और देवास स्थित मौजूदा नोट मुद्रणालयों में नये नोटों की उपलब्धता में मामूली सा सुधार हुआ। बैंकों को पुनः जारी करने योग्य नोट की अधिकतम संख्या में छंटाई करके और आधिक्य निजीकरणों से नोट प्राप्त करने पड़े। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कम मूल्यवर्ग वाले नोटों के लिए और मिक्के ढालने में वृद्धि, मुद्रणालयों में प्रतिरिक्त क्षमता बढ़ाने और 10 रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग वाले अपेक्षाकृत छोटे आकार वाले नोटों के नये प्रकार की शुरुआत जैसे उपायों के कारण नये नोटों की उपलब्धता में वृद्धि होगी। उत्पादन के प्रथम चरण के रूप में मसूर तथा सल्फोनी में दो नये नोट मुद्रणालय की 2 परियोजनाओं में निर्माण का कार्य समाप्त होने वाला है।

14.3 स्वर्ण प्रबंध प्रभाग: वर्ष 1991 के पूर्वार्ध में विदेशी भुगतानों के संकट के प्रबंधन में स्वर्ण ने जो भूमिका अदा की उसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि बाह्य समायोजन के लिए घरेलू स्वर्ण जुटाना जाय तथा वैध तरीकों से देश में स्वर्ण की उपलब्धता में सुधार लाने से संबंधित नीतियां तैयार की जायें। इसी संदर्भ में सोने और चांदी के आयातों में उवारीकरण तथा बाजार विनियमन जैसे मामलों, देश में सोने को परखने और परिष्कृत करने की सुविधाओं में वृद्धि करने जैसे उपाय करने की आवश्यकता है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में आभूषणों के नियतों का नवीकरण करने के लिए पर्याप्तता करने की आवश्यकता होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वर्ण के महत्व और बाह्य समायोजन में उसके प्रयोग की संभावनाओं को देखते हुए बाह्य निवेश तथा परिचालन विभाग में एक स्वर्ण प्रबंध प्रभाग बनाया गया। यह प्रभाग निम्नलिखित कार्य करेगा:

(1) स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बुलियन बाजारों की गतिविधियों पर संगत आंकड़े एकत्र करके उन पर नजर रखना; (2) भारत में बुलियन बाजार से संबंधित नीतिगत तथा विकास संबंधी मामलों की जांच करना और सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करना; (3) उपयोग में न लाये जाने वाले अनंत के पास रखे स्वर्ण को प्राप्त करने से संबंधित योजनाएं तैयार करना।

14.4 आंतरिक ऋण प्रबंधन कक्ष: चूंकि मौद्रिक नीति को अप्रत्यक्ष तरीके से आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव डालने हुए विकसित हो रहे आर्थिक वातावरण के अनुकूल अपने को ढालना है, इसलिए आंतरिक ऋण प्रबंधन नीतियों

तथा कार्यों को मुद्रा कराना तत्काल आवश्यक हो गया है। इसी आवश्यकता की प्रतिक्रिया स्वरूप, पहली अक्टूबर 1992 में रिजर्व बैंक में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में आंतरिक ऋण प्रबंधन कक्ष का गठन किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: (1) संपूर्ण मौद्रिक नीति के एक अंग के रूप में आंतरिक ऋण प्रबंधन से संबंधित उपयुक्त नीतियां तैयार करना और इसके अनुसरण में खुले बाजार कार्यों, बाजार उधारों, राज्य सरकारों को अर्थोपाय अधिमों और संबद्ध मामलों की तरह आंतरिक ऋण कार्यों की व्यवस्था करना, तथा (2) एक सक्रिय एवं मजबूत सरकारी प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना।

14.5 एक सक्रिय आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति के एक अंग के रूप में 1992-93 में दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी तथा 91 एवं 364 में दिवसीय खजाना बिलों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार ने अपने बाजार उधार के अंग के रूप में संग्रहण जुटाये। जैसा कि खंड I में बताया गया है, सरकारी प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों में गौण बाजार विकसित करने के लिए एक समर्पित संस्था के विकास दिशा में यह तय किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम स्थापित किया जाये।

14.6 बाजार आसूचना कक्ष: सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन में अनियमितताओं के संबंध में जानकारीरामन समिति की पहली रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि बैंक को अपने बाजार आसूचना संगठन को मुद्रा कराना चाहिए ताकि जब भी जरूरी हो आरंभिक कार्रवाई शुरू की जा सके। इन सिफारिशों के अनुसरण में, बैंक में बाजार आसूचना कक्ष स्थापित किया गया है। इस आसूचना कक्ष का काम बाजार गतिविधियों से स्वयं को अवगत कराना है। बाजार आसूचना कक्ष बैंक से संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। यह इकाई बैंकिंग आसूचना के अतिरिक्त होगी जिसका काम बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग देखेगा।

14.7 रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण: जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) तथा अनिवामी (विदेशी) रुपया खाता का सर्वेक्षण जुलाई 1988 से जून 1991 के दौरान पुनः किया गया। यह सर्वेक्षण 453 नमूना शाखाओं के आधार पर हुआ था और अनुमानित आंकड़े तैयार किये गये। उम्मीद है कि इसके परिणाम शीघ्र ही घोषित कर दिये जायेंगे। रिजर्व बैंक ने भी जुलाई 1992 में, 31 मार्च, 1992 का संदर्भ तादीख मानकर, भारत की विदेशी देयताओं एवं परिसंपत्तियों की गणना का काम शुरू किया। इस गणना में भारत सरकार, रिजर्व बैंक के आधिकारिक क्षेत्र तथा प्राइवेट कॉर्पोरेट उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित बैंक और बीमा कंपनियों और आधिकारिक क्षेत्र शामिल हैं।

14.8 कंप्यूटरीकरण की प्रगति : ग्राहक सेवाओं तथा कार्यों और बैंकिंग उद्योग की लाभप्रदता एवं व्यवहार्यता में कंप्यूटरों तथा संचार तकनीक के उपयोग को प्रमुख भूमिका निभानी है। बैंकिंग के कातिपय क्षेत्रों के कंप्यूटरीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की जा चुकी है।

14.9 रिजर्व बैंक के संबंध में, ग्राहक केन्द्रों के निर्गम विभाग में आंतरिक लेखांकन तथा मुद्रा तिजोरी लेखा मांड्यूल का काम कंप्यूटरीकृत हो चुका है। वेतनपत्रक मांड्यूल कंप्यूटरीकरण के बारे में, पहले से ही कंप्यूटरीकृत पांच केन्द्रों के अलावा, अन्य कार्यालयों की इस बारे में स्थिति भिन्न-भिन्न है। विधि विभाग में लगाये गये मिनी कंप्यूटर पर वैध साफ्टवेयर के विकास के लिए मार्गदर्शी परियोजना का काम पूरा कर लिया गया है। आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के नई दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, अहमदाबाद तथा मद्रास क्षेत्रीय कार्यालयों, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तिरुवनन्तपुरम, बंगलूर, हैदराबाद तथा बंबई क्षेत्रीय कार्यालयों, वित्तीय कंपनी विभाग (केन्द्रीय कार्यालय कक्ष), बंबई और प्रेम संपर्क विभाग, बंबई में पर्सनल कंप्यूटर लगाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन को तीन पर्सनल कंप्यूटर दिये गये हैं। वेतनपत्रक तैयार करने के लिए नई दिल्ली के निर्गम विभाग में मिनी कंप्यूटर से दो पर्सनल कंप्यूटरों को जोड़ा जा रहा है। ए एल पी एम (लॉन के साथ) मद्रास, बंबई, नई दिल्ली तथा हैदराबाद कार्यालय में लगाये गये हैं। साफ्टवेयर लगाया गया है और प्रशिक्षण दिया गया है। टेस्ट/विरलेस प्रयोग शुरू कर दिये गये हैं। इस बीच खद्रास में कंप्यूटर प्रणाली कार्य प्रारंभ हो चुका है। ए.एल.पी.एम. (लॉन के साथ) जसा लेखा विभाग, बंगलूर में शीघ्र काम करने लगेगा। बंबई में एस जी एल के कामकाज का कंप्यूटरीकरण काम करने लगा है और केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के श्रृणों के लिए व्याज गणना सहित एम जी एल का कामकाज बंबई, मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद, तथा कानपुर में शुरू हो गया है। 91 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी तथा आंतरिक श्रृण प्रबंधन कक्ष के खुले बाजार कार्यों से संबंधित कामकाज को संसाधित करने के लिए साफ्टवेयर पैकेज विकसित कर लिये गये हैं और वे काम करने लगे हैं। बाह्य निवेश और परिचालन विभाग में कामकाज कक्ष में सेतदेन का काम संसाधित करने के लिए एक साफ्टवेयर पैकेज विकसित किया जा रहा है। आशा है कि 31 मार्च, 1994 तक सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग में वर्तमान सी आई आई इन्मिबेल बुल मेनफ्रेम कंप्यूटर प्रणाली के स्थान पर अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रणाली लगा दी जायेगी।

14.10 बैंक समाशोधन का कंप्यूटरीकरण : बैंकिंग क्षेत्र-समाशोधन एक जटिल कार्य है, इसलिए बैंक ने हाल के वर्षों में इस बात की पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से

ज्यादा काम कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत आय। सभी चार महानगरों में 1989 से एम आई सी आर समाशोधन का काम हो रहा है, बैंक की प्रबंध व्यवस्था में आने वाले सात क्षेत्रों के अन्य समाशोधन गृहों के निपटान कार्य का कंप्यूटरीकरण किया गया है। बड़ीदा तथा पुणे के समाशोधन गृहों का निपटान कार्य भी कंप्यूटर से होने लगा है। इन दोनों की प्रबंध व्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक करता है।

14.11 निर्दिष्ट केन्द्रों के बाहर के चेकों की शीघ्र बसूली के लिए, रिजर्व बैंक ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों को पुनर्रके समाशोधन से जोड़ दिया है। बैंक ने चार और केन्द्रों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद तथा नागपुर को भी इकतरके समाशोधन के लिए चार महानगर केन्द्रों से जोड़ दिया है। क्षेत्रीय प्रिड समाशोधन की धारणा को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रवधारणा के क्षेत्र के बाणिज्यिक महत्व वाले केन्द्रों को इकतरके समाशोधन वाले निकटतम महानगर केन्द्र से जोड़ा जाएगा। कानपुर को नयी दिल्ली तथा तिरुवनन्तपुरम को बंबई और मद्रास से जोड़ा गया है। तमिलनाडु राज्य में, मद्रास से रयारह केन्द्रों को जोड़ा गया है और योजना यह है कि राज्य के भी जिला मुख्यालयों को मद्रास से जोड़ा जाए।

14.12 दूरसंचार नेटवर्क : बैंकनेट, जो बैंकिंग उद्योग के लिए एक समर्पित संचार नेटवर्क है, का विस्तार सात केन्द्रों अर्थात् बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद, बंगलूर तथा नागपुर स्थित 248 पत्तन शहरों को शामिल करने के लिए किया गया है। दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से पुणे और अहमदाबाद को नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति मिलने के पश्चात् बैंक नेट के विस्तार में निश्चय ही तेजी आयेगी। नेटवर्क का प्रयोग अंतर शहर समाशोधन, निधियों के अंतरण आदि से संबंधित अंतरण जबाबी सूचनाओं को भेजने के लिए किया जा रहा है।

14.13 एक ओर जहाँ बैंक नेटवर्क उपयोगी भूमिका अदा कर रहा है, वहीं उसकी कातिपय सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं : (i) नेटवर्क से बाहर 400 बाईट्स आकार से ज्यादा के फी फॉर्मेट देश नहीं भेजे जा सकते, (ii) बहु-विध फाइल अंतरण प्रणाली का अभाव, (iii) साफ्टवेयर विकास प्रक्रिया, नए नमूने तैयार करने के लिए विक्रेता पर निर्भरता तथा (iv) बैंक आउटपुट उपयोगिता का अभाव। बैंकनेट की सीमाओं को दूर करने तथा उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए आरबीआई नेट नामक एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। आशा है कि अगले छह महीने में यह कार्य करना शुरू कर देगा। शुरू में इस नेटवर्क से बैंक के सभी कार्यालय जोड़े जायेंगे और बैंक के कार्यालयों के बीच काफी बड़ी मात्रा में आंकड़े, दस्तावेज आदि के विनिमय की सुविधा होगी। इसमें अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था होगी तथा यह बैंकनेट के साथ-साथ काम करेगा। पहले चरण के रूप में, सूनिक्स आरबीआईनेट, बम्बई तथा मद्रास में लगाया जायेगा।

14.14 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत में तीन और बैंक स्विफ्ट नेटवर्क में शामिल हो गये जिससे भारत में नेटवर्क के चालू उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 41 हो गयी है; बैंक के दुरु और सतत प्रयासों के कारण दूर-संचार विभाग ने स्विफ्ट के उपयोगकर्ता बैंकों को बम्बई और दूर-दराज के केन्द्रों में उनकी महत्वपूर्ण विदेशी शाखाओं को पी एस टी एन और टेलिक्स लाइनों से जोड़ने की अनुमति प्रदान की। रिजर्व बैंक दूर-संचार विभाग के अनुमोदन को शीघ्र लागू किये जाने पर निगरानी रख रहा है ताकि बैंकों के ग्राहकों को बेहतर और शीघ्र ग्राहक सेवा प्रदान करके नेटवर्क का इष्टतम उपयोग किया जा सके। बैंक के अंदर, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग स्विफ्ट का उपयोगकर्ता विभाग है। इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि जमा-लेखा विभाग, बम्बई को इससे जोड़ा जाए ताकि वह स्विफ्ट के जरिए अपने सभी विदेशी मुद्रा संबंधी संदेश भेज सके। ऐसा करने से जमा लेखा विभाग में इस समय विदेशी मुद्रा संदेशों के निपटान की पद्धति में पर्याप्त सुधार होगा।

कार्यालय स्वचालन :

14.15 श्रीनगर कार्यालय को छोड़कर बैंक के सभी कार्यालयों प्रशिक्षण महाविद्यालयों में फैक्स मशीनें लगायी गयी हैं। फैक्स माडेम कार्ड पर्सनल कम्प्यूटरों में राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में (केन्द्रीय कार्यालय और बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय), लोक ऋण कार्यालय, बम्बई तथा सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग में लगाये गये हैं।

14.16 रिजर्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण योजना : जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, रिजर्व बैंक ने आलोच्य वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण आयोजना के प्रयोग का काम शुरू किया है। आंतरिक कार्य-दल ने बाहर के कन्सल्टेंट, मेसर्स ए.एफ. फर्ग्युसन, के मार्गदर्शन में एक प्रारूप योजना का दस्तावेज तैयार किया जिसने कतिपय महत्वपूर्ण दबाव वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण कार्यवाहियों की रूप-रेखा प्रस्तुत की।

14.17 मानव संसाधन विकास के संबंध में विशेषज्ञ समिति : भारतीय रिजर्व बैंक में मानव संसाधन विकास के संबंध में विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष एस.एस. मराठे) ने मानव संसाधन विकास के सभी पहलुओं अर्थात् : (i) अधिकारियों की सीधी भर्ती, (ii) स्थान-नियोजन, (iii) पदोन्नति, (iv) प्रशिक्षण और (v) कार्य निष्पादन के मूल्यांकन आदि को शामिल करते हुए व्यापक सिफारिशों की। शुरुआत के रूप में, बैंक अधिकारियों की सीधी भर्ती से संबंधित सिफारिशों में से एक सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी और आयु-सीमा में छूट और ग्रेड "बी" सीधी भर्ती पदों

के लिए आवेदन करने के इच्छुक स्टाफ सदस्यों के लिए अपेक्षित न्यूनतम सेवा अवधि को समाप्त करने का निर्णय लिया।

14.18 एल.के.झा स्मारक व्याख्यान : डा. जैकब ए. फ्रेंकेल, गवर्नर, बैंक आफ इंडिया ने 30 नवम्बर 1992 को बम्बई में "आर्थिक समायोजन की युक्ति" पर दूसरा एल.के.झा स्मारक व्याख्यान दिया।

14.19 रिजर्व बैंक का इतिहास : 1951—1967 की अवधि के दौरान की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास का समेकन कार्य दिशा निदेशन समिति के मार्गनिर्देशन में चल रहा है।

14.20 विकास अनुसंधान दल : जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, बैंक के व्यावसायिक स्टाफ तथा बैंक से बाहर के शैक्षिक तथा व्यावसायिक विशेषज्ञों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों के लिए एक मंच की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विकास अनुसंधान दल गठित किया गया। अभी तक छह विकास अनुसंधान दल के अध्ययन प्रकाशित किये गये हैं और पांच अध्ययनों पर इस समय काम चल रहा है।

14.21 इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान : आलोच्य वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ने आर्थिक सुधारों के लिए नीति संबंधी विकल्प, पर्यावरण और आर्थिक विकास, विश्व पर्यावरण की सुविधा, नवीन प्रक्रिया और विकास से संबंधित विषयों पर सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया। संस्थान अगस्त 1990 से विकास नीति विषय पर चार बर्षीय पी.एच.डी. कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उसने अगस्त 1992 में अनुसंधानकर्ताओं के तीसरे बैठ को दाखिला दिया।

14.22 प्रशिक्षण : प्रशिक्षण और ज्ञान को अद्यतन बनाना और नयी सूचना को अपनाना देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में तकनीक और विकास ने पहले की अपेक्षा अब अधिक महत्व प्राप्त किया है। इसे समझते हुए, बैंक की प्रशिक्षण संस्थाओं ने वर्ष के दौरान अनेक नये कार्यक्रम शुरू किये जिससे उदीयमान आर्थिक नीतियों और सुधार उपायों की अपेक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है।

14.23 बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई : महाविद्यालय ने 104 कार्यक्रम (हिन्दी में 11 कार्यक्रम-सहित) आयोजित किये जिनमें 2,098, सहभागियों ने लाभ उठाया।

1954 में महाविद्यालय के प्रारंभ से प्रशिक्षित सहायियों की कुल संख्या बढ़कर 45,872 हो गयी।

14.24 वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने सात विभिन्न क्षेत्रों में नये कार्यक्रम प्रारंभ किये, वे हैं: बैंक की लाभप्रदता, उद्यारीकृत विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित नीतियाँ, भुगतान संतुलन का प्रबंध, बैंकों में लागत निर्धारण, कंप्यूटरीकृत परिवेश में निरीक्षण, कंपनी शेयरों/डिबेंचरों के सरकारी निर्गम का प्रबंध और पुनर्वास पैकेज की तैयारी में कार्यचालन एजेंसियों की भूमिका। इन सभी कार्यक्रमों ने संमष्टि तथा व्यक्ति आर्थिक नीतियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा। महाविद्यालय ने वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र की सुस्पष्टता बैंकों में सुरक्षा पहलू एवं बैंकिंग विधि और व्यवहार पर भी सेमिनार की व्यवस्था की।

रिजर्व बैंक स्टाफ, महाविद्यालय, मद्रास

14.25 महाविद्यालय ने वर्ष के दौरान 83 कार्यक्रम का आयोजन किया जिनका 1,855 कर्मचारियों ने लाभ उठाया। 1963 में महाविद्यालय में प्रारंभ से प्रशिक्षित कुल अधिकारियों की संख्या बढ़कर 30,345 हो गयी।

14.26 महाविद्यालय ने कुछ नये कार्यक्रम प्रारंभ किये वे हैं: संकाय सदस्यों के लिए कम्प्यूटर कार्यक्रम और नव पदोन्नत सहायक कोषपालों के लिए कार्यक्रम, लोक ऋण कार्यालय के एस. जी. एल खातों का कम्प्यूटरीकरण और सप्टु ओद्योगिक गृहों के लिए वित्तपोषण।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

14.27 आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय 117 कार्यक्रम (केवल हिन्दी में 21 कार्यक्रम-सहित) क्रम आयोजित किये जिनमें 2,572 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 1969 में महाविद्यालय के प्रारंभ से प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या 43,050 है।

14.28 आलोच्य वर्ष के दौरान, महाविद्यालय ने निम्नलिखित के संबंध में नये कार्यक्रम आयोजित किये: परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन, कृषि नियतों का वित्तपोषण, ग्रामीण वित्तपोषण ग्रामीण ऋण और वृक्षारोपण एवं बागवानी पर कार्यमूलक कार्यक्रमों के साथ विकास संभाव्यता को जोड़ना, तथा मत्स्य उद्योग के विकास के लिए वित्तपोषण, पशु-पालन, कृषिगत क्षेत्र का वित्तपोषण, लघु सिंचाई और वर्षा पर आधारित कृषि। महाविद्यालय ने रेशम उद्योग के विकास के लिए ऋण सहायता बायो-तकनीक परियोजनाओं और स्वयं सहायता दलों के संबंध में बैंक वित्त पर भी सेमिनारों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय कृषि ऋण मंच की ओर से 'लघु परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रबन्ध' पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।

आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

14.29 वर्ष 1992-93 के दौरान बैंक के चार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने श्रेणी III कर्मचारियों के लिए

कुल 113 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें कम्प्यूटर की प्रारंभिक जानकारी पर आयोजित कार्यक्रम शामिल है। वर्ष के दौरान प्रशिक्षित श्रेणी III कर्मचारियों की संख्या 1,939 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 184 थी। अब तक प्रशिक्षण श्रेणी III और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या बढ़कर क्रमशः 41,841 और 3,168 हो गयी है।

वाणिज्यिक बैंकों में प्रशिक्षण

14.30 वर्ष 1986 में प्रारंभ किये गये वाणिज्यिक बैंकों में रिजर्व बैंक के ग्रेड ए, बी तथा सी अधिकारियों की प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 124 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस समय, इस योजना के अंतर्गत 31 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी एक वाणिज्यिक बैंक के साथ छह महीने तक सम्बन्ध रहा।

भारत और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

14.31 बैंक ने वर्ष 1992-93 के दौरान भारत के विभिन्न प्रमुख बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों के लिए कुल 349 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया।

14.32 बैंक ने 38 अधिकारियों को अमेरिका, इंग्लैंड, स्विटजरलैंड, जर्मनी, जापान, थाइलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स, जिम्बावे, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मालदीव आदि 14 देशों की बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण/अध्ययन के लिए भी प्रतिनियुक्त किया था।

14.33 चार और अधिकारियों के विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए चुने जाने में, स्वर्ण जयंती स्कीम के अंतर्गत लाभ उठाने वाले अधिकारियों की संख्या 1985 में स्कीम लागू होने से लेकर अब तक बढ़कर 28 हो गई है। उक्त स्कीम विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए बैंक के अधिकारियों को छांदवृत्ति प्रदान करने के लिए शुरू की गई।

विदेशी बैंकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण मुविद्यान

14.34 वर्ष 1992-93 के दौरान कुल मिलाकर सात विभिन्न देशों के 95 अधिकारियों ने बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण अध्ययन सुविधाओं का लाभ उठाया। इनमें से 36 श्रीलंका से, 7 कोरिया से, 12 युगांडा से, 7 तंजानिया से, 6 नेपाल से, 8 थाईलैंड से, 8 अफगानिस्तान से, 1 जापान से, 11 उजबेकिस्तान से और 3 मारीशस से थे। वर्ष 1981 में अब तक विदेशी केन्द्रीय वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षण किए गए अधिकारियों की कुल संख्या 908 थी।

पी.एच.डी. के लिए प्रायोजित स्कीम

14.35 आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग से अधिकारियों को एम.पिल. पीएचडी. कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित करने की स्कीम के अंतर्गत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पीएचडी. कार्यक्रम के लिए बम्बई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में तीन अधिकारियों को और पीएचडी. कार्यक्रम के लिए ही इंडिया गांधी विकास अनुसंधान संस्थान बम्बई में दो अधिकारियों को प्रायोजित किया गया।

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण

14.36 आलोच्य वर्ष के दौरान कम्प्यूटर के क्षेत्र में अर्हता प्राप्त करने के लिए बैंक की प्रोत्साहन स्कीम जारी रही। 1987 में स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक देश में विभिन्न संस्थाओं में 128 अधिकारियों तथा 537 लिपिकीय स्टाफ ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया है।

व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम

14.37 भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान, हैदराबाद द्वारा संचालित सनदी वित्तीय विश्लेषक कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की स्कीम जारी है। अब तक इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए 171 कर्मचारियों को अनुमति दी गई है।

नियोक्ता कर्मचारी संबंध

14.38 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक में औद्योगिक वातावरण अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा।

14.39 गत वर्ष की रिपोर्ट में ब्राल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फीडबैक और बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक संयुक्त अध्ययन दल के गठन करने का उल्लेख किया गया था। जिसका कार्य मूल संवर्ग में भर्ती करने और आंशिक कर्मचारियों आदि को नियमित करने के प्रश्न पर विचार करना था। दल ने नवम्बर 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा दल द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशों को बैंक ने सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। इस बीच बैंक ने इस संबंध में ब्राल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फीडबैक के साथ समझौता कर लिया है और इस समझौते को प्रमेल में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

14.40 अधिकारियों के स्थानान्तरण से संबंधित अपनी मौजूदा नीति की समीक्षा करने और नये मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के उद्देश्य से बैंक ने अपने केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक श्री एम.एस. पटवर्धन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

स्टाफ कल्याण

14.41 भारतीय रिजर्व बैंक जिसका सहायता निधि स्कीम के अंतर्गत जो लाभ अब तक केवल सदस्यों के

जीवित रहते तक उसके पति/पत्नी को दिए जाते थे अब 1 जनवरी, 1993 से सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसके पति/पत्नी को दिए जाते रहेंगे। 1 जनवरी 1993 में मुख्य प्रबंधक की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनायी गयी है जिसमें चार माध्यताप्राप्त अधिकारियों और कामगार कर्मचारियों की एसोमिएशनों में से एक-एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। समिति इस स्कीम में सुधार लाने के उपायों के बारे में सुझाव देगी।

14.42 वर्ष के दौरान बैंक ने यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी, 1986 से पूर्व बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों की विधवाओं/विधुरों/पात्र बच्चों को 150 रुपए प्रति माह के हिसाब से अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए। इस अनुग्रह राशि पर मंहगाई राहत भी उसी दर से दी जाएगी जो परिवार पेंशन के लिए अनुमत है। यह अनुग्रह राशि 1 जनवरी, 1986 से ही देय है।

प्रारक्षित श्रेणियों को रोजगार : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

14.43 वर्ष 1992 के दौरान बैंक की भर्ती के समय विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निम्नलिखित प्रतिनिधित्व दिया गया :

श्रेणी	भर्ती किए गए कुल उम्मीदवारों की संख्या	जिनमें से				प्रतिशत
		अनु. जाति	अनु. जन जाति	अनु. जाति	अनु. जन जाति	
1	2	3	4	5	6	
श्रेणी I	18	3	1	16.7	5.6	
श्रेणी III	95	36	8	27.4	8.4	
श्रेणी IV	116	50	13	43.1	11.2	
इनमें से :						
(क) सफाई कर्मचारी	24	21	1	87.5	4.2	
(ख) अन्य	92	29	12	31.5	13.0	

14.44 इससे बैंक में 31 दिसम्बर, 1992 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या श्रेणी I में बढ़कर क्रमशः कुल 563 और 124 हो गई। तथापि सेवानिवृत्ति त्यागपत्र आदि के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या में मामूली सी कमी होकर श्रेणी III में यह संख्या क्रमशः 2,417 और 1,177 तथा श्रेणी IV में क्रमशः 2,467 और 707 रही। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सम्पर्क अधिकारी

ने बैंक के भोपाल शाखा तथा कोचि हैदराबाद जयपुर जम्मू नागपुर नई दिल्ली और निरुवन्तपुरम कार्यालयों में रखे गए आरक्षण रोस्टर्स का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान प्रबन्ध तंत्र और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और बौद्ध कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के बीच तीन बार बातचीत हुई जिसमें बैंक में आरक्षण नीति को लागू करने से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई।

भूतपूर्व सैनिक

14.45 कैलेंडर वर्ष 1992 के दौरान श्रेणी III के लिए 14.5 प्रतिशत और श्रेणी 4 के लिए 24.5 प्रतिशत की आरक्षण संबंधी निर्धारित दरों की तुलना में श्रेणी III में चार और श्रेणी 4 में 14 रिक्त पदों को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरा जा सका जबकि इन पदों की अपेक्षित संख्या क्रमशः 14 और 28 थी। तथापि सेवानिवृत्ति त्यागपत्र आदि के कारण पिछले कैलेंडर वर्ष की तुलना में 1992 के अंत में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या में मामूली-सी कमी होकर श्रेणी III में यह 734 और श्रेणी IV में 1,001 रही।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

14.46 कैलेंडर वर्ष 1992 के दौरान श्रेणी III में दो और श्रेणी IV में छह शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती की गई जिसमें भर्ती किए गए शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर 431 हो गई।

हिन्दी का संवर्धन

14.47 राजभाषा के सांविधिक उपबंधों के अन्तर्गत अपने सामान्य कार्य करने के अलावा बैंक ने राजभाषा के महत्व के बारे में विभिन्न नये नये उपायों के जरिये स्टाफ में जागरूकता को बढ़ाया। इस संबंध में किए गए उपाय हैं : विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन मूल पत्राचार को बढ़ावा देना बैंक के परिमार्गों में महत्वपूर्ण स्थानों पर हिन्दी शब्दों और वाक्यों को प्रदर्शित करना और हिन्दी से अंग्रेजी के सामान्य अनुवाद में कमी लाना।

14.48 बैंक के कर्मचारियों के लिए बैंकिंग विषयों पर मूलरूप से हिन्दी में पुस्तक लिखने की एक योजना आरम्भ की गई है जिसका बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों भी लाभ उठा सकते हैं।

14.49 सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बैंक दोनों ही में राजभाषा के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए बेहतर कार्य के लिए पुरस्कार देने की परम्परा को बनाये रखते हुए क्रमशः अगस्त 1992 और अक्तूबर 1992 में दो राजभाषा शील्ड पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किये गये। गृह पत्रिका पुरस्कार वितरण से संबंधित एक समारोह भी आयोजित किया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को गृह पत्रिका का यह पुरस्कार हिन्दी में उत्कृष्ट सामग्री और उत्कृष्ट साज सजा आदि के लिये

दिया जाता है। जहां तक अंग्रेजी टंककों की हिन्दी टंकण प्रशिक्षण देने का संबंध है बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में 14 से 30 की वृद्धि कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक का प्रयास जारी है कि बैंकिंग कार्य के कम्प्यूटरीकरण में हिन्दी माफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है।

14.50 इसके अतिरिक्त बैंक की वार्षिक रिपोर्ट भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट गृहरी बैंक विभाग द्वारा प्रकाशित परिपत्रों का सार और महत्वपूर्ण समितियों की अनेक रिपोर्टों आदि के हिन्दी पाठ प्रकाशित करने के लिए उनका हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया गया।

14.51 बैंक ने बैंकिंग परिभाषा 'कोश' जो बैंकिंग शब्दों और वाक्यों का एकक व्याख्यात्मक कोश है की पाण्डुलिपि को अंतिम रूप दे दिया है और इसे शीघ्र प्रकाशित किया जायेगा।

14.52 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' मनाया गया। इस दिन संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस अवसर पर केन्द्रीय कार्यालय के विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गये।

कार्यालय भवन और रिहाइशी आवास

14.53 वर्ष 1992-93 के दौरान कार्यालय भवनों आवासीय क्वार्टरों के निर्माण बैंक सम्पत्ति में संवर्धन परिवर्तन करने पर पूंजी लेख में 17.26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। जहां तक रिहाइशी आवास का संबंध है, आसन, ग्रहमदाबाद में अधिकारियों के 102 फ्लैट्स नेपीयन सी रोड बम्बई में अधिकारियों के 28 फ्लैट्स और मानवीदनगर जयपुर में 132 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा होनेवाला है। जम्मू में एक कार्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। मासब टैंक हैदराबाद में बैंक प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कलकत्ता में मिक्का नोट वाल्ट का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है और एक और वाण्ट हैदराबाद में शुरू करने की योजना है। बम्बई में अधिकारियों के लिए 42 फ्लैट्स और निरुवन्तपुरम में श्रेणी III और IV कर्मचारियों के लिए 120 क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है। अधिकारियों के लिए 80 तथा बेलापुर नई बंबई में हाल ही में श्रेणी III और IV स्टाफ के लिए 360 फ्लैटों के निर्माण का ठेका दिया गया है। त्रिकूटनगर जम्मू कनिष्क रोड बंगलूर में अधिकारियों के लिए आवासीय फ्लैट्स तथा चारकोप कांदिवली बम्बई में स्टाफ क्वार्टर निर्माण करने की योजना तैयार की जा रही है।

14.54 आवासीय क्वार्टरों के मामले में अधिकारियों और श्रेणी III और IV कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गए क्रमशः 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत संतोषजनक मानव

की तुलना में बैंक ने अधिकांश केंद्रों पर अधिकारियों के आवासीय क्वार्टरों के मामले में ये मानदण्ड लगभग प्राप्त कर लिये हैं। 21 केंद्रों में से श्रेणी III स्टाफ के लिए 14 केंद्रों पर तथा श्रेणी IV के लिए 12 केंद्रों ने अपेक्षित संतोषजनक स्तर प्राप्त कर लिया गया है।

14.55 आवास ऋण : बैंक ने 20 जुलाई 1992 से श्रेणी I के कर्मचारियों द्वारा मकान/प्लैट प्राप्त करने/निर्माण करने के लिए आवास-ऋण तथा भविष्य निधि अधिम/आहरण दोनों को मिलाकर होनेवाली उच्चतम राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है तथा इसी प्रकार श्रेणी III/IV के कर्मचारियों के लिए यह राशि 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी है। इसके साथ ही, संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी अपने विधेकाधिकार से कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत तक और ऋण मंजूर कर सकता है।

14.56 यह भी निर्णय लिया गया है कि अभिदाता 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अपने भविष्य निधि से आहरण कर सकता है (विद्यमान 15 वर्ष की सेवा के बजाए), लेकिन यह अनुमति केवल नया मकान अथवा नया प्लैट प्राप्त करने के लिए ही होगी।

14.57 केन्द्रीय बोर्ड समिति ने एक—“आंतरिक दल” गठित करने का निदेश दिया है जो स्कीम के विद्यमान मौद्रिक मानदण्डों में बिना कोई उदारीकरण किए मौजूदा आवास ऋण नियमावली को मरल बनाने का प्रयास करेगा ताकि इसके ढाँचे को सक्षिप्त बनाया जा सके और अन्य बैंकों की तुलना में रिजर्व बैंक में प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का अध्ययन किया जा सके और ऐसे उपाय सुझा सके जिससे आवास ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी प्रोत्साहित हों।

14.58 वर्ष 1992-93 (जुलाई-जून) के दौरान बैंक ने कर्मचारियों को आवास ऋण (भूमितियों/व्यक्तियों) को कुल 9.98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जिसका व्योग नीचे दिया गया है :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	ऋण की राशि (रुपये)
1	2	3
क. सहकारी आवास समितियाँ	18**	60**
(1) नये ऋण	—	—
(2) प्रतिरिक्त ऋण	18**	60**
ख. केन्द्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण	—	181**
(1) नये ऋण	—	105**
(2) प्रतिरिक्त ऋण	—	76**

1	2	3	4
ग. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण	—	840*	7,91,34,565*
(1) नये ऋण	—	544*	6,71,20,145*
(2) प्रतिरिक्त ऋण	—	296*	1,20,14,420*
कुल ख+ग का जोड़	18	1081	9,98,90,085

टिप्पणी : आंकड़े अनुमानित हैं।

*बंगलूर, कलकत्ता (बेकिंग), कलकत्ता (निर्गम), नयी दिल्ली, हैदराबाद और जम्मू कार्यालयों के संबंध में 31 मार्च 1993 तक स्वीकृत आवास ऋण।

**1 जुलाई, 1992 से 30 जून 1993, तक के आंकड़े।

14.59 केन्द्रीय बोर्ड : बैंक के गवर्नर, श्री एस. वेकिटरमणन ने 21 दिसंबर, 1992 को कारबार की समाप्ति पर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया। उनके स्थान पर योजना आयोग के सदस्य, डॉ. सी. रंगराजन को गवर्नर के रूप में 22 दिसंबर, 1992 में तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया।

14.60 श्री डी. आर. मेहता, महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार को 11 नवंबर, 1992 में 30 जून, 1995 तक की अवधि के लिये बैंक में उप-गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।

14.61 स्थानीय बोर्ड : बैंक मुखेद सूचित करता है कि श्री आर. एम. गुप्त को 6 जनवरी, 1993 को निधन हो गया। वे 25 अगस्त, 1984 में मृत्यु पर्यंत उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य थे। बोर्ड उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःखद घड़ी में अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करता है।

14.62 वर्ष के दौरान किसी स्थानीय बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

14.63 कार्यपालकों की नियुक्ति : सर्वश्री ए. पी. अय्यर और पी. बी. कुलकर्णी को 14 सितंबर 1992 में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

14.64 केन्द्रीय बोर्ड की निरीक्षण और लेखा-परीक्षा-उप समिति : आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण कार्य को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने और कार्यों में अधिकतम उत्पादकता तथा कुशलता के उद्देश्यों की दिशा में एक नया रूप देने की दृष्टि से नवंबर 1992 में केन्द्रीय बोर्ड की निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा उप-समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक श्री एम. एस. मंगटे हैं।

14.65 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के संबंध में केन्द्रीय बोर्ड की उप-समिति : वित्तीय पर्यवेक्षण के प्रस्तावित बोर्ड का संगठनात्मक और संरचनात्मक आधार तैयार करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक श्री ए. एस. मंगटे की अध्यक्षता

में मार्च 1993 में केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति बनायी गयी। उप समिति ने 13 मई 1993 को बोर्ड के संमेलन अर्पणी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आशा है कि वित्तीय पर्यवेक्षण और कार्य करना अधिक करेगा।

XV. बैंक का वर्ष 1992-93 का लेखा (जुलाई-जून)

1. आय

15.1 30 जून 1993 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान बैंक की आय विभिन्न प्रावधानों के लिए किये गये समायोजनों के पश्चात् पिछले वर्ष की 5,699.56 करोड़ रुपये की आय की तुलना में 5,632.12 करोड़ रुपये रही अर्थात् इस आय में 67.44 करोड़ रुपये (अर्थात् 1.18 प्रतिशत) की कुछ ही कमी आयी। आय के स्रोत नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये)

वर्ग	30 जून 1993 की समाप्त वर्ष	30 जून 1992 की समाप्त वर्ष
(1)	(2)	(3)
(क) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकारों आदि को दिये गये ऋणों और सविमों पर व्याज (विदेशी प्रतिभूतियों, जमा राशियों आदि पर व्याज सहित)	4,588.69	4,527.84
(ख) विदेशी खजाना बिलों पर बट्टा	993.11	819.83
(ग) ऋण प्रेषणों, खरीदे गये तार अंतरणों आदि पर विविध प्रसार विदेशी सेनदेनी सहित)	0.94	307.81

1	2	3
(घ) लोक ऋण के प्रबंधन कमीशन तथा अन्य विविध आय	49.38	44.16
कुल आय	5,632.12	5,699.56

15.2 व्याज में होने वाली आय पर 1992-93 के दौरान 60.85 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। उपाजित डिस्काउंट में 173.48 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रमुखतः रुपया खजाना बिलों पर होने वाली डिस्काउंट आय में हुई वृद्धि के कारण हुई।

2. व्यय

15.3 1991-92 (जुलाई-जून) के दौरान कुल 4,199.56 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था जिसमें 1992-93 (जुलाई-जून) के दौरान 71.44 करोड़ रुपये की मामूली कमी हुई और यह व्यय 4,128.12 करोड़ रुपये पर रहा। इस कमी के पीछे प्रमुख कारण था अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजनों के लिए उनके अतिरिक्त शेषों पर अदा किये जाने वाले व्याज में कमी। व्याज भुगतानों की 3,057.77 करोड़ रुपये की राशि में से अनुसूचित बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजनों के लिए रिजर्व बैंक के पास रखी गयी उनके पास अतिरिक्त शेषों की राशियों (अर्थात् 3 प्रतिशत के सांविधिक अनुपात के अंदर) पर वर्ष के दौरान उक्त बैंकों को किये गये व्याज भुगतानों की राशि ही अर्थात् 2,339.96 करोड़ रुपये की जो कुल व्यय का 56.88 प्रतिशत थी (सारणी 15.1)।

सारणी 15.1: भारतीय रिजर्व बैंक आय और व्यय 1982-83 से 1992-93

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कुल आय (मूल)	1343.61	1645.13	1886.28	2209.67	2896.85	3541.23	4030.25	4426.73	4624.97	5699.56	5632.12
2.	निम्नलिखित में वित्तियोग:											
	क) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण	315.00	315.00	350.00	400.00	430.00	450.00	450.00	450.00	525.00	—	1.00
	(दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि)	225.00	275.00	300.00	350.00	300.00	330.00	330.00	375.00	400.00	—	1.00
	ख) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण											
	(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि											
	ग) राष्ट्रीय रासायन ऋण											
	(स्विकारण निधि)	75.00	80.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	—	1.00
	घ) राष्ट्रीय आवास ऋण	—	—	—	—	—	50.00	25.00	50.00	50.00	—	1.00
	(दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि)											
3.	जोड़ (क+ख+ग+घ)	615.00	670.00	675.00	760.00	740.00	840.00	815.00	960.00	995.00	—	4.00
4.	निवृत्त आय (1-3)	728.61	975.13	1211.28	1449.67	2156.85	2701.23	3215.25	3466.73	3629.97	5699.56	5627.12
5.	व्यय											
	इ) अनुसूचित कमिश्न बैंकों को आय व्यय	303.19	503.28	625.00	810.00	1042.99	1521.59	1829.82	2137.33	2431.02	2683.68	2339.96
	ख) एजेंसी प्रसार	82.28	93.93	132.85	150.01	163.64	173.88	259.46	261.25	265.62	302.34	386.68
	ग) प्रतिपूर्ति मुद्रण	35.94	43.42	58.28	100.08	173.05	206.81	187.02	143.71	162.27	238.30	295.65
	घ) विस्तारित निधि !											
	मुद्रा पर व्यय	—	—	—	—	368.00	357.00	445.18	398.89	62.00	540.42	616.75
	इ) अन्य व्यय	97.20	124.50	185.15	179.58	199.13	231.81	283.64	325.43	359.03	434.82	489.05
6.	कुल व्यय	518.61	765.13	1001.23	1239.67	1946.81	2491.12	3005.12	3256.61	3279.97	4199.56	4128.12
	(क+ख+ग+घ+इ)											
7.	सकार को अर्जित राशि (4-6)	210.00	210.00	210.00	210.00	210.04	210.11	210.13	210.12	350.00	1500.00	1500.00

*इसमें स्थापना व्यय, निधियों पर भाज और अन्य आय शामिल हैं।

15.4 स्थापना पर आने वाले लागत-व्यय में 25.79 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और यह व्यय कुल 303.08 करोड़ रुपये रहा जो कुल व्यय का 7.34 प्रतिशत था। यह वृद्धि प्रमुखतः सभी श्रेणियों के स्टाफ की महंगाई भत्तों में दी जाने वाली आवधिक वृद्धियों तथा वेतन के समय-मानों में वार्षिक वेतन-वृद्धियों के कारण हुई।

15.5 प्रतिभूति मुद्रण प्रासंगिक लागतों पर कुल व्यय का 7.16 प्रतिशत अर्थात् 295.65 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। यह राशि पिछले वर्ष हुए व्यय से 57.35 करोड़ रुपये अधिक थी। यह वृद्धि नोटों और चेकों के मुद्रण पर लिये जाने वाले प्रचारों तथा नोटों की अलग-अलग आपूर्ति संबंधित प्रचारों की दरों में सामान्यतः होने वाली वृद्धि के कारण हुई।

15.6 एजेंसी द्वारा किये जाने वाले सरकारी लेनदेनों में हुए उच्चतर कारबार के फलस्वरूप एजेंसी प्रभार 83.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 386.68 करोड़ रुपये हो गया जो कुल व्यय का 9.37 प्रतिशत था।

15.7 पिछले वर्ष के लेखाओं से संबद्ध लेखा एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की टिप्पणियों में "सेवानिवृत्ति लाभ" के अंतर्गत 1(ज) के सामने यह कहा गया था कि कर्मचारियों के लिए निर्धारित पेंशन योजना के लिए बीमा संबंधी मूल्यांकन के आंकड़े अभी प्राप्त होने बाकी हैं। बीमा संबंधी मूल्यांकन के आधार पर 31 मार्च 1992 के दिन पेंशन निधि के संबंध में जो देनदारी बरती थी, उतनी राशि 1992-93 के दौरान उक्त निधि में पूर्णतः डाल दी गयी है।

15.8 रिजर्व बैंक के लाभ की राशि के अधिशेष को भारत सरकार को अंतरित किये जाने से पूर्व इस लाभ में से एक बड़ी राशि का विनियोग विभिन्न सांविधिक निधियों में किये जाने की प्रथा थी ताकि इस विनियोग राशि का उपयोग कृषि विकास और औद्योगिक एवं आवास वित्त संस्थाओं को ऋण और अग्रिम दिये जाने में किया जा सके पिछले वर्ष के दौरान यह नीति निर्णय लिया गया कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में उपर्युक्त निर्णय को लागू करते हुए आवश्यक संशोधन किये जाने तक, वर्ष 1992-93 के लाभ की राशि में से चारों सांविधिक निधियों में एक-एक करोड़ रुपये अंशदान किया गया है तथा 1992-93 (जुलाई—जून) की 1500 करोड़ रुपये के अधिशेष की राशि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को उसी प्रकार अंतरित कर दी गयी जैसे पिछले वर्ष 1991-92 के अधिशेष में से की गयी थी। (सारणी 15.1)।

3. तुलन पत्र

जमाराशियां—बैंक

15.9 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की रिजर्व बैंक के पास जमाराशियों में पिछले वर्ष के कुल 43,448.11 करोड़ रुपये में 2,176.25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और ये जमाराशियां बढ़कर कुल 45,624.36 करोड़ रुपये हो गयीं

जबकि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों, अन्य अनुसूचित सहकारी बैंकों, गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों की कुल जमाराशियों में पिछले वर्ष के 448.37 करोड़ रुपये में 138.53 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और ये जमाराशियां बढ़कर 1992-93 (जुलाई—जून) के दौरान कुल 586.90 करोड़ रुपये हो गयीं।

जमाराशियां—अन्य

15.10 अन्य जमाराशियों के अंतर्गत पिछले वर्ष का 7,690.07 करोड़ रुपये का स्तर बढ़कर 12,738.93 करोड़ रुपये हो गया और इस प्रकार इसमें 5,048.86 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई इस वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि खाता संख्या 1 के शेष में 4,360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का होना था।

विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां

15.11 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में शामिल हैं निर्गम विभाग की विदेशी प्रतिभूतियां विदेशों में रखे हुए शेष तथा बैंकिंग विभाग के 'निवेशों' का एक अंश। ये परिसम्पत्तियां 30 जून, 1992 के दिन 16,124.93 करोड़ रुपये की थीं जो 4,358.44 करोड़ रुपये बढ़कर 30 जून 1993 के दिन 20,483.37 करोड़ रुपये हो गयीं।

भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां और निवेश

15.12 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में निवेश की राशि 30 जून, 1992 के दिन 94,028.76 करोड़ रुपये थी जिसमें वर्ष के दौरान भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में हुए निवेशों में वृद्धि के कारण 17,258.96 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और यह राशि बढ़कर 1,11,287.72 करोड़ रुपये हो गयी।

ऋण और अग्रिम

15.13 अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण में प्रमुखतः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निर्यात पुनर्वित्त के अंतर्गत बकाया राशियों में कमी होने के कारण भारी गिरावट आयी, यह ऋण राशि जून 1992 के अंत में 12,583.54 करोड़ रुपये थी जिसमें 5,860.77 करोड़ रुपये की भारी गिरावट आयी और यह घटकर जून 1993 के अंत में 6,722.77 करोड़ रु० रह गई।

अन्य परिसम्पत्तियां

15.14 अन्य परिसम्पत्तियां 30 जून 1992 के दिन 4,338.18 करोड़ रु० थीं जिनमें 380.01 करोड़ रु० की वृद्धि हुई और ये बढ़कर 4,728.19 करोड़ रु० हो गयीं। यह वृद्धि प्रमुखतः बैंकिंग विभाग की स्वर्ण धारिता (1,651.29 करोड़ रुपये) के कारण हुई थी।

विदेशी मुद्रा जमाराशि योजनाओं के लिए विनियम जोखिम

15.15 30 जून, 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवार्य खाता आहरणों/नवीकरणों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,569.57 करोड़ रुपये की हानि उठाई

जबकि 30 जून, 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान यह हानि 5,531 91 करोड़ रुपये की थी। इसका कारण 1992-93 में अपेक्षाकृत कम मात्रा में रुपये का बाहर जाना तथा रुपये के मूल्य-ह्रास का अपेक्षाकृत अल्प प्रभाव था। भारत सरकार 1 जनवरी, 1993 से रुपये के वार्षिक बहिर्गमन पर विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों में संबंधित विनिमय जोखिम की देयताओं को लेने के लिए सहमत हुई। ऐसी देयताओं को लेने का कार्य सुकर बनाने के लिए मौजूदा प्रावधानों में से अनिश्चित लाभों और निधियों को भारत सरकार को अंतरित करने का बैंक प्रयास करेगा।

लेखा-परीक्षक

15.16 बैंक के लेखाओं की लेखा-परीक्षा में मै. ब्रह्मय्या एण्ड कं., मद्रास, मै. एन.एम. रायजी एंड कं., बंबई, मै. गोयल गर्ग एण्ड कं., नयी दिल्ली, मै. जे.एन. शर्मा एण्ड कं., कानपुर, मै. एम. आनंदम एण्ड कं., हैदराबाद और मै. मित्रा कृंडु एण्ड बसु, कलकत्ता द्वारा की गयी है। जहाँ पहले चार लेखा परीक्षकों को 1992-93 को लिए पुनः नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गयी, अन्य दो लेखा परीक्षक नये नियुक्त किये गये हैं। छः क्षेत्रों में विभाजित बैंक के सभी कार्यालयों को सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा किये जाने के लिए आवंटित किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून, 1993 की स्थिति का तुलन-पत्र

निर्गम विभाग

(हजार रुपये में)

देयताएं	1992-93 रु.	1991-92 रु.	परिमर्पितियां	1992-93 रु.	1991-92 रु.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट			सोने का सिक्का और मुद्रियतः		
गंचखन में नोट	5,53,91	13,45,21	(क) भारत में रखा हुआ	9743,19,77	7275,91,94
जागे किये गये कुल नोट	75078,23,23	64550,25,75	(ख) भारत से बाहर रखा हुआ	557,91,84	467,50,24
	75083,77,14	64563,70,96	विदेशी प्रतिभूतियां जोड़	200,00,00	200,00,00
			रुपया सिक्के	10501,11,61	7943,42,18
			भारत सरकार को हाया प्रतिभूतियां	117,32,34	96,01,23
			देशी विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र	61465,33,19	56524,27,55
कुल देयताएं	75083,77,14	64563,70,96	कुल परिमर्पितियां	75083,77,14	64563,70,96

बैंकिंग विभाग

देयताएं	1992-93 रु.	1991-92 रु.	परिमर्पितियां	1992-93 रु.	1991-92 रु.
प्रदत्त पुरा	5,00,00	5,00,00	नोट	5,53,91	13,45,21
प्राप्तित निधि	6500,00,00	6500,00,00	रुपया सिक्के	7,73	7,57
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	5676,00,00	5675,00,00	छोटे सिक्के	5,98	11,01
राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	176,00,00	175,00,00	खरीदेनया भुनाये गये बिलः		
जमाराशियां			(क) आंतरिक	--	--
(क) सरकार			(ख) बाहरी	--	--
(1) केन्द्र सरकार	53,02,33	47,30,04	(ग) सरकारी खजाना बिल	2460,14,37	1827,77,16
(2) राज्य सरकारें	92,02,98	39,16,17	विदेशों में रखे गये शेयर	16600,14,57	14690,06,84

(ख) बैंक			निवेश	50505,60,84	38739,34,93
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	45624,35,95	43448,10,84	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा ऋणमः		
(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	280,09,18	250,01,04	(1) केन्द्र सरकार	---	---
(3) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	237,99,66	135,16,23	(3) राज्य सरकारें	74,35,00	170,73,00
(4) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	9,84,95	10,55,21	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा ऋणमः		
(5) अन्य बैंक	56,96,13	52,65,07	(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3110,31,27	7471,98,19
(ग) अन्य	12738,92,66	7690,07,35	(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,36,20	12,68,58
देय बिल	18,46,28	126,06,92	(3) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	23,47,00	---
अन्य देयताएं	15264,92,20	13857,74,23	(4) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	---	---
			(5) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3225,16,12	3582,27,17
			(6) अन्य	355,46,81	1516,59,75
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन)		
			निधि से ऋण, ऋणम तथा निवेश :		
			(क) निम्नलिखित को दिए गये ऋण तथा ऋणमः		
			(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3421,74,03	3576,55,41
			(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	877,00,00	877,00,00
			(3) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	170,00,00	170,00,00
			(4) अन्य	995,00,00	840,00,00
			(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश :		
			(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	---	---
			(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	---	---
			(3) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	---	---
			(4) अन्य	---	---
			राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन)		
			निधि से ऋण, ऋणम तथा निवेश :		
			(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण	175,00,00	175,00,00
			(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बांडों/डिबेंचरों में निवेश	---	---
			अन्य परिसंपत्तियां	4728,18,51	4348,18,26
कुल देयताएं	86735,62,34	78011,83,10	कुल परिसंपत्तियां	86735,62,34	78011,83,10

लेखा संबंधी नोट और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां संलग्नक के अनुसार हैं।

(हज़ार रुपये में)

30 जून 1993 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

	1992-93	1991-92
	रु.	रु.
आय	5632,12,13	5699,56,44
व्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन आदि	5632,12,13	5699,56,44
जोड़	5632,12,13	5699,56,44
व्याज		
व्यय	3057,76,54	3311,47,46
स्थापना व्यय	303,08,13	277,29,02

निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय	10,48	8,26
स्वजाना प्रेषण	18,61,93	5,59,14
एजेन्सी प्रभार	386,68,50	302,34,10
प्रतिभूति छपाई (बैंक, नोट फार्म आदि)	295,64,84	238,29,63
मुद्रण और लेखन-सामग्री	2,84,96	3,00,97
झाक और तार खर्च	5,64,97	5,31,53
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	17,35,92	15,83,94
लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय	11,67	8,32
विविध प्रभार	31,02	45,89
बैंक संपत्ति का मुल्यांकन और उसकी मरम्मत	20,41,25	20,47,81
विविध व्यय	19,51,92	19,30,37
	4128,12,13	4199,56,44
	1504,00,00	1500,00,00

उपलब्ध शेष राशि

घटाइये : निम्नलिखित में अंशदान :	1,00,00	---
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	1,00,00	---
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि 2	1,00,00	---
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि 2	1,00,00	---
राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	4,00,00	---
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	1500,00,00	1500,00,00

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।

2. ये निधियाँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी जाती हैं।

(पी. वाय. पाध्ये)
मुख्य लेखाकार

(डी. प्रार. मेहता)
उप गवर्नर

(ए. एस. तारापीर)
उप गवर्नर

(सी. रंगराजन)
गवर्नर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1993 की स्थिति के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे पर केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून 1993 की स्थिति के तुलन-पत्र की ओर से उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की जाँच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो स्पष्टीकरण और जानकारी माँगी, ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार बैंक के बही-खातों तर टिपणी तथा उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अन्तर्गत बताये गये विनियमों के अनुसरण में सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों को सचची और सही स्थिति का पता लग सके।

मैसर्स प्रहमया एण्ड कं.

मैसर्स गोंयल गर्ग एण्ड कं.

मैसर्स एन०एम. रायजी

मैसर्स मित्रा कुंडु एंड बंसु

मैसर्स जे. एन. शर्मा एंड कं.

मैसर्स एम. प्रानंथम

एण्ड कं.

एण्ड कं.

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक

भारतीय रिजर्व बैंक

(संलग्नक)

लेखा सम्बन्धी उपपणियां और उल्लेखनीय लेखा नीतियां

1. उल्लेखनीय लेखा नीतियां

1.1 स्वर्ण-धारण राशियां : निर्गम और बैंकिंग विभागों द्वारा धारित स्वर्ण का मूल्यांकन, स्वर्ण के मासिक औसत संदेन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में चल रही डालर का भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

1.2 विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश : विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबार-दिन पर चल रहे लागत अथवा बाजार मूल्य के निचले स्तर पर किया जाता है और उन्हें उस दिन चल रही भारतीय रिजर्व बैंक की (संदर्भ दर पर आधारित) दरों पर रुपये के सममूल्य पर परिवर्तित कर दिया जाता है। जहां प्रतिभूतियों के मूल्य-ह्रास को लाभ एवं हानि लेखा के नाम खाल दिया जाता है वहीं प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि को नजर अंदाज कर दिया जाता है।

1.3 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश : प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्ष के अंत के चालू आयवक्र पर आधारित लागत अथवा दरों के निचले स्तर पर किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाली कुल आय को निवेश लेखा में जमा कर दिया जाता है। लाभ/हानि को केवल उक्त प्रतिभूतियों के वापस प्राप्त किये जाने के समय दर्ज किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां प्रतिभूतियों के एक अंश से होने वाली आय उक्त श्रेणी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के ब्रह्ममूल्य से अधिक हो।

1.4 सरकारी खजाना बिल : खजाना बिलों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

1.5 रिजर्व बैंक के निवेश : भारतीय स्टेट बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक तथा भारतीय भित्तीकाटा और बिजुल गृह लि. के शेयरों में बैंक के निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

1.6 ऐसे मामलों को छोड़कर जहां दरें संविदा के अनुरूप निर्धारित की गई हैं विदेशी मुद्राओं में परिसंपत्तियां और देयताएं तुलनपत्र में मौजूद दिनांक की रिजर्व बैंक की

दरों (संदर्भ दर पर आधारित) पर रुपये में परिवर्तित की जाती हैं। जिस महीने में लेन-देन किये गये हैं उस महीने की धारिता दरों पर आय और व्यय को रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

1.7 लाभ एवं हानि खाता : आय और व्यय को उपाजन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। उपाजित आय का हिसाब में लिया जाता और बकाया खर्चों का प्रावधान किया जाना केवल 1 लाख रुपये या अधिक की अलग अलग मद के लिए किया जाता है।

1.8 सेवानिवृत्ति लाभ : बीमे के मूल्यांकन का आधार मानते हुए उपदान निधि में प्रतिवर्ष और पेंशन निधि के मामले में दो वर्ष में एक बार अंशदान किया जाता है।

1.9 मूल्यह्रास : परिसंपत्तियों और विद्युत संस्थानों जैसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का हिमाव मूल्य-ह्रासित मूल्य पद्धति के आधार पर लगाया जाता है और कंप्यूटरों, मोटर वाहनों आदि के मामले में मूल्यह्रास का हिमाव मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लगाया जाता है। तथापि, वर्ष की दूरी छमाही में अभिवृद्धि परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता।

2. आरक्षित निधि : भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में 5 करोड़ रुपये का आरंभिक अंशदान और स्वर्ण के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप 6,495 करोड़ रुपये की मूल्यवृद्धि—दोनों ने मिलकर आरक्षित निधि का निर्माण किया।

3. जमाराशियां—अन्य : इनमें प्रमुखतः विदेशी केन्द्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त जमा राशियां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के शेष, स्टाफ पेंशन, भविष्य निधि और उपदान के अंशदानों की राशियां शामिल हैं।

4. अन्य देयताएं : इनमें प्रमुखतः विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए और अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए रखी गयी आरक्षित निधियां शामिल हैं।

5. निवेश : बैंकिंग विभाग के निवेश में विदेश में निवेश मुद्राओं में रखे 3,683.22 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1,234.87 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

2. विदेशी निवेशों में बांड उधार स्कीम के अंतर्गत मुक्त भागीदारी आधार पर ऋण के रूप में दिये गये 87.98 करोड़ रुपये मूल्य (अंकित मूल्य 88.38 करोड़ रुपये) के बांड शामिल हैं।

6. अन्य परिसंपत्तियाँ : इनमें प्रमुखतः स्वर्ण "1 645.29 करोड़ रुपये मूल्य (पिछले वर्ष 1 188.65 करोड़ रुपये)

का भारत से बाहर धारित स्वर्ण" अचल परिसंपत्तियाँ चालू पूँजीगत निर्माण कार्य प्राप्य राशियाँ अन्तर-कार्यालय खातों में शेष राशियाँ स्टाफ को दिये गये ऋण और अग्रिम तथा एशियाई समाशोधन गंध एकाउंट की शेष राशियाँ शामिल हैं। अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख लागत मूल्य पर किया गया है किन्तु उसमें से संचित मूल्यह्रास को घटा दिया गया है।

परिशिष्ट सारणियों की विषय-सूची

सारणी संख्या

नोट्स

पृष्ठ संख्या

1. नीतिगत गतिविधियाँ एवं स्वरूप

- 1.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों के लिए ब्याज दर संरचना
- 1.2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वाणिज्य अग्रिमों पर ब्याज दरें
- 1.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नियत ऋण पर ब्याज दरें
- 1.5 चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अधीन पण्यों की जमानत पर बैंक-अग्रिमों के लिए न्यूनतम मार्जिन और उच्चतम ऋण सीमा का स्तर

2. वार्षिक अर्थ-व्यवस्था कार्य निष्पादन और समस्याएँ

- 2.1 वार्षिक सकल देशी उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना तथा वृद्धि दरें
- 2.2 देशी अचल तथा निवेश अनुदान के अनुमान
- 2.3 कृषि उत्पादन
- 2.4 खाद्यान्नों की गन्कारी खरीद, निकासी और स्टॉक
- 2.5 औद्योगिक-उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियाँ
- 2.6 विनिर्माण क्षेत्र के 17 प्रमुख समूहों में वृद्धि
- 2.7 आधारभूत संरचना वाले उद्योगों के उत्पादन

3. सरकारी वित्त

- 3.1 केन्द्र सरकार के घाटे के मापदंड
- 3.2 केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक के निक्षेप ऋण के पाक्षिक स्तर
- 3.3 सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण
- 3.4 भारत सरकार का कुल ऋण देयताएँ
- 3.5 केन्द्र सरकार की बजटीय स्थिति
- 3.6 राज्य सरकारों के घाटे के मापदंड
- 3.7 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण
- 3.8 केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तिशक्तियों और संवितरण
- 3.9 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विकास संबंधी तथा विकासोन्मुख व्यय
- 3.10 केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व
- 3.11 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा आयोजित स्थानीय प्राधिकरण एवं संस्थाओं के बाजार उधार
- 3.12 केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर कूपन दरें 215

4. मुद्रा और मूल्य प्रवृत्तियाँ

- 4.1 मुद्रा स्टॉक (एम) में घट बढ़ घटक और स्त्रोत
- 4.2 प्रारंभित मुद्रा में घट बढ़ घटक और स्त्रोत
- 4.3 चल मुद्रा के बाह्य क्षेत्र, सकल जमा राशियों, एम 1 और एम 3 की प्रवृत्तियाँ
- 4.4 मौद्रिक अनुपात
- 4.5 महत्वपूर्ण अंकित गति-अनुसूचित वाणिज्य बैंक
- 4.6 मार्च के अंतिम सप्ताह में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वृद्धि दरें में घट-बढ़
- 4.7 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के रोज़ जमा-समाधन
- 4.8 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा कल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण
- 4.9 सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण
- 4.10 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता
- 4.11 भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लि. की रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त
- 4.12 मुद्रा बाजार निष्पत्तियों में भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लि. का संयोजी आधार
- 4.13 भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लि. की प्रवृत्ति रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त की ब्याज दरें
- 4.14 भारतीय मित्रीकाटा, और वित्त गृह लि. की मांग उधार दरें
- 4.15 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अमा-प्रमाणपत्र जारी करना

सारणी संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
4.16	भारत सरकार के 364 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी	
4.17	भारत सरकार के 91 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी	
4.18	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी	
4.19	रिजर्व बैंक द्वारा पुनः खरीद की नीलामी	
4.20	थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट बढ़ (आधार : 1981-92 = 100)	
4.21	सामान्य थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में समूहों/पण्यों का मार्गिकित योगदान (आधार : 1981-82 = 100)	
4.22	थोक मूल्य सूचकांक तथा उद्योगिक मूल्य सूचकांक में प्रदर्शित मूल्यवृद्धि को वार्षिक और तिमाही वरें (बिन्दुवार आधार पर)	
4.23	ग्रामों के रूप में सोने और चांदी का अनुपात	
6.24	देशों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा चांदी की कीमतें	
6.25	सोने और चांदी की कीमतें-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का मासिक प्रसार और अंतर	
5.	पूँजी बाजार की गतिविधियाँ	
5.1	सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता	
5.2	सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों की पूँजी जुटावे के लिए नए निगमों हेतु नियंत्रक, पूँजी निगम और भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) का अनुमोदन	
5.3	गैर-सरकारी मार्बेजलिक लि. कंपनिया के नये पूँजी निगम	
5.4	भारतीय रिजर्व बैंक-साधारण शेयर मूल्य का अखिल भारतीय सूचकांक (साप्ताहिक) (आधार : 1980-81 = 100)	
5.5	गैर बैंकिंग निगमित क्षेत्र में जमाराशियाँ	
6.	बाह्य क्षेत्र की गतिविधियाँ	
6.1	भारत का समग्र भुगतान संतुलन	
6.2	वित्तपोषण की आवश्यकता तथा वित्तपोषण के स्त्रोत	
6.3	भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियाँ	
6.4	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन देन	
6.5	भारत का विदेश व्यापार	
6.6	भारत के मुख्य पण्यों का निर्यात	
6.7	भारत के मुख्य पण्यों का आयात	
6.8	रुपया भुगतान क्षेत्र तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार	
6.9	बाहरी सहायता	
6.10	अनिवासी (विदेशी) रुपये खाता योजना और विदेशी मुद्रा अनिवारी रुपये खाता योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियाँ की देयताएँ	
6.11	विदेशी मुद्रा अनिवारी खाते की जमाराशियों पर ब्याज वरें	
6.12	भारत के विदेशी ऋण	
6.13	रुपये की विनिमय वरें	

परिशिष्ट भारणी 1.1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रग्रिमों के लिए ब्याज दर संरचना

(प्रतिमास वार्षिक)

खाते की श्रेणी 1991	सागू वरें					
	9 अक्तूबर, 1991	22 अप्रैल 1992	9 अक्तूबर 1992	1 मार्च 1993	8 अप्रैल 1993	24 जून, 1993
1	2	3	4	5	6	7
1. ऋण सीमा का प्रकार						
1. 7,500 रुपये तक और उसके सहित	11.5	11.5	11.5	11.5	12.0	12.0
2. 7,500 रुपये से अधिक और 15,000 रु. तक	13.0	13.5	13.5	13.5		
3. 15,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक	13.5					
4. 25,000 रु. से अधिक और 50,000 रु. तक	15.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.0
5. 50,000 रु. से अधिक और 2 लाख रु. तक	16.5					
6. 2 लाख रु. से अधिक @ (न्यूनतम)	20.0*	19.0*	18.0*	17.0*	17.0*	16.0*

1	2	3	4	5	6	7
II. ग्रामियों की विशिष्ट श्रेणियाँ						
1. विभेदक व्याज दर ग्रामिम	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2. कृषि सधु उद्योग और दो बाहनों तक रखने वाले परिवहन परिचालकों को मीयादी ऋण						
ऋण सीमा का आकार						
(1) 25,000 रु. से अधिक और 50,000 रु. तक	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
(2) 50,000 रु. से अधिक और 2 लाख रु. तक	15.0					
(3) 2 लाख रु. से अधिक (न्यूनतम)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
III. (1) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण						
(2) व्यक्तियों को शीयरी और डिबेंचरों/बांडों पर ऋण						
(3) गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य व्यक्तिगत ऋण						

बैंकों की दरें निर्धारित करने की छूट है

परिशिष्ट सारणी I. 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वाणिज्य ग्रामिमों पर व्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

प्रभावी तारीख	व्याज की दर
1	2
1 मार्च, 1978	15.0
13 सितम्बर, 1979	18.0
1 जुलाई, 1980	19.4
2 मार्च, 1981	19.5 * अधिक नहीं
1 अप्रैल, 1983	18.0 से अधिक नहीं
1 अप्रैल, 1985	17.5 से अधिक नहीं
1 अप्रैल, 1987	16.5
10 अक्टूबर 1988	16.0 (न्यूनतम)
13 अप्रैल, 1991	17.0 (न्यूनतम)
4 जुलाई, 1991	18.5 (न्यूनतम)
9 अक्टूबर, 1991	20.0 (न्यूनतम)
2 मार्च, 1992	19.0 (न्यूनतम)
9 अक्टूबर, 1992	18.0 (न्यूनतम)
1 मार्च, 1993	17.0 (न्यूनतम)
24 जून, 1993	16.0 (न्यूनतम)

* व्याज दर सहित।

परिशिष्ट सारणी I. 3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों पर व्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

खाते का वर्ग	लागू दरें				
	9 अक्टूबर, 1991	24 अप्रैल, 1992	9 अक्टूबर, 1992	1 मार्च, 1993	1 जुलाई, 1993
1	2	3	4	5	6
चालू वसूत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0
मीयादी जमा राशियाँ					
46 दिनों से तीन वर्ष तक और इससे अधिक	11.0*	13.0@	12.0	11.0	11.0
		से अनधिक	से अनधिक	से अनधिक	से अनधिक

* यह दर तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए स्थायी दर थी और अल्पावधि परिपक्वता के लिए इससे कम स्थायी दर निर्धारित की गयी थी।

@ 22 अप्रैल, 1992 से प्रभावी।

परिशिष्ट सारणी I. 4 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निर्यात ऋण पर व्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

निर्यात ऋण	लागू करें				
	1 जनवरी, 1992	2 मार्च, 1992	9 अक्टूबर 1992	1 मार्च, 1993	24 जून, 1993
1	2	3	4	5	6
1. पोत लदान से पूर्व ऋण					
(1) (क) 180 दिन तक	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(ख) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक*	17.0	17.0	16.0	15.0	15.0
(2) सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन के लिए ई सी जी सी द्वारा शामिल 90 दिन तक की गारंटी के बदले में	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
2. पोत-लदान के पश्चात ऋण					
(1) मार्गस्थ अवधि के मांग बिल (फेडरल द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(2) मीमादी बिल (निर्यात बिलों, फेडरल द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि की मीमादी अवधि को शामिल करते हुए कुल अवधि के लिए, जहां भी लागू हो अनिश्चित अवधि भी शामिल है।)					
(क) 90 दिन तक	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(ख) 90 दिन से अधिक और पोत लदान की तारीख से छः माह तक	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
(ग) पोत-लदान की तारीख से छः माह से अधिक	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0
(3) ई सी जी सी गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन के लिए (90 दिन तक)	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(4) अन्तर्गत शेष राशि के लिए (90 दिन तक)	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(5) अधिधारण धन के लिए (केवल आपूर्ति भाग के लिए) पोत लदान की तारीख से एक वर्ष में ऋण देय (90 दिन तक)	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
3. घास्यगत ऋण					
180 दिन से अधिक की अवधि के लिए घास्यगत ऋण	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
4. निर्यात ऋण, अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट नहीं (न्यूनतम)	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
5. त्रिवेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित पोतलदान निर्यात ऋण					
(1) मार्गस्थ अवधि के मांग बिल (फेडरल द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)	8.5	6.5	6.5	6.5	6.5
(2) मीमादी बिल (निर्यात बिलों की मीमादी अवधि, मार्गस्थ अवधि, फेडरल द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, छूट की अवधि जहां भी अनुमेय हो, कुल अवधि में पोतलदान की तारीख से छः माह तक शामिल है)	8.5	6.5	6.5	6.5	6.5
(3) निर्यात ऋण, पी एम सी एफ सी के लिए, अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट नहीं @				8.5	8.5

* व्याज दर को छोड़कर

@ (i) 13 अक्टूबर 1992 से लागू

* 12 मार्च 1992 से भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता समाप्त की गयी है।

परिशिष्ट सारणी 11.5 : अत्यन्तमक ऋण नियंत्रणों के अधीन पण्यों की वर्तमान पर देश-अधिसो के लिए व्यूयनग पाठन और उच्चतम ऋण सीमा का स्तर

(प्रतिशत)

पण्य	न्यूनतम माजित (24 जून, 1993 से लागू)			उच्चतम ऋण सीमा का स्तर
	मिले/संसाधन युनिटें	अन्य	गोदाम रसीदें	
1	2	3	4	5
1. धातु/धातु	45	60	45	85
2. गेहूँ	30	45	30	100
3. दालें	45	60	45	100
4. अन्य खाद्यान्न	45	60	45	100
5. तिलहन (जैसे मूंगफली, तोरिया/सरसों, बिनीया, अलसी, एरण्ड और सभी आयातित तिलहन)	30	45	30	100
6. वनस्पति तेल (जैसे मूंगफली, तोरिया/सरसों, बिनीया, अलसी, एरण्ड, वनस्पति और सभी आयातित वनस्पति तेल)	30 ^(a)	45	30	100
7. बीनी				
(क) आयाती स्टॉक	0	—	—	—
(ख) अनिर्गत स्टॉक	20	—	—	—
(ग) निर्गत स्टॉक	75	75	60	—
8. मुड़ और खाद्यकारी	45	75	60	—
9. रुई और कपास	*8	45	30	1157

(a) पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पति विनिर्माताओं के संबध में लागू।

* अत्यन्तमक ऋण नियंत्रण शर्तों से छूट प्राप्त।

* मिलों/संसाधन युनिटों के अलावा अन्य पर लागू।

— लागू नहीं।

परिशिष्ट सारणी 11.1 : वास्तविक सकल देशी उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना तथा वृद्धि दरें

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	वास्तविक म. दे. उ. में अंश				वृद्धि दर			
	1991-92*	1990-91	1980-81	1992-93 [†]	1991-92 [†]	1990-91	सातवीं योजना दशक (1985-86 से 1989-90)	(1980-81 से 1989-90)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कृषि और संबद्ध कार्य	30.8	31.6	38.1	—5.1	—1.4	+1.8	+3.4	+2.9
कृषि	28.1	29.3	34.7	—5.1	—1.8	+4.9	+3.9	+3.1
2. उद्योग	24.7	25.2	29.9	—1.5	—0.9	+7.2	+7.5	+7.3
विनिर्माण	20.3	21.0	17.7	—0.9	—2.3	+7.5	+7.1	+7.2
3. सेवाएं [‡]	44.5	43.2	41.0	+5.0	+4.5	+4.3	+7.0	+6.4
जोड़	100.0	100.0	100.0	+4.2	+3.2	+5.2	+5.8	+5.4

* स्वरित अनुमान (जनवरी 1993), केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

[†] भा. रि. के अनुमान।

(a) निर्माण सहित।

परिशिष्ट सारणी 11.2 : देशी बचत तथा निवेश अनुमान के अनुमान

क्षेत्र/राजकोष वर्ष	खान बाजार कीमतों पर सफल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मूल्य बचत		खान बाजार कीमतों पर शुद्ध देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मूल्य बचत		तथा निवेश	
	1992-93@	1991-92@	1990-91@	1992-93@	1991-92@	1990-91@
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू क्षेत्र की बचत जिसमें से : वित्तीय आस्तियों में बचत*	17.7	19.4	19.9	16.2	17.5	18.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र	7.7	9.1	8.6	3.5	10.2	9.5
3. देशी निजी कंपनी क्षेत्र	2.0	1.7	1.1	-3.0	-3.3	-3.8
4. कुल : देशी बचत (1+2+3)	22.5	23.8	23.7	14.2	15.2	15.2
5. विदेशी स्वतंत्रों का शुद्ध आगमन	2.2	1.0	3.5	2.5	1.1	3.9
6. कुल निवेश (4+5)	24.8	24.8	27.1	16.6	16.3	19.1

खान बाजार कीमतों पर सफल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद
(करोड़ रुपये)

@अंतिम अनुमान 1/2 त्वरित अनुमान 1\$ भा. रि. डे. के अनुमान

*वित्तीय आस्तियों के लिए इनका समायोजन किया गया। चूंकि वित्तीय आस्तियों में वस्तु अचल आस्तियों के लिए पूंजी के उपयोग में शामिल नहीं होती।

धन: शुद्ध औसत सफल औसतों से अधिक आते हैं। इसी प्रकार विदेशी स्वतंत्रों के शुद्ध आगमन में होता है।

टिप्पणियाँ :

1. नये आंकड़ों के प्राप्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय तथा बचत और निवेश के अनुमानों में संशोधन होने के कारण बैंक की पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गए तथा 1991-92 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के त्वरित अनुमानों में प्रतिशत औसत 1990-91 तथा 1991-92 के औसतों से भिन्न हैं।

2. पूर्णक किए जाने के कारण आंकड़े कुल योग से भिन्न हो सकते हैं।

परिशिष्ट सारणी 11.3 : कृषि उत्पादन

फसल	(मिलियन टन में)			
	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90
	(अनुमानित)	(अंतिम)		
1. सभी फसलें*	5.1*	-2.5	2.7	2.1
2. खाद्यान्न	181.2	167.1	176.4	171.0
चावल	72.6	73.7	74.3	73.6
गेहूं	57.0	55.1	55.1	49.8
मोटे अनाज	36.9	26.3	32.7	34.8
दालें	14.7	12.0	14.3	12.8
क) खरीफ	103.2	91.4	99.4	101.0
चावल	64.6	64.8	66.3	65.9
मोटे अनाज	32.3	22.2	27.7	29.1
दालें	6.3	4.4	5.4	5.5
ख) रबी	8.0	8.8	8.0	7.7
चावल	57.0	55.1	55.1	49.8
गेहूं	4.6	4.1	5.0	5.2
मोटे अनाज	8.1	7.6	8.9	7.3
दालें				
3. तिलहन	20.6	18.3	18.6	16.1
4. गन्ना	238.0	249.3	241.1	225.6
5. कपास**	11.7	9.8	9.8	11.4
6. जूट और मेस्ता@	7.6	10.2	9.2	8.3

पूर्णांक किए जाने की वजह से जोड़ में अन्तर हो सकता है।

* प्रत्याशित \$ वृद्धि करें (प्रतिशत में) कृषि उत्पादन के सूचकांक पर आधारित है।

(1969-70-100 को समाप्त तीन वर्ष)

** मिलियन गांठे—एक गठठा = 170 कि. घा. @ मिलियन गांठे—एक गठठा = 180 कि. घा.

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणी II. 4 : खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, निकासी और स्टॉक

(मिलियन टन)

राजकोषीय वर्ष/प्रवधि	सरकारी खरीद			निकासी			स्टॉक*		
	बावल	गेहूं	जोड़	बावल	गेहूं	जोड़@	बावल	गेहूं	जोड़@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1990-91	12.8	11.1	23.9	7.9	8.2	16.1	11.2	5.8	17.3
1991-92	10.4	7.8	18.2	10.1	9.1	19.2	9.8	2.4	12.2
1992-93	12.6	6.4	19.0	9.4	7.7	17.1	11.0	3.0	14.7
पहली तिमाही (अप्रैल - जून)									
1992-93	1.1	6.3	7.4	2.3	1.9	4.2	8.4	6.7	15.1
1993-94\$	1.5	12.7	14.2	2.1	1.0	3.1	10.4	15.2	26.4

* ये स्टॉक राजकोषीय वर्ष के लिए मार्च के अन्त के हैं।

@ मोटे अनाज शामिल हैं।

\$ अन्तिम।

‡ वर्ष 1993-94 राजकोषीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए, निकासी तथा स्टॉक आंकड़े मई 1993 तक के हैं।

स्रोत : खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणी II. 5 : औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियाँ

(आधार 1980-81 = 100)

क्षेत्र	खनन और उद्योग		निर्माण		विजली		सामान्य	
	11.46		77.11		11.43		100.00	
आगत वर्ष	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1988-89	199.1	7.9	175.6	8.7	198.2	9.5	189.9	8.7
1989-90	211.6	6.3	190.7	8.6	219.7	10.9	196.1	8.6
1990-91	221.2	4.5	207.8	8.9	236.8	7.8	212.6	8.2
1991-92	221.5	0.1	204.6	-1.5	257.0	8.5	212.5	0.0
अप्रैल - जून	203.4	-3.6	187.7	-3.7	243.4	6.7	195.9	-2.3
जुलाई - सितम्बर	193.1	-1.8	193.9	-1.2	252.5	10.0	200.5	0.2
अक्टूबर - दिसम्बर	228.1	6.0	197.6	-2.7	262.2	10.4	203.4	0.05
जनवरी - मार्च	261.4	-0.3	239.3	1.0	269.7	7.1	245.4	1.6
1992-93	225.8	1.9	206.1	0.7	269.7	4.9	213.6	1.5
अप्रैल - जून	220.1	8.2	195.8	4.3	258.0	6.0	205.7	5.0
जुलाई - सितम्बर	195.4	1.2	199.6	2.9	259.0	2.5	205.8	2.7
अक्टूबर - दिसम्बर	223.8	1.9	205.8	4.2	276.6	5.5	215.9	3.6
जनवरी - मार्च	263.9	1.0	223.1	-6.8	283.4	5.8	234.9	-4.3

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

परिशिष्ट सारणी II.6 : विनिर्माण क्षेत्र के 17 प्रमुख समूहों में वृद्धि

(प्राधार : 1980-81 = 100)

उद्योग समूह	सूचकांक	प्रतिशत में घट-बढ़				संबंधित अंशदान (प्रतिशत में)			
		1992-93	1991-92	1990-91	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92	
भारत		2	3	4	5	6	7	8	9
I. घनात्मक									
तेज-वृद्धि (1992-93 के दौरान)									
1. खाद्य और खाद्य उत्पाद	5.33	175.7	166.2	169.8	5.7	-2.1	45.2	-7.9	
2. रसायन और रासायनिक उत्पाद	12.51	270.2	262.8	254.1	5.1	3.4	149.9	44.9	
3. परिवहन उपकरण	6.39	198.5	191.5	192.5	3.7	-0.5	40.0	-2.6	
4. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	0.45	190.5	185.0	197.2	3.0	-6.2	2.2	-2.3	
5. रबर, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद	4.00	176.8	172.4	174.0	2.6	-0.9	15.7	-2.6	
6. बमझा तथा बमझा एजेंट उत्पाद	0.49	200.9	196.6	194.3	2.2	1.2	1.9	0.5	
7. सूती वस्त्र	12.31	128.3	126.2	126.6	1.7	-0.3	23.1	-2.0	
8. अन्य विनिर्माण उद्योग	0.90	271.0	269.8	321.8	0.4	-16.2	1.0	-19.3	
गिरावट (1992-93 के दौरान)									
9. गैर धात्विक खनिज उत्पादन	3.00	207.2	205.2	193.1	1.0	6.3	5.4	15.0	
II. ऋणात्मक (1992-93 के दौरान)									
10. वस्त्र उत्पाद (जिसमें पहनने के कपड़े शामिल हैं)	0.82	78.7	97.2	103.2	-19.0	-5.8	-13.5	-2.0	
11. धातु उत्पाद	2.29	126.3	139.9	143.1	-9.7	-2.2	-27.8	-3.0	
12. पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	1.57	113.6	119.1	104.8	-4.6	13.6	-7.7	9.3	
13. जूट, हेम्प और मेस्ता वस्त्र	2.00	87.2	90.4	101.6	-3.5	-11.0	-5.7	-9.2	
14. इलेक्ट्रिकल मशीनरी	5.78	476.4	493.6	563.6	-3.5	-12.4	-88.8	108.7	
15. मशीन और मशीन औजार	6.24	178.2	184.4	186.9	-3.4	-1.3	-34.6	-6.4	
16. कागज और कागज उत्पाद	3.23	208.7	209.6	198.0	-0.4	5.9	-2.6	15.4	
17. भूत धातु व मिश्रधातु उद्योग	9.80	168.1	168.5	158.8	-0.2	6.1	-3.5	39.2	
विनिर्माण	77.11	206.1	204.6	207.8	0.7	-1.5	100.0	-100.0	

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

परिशिष्ट सारणी II.7 : आधारभूत संरचना वाले उद्योगों के उत्पादन

उद्योग	भाग	यूनिट	राजकीय वर्ष			
			उत्पादन		विकास दर (प्रतिशत)	
			1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6	7
विद्युत	11.43	बिलियन यूनिट	300.99	286.71	4.9	8.5
कोयला	6.61	मिलियन टन	238.22	229.29	3.9	8.3
विक्रीयोग्य इस्पात	5.21	मिलियन टन	10.45	10.07	3.9	8.1
सीमेंट	1.60	मिलियन टन	54.14	54.01	0.2	10.9
कच्चा पेट्रोलियम	2.41	मिलियन टन	26.95	30.35	-11.2	-8.1
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद*	1.52	मिलियन टन	49.74	47.82	4.0	-0.7
मूलभूत संरचना वाले उद्योगों का सम्मिश्रित सूचकांक	28.77		233.9	228.2	2.5	6.1
(प्राधार 1980-81 = 100)						

* इसमें कृषि रिफाइनरी उत्पाद का 93 प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत : योजना और कार्यक्रम विभाग, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणी III. 1: केन्द्र सरकार के बाड़े के मापदंड

वर्ष	समाज राज- कोषीय घाटा (@)	निवल राजकोषीय घाटा (a)	प्राथमिक घाटा	मुद्राकृत घाटा	परम्परागत घाटा	राजस्व घाटा	(करोड़ रुपये)
							प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8
	8,299	5,110	4,301	3,551	2,477	2,037	1,86,013
1980-81	8,666	4,591	3,611	3,207	1,400	392	1,59,760
1981-82	10,627*	5,973	4,887	3,368	1,656*	1,308	1,78,132
1982-83	13,030 ^b	8,171	6,044	3,949	1,117*	3,540	2,07,589
1983-84	17,416	10,972	8,961	6,055	3,745	4,225	3,31,343
1984-85	21,857*	13,543	10,626	6,190	5,315*	5,889	2,62,243
1985-86	26,342	17,036	13,143	7,901	8,261	7,777	2,92,949
1986-87	27,044	18,431	12,935	6,559	5,816	9,137	3,33,201
1987-88	30,923	20,770	13,473	6,503	5,642	10,515	3,96,593
1989-90	34,932	23,722	14,439	13,813	10,592	11,914	4,53,986
1990-91	41,632	30,692	17,651	14,746	11,317	18,562	5,30,865
1991-92	46,325	24,623	8,982	5,508	6,855	16,261	6,09,500
1992-93 (सं.प्र.)	36,722	26,037	5,974	5,400\$	7,202+	16,700	7,03,000≠
1993-94 (ब.प्र.)	36,959	26,926	3,457	4,314	4,314	17,630	7,85,000++

प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

	6.10	3.76	3.16	2.61	1.82	1.50
1980-81	5.42	2.87	2.26	2.01	0.88	0.25
1981-82	5.97	3.35	2.74	1.89	0.93	0.73
1982-83	6.28	3.94	2.91	1.90	0.68	1.22
1983-84	7.53	4.74	3.87	2.62	1.62	1.83
1984-85	8.33	5.16	4.05	2.36	2.03	2.25
1985-86	8.99	5.82	4.49	2.42	2.82	2.65
1986-87	8.12	5.53	3.88	1.97	1.75	2.74
1987-88	7.80	5.24	3.40	1.64	1.42	2.65
1989-90	7.85	5.23	3.18	3.04	2.33	2.82
1990-91	8.41	5.78	3.32	2.78	2.14	3.50
1991-92	5.96	4.04	1.47	0.90	1.12	2.87
1992-93	5.22	3.70	0.85	0.77	1.02	2.38
1993-94++	4.71	3.43	0.44	0.55	0.55	2.25

सं.प्र. संशोधित अनुमान।

ब.प्र. बजट अनुमान।

≠ भारि.वै. के अनुमान।

++ कच्चे अनुमान।

@ पूर्वीगत लेखों में कतिपय प्रति प्रविष्टियों के कुछ समायोजनों के कारण ये आंकड़े पहले प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं।

* इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गये 1982-83 में 1,743 करोड़ रुपये, 1983-84 में 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में 1,628 करोड़ रुपये के सत्यापित ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

\$ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार, वर्ष 1992-93 के दौरान, सरकारी लेखा के समाप्ति के बाद, 4,257 करोड़ रुपये का मुद्राकृत घाटा दर्शाया गया है।

+ 31 मार्च 1992 के सरकारी लेखों के समाप्ति पर 12,757 करोड़ रुपये का घाटा भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार दर्शाया गया है।

++ चालू बाजार भाव के सकल उत्पादन में 13 प्रतिशत की वृद्धि मानी जाती है।

टिप्पणी: परम्परागत घाटा, अर्थात् सभी आय और व्यय (राजस्व और पूँजीगत दोनों) का अन्तर है। राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय का अन्तर सूचित करता है। मुद्राकृत घाटा, भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार को निवल ऋण में वृद्धि, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की 91 दिनों की राजकोषीय विलों की जमापूँजी तथा केन्द्र सरकार के बाजार उधाराओं में उसका अंशदान है। कुल राजकोषीय घाटा, अर्थात् कुल व्यय की अधिकता जिसमें राजस्व प्राप्ति (बोध्य अनुदान भी शामिल है) और अण्णतर पूँजीगत प्राप्ति का समुची शामिल है। निवल राजकोषीय घाटा अर्थात् सकल राजकोषीय घाटा और निवल ऋणों का अन्तर है। सकल राजकोषीय घाटे में से निश्चय ब्याज भुगतानविराज घटाकर प्राथमिक घाटा दर्शाता है।

स्रोत: केन्द्र सरकार का बजट प्रलेख तथा आर्थिक सर्वेक्षण, 1992-93

परिशिष्ट सारणी III. 2 : केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक के निवल धन के तात्त्विक स्तर(१)

(करोड़ रुपये)

प्रवर्ध	केन्द्र का बजट घाटा				केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल धन			
	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
	1	2	3	4	5	6	7	8
बजट अनुमान		4,314	5,389	7,719	7,206	4,314	5,389	7,719
(प्राथमिक वास्तविक -								
1 (सर्वांगी) दिनांक 3-4-92		887	4,774	2,271	2,679	2,413	3,847	2,712
2 17-4-92		4,057	6,115	3,716	3,204	9,476	6,522	4,050
3 1-5-92		8,186	6,604	5,508	5,754	12,101	5,229	4,994
4 15-5-92		11,964	8,924	8,409	6,638	13,691	7,218	6,761
5 29-5-92		13,046	10,414	8,925	8,228	13,726	7,985	7,531
6 12-6-92		16,201	10,854	11,029	7,698	10,065	7,192	9,607
7 26-6-92		16,953	9,886	11,503	9,107	9,201	3,912	9,188
8 10-7-92		20,718	14,102	12,747	9,996	18,889	9,193	11,165
9 24-7-92		20,750	14,949	11,873	10,128	17,498	8,113	10,580
10 7-8-92		21,727	13,933	12,799	10,976	16,444	7,872	10,759
11 21-8-92		21,065	11,792	11,571	8,729	16,245	5,657	10,303
12 4-9-92			13,007	13,442	10,290		7,236	11,029
13 18-9-92			11,159	10,393	10,289		5,512	8,890
14 2-10-92			10,169	12,406	11,971		4,723	10,445
15 16-10-92			9,868	13,097	10,755		6,424	11,866
16 30-10-92			9,986	11,409	11,830		7,111	9,564
17 13-11-92			12,609	11,245	13,636		9,110	12,418
18 27-11-92			13,261	15,272	13,001		9,549	13,117
19 11-12-92			15,440	17,119	15,330		10,741	15,830
20 25-12-92			11,511	11,503	13,097		1,450	9,812
21 8-1-93			14,134	16,177	15,093		8,723	14,979
22 22-1-93			14,637	14,138	15,123		9,065	13,961
23 5-2-93			15,166	15,726	15,442		9,441	15,305
24 19-2-93			15,658	15,024	14,627		8,773	14,451
25 5-3-93			14,327	13,011	15,072		4,254	12,185
26 19-3-93			13,960	10,606	11,969		2,262	10,452
27 31-3-93			12,757	6,942	11,430		4,257	5,508
तिमाही बीसत								
पहली तिमाही		10,956	8,082	7,337	6,187	10,097	5,986	6,104
दूसरी तिमाही		21,965	13,157	21,137	0,008	17,919	7,261	0,154
तीसरी तिमाही			11,835	13,622	12,803		7,016	11,865
चौथी तिमाही			14,647	14,114	14,554		7,087	13,606
वित्त वर्ष का औसत			11,811	11,508	10,818		6,718	10,209

(ए) भारतीय रिजर्व बैंक के अधिलेखों पर आधारित।

२० प्रमत्त 1993 तक।

३ वर्ष 1992-93 के वसूली के संगी दिनांक निर्दिष्ट किए गये हैं; जहाँ वर्षों के समूह में दिनांक तदनुसंग पद्धतियों से संशोधित।

टिप्पणी : बजट संशोधनों के अनुसार केन्द्र का घाटा 1990-91 (लेखा) में 11,147 करोड़ रुपये और 1992-92 (लेखा) में, 6,855 करोड़ रुपये का था।

परिमिष्ट सारणी III.3. मध्य राजकोषीय घाटे का विश्लेषण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	विदेशी वित्त		देशी वित्त			कुल वित्त/मध्य
	बाजार ऋण	अन्य देयताएँ	परम्परागत घाटा \$	जोष		राजकोषीय
				(2 + 4 + 5)	घाटा (2 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1,281 (15.4)	2,679 (32.3)	1,862 (22.4)	2,477 (29.9)	7,018 (84.6)	8,299 (100.0)
1981-82	964 (11.1)	2,913 (33.6)	3,380 (39.1)	1,400 (16.2)	7,702 (88.9)	8,666 (100.0)
1982-83	1,258 (11.8)	3,771 (35.5)	3,942 (37.1)	1,655* (15.6)	9,369 (88.2)	10,627 (100.0)
1983-84	1,338 (10.3)	4,038 (31.0)	6,237 (47.8)	1,417* (10.9)	11,692 (89.7)	13,030 (100.0)
1984-85	1,452 (8.3)	4,095 (23.5)	8,124 (46.7)	3,745 (21.5)	15,964 (91.7)	17,416 (100.0)
1985-86	1,449 (6.6)	4,881 (22.4)	10,209 (46.7)	5,315* (24.3)	20,408 (93.4)	21,857 (100.0)
1986-87	2,024 (7.7)	5,532 (21.0)	10,525 (39.9)	8,261 (31.4)	24,318 (92.3)	26,342 (100.0)
1987-88	2,893 (10.7)	5,862 (21.7)	12,473 (46.1)	5,810 (21.5)	24,151 (89.3)	27,044 (100.0)
1988-89	2,460 (8.0)	8,418 (27.2)	14,403 (46.6)	5,642 (18.2)	28,463 (92.0)	30,923 (100.0)
1989-90	2,595 (7.3)	7,404 (20.8)	15,041 (42.2)	10,592 (29.7)	33,037 (92.7)	35,632 (100.0)
1990-91	3,181 (7.1)	87,001 (17.9)	22,103 (49.5)	11,347 (25.5)	41,451 (92.9)	44,632 (100.0)
1991-92	5,421 (14.9)	7,510 (20.7)	16,539 (45.6)	6,855 (18.9)	30,904 (85.1)	36,325 (100.0)
1992-93 (सं. अ०)	4,430 (12.1)	3,670 (10.0)	21,420† (58.3)	7,202 (19.6)	32,292 (87.9)	36,722 (100.0)
1993-94 (सं. अ०)	5,454 (14.8)	3,700 (10.0)	23,491** (63.5)	4,314 (11.7)	31,505 (85.2)	36,959 (100.0)

कोष्ठकों में दर्शाये गये आकड़े कुल वित्त/मध्य राजकोषीय घाटे के प्रतिशत दर्शाते हैं।

* भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्टों को समाप्त करने के लिए राज्यों को दिए गए 1982-83 में 1,743 करोड़ रुपये, 1983-84 में 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में 1,628 करोड़ रुपये के सध्यावधि ऋणों का छोड़कर।

† अन्य देयताओं में भू-बनने, भविष्य निधियाँ, विशेष जमा राशियाँ, आरक्षित निधियाँ, 364 दिवसीय खजाना बिल आदि शामिल हैं।

\$ भारतीय रिजर्व बैंक के पास तकदी शेयरों में निवल परिवर्तनों से संचित निर्गमित 91 दिवसीय खजाना बिलों में बट-बट के रूप में परिसंचित।

‡ 182 दिवसीय/364 दिवसीय खजाना बिलों विलों विलों में 5,300 करोड़ रुपये की प्राप्ति को जोड़कर उनमें से 182 दिवसीय खजाना बिलों का निवल भुगतान।

** 364 दिवसीय का खजाना विलों में निवल प्राप्ति के 6,000 करोड़ रूप में विलों में।

सं.अ० - संशोधित अनुमान।

सं.अ० - समष्टि अनुमान।

स्रोत: भारत सरकार के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी III. 4: भारत सरकार की कुल व्ययों का विवरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आंतरिक ऋण	अन्य स्रोत	भविष्य निधि और अन्य स्रोत	आश्रित निधियाँ और अमाराजियाँ	कुल आंतरिक व्यय (2+3+4+5)	विदेशी व्यय	कुल व्यय (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	30,864 (22.7)	7,976 (5.9)	5,977 (4.4)	3,631 (2.6)	48,451 (35.6)	11,208 (8.3)	59,749 (43.9)
1981-82	35,653 (22.3)	9,375 (5.9)	7,203 (4.5)	3,627 (2.3)	55,858 (35.0)	12,328 (7.7)	68,186 (42.7)
1982-83	46,939 (26.4)	11,098 (6.2)	8,789 (5.0)	4,364 (2.4)	71,190 (40.0)	13,682 (7.7)	84,872 (47.7)
1983-84	50,263 (24.2)	13,506 (6.5)	10,368 (5.0)	6,004 (2.9)	80,141 (39.6)	15,120 (7.3)	95,261 (45.9)
1984-85	58,537 (25.3)	17,157 (7.4)	12,547 (5.4)	8,563 (3.7)	96,804 (41.8)	16,637 (7.2)	1,13,441 (49.0)
1985-86	71,039 (27.1)	21,449 (8.2)	15,410 (5.9)	11,433 (4.3)	1,19,331 (45.5)	18,153 (5.9)	1,37,884 (52.4)
1986-87	86,312 (29.5)	24,725 (8.4)	20,204 (6.9)	15,006 (5.1)	1,46,247 (49.9)	20,200 (6.9)	1,66,546 (56.8)
1987-88	98,646 (29.6)	28,358 (8.5)	26,170 (7.8)	19,164 (5.8)	1,72,338 (51.7)	23,220 (7.0)	1,96,566 (58.7)
1988-89	1,14,498 (28.9)	33,833 (8.5)	34,702 (8.7)	20,992 (5.3)	2,04,025 (51.4)	25,746 (6.5)	2,29,771 (57.9)
1989-90	1,33,193 (29.3)	41,791 (9.2)	45,273 (10.0)	19,592 (4.3)	2,39,849 (52.8)	28,343 (6.2)	2,68,192 (59.0)
1990-91	1,54,004 (29.0)	50,100 (9.4)	57,007 (10.8)	21,922 (4.1)	2,83,033 (55.3)	31,525 (5.9)	3,14,518 (59.2)
1991-92	1,72,750 (28.3)	55,755 (9.2)	63,745 (10.8)	23,464 (3.8)	3,17,714 (52.1)	36,948 (6.1)	3,54,662 (58.2)
1992-93 (संशुद्ध)	1,93,035 (27.4)	59,955 (8.5)	77,191 (11.0)	25,083 (3.6)	3,55,264 (50.5)	41,218 (5.9)	3,96,482 (56.4)
1993-94 (संशुद्ध)	2,04,690 (26.1)	63,855 (8.1)	94,685 (12.1)	26,777 (3.4)	3,90,007 (49.7)	46,453 (5.9)	4,36,460 (55.6)

टिप्पणी: क्रोडों में दर्ज गये आंकड़े वर्तमान बाजार भावों पर सकल वेत। उत्पाद के प्रतिफल दर्शाते हैं।

स्रोत: भारत सरकार के बजट प्रलेख।

संशुद्ध—संशोधित अनुमान।

संशुद्ध—बजट अनुमान।

परिशिष्ट सारणी III. 5: बजट सरकार की बजटिय स्थिति

संकेत	(करोड़ रुपये)			
	1993-94 (ब.प्र.)	1992-93 (म.प्र.)	1992-93 (ब.प्र.)	1991-92 (लेखा)
1. राजस्व लेखा	84,209	78,279	75,688	66,047
(i) प्राप्तियां (क)	1,01,839	94,979	89,570	82,330
(ii) व्यय (क)	-17,630	-16,700	-13,882	-16,261
(iii) अधिशेष (+)/बाटा (-)				
2. पूंजीगत लेखा	42,800	39,245	38,010	38,528
(i) प्राप्तियां	29,484	29,747	29,517	29,122
(ii) संवितरण	+13,316	+9,498	+8,493	+9,406
(iii) अधिशेष (+)/बाटा (-)	1,27,009	1,17,524	1,13,698	1,04,575
3. कुल प्राप्तियां [1 (i) + 2 (i)]	1,31,323	1,24,726	1,19,087	1,11,430
4. कुल व्यय [1 (ii) + 2 (ii)]	-4,314	-7,202	-5,389	-6,855
5. समग्र अधिशेष (+)/बाटा (-)	3,700	3,670	5,000	7,510
6. निवल बाजार ऋण	(4,848)	(4,821)	(6,151)	(8,921)

(क) राजस्व खाते के संबंध में वाणिज्यिक विभागों की छोड़कर

मं.प्र. : संशोधित अनुमान।

ब.प्र. : बजट अनुमान।

स्रोत: भारत सरकार के बजट दस्तावेज। कोष्ठकों के अंकड़े सकल बाजार ऋणों को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी III. 6: राज्य सरकारों के घाटे के मापदण्ड

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	निवल राजकोषीय घाटा	सुदृढ़ीकृत घाटा*	परम्परागत घाटा	(करोड़ रुपये)	
					राजस्व घाटा	बाजार भावी पर बजट उपार्ध के प्रतिफल के रूप में सकल राजस्व घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	3,712	1,714	487	897	+1,486	2.7
1981-82	4,062	2,209	789	1,020	+1,379	2.5
1982-83	4,986	2,830	+860	820	+888	2.8
1983-84	6,359	4,067	38	561	+211	3.1
1984-85	8,199	5,834	1,486	1,438	924	3.5
1985-86	7,520	4,799	+1,862	+1,688	+654	2.9
1986-87	9,269	6,107	516	667	+169	3.2
1987-88	11,219	7,742	+157	66	1,088	3.4
1988-89	11,672	8,884	425	+380	1,807	3.0
1989-90	15,433	11,645	255	161	3,682	3.4
1990-91	18,787	14,532	420	+72	5,309	3.5
1991-92	18,900	15,746	+340	96	5,650	3.1
1992-93 (मं.प्र.)	19,988	15,249	176	1,236	4,117	2.8
1993-94 (ब.प्र.)	23,707	17,298	उत्त०	2,640	4,524	3.0

(a) से संबंधित: आंकड़े

* आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास खाता रखनेवाले 23 राज्यों से संबंधित हैं। राज्यों का सुदृढ़ीकृत घाटा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए ऋण और अधिग्राह्य भारतीय रिजर्व बैंक के पास इतना जमा राशियों का निवल है।

+ अधिशेष दर्शाते हैं।

मं.प्र. - बजट अनुमान।

मं.प्र. - संशोधित अनुमान।

उ.प्र. - उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: राज सरकार का बजट प्रलेख।

परिमित सारणी III राज्यों के वित्त राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र सरकार से ऋण (निवल)	बाजार से उधार (निवल)	अन्य [†]	सकल राजकोषीय घाटा (2+3+4)	कुल	राज्यों की बनाया देयताएं मार्च के अन्त में केन्द्र से ऋण और अग्रिम	बाजार ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	1,564 (42.1)	184 (5.0)	1,964 (52.9)	3,712 (100.0)	23,977	17,071	2,973
1981-82	2,000 (49.2)	339 (8.4)	1,723 (42.4)	4,062 (100.0)	27,729	19,080	3,328
1982-83	2,735 (54.8)	393 (7.9)	1,858 (37.3)	4,986 (100.0)	29,457	20,425 ^(a)	3,735
1983-84	3,031 (47.7)	563 (8.8)	2,765 (43.5)	6,359 (100.0)	38,493	27,539 ^(a)	4,108
1984-85	3,580 (43.7)	693 (8.4)	3,926 (47.9)	8,199 (100.0)	44,394	31,226 ^(a)	5,100
1985-86	5,757 (76.6)	1,010 (13.4)	753 (10.0)	7,520 (100.0)	52,474	38,692 ^(a)	6,104
1986-87	4,786 (51.6)	1,147 (12.4)	3,336 (36.0)	9,269 (100.0)	59,373	43,468 ^(a)	7,257
1987-88	5,832 (52.0)	1,521 (13.6)	3,864 (34.4)	11,219 (100.0)	68,523	49,300 ^(a)	8,779
1988-89	6,668 (57.3)	1,973 (16.9)	3,011 (25.8)	11,672 (100.0)	79,496	55,985 ^(a)	10,712
1989-90	7,917 (51.3)	2,298 (14.9)	5,218 (33.8)	15,433 (100.0)	92,300	63,903 ^(a)	12,919
1990-91	9,978 (53.1)	2,556 (13.6)	6,253 (33.3)	18,787 (100.0)	1,08,203	73,852 ^(a)	15,474
1991-92	9,374 (49.6)	1,864 (9.9)	7,662 (40.5)	18,900 (100.0)	1,24,099	83,228 ^(a)	17,338
1992-93 (सं.प्र.)*	9,118 (45.6)	2,214 (11.1)	8,656 (43.3)	19,988 (100.0)	1,40,079	92,344 ^(a)	19,552
1993-94 (सं.प्र.)*	10,207 (43.1)	2,188 (9.2)	11,312 (47.7)	23,707 (100.0)	1,58,144	1,02,351 ^(a)	21,740

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत हैं।

† आरक्षित निधि, जमा राशियाँ और अग्रिम, भविष्य निधियाँ, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण आदि शामिल हैं।

\$ इनमें आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार और भविष्य निधियों आदि से ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

* आंकड़े 23 राज्यों से संबंधित हैं।

(a) केन्द्र द्वारा राज्यों को उनके ओवरड्राफ्ट चुकाने के लिए 1982-83, 1983-84, 1985-86 में दिये गये क्रमशः 1,74.3 करोड़ रुपये 400 करोड़ रुपये और 1,628 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण शामिल हैं।

सं.प्र. - संशोधित अनुमान।

सं.प्र. - बजट अनुमान।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी III. 8: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण@

(करोड़ रुपये)

मदें	1993-94* (ब.अ.)	1992-93 (सं.अ.)	1992-93 (ब.अ.)	1991-92 (लेखा)	प्रतिशत (3)/(5)	घट-बढ़ (2)/(3)
1	2	3	4	5	6	7
I. कुल प्राप्तियाँ	2,22,066	2,06,019	2,00,475	1,88,505	9.3	7.8
(अ) राजस्व प्राप्तियाँ	1,59,872	1,47,655	1,45,148	1,27,405	15.9	8.3
उनमें से :						
कर प्राप्तियाँ (क+ख)	1,30,956	1,18,703	1,16,612	1,02,674	15.6	10.3
(क) प्रत्यक्ष कर	26,000	23,086	21,404	19,040	21.3	12.4
(ख) अप्रत्यक्ष कर	1,04,956	95,617	95,208	83,634	14.3	9.8
(आ) पूँजीगत प्राप्तियाँ	62,194	58,364	55,327	61,000	-4.5	6.6
II. कुल संवितरण (अ+आ+इ)	2,29,020	2,14,477	2,05,776	1,95,456	9.7	6.8
(अ) विकास संबंधी व्यय (क+ख+ग)	1,21,080	1,17,378	1,11,253	1,08,766	7.9	3.1
(क) राजस्व	89,618	87,924	82,293	81,013	8.5	1.9
(ख) पूँजीगत परिव्यय	19,363	18,269	18,008	16,221	12.6	6.0
(ग) ऋण और अग्रिम	12,099	11,185	10,952	11,532	-3.0	8.0
(आ) विकासेतर व्यय (क+ख+ग)	98,069	85,720	85,640	72,956	17.5	14.4
(क) राजस्व	91,339	79,525	79,262	67,303	18.2	14.9
(ख) पूँजी	6,207	5,699	5,912	5,275	8.0	8.9
(ग) ऋण और अग्रिम	523	496	466	378	31.2	8.3
इ. अन्य	9,871	11,379	8,883	13,734	-17.1	-13.3
III. समग्र अधिशेष (+)/घटा (-)	-6,954	-8,458	-5,301	-6,951	21.7	-17.8

@ केन्द्र सरकार के राजस्व खाते के संबंध में वाणिज्यिक विभागों को मिलाकर।

* बजट प्रस्तावों की राशि सम्मिलित है।

टिप्पणी: (1) जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, ये आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें से 11 लेखा अनुदान बजट से हैं।

(2) अन्य वितरणों में आंतरिक और विदेशी ऋण की चुकौती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन, आकस्मिक निधियों में विनियोजन एवं निवल प्रेषण शामिल हैं तथा इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने बजट में उल्लिखित राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार की ऋणों की चुकौती संबंधी आंकड़ों में अन्तर के लिए समायोजित किया गया है।

ब.अ. - बजट अनुमान।

सं.अ. - संशोधित अनुमान।

स्रोत: भारत सरकार और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी III. 9: केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विकास संबंधी तथा विकासेतर व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र सरकार			राज्य सरकारें				केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति			
	विकास संबंधी व्यय	विकासे-तर व्यय	कुल	विकास संबंधी व्यय	विकासे-तर व्यय	अन्य*	कुल	विकास संबंधी व्यय	विकासे-तर व्यय	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1980-81	13,932 (57.6)	10,245 (42.4)	24,177 (100.0)	15,961 (70.1)	4,289 (18.8)	2,520 (11.1)	22,770 (100.0)	25,845 (66.0)	11,977 (30.6)	1,338 (3.4)	39,160 (100.0)
1981-82	16,084 (60.9)	10,311 (39.1)	26,415 (100.0)	17,960 (70.2)	4,996 (19.6)	2,615 (10.2)	25,571 (100.0)	28,796 (64.7)	13,609 (30.6)	2,074 (4.7)	44,479 (100.0)
1982-83	19,557 (60.7)	12,673 (39.3)	32,230 (100.0)	20,649 (71.0)	5,883 (20.2)	2,585 (8.8)	29,097 (100.0)	33,643 (64.6)	16,473 (31.7)	1,941 (3.7)	52,057 (100.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1983-84	22,207 (58.8)	15,564 (41.2)	37,771 (100.0)	23,972 (71.2)	6,882 (20.4)	2,814 (8.4)	33,668 (100.0)	38,352 (63.9)	19,936 (31.3)	1,701 (2.8)	59,989 (100.0)
1984-85	27,275 (59.6)	18,525 (40.4)	45,900 (100.0)	27,958 (70.3)	8,340 (21.0)	3,448 (8.7)	39,746 (100.0)	46,265 (64.6)	23,390 (32.6)	1,999 (2.8)	71,654 (100.0)
1985-86	29,979 (58.9)	20,927 (41.1)	50,906 (100.0)	31,753 (70.7)	9,617 (21.4)	3,519 (7.9)	44,869 (100.0)	55,032 (65.1)	27,332 (32.4)	2,106 (2.5)	84,470 (100.0)
1986-87	35,498 (57.7)	26,060 (42.2)	61,558 (100.0)	36,827 (70.6)	11,220 (21.5)	4,149 (7.9)	52,196 (100.0)	64,441 (63.4)	33,682 (33.2)	3,479 (3.4)	1,01,602 (100.0)
1987-88	26,573 (54.7)	30,261 (45.3)	66,834 (100.0)	42,141 (70.2)	13,754 (22.9)	4,104 (6.9)	59,999 (100.0)	69,087 (62.2)	39,460 (35.5)	2,814 (3.3)	1,11,161 (100.0)
1988-89	41,536 (53.9)	35,579 (46.1)	77,115 (100.0)	47,064 (69.8)	15,803 (23.4)	4,699 (6.8)	67,466 (100.0)	78,983 (61.6)	45,940 (35.8)	3,322 (2.6)	1,28,245 (100.0)
1989-90	54,204 (56.9)	41,020 (43.1)	95,224 (100.0)	53,150 (69.2)	19,253 (25.1)	4,406 (5.7)	76,809 (100.0)	89,386 (60.5)	54,300 (36.8)	3,939 (2.7)	1,47,625 (100.0)
1990-91	58,645 (54.3)	49,367 (45.7)	1,08,012 (100.0)	62,831 (68.8)	23,162 (25.4)	5,295 (5.8)	91,288 (100.0)	98,151 (58.8)	63,973 (38.3)	4,759 (2.9)	1,66,883 (100.0)
1991-92+	61,807 (54.0)	52,693 (46.0)	1,14,500 (100.0)	73,932 (64.3)	27,814 (24.2)	13,235 (11.5)	1,14,981 (100.0)	1,08,766 (55.7)	72,956 (37.3)	13,734 (7.0)	1,93,458 (100.0)
1992-93+ (संश्रु.)	65,877 (51.2)	62,814 (48.8)	1,28,691 (100.0)	79,948 (65.2)	32,729 (26.7)	9,918 (8.1)	1,22,595 (100.0)	1,17,378 (54.7)	85,720 (40.0)	11,379 (5.3)	2,14,477 (100.0)
1993-94+ (ब.प्र.)	65,245 (48.0)	70,554 (52.0)	1,35,799 (100.0)	85,430 (64.0)	39,073 (29.3)	9,021 (6.7)	1,33,524 (100.0)	1,21,080 (52.9)	98,069 (42.8)	9,871 (4.3)	2,29,020 (100.0)

- † केन्द्र सरकार के राज्य खाते के संबंध में वार्षिक विवरण शामिल हैं।
- (ii) इसमें आन्तरिक और विदेशी ऋणों की चुकोती शामिल नहीं है।
- * इसमें आन्तरिक ऋणों की चुकोती, केन्द्र की ऋण की चुकोती, धन प्रेषण (चिबल) तथा आकस्मिक निधि के लिये वित्तियोजन, स्थानीय निकायों और पंचायती राज मंत्रालयों की क्षतिपूर्ति तथा समन्वय की राशि शामिल हैं।
- §§ इसमें आन्तरिक और विदेशी ऋण की चुकोती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज मंत्रालयों की राज मंत्रालयों की मुद्रावृद्धि और समन्वय, आकस्मिक निधियों के लिए वित्तियोजन, राज्य सरकारों के निवल प्रेषण शामिल हैं तथा उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने बजट में उल्लिखित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की ऋणों की चुकोती संबंधी आकड़ों में अन्तर के लिए समायोजित किया गया है।
- † जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, ये आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं, जिनमें से 11 नेत्रा अनुदान बजट से हैं।
- बजट - बजट अनुमान संश्रु. - संशोधित अनुमान
- टिप्पणी : 1. आंकड़ों में दिये गये आंकड़े संबंधित कुल व्यय में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
2. अंतरसरकार समायोजनों के कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के आंकड़ों का जोड़ समूह स्थिति से मेल नहीं खाता है।
3. 1989-90 से पूर्व केन्द्र सरकार से व्यय संबंधी आंकड़ों में रेलवे पर किये गये पूंजीगत व्यय तथा अन्य व्यय जमा राशियों पर राज्यों की दिये गये ऋणों की हिसाब से नहीं लिया गया है।
- स्रोत : अंतरसरकार और राज्य सरकारों के बजट प्रत्यक्ष।

परिशिष्ट तालिका III, 10: केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र (सकल)			राज्य-†			केन्द्र और राज्य सरकार संयुक्त		
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2,907	10,242	13,149	686	5,929	6,615	8,593	16,171	19,764
(क)	21.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	18.2	81.8	100.0
(ख)	2.1	7.6	9.7	0.5	4.4	4.9	2.7	11.9	14.6
1984-85	4,626	18,802	23,428	1,230	11,108	12,338	5,856	29,910	35,766
(क)	19.7	80.7	100.0	10.0	90.0	100.0	16.4	83.6	100.0
(ख)	2.0	8.2	10.2	0.6	4.8	5.4	2.5	13.0	15.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1985-86	5,563	23,109	28,672	1,401	12,919	14,320	6,964	36,028	42,992
(क)	19.4	80.6	100.0	9.8	19.0	100.0	16.2	83.8	100.0
(ख)	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4
1986-87	6,134	26,559	32,793	1,685	14,934	16,619	7,919	41,433	49,412
(क)	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0
(ख)	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	14.1	16.8
1987-88	6,751	30,861	37,612	1,960	17,438	19,398	8,711	48,299	57,010
(क)	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0
(ख)	2.0	9.3	11.3	0.6	5.2	5.8	2.6	14.5	17.1
1988-89	8,824	35,596	44,420	2,413	19,988	22,401	11,237	55,584	66,821
(क)	19.9	80.1	100.0	10.8	89.2	100.0	16.8	83.2	100.0
(ख)	2.2	9.0	11.2	0.6	5.1	5.7	2.8	14.1	16.9
1989-90	10,093	41,578	51,581	3,006	22,989	25,995	13,009	64,567	77,576
(क)	19.4	80.6	100.0	11.6	88.4	100.0	16.8	83.2	100.0
(ख)	2.2	9.2	11.4	0.7	5.1	5.8	2.9	14.3	17.2
1990-91	11,024	46,489	57,513	3,244	26,804	30,048	14,268	73,243	87,561
(क)	19.2	80.8	100.0	10.8	89.2	100.0	16.5	83.7	100.0
(ख)	2.5	8.8	11.0	0.6	5.1	5.7	2.7	13.9	16.6
1991-92	15,200	52,066	67,266	3,840	31,567	35,407	19,040	83,633	1,02,673
(क)	22.6	77.4	100.0	10.8	89.2	100.0	18.5	81.5	100.0
(ख)	2.5	8.5	11.0	0.6	5.2	5.8	3.1	13.7	16.8
1992-93*									
(म.प्र.) (क)	18,877	59,827	78,704	4,209	35,790	39,989	23,086	95,617	1,18,703
(ख)	24.0	76.0	100.0	10.5	89.5	100.0	19.4	80.6	100.0
1993-94*									
(ब.अ.) (क)	21,261	63,527	84,788	4,739	41,429	46,168	26,000	1,04,956	1,30,956
(ख)	25.1	74.9	100.0	10.3	89.7	100.0	19.9	80.1	100.0
	2.7	6.1	10.8	0.6	5.3	5.9	3.3	13.4	16.7

† हममें केन्द्रीय बजट प्रलेखों में सूचित केन्द्रीय करो में राज्यों के अंश को शामिल नहीं किया गया है।
 * राज्य सरकारों के संबंध में साफ़ 25 राज्यों से संबंधित है जिनमें से 11 लेखा अनुदान बजट से हैं।
 टिप्पणी : (क) कुल कर राजस्व का प्रतिशत दर्शाता है और (ख) सकल देशी उत्पाद के अनुपात की तुलना में प्रतिशत दर्शाता है।
 स्रोत : भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट प्रलेख।

परिशिष्ट भाग III. 11. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा प्रायोजित स्थानीय प्राधिकरण एवं संस्थाओं के बाजार उधार (करोड़ रुपये)

सरकारी/प्राधिकरण	सकल बाजार उधार		चुकोलिया		निम्न बाजार उधार	
	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6	7
1. केन्द्र सरकार	4,821	8,919	1,151	1,418	3,670	7,501
2. राज्य सरकार	3,805	3,364	334	..	3,471	3,364
3. केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित संस्थाएं	2,248	2,702	498	14	1,750	2,688
4. राज्य सरकारों द्वारा प्रयोजित संस्थाएं (इनमें स्थानीय प्राधिकरण तथा राज्य भूमि विकास बैंक शामिल हैं)	1,223	1,200	103	104	1,120	1,096
5. कुल बाजार उधार	12,097	16,185	2,086	1,536	10,011	14,649

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख।

परिशिष्ट सारणी III. 12 : केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिबृत्तियों पर छूट दरें

(प्रतिगत वार्षिक)

वर्ष	परिपक्वता अवधि वर्षों में	केन्द्र सरकार																	राज्य सरकार														
		3	5	6	7	8	9	10	15	18	20	23	28	30	10	13	15	20															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
1984-85		7.75	8.00				8.50			9.50		10.25	10.50				9.00																
1985-86		9.00		9.25			9.50			10.50	10.80		11.50				9.75																
1986-87		10.00		10.20			10.50		11.30	11.50							11.00																
1987-88						10.30	10.50	11.00		11.50							11.00																
1988-89		10.00					10.50	11.00		11.50							11.50																
1989-90							10.75	11.25		11.50							11.50																
1990-91		10.50					10.75	11.25		11.50							11.50																
1991-92		10.75					11.00	11.50		12.00							12.00																
							12.50										12.50																
1992-93		12.00	12.30	12.60	12.70		12.75																										
1993-94		12.75	13.00		13.25		13.40																										

छूट दर को 3 अक्टूबर 1991 और 26 मार्च 1992 को बहाकर क्रमशः 12.00 और 12.50 प्रतिगत कर दिया गया।

+ पूर्व घोषित।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख।

परिशिष्ट सारणी IV. 1 : मुद्रा स्टाक (ए म3) में घट बढ़-बटक की रकम

(करोड़ रुपये)

वर्ष	31 मार्च	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़*																वर्धन-बुल	
		1992-93*																	
		राशि	प्रतिगत	राशि	प्रतिगत	राशि	प्रतिगत	राशि	प्रतिगत	राशि	प्रतिगत	राशि	प्रतिगत	राशि	प्रतिगत	राशि	प्रतिगत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1. एम3 (क+ख+ग)	3,62,665	45,184	14.2	51,653	19.4	18,391	5.1	19,452	6.1										
(क) जमा के पास चल मुद्रा	68,512	7,414	12.1	8,050	15.2	6,088	8.9	2,763	4.5										
(ख) बैंकों के पास कुल जमा राशि (i+ii)	2,92,650	37,152	14.5	43,392	20.5	9,171	3.1	11,690	4.6										
जिसमें से बाह्य जमा राशियाँ	34,116	5,843	20.7	5,632	24.8	1,124	3.3	5,069	17.9										
(i) सभी विदेशी चल मुद्रा जमा राशियाँ	25,500	5,061	24.8	4,824	30.9	499	2.0	4,291	21.0										
(ii) अतिवासी विदेशी जमा राशियाँ	8,616	782	10.0	808	11.5	625	7.3	778	9.9										

(करोड़ रुपये)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. नांग जमा राशिवा		53,263	408	0.8	13,685	34.9	-873	-1.6	-711	-3.3
2. भिमादी जमा राशिवा		2,39,387	36,744	18.1	20,707	17.2	10,044	4.2	12,401	6.1
(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास "अन्य जमा राशिवा"		1,503	618	69.8	211	31.3	3,132	202.4	4,939	524.9
III. मुद्रा स्टॉक के स्टॉक (एस.3) (1+2+3+4+5)		1,23,278	8,440	7.3	21,946	23.6	8,347	6.8	7,051	6.1
1. सरकार को निवल बैंक ऋण (अ+आ)		1,76,089	17,826	11.3	18,070	12.9	13,654	7.8	6,442	4.1
अ. सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण (1+ii)†		98,449	4,433	4.7	5,168	5.8	7,303	7.4	2,320	2.5
(i) केन्द्रीय सरकार पर निवल ऋण (क+ख)		96,523	4,257	4.6	5,508	6.3	9,201	9.5	3,913	4.2
(क) केन्द्रीय सरकार पर ऋण		97,621	3,273	3.5	5,904	6.7	8,158	9.4	1,406	2.0
(ख) केन्द्रीय सरकार की जमा राशिवा		1,098	-984	-47.3	396	23.5	-1,043	-95.0	-2,007	-96.4
(ii) राज्य सरकारों पर निवल ऋण (क+ख)		1,926	176	10.1	-340	-16.3	-1,892	-98.5	-1,593	-91.9
(क) राज्य सरकारों पर ऋण		1,926	176	10.1	-340	-16.3	-1,880	-97.6	-1,577	-90.1
(ख) राज्य सरकारों की जमा राशिवा		0	0	—	0	—	18	—	16	—
आ. सरकार की अन्य बैंकों के ऋण		77,640	13,393	20.8	12,902	25.1	6,351	8.2	4,122	6.2
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (अ+आ)		2,16,374	28,380	15.1	16,225	9.4	3,916	1.8	8,811	4.7
अ. वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण (ए)		6,220	-1,040	-14.3	918	14.5	179	2.9	93	1.3
आ. वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण		2,10,154	29,420	16.3	15,307	9.3	3,737	1.8	3,718	4.8
3. वैदेशिक क्षेत्र को निवल विदेशी मुद्रा आनिर्वा (अ+आ)‡		25,681	3,809	17.4	11,291	106.7	1,681	6.5	949	3.9
अ. भारतीय रिजर्व बैंक को निवल विदेशी मुद्रा आनिर्वा		22,647	3,809	20.2	10,855	136.0	1,681	7.4	949	4.5
आ. अन्य बैंकों को निवल विदेशी मुद्रा आनिर्वा		3,034	0	0.0	436	16.8	—	—	—	—
4. जनता के प्रति सरकार की वत मुद्रा देयताएं		1,798	94	5.5	83	5.1	15	0.8	31	1.8
5. सीमादी जमा राशिवा के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं (अ+आ)		57,277	4,925	9.4	-5,984	-10.3	875	1.5	-3,319	-6.3
अ. भारतीय रिजर्व बैंक को निवल मुद्रा देयताएं‡		28,056	641	2.3	393	1.5	-270	-1.0	-2,205	-8.0
आ. अन्य बैंकों को निवल मुद्रा देयताएं (पब्लिश)		29,221	4,284	17.2	-6,377	-20.4	1,145	3.9	-1,114	-4.5

* अनुविभाग

† विदेश प्रभारिता शामिल है और 31 मार्च 1993 के लिए इनमें कोई वृद्धि के लिए अनुविभागीय मुद्रा कोष

को हिस्से में शामिल किया गया है। अनुविभाग (211) 95 मिलियन विदेशी मुद्रा देयता के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

‡ अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

** अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

†† अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

‡ अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

‡ अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

‡ अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

‡ अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

‡ अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

‡ अनुविभाग (अनुविभाग) के अलावा बैंक क्षेत्र को निवल मुद्रा देयताएं

परिशिष्ट सारणी 4 2 : प्रारम्भित मुद्रा में घट-बढ़ घटक और स्त्रोत

(करोड़ रुपये)

सर्वे	31 मार्च, 1993 को बकाया*	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़†							
		1992-93*		1991-92		1993-94†		1992-93	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रारम्भित मुद्रा (1+2+3+4)	1,10,943	11,433	11.5	11,726	13.4	3,933	3.5	6,068	6.1
1 जनता के पास बाल मुद्रा	68,512	7,414	12.1	8,050	15.2	6,088	8.9	2,763	4.5
2 भारतीय रिजर्व बैंक के पास 'शून्य' जमा राशियाँ	1,593	618	69.8	211	31.3	3,132	208.4	4,999	564.9
3 बैंकों के पास सरकारी	2,788	148	5.6	496	18.2	107	3.8	305	11.6
4 भा. रि. बैं. के पास बैंकों की जमा राशियाँ	38,140	3,258	9.3	3,059	9.6	—5,484	—14.4	—1,999	—5.7
प्रारम्भित मुद्रा के स्त्रोत (1+2+3+4+5+6)									
1 सरकार को भा. रि. बैं. का निवल ऋण ‡	98,449	4,433	4.7	5,168	5.8	7,393	7.4	2,320	2.5
जिसमें से : केन्द्र सरकार को	96,523	4,257	4.6	5,508	6.3	9,201	9.5	3,913	4.2
2 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर भा. रि. बैं. के ऋण @	9,885	4,783	93.7	—4,905	—49.0	—5,615	—56.8	570	11.2
3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा. रि. बैंक का ऋण	6,220	—1,040	—14.3	918	14.5	179	2.9	93	1.3
4 भा. रि. बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ**	22,647	3,909 (2,369)	20.2 (12.6)	10,855 (9,141)	136.0 (114.5)	1,681 (462)	7.4 (2.0)	849 (1,049)	4.5 (5.6)
5 जनता के प्रति सरकार को मुद्रा देनाएं	1,798	94	5.3	83	5.1	15	0.8	31	1.8
6 भा. रि. बैं. की निवल मुद्रा देनाएं**	28,056	641	2.3	393	1.5	—270	—1.0	—2,205	—8.0
भा. रि. बैं. की निवल विदेशी आस्तियाँ।	88,296	7,629	9.5	871	1.1	2,152	2.4	5,219	6.5

*घनत्वित कोटकों में दिये गये आंकड़ों में स्थण पुनर्मूल्यांकन शामिल नहीं है।

@माबाई सहित

**17 फरवरी 1990 से पचासी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आसपास पुनर्मूल्यांकन के बाद वर्षों के मूल्य में हुई वृद्धि शामिल है। ऐसे अधिभूत का रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देनाओं पर तदनुक प्रभाव पड़ता है। कोष्ठ में दिये गये आंकड़े ऐसे पुनर्मूल्यन को छोड़कर हैं।

‡31 मार्च से संबंधित आंकड़ों पर आधारित।

†विशेष प्रतिलियाँ भी शामिल हैं और 31 मार्च, 1993 के लिए इसमें 752 करोड़ रुपये (211.95 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के बराबर) अर्ह राशि शामिल हैं जो कोटा वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्जित परिसंपत्ति अभिवान के रूप में दिये हुए वर्ष की गयी थी।

परिशिष्ट सारणी 4.3 : चल मुद्रा के धाय बैग, सकल जमाराशियाँ, एम¹ और एम² की प्रवृत्तियाँ

	औसत* (करोड़ रुपये)				धाय बैग अनुपात			
	चल मुद्रा	कुल जमाराशियाँ	एम ¹	एम ²	सकल घरेलू उत्पाद/चल मुद्रा	सकल घरेलू/सकल जमाराशियाँ	सकल घरेलू/उत्पाद/एम ¹	सकल घरेलू/उत्पाद/एम ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987-88	31,490	1,21,744	53,039	1,53,546	10.563	2.732	6.155	2.166
1988-89	35,934	1,43,556	61,877	1,79,884	10.992	2.751	6.384	2.196
1989-90	42,678	1,70,554	74,370	2,13,807	10.558	2.642	6.059	2.108
1990-91	50,046	1,98,066	87,375	2,49,282	10.581	2.674	6.061	2.124
1991-92	57,675	2,33,125	1,04,194	2,92,260	10.568	2.614	5.850	2.085
1992-93	64,802	2,76,512	1,20,407	3,45,376	10.848	2.542	5.839	2.035

*वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग शुक्रवारों के औसत।

@अनन्तिम

परिशिष्ट सारणी 4.4 : मीट्रिक अनुपात

मर्के	1992-93@	1991-92	1990-91	1910-90	1988-89	1987-88
1	2	3	4	5	6	7
अंक-वर-अंक आधार पर						
(बुद्धिशील अनुपात)						
(क) चलमुद्रा/कुल जमाराशियाँ (सी/एडी)	0.234	0.239	0.241	0.296	0.198	0.298
(ख) चलमुद्रा/एम ² (सी/एम ²)	0.189	0.192	0.193	0.213	0.163	0.229
(ग) कुल जमाराशियाँ/एम ² एडी/एम ²)	0.807	0.805	0.804	0.790	0.827	0.767
(घ) स्थूल मुद्रा गुणक (एम ² /घार एम)	3.269	3.191	3.423	2.560	3.086	2.608
(ङ) संकीर्ण मुद्रा गुणक (एम ¹ /घार एम)	1.111	1.154	1.161	0.975	0.869	0.811
(च) बैंक की प्रारम्भित निधि/कुल जमाराशियाँ (घार/एडी)	0.140	0.147	0.120	0.228	0.182	0.197
औसत आधार पर						
(बुद्धिशील अनुपात)						
(क) चलमुद्रा/कुल जमाराशियाँ (सी/एडी)	0.234	0.262	0.268	0.204	0.204	0.244
(ख) चलमुद्रा/एम ² (सी/एम ²)	0.188	0.209	0.208	0.199	0.169	0.196
(ग) कुल जमाराशियाँ/एम ² (एडी/एम ²)	0.801	0.798	0.776	0.796	0.828	0.802
(घ) स्थूल मुद्रा गुणक (एम ² /घार एम)	3.200	3.109	3.026	3.159	3.127	2.482
(ङ) संकीर्ण मुद्रा गुणक (एम ¹ /घार एम)	1.116	1.108	1.109	1.163	0.930	0.772
(च) बैंक की प्रारम्भित निधि/कुल जमाराशियाँ (घार/एडी)	0.141	0.150	0.116	0.138	0.179	0.255

टिप्पणी : (1) अनन्तिम आधार पर, अनुपात 31 मार्च के माफ़ि पर आधारित हैं, जबकि औसत आधार पर, अनुपात, वर्ष के रिपोर्टिंग शुक्रवार के औसत के आधार पर निकाले गये हैं। इस सारणी में दिये गये सभी अनुपात बुद्धिशील अनुपात हैं।

(2) अंक-वर-अंक आधार पर यहाँ दर्शाये गये अनुपात पूर्वे रिपोर्टों में दिये गये अनुपातों से भिन्न हैं, क्योंकि उनका आधार मार्च का अन्तिम रिपोर्टिंग शुक्रवार था।

@ अनन्तिम

परिशिष्ट सारणी IV. 5 : महत्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक—अनुसूचित बाण्ड्य बैंक

(करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित विरुद्ध वर्ष में घट-अवृ						
1	2 19 मार्च 1993 को बकाया	3 1992-93	4 1991-92	5 1990-91	(अप्रैल-जून)	
					6 1993-94	7 1992-93
1. कुल मांग और सीमादी देयताएँ (आरिबैं/बाओबिबैं/माबाई से उधार को छोड़कर)	2,97,709	45,914	39,709	26,251	10,428	16,380
		(18.2)	(18.7)	(14.1)	(3.5)	(6.5)
2. कुल जमा राशिबां (क+ख)	2,68,572	27,814	38,216	26,583	8,664	12,256
		(16.4)	(19.8)	(15.3)	(3.2)	(5.3)
(क) मांग जमा राशिबां	46,461	1,373	11,895	4,337	744	159
		(3.0)	(35.3)	(15.0)	(1.6)	(0.4)
(ख) सीमादी जमा राशिबां	2,22,111	36,441	26,321	21,246	9,407	12,097
		(19.6)	(16.5)	(15.4)	(4.2)	(6.5)
3. आ रि बें से उधार	1,619	1,042	—2,891	1,069	—1,020	1,039
		(180.5)	(—83.4)	(44.6)	(—63.0)	(180.0)
4. बैंक ऋण (क+ख)	1,51,982	25,390	9,291	14,848	3,534	9,052
		(21.0)	(8.0)	(14.6)	(2.3)	(6.4)
(क) बाण्ड्य ऋण	6,743	2,073	164	2,500	2,833	431
		(44.4)	(3.6)	(124.6)	(42.0)	(9.2)
(ख) बाओबिबैं ऋण	1,45,239	24,317	9,127	12,348	701	7,621
		(20.1)	(8.2)	(12.4)	(0.5)	(6.3)
5. निवेश (क+ख)	1,05,656	13,460	14,131	10,696	6,137	4,291
		(17.1)	(20.2)	(16.6)	(5.8)	(4.8)
(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	75,945	13,218	12,729	6,706	6,733	4,076
		(21.1)	(15.5)	(18.2)	(8.2)	(6.5)
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	79,711	2,242	2,402	2,990	—97	215
		(8.2)	(9.6)	(13.5)	(—0.3)	(0.8)
6. गैर बैंक ऋण	2,293	285	204	155	114	179
		(14.2)	(11.3)	(9.4)	(5.0)	(18.4)
7. आ रि बें के पास शेष जमा	28,585	—5,644	10,318	398	8,052	—2,226
		(—16.4)	(43.2)	(1.7)	(10.7)	(—6.5)
8. ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	56.6	56.6	54.4	60.4	56.1	55.0
9. बाओबिबैं ऋण—जमा अनुपात (प्रतिशत)	54.1	54.1	52.4	58.1	52.6	56.1

* प्रस्तुति

(ॐ) संबंधित अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को बकाया से संबंधित अनुपात।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-अवृ को दर्शाते हैं।

2. आंकड़ों को पूर्णांकित किये जाने के कारण घटक सदों के कुल जोड़ से मेल नहीं खायेगे।

3. घातात्मक बंक के लिए कोई चिह्न नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट सारणी 4.6 : मार्च के अंतिम सप्ताह में अनुसूचित जाण्डिय बेंकों की बुनिदा मटों में षट-बढ़

निम्नलिखित तारीख को बकाया																(करोड़ रुपये)
मद	षट-बढ़															
	20 मार्च 1992	19 मार्च 1993	26 मार्च 1993	31 मार्च 1993	2 अप्रैल 1993	16 अप्रैल 1993	30 मार्च 1992	20 मार्च 1993	19 मार्च 1993	26 मार्च 1993	31 मार्च 1993	1 मार्च 1993	31 मार्च 1993	2 अप्रैल 1993	16 अप्रैल 1993	
								की तुलना में	की तुलना में	की तुलना में	की तुलना में	की तुलना में	की तुलना में	की तुलना में	की तुलना में	
1. कुल	2,30,758	2,68,572	2,74,938	2,81,085	2,79,860	2,75,539	2,75,502	37,814	6,366	6,147	12,513	12,513	-1,225	-4,321	-37	
अमराशिया								(16.4)	(2.4)	(2.2)	(4.7)	(4.7)	(-0.4)	(-1.5)	(0.0)	
(क+ख)									(16.8)	(16.3)	(33.1)	(33.1)	(3.2)	(11.4)	(0.1)	
(क) मांग	45,088	46,461	49,541	53,908	52,761	48,655	47,455	1,373	3,080	49,367	7,447	7,447	-1,147	-4,106	-1,206	
अमराशिया								(3.0)	(6.6)	(8.8)	(16.0)	(16.0)	(-2.1)	(-7.8)	(-2.5)	
(ख) मावधि	1,85,670	2,22,111	2,25,397	2,27,177	2,27,099	2,26,884	2,28,047	36,441	3,286	1,780	5,066	5,066	-78	-215	1,163	
अमराशिया								(19.6)	(1.5)	(0.8)	(2.3)	(2.3)	(0.0)	(-0.1)	(0.5)	
									(9.0)	(4.9)	(13.9)	(13.9)	(0.2)	(0.6)	(3.2)	
3. बैंक रूप	1,25,592	1,51,982	1,54,838	1,59,356	1,58,763	1,57,832	1,55,819	26,390	2,856	4,518	7,374	7,374	-593	-931	-2,03	
(क+ख)								(21.0)	(1.9)	(2.9)	(4.9)	(4.9)	(0.4)	(-0.6)	(-1.3)	
									(10.8)	(17.1)	(27.9)	(27.9)	(2.2)	(3.5)	(7.6)	
(क) खास रूप	4,670	6,743	6,788	7,010	7,010	6,598	7,412	2,073	45	222	267	267	0	-422	82	
								(44.4)	(0.7)	(3.3)	(4.0)	(4.0)	(0.0)	(6.0)	(12.5)	
(ख) खास रूप	1,20,922	1,45,239	1,48,050	1,52,346	1,51,753	1,51,244	1,48,407	24,317	2,811	4,296	7,107	7,107	-593	-509	-2,837	
								(20.1)	(1.9)	(2.9)	(4.9)	(4.9)	(0.4)	(-0.3)	(-1.9)	
									(11.6)	(17.7)	(29.2)	(29.2)	(2.4)	(2.1)	(11.7)	

टिप्पणी 1. लघु कोष्ठकों में दिय गये आंकड़े प्रतिशत में षट बढ़ दर्शाते हैं।

2. चौकीर कोष्ठकों में दिय गये आंकड़े वित्त वर्ष के षट बढ़ के प्रतिशत के रूप में पूर्ण षट बढ़ दर्शाते हैं।

3. घनत्वक बढ़न के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV. 7 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर जमा-संसाधन

(करोड़ रुपये)

महें	निम्नलिखित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग मंथवार को बकाया			घट-बढ़	
	1993	1992	1991	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6
1. कुल जमा-संसाधन	2,68,572	2,30,758	1,92,542	37,814	38,216
				(16.4)	(19.8)
2. सकल मांग और मीयादी देयताएं	2,97,709	2,51,795	2,12,086	45,914	39,709
				(18.2)	(18.7)
3. बैंकिंग प्रणाली की प्राप्ति	11,043	7,927	5,582	3,116	2,343
				(39.3)	(42.0)
4. अंतर बैंक प्राप्ति से इतर सकल मांग और जिबादी देयताएं (2-3)	2,86,666	2,43,868	2,06,504	42,798	37,364
				(17.5)	(18.1)
5. घातर (4-1)	18,094	13,110	13,062	4,984	— 852
				(38.0)	(— 6.1)
6. धन्य उधार	112	362	470	-250	-108
				(-69.1)	(-23.0)
7. वित्तीय संस्थाओं से बिल पुनर्भुनाई	779	3,874	3,479	-3,095	395
				(-79.9)	(11.4)
8. गैर जमा संसाधन (5+7)	18,873	16,984	17,441	1,889	— 457
				(11.1)	(-2.6)
हापन मद					
भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय मित्रीकाटा और बिल गृह से मांग मुद्रा उधार*	8,203	1,212	2,275	6,991	-1,063
				(576.8)	(-46.7)

कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े प्रतिशत से घट-बढ़ को दर्शाते हैं।

*मार्च 1991, मार्च 1992 और मार्च 1993 के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नाबाई और धन्य से उधार संबंधी प्रांकड़े शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी IV. 8 : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित तारीखों को बकाया			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़	
	मार्च 19 1993	मार्च 20 1992	मार्च 22 1991	अप्रैल-मार्च 1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6
(1) सकल बैंक ऋण (1+2)	1,47,071	1,26,005	1,18,019	21,066	7,986
1. सार्वजनिक खाद्य वसूली ऋण	6,743	4,670	4,506	2,073	164
2. खाद्येतर सकल बैंक ऋण	1,40,328	1,21,335	1,13,513	18,993	7,822
				(100.0)	(100.0)
(अ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	49,758	45,425	42,915	4,333	2,510
	(35.0)	(38.7)	(39.3)	(22.8)	(32.1)
(1) कृषि	19,884	18,157	16,750	1,727	1,407
	(14.0)	(15.5)	(15.3)	(9.1)	(18.0)
(2) लघु उद्योग	20,027	18,150	17,181	1,877	969
				(9.9)	(12.4)
(3) धन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	9,847	9,118	8,984	729	134
				(3.8)	(1.7)
(आ) उद्योग (महोले और बड़े)	58,627	47,090	44,508	11,537	2,58
				(60.7)	(33.0)

1	2	3	4	5	6
(इ) घोक व्यापार (खाद्यान्न वस्तुओं से इतर)	6,909	6,154	5,910	755	244
				(4.0)	(3.1)
(1) भारतीय रूई निगम	224	208	91	16	11
				(6.1)	(1.5)
(2) भारतीय खाद्य निगम (उर्वरक वितरण के लिए)	24@	21	212	3	191
				(0.0)	(-2.4)
(3) भारतीय जूट निगम	122	70	62	52	8
				(0.3)	(0.1)
(4) अन्य व्यापार	6,539	5,855	5,545	684	310
				(3.6)	(4.0)
(ई) ग्राम्य क्षेत्र	25,034	22,666	20,180	2,368	2,486
				(12.5)	(31.8)
2. निर्यात ऋण [मव व (2) 1 के अन्तर्गत शामिल]	15,348	10,294	9,186	5,054	1,108
				(26.6)	(14.2)
3. निवल बैंक ऋण (अंतर बैंक सहभागिता सहित)	1,42,149	1,17,443	1,09,298	24,706	8,145

@ बैंक द्वारा लिये गये उच्च दम्भात्मक ऋण को दर्शाती है जिससे समाप्त किया जाना है।

- टिप्पणी : 1. ये आंकड़े अंतिम हैं और 48 अनुसूचित बाणिज्य बैंकों में संबंधित हैं जो समस्त अनुसूचित बाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को दर्शाते हैं। सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में भा.रि.बैं., भा.ओ.वि.बैं., एग्रीज बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा अंतर बैंक सहभागिता के साथ पुनः धुनाये गये बिलों को शामिल किया गया है।
2. सब कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण के प्रतिशत दर्शाते हैं।
3. चौकोर कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े मव III में दिये गये अन्तर-बैंक सहभागिता सहित निवल बैंक ऋण के समानुपाती हैं।

परिमिष्ट सारणी IV. 9 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण @

उद्योग	निम्नलिखित तारीखों को बकाया			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़	
	19 मार्च	20 मार्च	26 मार्च	अप्रैल-मार्च	
	1993	1992	1991		
				1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6
उद्योग	78,654	65,240	61,689	13,414	3,551
(सूती, मशीनें और बड़े उद्योगों का जोड़)					
1. कोयला	341	246	229	95	17
2. लोहा और इस्पात	5,691	3,692	3,292	1,999	400
3. अन्य धातुएं और धातु उत्पाद	2,691	2,312	2,227	379	85
4. सभी इ.जी.निर्यात उत्पाद	17,065	14,842	13,931	2,223	911
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	2,308	2,092	1,874	216	218
5. बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन	1,405	1,298	1,152	107	146
6. सूती वस्त्र	4,665	4,278	4,073	387	205
7. जूट वस्त्र	349	330	339	19	-9
8. ग्राम्य वस्त्र	4,647	3,970	3,761	677	209
9. चीनी	1,254	899	639	355	260
10. चाय	791	658	608	133	50
11. खाद्य पदार्थों के अभिसंस्करण	1,423	1,241	1,216	182	25
12. धनस्पति तेल (धनस्पति सहित)	1,015	898	865	117	33
13. रम्भाकू और नम्बाकू उत्पाद	741	550	391	191	159
14. कागज और कागज उत्पाद	1,590	1,501	1,482	89	19
15. रबर और रबर की वस्तुएं	1,186	1,077	989	109	88
16. रसायन, रजक, पेंट आदि उनमें से	10,114	8,280	7,743	1,834	537
(1) उर्वरक	1,715	1,357	1,309	358	48
(2) पेट्रो-रसायन	943	614	680	329	-66
(3) दवाइयों और औषधियां	1,315	1,127	987	189	140

(करोड़ रुपये)

परिशिष्ट सारणी IV. II भारतीय मितिकाया और वित्त गृह IV. 11 लि. को रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त

महीने के अंतिम दिन को		नौजामी के जरिये बेचे गये खजाना बिलों के छात्रागियों की जमानत पर पुनर्वित्त				अल्पावधि वाणिज्यिक बिलों की जमानत पर पुनर्वित्त				केन्द्रीय सरकार की विनियमित प्रविष्टियों की जमानत पर पुनर्वित्त			
माँसा	बकाया	महीने के दौरान प्रयुक्त अधिकतम राशि	स्तरण 4 में दर्शाया गया अधिकतम प्रयुक्त राशि के अनुरूप माँसा	माँसा	बकाया	महीने के दौरान प्रयुक्त अधिकतम राशि	स्तरण 4 में दर्शाया गया अधिकतम प्रयुक्त राशि के अनुरूप माँसा	माँसा	बकाया	महीने के दौरान प्रयुक्त अधिकतम राशि	स्तरण 12 दर्शाया गया अधिकतम प्रयुक्त राशि के अनुरूप माँसा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1992													
मार्च	600.00	कुछ नहीं	580.48 (28-2-92)	600.00	50.00	कुछ नहीं	50.00	50.00	--	--	--	--	
जून	100.00	26.55	87.75 (19-5-92)	100.00	200.00	151.30	200.00	200.00	100.00	18.00	100.00	100.00	
सितंबर	100.00	1.15	100.00 (7-9-92)	100.00	100.00	कुछ नहीं	--	100.00	100.00	कुछ नहीं	--	100.00	
दिसंबर	100.00	57.69	57.69 (30-12-92)	100.00	100.00	कुछ नहीं	--	100.00	100.00	कुछ नहीं	100.00	100.00	
1993													
मार्च	300.00	कुछ नहीं	288.91 (23-3-93)	300.00	100.00	कुछ नहीं	100.00	100.00	100.00	कुछ नहीं	41.85 (30-3-93)	100.00	
जून	100.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100.00	100.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100.00	100.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100.00	
जुलाई	100.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100.00	100.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100.00	100.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100.00	

परिशिष्ट सारणी IV. 12 मुद्रा बाजार लिखितों से भारतीय मितिकाय और वित्त गृह का संबंधी आवृत्ति

(करोड़ रुपये)

लिखित	राजकोषीय वर्ष		1993-94 के दौरान		वर्ष 1992-93 के 14 अप्रैल 1992 तक
	1992-93	1991-92 (13 अप्रैल 1992 तक)	दौरान	दौरान	
1	2	3	4	5	
1. मांग सिधियां (नोटिस सिधियों सहित)	4,57,013	2,94,373	1,95,258		1,78,522
2. खजाना बिल	16,019	23,110	3,532		10,325
3. वाणिज्यिक बिल	786	6,995	16		560
4. जमा प्रमाणपत्र	33	32	119		6
5. वाणिज्यिक पत्र	--	42	--		--
6. सावधि जमा राशियां	3,797	5,959	991		2,341
7. केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	18,645	--	12,504		3,583

परिशिष्ट सारणी IV. 13 भारतीय मितिकाय और वित्त गृह लि. को पदत रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त की व्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

नीलामी द्वारा बेचे गये खजाना बिलों की धारिताओं पर पुनर्वित्त			वाणिज्यिक बिलों पर पुनर्वित्त			दिनांकित प्रतिभूतियों पर पुनर्वित्त		
प्रभावी तारीख	व्याज की दर	प्रभावी तारीख	व्याज की दर	प्रभावी तारीख	व्याज की दर	प्रभावी तारीख	व्याज की दर	प्रभावी तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1992		1992		1992				
जुलाई 1	10.00	जुलाई 1	17.00	जुलाई	12.00			
		जुलाई 11	15.00					
सितंबर 19	11.00							
21	10.00							
1993								
फरवरी 12	11.00							
13	10.00							
मार्च 15	11.00							
16	10.00							
20	11.00							
22	12.00							
अप्रैल 3	10.00							

परिशिष्ट सारणी IV. 14 भारतीय मितिकाय और वित्त गृह लि. की भाग उधार दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

न्यूनतम दिनांक को समाप्त पक्ष के लिए				न्यूनतम दिनांक को समाप्त पक्ष के लिए			
उधार दर		उधार दर		उधार दर		उधार दर	
अंश	निश्चर	मध्य दर का प्रोसेस*	अंश	निश्चर	मध्य दर का प्रोसेस*	अंश	निश्चर
1	2	3	4	5	6	7	8
1991				1992			
जुलाई 12	10.25	38.50	27.40	जुलाई 10	3.00	18.50	12.70
26	5.00	27.00	14.05	24	1.25	16.50	8.70
अगस्त 9	5.00	17.50	12.60	अगस्त 7	3.50	12.50	9.20
23	9.00	15.00	13.40	21	3.00	12.50	8.65

	1	2	3	4	5	6	7	8	
सितंबर	6	3.50	15.00	10.95	सितंबर	4	3.00	12.50	9.10
	20	3.00	14.50	10.85		18	3.00	12.00	10.15
अक्तूबर	4	5.00	50.00	18.60	अक्तूबर	2	2.00	14.00	10.10
	18	4.00	35.25	19.65		16	3.50	15.00	10.55
						30	3.00	13.25	8.40
नवंबर	1	10.00	24.50	14.90					
	15	15.00	36.00	23.25	नवंबर	13	4.50	11.75	10.20
	29	5.00	36.00	20.55		27	1.50	12.75	8.45
दिसंबर	13	2.00	21.00	9.35	दिसंबर	11	5.00	10.75	8.40
	27	2.50	18.25	9.60		25	9.00	11.75	10.05
1992					1993				
जनवरी	10	5.25	16.25	9.95	जनवरी	8	10.25	13.00	11.25
	24	4.00	10.75	9.25		22	5.00	11.75	10.65
फरवरी	7	2.75	10.00	8.40	फरवरी	5	3.00	11.50	9.80
	21	5.00	10.00	8.30		19	5.00	12.25	10.70
मार्च	6	4.50	9.75	8.75	मार्च	5	10.50	12.50	11.30
	20	2.00	20.25	10.50		19	5.00	13.50	11.85
अप्रैल	3	6.00	15.00	26.70	अप्रैल	2	5.00	25.00	16.55
	17	4.00	36.50	18.00		16	2.00	20.00	10.00
मई	1	20.00	86.00	42.05		30	4.00	10.75	8.30
	15	6.00	51.00	34.15	मई	14	2.50	10.50	6.65
	29	3.50	36.00	17.05		28	3.25	10.25	6.50
जून	12	4.50	16.50	11.45	जून	11	5.00	9.25	6.40
	26	5.00	22.00	15.00		25	5.00	8.25	5.45
जुलाई	10	5.00	18.50	12.70	जुलाई	9	4.25	8.00	5.55
	24	1.25	16.50	8.70		23	3.50	6.75	5.30
अगस्त	7	3.50	12.50	9.20	अगस्त	6	1.25	6.50	4.30
	21	2.00	12.50	8.65		20	2.00	6.00	5.20

*यह दैनिक मध्य दर का एक साधारण प्रोजेन है।

परिशिष्ट सारणी IV. 15 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा-प्रमाणपत्र जारी करना

	निम्नलिखित की समाप्त पक्षमात्रा	जमा-प्रमाणपत्र जारी करने वाले बैंकों की संख्या	कुल बकाया (करोड़ रुपये)	जमा-प्रमाणपत्रों की प्रमाणी व्याज-दर (प्रतिशत वार्षिक)
	1	2	3	4
1992				
जुलाई	10	53	7,508	13.50-17.75
	24	52	7,800	13.00-19.76
अगस्त	7	52	8,160	13.00-17.30
	21	52	8,145	13.50-17.30
सितंबर	4	51	8,187	13.50-17.30
	18	51	8,249	13.00-10.00
अक्तूबर	2	51	8,469	13.50-17.24
	16	50	8,520	13.00-17.50
	30	49	8,458	13.00-17.30
नवंबर	13	49	9,044	13.00-17.50
	27	49	9,332	13.00-17.19
दिसंबर	11	49	9,280	13.00-17.19
	25	48	9,995	12.25-17.50
1993				
जनवरी	8	51	10,016	12.50-17.50
	22	51	9,962	13.50-16.50
फरवरी	5	50	10,261	13.00-17.20
	19	50	10,106	13.00-17.19

	1	2	3	4
मार्च	5	51	10,163	12.50-17.19
	19	51	9,803	12.50-16.50
अप्रैल	2	51	9,885	13.00-18.00
	16	51	10,319	12.50-17.25
	30	50	10,648	11.50-17.00
मई	14	50	10,797	12.00-17.00
	28	49	11,267	12.00-16.00
जून	11	50	11,744	12.00-16.50

परिशिष्ट सारणी IV. 16 : भारत सरकार के 364 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	प्रस्तुत बोलियाँ संख्या	कूल अंकित मूल्य	स्वीकृत बोलियाँ संख्या	कूल अंकित मूल्य	तय मूल्य (प्रतिशत)	तय मूल्य पर निहित लाभ (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि निधियन से पहले	निधियन के बाब
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1992									
अप्रैल	28 अप्रैल	30	75 1,128.65	53	666.15	89.75	11.4206	666.15	3.43
मई	13 मई	15	57 1,396.48	44	961.48	89.75	11.4206	1,627.63	176.76
	27	29	60 1,087.23	41	797.75	89.75	11.4206	2,425.38	333.01
जून	09 जून	11	43 537.64	33	412.64	89.75	11.4206	2,828.02	378.11
	24	26	85 1,756.16	66	1,474.16	89.75	11.4206	4,312.18	755.76
जुलाई	07 जुलाई	10	28 589.00	10	387.00	89.80	11.3586	4,699.18	788.26
	22	24	56 1,979.65	16	854.60	89.87	11.2718	5,553.78	860.86
अगस्त	05 अगस्त	7	67 1,623.35	21	795.85	89.93	11.1976	6,349.63	1,009.36
	19	21	55 997.80	35	810.00	89.95	11.1729	7,159.63	1,255.46
सितंबर	02 सितंबर	4	17 163.00	12	139.50	89.95	11.1729	7,299.13	1,202.86
	16	18	25 118.00	15	43.00	89.95	11.1729	7,342.13	1,274.86
	29 अक्तूबर	1	13 165.60	10	130.60	89.85	11.2966	7,472.73	1,391.46
अक्तूबर	13	16	16 337.00	10	264.00	89.85	11.2966	7,736.73	1,305.46
	28	30	18 116.80	10	69.80	89.85	11.2966	7,806.53	1,306.93
नवंबर	11 नवंबर	13	26 265.00	3	20.00	89.86	11.2842	7,826.53	1,306.93
	25	27	49 485.11	9	75.11	89.88	11.2595	7,901.64	1,526.93
दिसंबर	8 दिसंबर	11	5 40.00	2	20.00	89.91	11.2223	7,921.64	1,346.93
	22	24	35 591.60	19	451.60	89.91	11.2223	8,373.24	1,470.43
1993									
जनवरी	06 जनवरी	8	32 340.00	4	45.00	89.95	11.1729	8,418.24	1,510.43
	19	22	22 131.02	2	6.00	90.00	11.1111	8,424.24	1,510.43
फरवरी	03 फरवरी	5	24 426.00	2	53.00	90.12	10.9652	8,477.24	1,513.43
	17	18	18 151.00	14	134.00	90.08	11.0124	8,611.24	1,577.43
मार्च	03 मार्च	5	10 42.50	9	41.50	90.05	11.0494	8,652.74	1,613.93
	17	19	29 163.50	21	124.00	90.09	11.1111	8,776.74	1,653.93
	31 अप्रैल	2	17 77.00	4	20.00	90.01	11.0988	8,796.74	1,673.93
अप्रैल	13	16	61 1,152.00	22	585.00	90.10	10.9878	9,381.74	2,258.93
	28	30	15 219.85	12	204.85	90.10	10.9878	8,920.44	2,460.35
मई	13 मई	13	28 223.75	23	156.75	90.05	11.0494	8,115.71	2,443.77
	26	28	26 229.20	26	229.20	89.90	11.2347	7,547.16	2,516.72
जून	09 जून	11	24 258.20	19	219.20	89.87	11.2718	7,353.72	2,690.82
	23	25	53 539.00	50	509.00	89.80	11.3586	6,388.56	2,822.17
जुलाई	7 जुलाई	9	31 448.00	22	367.00	89.80	11.3586	6,668.56	2,158.67
	21	23	54 1,313.00	46	1,052.00	89.80	11.3586	6,565.96	4,136.07
अगस्त	4 अगस्त	6	60 1,154.00	54	1,044.00	89.80	11.3586	6,814.11	5,031.57
	18	20	59 1,572.50	35	903.25	89.81	11.3338	6,906.36	5,687.82

* 19-4-1993 को, 1993-94 में परिपक्व होने वाले कुल 7122.81 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य वाले बिलों को 12.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1996 में परिचालित किया गया था।

परिशिष्ट सारणी IV, 17: भारत सरकार के 91 दिवसीय खजाना विलों की विलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्णय की तारीख	अविश्वचित राशि	प्रस्तुत बोलियाँ	कुल अंकित मूल्य	स्वीकृत बोलियाँ	कुल अंकित	भा. रि. ब. द्वारा अभिदान	तय मूल्य (प्रतिशत)	तय मूल्य पर निहित लाभ	निर्णय की तारीख को बकाया राशि जोड़ भा. रो. ब. के बाहर	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1993													
जनवरी	8 जनवरी	9	250	10	226.00	4	199.50	97.80	8.9980	250.00	50.50	199.50	
	15	16	100	4	11.00	3	94.00	97.78	9.0816	350.00	56.50	293.50	
	22	23	100	6	86.00	4	94.00	97.65	9.6262	450.00	62.50	387.50	
	29	30	100	4	31.00	4	69.00	97.62	9.7521	550.00	93.50	456.50	
	5 फरवरी	6	100	5	7.85	4	7.35	97.60	9.8361	650.00	100.85	549.15	
फरवरी	12	13	100	27	93.25	19	66.75	97.55	10.0461	750.00	167.60	582.40	
	18	20	100	4	1.00	0	0.00	97.60	9.8361	850.00	167.60	682.40	
	26	27	100	6	8.00	6	8.00	97.50	10.2564	950.00	175.60	774.40	
	5 मार्च	6	100	6	2.50	6	2.50	97.45	10.4669	1,050.00	178.10	871.90	
	12	13	100	9	7.00	6	4.50	97.40	10.6776	1,150.00	182.60	967.40	
मार्च	19	20	100	2	10.50	2	10.50	97.35	10.8885	1,250.00	193.10	1,056.90	
	26	27	100	3	10.00	3	10.00	97.33	10.9730	1,350.00	203.10	1,146.90	
	2 अप्रैल	3	100	11	73.50	10	73.00	97.30	11.0997	1,450.00	276.10	1,173.90	
	8	10	150	18	220.00	8	150.00	97.38	10.7620	1,350.00	375.60	974.40	
	16	17	200	47	770.00	8	200.00	97.68	9.5004	1,450.00	569.60	880.40	
मई	22	23	150	11	180.00	5	140.00	97.68	9.5004	1,500.00	703.60	796.40	
	29	30	125	4	20.00	4	20.00	97.60	9.8361	1,525.00	692.60	832.40	
	7 मई	8	50	10	121.00	5	50.00	97.62	9.7521	1,475.00	735.25	739.75	
	14	15	50	16	120.00	3	50.00	97.65	9.6262	1,425.00	718.50	706.50	
	21	22	50	9	50.00	8	45.00	97.63	9.7101	1,375.00	763.50	611.50	
जून	28	29	75	16	123.00	9	74.50	97.62	9.7521	1,350.00	830.00	520.00	
	4 जून	5	100	12	87.00	12	87.00	97.58	9.9201	1,350.00	914.50	435.50	
	11	12	100	20	245.00	8	100.00	97.57	9.9621	1,350.00	1,010.00	340.00	
	18	19	100	18	185.00	12	100.00	97.55	10.0461	1,350.00	1,099.50	250.50	
	25	26	100	30	219.00	11	87.00	97.54	10.0882	1,350.00	1,176.50	173.50	
जुलाई	2 जुलाई	3	100	32	312.00	15	100.00	97.55	10.0461	1,350.00	1,203.57	146.50	
	9	10	100	26	351.00	9	100.00	97.56	10.0041	1,300.00	1,153.50	146.50	
	16	17	150	34	526.00	5	150.00	97.60	9.8631	1,250.00	1,103.50	146.50	
	23	24	250	48	756.00	24	250.00	97.60	9.8361	1,350.00	1,213.50	136.50	
	30	31	250	49	1,043.00	23	250.00	97.62	9.7521	1,475.00	1,443.50	31.50	
अगस्त	6 अगस्त	7	350	60	1,260.40	4	350.00	97.69	9.4585	1,775.00	1,743.50	31.50	
	13	14	450	65	1,627.00	33	450.00	97.72	9.3328	2,175.00	2,143.50	31.50	
	20	21	500	36	1,879.00	18	500.00	97.74	9.2490	2,625.00	2,598.50	26.50	

परिशिष्ट सारणी IV. 18 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	अभिदान की तारीख	अधिसूचित राशि	अवधि (वर्ष)	प्रस्तुत बोलियाँ संख्या	स्वीकृत बोलियाँ संख्या	भारिब का अभिदान	अधिकतम मूल्य/भाय (प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1992									
3 जून	5 जून	1,000.00	5	100	1,479.05	21	713.25	286.75	12.00
3 अगस्त	5 अगस्त	1,000.00	10	80	1,390.50	56	646.50	353.50	12.75
1 दिसम्बर	3 दिसम्बर	1,000.00	6	82	660.50	26	261.25	738.75	12.30
1993									
1 फरवरी	3 फरवरी	1,000.00	7	76	770.56	59	628.56	371.44	12.60
26 फरवरी	27 फरवरी	820.85*	8	59@	575.00@	20@	357.298*	463.56*	12.70
3 जून	4 जून	1,000.00	5	62	1,212.00	4	1,000.00	0.00	13.00
15 जून	16 जून	1,000.00	9	74	1,037.00	22	565.20	434.80	13.40
27 जुलाई	28 जुलाई	1,000.00	7	86	1,393.00	52	1,000.00	0.00	13.25

*नकदी द्वारा अभिदान कुल राशि 675.40 करोड़ रुपये और परिवर्तन द्वारा अभिदान राशि 145.45 करोड़ रुपये है।

@ये आंकड़े प्रतियोगी बोलियाँ दर्शाते हैं।

\$हस राशि में परिवर्तन द्वारा 18.29 करोड़ रुपये और शेष राशि की नकदी शामिल है।

**हस राशि में परिवर्तन द्वारा 127.16 करोड़ रुपये और शेष राशि की नकदी शामिल है।

परिशिष्ट सारणी IV. 19 रिजर्व बैंक द्वारा पुनः खरोद की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	बिक्री की तारीख	पुनः खरीद की अवधि (दिन)	प्रस्तुत बोलियाँ संख्या	कुल प्रकृत संख्या मूल्य	स्वीकृत बोलियाँ संख्या पुनः कुल प्रकृत खरीद की मूल्य दर (प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1992								
दिसम्बर	10 दिसम्बर	11	1	13	2,120	13	2,120	6.00
	17	18	1	66	10,595	29	6,075	9.25
	21	24	2	49	8,295	49	8,295	12.50
	21 जनवरी	1,93	1	56	11,519	26	3,130	11.50
1993								
जनवरी	7 जनवरी	8	1	54	7,163	19	2,743	8.00
	14	15	1	25	2,587	3	402	10.50
	19	22	1	26	4,285	16	2,645	6.00
	28	29	1	11	1,175	2	250	9.50
फरवरी	4 फरवरी	5	1	28	4,060	9	2,935	5.00
	11	12	1	10	2,335	2	890	10.50
	17	18	2	25	4,162	19	3,787	5.50
	25	26	1	18	2,705	2	930	10.50
मार्च	4 मार्च	5	1	82	9,749	58	8,374	10.50
	11	12	1	52	8,397	34	6,650	12.50
	17	19	1	70	9,837	63	9,570	11.75
	23	26	1	50	6,847	10	4,730	14.50
अप्रैल	30	31	2	22	5,160	21	5,110	19.50
	1 अप्रैल	2	1	38	3,817	22	3,077	7.00
	7	8	2	32	4,430	2	400	11.50
	8	10	7	34	2,591	5	450	10.00
	22	23	10	47	2,571	7	515	7.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मई	4 मई	5	10	28	1,761	12	1,008	7.50
	12	13	2	16	1,649	15	1,648	5.00
	19	20	9	24	1,887	16	1,775	7.00
	23	24	5	22	2,557	9	1,550	5.75
	28	29	14	44	4,370	15	1,543	7.75
जून	3 जून	4	1	24	3,117	23	3,116	7.75
	10	11	1	49	9,349	45	8,249	8.75
	17	18	1	77	10,201	75	9,801	9.50
	24	25	1	109	14,247	73	10,817	8.50
	25	26	14	51	3,682	32	1,475	8.50
	30 जुलाई	1	8	74	4,733	19	2,967	7.00
अगस्त	13	14	10	81	7,795	37	4,703	6.50
	16	17	7	66	3,930	14	727	6.50
	23	24	14	63	6,389	22	4,130	6.50
	29	30	8	60	5,116	20	1,041	6.00
अगस्त	6 अगस्त	7	14	59	6,887	20	5,398	6.00
	20	21	14	43	6,037	8	4,368	6.00

* नकद रूप में अधिभुक्त राशि 675.90 करोड़ रुपये है तथा परिवर्तन द्वारा उक्त राशि 145.45 करोड़ रुपये आकड़े प्रतियोगी बोलियों की शीतक है।

\$- इस राशि में 18.29 करोड़ रुपये परिवर्तन द्वारा तथा शेष रुपये नकद रूप में शामिल है।

**/- इस राशि में 121.16 करोड़ रुपये परिवर्तन द्वारा तथा शेष रुपये नकद रूप में शामिल है।

परिशिष्ट सारणी IV.20 : थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट-बढ़ (आधार 1981-82-100)

(प्रतिशत में)

मुख्य समूह/समूह/उप समूह/पण्य	वित्तीय वर्ष के दौरान		प्रथम तिमाही के दौरान		विन्युक्त आधार पर		
	सारांक विन्युक्त आधार		श्रीत आधार		विन्युक्त आधार पर		
	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92	1993-94*	1992-93	
	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.000	7.0	13.6	10.0	13.7	2.4	3.2-
I. प्राथमिक वस्तुएं	32.295	3.0	15.3	7.3	18.2	2.6	4.1
1. खाद्य वस्तुएं	17.386	5.4	20.9	12.3	20.2	2.6	7.1
(क) अनाज	6.824	-2.7	26.9	13.5	22.2	0.2	1.2
(i) चावल	3.685	-0.2	30.7	14.5	21.7	0.5	2.3
(ii) गेहूं	2.248	2.7	12.3	11.4	18.3	0.6	-3.1
(ख) दालें	1.093	2.7	9.4	3.5	9.3	2.2	-0.1
(ग) फल व सब्जियां	4.089	9.7	19.0	7.5	24.1	6.2	10.3
(घ) दूध	1.961	9.6	13.7	12.0	12.9	2.6	18.5
(ङ) घड़े, मछली और मांस	1.783	17.1	16.3	16.4	14.6	-3.8	2.8
(च) मिर्च, मसाले, अटनी आदि	0.947	3.0	41.3	22.9	46.7	6.8	14.1
(छ) अन्य खाद्य वस्तुएं	0.689	27.9	-5.0	10.0	-8.9	9.3	20.7
(i) चाय	0.564	30.8	0.4	13.5	-9.6	11.5	26.6
(ii) काफी	0.125	15.8	-22.2	-4.6	-5.5	-0.7	-4.2
2. गैर-खाद्य वस्तुएं-	10.081	-1.4	8.1	-0.2	17.8	3.0	-0.8
(क) रेशे	1.791	-10.5	14.4	-10.7	38.8	3.3	0.3
(i) कपास	1.335	-10.9	24.7	-8.6	63.4	3.1	3.0
(ख) तिलहन	2.861	-8.7	4.7	-1.9	20.3	6.0	2.3
3. खनिज	4.828	2.8	5.2	2.3	4.1	0.0	0.0
(i) पेट्रोलियम, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	4.274	1.9	1.9	1.7	1.4	0.0	0.0
II. ईंधन, पावर, विद्युत और जिकनाई के पदार्थ	10.663	15.2	13.2	14.1	13.1	3.4	0.3
(क) कच्चा कोयला	0.353	14.9	26.1	10.0	7.0	4.8	0.0
(ख) खनिज तेल	6.666	18.8	9.2	13.6	16.1	0.1	0.1
(ग) बिजली	2.741	9.8	13.7	11.8	10.8	9.4	0.9

1	2	3	4	5	6	7	8
III. विनिर्मित उत्पाद	57.042	7.9	12.6	10.9	11.3	2.0	3.2
(क) चीनी, खांडमारी और गैस	4.059	27.9	5.5	12.1	5.3	20.7	11.8
(i) चीनी	2.013	13.9	18.9	13.1	10.6	2.8	3.2
(ii) खांडमारी	0.300	26.9	-6.9	5.1	3.1	14.7	14.2
(iii) गड़	1.746	47.4	-6.9	12.1	0.4	40.3	23.2
(ख) खाद्य	2.445	-7.1	1.9	-0.5	19.1	3.1	5.3
(ग) सूती वस्त्र	6.093	5.5	16.0	8.9	14.4	0.0	0.6
(घ) रसायन और रसायन उत्पाद	7.355	12.8	15.5	14.3	13.9	1.5	3.0
(य) सीमेंट	0.860	-3.5	17.4	6.4	15.9	1.5	-1.8
(च) लोहा और इस्पात	2.441	12.2	4.5	9.5	5.5	0.9	8.8

* चाय और कॉफी समाविष्ट करें।

* अनंतिम

परिशिष्ट सारणी 4.21 : सामान्य थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में समूहों/पण्यों का भारांकित योगदान (आधार 1981-82-100)

(प्रतिशत में)

प्रमुख समूह/समूह/उप समूह/पण्य	वित्तीय वर्ष			प्रथम तिमाही		बिबुवार आधार पर	
	भारांकित बिबुवार आधार			औसत आधार			
	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92	1993-94	1992-93	
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
I प्राथमिक वस्तुएं	32.295	14.4	37.1	24.9	43.2	35.2	42.4
1. खाद्य वस्तुएं	17.386	15.6	29.4	24.8	28.1	22.4	45.4
(क) अनाज	6.824	-2.9	13.4	9.4	10.8	0.5	2.8
(i) चावल	3.685	-0.1	8.2	5.6	5.7	0.8	3.0
(ii) गेहूं	2.248	0.9	2.2	2.5	2.8	0.6	-2.3
(ख) दालें	1.093	0.5	0.9	0.5	0.9	1.2	0.0
(ग) फल व सब्जियां	4.089	6.3	6.1	3.8	8.0	12.3	26.5
(घ) दुध	1.961	3.1	2.3	2.7	2.1	2.5	0.6
अंडे, मछली और मांस	1.783	4.6	2.2	3.1	2.0	-3.3	1.7
(च) मिरच, मसाले, जटनी आदि	0.947	0.8	4.8	4.4	5.0	5.4	8.6
(छ) अन्य खाद्य वस्तुएं	0.689	3.2	-0.3	0.9	-0.7	3.8	5.1
(i) चाय	0.564	2.8	0.0	1.0	-0.6	3.8	5.3
(ii) काफी	0.125	0.3	-0.4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2
2. गैर-खाद्य वस्तुएं	10.081	-2.1	6.6	-0.2	13.9	12.5	-2.6
(क) रेशे	1.791	-2.8	2.0	-2.2	4.8	2.2	0.2
(i) कपास	1.335	-2.2	2.4	-1.3	4.9	1.6	1.3
(ख) तिलहन	3.861	-4.9	1.5	-0.8	6.1	8.5	2.9
3. खनिज	4.828	1.0	1.1	0.6	0.9	0.0	0.0
(i) पेट्रोलियम, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	4.274	0.6	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0
II. हथिन, पावर, विद्युत और चिकनाई के पदार्थ	10.663	22.6	10.2	14.4	9.8	16.3	0.9
(क) कच्चा कोयला	0.353	1.1	0.9	0.9	0.3	1.1	0.0
(ख) खनिज तेल	6.666	15.2	4.0	7.9	6.6	0.2	0.1
(ग) बिजली	2.741	4.3	3.1	3.5	2.4	12.5	0.8
III. विनिर्मित उत्पाद	57.042	63.0	52.7	60.6	47.0	48.7	56.2
क) चीनी, खांडमारी और गुड़	4.059	11.5	1.3	3.8	1.3	30.3	10.6
(i) चीनी	2.013	3.1	2.1	2.0	1.2	2.0	1.6
(ii) खांडमारी	0.300	0.7	-0.1	0.1	0.1	1.3	0.8
(iii) गुड़	1.746	7.7	-0.7	1.7	0.0	27.0	8.3
(ख) खाद्य	2.445	-2.9	0.5	-0.1	4.1	3.3	4.8
(ग) सूती वस्त्र	6.093	4.6	6.8	5.2	6.0	-0.1	1.1
(घ) रसायन और रसायन उत्पाद	7.335	10.9	6.7	8.5	6.0	4.1	5.6
(य) सीमेंट	0.860	-0.4	1.1	0.5	0.8	0.5	-0.5
(च) लोहा और इस्पात	2.441	4.2	0.9	2.4	1.1	1.0	6.6

* चाय और कॉफी समाविष्ट करें। * अनंतिम

परिशिष्ट सारणी 4.22 : थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रवर्धित मूल्य वृद्धि की वार्षिक और तिमाही बरें (बिबुवार आधार पर)
(प्रतिशत में)

मर्दे	1992-93					1991-92				1993-94	
	तिमाही					तिमाही				तिमाही	
	वार्षिक					वार्षिक				वार्षिक	
	अप्रैल जून	जुलाई सितम्बर	अक्तूबर दिसम्बर	जनवरी मार्च	घट-बढ़	अप्रैल जून	जुलाई सितम्बर	अक्तूबर दिसम्बर	जनवरी मार्च	घट-बढ़	अप्रैल जून
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
थोक मूल्य सूचकांक@	3.2	3.0	0.3	0.4	7.0	4.3	5.0	2.0	1.7	13.6	2.4
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य	3.1	3.0	0.0	0.0	6.1	4.0	5.7	1.8	1.8	13.9	2.9
शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक*	2.6	3.6	0.5	0.0	6.8	3.0	5.7	1.6	2.7	13.6	N.A.
कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक*	2.1	4.1	-4.0	-1.3	0.7	2.1	11.3	3.4	3.8	21.9	0.4

@आधार : 1981-82-100

†आधार 1982-100

* आधार 1984-85-100

* आधार : 1960-61-100

परिशिष्ट सारणी 4.23 : ग्रामों के रूप में सोने और चांदी का अनुपात*

वर्ष	बम्बई बाजार में*		अंतर्राष्ट्रीय बाजार में *	
	औसत कीमत के आधार पर		औसत कीमत के आधार पर	
	वर्ष के अन्त की कीमत के आधार पर	वर्ष के अन्त की कीमत के आधार पर	वर्ष के अन्त की कीमत के आधार पर	वर्ष के अन्त की कीमत के आधार पर
1	2	3	4	5
1980-81	59	63	37	43
1981-82	66	61	46	45
1982-83	62	58	44	39
1983-84	53	55	38	40
1984-85	55	53	46	49
1985-86	55	54	54	65
1986-87	55	54	71	67
1987-88	56	51	64	68
1988-89	50	46	66	66
1989-90	47	49	72	75
1990-91	51	53	83	92
1991-92	59	54	87	83
1992-93	58	75	89	87

† प्रति एक ग्राम स्वर्ण के बदले में प्राप्त चांदी (ग्रामों में)

*बम्बई बलियन संघ के भावों पर आधारित।

* लंदन और न्यूयार्क के बाजारों के लिए प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया से प्राप्त भावों पर आधारित।

परिशिष्ट सारणी 4.24: देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा चांदी की कीमत

वर्ष	स्वर्ण		चांदी		बम्बई और	बम्बई और
	बम्बई बाजार स्टैंडर्ड सोना		बम्बई बाजार (0.999 तक)		लंदन की	न्यूयार्क की
	(प्रति 10 ग्राम स्पेस)		परिष्कृत प्रति किग्रा. स्पेस		कीमतों में	कीमतों में
					अंतर	अंतर
					(औसत प्रतिशत)	
	वर्ष के अंत में	औसत	वर्ष के अंत में	औसत	स्वर्ण*	चांदी**
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1,700 (27.8)	1,522 (31.3)	2,720 (2.4)	2,617 (13.9)	2.5	-3.49
1981-82	1,645 (-3.2)	1,719 (12.9)	2,680 (-1.5)	2,636 (-0.7)	42.1	0.3
1982-83	1,800 (9.4)	1,723 (0.2)	3,105 (15.9)	2,798 (6.2)	37.8	-1.1
1983-84	1,975 (9.7)	1,859 (7.8)	3,570 (15.0)	3,506 (25.3)	38.5	-0.3
1984-85	2,130 (7.8)	1,984 (6.8)	3,955 (10.8)	3,594 (2.5)	53.3	27.9
1985-86	2,140 (0.5)	2,126 (7.1)	4,015 (1.5)	3,918 (9.0)	64.8	63.5
1986-87	2,570 (20.1)	2,324 (9.3)	4,794 (19.4)	4,247 (8.4)	47.3	91.3
1987-88	3,130 (21.8)	3,082 (32.7)	6,066 (26.5)	5,539 (30.4)	61.2	83.6
1988-89	3,140 (0.3)	3,175 (3.0)	6,755 (11.4)	6,367 (14.9)	62.0	114.3
1989-90	3,200 (1.9)	3,229 (1.7)	6,463 (-4.3)	6,842 (7.5)	56.5	140.4
1990-91	3,466 (8.2)	3,452 (6.9)	6,646 (2.8)	6,761 (-1.2)	59.5	162.1
1991-92	4,334 (25.0)	4,298 (24.5)	8,040 (21.0)	7,332 (8.5)	51.3	124.2
1992-93	4,140 (-4.5)	4,104 (-4.5)	5,489 (-31.7)	7,078 (-3.5)	23.2	88.7

कोष्ठकों के आकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

* फरवरी 1992 तक यह अंतर इस प्रकार निकाला जाता था कि पहले लंदन बाजार में प्रति शुद्ध ट्राय औंस डालरों के भाव को लंदन में अमरीकी डालरों के हाज़िर खरीद और बिक्री पर आधारित दैनिक औसत को प्रति दस ग्राम स्पेस भाव में बदला जाता था और फिर उसे रिजर्व बैंक की हाज़िर स्टैलिग की बिक्री और खरीद के भाव में घटाया जाता था। मार्च 1992 से भावों को बम्बई में अमरीकी डालरों की भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के हाज़िर बिक्री और खरीद के दैनिक औसत पर बदला जाता है।

** फरवरी 1992 तक, इस अंतर को इस प्रकार निकाला जाता था कि पहले न्यूयार्क बाजार में सेंट प्रति ट्राय औंस में अमरीकी डालर के हाज़िर खरीद और बिक्री के दैनिक औसत दर को रुपये प्रति कि. ग्राम में बदला जाता था और फिर उसे स्टैलिग के भारतीय रिजर्व बैंक की हाज़िर बिक्री और खरीद की औसत दरों से घटाया जाता था। मार्च, 1992 से भावों को बम्बई में अमरीकी डालरों की भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के हाज़िर बिक्री और खरीद की दैनिक औसत दर पर बदला जाता है।

स्रोत : (1) बम्बई बुलियन संघ, (2) प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

परिशिष्ट सारणी IV. 25 सोने और चांदी की कीमतें—राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का मासिक औसत और अंतर

माह/वर्ष	स्वर्ण (प्रति 10 ग्राम स्पए)			चांदी (प्रति किग्रा. स्पए)		
	बम्बई-लंदन			बम्बई-न्यूयार्क		
	बम्बई	लंदन	अंतर	बम्बई	न्यूयार्क	अंतर
1	2	3	4	5	6	7
1992						
अप्रैल	4,497.18	3,365.70	1,131.48 (33.6)	8,395.41	3,998.67	4,396.74 (110.0)
मई	4,176.77	3,287.43	289.34 (27.1)	7,973.09	3,976.31	8,996.78 (100.5)
जून	4,110.15	3,313.26	796.89 (24.1)	7,255.88	3,942.31	3,313.47 (84.0)
जुलाई	4,136.55	8,428.00	708.55 (20.7)	7,537.00	3,686.19	3,850.81 (104.5)
अगस्त	4,094.00	8,323.88	770.12 (23.2)	7,626.14	3,660.16	3,965.98 (108.4)
सितम्बर	4,086.13	3,337.85	749.28 (22.5)	7,351.50	3,638.57	3,712.93 (102.0)
अक्तूबर	4,079.00	8,320.23	758.77 (22.9)	7,196.33	3,608.26	3,588.07 (99.4)
नवम्बर	3,998.61	3,241.48	757.13 (23.4)	6,539.35	3,645.50	2,893.85 (79.4)
दिसम्बर	3,966.81	3,305.05	661.76 (20.0)	6,644.71	3,663.73	2,980.98 (81.4)
1993						
जनवरी	3,977.24	3,271.32	705.92 (21.6)	6,810.35	3,654.02	3,156.38 (86.4)
फरवरी	4,027.10	3,457.45	569.65 (16.5)	6,056.71	3,820.80	2,235.91 (58.5)
मार्च	4,094.39	3,344.74	749.65 (22.4)	5,554.22	3,703.81	1,850.41 (50.0)
अप्रैल	4,331.27	8,446.90	884.37 (25.7)	5,809.41	3,999.53	1,809.88 (45.3)
मई	4,518.50	3,697.13	821.37 (22.2)	6,187.13	4,479.20	1,707.93 (38.1)
जून	4,468.20	3,752.33	715.87 (19.1)	6,009.88	4,407.98	1,601.90 (36.3)
जुलाई	4,564.59	8,957.87	606.73 (15.3)	6,481.48	5,080.34	1,401.14 (27.6)

टिप्पणियाँ : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत अंतर सूचित करते हैं।

स्रोत : 1. बम्बई वलियत मंत्र 2. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया

परिशिष्ट माली V.1 : सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संचालित सहायता

(सर्वोच्च स्तर)

संस्थाएं	राजकीय वर्ष										अन्य वर्ष	
	1992-93		1991-92		1990-91		स्वीकृतियों में		संचालकों में		संचालकों में	
	सं	वि	सं	वि	सं	वि	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
अ. भारतीय विकास बैंक (अ)	20,893.7	13,907.4	16,759.7	11,447.7	14,896.4	9,551.7	4,139.0	1,865.2	5,459.7	1,896.0		
(1 में 5)							(34.7)	(12.5)	(21.5)	(19.8)		
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	18,908.5	12,574.5	14,545.5	10,082.5	12,872.7	9,278.5	4,363.7	1,670.6	2,492.0	1,804.0		
							(30.0)	(11.0)	(24.7)	(21.8)		
2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	9,459.4	6,668.5	7,590.0	5,762.8	8,431.2	4,459.4	1,869.4	1,158.8	905.7	1,303.4		
							(24.6)	(18.0)	(15.7)	(29.2)		
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	9,330.5	6,529.5	7,106.2	5,279.0	5,985.0	4,016.9	2,214.3	1,121.2	1,250.5	1,262.1		
							(31.2)	(18.7)	(23.7)	(51.4)		
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	8,701.9	6,042.1	6,414.1	4,760.8	5,156.5	3,487.6	2,287.8	1,257.6	1,281.3	1,273.2		
							(55.7)	(24.4)	(26.9)	(36.5)		
5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2,492.8	1,713.0	2,415.0	1,604.8	2,535.9	1,574.8	57.8	—88.9	138.2	50.9		
							(2.4)	(—3.5)	(8.0)	(1.9)		
6. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	5,882.7	3,315.2	4,094.9	2,351.3	3,744.0	1,967.6	1,787.8	350.9	963.9	383.7		
							(43.7)	(9.4)	(41.0)	(19.5)		
7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2,908.4	2,145.8	2,845.9	2,027.4	2,408.8	1,858.5	62.5	437.1	118.4	188.9		
							(2.2)	(18.1)	(5.8)	(10.1)		
8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1,534.8	1,100.2	1,521.6	1,180.4	1,215.6	1,094.6	213.2	103.0	119.9	85.3		
							(16.1)	(8.9)	(10.2)	(7.8)		
9. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2,94.2	183.9	277.7	185.2	304.7	153.9	16.6	43.0	—1.5	51.2		
							(6.0)	(18.2)	(—0.7)	(20.3)		
10. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	9,29.3	579.6	542.2	245.4	458.6	224.9	387.1	103.6	334.2	20.5		
							(71.4)	(25.6)	(17.6)	(9.1)		
11. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	14.8	18.4	11.1	8.4	11.0	7.3	3.7	0.1	2.0	1.1		
							(33.3)	(0.9)	(23.8)	(15.1)		
12. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	22.6	23.2	18.6	17.8	11.0	11.4	10.0	7.6	5.4	6.4		
							(53.8)	(69.1)	(30.3)	(56.1)		
13. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	760.9	486.3	409.0	170.9	331.6	167.0	351.9	77.4	315.4	3.3		
							(86.0)	(22.3)	(124.6)	(2.3)		
14. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	125.9	59.7	103.5	48.2	85.0	39.2	21.5	18.5	11.4	9.1		
							(20.8)	(21.8)	(23.6)	(23.2)		
15. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	9,295.1	6,963.6	5,843.4	3,910.8	2,924.7	1,929.0	3,449.7	2,918.7	2,652.8	1,981.8		
							(59.0)	(99.8)	(78.1)	(102.7)		

परिशिष्ट सारणी V.2 : सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों की पूंजी जुटाने के लिए नये निर्गम हेतु नियंत्रक, पूंजी निर्गम और भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) का अनुमोदन

(करोड़ रुपये)

निर्गम का प्रकार	(अप्रैल-मई)*		1992-93†		बीड (अप्रैल-मार्च)		1991-92		1990-91	
	(अप्रैल-मई)*		(जून-मार्च) **		(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ. गैर-सरकारी कंपनियों	328	2,245	999	18,596	1,328	20,841	1,248	12,341	1074	6,423
जिसमें से										
i. इक्विटी (ए)	272	1,187	845	8,996	1,117	10,183	869	4,291	841	2,833
ii. डिबेंचर	57	1,058	154	9,600	211	10,658	375	8,050	233	3,570
आ. सरकारी कंपनियों के	2	60	1	320	3	380	20	7,071	31	6,208
जिसमें से										
i. इक्विटी	1	10	1	320	2	330	3	76	14	201
ii. सरकारी क्षेत्र के बीड	1	50	—	—	1	50	17	6,985	17	6,007
कुल जोड़ (अ+आ)	331	2,305	1,000	18,916	1,331	21,221	1,263	19,402	1,105	12,631

*नियंत्रक, पूंजी निर्गम द्वारा सहमति/प्रतिस्वीकृति (अप्रैल-मई)

**भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा दी गई अनापत्ति (जून 1992-मार्च 1993)। ग्राइलीवीपीआई द्वारा निर्गम बांडों के छांकड़ शामिल नहीं हैं।

(A) प्रीमियम और बोनस शेयरों सहित और जून 1992 से बोनस शेयरों को छोड़कर।

†अनंतिम

स्रोत : 1. नियंत्रक, पूंजी निर्गम

2. भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड

परिशिष्ट सारणी V.3 : गैर सरकारी सांख्यिकीय लि. कंपनियों के नये पूंजी निर्गम

(करोड़ रुपये)

1	राजकीय वर्ष					
	1993-94		1991-92		1990-91	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	2	3	4	5	6	7
1. इक्विटी शेयर (क+ख)	867	9,981.0	368	1,731.3	246	1,284.3
	(324)	(5,184.1)	(58)	(227.5)	(40)	(127.9)
(क) प्राइवेट	484	3,846.0	158	1,043.3	105	993.0
	(103)	(876.8)	(16)	(26.7)	(15)	(74.1)
(ख) राइट्स	383	6,135.0	210	688.0	141	289.3
	(219)	(4,307.3)	(41)	(200.8)	(25)	(53.8)
2. अधिमूल्य शेयर सीसीपी सहित (क+ख)	1	0.5	3	1.3	5	13.1
(क) प्राइवेट	--	--	1	0.5	2	13.0
(ख) राइट्स	1	0.5	2	1.0	1	0.1
3. डिबेंचर (क+ख)	169	9,844.1	146	4,024.0	115	3,014.8
(क) प्राइवेट	47	5,187.6	50	887.9	45	1,040.1
(ख) राइट्स	122	6,656.5	96	3,136.1	70	1,974.7
जिसमें से						
(i) परिवर्तनीय (क+ख)	150	7,864.9	133	3,496.9	94	2,356.6
(क) प्राइवेट	44	1,567.1	47	856.1	38	877.0
(ख) राइट्स	106	5,297.8	86	2,640.8	56	1,479.6
(ii) अपरिवर्तनीय (क+ख)	19	1,979.2	11	527.1	1	683.2
(क) प्राइवेट	3	620.5	3	11.8	7	163.1
(ख) राइट्स	16	1,358.7	10	515.3	14	496.1

1	2	3	4	5	6	7
4. जाड़ (1+2+3)	1,037	19,825.6	517	5,756.8	364	4,313.2
(क) प्रॉस्पेक्टम	531	7,033.6	209	1,911.7	152	2,048.1
(ख) राइटस	506	12,792.0	308	3,845.1	212	2,264.1

टिप्पणियाँ : 1. आंकड़े अंतिम हैं।

2. इक्विटी शेयरों में बोनस निर्गम शामिल नहीं हैं।

3. कोटक में विण राफ आंकड़े पूर्ण निर्गमों पर प्रीमियम के संबंध में हैं, इन्हें संबद्ध आंकड़ों में शामिल कर लिया गया है।

4. इन आंकड़ों में विनिय संस्थाओं इत्यादि के पास निर्जल तोर पर रखे गए निर्गम शामिल नहीं हैं। उसमें आई सी आई की आई, आई.एन.सी. एमसीआईसीआई द्वारा एकत्रित घनराशिया शामिल हैं।

5. परिवर्तनीय डिबेंचरों में आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं।

6. अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में जमानती प्रीमियम नोट शामिल है।

7. आंकड़ों में प्रति अंशदान और न्यून अंशदान की राशि शामिल है, जहां भी सूचना विशेष उपलब्ध थी।

8. आंकड़े कंपनियों द्वारा जारी विवरण पत्र/परिपत्रों/विज्ञापनों, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावितियों के उत्तर में उसे कंपनियों से प्राप्त उत्तरों, स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त सूचना, प्रेस रिपोर्टों आदि में एकत्र किए गए।

9. डिबेंचरों में बांड शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6	7
व्यवसायिक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पण्यों के लिए उधार की दर व्यवसायिक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत पण्यों पर ऋण/ अभिम/नकदी ऋण/घोषण/डाण्ड (न्यूनतम)	20.0	19.0	18.0	17.0	17.0	36.0

* ब्याज की छंटाई।

4 इस श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए बिल धुलाई सुविधा पर लागू ब्याज की दर बसूल किये गये उधार की दर से 1 प्रतिशत कम है।

इन दरों से सितम्बर 1990 से हुए परिवर्तनों की नीचे दिया गया है :

16.0 (न्यूनतम)	22 सितम्बर 1990 से लागू
17.0 (")	13 अप्रैल 1991 से लागू
18.5 (")	4 जुलाई 1991 से लागू
20.0 (")	9 अक्टूबर 1991 से लागू
19.0 (")	2 मार्च 1992 से लागू
18.0 (")	9 अक्टूबर 1992 से लागू
17.0 (")	1 मार्च 1993 से लागू
16.0 (")	24 जून 1993 से लागू

टिप्पणी : 1. जहां अल्पकालीन ऋण प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े आकार की बहु उद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समिति माध्यम से अल्पकालीन ऋण विधे जाते हैं, वहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े आकार की बहु उद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समितियों से बैंकों द्वारा बसूल की जाने वाली ब्याज दर ऋण सीमा के विभिन्न आकार के लिए उपयुक्त मर संचय I में दर्शाये गये अंतिम उपभोक्ताओं के लिए लागू दरों से 2.5 प्रतिशत अंक कम होगी।

2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े आकार की बहु उद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समिति के माध्यम से दिए जाने वाले मीयारी ऋणों के संबंध में बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े आकार की बहु उद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समिति से बसूल किए जाने वाले ब्याज की दर ऋण सीमा के विभिन्न आकार के लिए उपयुक्त मर संचय I और II (2) के मीयारी ऋणों के लिए निर्धारित दरों से 1.5 प्रतिशत अंक कम होगी।

3. अंतिम हितधिकारियों को ऋण देने के लिए मध्यस्थ एजेंसियों (आवास ऋण देने वाली एजेंसियों सहित) तथा इनपुट संबंधी समर्थन प्रदान करने वाली एजेंसियों मंजूर किए गए बिल के मामले में ब्याज दरें उस न्यूनतम दर से 3.00 प्रतिशत अंक तक कम होनी चाहिए जो 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा से आने वाली श्रेणी पर लागू होती है।

परिशिष्ट सारणी 5.4: भारतीय रिज़र्व बैंक - साप्ताहिक शेयर मूल्यों का प्रक्षिप्त
भारतीय सूचकांक (साप्ताहिक)
(आधार: 1988-89 = 100)

वर्ष माह	औसत +	उच्च	निम्न	माह/वर्ष के अंतिम सप्ताहांत में		
1	2	3	4	5		
1991-92	776.2	1485.4	536.9	1485.4		
(अप्रैल - मार्च)	(+ 55.1)			(+ 181.4)		
1992-93	1142.1	1656.9	892.1	892.1		
(अप्रैल - मार्च)	(+ 47.1)			(- 39.9)		
अप्रैल 1992	1620.2	1656.9	1597.3	1622.0		
मई	1345.5	1519.3	1206.8	1206.8		
जून	1161.6	1174.3	1148.9	1157.5		
जुलाई	1141.7	1159.2	1108.8	1108.8		
अगस्त	1077.2	1134.2	1032.3	1134.2		
सितम्बर	1214.7	1243.5	1168.4	1234.1		
अक्टूबर	1181.9	1227.5	1122.8	1122.8		
नवम्बर	1045.6	1102.1	1010.8	1010.8		
दिसम्बर	1003.1	1022.4	978.2	998.2		
जनवरी 1993	985.9	1002.2	966.1	1002.2		
फरवरी	1009.0	1024.6	993.4	1007.8		
मार्च	912.9	955.7	892.1	892.1		
जापम सर्वे 1983-89	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	(1988-89 से 1992-93) का औसत
बटवों के गुणज (प्रतिशत में) +	16.20	5.90	14.66	27.04	16.21	16.00
वियोजन (सीमा)	121.10	93.70	258.60	948.50	764.80	437.34

+ साप्ताहिक सूचकांकों पर आधारित *अनंतिम
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में अंतर का प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी 5.5: गैर बैंकिंग निगमित क्षेत्र में जमा राशियाँ

(करोड़ रुपये)

वर्ष	1991-92*				1990-91			
	सूचना देने वाली कंपनियों की संख्या	नियंत्रित जमा राशियाँ	छूट प्राप्त जमा राशियाँ	जोड़	सूचना देने वाली कंपनियों की संख्या	नियंत्रित जमा राशियाँ	छूट प्राप्त जमा राशियाँ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल जमा राशियाँ जिनमें से	12,817	9,269	44,290	53,559	10,166	7,907	37,354	45,261
(i) गैर-बितीय कंपनियों	2,393	4,608	23,673	28,281	2,367	4,618	21,829	26,447
	(18.7)	(49.7)	(53.4)	(52.8)	(23.3)	(58.4)	(58.4)	(58.4)
(ii) बितीय कंपनियों	8,656	2,904	19,311	22,215	6,663	2,013	14,589	16,602
	(67.5)	(31.3)	(43.6)	(41.5)	(65.5)	(25.5)	(39.1)	(36.7)
(iii) विभिन्न गैर बैंकिंग कंपनियों और गैर बैंकिंग कंपनियों	1,768	1,757	1,306	3,063	1,136	1,276	936	2,212
	(13.8)	(19.0)	(3.0)	(5.7)	(11.2)	(16.1)	(2.5)	(4.9)

*अनंतिम ** मार्च के अंत में

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सूचना देने वाली कंपनियों/नियंत्रित/छूट प्राप्त/मूल जोड़ के, यथास्थितानुसार शुद्ध का प्रतिशत हैं।

परिशिष्ट सारणी 6.1 भारत का वन्य भुगतान संतुलन

संव	करोड़ रुपये			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	1992-93 (तु. म.)	1991-92 (अ. अ.)	1990-91 (प्राथमिक)	1992-93 (तु. अ.)	1991-92 (अ. अ.)	1990-91 (प्राथमिक)
1	2	3	4	5	6	7
(अ) चालू लेखा						
1. निर्यात अहाज तक निःशुल्क	54,418	44,923	33,123	18,789	18,223	13,477
2. आयात (छागत, बीमा व बाड़ा सहित)	65,945	50,159	50,086	22,896	20,347	27,914
3. व्यापार संतुलन	-11,527	-5,236	-16,933	-4,106	-2,124	-9,437
4. अधिकाधिक अंतरण, शुद्ध	1,901	6,050	928	356	426	161
5. अन्य अदृश्य लेन-देन	-1,195	-1,000	-1,261	-1,261	-437	-703
6. चालू लेखा शेष	-14,631	-5,186	-17,366	-4,921	-2,135	-9,679
(आ) पूंजीगत लेखा						
1. विदेशी सहायता, शुद्ध	5,645	7,188	3,965	1,842	2,916	2,210
संवितरण	10,362	10,644	6,095	3,81	4,318	3,397
भ्रष्ट परिशोधन	-4,717	-3,456	-2,130	-1,539	-1,402	-1,187
2. नाणजिक उधार शुद्ध	-1,461	4,060	4,588	-451	1,647	2,553
संवितरण	3,562	7,457	8,183	1,188	3,025	4,562
भ्रष्ट परिशोधन	-5,023	-3,397	-3,595	-1,639	-1,378	-2,004
3. धनिबासी, भारतीयों की जमागणियाँ, शुद्ध	5,419	-6,111	2,756	1,949	-454	1,536
4. स्वयं ऋण चुकोती	-2,994	-3,260	-2,140	-977	-1,332	-1,192
5. अन्य पूंजी शुद्ध	6,124	6,077	4,046	1,998	2,152	2,253
6. कुल पूंजीगत लेखा	17,733	12,954	13,215	4,361	4,929	7,365
(इ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (शुद्ध)	3,363	2,077	2,178	1,238	781	1,211
(ई) विशेष आहरण अधिकार प्रान्टन	—	—	—	—	—	—
(उ) कुल पूंजीगत लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष आहरण अधिकार प्रान्टन	16,096	15,031	15,393	5,649	5,710	8,579
(ऊ) कुल चालू लेखा, पूंजीगत लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष आहरण अधिकार प्रान्टन	1,465	9,845	-1,973	728	3,575	-1,100
(ए) कुल - चूक	1,088**	—	-320	—	—	-178
(ऐ) आरक्षित निधियों और मुद्रागत स्वर्ण (बुद्धि -/ गिरावट +)	-2,563	-8,845	2,293	-728	-3,573	1,278

① भारतीय विकास बैंड सहित

*पुनर्वित्तिय ऋण की छोड़कर

तु. अ. - सुरक्षित अनुमान, अ. अ. - अपेक्षित अनुमान,

**1992-93 के दौरान भूल-चूक होने की वजह से उदारीकृत वित्तिय दर प्रवेश प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त और वृत्तांतों के लिए विभिन्न वित्तिय दर का लागू किया जाता रहा।

टिप्पणी . 1 फार्मेट का स्वरूप जिसमें भुगतान संतुलन यहाँ प्रस्तुत किया गया है उसके लिए रूपया (पैरा 6.3 देखें)

2. लेन-देन के स्वरूप पर आधारित पष्ठी या अधिकाधिक विविध पूंजी के अधीन "वैर मुद्रा स्वर्ण" के आंकड़े समायोजित कर दिये गए हैं।

3. उदारीकृत अंतर्भाव नियमों के अंतर्गत सीटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये स्वर्ण और बाँदी की छोड़कर 1992-93 के दौरान भुगतान संतुलन

परिशिष्ट सारणी 6.2 वित्तपोषण की आवश्यकता तथा वित्तपोषण के स्रोत

(करोड़ रुपये में)

संव	1992-93 (त. म.)	1991-92 (अ. म.)	1990-91 (त. म.)	कुल सातवीं पंचवर्षीय योजना	1992-93 (त. अ.)	1991-92 (अ. अ.)	1990-91 (त. अ.)	कुल सातवीं पंचवर्षीय योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. चालू खाते का बाटा - भूल चूक सहित	13,533	5,186	17,686	39,285	4,921	2,135	9,857	27,999
2. अमुकों की चुकोती	988	6,127	1,156	5,153	335	459	644	3,610
3. स्वयं ऋण चुकोती	2,994	3,260	2,140	अप्राप्त	977	1,322	1,192	अप्राप्त
4. वित्तपोषणों की आवश्यकता (1 + 2 + 3)	17,385	9,573	20,982	44,438	6,233	3,926	11,693	31,609

1	2	3	4	5	6	7	8	9
विना पोषक								
5. विदेशी सहायता	5,645 (32.4)	7,188 (75.1)	3,965 (18.9)	12,728 (28.6)	1,842 (29.6)	2,198 (74.2)	2,120 (18.9)	9,115 (28.8)
6. वाणिज्यिक उधार	-1,461 (-8.4)	4,060 (42.4)	4,588 (21.9)	10,647 (24.0)	-451 (-7.2)	1,647 (42.0)	2,558 (21.9)	754.5 (23.9)
7. घनिवासी जमाराणियाँ	5,419 (31.2)	-1,111 (-11.6)	2,756 (13.1)	10,164 (22.9)	1,949 (31.3)	-454 (-11.5)	1,536 (13.1)	7,324 (23.2)
8. अमुकी आहरण	4,231 (24.3)	3,204 (33.5)	3,334 (15.9)	—	1,623 (26.0)	1,240 (31.6)	1,858 (15.8)	—
9. अन्य वृत्ति	6,124 (35.2)	6,077 (63.4)	4,046 (19.3)	5,823 (13.1)	1,998 (32.0)	2,152 (54.8)	2,255 (19.3)	3,995 (12.6)
10. सकल मुद्रा का प्रयोग	-2,563 (-14.7)	-9,845 (-102.8)	2,293 (10.9)	5,076 (11.4)	-728 (-11.7)	-3,575 (-91.1)	1,278 (10.9)	3,627 (11.5)

(1) दृष्टाव्य नारणी 6.1 के अन्तर्गत टिप्पणी देखें।

* घनिवासी भारतीय जमाराणियों पर प्रोदभूत व्याज शामिल नहीं हैं।

वृ. अ. - मुक्त अनुमान, अ. अ. - अवस्थित अनुमान उ. न. - उल्लेख नहीं

टिप्पणी. 1. कोष्टकों के आंकड़े वित्तपोषण संबंधी आवश्यकता (मद 3) के अमरीनी डालर में परिवर्तन संबंधित वार्षिक औसत दरों पर किये गये हैं।

(1991-92 में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए लेन-देन का छोड़कर)

2. 1991-92 के वाणिज्यिक उधार के आंकड़ों में 1627 मिलियन अमरीकी डालर (1192 मिलियन बि. आ. अ.) के बाह्य विपणन बांड शामिल हैं। एमडीआर 1192 मिलियन)

3. मानवी पक्षवर्षीय ओझा के आंकड़े हाल ही के वर्षों के आंकड़े के साथ पूर्ण रूप से सुनवीय नहीं।

परिशिष्ट नारणी 6.3: भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियाँ

निम्नलिखित साह के अन्त में	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियाँ (करोड़ रुपये)				आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियाँ मिलियन अमरीकी डालर				कोष में आरक्षित (निधियों की)		
	विशेष आहरण अधिकार *	विदेशी मुद्रा आस्थियाँ	वृत्त (2-3-4)	विशेष आहरण अधिकार	विदेशी मुद्रा आस्थियाँ	कुल (6+7+8)	कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियाँ** (बि. आ. अ. मिलियन में)	आरक्षित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ (बि. आ. अ. मिलियन में)	स्थिति (बि. आ. अ. मिलियन में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मार्च 1991	200	6,824	4,388	11,416	102	3,496	2,236	5,834	4,329 (2,111)	-1,284 (-934)	---
जून 1991	133	7,111	2,382	9,926	63	3,524	1,124	4,711	3,564 (1,278)	-765 (-833)	---
सितम्बर 1991	476	8,658	4,442	13,576	184	3,353	1,722	5,259	3,838 (1,766)	-491 (-345)	---
दिसम्बर 1991	120	9,189	9,287	18,896	16	3,673	3,580	7,391**	5,093 (2,930)	766 (819)	---
मार्च 1992	233	9,039	14,578	23,850	90	3,499	5,631	9,220	6,716 (4,586)	2,387 (2,455)	---
जून 1992	297	8,932	16,125	25,354	115	3,459	6,221	9,795	6,838 (4,822)	122 (256)	---
सितम्बर 1992	88	9,053	14,937	24,078	34	3,595	5,777	9,316	6,310 (4,340)	-397 (-226)	---
दिसम्बर 1992	10	8,937	14,297	23,244	4	3,420	5,461	8,885	6,456 (4,372)	-260 (-194)	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मार्च 1993	55	10,549	20,140	30,744	16	3,380	6,434	9,832	7,033 (5,015)	317 (449)	292
जून 1993	586	11,946	20,483	33,015	187	3,807	6,553	10,547	7,518 (5,201)	485 (186)	212

*संबंधित महीनों के अन्त में तय - विशेष आहरण की विनिमय दर पर

****पिष्टले मार्ध की तुलना में घट - बढ़ ।**

****स्वर्ण को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य के निकट किया गया है।**

इसमें सरकार से 191 मिलियन अमरीकी डालर के स्वर्ण का अभिग्रहण शामिल है।

टिप्पणी :

1. विदेशी मुद्रा प्राप्तियों और विशेष आहरण अधिकारों का असुरीकी डालरों में परिवर्तन अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा निर्धारित विनियम पर किया जाता है।
2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के स्तर/बट-बट को दर्शाते हैं, इनमें स्वर्ण का पुनर्मापन शामिल नहीं है।

परिशिष्ट सारणी 6.4 : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन-देन

(विशेष आहरण अधिकार मिलियन में)

समाप्त माह		सकल आहरण	संचयी पुनः खरीद	बकाया निवल आहरण (2) - (3)	अ. म. को ऋण का निवल आहरण (-)/चुकीली(-)
1		2	3	4	
मार्च	1991	5,168	3,221	1,948	800
जून	1991	5,169	3,300	1,869	-79
सितम्बर	1991	5,804	3,396	2,408	460
दिसम्बर	1991	5,889	3,463	२,426	478
मार्च	1992	6,074	3,558	2,516	568
जून	1992	6,074	3,612	2,462	-54
सितम्बर	1992	6,536	3,696	2,840	324
दिसम्बर	1992	6,998	3,378	3,260	744
मार्च	1993	7,229	3,796	3,433	917
जून	1993	7,460	3,825	3,635	202

*पिछले साल की तुलना में घट-बढ़।

टिप्पणी : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधी सकल आहरण, पुनः खरीद और बकाया देयताओं विस्तारित निधि सुविधा, वैकल्पिक ऋण व्यवस्था तथा प्रतिपूरक और आवसिक वित्तीय सुविधा के संबंध में लेनदेनों से संबंधित हैं, तथा इनमें व्यास निधि ऋण संबंधित लेन देन शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट सारणी 6.5: भारत का विदेश-व्यापार

	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डालर			मिलियन विशेष आहरण अधिकार		
	1991-93*	1991-92	1990-91	1992-93†	1991-92	1990-91*	1992-93*	1991-92	1990-91
I. निर्यात	53,551 (21.1)	44,042 (15.5)	32,553 (17.6)	18,421 (3.1)	17,868 (-1.5)	18,145 (9.1)	14,564 (9.0)	15,173 (0.6)	15,100 (1.1)
पेट्रोलियम तेल और स्टेहक पदार्थ	1,379 (34.9)	1,022 (9.0)	938 (34.6)	476 (14.8)	415 (-20.7)	523 (24.9)	371 (11.4)	306 (-19.0)	377 (15.8)
तेल से इतर पदार्थ	51,972 (20.8)	43,020 (16.1)	31,615 (17.2)	17,945 (2.8)	17,451 (-1.0)	17,620 (8.7)	14,993 (8.7)	12,867 (1.1)	12,723 (0.7)
II. आयात	62,923 (31.5)	47,851 (10.8)	43,193 (22.0)	21,726 (11.9)	19,411 (-19.4)	24,073 (13.2)	16,941 (18.4)	14,513 (-17.7)	17,382 (4.9)
तेल तथा पेट्रोलियम	17,153	13,127	10,816	6,100	5,364	6,028	4,618	3,926	4,353
तेल व स्टेहक पदार्थ	(30.7)	(21.4)	(72.4)	(15.7)	(-11.0)	(60.0)	(17.6)	(-9.8)	(48.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तेल से उत्तर पदार्थ	45,770	34,724	52,577	15,626	14,047	18,045	12,323	10,387	13,029
	(-1.8)	(7.3)	(11.1)	(11.2)	-(22.2)	(3.1)	(18.6)	(-20.1)	-(4.5)
III व्यापार संतुलन	-9,572	-3,309	-10,640	-3,305	-1,545	-5,910	-2,577	-1,140	-4,282
नेल-- संबंधी शेष	-15,774	-12,105	-9,878	5,624	-4,994	5,505	-4,247	-3,620	3,975
नेल से उत्तर शेष	+6,202	+8,296	-762	+2,319	+3,404	-425	+1,670	+2,480	-2.0

* धर्मेतिम

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में घटबढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय

परिशिष्ट सारणी 4.6: भारत के मुख्य पण्यों का निर्यात

पण्य समूह	करोड़ रुपये			प्रतिशत घट-बढ़		मिलियन अमरीकी डालर			प्रतिशत घट-बढ़	
	1992-93*	1991-92	1990-91			1992-93*	1991-92	1990-91		
	(अ)	(अ)	(2)/(3)	(3)/(4)			(7)/(8)	(8)/(9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घ. प्राथमिक उत्पाद:	10,937	10,187	7,754	7.4	31.4	3,776	4,132	4,322	-8.6	-4.4
उनमें से:	(20.5)	(23.1)	(23.8)			(20.5)	(23.1)	(23.8)		
(क) कृषि और उससे संबंधित उत्पाद	8,791	7,895	6,019	11.4	31.2	3,055	3,303	3,153	-5.2	-4.5
	(16.5)	(17.9)	(18.5)			(16.5)	(17.9)	(18.5)		
(ख) अयस्क और खनिज	2,146	2,292	1,735	-6.4	32.1	741	930	967	20.3	33.9
	(4.0)	(5.2)	(5.5)			(4.0)	(5.2)	(5.3)		
आ. विनिर्मित वस्तुएं	40,375	22,413	23,510	24.6	39.1	15,941	15,149	12,991	6.0	1.2
	(75.7)	(73.6)	(71.6)			(75.7)	(73.6)	(71.6)		
उनमें से:										
(क) जमड़ा और जमड़े की वस्तुएं	3,692	3,128	2,600	18.1	20.3	1,275	1,269	1,449	0.5	12.4
	(6.9)	(7.1)	(8.0)			(6.9)	(7.1)	(8.0)		
(ख) रसायन और उससे संबंधित उत्पाद	3,615	3,648	2,344	-0.9	55.6	1,248	1,480	1,507	-15.6	13.2
	(8.8)	(8.3)	(7.2)			(6.8)	(8.3)	(7.2)		
(ग) इंजीनियरी वस्तुएं	7,140	5,554	4,038	28.6	57.5	2,465	2,253	2,250	9.4	0.1
	(15.4)	(12.6)	(12.4)			(13.4)	(12.6)	(12.4)		
(घ) वस्त्र विनिर्मित वस्तुएं	12,423	9,872	6,775	25.8	45.7	4,289	4,005	3,776	7.1	6.1
	(25.3)	(22.4)	(20.8)			(25.3)	(22.4)	(20.8)		
उनमें से:										
(i) सूती धागा,	3,929	5,204	2,100	22.6	52.6	1,356	1,500	1,170	4.4	11.1
	(7.4)	(7.3)	(6.5)			(7.4)	(7.3)	(6.5)		
(ii) सिले-सिलारे वस्त्र	6,918	5,422	4,012	27.6	55.1	2,289	2,199	2,256	8.6	-1.6
	(15.0)	(12.5)	(12.5)			(13.0)	(12.3)	(12.5)		
(3) वस्त्रकारी की वस्तुएं	10,818	8,549	6,167	29.9	35.4	3,746	3,387	3,437	10.6	-1.5
	(20.3)	(19.0)	(18.9)			(20.3)	(19.0)	(18.9)		
उनमें से:										
(i) रत्न और आभूषण	8,839	6,750	5,247	31.0	28.6	3,053	2,738	2,924	11.5	-8.4
	(16.6)	(15.5)	(16.1)			(16.6)	(15.3)	(16.1)		
(2) खनिज और जिकनाई \$ की वस्तुएं	1,379	1,022	938	34.9	9.0	476	415	523	14.8	-20.7
	(2.6)	(2.5)	(2.9)			(2.6)	(2.3)	(2.9)		
ई अन्य	659	419	551	57.2	-23.9	228	170	50.7	55.8	-44.6
	(1.2)	(1.0)	(1.7)			(1.2)	(1.0)	(1.7)		
कुल निर्यात (क+ख+ग+घ)	53,351	44,042	32,553	21.1	25.3	18,421	17,866	18,143	3.1	-1.5

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल निर्यात से प्रतिशत दर्शाते हैं।

*धर्मेतिम: केवल कच्चे पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित हैं।

*मशीनरी, परिवहन, उपकरण, धातु उत्पादक, जिसमें लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर पुर्जों और योजना सामान से संबंधित।

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और आंक संकलन महानिदेशालय

परिशिष्ट सारणी VI. 7: भारत के मुख्य पण्यों का आयात

पण्य समूह	करोड़ रुपये			प्रतिशत घट-बढ़		मिलियन अमरीकी डालर		शत व -बढ़		
	1992-93*	1991-92	1990-91	(2)/(3)	(3)/(4)	1992-93*	1991-92	(7)/(8)	(8)/(9)	(9)/(10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 थोक आयात	27,736	21,537	19,685	10.0	8.4	9,754	8,694	10,971	12.2	-20.8
उनमें से	(44.1)	(44.6)	(55.6)			(44.9)	(44.8)	(45.6)		
अ) पेट्रोलियम										
पेट्रोलियम के उत्पाद	17,155	13,127	10,816	30.7	21.4	6,100	5,364	6,028	13.7	-11.0
तथा संबंधित सामग्री	(27.5)	(27.4)	(25.0)			(28.1)	(27.6)	(25.0)		
आ) थोक उपभोक्ता वस्तुएं	1,413	677	999	108.5	-12.0	488	274	55.7	77.7	-50.7
उनमें से:	(2.2)	(1.4)	(2.5)			(2.2)	(1.4)	(2.3)		
(क) अनाज और अनाज से बनी चीजें	924	175	182	452.9	-4.9	319	70	105	155.6	-30.8
(ख) खाद्य तेल	172	248	126	-10.4	-25.9	-60	101	182	-40.8	-44.6
(ग) दालें	316	255	481	23.8	-46.9	109	104	268	5.5	-61.4
(घ) चने	--	1	9	--	-91.1	--	--	5	--	--
(इ) अन्य थोक मर्दे	9,170	7,532	7,870	21.7	-4.3	3,166	3,056	4,586	2.6	-30.3
उनमें से:	(14.6)	(17.7)	(18.2)			(14.6)	(15.7)	(18.2)		
(क) उर्वरक	2,827	2,352	1,766	20.2	33.2	976	954	984	2.3	-3.1
(1) कच्चा	458	455	347	0.6	31.2	158	185	193	14.4	-4.5
(2) गंधक और बिना तपाये लोहे के पाइराइट	350	307	278	14.1	10.2	121	124	15.5	-2.9	-19.8
(3) विनिर्मित	2,020	1,591	1,141	27.0	9.4	697	645	633	8.1	1.5
(ख) अलौह धातुएं	1,119	840	1,102	33.3	-23.8	386	341	614	13.4	-44.5
(ग) कागज, गत्ता और उनसे बनी वस्तुएं (यद्यपि कागज सहित)	483	488	456	-1.1	7.0	167	198	254	-15.8	-22.1
(घ) कच्चा रबड़	258	132	226	41.3	-19.6	39	74	126	20.7	41.5
(ङ) लुई, और रेशी कागज	400	299	458	34.0	-34.8	118	121	255	255	-52.3
(च) धातुमय अयस्क और धातु की छीलन	1,792	1,175	1,528	52.5	-23.1	619	477	852	29.9	-44.1
(छ) लोहा और स्पात	2,291	2,197	2,334	4.3	-5.9	791	891	1,301	-11.2	-31.5
11 फुटकर आयात	35,187	26,514	25,508	32.7	12.8	11,972	10,717	13,102	11.7	-18.2
	(45.9)	(55.4)	(54.4)			(55.1)	(55.2)	(54.4)		
अ) पूंजीगत वस्तुएं	12,926	10,426	10,471	23.9	-0.5	4,463	4,211	5,857	5.4	-27.5
	(20.5)	(21.8)	(24.2)			(20.5)	(21.8)	(24.2)		
अ) मुख्यतः निर्यात से संबंधित मर्दे	12,030	8,828	6,603	36.3	33.7	4,154	3,581	3,680	16.0	-2.7
	(19.1)	(18.4)	(15.3)			(19.1)	(18.4)	(15.3)		
(क) मोती, कीमती और अर्द्धकीमती पत्थर	7,011	4,825	3,738	45.3	29.1	2,421	1,957	3,083	23.7	-6.0
(ख) रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक	4,242	3,399	2,289	24.8	48.5	1,465	1,379	1,276	6.2	8.1
(ग) वस्तुयोगी घागा, वस्त्र आदि	417	358	443	23.0	-21.7	144	117	247	5.1	-44.4
(घ) काजू की गिरी कच्ची	860	267	134	35.1	99.0	124	108	75	15.0	44.9
(ङ) अन्य	10,255	7,252	6,634	41.4	11.7	3,355	2,901	3,586	15.6	19.0
उनमें से:	(16.1)	(15.2)	(14.9)			(15.4)	(15.0)	(14.9)		
(क) कृत्रिम रेजिन तथा प्लास्टिक के सामान	1,206	1,401	1,095	-15.9	28.1	417	569	610	-26.8	-6.8
(ख) व्यावसायिक वैज्ञानिक तथा गृह संबंधी सामान आदि	1,484	1,004	1,060	47.8	-5.5	518	407	591	26.8	31.0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ब) औपघ्रीय और मव- जाय उत्पाद		1,379	1,036	789	33.1	31.1	476	420	440	13.1 -4.4
(ङ) रसायन सामग्री और उसके उत्पाद		711	559	468	27.7	19.2	246	217	261	8.7 -13.2
		450	338	236	33.0	18.2	155	137	159	13.2 14.0
(च) घटाने के लिये विनिश्चित वस्तु		250	219	301	14.0	7.9	86	89	111	31.9 -21.4
कुल घाटान (I+II)		82,927	47,851	43,193	31.5	10.8	21,726	19,411	24,073	11.9 -19.4

***अ--अंतिम**

टिपणी कोष्ठकों में दिये गये अंकड़े कुल आयतन प्रतिशत दर्शाते हैं।

कोट. वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय.

परिशिष्ट सारणी 6.8: शर्या भगतान क्षेत्र तथा सामान्य मद्रा क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार

	रु. म.क्षे.			सा.म.क्षे.			फोड		
राजकोषीय वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार	निर्यात	आयात	व्यापार	निर्यात	आयात	व्यापार योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	करोड़ रुपाई								
1985-86	2,510	3,071	219	8,585	17,587	-9,002	10,895	19,658	-8,763
1986-87	2,231	1,359	872	10,221	18,737	-8,516	12,452	20,096	-7,644
	(-3.4)	(-34.4)		(19.1)	(6.5)		(14.1)	(2.2)	
1987-88	2,444	1,885	559	11,240	20,559	-7,129	15,674	22,244	-6,570
	(9.5)	(18.7)		(29.4)	(8.7)		(25.9)	(10.7)	
1988-89	1,163	1,655	1,507	17,070	26,580	-9,510	20,232	28,215	-8,003
	(29.4)	(12.2)		(29.0)	(10.6)		(29.1)	(26.9)	
1989-90*	5,172	2,679	2,494	22,508	32,777	10,229	27,681	35,416	-7,735
	(63.6)	(61.9)		(31.9)	(23.2)				
1990-91	5,507	2,869	2,638	27,046	40,524	-12,278	32,553	42,193	10,640
	(6.5)	(7.1)		(20.2)	(23.2)		(17.6)	(22.0)	
1991-92	4,433	1,970	2,463	39,609	35,881	-6,272	44,042	47,851	-3,809
	(-19.5)	(-31.1)		(46.5)	(11.8)		(55.1)	(10.8)	
1992-93*	1,970	1,076	894	51,181	61,847	-10,466	53,151	67,921	-9,572
	(-55.6)	(-45.4)		(29.7)	(34.8)		(21.1)	(31.5)	
	मिलियन अमेरिकी डालर								
1985-86	1,888	1,693	195	7,017	14,374	-7,358	8,905	16,067	-7,162
1986-87	1,746	1,064	682	7,998	14,662	-6,664	9,744	15,726	-5,982
	(-7.5)	(-37.2)		(14.0)	(2.0)		(9.4)	(-2.1)	
1987-88	1,885	1,454	431	10,204	15,702	-5,498	12,039	17,156	-5,067
	(8.0)	(56.7)		(27.3)	(7.1)		(24.1)	(9.1)	
1988-89	2,183	1,143	1,041	11,787	18,354	-6,567	13,971	19,497	-5,526
	(15.8)	(21.4)		(15.5)	(16.9)		(15.6)	(13.6)	
1989-90*	3,107	1,609	1,498	13,519	19,663	6,144	16,626	21,272	5,646
	(42.3)	(40.8)		(14.7)	(7.1)		(19.0)	(9.1)	
1990-91	3,069	1,499	1,470	15,073	22,474	-7,400	18,143	24,072	-5,930
	(-1.2)	(-0.6)		(11.5)	(14.3)		(9.1)	(13.2)	
1991-92	1,798	799	999	16,068	18,612	-2,544	17,863	19,411	-1,548
	(-41.4)	(-50.0)		(6.6)	(-17.2)		(-1.5)	(-19.4)	
1992-93*	680	272	308	17,741	21,354	-3,614	17,421	21,726	-4,305
	(-62.2)	(-50.5)		(10.4)	(14.7)		(3.1)	(11.9)	

*अन्तिम

प्रिण्टिंग : (1) कोठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट बढ़ाव दर्शाते हैं.

(2) 1989-90 तक हमारे के देशों में पांच देशों प्रधान सोवियत गण, रूसिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और गोलैंड शामिल हैं, 1990-91 से उक्त में से पहले के तीन देश शामिल हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक मासिकता और एक संकलन महानिदेशालय

करोड रुपये

सं. —संशोधित

अ. ---अनन्तिम

टिप्पणी : 1. ऋणों में गैर-सरकारी ऋण शामिल हैं, परंतु आपूर्तिकर्ता ऋण तथा वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं हैं।

2. अनदानों में पी.एल. 480-II अनदान शामिल नहीं है।

3. अंगकडे अमरीकी डालर में वार्षिक औसत दरों पर परिवर्तित किये गये हैं।

स्रोत : सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, भारत सरकार ।

तद्विषय मन्त्रालयों VI 10 अविवासी विदेशी रुग्ण खाता योजनाओं के अन्तर्गत जमरानि की देयताएं

(करोड़ रुपये)

भारतवासी (विदेशी) खाता रुपया																	विदेशी मुद्रा अतिरिक्त खाता (@@)																
मार्च के अंत में		वर्ष के दौरान आवक @	कुल बकाया*	वर्ष के दौरान आवक	बकाया													कुल आवक	बकाया राशियों का कुल जोड़														
		करोड़ रुपये	मिलियन करोड़ डालर	मिलियन करोड़ अमेरिकी डालर	मिलियन करोड़ अमेरिकी डालर	पोड स्टॉक	दृष्टा कोण	देन	जोड़ करोड़ रुपये	(8 से 11) मिलियन अमेरिकी डालर	रुपये (2+6) डालर (13+7)	अमेरिकी रुपये डालर (4+12) डालर (5+13)																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
1988	477	368	5,107	3,942	1,363	1,051	4,406 (3,410)	541 (222)	—	—	4,947	3,827	1,840	1,419	10,054	7,769																	
1989	235	162	5,899	3,774	2,230	1,540	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,255	5,275	2,465	1,702	14,154	9,049																	
1990	277	166	6,507	3,777	2,165	1,309	9,304 (5,409)	337 (119)	1,028 (1,013)	655 (60,327)	11,324	6,586	2,442	1,475	17,831	10,363																	

	1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1991	156	84	7.349	3.746	255	168	11,270 (5,754)	305 (89)	1,005 (874)	825 (59,403)	13,405	6,838	411	252	20,754	10,584	
1992	-44	-27	8.071	2.5913,605	-1,611	10,390 (3,978)	2,002 (4,451)	447 (284)	859 (44,028)	13,608	5,256	-3,649	-1,638	21,679	7,847		
1993	111	39	9.062	2.884	223	86	10,107 (3,236)	3,557 (752)	431 (222)	2,477 (91,020)	16,572	5,287	334	125	25,634	8,171	
1993 (अप्रैल-जून)	-191	-60	9.099	2.900	-592	-189	9,364 (2,988)	3,621 (774)	474 (258)	2,677 (91,577)	16,136	5,167	-783	-249	25,235	8,067	

② अनुमोदित प्रोद्भूत व्याज को छोड़कर

*प्रोद्भूत व्याज सहित

② प्रोद्भूत व्याज शामिल नहीं है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित मुद्राओं में मिलियन में बताया जमातियां हैं।

2. अमरीकी डॉलर में परिवर्तन आंकड़ों के मामले में वार्षिक औसत दर पर तथा बताया क्षेत्र राशियों के मामले में बर्षों की दर पर किये गये हैं।

3. वर्ष 1993 के अतिवासी (विदेशी) रकमा आंकड़े अतिवृत्ति हैं।

परिशिष्ट सारणी VI. 11 : विदेशी मुद्रा अतिवासी खाते की जमा राशियों पर व्याज दरे

(प्रतिशत वार्षिक)

अमरीकी डॉलर	पौंड स्टर्लिंग																द्व्युष माह			येन
प्रभावी तारीख	6 महीने व उससे अधिक तथा 1 वर्ष से कम		2 वर्ष व उससे अधिक तथा 3 वर्ष से कम		केवल 3 वर्ष व उससे अधिक तथा 1 वर्ष से कम		केवल 2 वर्ष व उससे अधिक तथा 1 वर्ष से कम		केवल 2 वर्ष व उससे अधिक तथा 1 वर्ष से कम		6 महीने व उससे अधिक तथा 1 वर्ष से कम		केवल 3 वर्ष व उससे अधिक तथा 1 वर्ष से कम		6 महीने व उससे अधिक तथा 1 वर्ष से कम		केवल 3 वर्ष व उससे अधिक तथा 1 वर्ष से कम			
	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
27 जनवरी, 1992	5.50	5.75	6.75	7.50	12.00	12.00	12.00	12.00	10.25	10.25	10.50	10.50	7.00	7.00	7.00	7.00				
27 मार्च, 1992	5.75	6.25	7.50	8.25	12.00	12.00	12.00	12.00	10.50	10.50	10.50	10.50	6.00	6.00	6.50	7.00				
13 जुलाई, 1992	4.75	5.25	6.25	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.50	10.50	10.50	10.50	5.75	6.00	6.00	6.50				
12 अक्टूबर, 1992	4.00	4.50	5.50	6.25	9.75	10.00	10.00	10.25	9.75	9.75	9.75	9.75	4.75	5.00	5.25	5.75				
2 नवंबर, 1992	4.50	5.00	6.00	6.75	8.00	8.00	8.75	9.25	9.00	9.00	9.00	9.00	4.75	5.00	5.25	5.75				
22 फरवरी, 1993	4.25	4.75	5.75	6.50	7.00	7.00	7.50	8.00	8.75	8.50	8.25	8.25	4.25	4.50	4.75	5.25				
15 मार्च, 1993	4.00	4.25	5.25	5.75	6.75	6.75	7.25	7.75	8.00	8.00	8.00	8.00	4.25	4.50	4.50	5.00				
10 मई, 1993	4.00	4.25	5.00	5.50	6.75	7.00	7.75	8.25	8.00	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00				
8 जून, 1993	4.25	4.50	5.50	6.00	6.75	7.00	7.75	8.25	8.00	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00				
29 जुलाई, 1993	4.25	4.75	5.50	6.00	7.75	7.00	7.50	8.00	7.75	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00				

परिशिष्ट सार्ग VI. 12: भारत के विदेशी ऋण

भय	भारत के अंत में			
	1993अ	1992	1991	1990
I. ऋण-वि	77,398 (24,808)	68,263 (23,089)	40,386 (20,800)	32,886 (19,164)
II. सरकारी उधार	71,350 (23,139)	63,787 (21,651)	38,329 (19,457)	31,575 (18,399)
(i.) न्यायनी	43,117 (15,474)	40,990 (14,320)	25,849 (13,377)	21,760 (12,672)
(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	47,073 (15,140)	40,017 (13,974)	25,221 (13,932)	21,055 (12,261)
(ख) अन्य	1,039	973	628	705
(ii) गैर-न्यायनी	(334) 23,833 (7,665)	(346) 22,797 (7,331)	(325) 12,589 (6,510)	(311) 9,815 (5,727)
(क) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक)	21,355 (6,868)	21,134 (6,796)	12,161 (6,293)	9,752 (5,690)
(ख) अन्य	2,478 (797)	1,663 (535)	419 (217)	63 (37)
III. गैर-सरकारी उधार	5,448 (1,759)	4,476 (1,438)	1,957 (1,013)	1,311 (765)
(1) न्यायनी	0	0	0	0
(2) गैर-न्यायनी	5,448 (1,759)	4,476 (1,438)	1,957 (1,013)	1,311 (765)
(क) सरकारी क्षेत्र	1,789 (578)	1,124 (138)	303 (157)	158 (92)
(1) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1,312 (424)	962 (398)	303 (157)	158 (92)
(2) अन्य	477 (154)	462 (150)	0	0
(ख) निजी संस्थाएँ	2,869 (826)	2,349 (754)	1,270 (657)	799 (465)
(1) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1,777 (574)	1,720 (553)	872 (451)	503 (292)
(2) अन्य	1,092 (352)	629 (201)	398 (206)	296 (173)
(ग) निजी क्षेत्र	790 (255)	703 (226)	384 (199)	354 (208)
(1) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	687 (222)	625 (201)	330 (171)	313 (184)

मद	मात्र के अंत में			
	1993अ	1992	1991	1990
(2) अन्य	103 (33)	78 (25)	54 (28)	41 (24)
II. द्विपक्षीय	48,623 (15,629)	47,603 (15,466)	27,378 (14,168)	22,993 (13,564)
अ. सरकारी उधार	40,575 (13,050)	40,371 (13,099)	23,065 (11,936)	19,444 (11,489)
(i) रियायती	40,575 (13,050)	40,371 (13,099)	23,065 (11,936)	19,444 (11,489)
(ii) गैर-रियायती	0	0	0	0
(आ) गैर-सरकारी उधार	3,048 (2,579)	7,232 (2,367)	4,313 (2,232)	3,549 (2,075)
(i) रियायती	1,253 (403)	928 (348)	514 (266)	441 (261)
	0	0	0	7
(क) सरकारी क्षेत्र				(4)
(ख) वित्तीय संस्थाएं	1,253 (403)	928 (348)	514 (266)	431 (255)
(ग) निजी क्षेत्र	0	0	0	12 (2)
(ii) गैर-रियायती	6,795 (2,176)	6,304 (2,019)	3,799 (1,966)	3,108 (1,814)
(क) सरकारी क्षेत्र	4,726 (1,513)	4,472 (1,432)	2,957 (1,530)	25,81 (1,507)
(ख) वित्तीय संस्थाएं	1,571 (503)	1,236 (396)	527 (273)	271 (158)
(द) गैर-सरकारी क्षेत्र	498 (160)	596 (191)	315 (163)	256 (149)

सद	साल के अंत में			
	1993	1992	1991	1990
III. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	14,985	89,34	5,132	2,572
IV. निर्यात ऋण	(4,799)	(3,451)	(2,623)	(1,493)
	13,127	12,418	8,374	8,002
	(4,206)	(3,990)	(4,301)	(4,655)
(क) क्रेता ऋण—उधार	3,989	3,566	2,230	1,877
	(1,277)	(1,142)	(1,154)	(1,096)
	2,050	1,380	933	950
(ख) आपूर्ति कर्ता ऋण	(656)	(442)	(483)	(555)
(ग) द्विपक्षीय ऋण के निर्यात ऋण संघटक	3,314	2,428	1,390	1,340
	(1,065)	(791)	(719)	(790)
(घ) रक्षा संबंधी निर्यात ऋण	3,774	5,044	3,821	3,835
	(1,208)	(1,615)	(1,945)	(2,214)
V. बाणिज्यिक उधार	36,251	35,664	19,727	15,988
	(11,606)	(11,700)	10,209	(9,335)
(क) बाणिज्य बैंक ऋण	20,156	20,933	13,200	11,453
	(6,453)	(6,704)	(6,831)	(6,678)
(ख) प्रतिभूतिकृत उधार राशियां (अ. बि. स. सहित)	13,990	13,219	5,840	4,227
	(4,479)	(4,512)	(3,522)	(2,468)
(ग) ऋण/प्रतिभूतिकृत उधार राशियां, भावि, बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय गारंटी (प्रत्याभूति) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सहित (इन्स्यू)	2,105	1,512	687	308
	(674)	(484)	(356)	(180)
VI. अनिवासी भारतीय और विदेशी मुद्रा (बी एण्ड ओ) जमा राशियां (एक वर्ष की परिपक्वता से अधिक)	23,124	19,581	16,418	13,988
	(7,403)	(7,056)	(8,319)	(8,135)
(क) अनिवासी भारतीय जमा राशियां उनमें से विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा राशियों पर उपचित ब्याज (ब्याज भना)	22,296	18,934	16,231	13,988
	(7,138)	(6,806)	(8,224)	(8,135)
	4,474	3,749	2,379	1,729
	(1,432)	(1,448)	(1,212)	(1,004)
	828	647	187	0
(ख) विदेशी मुद्रा (बी एण्ड ओ) जमा राशियां	(265)	(250)	(95)	
VII. कुल दीर्घवधि ऋण (I से VI)	2,13,508	1,92,463	1,17,415	99,439
	(68,541)	(64,753)	(60,520)	(56,346)
VIII भत्तापक्षि ऋण	13,909	15,881	11,683	9,465
(क) अनिवासी भारतीय जमा राशियां	(4,453)	(5,556)	(6,006)	(5,185)
	7,837	6,494	6,902	5,562
(एक वर्ष की परिपक्वता से कम)	(2,509)	(2,489)	(3,572)	(3,232)

1	2	3	4	5
(ब) विदेशी मुद्रा (बी एण्ड सी) जमा राशियाँ	2,433 (779)	924 (357)	328 (167)	00 00
(ग) अन्य (6 महीने से अधिक)	3,639 (1,165)	8,463 (2,710)	4,453 (2,267)	3,903 (2,253)
IX. कुल जोड़ (VII+VIII)	2,27,417 (72,994)	2,08,344 (70,309)	1,29,098 (66,526)	1,03,904 (61,831)
भाषण मदें				
6 महीने के अस्पामबि ऋण	5,661 (1,793)	4,738 (1,517)	4,976 (2,533)	3,427 (2,004)
रपए आपूर्तिनार्ता का ऋण	67 (21)	72 (20)	65 (33)	58 (33)
असैमिक सफल ऋण	2,965 (934)	3,085 (1,178)	2,259 (1,164)	1,741 (1,016)
नैर-असैमिक सफल ऋण	30,177 (9,661)	28,796 (9,222)	22,875 (11,645)	17,276 (9,972)
X कुल (अभी मय सहित)	2,66,167 (85,493)	2,45,038 (82,246)	1,59,273 (81,901)	1,28,451 (74,856)

ऋण संकेतक

ऋण स्टाक—मूल्य देसी उत्पाद अनुपात

(प्रतिशत में)

(बेसों मदी की छोड़कर)

32.4 34.2 24.9 23.3

ऋण स्टाक—मूल्य देसी उत्पाद अनुपात

(प्रतिशत में) (अभी मदी सहित)

37.9 40.2 30.0 28.3

कर्ज शोधन—मूल्य (राजकोषीय वर्ष के लिए)

(प्रतिशत में)

29.1 29.2 25.2 24.9

नैर-असैमिक ऋण पर कर्ज शोधन की छोड़कर

30.8 31.6 30.5 29.9

नैर-असैमिक ऋण—मूल्य—सहित ।

अतिवासी भा—मूल्य—अधिकतम मात्रा शामिल है ।

धन : अनस्थित : ऋण नहीं

असंशोधित धन

टिप्पणी : दिए गए आंकड़े अस्थायी डेटा पर आधारित हैं ।

परिमित सारणी VI.13 : रुपए की विनिमय दरें

(विशेष आन्तरिक अधिकार/विदेशी मुद्रा की प्रति यूनिट के बराबर रुपए)

वर्ष	विशेष आन्तरिक अधिकार	धनरोपी डॉलर	पौंड स्टर्लिंग	जमूना मार्क	जापानी येन
1	2	3	4	5	6
घ. मासिक औसत दरें* (अप्रैल—मार्च)					
1988-89	19.2619	14.4817	25.5959	8.0494	0.1130
1989-90	21.3684	16.6492	26.9179	9.0922	0.1166
	(—9.9)	(—13.0)	(—4.9)	(—11.5)	(—3.1)
1990-91	24.8491	17.9428	33.1930	11.4351	0.1279
	(—14.0)	(—7.2)	(—18.9)	(—20.5)	(—8.8)
1991-92	33.4325	24.4737	42.5152	14.6248	0.1845
	(—25.7)	(—26.7)	(—21.9)	(—21.8)	(—30.7)
(अप्रैल—फरवरी)					
1991-92	33.2584	24.3449	42.3183	14.4449	0.1835
1992-93	36.5615	25.9701	48.0532	16.7031	0.2072
	(—9.0)	(—6.3)	(—11.9)	(—13.5)	(—11.4)
घा. मासिक औसत दरें					
मार्च 1992*	35.3472	25.8901	44.6775	15.6033	0.1949
मार्च 1992 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	—	29.4551	51.9558	18.1709	0.2270
मार्च 1993 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	—	31.5256	46.9520	19.1156	0.2695
मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यह्रास (—)					
मार्च 1992 की तुलना में मार्च 1993 में %	—	—6.6	13.1	—4.9	—15.8
जून 1992*	36.5507	25.8909	47.7889	16.4646	0.2043
जून 1992 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	—	30.2361	55.9065	19.1931	0.2383
मार्च 1993 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	—	31.4668	47.4174	19.0123	0.2929
में % मूल्य वृद्धि (+)/मूल्यह्रास/(—)					
जून 1992** की तुलना में जून 1993**	—	—3.7	17.9	1.0	—18.6
ड. निम्नलिखित की विनिमय दरें:					
31 मार्च 1992*	35.5143	25.8900	44.9490	15.7294	0.1948
31 मार्च 1992 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	—	31.2256	53.6913	18.8501	0.2328
31 मार्च 1993 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	—	31.2354	46.6200	19.2864	0.2699
30 जून 1992*	37.0530	25.8909	49.2789	17.0182	0.2061
30 जून 1992 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	—	30.6607	58.4795	20.2429	0.2460
30 जून 1993 (भा. वि. मु. न्या. सं.)*	—	31.3381	47.3373	18.5701	0.2937

*रिज़र्व बैंक की अधिकारिक दर दर्शाता है।

**भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की सांकेतिक दर दर्शाता है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए आंकड़े रुपए की प्रतिगत मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यह्रास (—) दर्शाते हैं।

[सं. एक. 19/18/93—बी. जो. I]

एम. एस. बीतारामन, जवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 3rd December, 1993

S.O. 1416.—In accordance with Section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1993.

THE ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

for the Year July 1, 1992 to June 30, 1993

PART ONE-ECONOMIC REVIEW

I. POLICY DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES

1.1 The year 1992-93 (July-June) was marked by encouraging progress towards economic stabilisation and revival of activity. The wide-ranging reform measures undertaken since July 1991 have begun to yield result: a deceleration in inflation, a recovery in GDP growth and stability in the external payments position.

1.2 The thrust of the new economic policy is towards creating a competitive environment in the economy as a means of improving productivity and efficiency of the system. Towards this end, there has been a further widening and deepening of the reform process during 1992-93 especially in the areas of fiscal monetary, exchange rate and trade policy.

THE PROCESS OF FISCAL ADJUSTMENT

1.3 A number of policy initiatives have been introduced in the fiscal area since July 1991, with a view to reducing the gross fiscal deficit of the Union Government in relation to domestic product (GDP). The ratio of gross fiscal deficit to GDP was brought down from 8.41 per cent in 1990-91 to 5.96 per cent in 1991-92. It further came down to 5.70 per cent in 1992-93 and is expected to be around 4.71 per cent in 1993-94 as per the budget estimates. The revenue deficit of the Centre as a percentage of the gross fiscal deficit remains high. It was 45.5 per cent in 1992-93 and will be around 48.0 per cent in 1993-94, as per budget estimates. As a result, the resource gap on revenue account has been filled by high-cost borrowed funds. Interest payments accounted for 41.5 per cent of revenue receipts in 1992-93 and are expected to rise to 45 per cent in 1993-94. Reduction in the gross fiscal deficit and Government borrowing will be necessary to bring down the share of interest payments as well as monetisation of the deficit. This however, has not happened in the first quarter of 1993-94, which witnesses a sharp rise in the conventional budgetary deficit and also a large increase in net Reserve Bank credit to the Central Government.

1.4 The present fiscal situation reflects the combined effects of lower than desired growth of output and reductions in tax and duty rates. Receipts lagged behind expenditures, even though reductions have been made in fertiliser and export subsidies, non-Plan grants, loans to State Governments and Union Territories and the share of capital outlays in total expenditure has declined.

1.5 Tax policies have been formulated against the backdrop of the recommendations of the Report of the Tax Reforms Committee (Chairman : Professor Raja J. Chelliah). The tax reforms undertaken so far in respect of indirect taxes (customs tariffs and excise duties) have resulted in substantial revenue losses, a large part of which has been borne by the Central Government. The initiatives in regard to direct taxes provide little in the way of additional revenues. Fiscal disequilibrium, as reflected in burgeoning revenue deficit, poses serious problems to the successful implementation of the reform process.

MONETARY POLICY : OBJECTIVES AND INSTRUMENTS :

1.6 The considerations which underlay the monetary policy during 1992-93 were : (i) bringing about a deceleration in monetary expansion with a view to containing inflation without undermining the revival of economic activity; (ii) reducing the monetised deficit (net Reserve Bank credit to the Centre) consistent with the Government's objective of bringing down gross fiscal deficit; and (iii) boosting exports in order to alleviate the problems of the external payments deficit.

1.7 Monetary policy in 1992-93 and the early months of 1993-94 can be broadly grouped under five major heads. First, a conscious effort was made to gradually reduce interest rates in the system as inflation rates declined and the macro economic situation improved. The opportunity was also taken to progressively rationalise the lending rate structure. Secondly, as the macro-economic crisis situation had eased, a quick move back to a lower level of reserve requirements was felt to be an appropriate policy response. Measures were also taken to allow a more liberal flow of refinance to banks and institutions to augment lendable resources. Thirdly, 1992-93 was a landmark in that there was a cautious attempt to move from direct to indirect instruments of monetary control and an attempt is being made to develop the tool of open market operations as an effective instrument of monetary control. As part of this strategy, attempts are being made to develop an adequate institutional framework to facilitate an active secondary security market. Fourthly, a number of policy measures were undertaken to improve the flow of credit to sectors such as exports priority sector including agriculture and small scale industry, and medium and large industry. Finally, as part of the endeavour to strengthen the financial system, considerable attention was paid to introducing measures to improve the working of the banks, financial institutions and non-bank financial companies.

1.8 The major monetary and credit policy measures undertaken during 1992-93 and the early part of 1993-94 together with their rationale are set out below :

(a) Interest Rates

(i) Lending Rates

1.9 The minimum lending rates of scheduled commercial banks for credit limits of over Rs. 2 lakhs had been raised, in response to the high inflation rate and the overall deterioration in the macro-economic situation, to the high level of 26.0 per cent effective October 9, 1991. With the abatement of inflationary pressures, the minimum rate was reduced in four stages by one percentage point each from 20.0 per cent to 16.0 per cent effective June 24, 1993. Furthermore, over the same period, the structure of lending rates was rationalised so that there are now only three categories as against since 1991 (Appendix Table 1.1 and 1.2).

(ii) Deposit Rates

1.10 In view of the deceleration in the inflation rate and the reduction in lending rates, a reduction in bank's maximum deposit rates was rendered possible. This was effected in two stages, enabling banks to maintain their economic viability. Rates on domestic term deposits of 46 days and above for scheduled commercial banks were reduced by one percentage point each effective October 9, 1992, from 'not exceeding 13.0 per cent' to 'not exceeding 12.0 per cent' and again effective March 1, 1993, to 'not exceeding 11.0 per cent' per annum. The rate on domestic saving deposits which was raised from 5.0 per cent to 6.0 per cent effective April 24, 1992 was lowered to 5.0 per cent effective July 1, 1993. Thus, maximum term deposits rate, the saving deposits rate and the lending rate for limits of over Rs. 2 lakhs have been reduced to the levels prevailing before the interest rates were raised on April 13, 1991 (Appendix Table 1.3).

1.11 The interest rate on savings accounts under the Non-Resident (External) Rupee Account Deposits (NRE) scheme was raised by one percentage point to 6.0 per cent per annum with effect from October 9, 1992. Term deposits rates payable on NRE accounts were also rationalised in accordance with the domestic deposit rates. Effective Octo-

ber 9, 1992, the term deposits rates for NRE accounts for maturity of 46 days to three years and above were made subject to a single prescription of 'not exceeding 13.0 per cent per annum. This rate was reduced by one percentage point to 'not exceeding 12.0 per cent per annum', effective April 8, 1993, in line with the reduction in the interest rates on domestic deposits.

(iii) Certificates of Deposit

1.12 With a view to enabling banks to raise resources at competitive rates of interest, scheduled commercial banks as permitted to raise Certificates of Deposit (CDs) without any interest rate ceiling. To promote an orderly market for CDs, limits are prescribed for their issue, the new limits introduced effective April 17, 1993 being that CDs can be issued equivalent to 10 per cent of the fortnightly average outstanding aggregate deposits in 1991-92. This prescription translates to Rs. 20,552 crore. A sizeable part of fixed deposits is thus freed from interest rate control.

(b) Measures Relating to Reserve Requirements

1.13 One of the major objectives of the financial sector reforms is to reduce the effective tax on the banking system represented by very high reserve requirements. Since April 1992, there have been significant modifications in respect of both the statutory liquidity ratio (SLR) and cash reserve ratio (CRR) which in effect have reduced substantially the pre-emption of incremental deposits of banks, from 63.5 per cent in 1991-92 to 45.0 per cent in the first half of 1992-93 and further to about 25.0 per cent in the second half of the year. With the adjustments undertaken in the CRR in the first half of 1993-94, the effective incremental CRR would be about 0.5 per cent.

(i) Statutory Liquidity Ratio

1.14 In the context of the moderation of the gross fiscal deficit set out in the Union Budget for 1992-93, the SLR up to the base level of outstanding net demand and time liabilities (DTL) (excluding non-resident liabilities) of scheduled commercial banks (excluding regional rural banks) as on April 3, 1992 was kept unchanged at 38.50 per cent. However, for any increase in the net DTL above the April 3, 1992 level, the SLR was stipulated at 30 per cent. In October 1992, the prescribed base level of SLR was reduced from 38.05 per cent to 37.75 per cent in three steps of 0.25 percentage point each from the fortnights beginning January 9, 1993, February 6, 1993 and March 6, 1993, respectively. This reduction in the SLR was estimated to have augmented the lendable resources of banks by about Rs. 1,650 crore. With the proposed further moderation in the gross fiscal deficit in 1993-94, the base level of SLR would be further reduced by one percentage point from 37.75 per cent to 36.75 per cent in four steps of 0.25 percentage point each with the fortnight beginning August 21, 1993, September 18, 1993, October 16, 1993 and November 13, 1993, respectively. This measure is expected to enhance the lendable resources of banks by a little over Rs. 2,150 crore and, together with the reduction in the incremental SLR, would reduce the effective SLR from 38.5 per cent as on April 3, 1992 to 35.4 per cent as at the end of March 1994.

(ii) Cash Reserve Ratio

1.15 The deceleration in the inflation rate, the reduction in the fiscal deficit and the need to carry forward the financial sector reforms prompted the Reserve Bank to bring about a substantial reduction in the effective CRR in a phased manner during 1992-93 and 1993-94. Accordingly, the incremental CRR of 10 per cent was discontinued from April 17, 1992. Again, of the impounded cash balances of Rs. 3,848 crore maintained under the 10 per cent incremental CRR between May 3, 1991, and up to the level of April 17, 1992, one-third (Rs. 1,280 crore) was released in three equal instalments in the fortnights beginning October 17, 1992, November 14, 1992 and December 12, 1992, respectively, implying a reduction in the effective CRR by about 0.6 percentage point. Furthermore, the base CRR of scheduled commercial banks (excluding regional rural banks) which had remained unchanged since July 1989, was reduced by one percentage point from 15.0 per cent to 14.0 per cent in two steps of 0.5 percentage point each from the fortnights beginning April 17, 1993, and May 15, 1993, respectively. In order to minimise the fragmentation of CRR, the concession hitherto granted to scheduled commercial banks of exempting a part of CDs from the maintenance of CRR

was withdrawn. From the fortnight beginning April 7, 1993, CDs issued by banks over the pre-May 2, 1992 limit equivalent to 5 per cent of the fortnight average outstanding aggregate deposits in 1989-90, are being subjected to CRR. As such, the entire outstanding amount of CDs are now subject to the CRR. Although this increased the CRR prescription by Rs. 520 crore, the reduction in CRR would augment the lendable resources of banks by about Rs. 2,360 crore. This measure, besides strengthening the profitability of banks, would facilitate significant increase in flow of bank credit to the productive sectors of the economy.

1.16 As mentioned in the previous year's Annual Report, the interest paid on eligible cash balances attenuates the effectiveness of CRR to achieve the desired monetary effect and as such it is better to lower the CRR prescription and not pay interest on these balances rather than maintain the CRR prescription at a higher level and pay interest on these balances. The rate of interest payable on eligible balances on the basis of the increase in net DTL over the level as on March 23, 1990, was reduced from 5.0 per cent to 3.0 per cent per annum with effect from May 2, 1992, and further from October 17, 1992, no interest is paid on these balances as well as eligible cash balances maintained under the 10 per cent incremental CRR. On the eligible cash balances based on the net DTL as of March 23, 1990, interest continues to be paid at a rate of 10.5 per cent per annum.

1.17 A significant development has been that three non-resident deposit schemes viz. (i) Non-resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit Scheme (NRNR), (ii) Foreign Currency (Ordinary Non-Repatriable) Deposit Scheme (FCON) and (iii) Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme have been fully exempted from reserve requirements. It is expected that these schemes would become more attractive than the earlier FCNR and NRE schemes.*

(c) Export Credit

1.18 Various steps have been taken to provide credit support to the export sector.

(i) Flow of Credit to Export Sector

1.19 In November 1992, it was stipulated that each scheduled commercial bank should target to attain a level of export credit of 10 per cent of its net bank credit by the end of June 1993. Non-compliance in this regard could invite bank-specific policy stipulations which could include raising of reserve requirements and withdrawal of refinance facilities.

(ii) Interest Rates on Export Credit

1.20 Recognising the need to facilitate an environment for promotion of exports, it was felt that some relief in terms of lower interest rates on export credit was apposite. Accordingly, effective October 9, 1992, the interest rates on export credit (rupee) provided by scheduled commercial banks were reduced by one percentage point across-the-board. Furthermore, effective March 1, 1993, the interest rates on export credit (Rupee) provided by scheduled commercial banks were again reduced by one percentage point across-the-board (Appendix Table 1.4). Thus, the basic lending rate on export credit has been reduced from 15.0 per cent as on March 2, 1992, to 14.0 per cent effective October 9, 1992, and further to 13.0 per cent with effect from March 1, 1993. Following reduction in the minimum lending rate for advances above Rs. 2 lakh by one percentage point to 16 per cent effective June 24, 1993, the interest rates in respect of usance bills for periods beyond 90 days upto six months and beyond six months have also been reduced from 17 per cent to 16 per cent and from 22 per cent to 21 per cent, respectively.

*In addition, a number of other schemes are exempted from reserve requirements. These are : (i) Balances in Exchange Farrow's Foreign Currency (EEFC) Accounts, (ii) Balances in Foreign Currency Accounts opened by Indian Exporters, (iii) Resident Foreign Currency (RFC) Accounts opened by Returning Indians with banks in India, (iv) Resident Foreign Currency (RFC) Accounts opened with banks in India by pilots of Air India, and (v) ESCROW Accounts opened by Indian exporters entering into countertrade arrangements with their counterparts abroad.

(iii) Tax on Interest Income from Export Credit

1.21 With a view to easing the burden on the export sector, in the Union Budget for 1993-94, it was announced that the interest accruing or arising on or after April 1, 1993, to any banking company on loans and advances made by it to any exporter as export credit, would be exempt from levy of interest tax. This had the effect of reducing the effective interest rate on export credit by about one-half of one percentage point.

(iv) Rediscounting of Export Bills Abroad

1.22 The question of allowing banks to rediscount export bills abroad has been under consideration of the Bank for some time. The Committee on Structure of Export Credit had also recommended that banks be allowed to rediscount export bills abroad. With a view to improving export competitiveness, it was announced in April 1993 that authorised dealers in India would be allowed to rediscount export bills abroad at rates linked to international interest rates.

(v) Export Credit Refinance

1.23 The Reserve Bank has been providing very liberal export credit refinance facilities to commercial banks. With the very rapid increase in such refinance limits, some moderation in these facilities was necessary. Effective October 31, 1992, the export credit refinance facilities were as follows: (a) Export credit (rupee) refinance was provided upto 60 per cent of the increase in outstanding export credit over the monthly average level of 1988-89 up to the monthly average level of 1989-90 plus 110 per cent of the increase over the monthly average level of outstanding export credit in 1989-90 as against 125 per cent till then, and (b) under the refinance facility against Post-Shipment Export Credit Denominated in US Dollars, banks were eligible for export credit refinance limits equivalent to 120 per cent of such outstanding credit provided by banks as against 133-1/3 per cent till then.

1.24 As export credit refinance limits showed a phenomenal increase, reaching a historically high level of 69.2 per cent of total export credit as on March 19, 1993, it was felt that export credit refinance would need to be moderated. Accordingly, from May 15, 1993, export credit (rupee) refinance is provided to the extent of 60 per cent of the increase in outstanding export credit over the monthly average level of 1988-89 up to the monthly average level of 1989-90 plus 100 per cent of the increase over the monthly average level of outstanding export credit in 1989-90, as against 110 per cent till then. Under the refinance facility against Post-Shipment Export Credit Denominated in US Dollars, banks would be eligible for export credit refinance limits equivalent to 100 per cent of such outstanding credit provided by banks as against 120 per cent hitherto. The reduction of over Rs. 1,150 crore in the export credit refinance limits, however, has been more than compensated by larger reductions in SLR and CRR to augment the lendable resources of banks, and as such, banks would have more than adequate resources to attain the stimulated target for export credit of 10 per cent of net bank credit during 1993-94. Since the interest rate charged on export credit refinance is higher than the interest paid on cash balances maintained with the Reserve Bank, the package of measures is designed to result in a significant increase in the income of banks.

(d) General Credit Measures

1.25 Special measures were introduced on January 18, 1993 to give additional stimulus to industry and agriculture.

(i) Additional Resources to National Bank for Agricultural and Rural Development

1.26 As the prospects for agriculture improved, the sector needed larger credit support whereas the limits of the two General Lines of Credit (GLC) provided by the Reserve Bank to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) had remained unaltered since 1989-90. In view of this, and as there has also been an escalation in prices of agricultural inputs in recent years, the Reserve Bank enhanced the General Line of Credit, for short-term agricultural operations to NABARD by Rs. 400 crore from Rs. 2,700 crore to Rs. 3,100 crore. This would enable NABARD to provide larger credit to finance short-term agricultural operations dur-

ing the 1993 Rabi season. In the credit policy for the first half of 1993-94 announced in April 1993, the limits under the General Line of Credit (GLC-1) provided by the Reserve Bank to NABARD for short-term seasonal agricultural operations were further increased by Rs. 200 crore from Rs. 3,100 crore to Rs. 3,300 crore.

(ii) Special Refinance Facility to Industrial Development Bank of India

1.27 To stimulate output of capital and intermediate goods industries, the Reserve Bank in January 1993 provided accommodation to Industrial Development Bank of India (IDBI) to the tune of Rs. 400 crore by way of special refinance facility at a fixed rate of interest of 14.0 per cent per annum. Another Rs. 200 crore were made available out of IDBI's own resources. The short-term accommodation was provided to IDBI under Section 17(4H)(b) of the RBI Act, 1934, at a fixed rate of interest of 14.0 per cent per annum under a special refinance facility to IDBI. The additional financial assistance through bill discounting and other schemes will be available to manufacturers of commercial vehicles, machinery manufacturers, hire-purchase and leasing companies and road transport corporations.

(iii) Lending Discipline and Norms

1.28 The Reserve Bank has relaxed norms for calculating maximum permissible bank finance (MPBF). Effective January 18, 1993, only two-third of the term loan instalments falling due for the repayment during the next 12 months are to be treated as current liabilities and the remaining one-third would be kept outside the current liabilities for the purpose of calculating MPBF. This measure enhances the borrower's eligibility for MPBF which substantially alleviated the liquidity problems faced by some borrowers. In the context of the easing of the pressure on the banks' resources and with a view to providing some more relief to borrowers, it was further decided in April 1993 that only one-third of such term loan instalments payable within the next 12 months would, henceforth be treated as items of current liabilities for the purpose of arriving at the MPBF. Thus, the credit availability to borrowers subject to MPBF would be enhanced by a little over Rs. 3,000 crore.

(iv) Package of Measures for Financing of Small Scale Industries

1.29 Considering the contribution of the small scale industries (SSI) sector to overall industrial production, exports and employment, a special package of measures was announced in the credit policy on April 7, 1993 with a view to improving the amount and timeliness of credit to this sector. While doing so, following the recommendations of the Committee to Examine the Adequacy of Institutional Credit to the Small Scale Industries Sector and Related Aspects headed by Shri P. R. Nayak a package of measures was announced on April 7, 1993 to facilitate credit flows to the SSI sector.

1.30 A simplified formula was worked out, under which a minimum of 20 per cent of the annual turnover of the SSI units would be made available as working capital finance to SSI units whose fund-based credit requirements do not exceed Rs. 50 lakh. The SSI units, on their part, would be required to bring in 5 per cent of their annual turnover as margin money. For the redressal of the grievances of SSI units, an institutional framework is being introduced.

(v) Restrictions on Credit to Certain Sectors

1.31 Effective April 8, 1993, the minimum margin for loans against shares and debentures/bonds was reduced from 75 per cent to 50 per cent and the ceiling for bank-wise credit was also removed. This was done to alleviate the problem posed to borrowers by the sharp decline in share prices. The existing limit of Rs. 5 lakh for advances to an individual borrower against the security of shares and debentures/bonds prescribed in January 1988, however, continues to be in force.

(vi) Priority Sector Advances by Foreign Banks

1.32 As against the target of 15 per cent of their net total outstanding advances to be provided to the priority sector, the foreign banks had attained a rate of less than 8 per cent as

at the end of March 1992. These banks have been asked to rectify the shortfall in the target by the end of June 1993. Considering that foreign banks do not have a rural branch network, it has also been decided to enlarge the definition of priority sector lending by foreign banks so as to include export finance in the target which, as a consequence, was raised to 32 per cent. This has been put into effect from July 1, 1993, and foreign banks should reach the target by the end of March 1994. Under this overall target for priority sector lending advances by foreign banks to the SSI sector and for export credit should each be not less than 10 per cent of net bank credit. Any shortfalls in achieving the sub-target in respect of advances to the SSI sector would have to be made good by depositing with the Small Industries Development Bank of India (SIDBI), at a rate of interest of 10 per cent per annum, the amount equivalent to the shortfall.

(e) Mobilisation of Foreign Currency Deposits

1.33 The large reliance on the Foreign Currency Non-Resident Accounts (FCNRA) Scheme has emerged as a matter of concern in the recent years. Borrowings under the Scheme are costly given the interest rate differentials offered and the exchange rate protection provided under the Scheme. The burden of exchange loss devolving on the Reserve Bank is an integral element of the cost of mobilising funds under the FCNRA Scheme. The experience during the payments crisis of 1990-91 and 1991-92 showed that the FCNRA Scheme can be quite volatile as evident in the outflow of US \$ 1.6 billion from these accounts in 1991-92. It is in this context that attempts have been made in the recent period to restructure the existing FCNRA Scheme and to put in place new schemes which (i) reduce the reliance on the FCNRA Scheme, (ii) make exchange risk cover a commercial proposition, and (iii) reduce the volatile component of deposits under the existing FCNRA Scheme.

1.34 New schemes such as the Non-Resident (Non-Repatriable) Deposit (NRNR) Scheme and the Foreign Currency (Ordinary) Non-Repatriable Deposit (FCON) Scheme were introduced to offer schemes with diverse features to attract a wide range of depositors than can be accommodated by any single scheme.

Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme

1.35 In April 1993, a new Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme was introduced and became effective from May 15, 1993. The Scheme is similar to the existing FCNR Scheme with one major difference. While the deposit rates would be the same as those prescribed for the existing FCNR Scheme and repatriation of funds will be freely permitted in foreign currencies, the Reserve Bank will not provide exchange rate guarantee to banks for deposits under the new Scheme and as such the exchange risk would be borne by the banks themselves. To enable banks to absorb exchange risk, the deposits under the new Scheme would not be considered as part of net DTL for calculation of reserve requirements. Again, lending out of resources mobilised under the Scheme would not be subject to any lending rate stipulations and such lending would not be considered as part of the net bank credit for the purpose of determining priority sector lending. The existing FCNR Scheme is also being continued but such deposits can be accepted only for periods over one year and up to three years.

FINANCIAL SECTOR REFORM

1.36 The previous Annual Report extensively addressed the issues relating to financial sector reform in the context of the recommendations of the Committee on the Financial System (Chairman: Shri M. Narasimham). The fiscal and monetary policy measures implemented during the course of the past one year and a half reflect not only the short-term stabilisation needs but also the reforms needed in the fiscal and financial sectors. The reform policies, insofar as the financial sector is concerned, can be classified broadly into three areas. In the first area are issues relating to the overall monetary policy including reserve requirements, interest rates, refinancing facilities and the activation of internal debt management instruments. Secondly, there are 'in-house' issues such

as, strengthening of banks and institutions by way of prescription of capital adequacy, and prudential norms, asset classification, cleaning up balance sheets and recapitalisation of banks. Finally, there are issues regarding the competitiveness of the financial structure by restructuring of banks and financial institutions to reap economies of scale, by allowing mergers/amalgamations and by allowing entry of new banks in the private sector.

1.37 In the area of reserve requirements, there has been a clear enunciation of the objective of controlling the gross fiscal deficit so as to enable a phased reduction in the SLR to 25 per cent in the next three years and the CRR to 10 per cent in the next four years. To the extent the fiscal deficit stays on course, it should be possible to adhere to this medium-term objective.

1.38 The structure of interest rates prescribed for commercial banks has been altered from a complex structure of rates to a more simplified one. The lending rates have been rationalised into three categories, of which one is a minimum rate. Deposit interest rates are subject to only one ceiling rate, and rates on CDs which are now a sizeable proportion of incremental fixed deposit are freely determined in the market. Decisions to change the interest rates of banks would have to take into account the impact of such changes on the viability of banks. The spread available to banks between the cost of funds and return on funds has to be adequate to take care of the servicing costs, establishment expenditures, and expenditures on account of branch expansion and diversification of functions. Any downward adjustment in lending rates would be possible only if the deposits rate could also be lowered which, in turn, depends not only on the expected medium-term inflation rate, but also the effective returns available on alternative financial assets. This apart, the system has to become more efficient to ensure that interest rate spreads between the cost of funds and the return on funds do not become a macro function of the extent of non-performing assets.

1.39 With the introduction of many new instruments on an auction basis, the interest rates on Government securities are increasingly being related to market rates and are now within the range of substitutability where rate movement would evoke a response from investors.

1.40 The instrument of refinance is essentially used to ensure that credit flows to the sector of paramount importance, viz. exports. There are clear limitations to which such refinance can be allowed to increase and while export refinance continues to account for an overwhelming part of total refinance, an unlimited growth of such concessional refinance could attenuate monetary control; this is the rationale underlying the periodic moderation of the rapid growth of such concessional refinance.

(a) Internal Debt Management Policy

1.41 The ability to execute monetary policy, to a large extent, hinges on the extent of monetisation of Government debt. While the size of the Government's internal debt is a result of fiscal policy, an active debt management policy is geared towards prudently influencing the composition, maturity structure and yield of Government securities which by reducing obligatory recourse to the Reserve Bank, and effectively controlling money supply enhances the efficacy of monetary policy.

1.42 It may be recalled that the Chakravarty Committee to Review the Working of the Monetary System (1985) had envisaged that in order to reduce the extent of debt monetisation, the borrowing requirements of the Government should, in the first instance, be financed from the open market. This can be ensured by evolving a market-clearing interest rate mechanism which necessitates, inter alia, developing Treasury bills as an active monetary instrument by making an upward revision in the yield of such bills; thus, not only institutional investors and banks but also other corporate bodies, local Government agencies, trusts and individuals, can constitute a sizeable market for Treasury bills and dated securities. This will, in the first place, result in substantially lowering the holdings of these instruments by the Reserve Bank, thereby leading to a corresponding

reduction in the Reserve Bank's credit to the Government and hence, in reserve money. It would give a fillip to the development of money and capital markets and thus improve the overall efficiency of the Financial system. Following the Chakravarty Committee, measures were introduced to restructure the maturity pattern and also telescope the interest rate structure on Government debt instruments. Subsequently, the Narasimham Committee advocated that interest rates on Government borrowing should progressively be market-related; and that this would facilitate the reduction in the SLR. However, an active internal debt management policy cannot by itself enable a reduction in the SLR which is contingent on moderation of the monetised deficit. Under a regime of moderation of the gross fiscal deficit, an active internal debt management policy enables an integration of debt management policy with monetary policy. However, any reduction in SLR should be consistent with reduction in the borrowing programme of the Government.

1.43 In 1992-93 and the early part of 1993-94, the monetary policy based on indirect methods of control was received an impetus and preliminary steps have been taken to develop a Government securities market. In the recent period, many reform measures have been introduced in this area including auctions of 364-day and 91-day Treasury bills, auctions of dated securities and Repo auctions. These measures are essentially a part of fiscal discipline in use of funds and also provide flexibility to the investors.

1.44 The coupon rate of 13.5 per cent on a 10-year security when juxtaposed with the weighted average of lending rates of banks of around 16 per cent shows that there is a possible confluence of interest rates in the system.

Securities Trading Corporation of India

1.45 There is a need to develop an institutional infrastructure so as to provide an active secondary market in Government dated securities and public sector bonds. With this end in view, the Reserve Bank proposes to set up a Securities Trading Corporation of India (STCI). The proposed institution could also hold short-term money market assets like Treasury bills as part of its liquidity management. The STCI would have an initial paid-up capital of Rs. 500 crore and the ownership of the Corporation would be broad-based to include the Reserve Bank, commercial and co-operative banks, financial institutions, mutual funds and public sector units.

(b) Prudential Norms for Commercial Banks

1.46 The previous Annual Report had given a detailed account of the introduction of the risk assets weighting system for determination of capital adequacy and of new rules for income recognition and provisioning. All Indian banks with international presence will have to achieve a capital to risk assets ratio of 8 per cent as early as possible and in any case by March 31, 1994. Foreign banks in India were required to achieve this norm by the end of March 1993. Other banks are to achieve a capital adequacy norm of 4 per cent by March 31, 1993, and the 8 per cent norm by March 31, 1996.

1.47 It was however, found that banks faced practical difficulties in implementing these norms. An informal group consisting of the Reserve Bank and commercial banks was constituted to look into the matter. The group suggested that from a pragmatic viewpoint a somewhat longer timeframe would need to be allowed for putting in place the envisaged measures. Accordingly, some relaxations were introduced for the two accounting years ending March 31, 1993 and March 31, 1994. These relaxations were with regard to 'past due' status of an account, treatment as non-performing assets (NPA) of advances granted for agricultural purposes, net worth of borrower/guarantor or value of security, treatment of loss assets, consortium advances and phasing of provisioning for NPAs and depreciation in investments. From a practical view point, it was felt that in respect of amounts of Rs. 25,00 and less, aggregate provisioning to the extent of 2.5 per cent of the total outstanding should be made rather than a case by case evaluation of a very large number of small accounts. Other major relaxations included scaling down of provisioning for NPAs during 1992-93 from 50 per cent of the total provisions on sub-standard assets, doubtful assets and on assets of Rs. 25,000 and less to 30 per cent

for March 1993. For loss assets, however, the entire amount would have to be provided for by March 1993.

1.48 Despite these relaxations the new norms would adversely affect the balance sheets of banks. The Government has, therefore, made a provision of Rs. 5,700 crore in the 1993-94 Budget for recapitalisation of nationalised banks. This will take care of the problem in the immediate period. Some of these banks would be able to raise equity resources from the capital market, or through an offer of debt instruments.

1.49 Even as measures to strengthen resources of banks are being undertaken, the issue relating to the delay in recovery of dues to banks has been a matter of serious concern in view of its implications for the current cash flow position of banks. At present, the legal process for realising banks' dues has not been conducive for quick recoveries. In this context a new Act, viz., 'Recovery of Dues due to Banks and Financial Institutions Act 1993, for the creation of Special Recovery Tribunals for banks and financial institutions has been passed by the Parliament on August 10, 1993, and the Act has come into effect from August 17, 1993.

(c) Private Sector Banks

1.50 There has been increasing recognition of the need to introduce greater competition in banking by allowing the entry of private sector banks. The Reserve Bank has accordingly formulated guidelines for establishment of new banks in the private sector, details of which are given in Part II of the Report. The minimum paid-up capital of a new private sector bank shall be Rs. 100 crore and it will have to observe prudential norms and capital adequacy of 8 per cent right from the beginning. A number of applications have been received and three of them belonging to financial institutions (Unit Trust of India, Housing Development Finance Corporation of India Ltd and Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.) have been approved in principle. These private sector banks are expected to come into operation shortly.

(d) Board for Financial Supervision

1.51 A strong system of supervision has become necessary in order to ensure that prudential regulations are observed. Emphasis needs to be placed on compliance with the guidelines and directives of the Reserve Bank. Moreover, it is necessary to have prudential internal control and risk assessment system within different constitution of the financial system, viz., banks, financial institutions and non-banking financial intermediaries. The modalities of the setting up of a Board for Financial Supervision within the Reserve Bank are at a very advanced stage and the Board is expected to be operative very shortly. The Board would attend exclusively to supervisory functions, and will have to ensure implementation of regulations in the areas of credit management, asset classification, income recognition, provisioning, capital adequacy and treasury operations.

(e) Reform in Other Segments of the Financial System

1.52 Recognising the need for the reform process to be broad-based, attention has also been focussed in the recent period to other segments of the financial system. The Marathe Committee has provided the basis for reform of the urban co-operative banks while the Shah Committee has provided the framework of reform in the case of non-bank financial companies. Action on both these reports has already been initiated and the details of measures taken are set out in Part II of the Report. The insurance sector had till recently not been brought within the ambit of the reform process; however, the Committee on Reforms in the Insurance Sector, with Shri R. N. Malhotra as Chairman, has been set-up to make recommendations on reforms in the insurance sector.

EXTERNAL SECTOR POLICIES

(a) Exchange Rate Policy

1.53 The Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) was instituted in March 1992 in conjunction with other measures of liberalisation in the areas of trade, industry,

foreign investment and the import of gold. As a transitional arrangement, LERMS served to impart stability to the external value of the rupee and to prepare the narrow inter-bank foreign exchange market for an augmented volume of transactions. However, it involved a dual exchange rate system, implicit in which was a tax on exports arising out of the differential in the rates of surrender of export proceeds. Moreover, the system could not be sustained for any length of time as it called for the rationing of subsidised foreign exchange among certain imports, inevitably resulting in distortions in resource allocation. As it functioned, there were indications of the diversion of remittances from their normal route to the capital account, since inflows into certain non-resident rupee deposit accounts were allowed full conversion at the market exchange rate whereas remittances in the form of current transfers were to be converted at the market exchange rate only to the extent of 60 per cent. A downward adjustment in the official exchange rate took place in early December 1992 and ultimate convergence of the dual rates was made effective as of March 1, 1993.

1.54 The unification of exchange rates marks an important step in the progress towards convertibility on current account. This is in line with the recommendation of the High Level Committee on Balance of Payments (See Box I). The freely floating exchange rate regime continues to operate within the framework of exchange control. Current receipts are surrendered to the banking system, which in turn meets the demand for foreign exchange arising out of permissible purposes. The rates of exchange at which these transactions are effected are determined in the market.

BOX I

Report of the High Level Committee on Balance of Payments

The High Level Committee on Balance of Payments constituted by the Government of India under the chairmanship of Dr. C. Rangarajan submitted its Interim Report in February 1992 and its Final Report in April 1993. The Committee made wider-ranging recommendations pertaining to various aspects of India's balance of payments and a number of important recommendations of the Committee were inputs into the policy decisions of the recent period.

Favouring a realistic exchange rate, the Committee recommended the unification of the exchange rates an important step towards full convertibility. In pursuance, the unified exchange rate system was introduced with effect from March 1, 1993.

The Committee also recommended that a reserve target range should be fixed from time to time taking into account the need to accommodate three months of imports and other payments obligations. In the Committee's view, reserves should not be allowed to fall below the floor level. The Committee also recommended that the option of the Reserve Bank converting gold into foreign currency resources should be constantly reviewed through the immediate case for exercising such an option is not established. Additionally, the Committee recommended that a part of the gold reserve should be available for conversion at short notice into currency resources to meet contingencies.

In regard to external assistance, the Committee suggested that 100 per cent of external assistance may be passed on to States for all sectors. It considered that commercial borrowings with a maturity period of less than five years should not be encouraged and favoured a cautious approach to public guaranteeing of external borrowings. It suggested an annual limit of US Dollar 2.5 billion in the case of disbursements of external commercial borrowings. Furthermore, the Committee concluded that debt-equity conversion is not a desirable option for debt management in India. The Committee recommended launching of gold bonds as an experiment.

To reduce the volatility and cost of NRI borrowings, the Committee recommended a minimum maturity period of one year in the case of FCNR deposits and gradual reduction in the differential between the international interest rates and FCNR rates. The Committee has also favoured development

of markets for NRI bonds to attract medium-term investment by NRIs.

The Committee observed that short-term debt should be permitted only for trade-related purposes. The Committee also recommended the setting up of a monitoring system for short-term debt for ascertaining the extent of outstanding short-term debt at any point of time. With a view to attracting foreign investments, the Committee favoured a National Investment Law for codifying the existing policy and practices relating to dividend repatriation, disinvestment and employment of foreign nationals.

For the medium-term, the Committee considered it necessary to achieve an annual growth in export of at least 15 per cent in dollar terms. Furthermore, it felt that a current account deficit of 1.6 per cent of GDP can be maintained through a sustained level of net capital receipts.

1.55 The authorised dealers (ADs) are not required to surrender to the Reserve Bank any part of foreign exchange sold to them. The Reserve Bank may, however, at its discretion, enter the market to purchase/sell foreign exchange. The sale of foreign exchange by the Reserve Bank is, in general, for approved purposes such as debt-service payments of the Government of India, and as a transitional arrangement to meet the full value of Exim Schemes and 40 per cent of certain other licences issued to exporters. The US dollar is the principal currency for the Reserve Bank's transactions. The Reserve Bank effects transactions at a rate of exchange which could move within a margin of 5 per cent of the prevailing market rate. Besides its buying and selling rates, the Reserve Bank also announces a Reference Rate based on the quotations of a few select banks in Bombay at twelve noon every day. The Reference Rate is applicable to BDR transactions, and transactions routed through the Asian Clearing Union.

1.56 The unified exchange rate provides an appropriate price incentive for increased export earnings. The gradual withdrawal of quantitative controls would improve the sensitivity of demand and supply to price changes and the exchange rate would help in efficient allocation of foreign exchange amount various needs. The changes in the exchange rate regime have been accompanied by measures of liberalisation of exchange control which are detailed in Part II of this Report. Modifications of trade policy have led to a substantial rationalisation in quantitative controls and the virtual removal of licensing. A large measure of price decontrol has also been effected, particularly in relation to key infrastructural inputs such as fertilisers, steel and cement. Given the narrowness of the market, a phased access to the foreign exchange market for bulk imports may help in the initial stages to avoid undue turbulence. As the foreign exchange market gains depth and breadth, with sub-markets in instruments and as there occurs a lateral integration with money and capital markets, the basic conditions for a free exchange regime would be met.

1.57 The initial experience with unified exchange rates has been encouraging. In the early months of the operation of the unified exchange rate system, there was an excessive supply of foreign exchange in the market attributable to faster repatriation of export proceeds, current and possible past accumulations and remittances, the shift of transactions from illegal channels into the banking system and weak import demand. As a result, the rupee has remained firm and has been strengthened on several occasions. There have also been sizeable accruals to the Reserve Bank's foreign currency assets due to sales by ADs.

(b) External Debt Management Strategy

1.58 Over the eighties the growing need for external financing has been accompanied by a shift towards costlier and more volatile sources of financing. In the Seventh Plan period (1985-90), commercial borrowings and non-resident deposits assumed equiproportional rules along with external assistance in meeting the financing requirements. The payments crisis of the latter half of 1990-91 and the first half of 1991-92 revealed that such a financing pattern was unsustainable in view of the problem of credibility. As a result, current account deficits, which

were ordinarily financeable were rendered unviable with normal capital flows shying away. It became clear that there was a need for a debt management strategy which would restructure the capital account so as to make it consistent with the external financing requirements of an economy undergoing structural transformation. Accordingly, initiatives were undertaken to reduce volatility, to chart out borrowing programmes based on overall and relative cost considerations and to eliminate the hidden costs of such borrowings, including the burden of exchange risk borne by the Reserve Bank.

1.59 The constraints on access to international financial markets imposed by the current low rating of the country by the international rating agencies have enabled the reorganisation of commercial borrowings in terms of the cost and maturity structure. Commitments involving sovereign guarantee and of original maturity above one year up to and including twelve years have been kept within a ceiling. A similar cap has been placed on short-term credits and concerted efforts have been made to liquidate the overhang of short-term debt. Over the medium-term, such measures, as noted by the High Level Committee on Balance of Payments, will lengthen the maturity of external borrowing restore the balance between concessional and non-concessional borrowing and ensure that the pre-emption of current receipts by debt-servicing is not unsustainable.

(c) Foreign Investment Policy

1.60 Following the external payments crisis of 1990-1992 there has been a shift in emphasis in favour of non-debt creating in flows of external financial. In the past foreign investment not accompanied by technology was not generally encouraged. In recognition of the fact that several frontier technologies are closely held and that administrative hurdles often impede the inflow of foreign investment, sweeping liberalisation was effected in industrial and foreign investment policies in July 1991, mention of which was made in the previous year's Report. The year under review also witnessed several further steps towards the creation of a congenial climate for attracting and absorbing foreign investment. The measures include stability imparted to exchange rates, ongoing financial sector reform trade policy liberalisation, and reduction in tariffs and excise duties.

1.61 As part of the ongoing process of developing a market-friendly environment for foreign investment, foreign institutional investors (FIIs), i.e. pension funds, mutual funds, asset management companies, investment trusts, nominee companies and incorporated or institutional portfolio managers have been allowed access to Indian stock exchanges. The participation of FIIs is under conditions comparable to generally accepted international standards. They face no lock-in period as regards disinvestment, no limit on investments and a concessional tax rate of 10 per cent on long-term (more than one year) capital gains and 30 per cent on short-term capital gains. A tax rate of 20 per cent on dividend and interest income also compares well with similar tax rates in other countries. Specific guidelines governing the participation of FIIs through stock exchanges have been evolved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) which are dealt with later in Part II.

1.62 The Government of India, with a view to fulfilling its commitment towards full convertibility of the rupee, promulgated an ordinance on January 8, 1993, introducing certain amendments to the Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1973, which was subsequently repealed and replaced by the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act of 1993. The amendments, which are deemed to have come into force from January 8, 1993, pertain mainly to the operations of 'FERA companies' in India. The new provisions (Section 28A and 73A) to provide better regulation of export of goods on lease or hire and ensuring better compliance by ADs. The salient changes effected in the FERA are set out in Part II of the Report.

(d) Trade Policy

1.63. The restructuring of trade policy has constituted an integral element of the reform programme pursued since July 1991. While liberalised grant of import licences for 1397 GI/94—21.

exporters was an important instrument of export promotion over the past few years, it carried with it administrative hurdles and misuse inherent in discretionary policy intervention. The Exim Policy 1992—97 announced in March 1992, therefore, set in motion elimination/simplification of procedures and a series of policy adjustments designed to enable the trade sector to help move towards greater competitive efficiency and improved internationalisation of the economy. The modifications effective April 1, 1993 represent a sequenced stage in this process.

1.64 The thrust of the modified measures has been two-pronged. On the one hand, the reforms were designed to support a broad-based export strategy by generalising the access to export incentives. Thus, in the recent modifications, sectors of the economy such as agriculture and allied activities and services are allowed improved access to imports. Units engaged in agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry and sericulture are allowed to avail of benefits of duty-free imports under EOU/EPZ schemes provided they export at least 50 per cent of their production in value terms. The category of capital goods was widened to include items relating to agricultural and allied activities. These items were hitherto in the negative list. The Export Promotion Capital Goods Scheme has been subject to periodic review and modification to allow for quicker access to import of capital goods. A new scheme was introduced for the services sector enabling concessional imports of capital goods related to professional services.

1.65 The other strand of trade policy reform has been the progressive dismantling of quantitative restrictions. The licensing mechanism has been streamlined and geared to play a positive role. With the removal of the actual user condition for the import of capital goods, raw materials, intermediates, components and spare parts, the access to imports is now un-differentiated among the few existing licences. The surviving quantitative control is a negative list for both exports and imports, comprising prohibited items or items generally not allowed for export or import, except under licensing or under canalisation. Under the recent modifications introduced effective April 1, 1993, the criterion for recognition of Export Houses, Trading Houses or star Trading Houses as well as the quantum of incentives admissible to them is now related to the FOB value of exports instead of to net foreign exchange earnings. The negative list of imports itself was shortened in August 1992. Hundred and forty-four entries have been removed from the negative list of exports with effect from April 1, 1993. The freeing of quantitative controls along with the lowering of tariffs and a floating exchange rate will serve to improve the sensitivity of exports and imports to price signals. Supported by the phased withdrawal of fiscal and other incentives, payments restrictions and ultimately of the remaining discretionary measures, the envisaged trade policy reforms would, when implemented in full, prepare the ground for attainment of the medium-term goals of full convertibility and competitive efficiency.

CAPITAL MARKET

1.66 The previous Annual Report made mention of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) being made the regulatory agency for the capital market in India. SEBI has brought out a number of guidelines/regulations separately for companies and development finance institutions for disclosure and investor protection relating to new issues over funds raised from the market. It has also issued regulation for insider trading, mutual funds, the activities of portfolio managers and merchant bankers. As per the SEBI's guidelines for development finance institutions, there no longer is need for promoters' contribution and underwriting would not be mandatory. In respect of these institutions, free pricing of shares is allowed subject to consistent good track record for three years, and credit rating has been made compulsory for debentures and bonds of more than three years. In regard to public offers of companies, SEBI's guidelines, while providing for free pricing of issues, imposed certain restrictions on private placement of promoters' quota and made underwriting mandatory. The Government on its part has issued guidelines for the entry of foreign institutional investors. A notification has also been issued to facilitate corporate membership in the stock exchanges.

1.67 The measures taken in the area of capital market reform are expected to make stock exchanges more efficient and provide protection to investors. As decline in the budgetary/official support for a number of public sector undertakings and nationalised banks is imminent, it would be necessary to ensure that capital markets work efficiently as vehicles for mobilising savings.

Guidelines for Market Makers

1.68 An important recent measure relates to promoting of the emergence of market makers who would specialise in buying and selling of securities by offering two-way quotations. To ensure that market makers would be in a position to impart liquidity to scrips and reduce volatile movements in share prices, guidelines have been set out by the Reserve Bank on August 5, 1993 regarding bank financing of their operations. As per the guidelines, scheduled commercial banks may exercise their commercial judgement in determining the working capital requirements of those market makers who are approved by SEBI. The existing minimum margin of 50 per cent of loans to individuals against shares, debentures/bonds would not, however, be applicable to bank advances to market makers.

JANAKIRAMAN COMMITTEE ON SECURITIES OPERATIONS OF BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

1.69 The previous Annual Report presented in a detailed manner the entire episode of gross irregularities committed by banks and financial institutions in the securities transactions. The findings as revealed by the first three reports of the Janakiraman Committee and its recommendations and the immediate set of remedial measures introduced by the Authorities were also covered in the previous year's Report. The Committee presented its fourth report in March 1993, and the fifth and the sixth (final) reports in April 1993. While the fourth and fifth reports covered a number of specific banks and financial institutions, the final report sets out the overall findings. The reports contain detailed findings in respect of 32 banks and institutions wherein the irregularities were of a serious nature. The findings reiterate the nexus between brokers/financial institutions and banks and the fact that most of the banks and their subsidiaries covered in the report consciously sought to circumvent Reserve Bank guidelines on Portfolio Management Scheme (PMS), ready forward transactions and issue of Bank Receipts (BRs) so as to enable brokers to have access to large funds for use in the stock market for huge profits.

1.70 The reports have identified four key factors in the perpetration of irregularities : (i) Improper and indiscriminate use of BRs; (ii) brokers increasingly dealing on their own accounts and carrying positions; (iii) banks' failure to periodically reconcile investments; and (iv) complete breakdown of internal control systems in a number of banks. The Committee has observed that as a consequence of these irregularities, the investment portfolios of banks have become fragile and weak. The Committee's final estimate of gross problem exposure of banks is of the order of Rs. 4,024 crore comprising the value of investments made by banks for which they do not hold any securities, SGL transfer forms or BRs or where they hold such securities, but the issuing banks do not appear to have sufficient backing therefor, and others including securities found to have been forged/fabricated.

1.71 The Committee pointed out the existence of inadequate internal control systems in banks, and weaknesses in the supervisory mechanism. In particular, the lack of awareness or appreciation of the all-pervasive nature of irregular practices, the lack of specialised knowledge of the sophisticated electronic data processing systems used by foreign banks, the absence of a good market intelligence system, the overstretched resources of the supervision system due to a stipulation about coverage of large number of branches during the inspections, and the insufficient importance given to treasury functions during inspections have been the chief reasons for the delay on the part of the Reserve Bank in detecting the widespread irregularities. Commenting on the role of external auditors, the Committee has, inter alia, observed that the auditors do not examine all the transactions and do not perceive it as part of their duty to examine the violations of the Reserve

Bank's guidelines. The Committee has further observed that the irregularities could possibly have been detected earlier if there had been greater co-ordination among the different controlling agencies.

1.72 The set of remedial measures undertaken by the Government of India and the Reserve Bank, in pursuance of the findings of the first three reports of the Committee was already covered in the previous year's Annual Report. The corrective measures suggested in the three later reports are the following :

- (i) Banks have been asked to undertake an immediate review of the adequacy of their internal audit departments.
- (ii) Modification in the inspection system of the Reserve Bank providing for more detailed annual financial inspection of banks and appointment of experienced firms of chartered accountants to verify the securities transactions of some banks.
- (iii) A ceiling of 5 per cent of total transactions put through the brokers has been placed on the transactions put through by a bank for each approved broker.
- (iv) Banks have been advised to place adequate systems for undertaking security transactions so that irregularities of the nature pointed out by the Janakiraman Committee do not recur.
- (v) A central depository for all securities in which banks normally deal would be set up. This is in line with the recommendation of the Nadkarni Committee on Trading in Public Sector Bonds and Units of Mutual Funds and is in the process of implementation.
- (vi) Regional Offices of the Reserve Bank would look into the compliance aspect vis-a-vis major and important instructions/directives of the Reserve Bank during the course of inspections and will also monitor compliance certificate by banks at prescribed periodicity.
- (vii) The Subsidiary General Ledger (SGL) operations in Public Debt Offices at Bombay Calcutta, New Delhi, Madras, Hyderabad and Bangalore have been computerised.
- (viii) The statutory auditors will be required to verify compliance by banks of the Reserve Bank's important instructions and directives after the audit of annual accounts.
- (ix) Expertise of retired senior Government officials has been drawn by appointing them as special officers to fix responsibility for the irregularities in some banks.
- (x) A detailed circular was issued by the Reserve Bank to all commercial banks for suitably regulating their investment transactions. The financial institutions were advised to strictly follow the spirit of the instructions issued to the commercial banks. These institutions were also advised to place before their respective Boards of Directors, a comprehensive note regarding the policies, practices, etc., followed in their respective institutions for ensuring that the transactions are handled and accounted for in a transparent and correct manner.
- (xi) Other measures include, inter alia, setting up of the Electronic Clearance Settlement and Depository (ECSD). A group set up in the Reserve Bank would guide and coordinate the work of establishing electronic system for clearance and settlement of trading in public sector bonds and units by the Stock Holding Corporation of India Ltd. and Unit Trust of India.

1.73 Those banks in which serious irregularities had occurred and had been commented upon in the Committee reports have been advised to lodge criminal complaints with the Central Bureau of Investigation wherever warranted and simul-

taneously to initiate departmental proceedings against the errant officials.

1.74 Mention was made in the previous year's Annual Report about the setting up of a Joint Parliamentary Committee (JPC) to enquire into all aspects of the irregularities for responsibilities and suggest appropriate measures for future reform of the system. The JPC has examined a number of persons including officials of the Government, Reserve Bank, banks and brokers. The JPC is expected to submit its report shortly to the Parliament.

II. THE REAL ECONOMY : PERFORMANCE AND PROBLEMS

1. MACRO-ECONOMIC SCENE

2.1 Real GDP growth recovered remarkably during 1992-93 from a low rate of 1.2 per cent during 1991-92 to an estimated 4.2 per cent (Table 2.1). Despite this recovery, the 1992-93 growth was markedly lower than the trend rate of 5.4 per cent per annum of the eighties, and 5.8 per cent per annum during the Seventh Plan period, 1985-90 (Appendix Table II.1). The recovery has been rendered possible principally because of a strong performance of agriculture which is stated to show an impressive growth of an estimated 5.1 per cent during 1992-93 as against a decline of 2.5 per cent in the preceding year. Industrial output growth at 1.3 per cent was an improvement, considering the fact that there was a decline in 1991-92; the recovery was, however, much lower than expected.

Table 2.1 : Macro-economic Indicators

(Per cent)			
Item	1992-93*	1991-92*	1990-91*
1	2	3	4
1. Real GDP Growth Rate	4.2	1.2	5.2
2. Gross Domestic Saving Rate	22.5	23.8	23.7
3. Gross Aggregate Investment Rate	24.8	24.8	27.
4. Net Domestic Saving Rate	14.2	15.2	15.2
5. Net Aggregate Investment Rate	16.6	16.3	19.1

* Provisional.

Note : Gross/Net Saving and Investment Rates are ratios with respect to GDP/NDP at Current Market Prices.

2.2 The gross domestic saving rate which had increased from 23.7 per cent of GDP in 1990-91 to 23.8 per cent in 1991-92, is estimated to decline to 22.5 per cent in 1992-93 due to a sharp fall in the household sector's saving financial assets from 9.1 per cent in 1991-92 to 7.7 per cent in 1992-93. The public sector's gross saving rate is, however, expected to go up from 1.7 per cent of GDP in 1991-92 to 2.0 per cent in 1992-93 reflecting improved saving of Government administration. The gross saving rate of the private corporate sector is estimated to have increased from 2.7 per cent of GDP in 1991-92 to 2.8 per cent in 1992-93.

Table 2.2 : Sector-wise Gross Domestic Saving Rates (Per cent)

Sector	1992-93*	1991-92*	1990-91*
1	2	3	4
1. Household Sector	17.7	19.4	19.9
1.1 Financial Assets	7.7	9.1	8.6
1.2 Physical Assets	10.0	10.3	11.3
2. Public Sector	2.0	1.7	1.1
3. Private Corporate Sector	2.8	2.7	2.7
Total Domestic Saving	22.5	23.8	23.7

* Provisional.

The net inflow of foreign resources which had declined sharply from 3.5 per cent of GDP in 1990-91, to 1.0 per cent in 1991-92, is expected to increase to about 2.2 per cent in 1992-93. The aggregate gross investment rate is estimated at 24.8 per cent in 1992-93 as in the previous year (Table 2.1 and Appendix Table II.2).

2. PRODUCTION TRENDS

AGRICULTURE

2.3 Agricultural production is expected to show a smart recovery in 1992-93 growing by about 5.1 per cent. Total foodgrains production in 1992-93 is expected to be around 181.2 million tonnes—much higher than the production of 167.1 million tonnes in 1991-92—mainly due to higher output of coarse grains and pulses. The 1992 Kharif foodgrains production estimated at 103.2 million tonnes would be higher than the output of 91.4 million tonnes in the previous Kharif season, though it would still be below the target of 103.3 million tonnes. Rabi foodgrains production has been placed at 78.0 million tonnes, as compared with 75.6 million tonnes in the previous Rabi season but lower than the target of 79.7 million tonnes (Appendix Table II.3).

2.4 Among other crops, oilseeds and cotton production have shown strong improvement; oilseeds output at the record level of 20.6 million tonnes in 1992-93, would show an increase of 12.6 per cent over the production of 18.3 million tonnes during the previous year. Cotton production is expected to increase by 19.4 per cent to a record level of 11.7 million bales from 9.8 million bales in 1991-92. Production of both sugarcane and jute and mesta would be lower as compared with the previous year (Appendix Table II.3).

2.5 The higher agricultural production has not only improved the availability of essential commodities but also contributed significantly to the deceleration in the rate of inflation.

Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains

2.6 As a result of higher foodgrains production and remunerative prices offered, procurement of foodgrains by public sector agencies during 1992-93 was higher. At 19.0 million tonnes, it was higher by 0.8 million tonnes over that in 1991-92. The off-take during 1992-93, however, was lower at 17.1 million tonnes as compared with 19.2 million tonnes in the previous year. This was partly on account of lower allocation for the public distribution system (PDS) and partly because of lower prices and greater choice of varieties offered in the open market. Consequently, stocks of foodgrains with public sector agencies as at the end of March 1993 stood higher at 14.7 million tonnes than the level a year ago (12.2 million tonnes) (Appendix Table II.4). With a better crop and a sharp increase in procurement prices, wheat procurement in Rabi 1993 reached a record level of 12.8 million tonnes up to July 30, 1993. With a significant improvement in stocks of both rice and wheat, stocks at the end of June 1993 were well above the prescribed norms.

INDUSTRY

2.7 Industrial output during 1992-93 showed a modest revival. During 1992-93, industrial production recorded a growth rate of 1.5 per cent as compared with the unchanged situation in the preceding year. The revival in output has been stronger in chemicals and chemical products, transport equipment and a few agro-based industries. The various policy measures taken since the beginning of 1992, the relaxation of import compression measures, the stability of the tax regime facing the corporate sector, the incentives for industrial exports and the relatively easy availability of credit provide the necessary pre-requisites for an enduring improvement in industrial output.

2.8 The growth rate during 1992-93, is far below the trend growth rate (7.7 per cent) during the eighties, and 8.5 per cent during the Seventh Plan period. The somewhat slower revival largely reflects the sluggish performance of infrastructure industries which registered a low growth rate of 2.5 per cent in 1992-93 as against 6.1 per cent recorded in the preceding year.

Manufacturing Sector

2.9 Among the sectors, manufacturing recorded a turnaround—an increase of 0.7 per cent in 1992-93 against a fall of 1.5 per cent in 1991-92. Disaggregated data of the manufacturing sector at the two-digit level for 1992-93 (Appendix Table II.6) show that eight industrial groups [weight of 42.38 per cent in the index of Industrial Production (IIP) recorded accelerated growth as compared with three industrial groups (with weight 17.08 per cent) in the preceding year. The major industrial groups which recorded revival include food and food products, chemicals and chemical products, transport equipment, wood and wood products, cotton textiles, rubber, plastic and petroleum products. The revival of some of the industry groups was attributable to the withdrawal of import restrictions imposed during 1991-92. In some of the industry groups, like chemicals, the revival was on account of substantial decline in raw material prices in international markets, lower interest burden, and the cost that the downward adjustment of the rupees provided to their exports. Non-metallic mineral products recorded deceleration, and eight groups (weight of 31.73 per cent in the IIP) showed declines partly because of paucity of raw materials and lower or slack demand.

Infrastructure Industries

2.10 During 1992-93, infrastructure industries performed sluggishly, with growth at 2.5 per cent as compared a rise of 6.1 per cent during the preceding year. With the exception of petroleum refinery products, all other industries have registered lower rates of growth. In particular, output of petroleum crude showed a decline of 11.2 per cent (Appendix Table II.7).

2.11 Electricity generation registered a lower rate of growth of 4.9 per cent in 1992-93 compared to 8.5 per cent

in the preceding year, mainly on account of lower hydro-power generation. The steep declaration in coal production to 3.9 per cent compared with 8.3 per cent in the preceding year was largely a reflection of slippage in the output of Singareni Collieries Company Limited compared with the target. Total dispatches of coal during 1992-93, however, were higher, and yet the total pit-head stocks of coal increased substantially by more than twice the optimal stock level (about 20 million tonnes). Cement and steel industries have been adversely affected by slack demand. Output of saleable steel registered a lower rate of growth of 3.9 per cent than that of 8.1 per cent during the preceding year. The sharp deceleration in the output of cement to 0.2 per cent from 10.9 per cent during 1991-92 could be attributed to the reduction in the Government off-take, decline in cement prices, and build-up of inventories.

2.12 The continued decline in the output of petroleum crude is a matter of serious concern. Petroleum crude output declined by 11.2 per cent during 1992-93 on top of the fall of 8.1 per cent during the preceding year. The decline in crude oil output despite adequate oil reserves (the reserves to production (R/P) ratio for the country is 26 : 1 as compared to 10.1 : 1 in USA and 9.0 : 1 in Western Europe) was mainly due to shut down of off-shore structures for preventive maintenance and disruption in oil production in the North-East. There were, however, some structural causes too for the declining trend in crude oil production like the under-investment in exploration and slow-down of drilling operation and the lack of generation of investible surpluses by the oil companies. Output of petroleum refinery products, however, recorded a significant rise of 4.0 per cent during 1992-93 as against a fall of 0.7 per cent during the previous year.

III. GOVERNMENT FINANCES

Central Government Budgetary Developments in 1992-93

3.1 The fiscal adjustment initiated during 1991-92, was maintained in 1992-93 with the major indicators of deficit of the Centre, relative to GDP, continuing their steady decline from the high levels in the recent past (Table 3.1). With the objective of reducing the gross fiscal deficit (GFD) to reasonable levels, specific measures were put in place during the year to restrain the growth in expenditures to about 12 per cent from an average of around 16 per cent in the late 'eighties and to mobilise non-debt creating financing. Consequently, the revised estimates of 1992-93 placed GFD at 5.22 per cent of GDP as compared with the actuals of 5.96 per cent in the previous year and 8.41 per cent in 1990-91; the GFD-GDP ratio during the latter half of the 'eighties averaged 8.22 per cent. Latest indications are that the GFD-GDP ratio would turn out to be 5.70 per cent in 1992-93 reflecting the lower than estimated accretion of receipts, especially in the last quarter of the year.

Table 3.1 : Measures of Deficit of the Central Government as Percentage of Gross Domestic Product at Current Market Prices

Year	(Per Cent)					
	Gross Fiscal Deficit	Net Fiscal Deficit	Net Primary Deficit	Monetised Deficit	Conventional Revenue Deficit	
1	2	3	4	5	6	7
1980-81 to 1984-85 (Average)	6.26	3.73	2.99	2.21	1.19	1.11
1985-86 to 1989-90 (Average)	8.22	5.40	3.80	2.29	2.07	2.58
1990-91	8.41	5.78	3.32	2.78	2.14	3.50

1	2	3	4	5	6	7
1991-92	5.96	4.04	1.47	0.90	1.12	2.67
1992-93 (RE)	5.22	3.70	0.85	0.77	1.02	2.38
	(5.70)*			(0.61)@	(1.81)@	
1993-94 BE	4.71	3.43	0.44	0.55	0.55	2.25

* Latest Estimates.

@Actuals according to Reserve Bank Records.

RE : Revised Estimates.

BE : Budget Estimates.

3.2 Besides the reduction in the GFD-GDP ratio, net Reserve Bank credit to the Centre (monetised deficit) to GDP has been brought down further to 0.77 per cent in 1992-93, as per the Budget for 1993-94, from 0.90 per cent in 1991-92, and from an average of 2.29 per cent in the latter half of the 'eighties. Consequently, the monetisation of the GFD was contained at less than 15 per cent in 1992-93 (RE) as against 15.2 per cent in 1991-92 and 33 per cent in 1990-91; on an average, the monetisation of the GFD was around 28 per cent in the latter half of the 'eighties. The lowering of the extent of monetisation in the past two years has been facilitated, inter alia, by the increasingly active internal debt management policy. The disquieting trend observed in the past of net Reserve Bank credit to the Centre remaining high during the year only to be reduced sharply at the year-end, was less evident during 1992-93. This may be seen from the fact that the fortnightly averages of each quarter hovered around the full-year average and the difference between the fortnightly average for the full financial year and the March 31, 1993 figure was markedly lower than in the previous year (Table 3.2). In the first quarter of 1993-94, the average net Reserve Bank credit to Centre shot up sharply to Rs. 10,097 crore as against Rs. 5,986 crore in the first quarter of 1992-93 (Table 3.2). The Reserve Bank conducted sales of dated securities from its portfolio under repurchase agreements (Repos) and if these Repo transactions had not taken place, the net Reserve Bank credit to the Centre would have been substantially higher. What is of even greater concern is that in July, 1993 the net Reserve Bank credit to the Centre averaged on weekly basis Rs. 17,404 crore as against Rs. 8,249 crore in July 1992.

Table 3.2 : Fortnightly Averages of Net RBI Credit to Central Government

(Rupees crore)				
Fiscal Year	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5
First Quarter (April-June)	10,097	5,986	6,104	5,841
Second Quarter (July-Sept.)	17,019**	7,264	10,454	8,185
Third Quarter (Oct.-Dec.)		7,016	11,865	11,938

1	2	3	4	5
Fourth Quarter (Jan.-Mar.)		7,087	13,606	15,130
March 31		4,257	5,508	14,746
Fiscal Year				
Average*		6,718	10,209	10,337

* This is the average of all fortnightly figures of net RBI credit to Central Government and the figure for March 31, after closure of Government accounts.

** Up to August 20, 1993.

3.3 The revised estimates of the revenue deficit at Rs. 16,700 crore exceeded the budget estimates by Rs. 2,818 crore. The deterioration in this regard was mainly on account of a near stagnation in the ratio of revenue receipts to GDP, a step-up in interest payments (by Rs. 500 crore), subsidies (by Rs. 1,621 crore), pension payments (by Rs. 305 crore) and security-related expenditures (by Rs. 285 crore) as also an enhanced provision for Plan purposes (Rs. 2,181 crore). Interest payments were higher mainly because of discount on 364-day Treasury bills, an instrument under which there was large mobilisation of resources in 1992-93 and higher cost of servicing external debt on account of exchange rate adjustment. In regard to subsidies, the delay in increasing issue prices to absorb the impact of higher procurement prices resulted in the food subsidy going beyond the allocated amount by Rs. 300 crore. Fertiliser subsidies were higher by Rs. 860 crore reflecting the reduction in the price of urea and higher input costs. In addition, a one-time assistance of Rs. 340 crore was provided to farmers for purchase of phosphatic and potassic fertilisers whose prices were decontrolled in August 1992. In the case of fertiliser subsidy, there is, however, the problem of having to ensure that the price relativities as between different types of fertilisers does not come in the way of optimal mix of fertiliser use. There was an additional provision of Rs. 400 crore for export subsidy; this was on account of settlement of claims in the pipeline for cash compensatory support and continuance of benefits for deemed exports. Pension payments increased due to an ad hoc one time increase allowed to defence pensioners. Mainly as a result of these expenditures, the revenue deficit formed the major part of the GFD, unlike in the eighties (Table 3.3).

Table 3.3 : Decomposition of Gross Fiscal Deficit

Year	(Per cent)				
	Revenue Deficit	Capital Outlay	Net Lending	Dis-investment	Gross Fiscal Deficit
1	2	3	4	5	6
				(2+3+4+5)	
1980-81 to 1984-85 (Average)	17.0	42.3	40.7	—	100.0
1985-86 to 1989-90 (Average)	31.5	34.2	34.3	—	100.0
1990-91	41.6	27.2	31.2	—	100.0
1991-92	44.8	31.4	32.2	8.4	100.0
1992-93 (RE)	45.5	34.7	29.1	9.5	100.0
1993-94 (BE)	47.71	34.7	27.1	9.5	100.0

RE : Revised Estimates.

BE : Budget Estimates.

3.4 A cause for concern was the high year-end budget deficit (conventional deficit) which, according to Reserve Bank Records stood at Rs. 12,757 crore, more than double the budget estimates of Rs. 5,389 crore and also substantially higher than the revised estimates of Rs. 7,202 crore. The fiscal year average turned out to be as high as Rs. 11,811 crore. In the first quarter of 1993-94, this stood at Rs. 10,056 crore (Table 3.4). In July 1993, there was a sharp upsurge in the budget deficit to weekly average of Rs. 20,909 crore as against Rs. 14,213 crore in July 1992. Indications are that the GFD-GDP ratio in 1992-93 would eventually turn out to be higher than the revised estimates of 5.22 per cent and could be around 5.70 per cent. Given the net lending, the net primary deficit defined as equivalent of net fiscal deficit less net interest payments (see Box II) would also go up, and would be higher than the revised estimates of 0.85 per cent of GDP.

BOX II

Primary Deficit

One of the measures of public sector deficit that has gained prominence in recent years is the primary deficit. This concept, also referred to as non-interest deficit, measures the impact of discretionary policy of the Government Budget and can be utilised for evaluating the sustainability of Government deficits.

The fiscal deficit that includes not lending on the expenditure side, is most commonly used and referred to as the gross fiscal deficit (GFD). There is no unanimity of view regarding the primary deficit that is derived from the GFD. One view is that primary deficit should be represented by GFD less interest payments of the Government. Another view is that it is equivalent to GFD less net interest payments. The fiscal deficit that does not include the Government's net lending (defined as loans and advances by Government less recoveries of loans) is referred to as net fiscal deficit. When net interest payments (interest payments less interest receipts) are deducted from net fiscal deficit, what is obtained is the net primary deficit—a concept which is relevant for determining the stability of debt to GDP ratio.

References : World Bank (1988) World Development Report, p. 56, Mario I Biejer and Adrienne Cheasty (1991). 'The Measurement of Fiscal Deficits—Analytical and Methodological Issues'. Journal of Economic Literature, December.

Table 3.4 : Centre's Fortnightly Average of Budget Deficit According to RBI Records

	(Rupees crore.)			
Fiscal Year	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5
First Quarter (April—June)	10,056	8,082	7,337	6,187
Second Quarter (July—Sept.)	21,065	13,157	12,137	10,068
Third Quarter (Oct.—Dec.)		11,835	13,622	12,803
Fourth quarter (Jan.—March)		14,647	14,114	14,554
March 31		12,757	6,492	11,430
Fiscal Year				
Average*		11,811	11,508	10,818

S Upto August 20, 1993.

* This is the average of all fortnightly figures of Budget deficit of the Central Government and the figure for March, 31, after closure of Government accounts.

Central Government Budget : 1993-94

3.5 The Budget for 1993-94, formulated against the backdrop of an improved macro-economic situation, while continuing to give further thrust to the on-going structural adjustment, also attempted to provide a stimulus to growth. Accordingly, the Budget incorporated a number of measures for stronger industrial revival and furthering agricultural and rural development. Besides, important measures were announced relating to financial sector reform, export stimulation and exchange rate management. The Centre's budget deficit at 1992-93 rates of taxes and duties has been placed at Rs. 333 crore in 1993-94. After taking into account the revenue loss of Rs. 4,522 crore on account of reduction in taxes and duties announced in the Budget, of which, the Centre's share would be Rs. 3,981 crore, the budget deficit was estimated at Rs. 4,314 crore*. The Budget also envisaged declines in the revenue deficit and GFD as proportions of GDP (Table 3.1 and Appendix Tables III.1 and III.5).

3.6 The fiscal correction, according to the Budget, is to be brought about essentially by reduction in the non-interest components of non-Plan expenditure and disinvestment of equity holdings in Central public sector enterprises. The specific areas of expenditure reduction inter alia include; absence of provision for payment of additional dearness allowance that may fall due in 1993-94, substantial reduction in payments to banks under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990, specific cuts in fertiliser and export subsidies, and reduction in non-Plan grants to States.

3.7 A noteworthy aspect of the Budget for 1993-94 is that it has stepped up Plan expenditure by Rs. 4,278 crore (11.6 per cent), of which Rs. 3,607 crore (18.4 per cent) would be on account of Central Plan outlay and the balance of Rs. 671 crore (3.9 per cent) would be towards assistance for State and Union Territories' Plans. The easing of the fiscal constraints and the moderation in inflation have enabled the Centre to provide for a substantially higher Plan outlay. Budgetary support for the Plan outlay has been stepped up by a lower order (18.4 per cent) than the increase of 35.3 per cent in Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of Central public sector enterprises.

Budgetary Operations of the States: 1993-94

3.8 The consolidated budgetary operations of the States** during 1993-94 continue to reflect inherent imbalances as evident from the major deficit indicators viz., overall/conventional deficit, revenue deficit and gross fiscal deficit). The overall/conventional deficit at Rs. 3,128 crore (at 1992-93 rates of taxation) is higher by about two and half times than the position in 1992-93 (Rs. 1,256 crore). After adjusting Rs. 1,030 crore from Additional Resource Mobilisation measures proposed by thirteen States and revenue loss of Rs. 542 crore @ as States' share from the new tax proposals in the Central Budget, the overall gap may turn out to be about Rs. 2,640 crore. During 1993-94, the deficit on revenue account would turn out to be higher at Rs. 4,524 crore than the estimated deficit of Rs. 4,117 crore in the preceding year. The deterioration in the revenue account which has been in evidence since 1987-88 has contributed to the rising GFD of the States from Rs. 11,259 crore in 1987-88 to an estimated Rs. 23,707 crore in 1993-94.

3.9 The persistent revenue deficit has resulted in lower resources available for capital outlay and net lending as evident from the decomposition of GFD (Table 3.5). Moreover, the rising GFD of the States has resulted in large outstanding debt of the States. Consequently, the outstanding debt of all States is budgeted to reach the level of Rs. 1,58,144 crore as at end-March 1994 as against Rs. 1,40,079 crore, as at end-March 1993 (Appendix Table III.7). The high level of debt has increased the interest burden of the States, pre-empting

* Subsequent to the presentation of the Budget, the Finance Minister, on May 4, 1993, announced certain further modifications/changes in the direct and indirect taxes which inter alia include increase in the exemption limit for personal income tax to Rs. 30,000 and reduction in the import and excise duties on certain specific items. These changes are expected to result in a net revenue loss of Rs. 125 crore to the Centre and Rs. 304 crore to the 25 States.

** The consolidated budgetary operations relate to twenty five States, of which, eleven States have vote-on-account budgets.

@ Excluding the share of States in the revenue loss amounting to Rs. 304 crore from post-budget tax concessions announced by the Central Government on May 4, 1993.

a sizeable portion of revenue receipts. The ratio of gross interest payments to revenue receipts is estimated to go up to 16.0 per cent during 1993-94 from 14.7 per cent in 1992-93. This ratio, on an average, was only 9.6 per cent during the eighties. The stagnation in non-tax revenue and rapid upsurge in non-interest revenue expenditure as proportions to GDP have led to a near stagnancy in primary revenue surplus (i.e., revenue deficit minus net interest payments). Consequently, the financing of net interest payments from the primary revenue surplus is expected to be only about 62.2 per cent in 1993-94 as against 77.0 per cent in the later half of the 'eighties.

3.10 There would be a sharp upsurge in non-developmental expenditure as budgeted during 1993-94, accounting for 29.3

per cent of the total disbursements as compared with 26.7 per cent during 1992-93 (Rs. 32,729 crore). As against the rise in disbursements on non-developmental expenditure, particularly expenditure on interest payments, administrative services and pensions, the efforts of the States to mobilise own resources have not shown commensurate improvement over the years. This is evident in the States' overall own deficit (which represents the resource gap in States' budgetary operations after netting out the resources transferred to States from the Centre and repayments of loans and interest payments made by the States to Centre) continues to remain stagnant at around 6 per cent of GDP since 1980-81.

Table 3.5 : Decomposition of GFD of the States

(Per cent)

Year	Revenue Deficit	Capital Outlay	Net Lending	Total (2+3+4)
1	2	3	4	5
1980-81 to 1984-85 (Average)	16.8+	75.3	41.5	100.0
1985-86 to 1989-90 (Average)	7.7	62.3	30.0	100.0
1990-91	28.3	49.1	22.6	100.0
1991-92	29.9	53.4	16.7	100.0
1992-93 (R.E.)	20.6	55.7	23.7	100.0
1993-94 (B.E.)	19.1	53.9	27.0	100.0
(Average of 1990-91 to 1993-94)	24.5	53.0	22.5	100.0

+ Indicates surplus.

3.11 The financing pattern of the States' total resource gap (GFD) reveals that about 43 per cent of the gap is estimated to be financed through loans from Central Government as compared with 46 per cent during 1992-93 and 53 per cent on an average during the 'eighties.

3.12 Net devolution of resources from the Centre to States as proportion to aggregate receipts during 1993-94 is budgeted to be around 34 per cent of the aggregate receipts, as against 35 per cent in 1992-93. During the 'eighties also this proportion was on an average around 34 per cent. Given the financial constraint of the Central Government, the States would require to create a large enough primary revenue surplus through reduction in current expenditure and raising revenues by effecting changes in the rates and base and by diversification.

Ways and Means Advances and Overdrafts of States

3.13 During the year under review, the Reserve Bank's normal and special Ways and Means Advances limits to 23

States continued to remain at Rs. 744.8 crore and Rs. 266.0 crore, respectively. The stipulation that overdrafts should be cleared within a maximum of seven consecutive working days continued to remain in operation as per the Overdrafts Regulation Scheme, 1985. During 1992-93, six States could not comply with the above stipulation on eleven different occasions. The Reserve Bank had, therefore, to stop payments on behalf of these State Governments on these eleven occasions. In contrast, during 1991-92, all the States complied with the Overdrafts Regulation Scheme.

Combined Budgetary Position of the Centre and States

3.14 The trends in the three major deficit indicators of the combined fiscal position of the Centre and States, viz., the GFD, the conventional deficit and the revenue deficit, show that despite a perceptible reduction in GFD-GDP ratio in recent years from the levels prevailing in the late 'eighties, the wide gap on the revenue account remains largely unaltered (Table 3.6).

Table 3.6 : Measures of Deficit of the Centre and States* as Proportion of GDP

(Per cent)

Year	Gross Fiscal Deficit**	Conventional Deficit	Revenue Deficit
1	2	3	4
1985-86 to 1989-90 (Average)	9.5	2.2	2.8
1990-91	10.1	2.1	4.5
1991-92	7.5	1.1	3.6
1992-93 (R.E.)	6.8	1.2	3.0
1993-94 (B.E.)	6.7	0.9	2.8

R.E. : Revised Estimates

B.E. : Budget Estimates.

* Net of inter-Government transactions.

** GFD of the Centre and States minus net lending to the States by the Centre.

3.15 According to budgeted estimations, the combined GFD would be 6.8 per cent of GDP in 1992-93 as against 7.5 per cent in 1991-92 and an average of 9.5 per cent during the second half of the 'eighties. Going by the latest indications the actual outturn would be higher by about 0.47 percentage point than the estimate presented in Table 3.6. The combined revenue deficit placed at 3.0 per cent of GDP in 1992-93 is higher than the average of 2.8 per cent during the period 1985-86 to 1989-90 but here too, there appeared to have been a slippage. The revenue deficit reflects an inherent problem in Government finances, viz., the near rigidity in revenue receipts and expenditures as proportions to GDP which were placed at around 21 per cent and 24 per cent, respectively, in 1992-93, almost the same on an average as in the second half of the 'eighties. The problem has been further accentuated by the reduction in the share of the developmental component of revenue expenditure from 55 per cent in the late 'eighties to 52 per cent in 1992-93.

3.16 The Budget estimates for 1993-94 reveal a reduction in GFD, revenue deficit and conventional deficit, expressed as proportions to GDP.

Market Borrowings: Central Government

3.17 Concerned about the GFD position, the Central Government has since 1991-92, consistently scaled down its market borrowing programme. Consequently, net market borrowings were placed lower at Rs. 3,670 crore during 1992-93 as compared with Rs. 7,500 crore in 1991-92, while gross market borrowings were Rs. 4,821 crore against Rs. 8,919 crore in 1991-92 (Appendix Table III.11). As part of a strategy to move towards market-related operations, the Reserve Bank on behalf of the Centre undertook, for the first time in 1992-93, auctions of dated securities. The cut-off yields on Central Government securities resulting from the auctions ranged between 12.00 per cent for a 5-year security and 12.75 per cent for a 10-year security (Appendix Table III.12). Although the Reserve Bank initially subscribed a little over two-fifths of the total, the major portion of this inventory was subsequently sold off in the market during 1992-93.

3.18 The Budget estimates for 1993-94 have placed the gross and net market borrowings of the Central Government at Rs. 4,848 crore and Rs. 3,700 crore, respectively which were marginally higher than the revised estimates for 1992-93.

3.19 During the fiscal year 1993-94, (up to end-July 1993), the Central Government held three auctions for dated securities, i.e. on June 3, June 15 and July 27, 1993 and mobilised Rs. 3,000 crore. The cut-off yields for the 5-year, 9-year and 7-year security were 13.00 per cent, 13.40 per cent and 13.25 per cent, respectively.

State Governments

3.20 During 1992-93 according to Reserve Bank Records, net market borrowings of the State Governments amounted to Rs. 3,471 crore. As against this, during 1991-92 the net market borrowings aggregated Rs. 3,364 crore. The coupon rate on State Government loans was fixed at 13.00 per cent for 15-year maturity.

3.21 According to Reserve Bank Records, during the fiscal year, 1993-94 (upto end-July, 1993), the State Governments in the first tranche on May 18, 1993 have floated 10-year loans bearing a coupon rate of 13.50 per cent, and mobilised Rs. 1,748 crore. In the second tranche on July 12, 1993, they mobilised Rs. 2,006 crore.

Gold Bonds Scheme, 1993

3.22 The Gold Bonds Scheme, 1993 which was opened for public subscription on March 15, 1993 closed on June 14, 1993. The Scheme mobilised 41.12 tonnes of gold from the public during this period. This is substantially larger than the quantity of gold anticipated under the Scheme. At domestic market price (as on June 29, 1993), it is valued at about Rs. 1,807 crore (Rs. 1,558 crore at international prices). The Union Budget for 1993-94 has assumed that credit of only Rs. 300 crore worth of gold (which at international prices would work out to about 8 tonnes), would be mobilised under the Scheme.

IV. MONETARY AND PRICE TRENDS

MONETARY AND BANKING TRENDS

4.1 Monetary expansion during the financial year 1992-93 was lower than the very large increase recorded in the previous year. The lower than envisaged increase in net Reserve Bank credit to the Centre and the modest accretion in net foreign exchange assets of the Reserve Bank moderated the rate of growth of reserve money, which in turn contributed to the deceleration in broad money during 1992-93. Both currency with the public and aggregate deposits of scheduled commercial banks increased at a slower pace. The growth in time deposits was strong, indicating the relative preference for this instrument to other forms of saving media; this was also partly attributable to the uncertainties arising out of the irregularities in security transactions. The moderation in monetary expansion together with containment of gross fiscal deficit relative to GDP and improved performance of the real sector brought about a significant deceleration in the rate of inflation during 1992-93.

MONETARY DEVELOPMENTS

4.2 The objectives of monetary policy were sought to be achieved by limiting the rate of monetary expansion without depriving the commercial sector of its genuine credit requirements. Both M3 and M1 showed decelerated growth (Table 4.1). M3 expansion accordingly turned out to be 14.2 per cent during the year, a rate which was lower than the 19.4 per cent expansion of the preceding year (Appendix Table IV.1) and an average growth rate of about 17 per cent over the decade 1980-81 to 1990-91.

4.3 Narrow money (M1) expansion (Rs. 8,440 crore or 7.3 per cent) in 1992-93, in fact, was not only lower than in 1991-92, (Rs. 21,946 crore or 23.6 per cent) but also the growth rate was the lowest in the past eleven years. Both currency with the public and demand deposits grew at a slower pace. Currency with the public expanded by 12.1 per cent in 1992-93 as against 15.2 per cent in the previous year. Demand deposits registered a markedly smaller expansion of 0.8 per cent compared with 34.9 per cent in the preceding year. Time deposits increased sharply by 18.1 per cent as against 17.2 per cent in 1991-92. 'Other' deposits with the Reserve Bank also rose sharply by Rs. 618 crore as against Rs. 211 crore in the previous year. These deposits tended to bulge during the course of the first three quarters of the year on reporting Fridays, as financial institutions parked their surplus funds with the Reserve Bank in view of the lack of demand for their funds following strict enforcement of the ban on ready forward transactions in securities. This phenomenon had, however, moderated in the last quarter of the year after Repo auctions in Government securities were introduced.

Table 4.1 : Variations in Broad Money (M3) : Components and Sources

Item	1992-93P	1991-92	(Rupees crore)	
			April-June	
			1993-94P	1992-93P
1	2	3	4	5
Narrow Money (M1)	8,440 (7.3)	21,946 (23.6)	8,347 (6.8)	7,031 (6.1)
Broad Money (M3)	45,184 (14.2)	51,653 (19.4)	18,391 (5.1)	19,452 (6.1)

1	2	3	4	5
Currency with the public	7,414 (12.1)	8,050 (15.2)	6,088 (8.9)	2,763 (4.5)
Aggregate deposits of which :	37,152 (14.5)	43,392 (20.5)	9,171 (3.1)	11,690 (4.6)
External deposits*	5,843 (20.7)	5,632 (24.8)	1,124 (3.3)	5,069 (17.9)
1. All foreign currency deposits	5,061 (24.8)	4,824 (30.9)	499 (2.0)	4,291 (21.0)
2. NRE deposits	782 (10.0)	808 (11.5)	625 (7.3)	778 (9.9)
Demand deposits	408 (0.8)	13,685 (34.9)	-873 (-1.6)	-711 (-1.3)
Time deposits	36,744 (18.1)	29,707 (17.2)	10,044 (4.2)	12,401 (6.1)
Net bank credit to Government	17,826 (11.3)	18,070 (12.9)	13,654 (7.8)	6,442 (4.1)
RBI's net credit to Government	4,433 (4.7)	5,168 (5.8)	7,303 (7.4)	2,320 (2.5)
of which to Centre	4,257 (4.6)	5,508 (6.3)	9,201 (9.5)	3,913 (4.2)
Bank credit to commercial sector	28,380 (15.1)	16,225 (9.4)	3,916 (1.8)	8,811 (4.7)
Net foreign exchange assets	3,809 (17.4)	11,291 (106.7)	1,681 (6.5)	849 (3.9)
Net non-monetary liabilities of the banking sector	4,925 (9.4)	-5,984 (-10.3)	875 (1.5)	-3,319 (-6.3)
RBI's net non-monetary liabilities	641 (2.3)	393 (1.5)	-270 (-1.0)	-2,205 (-8.0)

Note : Figures in brackets are percentage variations.

P : Provisional

* Relate to scheduled commercial banks only.

4.4 On the sources side, the growth in net bank credit to the Government declined for the second successive year. Expansion of the net Reserve Bank credit to the Centre, which captures the monetised deficit, was contained at Rs. 4,257 crore (4.6 per cent) in 1992-93 as compared with Rs. 5,508 crore (6.3 per cent) in 1991-92 and Rs. 14,745 crore (20.5 per cent) in 1990-91. The actual outcome was lower than the ceiling for the year (Table 4.2).

4.5 While credit to the Government sector contracted, banks' lending to the commercial sector increased and this was facilitated by the injection of resources from the Reserve Bank for industry and agriculture, the reduction in SLR, the withdrawal of incremental CRR and increased Reserve Bank's accommodation to banks. The expansion in credit to the commercial sector was as much as Rs. 28,380 crore (15.1 per cent), as against Rs. 16,225 crore (9.4 per cent) in 1991-92.

4.6 Net foreign exchange assets of the banking sector, which registered a large increase in 1991-92, showed a decline for the larger part of the year. Subsequent to the revaluation of these assets in March 1993, at market rates, following the unification of exchange rates, these assets showed a rise. Net non-monetary liabilities of the Reserve Bank experienced a larger increase of Rs. 641 crore during 1992-93. However, throughout most part of the year, net non-monetary

liabilities of the Reserve Bank experienced a decline, reflecting, among others, the losses on the foreign assets and the larger transfer of profit of the Reserve Bank to the Central Government. Following the unification of the exchange rates and the consequent revaluation of foreign exchange assets since March 5, 1993, this trend was reversed.

Reserve Money and Net Domestic Assets of the Reserve Bank

4.7 Notwithstanding the moderate increase in net Reserve Bank credit to the Centre, the expansion of reserve money at Rs. 11,438 crore was closer to Rs. 11,726 crore in 1991-92 (Appendix Table IV.2). With net foreign exchange assets of the Reserve Bank increasing by a substantially lower amount than in the previous year, the net domestic assets (NDA) of the Reserve Bank, however, showed a sharper rise of Rs. 7,629 crore (9.5 per cent) than that of Rs. 871 crore (1.1 per cent) in 1991-92. Nonetheless, the ceiling on the expansion of NDA set for 1992-93 was fully met (Table 4.2).

4.8 Although the monetary expansion in 1992-93 was lower than the trend rate during the last eleven years, it was still high in relation to the indicative target and the actual price and output developments. The need to maintain monetary and price stability has, therefore, become paramount. Accordingly, monetary expansion in 1993-94 has been targetted at about 12.0 per cent.

Table 4.2 : Ceiling on Net Domestic Assets and Actual Performance

(Rupees crore)

Item	Outstanding as on March 31, 1992	Targeted Expansion over March 31, 1992				Targetted Outstanding as on March 31, 1993	Actual Performance so far : Expansion over March 31, 1992 as on				Actual Outstanding as on Mar 31, 1993 (P)
		June 26, 1992	September 18, 1992	December 25, 1992	March 31, 1993		June 26, 1992 (P)	Sept. 18, 1992 (P)	Dec. 25, 1992 (P)	March 31, 1993 (P)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Reserve Money (RM)	99,505	7,100	5,900	10,900	13,700	1,13,200 [13.8]	6,068	5,627	4,710	11,438	1,10,943 [11.5]
Net Domestic Assets (NDA)	80,667	10,900	9,300	13,600	16,200	96,871 [20.1]	5,219	5,533	7,473	7,629	88,296 [9.5]
Adjusted NDA@	92,798	9,246	7,373	13,389	12,131	99,200	2,320	3,836	223	4,433	98,449 [4.7]
RBI credit to Govt.	94,016	7,300	7,500	7,400	5,800	@@[5.5]					
o/w Credit to Centre	92,266	7,400	7,600	7,000	6,100	97,666 [6.6]	3,913	5,513	1,450*	4,257*	96,523* [4.6]
					5,400M						
RBI claims on others	12,362	3,700	2,100	6,500	10,700	23,100 [86.8]	663	—1,006	1,903	3,743	16,105 [30.3]
o/w (i) banks	5,102						570	227	3,166	4,783	9,885
(ii) comm. sec.	7,260						93	—1,233	—1,263	—1,040	6,220
Other items (net)	25,711	25,100	—2,236	—2,703	—5,347	547	26,258
Net Foreign Assets	18,838	—3,800	—3,400	—2,700	—2,500	16,300 [—13.5]	849	94	—2,763	3,809	22,647 [20.2]
2. Indicative Targets											
Net bank credit to general	1,58,263	9,400	10,600	11,400	10,400	1,68,700	6,442	10,921	12,175	17,826	1,76,089
Government (Ceiling)											
Broad Money (M3)	3,17,481	9,600 (3.0)	11,700 (3.7)	25,200 (8.0)	32,700 (10.4)	3,47,800 [10.4]	19,452	24,223	34,125	45,184	3,62,665 [14.2]

@ Net of adjustments of the following factors, viz., changes in exchange rates, value of gold, reserve requirements and net international reserves floor.

P : Provisional. @@year-end target as on March 31, 1993

* Figures are inclusive of Rs. 752 crore (equivalent of SDRs 211.95 million) incurred on account of Reserve Asset subscription made to the IMF towards the Quota increase.

Notes : 1. To determine compliance with the ceilings on RBI variables for June, September, and December, the simple average was taken of the four Fridays leading up to (and including) the last reporting Friday; for March 31, the data was averaged over the last four Fridays of March and March 31 (after the closure of Government accounts).

2. Figures in square brackets are growth rates over the financial year.

3. Figures in parentheses represent percentages.

4. Targets are based on provisional figures for 1991-92.

Trend during the First Quarter : 1993-94

4.9 The pace of monetary expansion in the first quarter of the financial year 1993-94 was slower, broad money (M3) having grown by Rs. 18,391 crore (5.1 per cent), compared with Rs. 19,452 crore (6.1 per cent) in the comparable period of the preceding year. In relation to the targeted growth of about 12.0 per cent, the pace of expansion in M3 in the first quarter of this year has been somewhat above the trajectory. Currency with the public grew at a faster pace of Rs. 6,088 crore (8.9 per cent) as compared with Rs. 2,763 crore (4.5 per cent) in the first quarter of the previous year. The increase in aggregate deposits was moderate, being Rs. 9,171 crore (3.1 per cent) against Rs. 11,690 crore (4.6 per cent) in the previous year. There was a sharp deceleration of bank credit to the commercial sector which at Rs. 3,916 crore (1.8 per cent) was less than half of Rs. 8,811 crore (4.7 per cent) in the comparable period of the previous year. Net Reserve Bank credit to Central Government expanded sharply. It was as much as Rs. 9,201 crore (9.5 per cent). This outcome does not capture the real liquidity impact, since there took place considerable amount of sales of Government securities from Reserve Bank's portfolio on Repo basis almost continuously throughout the quarter. If a weighted average of Repo transactions is considered, the expansion in net Reserve Bank credit to the Centre over the quarter would be about Rs. 17,524 crore, a rise of 18.2 per cent compared with the rise of Rs. 3,913 crore or 4.2 per cent in the first quarter of 1992-93. Net foreign exchange assets of the banking system too increased sharply by Rs. 1,681 crore against a lower rise of Rs. 849 crore in the corresponding quarter of the previous year. Reserve money growth, however, decelerated the growth of Rs. 3,833 crore (3.5 per cent) being much less than that of Rs. 6,068 crore (6.1 per cent) in the first quarter of preceding year, reflecting essentially the lower requirements of cash reserves partly because of the reduction in CRR and partly because of sluggish demand for commercial credit which in turn resulted in lower use of refinance facilities by banks (Table 4.1).

Some Monetary Relationships

4.10 There was a reduction in income velocity ratios (excepting that of currency) during 1992-93 reflecting, among others, a rise in the demand for money, and in particular, for bank deposits (Appendix Table IV. 3). Both on an average and on a point-to-point basis, incremental broad money multipliers registered some increases. This indicated the effect mainly of the reduction in the effective cash reserve requirements and the relative preference for deposits to currency exhibited by economic units (Appendix Table IV. 4).

BANKING TRENDS

4.11 A deceleration in the growth of aggregate deposits and, in particular, demand deposits and substantial increase in bank credit characterised the scheduled commercial bank's operations during the fiscal year 1992-93 (March 20, 1992 to March 19, 1993).

4.12 The growth of aggregate deposits of scheduled commercial banks slackened to Rs. 37,814 crore (16.4 per cent) from the previous year's level of Rs. 38,216 crore (19.8 per cent) (Appendix Table IV.5). The extent of overshooting of the initial working estimate in this area was the highest in 1992-93 since these working estimates have been set out in the 'eighties (Table 4.3).

Table 4.3 : Scheduled Commercial Banks—Growth of Aggregate Deposits

Year	Working Estimates		Actual Achievement	
	Amount	Growth (per cent)	Amount	Growth (per cent)
1982-83	7,000	16.0	7,625	17.4
1983-84	8,000	15.7	9,238	18.0
1984-85	9,600	15.8	11,648	19.2
1985-86	11,500	16.2	13,160	18.2
1986-87	15,000	17.5	17,320	20.3
1987-88	18,500	18.1	15,321	14.9
1988-89	20,500	17.4	22,105	18.7
1989-90	24,000	17.3	26,809	19.1
1990-91	27,500	16.6	25,583	15.3
1991-92	29,500	15.4	38,216	19.8
1992-93	27,000	11.7	37,814	16.4

4.13 The absence in 1992-93 of the two special factors that operated in 1991-92 viz., deposits on account of India Development Bonds and margin money deposits kept by the canalising agencies largely accounted for deceleration in aggregate deposits, and in particular, demand deposits during 1992-93. Time deposits, however, showed a strong growth essentially due to the real positive interest rates offer on all maturities of term deposits for the good part of the year, the removal of tax deduction at source on interest income from bank deposits, and the increase in bank deposits in the context of the irregularities in the securities market.

4.14 The expansion in bank credit accelerated sharply, the increase being Rs. 26,390 crore (21.0 per cent), more than two and a half times the unusually low increase of Rs. 9,291 crore (8.0 per cent) recorded in the preceding year (Table 4.4). This was rendered possible by the release of resources of banks through large reductions in reserve requirements, and release of Rs. 1,000 crore in January 1993 to select sectors for reviving industrial and agricultural growth. Food credit increased sharply by Rs. 2,073 crore (44.4 per cent) as compared with a meagre growth of Rs. 164 crore (3.6 per cent) during 1991-92, reflecting the large Kharif procurement following the rise in food-grains output and the increase in procurement prices. Non-food credit expansion was substantially higher than in the previous year (Rs. 24,317 crore or 20.1 per cent against Rs. 9,127 crore or 8.2 per cent in 1991-92). While this cannot be wholly explained by the modest industrial revival, there were certain other factors at work: reduction in the cost of credit with the lowering off the minimum lending rate, inventory build-up in sectors facing demand recession, increased demand by public sector undertakings and larger increase in export credit, and policy measures, such as, removal of stipulation of incremental net non-food credit-deposit ratio, reduction in the SLR, and easing of the norms of inventory and receivables up to 20 per cent of the standard norms essential for meeting the borrowers' current level of production. There was as a result, a shift in the portfolio from investments to credit. Scheduled commercial banks' investments in Government and other approved securities recorded deceleration. Investments in Government securities rose marginally to Rs. 13,218 crore from Rs. 12,729 crore in the previous year in absolute terms, while those in approved securities registered a lower increase, i.e. Rs. 2,242 crore as compared with Rs. 2,402 crore in the previous year.

Table 4.4 : Banking Variables : Growth Rates

Variables	(Per cent)						
	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89	1993-94	1992-93
						(April-June)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Aggregate Deposits	16.4	19.8	15.3	19.1	18.7	3.2	5.3
Demand Deposits	3.0	35.8	15.0	23.6	15.3	-1.6	0.4
Time Deposits	19.6	16.5	15.4	18.2	19.4	4.2	6.5
Bank Credit	21.0	8.0	14.6	19.8	20.1	2.3	6.4
Food Credit	44.4	3.6	124.6	160.9	64.9	42.0	9.2
Non-food Credit	20.1	8.2	12.4	18.5	22.8	0.5	6.3
Investment	17.1	20.2	16.6	17.8	17.5	5.8	4.8

@ Provisional

Note : No sign is indicated for positive variation.

4.15 There was a distinct change in the pattern of investments by scheduled commercial banks during 1992-93 following certain policy initiatives relating to Government securities. Commercial banks have responded favourably to instruments being sold on auction basis.

4.16 With the sharp rise in credit and deceleration in deposits, the credit-deposit ratio of scheduled commercial banks rose to 56.6 per cent as compared with 54.4 per cent in the preceding year.

4.17 Both aggregate deposits and bank credit of scheduled commercial banks tended to show a bulge between the last Friday of March and the last day of March as in recent years, with the aggregate deposits increasing by Rs. 6,147 crore or 2.2 per cent (Rs. 4,502 crore or 1.9 per cent) and bank credit by Rs. 4,518 crore or 2.9 per cent (Rs. 4,079 crore or 3.1 per cent). As in the previous year, the unwinding of such a large increase in deposits took place in the subsequent reporting weeks of April 1993 (Appendix Table IV.6).

Non-Deposit Resources

4.18 With deceleration in aggregate deposit growth during 1992-93, the use of non-deposit resources by banks showed a distinct upturn in 1992-93 in sharp contrast to a fall in 1991-92 (Appendix Table IV.7). On an aggregate basis, the use of additional non-deposit sources rose by Rs. 1,889 crore; during 1991-92, banks' use of such resources had declined by Rs. 457 crore.

Trends During the First Quarter: 1993-94

4.19 During the first quarter of the Financial year 1993-94 (April-June), there was subdued growth in both aggregate deposits and bank credit of scheduled commercial banks. Aggregate deposits rose by Rs. 8,664 crore (3.2 per cent) as compared with an increase of Rs. 12,256 crore (5.3 per cent) in the comparable period of 1992-93. The expansion of bank credit was much lower at Rs. 3,534 crore (2.3 per cent) than that of Rs. 8,052 crore (6.4 per cent) of the previous corresponding period. Food credit, however, registered substantial growth at Rs. 2,833 crore (42.0 per cent) owing to improved wheat procurement operations. The expansion of non-food credit at Rs. 701 crore (0.5 per cent) was far below the increase of Rs. 7,621 crore (6.3 per cent) recorded in the comparable period of 1992-93. Growth in investment by banks in Government and other approved securities was higher at Rs. 6,137 crore (5.8 per cent) than Rs. 4,291 crore (4.8 per cent) recorded during the corresponding period of previous year. The perceptible slowdown in the expansion of non-food credit in the first quarter of 1993-94 as compared with the previous year is attributable to a number of factors. First, banks have been exercising caution in regard to lending in view of stricter provisioning norms and the introduction of a capital to risk-assets ratio. Secondly, banks have undertaken a larger amount of write-offs in March 1993. Thirdly, a number of large borrowers have increased their recourse to Commercial Paper. Fourthly, a number of companies having raised large amounts from the capital market in 1992-93 are flushed with funds and have reduced their borrowings from banks. Fifthly, some of the large public sector units, particularly in trading activity, have reduced their borrowings from banks. Sixthly, the April-June quarter is normally a period of subdued credit as there is a seasonal return flow of credit. While the non-food credit expansion in the first quarter of

1993-94 appears very subdued as compared with the comparable expansion in 1992-93, it is in alignment with the expansion in 1991-92 and 1990-91 (Table 4.5).

Table 4.5 : Non-food Credit Expansion in the First Quarter (April-June)

	1993-94 ^(a)	1992-93	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5
Rupee Crore	701	7,621	149	648
Per cent	0.5	6.3	0.1	0.7

@Provisional

Sectoral Deployment of Credit

4.20 Data on sectoral deployment of gross bank credit for the financial year 1992-93 (April-March), indicate acceleration in non-food gross bank credit of the order of Rs. 18,993 crore as compared to a smaller expansion of Rs. 7,822 crore during the corresponding period of 1991-92 (Appendix Table IV.8). Industry-wise break up of incremental credit shows larger credit expansion to all engineering, iron and steel, chemical group, gems and jewellery, construction and petroleum in the main, while credit to electricity (generation and transmission) and leather and leather products witnessed smaller expansion (Appendix Table IV.9).

The Reserve Bank's Refinance

4.21 The flow of bank credit to the export sector increased substantially in 1992-93, the order of increase being 40.6 per cent. Between March 19, 1993 and June 25, 1993, there was a further increase of 12.9 per cent. The total export credit refinance limits increased by 85.9 per cent between March 20, 1992 and March 19, 1993 and the total export credit refinance limits were equivalent to 69.2 per cent of outstanding export credit as on March 19, 1993 (Table 4.6). The total export credit refinance limits increased by a further 7.9 per cent between March 19, 1993 and June 25, 1993, despite the adjustment in the refinance formula as mentioned in Section 1. Between March 19, 1993 and August 6, 1993, while outstanding export credit of banks increased by 15.1 per cent, their export credit refinance limits increased by 10.8 per cent.

4.22 Under the new refinance facility, viz., the Government Securities Refinance Facility introduced in October 1992, there was no outstanding amount of refinance as on June 25, 1993.

TRENDS IN THE SHORT-TERM MONEY MARKET

Discount and Finance House of India Ltd.

4.23 During 1992-93, with the exception of call and notice lending, the Discount and Finance House of India Ltd.'s (DFHI's) turnover in all the other segments of the money market was lower in relation to their respective levels in the preceding year. In the call and notice money market, DFHI accounts for a share of a little more than 10 per cent and showed a cumulative annual turnover of Rs. 4,57,013 crore as compared with Rs. 2,94,474 crore recorded in the previous year; the daily average lending by DFHI in the market increased from Rs. 799 crore in 1991-92 to Rs. 1,243 crore in 1992-93.

4.24 DFHI commenced its operation in Central Government securities in April 1992 and the cumulative turnover

Table 4.6 : Export Credit Refinance

As on	Refinancing of Export Credit Denominated in Indian Rupees			Refinancing of Export Credit Denominated in US Dollars			Total		
	Out-standing Export Credit	Export Credit Refinance Limits	Ratio of col (3) to col (2)	Out-standing Export Credit	Export Credit Refinance Limits	Ratio of col (6) to col (5)	Out-standing Export Credit	Export Credit Refinance Limits	Ratio of col (9) to col (8)
March 20, 1992	10,672	5,564	52.1	23	30	130.4	10,695	5,594	52.3
June 26, 1992	11,852	6,939	58.5	168	224	133.3	12,020	7,163	59.6
August 7, 1992	11,565	6,647	57.5	745	993	133.3	12,310	7,640	62.1
March 19, 1993	11,228	5,834	52.0	3,810	4,568	119.9	15,038	10,402	69.2
June 25, 1993	12,298	6,548	53.2	4,679	4,679	100.0	16,977	11,227	66.1
August 6, 1993	12,364	6,580	53.2	4,945	4,945	100.0	17,309	11,525	66.6

(Rupees crore)

was Rs. 18,645 crore by the end of March 1993 but the overwhelming proportion of these transactions related to Repos with the Reserve Bank; the cumulative transactions with others were only Rs. 2,713 crore. The commercial bill activity was at a low ebb with a sharp decline in cumulative turnover to Rs. 786 crore in 1992-93 from Rs. 6,995 crore in 1991-92. This was a consequence of reduced recourse to the bill system following the Reserve Bank's action in July 1992 to curb irregular use of the bill discounting/rediscouting facility. The activity in other money market instruments, such as, CDs and CPs was also subdued.

Call Money Market

4.25 Reflecting relatively comfortable liquidity conditions in the banking system, call money rates were generally easy during 1992-93. Significant reduction in reserve requirements contributed to the decline in the monthly weighted average lending rate of DFHI from 29.36 per cent in April 1992 and 23.99 per cent in May 1992 to 14.75 per cent in June 1992. Since July 1992, the call money market remained easy and rates were generally quoted in the range of 9.00 to 12.00 per cent till the last week of March 1993 when the rates firmed up due to year-end increase in the demand for funds. The call money market remained easy subsequently and the monthly weighted average lending rates of DFHI during the months of May and June 1993 worked out to 7.29 per cent and 6.07 per cent, respectively.

4.26 The fortnightly daily average borrowings of 32 major scheduled commercial banks declined from Rs. 10,387 crore during the fortnight ended July 10, 1992 to Rs. 8,520 crore during the fortnight ended June 25, 1993. Consequently, the fortnightly daily average lendings by financial institutions decreased from Rs. 7,434 crore during the fortnight ended July 10, 1992 to Rs. 6,354 crore during the fortnight ended June 25, 1993.

Certificates of Deposit and Commercial Paper

4.27 The outstanding amount of CDs issued by 50 scheduled Commercial banks as on June 11, 1993, was Rs. 11,744 crore as compared with that of Rs. 6,990 crore by 52 scheduled commercial banks as on June 26, 1992. The outstanding CDs at the end of March 1993 amounted to 67.0 per cent of the limits (Appendix Table IV.15). The typical interest rates for CDs with a maturity of 3 months which were in the range of 15 to 16 per cent in the month of June 1992 came down to a range of 14.5 per cent to 15.5 per cent in March 1993. The typical rate of interest on CDs with a maturity of one year also came down marginally from 15.0-16.5 per cent in June 1992 to 14.5-16.0 per cent per annum in March 1993. The rates of interest on CDs further declined in the subsequent months. Six all-India financial institutions, viz., IDBI, ICICI, IFCL, IRBI, SIDBI, and EXIM Bank, have also been permitted to issue CDs with maturity of more than one year and up to three years for an aggregate amount of Rs. 3,750 crore; the outstanding amounts of such CDs stood at Rs. 2,040 crore as on June 25, 1993, with rates of interest offered ranging between 14.5 per cent and 17.0 per cent.

4.28 The outstanding amount of CPs increased from Rs. 198 crore issued by 14 companies as on June 30, 1992 to Rs. 1,455 crore by 57 companies as at the end of July 1993; which was also the peak level of the outstanding amount of CPs. Most of the CPs issued during the year 1992-93 offered effective interest rates ranging from 15.5 per cent to 17.5 per cent per annum. However, the effective interest rates on CPs issued in subsequent months came down significantly and CPs issued in the month of July 1993 carried effective interest rates ranging from 12.0 per cent to 13.5 per cent. The bulk of CPs were held by banks.

Bills Rediscounting Market

4.29 The activity in the bills discounting/rediscouting market came down considerably. The outstanding amount of commercial bills rediscounted by scheduled commercial banks and financial institutions came down from Rs. 3,874 crore at the end of March 1992 to Rs. 779 crore at the end of March 1993; it further came down to Rs. 679 crore at the end of May 1993.

INTERNAL DEBT MANAGEMENT OPERATIONS

4.30 In 1992-93, there were a number of policy changes to activate internal debt management operations and it was

recognised that pre-emption of resources of the banking system would need to be reduced to ensure more efficient resource use. The monetary policy of April 1992 heralded a new approach to internal debt management by introducing market-orientation in regard to absorption of Government of India rupee dated securities and longer-term Treasury bills. An auction system was introduced for Central Government securities including Treasury bills of varying maturities. This was to be facilitated by the overall reduction in the Government's borrowing programme in 1992-93.

4.31 One of the main features of the reoriented internal debt management policy was to make Government dated securities attractive to investors. Secondly, interest rates were allowed, within an overall ceiling to respond to the market. In 1991-92, the maximum coupon rate was raised in two steps from 11.5 per cent to 12.5 per cent, while the maximum maturity was reduced from 20 years to 15 years. In 1992-93, the maximum coupon rate was at 13.0 per cent for 15 years. The Central Government securities were auctioned for shorter maturities up to 10 years at coupon rates ranging from 12.0 per cent for a 5-year to 12.75 per cent for a 10-year maturity. In 1993-94, the maximum coupon rate was raised to 13.5 per cent with a further reduction of maximum maturity to 10 years.

182-Day Treasury Bills

4.32 The outstanding of 182-day Treasury bills which at the end of March 1992 amounted to Rs. 3,986 crore, were fully repaid by mid-October 1992 and no fresh 182-day Treasury bills were issued after April 16, 1992.

364-Day Treasury Bills

4.33 A new instrument in the form of 364-day Treasury bills was introduced at the end of April 1992. The auction of these bills on a fortnightly basis, has since then become a regular feature. These auctions evoked good response from investors which was a reflection partly of the relative attractiveness of the instrument and partly because it provided a safe avenue to investors in the face of uncertainties prevailing in the Government securities market consequent to irregularities in the securities transactions which surfaced in the early part of 1992-93. Gross borrowings through 364-day Treasury bills amounted to Rs. 8,777 crore in 1992-93. The implicit yield rates at the cut-off prices decided in the auctions ranged between 10.96 per cent per annum and 11.42 per cent per annum. Since Rs. 3,986 crore of 182-day Treasury bills were outstanding at the end of March 1992, and these matured, the Government was able to mop up Rs. 4,791 crore, net of repayments of longer dated Treasury bills against a budgeted total of Rs. 500 crore. Significantly, the entire subscription to these longer dated bills was by the market and no part of it was held by the Reserve Bank. During the fiscal year 1993-94 up to August 20, 1993, Rs. 4,034 crore was raised in the 364-days Treasury bills auctions (Appendix Table IV.16).

4.34 The amounts of 364-days Treasury bills due to mature in 1993-94 were large and to obviate the problems inherent in a sharp liquidity increase, the Government offered to sell on April 19, 1993, 12.75 per cent Government stock, 1996, in conversion of 364-day Treasury bills maturing in 1993-94. Of the bills eligible for conversion, amounting to Rs. 8,777 crore (face value), Rs. 7,123 crore (face value) were offered by investors for conversion representing 81.2 per cent of the eligible bills. As such, the 364-day Treasury bills maturing in 1993-94 amounted to Rs. 1,654 crore (face value). The amount converted into the 12.75 per cent Central Government stock, 1996, aggregated Rs. 6,946 crore sale value.

91-Day Treasury Bills

4.35 Another step in the direction of active debt management operations was the introduction of an auction scheme for issue of 91-days Treasury bills with a predetermined amount but with Reserve Bank participation. The cut-off yields were significantly higher than the fixed discount rate of 4.6 per cent per annum on such bills sold on tap. The outstanding 91-day Treasury bills as at the end of March 1993 amounted to Rs. 1,350 crore, of which Rs. 1,147 crore was held by the Reserve Bank and Rs. 203 crore by others. As on August 21, 1993, the total outstanding was Rs. 2,625 crore, of which only Rs. 27 crore was held by the Reserve Bank and Rs. 2,598 crore was held by others. Thus, in the recent period, the absorption of 91-day Treasury bills by the market has gone up substantially (Appendix Table IV.17)

Government Dated Securities

4.36 For the first time, in 1992-93 the Central Government raised its entire gross market borrowing of Rs. 4,821 crore through the auction system. While the Reserve Bank initially subscribed Rs. 2,214 crore, the bulk of these securities were later sold by the Reserve Bank in the market. During 1993-94, the Central Government raised till August 14, 1993, a gross market borrowing of Rs. 7,000 crore. The Reserve Bank initially subscribed only Rs. 435 crore (Appendix Table IV.19). With the introduction of an auction system, the coupon rates for Central Government loans emerged through cut-off yields at which competitive bids were accepted in auctions. Such coupon rates turned out to be more attractive than the predetermined coupon rates fixed in the previous year for comparable maturities. The improvement in coupon rates was on top of a shortening of the maturity periods. The rates for borrowings by State Governments and other bodies have, however, continued to be fixed. The State Governments have raised an amount of Rs. 3,754 crore (gross) in the first two tranches floated during the fiscal year 1993-94 up to end-July. The highest rate was 13.0 per cent for a 15-year State Government security in 1992-93. This rate was raised to 13.5 per cent in 1993-94 for a 10-year State Government security. The fixed rate in effect provided a cap within which the auction system has operated. The coupon rates which have emerged on securities (both Central and State Governments) over the past three years indicate that the yield curve has been sloping upward gently as years to maturity expanded (see Box III and Table 4.7).

4.37 The Reserve Bank conducted auctions of Repurchase Agreements (Repos) for Central Government dated securities from time to time to even out short-term liquidity in the banking system within the fortnightly make-up period. The first auction was held on December 10, 1992, and up to August 20, 1993, 38 such Repo auctions have been conducted. This has been yet another step towards developing open market operations. Initially, the Repo auctions were for very short periods of one or two days and, thereafter Repos up to 14 days have been introduced. Given the reserve requirement system over a period of 14 days, the liquidity impact of the Repo auctions for varying periods needs to be assessed by averaging the turnover over the 14-day period.

BOX III

The Yield Curve

The shape of the yield curve reflects the relationship among yields of securities that differ only with respect to their term to maturity. The general perception is that the curve will be upward moving up to a point when it gets to be flattened. The curve will be as indicated.

There are at least three competing theories that attempt to explain the term structure of interest rates, viz., the expectations, liquidity preference and preferred habitat theories.

According to the expectations theory, the shape of the curve can be explained by the expectations of investors about future interest rates. If short-term rates are expected to be relatively low in the future, then the long rate will be below the short rate. Similarly, long rates will exceed the current short rate if there is an expectation that rates would be higher in the future. The theory was developed by J. R. Hicks (1939), F. Lutz (1940) and B. Malkiel (1966).

Keynes' liquidity preference theory, as advanced by J. R. Hicks (1939) accepts the fact that expectations influence the shape of yield curve. Nevertheless, short-term issues, particularly in a world of uncertainty, would be more desirable to most investors because of their liquidity property than longer term issues. If no premium exists for holding longer term instruments, investors would prefer to hold short-term securities in order to minimize the possible variations in the nominal value of their portfolio.

Critics of the expectations theory, such as, J. Culbertson (1957) and F. Modigliani and R. Sutch (1966) point out that liquidity preference cannot be the main consideration for all classes of investors. In their view, insurance companies, pension funds and even retired persons will prefer the long rather than short-term securities to avoid the possible fluctuations in interest rate. On the other hand, commercial banks or

corporate investors may prefer liquidity and therefore short-term issues. Investors thus have preferred habitats and the markets are likely to be segmented, with yield being determined by the forces of demand and supply in each market.

References : Culbertson, J. (1957), "The Term Structure of Interest Rates Quarterly Journal of Economics, November, Hicks, J.R. (1939), Value and Capital London, Oxford University Press; Lutz, F. (1940), "The Structure of Interest Rates", Quarterly Journal of Economics, November, Malkiel, B. (1966), The Term Structure of Interest Rates, Princeton, Princeton University Press; and Modigliani, F. and Sutch, R. (1966), "Innovations in Interest Rate Policy", American Economic Review, May.

Table 4.7 : Coupon Rates of Government Securities

Maturity Period	(Per cent per annum)		
	1993-94*	1992-93*	1991-92†
3 years	12.75@	—	—
5 years	13.00	12.00	10.75
6 years	—	12.30	—
7 years	13.25	12.60	—
8 years	—	12.70	—
9 years	13.40	—	—
10 years	13.50@ @	12.75	11.00
15 years	—	13.00	12.50

† Fixed coupon rates.

* Rates emerged in auctions except 12.75 per cent for 3-year maturity.

@ Fixed coupon rate on Government

— Stock issued in conversion of 364-day Treasury bills.

@@ Fixed coupon rate on State Government securities.

4.38 There were two other changes in the securities operations. The first related to Switch Quotas. A system of allotting annual Switch Quotas was prevalent since 1973 mainly to enable banks/institutions to improve the yields on their investments in Government securities. Under the system, an annual quota to each bank/institution was fixed for purchase of one loan against sale of another. After a review of the Switch Quota facility, the system was dispensed with effective April 1, 1992 as it did not have any impact on monetary aggregates and was not consistent with the objective of developing open market operations as a tool of monetary policy. The second was regarding the sale purchase list of the Reserve Bank. The Bank now offers for sale only a select number of securities which it wishes to undertake instead of listing in its offer list all dated securities in its portfolio. Another significant measure is that the Reserve Bank has put on its purchase list certain securities for cash with a view to providing total liquidity to at least a few securities.

PRICE TRENDS

4.39 Much the most important development of 1992-93 has been the sharp deceleration in the inflation rate on a sustained basis. The Wholesale Price Index (WPI) at the end of March 1993 was higher by 7.0 per cent than that a year ago. In the previous financial year, the inflation rate was nearly double the rate registered in the year under review (Table 4.8). A number of factors have contributed to this outcome—the reduction in the gross fiscal deficit of the Union Government in relation to GDP, the moderation in the monetary expansion, and the improvement in the supply position. A favourable monsoon resulted in a bumper Kharif crop. There has also been an improvement in Rabi output. Imports of foodgrains and allied products have helped to ease the pressure on food prices. The resurgence of industrial activity though modest in comparison with the situation in the eighties, helped to dampen inflationary expectations.

4.40 The inflation rate, on a point-to-point basis as measured through the WPI (base : 1981-82=100) for 'All Commodities', at 7.0 per cent in 1992-93 was the lowest since August 1989. The annualised inflation rate was over 10 per cent in each month from October 1990 till end-July 1992, with a peak of 16.4 per cent in August 1991. The rate came down to single-digit in a sustained manner only from November 1992 onwards. On an average basis, the inflation rate was 10.0 per cent in 1992-93, which was much lower than the figure of 13.7 per cent in the preceding year (Appendix Table IV.20).

Table-4.8 : Annual Rate of Inflation in Terms of WPI
(Point-to-Point 12-Month Period Increase)

	(Per cent)					
At the end of	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89
April	7.0	13.6	11.4	9.0	5.9	9.6
May	7.2	12.9	12.3	8.4	7.2	9.3
June	6.1P	12.3	12.3	9.4	6.5	9.5
July	5.8P	10.4	14.5	9.3	6.4	8.3
August	6.2P*	9.2	16.4	7.6	8.9	6.3
September		10.2	15.9	7.9	9.0	6.9
October		10.2	14.3	10.1	7.6	7.3
November		8.5	14.6	11.1	7.5	7.0
December		8.4	14.3	12.6	7.7	4.4
January		7.6	12.9	13.5	8.1	5.6
February		7.4	13.2	13.2	8.7	5.3
March		7.0	13.6	12.1	9.1	5.7

P—Provisional

*—upto August 14, 1993

4.41 A notable feature of the year was the sharp deceleration in the movements of prices of essential commodities of mass consumption. Although the weighted contribution of 'primary articles' at 14.4 per cent seemed to be high (Appendix Table IV.21), the major contributors to this outcome were fruits and vegetables, milk eggs, fish and meat and tea with their weight totalling 8.397 per cent, almost one half of the total weight of food articles. The weighted contribution of the rest of the food articles (largely cereals) to the general price level was in fact negative.

4.42 The weighted contribution of the 'fuel, power, light and lubricants' group to the general price level was as much as 22.6 per cent during 1992-93, as against 10.2 per cent in 1991-92. This could be explained in terms of the sharp increase in the administered prices of petrol and petroleum products (18.8 per cent as compared with 9.2 per cent in the preceding year) and electricity tariff by various State Governments (9.8 per cent as against 13.7 per cent in the last year). The weighted contribution of the 'manufactured products' group to the general price level was the highest at 63.0 per cent. The rise was mainly accounted for by steep increases in the prices of 'sugar, khandsari and gur', fertilizers, cotton textiles and iron and steel. Substantial declines were noticed in prices of edible oils and cement.

4.43 The deceleration in the inflation rate in 1992-93 was also reflected in the movements of all the three Consumer Price Indices (CPI) for Industrial Workers, Urban Non-manual Employees and Agricultural Labourers. What was most striking was that the CPI for Agricultural Labourers recorded the lowest rise, on a point-to-point basis, of only 0.7 per cent in contrast to a rise of 21.9 per cent in the preceding year. The CPI for Industrial Workers and also Urban Non-manual Employees increased by 6.1 per cent and 6.8 per cent, respectively, rates which were half of those registered in the previous year. The higher weightage of food articles in the CPI of Agricultural Labourers than in the CPI for Industrial Workers and Urban Non-manual Employees was reflected in its growth rate for the year (Appendix Table IV.22).

Trends During the First Quarter : 1993-94

4.44 The overall declining trend witnessed in the annual inflation rate in 1992-93 was evident during the first quarter of 1993-94 also. The General Index of Wholesale Prices registered a smaller rise of 2.4 per cent, lower than the increase of 3.2 per cent recorded in the comparable period of 1992-93. While the declining trend in the price-level is explained by the general easiness in the indices of 'two major commodity groups, viz., 'primary articles' and 'manufactured products', the slowdown in the indices of 'primary articles' was prominent during this period. The 'fuel' group, however, recorded a substantial increase of 3.4 per cent as compared with an increase of 0.3 per cent in the comparable quarter a year ago, contributing to the extent of 16.3 per cent to the general price rise as against a negligible share of 0.9 per cent in the preceding year. The declining trend in the growth of WPI could be attributed to the high food stocks, facilitated by record food procurement in the year 1993-94, as also the favourable monsoon for the year 1993-94 which has dampened the inflationary expectations. The CPI for Industrial Workers registered an increase of 2.9 per cent during the first quarter of 1993-94, lower than 3.1 per cent recorded in the corresponding period of 1992-93.

4.45 During the current financial year 1993-94 (up to August 14, 1993), the Wholesale Price Index recorded an annualised inflation rate of 6.2 per cent on a point to point basis which was much lower than 9.3 per cent registered in the comparable period of the previous year.

Bullion Prices

4.46 During 1992-93, a number of policy announcements of a far-reaching nature were made relating to the bullion markets. It may be recalled that a gold import policy was announced in the 1992-93 Union Budget under which gold up to five kilogrammes could be imported by Non-Resident Indians (NRIs) and returning Indians on payment of a nominal import duty. On February 8, 1993, the Government announced a liberalised silver policy, under which import of silver up to a maximum of 100 kilogrammes was allowed by incoming passengers of Indian origin or those holding Indian passports no payment of customs duty of Rs. 500 per kilogramme. Again on February 18, 1993, the Gold Bonds Scheme, 1993, was announced which, as mentioned earlier, was kept open for public subscription for three months up to June 14, 1993, and helped mobilise 41.12 tonnes of gold. These policy measures have had a bearing on the prices of gold and silver. The domestic price of gold which exhibited a rising trend in previous years experienced a reversal during 1992-93. The average annual price of gold, both on year-end monthly average basis, registered a decline of 4.5 per cent in 1992-93 in contrast to a substantial increase of 25 per cent in the previous year (Appendix Tables IV.23 to IV.25). With gold prices in the international markets also displaying declining trends, the spread between the domestic and international prices of gold which was 51.3 per cent in 1991-92 declined by more than half to 23.2 per cent in 1992-93, with the lowest spread recorded at 16.5 per cent in February 1993.

4.47 There was a sharp decline in the domestic price of silver during the year, especially after the announcement of the policy in February 1993 allowing import of silver. In 1992-93, on an year-end basis, silver price recorded a fall of 31.7 per cent and on an average basis, by 3.5 per cent. The average annual spread between the domestic and international price of silver narrowed down considerably from 124.2 per cent in 1991-92 to 88.7 per cent in 1992-93. On a monthly basis, the spread which stood at 110 per cent in April 1992 declined sharply to 50 per cent in March 1993.

Trends During the First Quarter : 1993-94

4.48. The domestic price of gold firmed up considerably during April and May 1993 due to the increase in seasonal demand, the demand for subscription to the Gold Bonds Scheme, 1993 and the spurt in international prices. By the end of June 1993, following the conclusion of the Gold Bonds Scheme on June 14, 1993 and the decline in the international prices of gold, the domestic price of gold tended to drift downward. This, however, was reverted again in July 1993. The spread which had widened to 25.7 per cent in April 1993, declined to 22.2 per cent in May 1993, 19.1 per cent in June and 15.3 per cent in July 1993. However, in July 1993, it increased substantially in the international markets during April and May softened in June 1993. However, in July 1993, it increased substantially with the spread between domestic and international prices declining continuously to 27.6 per cent.

V. CAPITAL MARKET DEVELOPMENTS

5.1 During the year under review the primary market witnessed an upsurge in activity both in terms of number and amount of new capital issues. The secondary market, however, experienced generally subdued conditions. Term capital financing also has increased substantially.

Operations of Term-financing and Investment Institutions

5.2 According to available data, the sanctions by all-India Financial Institutions (net of inter-institutional flows) for 1992-93 (April-March) at Rs. 29,809 crore indicated a substantial increase of 34.9 per cent as against 24.5 per cent in the previous year (Appendix Table V.1). Disbursements during the period rose by 34.8 per cent as compared to 34.6 per cent in the preceding year. Investment institutions (UTI, LIC and GIC) experienced a substantial increase in both sanctions and disbursements during 1992-93 (April-March). The all-India term lending institutions have been facing adjustment in that their concessional resources through guaranteed bonds have been reduced and the system of Long Term Operations (LTO) allocation from the Reserve Bank being discontinued. As such, the financial institutions have had increasingly to access the market for their resources. This would entail a reorientation of the operations of financial institutions.

Corporate Investment Forecast

5.3 The Reserve Bank has been generating estimates of corporate investment (on a financial year basis), as per the methodology evolved by Dr. C. Rangarajan, which by and large, have been robust. The latest study on forecast of investment of the private corporate sector has estimated that capital expenditure aggregating to Rs. 25,335 crore in nominal terms would have been incurred during 1992-93. Including the assistance of Rs. 436 crore under the Bill Rediscouinting Scheme and Rs. 23 crore under the Technical Development Fund Scheme, the capital expenditure would work out to Rs. 25,794 crore, denoting a rise of 29.7 per cent over the year as against a rise of 4.2 per cent in 1991-92. In real terms i.e. at 1980-81 prices, total investment amounted to Rs. 11,051 crore in 1992-93, registering an increase of 15.4 per cent as against a decline of 4.3 per cent in 1991-92. During 1992-93, in all 1,175 projects in the private corporate sector (including joint sector) were sanctioned assistance by the major term lending institutions, viz., IDBI, IFCI and ICICI. New projects have accounted for the largest share of 29.1 per cent (Rs. 7521 crore for 259 projects). There was a market deviation in the pattern of industry-wise distribution during 1992-93. Chemicals and petrochemicals accounted for the highest share of 27.8 per cent (Rs. 7186 crore for 142 projects) of the total cost of all projects, followed by textiles other than jute with a share of 16.6 per cent (Rs. 4,295 crore for 212 projects). Metal and metal products ranked third with a share of 16.1 per cent (Rs. 4,161 crore for 135 projects). In the previous year, metals and metal products accounted for a share of 39.0 per cent followed by chemicals and petrochemicals (10.0 per cent) and textiles other than jute (9.6 per cent).

New Issues Market

5.4 With the abolition of the office of the Controller of Capital Issues (CCI) with effect from May 29, 1992, Government and non-Government companies sought clearance of offer documents from the securities and Exchange Board of India (SEBI). The amount approved (consents/acknowledgements including premium and bonus shares) both by CCI (April-May 1992) and SEBI (June 1992-March 1993) totalled Rs. 20,841 crore for non-Government companies and Rs. 380 crore for Government companies (Appendix Table V.2).

5.5 The primary capital market for new issues by non-Government public limited companies during 1992-93 registered a sharp rise of 244.4 per cent as against 33.5 per cent in 1991-92 (Appendix Table V.3). This spurt could be attributed largely to the abolition of capital issues control

with effect from May 29, 1992, and to the general stance of policy. The total capital issues during 1992-93, were almost equally split as between equity shares and debentures. Among the new capital issues, non-convertible debenture issues and rights issue were predominant.

5.6 A notable feature during the year was the floating of 34 mega issues (issue of Rs. 100 crore each and above) for a record amount of Rs. 8,972 crore equivalent to 45.3 per cent of the total new capital issues as against Rs. 1,985 crore (9 mega issues) according for 34.5 per cent in the preceding year.

5.7 The year 1992-93 also witnessed a spate of equity issues with a high premium, particularly, in the form of rights issues. There were 324 equity issues floated with 'premium' as against 58 such issues in 1991-92. The total premium at Rs. 5,184 crore constituted 51.9 per cent of the total equity issues as against Rs. 227 crore or 13.1 per cent during 1991-92. In the first quarter of 1993-94, the amount of new issues through equity shares at Rs. 2,287 crore increased by 23.7 per cent over that of the corresponding quarter of 1992-93, largely on account of premium.

5.8 Another important development in the capital market was the introduction of innovative/hybrid instruments having special features to attract more investors for new issues, like warrants attached to non-convertible debentures, zero-interest convertible bonds, equity attached with warrants, secured premium notes attached with warrants, and deep discount bonds. The available data, for 1992-93, show that Rs. 4,703 crore were raised through such hybrid innovative instruments as against Rs. 198 crore in 1991-92. Another feature during 1992-93 was that of bunching of issues. During September-November, 1992, 317 issues were floated aggregating Rs. 8,518 crore which accounted for 43.0 per cent of total capital issues.

5.9 In the more recent period primary issues have had difficulty in being fully subscribed and there have been problems of large development on underwriters who, in turn, arranged with financial institutions to have these issues taken up at a discount. These matters have been engaging the attention of Securities and Exchange Board of India.

Equity Prices

5.10 The stock markets during the most part of 1992-93 remained subdued, contrary to the unprecedented buoyancy that prevailed during the previous year. The high level of equity prices reached towards the end of March and beginning of April 1992, could not be sustained once the irregularities in transactions involving banks, financial institutions and stock brokers came to light. Thereafter the stock markets experienced continuing decline in share prices till the middle of August 1992. After a short recovery in September 1992, equities once again drifted downward till January 1993. Share prices witnessed a rise during February 1993 but this proved to be shortlived. The Reserve Bank All-India Index Number of Ordinary Share Prices (Base : 1980-81=100) (Weekly) which stood at 1,485.4 at the week ended March 28, 1992, moved down to 1,134.2 in the week ended August 29, 1992, and closed at 892.1 by the end of March 1993 (Appendix Table V.4). The Bombay Stock Exchange (BSE) Sensitive index (1978-79=100) also showed a similar trend (Graph 6).

5.11 The average Reserve Bank index for 1992-93 at 1,142.1, indicated a gain of 47.1 per cent against the rise of 55.1 per cent during 1991-92. On a point-to-point basis, however, the index recorded a decline of 39.9 per cent from 1,485.4 at the week ended March 28, 1992 to 892.1 at the week ended March 27, 1993, in contrast to the substantial gain of 18.14 per cent in the previous year. The industry wise analysis indicated that all the industry groups experienced heavy losses with the exception of aluminium group shares which gained 6.5 per cent. The maximum loss of 66.2 per cent was sustained by cement group's shares, followed by rubber and rubber products (63.6 per cent) and man-made fibres (59.2 per cent).

5.12 The available data on the Bombay Stock Exchange (BSE) show that all the major indicators, viz., market turnover, market capitalisation and price-earning ratio reflected the subdued trend in the secondary market during the year 1992-93. The average monthly turnover of Rs. 3,807 crore during 1992-93 was lower by 36.3 per cent than the previous year (Rs. 5,981 crore). The BSE data on market capitalisation as at the end of March 1993 aggregated Rs. 2,10,952 crore (provisional) which was 34.8 per cent lower as compared with Rs. 3,23,363 crore 12 months ago. The price-earning (P/E) ratio witnesses a steady decline from April 1992 except for brief spurts in September 1992 and February 1993. The average P/E ratio (calculated for 30 scrips included in BSE Sensitive index, Base : 1978-79 = 1000 which was 52.6 in April 1992 declined to 29.3 in March 1993. Even at the March 1993 level, the P/E ratio is regarded as being high as compared with the P/E ratio obtaining in a number of markets in other countries¹⁴.

5.13 The volatility of share prices, measured in terms of the co-efficient of variation (C.V.), was less during 1992-93 as compared with the previous year. The C.V. of the index was substantially lower at 16.2 per cent during 1992-93 as against 27.0 per cent in 1991-92. The dispersion (the range between high and low) in the index was lower at 764.8 as compared with 948.5 in the preceding year.

5.14 During the first quarter of 1993-94, movements in security market continued to be subdued. At the end of June 1993, the RBI index stood at 850.6 as against 892.1 at the end of March 1993. The BSE Sensitive Index showed a similar trend.

Foreign Institutional Investors

5.15 The number of steps taken during the year to attract more inflow of foreign institutional investment into the country have been set out in Section-I. According to available information, SEBI and Reserve Bank have granted permission to 56 Foreign Institutional Investors (FIIs) up to July, 1993. To further attract investments by FIIs, the Budget for 1993-94, contained tax incentives. The short-term capital gains tax was reduced to 30 per cent while dividend income would be taxed at 20 per cent. These would place the Indian market on terms comparable with many countries of the world.

¹⁴At the end of 1991, the P/E ratio stood at 12.70 in France, 15.10 in Germany, 15.20 in U.K. and 21.70 in the United States

Over the Counter Exchange of India

5.16 Over the Counter Exchange of India (OTCEI) commenced its operations from October 6, 1992. By the end of March 1993, 7 scrips were listed with OTCEI. As the monthly turnover of OTCEI moved up to Rs. 106 lakh during June 1993 from Rs. 17 lakh in October 1992, OTCEI has decided to offer benefits of their trading to investors for shares currently listed on other exchanges. As of end June 1993, 8 scrips were listed with OTCEI. It is expected that trading on 25 permitted securities will commence very shortly. 1397 GI/94—23

OTCEI has started trading in debt instruments, beginning May 20, 1993, with Infrastructure Leasing and Financial Services (IL&FS) as the compulsory market maker. OTCEI is in the process of opening regional windows, beginning with Delhi and Madras, to be followed by Calcutta and other metropolitan areas.

National Stock Exchange of India Ltd

5.17 The National Stock Exchange of India Limited (NSEI) promoted by IDBI, ICICI, IFCT, GIC, LIC, State Bank of India, SBI Capital Markets, SHCIL and IL&FS was incorporated as a company under the Companies Act, 1956, on November 27, 1992. NSEI has been granted recognition by the Government of India with effect from April 26, 1993, initially for a period of five years. The main objective of NSEI is to ensure comprehensive nation-wide securities trading facilities to investors through automated screen based trading and automatic post trade clearing and settlement facilities. The NSEI will be encouraging corporate trading members with dealer new-works, computerised trading and short settlement cycles. It proposes to have two segments, one dealing with wholesale debt instruments and the other dealing with capital market instruments. The Electronic Clearing and Depository System (ECDS) proposed to be set up by the Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) would provide the requisite clearing and settlement systems.

Public Sector Undertakings' Bonds

5.18 During 1992-93 as many as 17 public sector undertakings (PSUs) were to raise Rs. 6,291 crore through bonds/debentures, but as per the provisional information only Rs. 1,062 crore were raised, as against Rs. 5,211 crore raised in 1991-92 (Table 5.1). The securities irregularities brought into sharp focus the major weaknesses in the PSU bond market. The floatations essentially depend on very short-term money market funds through the mechanism of REPOs and as this outlet was no longer available once the securities irregularities came to light, it was virtually impossible for PSUs to float bonds. The Union Budget for 1993-94 has indicated that PSUs would be raising Rs. 6,882 crore by way of bonds/debentures. A pre-requisite for a normalisation of the PSU bonds market is the development of proper and timely issue of bonds, provision of adequate liquidity and a transparent system of trading to meet their resources demand during 1993-94.

Table 5.1 : Public Sector Undertakings—Issue of Bonds during 1985-86 to 1992-93

(Rupees crore)			
Year	Tax Free Bonds	Taxable Bonds	Total (2+3)
1	2	3	4
1985-86	—	353.7	353.7
1986-87	898.0	776.1	1,674.1
1987-88	1,737.3	946.9	2,684.2
1988-89	2,080.0	417.7	2,497.7
1989-90	2,597.0	1,132.0	3,729.0
1990-91	2,345.0	1,118.1	3,463.1
1991-92	2,368.6	2,842.2	5,210.8
1992-93	10.5	1,052.0	1,062.5

Source : Returns received from the respective public Sector Undertakings.

Disinvestment of Public Sector Enterprises' Shares

5.19 The Government of India as a part of a package of public enterprise reform, had initiated the process of disinvestment during 1991-92. This was continued in 1992-93. During 1991-92, equities equivalent to 5 to 20 per cent of total capital in 31 public sector enterprises (PSEs) were disinvested in two phases in December 1991 and February 1992. The realisation from disinvestment during the year aggregated Rs. 3,038 crore (Table 5.2).

5.20 For the year 1992-93, a target of Rs. 3,500 crore of PSE disinvestment was set in the Union Budget. Against this target, Rs. 1,866 crore was realised in two tranches in October 1992 and December 1992. All the bids received in the third tranche during the March 1993 auction were rejected on the ground that they were below the reference prices fixed on the Government. In the Union Budget 1993-94, it has been proposed to realise Rs. 3,500 crore through disinvestment. To realise the budgeted amount, it would be necessary to have action plans as suggested by the Committee on Disinvestment of Shares in Public Sector Enterprises (See Box IV).

Table 5.2 : Disinvestment of Public Sector Enterprises' Shares

Year	No. of Share sold (crore)	Total realisation (Rs. crore)	Average realisation (Rupees)
1	2	3	4
1991-92			
(i) 1st Tranche	51.62	1,427	27.65
(ii) 2nd Tranche	35.59	1,611	45.25
1992-93			
(i) 1st Tranche	12.87	682	53.00
(ii) 2nd Tranche	31.06	1,184	38.10

BOX IV

Report of The Committee on Disinvestment of Shares in Public Sector Enterprises

The Committee on Disinvestment of Shares in Public Sector Enterprises, with Dr. C. Rangarajan as its Chairman, submitted its report to the Government in April 1993. The terms of reference of the Committee were; (a) to devise criteria for selection of public sector enterprises (PSEs) for disinvestment during 1992-93; (b) to advise on limits on the percentage of equity to be disinvested in respect of such PSEs; (c) to suggest the target clientele; (d) to suggest the modus operandi of disinvestment; (e) to lay down the criteria for valuation of equity shares of PSEs; and (f) to make other relevant recommendations. Some of the major recommendations of the Report are presented here.

Although 1992-93 had ended, by the time the Report was finalised and submitted, the Committee noted the existing status of disinvestment and the policies adopted during 1992-93. It is generally agreed that a public issue by way of an

offer to the members of the public would be most desirable, though if time and market circumstances do not permit it, bid mechanisms close to a public offering should be devised.

The Committee observed that there is first a need to broadly indicate the objectives of disinvestment in public sector equity. Limits to the level of disinvestment, in the Committee's view, are derived from the target level of Government ownership in each enterprise in the medium-term. It considered the following target levels of ownership; in respect of units reserved for the public sector, 51 per cent to enable control over management; and in exceptional cases of enterprises having dominant share or the need for separate identity for strategic reasons, 26 per cent. The Committee felt that the Government may hold more than 26 per cent of the total equity in enterprises with outstanding prospects and high growth potential. It recommended that the desirable level of equity base and the targeted level of Government ownership be decided in the light of considerations such as the estimate of on-going investment plans for expansion/modernisation/technical collaboration, the pattern of financing of such expansion through additional debt or expanded equity, the existing debt-equity structure including scope for increasing either one of the components and the feasibility of issuing convertible bonds for raising adequate resources. The Committee also recommended settlement of all modalities and accounting procedures for settlement of large arrears, if any of dues payable receivable and appointment of a merchant banker for each PSE.

The Committee recommended that once a reasonable market price is established in a normal trading atmosphere over a reasonable period of time and a public enterprise completes the preparatory work, the fixed price method would be the most appropriate. Where this is not possible, the auction method with wide participation may be adopted. It also recommended that disinvestment should be planned and implemented separately for each enterprise and a merchant banker be appointed for devising the modus operandi of sales. An enterprise-specific approach including timing of issue and choosing intermediaries was favoured by the Committee. It also recommended that 10 per cent of the proceeds be set apart by the Government for lending to the PSE concerned on concessional terms to meet their expansion/rationalisation needs.

Regarding the valuation of PSE equity shares, the Committee felt that discounted cash flow to be most relevant, even though it is the most difficult to implement. It recommended that an explicit assessment of the scope and limits for selling non-income generating assets and rationalising labour force should be made. Furthermore, the Committee cautioned that policies affecting future profitability (such as guaranteed rate of return) may be extended only after careful assessment of the implications of such assurances on the economic efficiency rather than immediate attractiveness of the shares to investors. It further recommended that wherever disinvestment is made through public issues, the offering price would need to be fixed with a close assessment of the need to project the issue as a success to pave way for subsequent offering and at the same time avoiding any criticism of underpricing.

Regarding target clientele, the Committee recommended that it should include the general public, mutual funds, NRIs and foreign investors, employees of PSEs with a ceiling on the number of shares that could be purchased at a discount on the market price, and under special circumstances, a reserved category of their stockholders.

The Committee recommended, after a study of the international experience and keeping in view our own requirements, the setting up of a Standing Committee on Public Enterprise Disinvestment to guide the public enterprises and Government in preparatory measures for disinvestment in areas such as financial restructuring, issues of diversification of ownership and medium-term corporate plan.

The Committee also commended for consideration the use of part of proceeds of disinvestment not only for National Renewal Fund, 10 per cent incentive for PSEs, and reduction in Government debt, but also for channelising resources to social sectors like literacy, health and employment generation in rural areas.

Guidelines for Market Makers

5.21 In Section 1, mention has been made about the promotion of market makers in some of the major Stock Exchanges. Market makers who offer two-way quotations for buying and selling of securities, would impart liquidity to scrips and help reduce volatility in share price movements. Market makers would be approved by the SEBI taking into account the recommendations of the concerned Stock Exchange. To carry out their operations, market makers require financial support from the banking system. The Reserve Bank has issued the following guidelines to scheduled commercial banks:

- (i) Market Makers who have been approved by SEBI would be eligible to approach scheduled commercial banks for grant of advances.
- (ii) While granting advances to Market Makers, scheduled commercial banks may exercise their commercial judgement in determining the working capital requirements.
- (iii) Banks may prescribe normal prudential margins based on their commercial judgement while providing advances to Market Makers. It is clarified that the existing minimum margin of 50 per cent on loan to individuals against shares, debentures/bonds would not be applicable to bank advances to Market Makers.
- (iv) The prescribed interest rate on such advances will depend upon the amount borrowed; the banks are free to determine the rate of interest on credit limits over Rs. 2 lakh which is subject to a minimum of 16 per cent at present.
- (v) Banks may accept as collateral for the advances to the Market Makers scrips other than the scrip in which the market making operations are undertaken.
- (vi) The credit limits to Market Makers should be determined by the banks taking into account the market minimum of 16 per cent at present.
- (vii) Banks should ensure that advances provided for market making is not diverted for investment in shares other than the scrip earmarked for market making purpose. For this purpose, a suitable follow-up and monitoring mechanism must be evolved.

- (viii) Under the existing guidelines it is stipulated that loans not exceeding Rs. 5 lakh can be provided to an individual borrower for meeting contingencies and needs of personal nature or for subscription for rights or new issues of shares/debentures or secondary market purchases against the security of existing shares, debentures/bonds. This ceiling of Rs. 5 lakh would not be applicable to Market Makers.

5.22 The Market Maker approved by SEBI would be required to make a market for a minimum of five scrips, initially those which are not included in the BSE National Index. Each Market Maker will be required to acquire at least 30,000 shares in each of the scrips.

Trends in Growth of Deposits with Non-Banking Corporate Sector

5.23 Data on aggregate deposits of 12,817 reporting non-banking companies are provisional and available only up to 1991-92. They showed an increase of Rs. 8,298 crore to reach Rs. 53,559 crore by end-March 1992 as against a rise of Rs. 11,730 crore reported by 10,166 companies for the year ended March 31, 1991. The total regulated deposits of the reporting companies at the end March 1992 increased by Rs. 1,362 crore with an outstanding level of Rs. 9,269 crore, while the exempted deposits rose by Rs. 6,936 crore compared with a rise of Rs. 10,581 crore in the previous year. The exempted deposits of the reporting companies stood at Rs. 44,290 crore by the end of March 1992. Non-financial companies accounted for 52.8 per cent of aggregate deposits of the reporting companies, while the financial companies accounted for 41.5 per cent. The miscellaneous and residuary non-banking companies together accounted for a meagre share of 5.7 per cent (Appendix Table V.5). The regulated deposits of the non-banking companies were equivalent to 4.0 per cent of the aggregate deposits of all scheduled commercial banks as on March 20, 1992.

VI. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR

6.1 The process of stabilisation of the balance of payments was carried forward during 1992-93. The self-balancing mechanism embodied in the Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) and exceptional financing from bilateral and multilateral sources enabled an accretion of US dollar 612 million to the country's stock of international reserves in 1992-93. By the end of March 1993, the Bank's foreign currency assets reached a level of US dollar 6,434 million. The response of the real sectors to the supply augmenting initiatives of structural reforms was weaker than anticipated, notwithstanding the strong recovery in agriculture. Social disturbances in the country, particularly in Bombay which accounts for roughly 60 per cent of transportation services related to India's foreign trade, stifled the seasonal upturn in both exports and imports which usually occurs in the second half of the financial year. The uncertainty surrounding external transactions with the constituents of the Commonwealth of Independent States (CIS) and the impediments to trade diversification in the context of the continuing recession in industrial countries were adverse exogenous developments which had a bearing on the external sector.

Balance of Payment

6.2 Preliminary balance of payments data are now available for the year 1990-91. For 1991-92 provisional estimates are available which closely approximate actuals. To bridge the gap in the availability of actual data, quick estimates for the year 1992-93 have been prepared on the basis of available information [Tables 6.1, 6.2 and Appendix Table VI.1].

6.3 Balance of payments data for the years 1990-91 to 1992-93 are presented in a format in which in the year of imports the value of defence-related imports are recorded under

imports with credits financing such imports shown in the capital account. Interest payments on defence debt owed to the General Currency Area (GCA) as and when they are made are recorded under investment income payments in the invisible account and principal repayment under amortisation of commercial borrowings in the capital account. In the case of the Rupee Payment area (RPA), interest payment on and principal repayment of debt is clubbed together and shown separately under the item 'Rupee Debt Service' in the capital account. This is in line with the recommendation of the High Level Committee on Balance of Payments (Chairman : Dr. C. Rangarajan).

Table 6.1 : India's Overall Balance of Payments

Item	US\$ million			Rupees crore		
	1992-93 (Quick Estimates)	1991-92 (Provi- sional Estimates)	1990-91 (Prelimi- nary)	1992-93 (Quick Estimates)	1991-92 (Provi- sional Estimates)	1990-91 (Prelimi- nary)
1	2	3	4	5	6	7
A. Current Account						
1. Exports f.o.b.	18,789	18,223	18,477	54,418	44,923	33,153
2. Imports c.i.f.	22,895	20,347	27,914	65,945	50,159	50,086
3. Trade Balance@	-4,106	-2,124	-9,437	-11,527	-5,236	-16,933
4. Current Account Balance	-4,921	-2,135	-9,857	-13,533	-5,186	-17,686
B. Total Capital Account, IMF and SDR Allocation	5,649	5,710	8,579	16,096	15,031	15,393
C. Reserves and Monetary Gold (increase—/decrease+)	-728	-3575	1278	-2563	-9845	2,293

@ After taking into account errors and omissions. See also Appendix Table VI.1.

Table 6.2 : Current Account Transactions as Proportion of GDP at Current Market Prices

Item	(Per Cent)				
	1992-93* (QE)	1991-92* (PE)	1990-91* (Prelimi- nary)	Seventh Five Year Plan (Annual average)	Sixth Five Year Plan (Annual average)
1	2	3	4	5	6
1. Exports	7.7	7.3	6.2	5.1	5.0
2. Imports	9.3	8.2	9.4	8.3	8.4
3. Trade deficit	1.6	0.9	3.2	3.2	3.4
4. Invisible receipts@	3.3	3.3	2.5	2.9	3.6
5. Invisible payments	3.8	3.3	2.6	1.9	1.5
6. Invisibles (net) (4-5)@	-0.5	0.0	-0.1	0.9	2.1
7. Current Account deficit (3-6)@	2.1	0.9	3.3	2.2	1.3

QE : Quick Estimates.

PE : Provisional Estimates.

@ Include official grants which are treated as part of current account receipts here.

* Include accrued interest on NRI deposits.

Note : Figures for Sixth and Seventh Five-Year Plans are not strictly comparable with those for recent years.

6.4 During 1992-93, a subdued export performance and a modest rise in import demand yielded a merchandise trade deficit of US \$ 4,106 million (Rs. 11,527 crore). While the trade deficit did widen over the year by US \$ 2 billion, this essentially reflected the compressed level of imports during 1991-92. The invisibles account recorded a deterioration. There was a decline in the rate of growth of tourist arrivals (including nationals of Pakistan and Bangladesh) by 2.2 per cent reflecting the impact of the disturbances which coincidentally occurred at the beginning of the tourist season. The rising trend in interest payments decelerated, although outward remittances on account of royalty, technical fees etc., continued to increase. Private transfer receipts mainly comprising remittances from non-resident Indians remained broadly at the level in preceding years, although there are indications of some diversion of remittances to the capital account to avail of the benefit of the full applicability of the market rate of exchange to such transfers which would otherwise have been converted at a composite of official and market rates in the ratio 40:60. The invisibles account inclusive of official transfers yielded a net outflow of US \$ 815 million (Rs. 3,104 crore). The current account deficit (inclusive of accrued interest on NRI deposits and official transfers) for 1992-93 is estimated at US \$ 4,921 million (Rs. 14,631 crore) or 2.1 per cent of GDP as against US \$ 2,135 million or 0.9 per cent of GDP in 1991-92. In 1990-91, the current account deficit was significantly higher at US \$ 9,679 million (Rs. 17,366 crore) or 3.3 per cent of GDP (Appendix Table VI.1).

6.5 Following the liberalisation in baggage rules for persons of Indian nationality or origin returning from abroad, which was effected in the Union Budget 1992-93, there was an estimated inflow of about 132 tonnes of gold valued at approximately US \$ 1.4 billion during 1992-93. In February 1993 similar liberalisation was extended to the import of silver, as a result of which, about 650 Kgs. of silver were brought into the country during 1992-93. However, this inflow of bullion is not reflected either under imports or under private transfer receipts in the balance of payments data for 1992-93.

6.6 In the capital account, the net inflow of external assistance declined by over US \$ 1 billion from that in the preceding year despite the mobilisation of exceptional financing from donors. Access to commercial markets was not attempted in view of the country's rating. Disbursements of commercial borrowings largely took the form of trade-related credits. There was a turnaround in the trend of net outflows under the FCNRA Scheme and net inflows began to occur from October 1992 onwards. The large accruals under the FCROD Scheme in the first four months of the year ceased with the discontinuation of the Scheme and the succeeding months witnessed withdrawals therefrom. Drawals under the Standby Arrangement negotiated with the IMF were in the form of purchases of US \$ 663 million (Rs. 1,717 crore)

in July 1992, US \$ 643 million (Rs. 1,685 crore) in December 1992 (of which US \$ 295 million or SDR 212 million was held in the Reserve Position in the Fund as India's Quota subscription towards the increase in Quotas under the Ninth General Review of Quotas), US \$ 319 million in February 1993 and US \$ 325 million in June 1993. Net purchases from the IMF amounted to US \$ 1,288 million in 1992-93 as against US \$ 781 million in the preceding year.

Foreign Exchange Reserves

6.7 India's foreign exchange reserves (comprising foreign currency assets of the Reserve Bank, gold held by the Reserve Bank and SDR balances held by the Government) rose from US \$ 9,220 million (Rs. 23,850 crore) at the end of March 1992 to US \$ 9,832 million (Rs. 30,744 crore) showing an increase of US \$ 612 million (Rs. 6,894 crore) (Appendix Table VI.3). Exclusive of gold revaluation and transactions with the IMF, the foreign exchange reserves declined by US \$ 525 million during 1992-93 against an increase of US \$ 2,794 million during 1991-92. During the first quarter of the current financial year, foreign exchange reserves increased by US \$ 715 million. Exclusive of gold revaluation and transactions with the IMF, reserves increased by US \$ 4 million during April-June 1993.

Foreign Currency Assets

6.8 The Bank's foreign currency assets rose from US \$ 2,236 million at end-March 1991 to US \$ 5,631 million at end-March 1992 and further to US \$ 6,434 million at end-March 1993. Thus, these assets rose by US \$ 803 million in 1992-93 over and above the rise of US \$ 3,395 million during 1991-92 (Graph 7). The balancing mechanism of the dual exchange rate system under the LERMS was evident in the broad correspondence between foreign currency purchases from and sales to authorised dealers. A sharp decline in aid receipts and large debt service payments resulted in a net outflow from the stock of foreign currency assets. Under the Memorandum of Understanding signed on May 5, 1992 between India and the Russian Federation, Technical Credit of US \$ 165 million (net of repayment of US \$ 3 million) was extended to Vneshtorgbank, Moscow, of which US \$ 88 million was adjusted against liabilities designated in rupees due to Russia with the balance of US \$ 77 million remaining to be repaid to India. The foreign currency assets were bolstered by an inflow of exceptional financing of US \$ 826 million (in the form of aid receipts) and net accruals from IMF drawals of US \$ 1,063 million. There was a turnaround in the net outflows under the FCNRA Scheme. Large inflows under the FCROD Scheme in the first four months of 1992-93 were counterbalanced by withdrawals in succeeding months so that the year ended with a net inflow of US \$ 350

Table 6.3 : Factors Affecting Movements in Foreign Currency Assets

Item	U.S. Dollar Million		Rupees crore	
	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
Transactions with	128	1,855	735	5,215
Net Aid Receipts	-976	-3	-2,234	-164
Technical Credit to Russia	-165	—	-429	—
Others	-698	-313	961	211
Special Factors	2,514	1,856	6,529	4,928
Exceptional	826	1,000	2,183	2,477
Financing				
Transactions with IMF	1,063	790	2,754	1,793
FCBOD Scheme	350	304	881	742
FCNRA Scheme	86	-1,611	223	-3,641
India Development Bonds	189	1,373	488	3,557
Change in Foreign Currency Assets	803	3,395	5,562	10,190
Change in Foreign Currency Assets exclusive of Special factors	-1,711	1,539	-967	5,262

ADs : Authorised Dealers

million. Exclusive of special factors (Table 6.3), the foreign currency assets would have recorded a decline of US \$ 1,711 million as against an increase of US \$ 1,539 million measured on a comparable basis. Between the end of March 1993 and the end of June, 1993 foreign currency assets increased by US \$ 119 million and stood at US \$ 6,553 million at the end of June, 1993.

Special Drawing Rights

6.9 Holdings of Special Drawing Rights (SDRs) fell by SDR 53 million during the fiscal year 1992-93 as compared with the fall of SDR 10 million during the preceding year. The decline during 1992-93 was a combined result of a net acquisition of SDRs worth SDRs 225 million, IMF drawals of SDR 446 million, repurchases of SDR 54 million, payment of charges/interest amounting to SDR 227 million (net of interest subsidy) to IMF, sale of SDRs worth SDR 231 million and payment of SDR 212 million to the IMF towards the increase in India's Quota. During April-June 1993, SDR holdings rose by SDR 169 million.

Gold

6.10 The gold holdings of the Reserve Bank of 354 tonnes value at US \$ 3,380 million (Rs. 10,549 crore) at the end of March 1993 included an addition of 0.25 tonnes valued at US \$ 2.5 million (Rs. 6.75 crore) to the gold stocks on account of receipt of interest on gold holdings kept abroad. There was also an accretion to the Bank's gold holdings due to purchases of 3.07 tonnes valued at US \$ 29.4 million (Rs. 82.57 crore) from the Government of India during December 1992 to March 1993. During April-June 1993, the value of gold holdings rose by US \$ 427 million, essentially reflecting the increase in the international market price of gold.

Merchandise Trade

6.11 Developments on the merchandise trade front proved to be less than satisfactory over the year as a whole. The modest recovery in exports during the first half of 1992-93 was largely offset in the second half of the year because of dislocation of trade following disturbances in Bombay and weak world demand. In US dollar terms, aggregate exports at US \$ 18,421 million rose by only 3.1 per cent during 1992-93. Imports, on the other hand, grew by 11.9 per cent to US \$ 21,726 million during the year (Appendix Table VI. 5).

India's Trade with General Currency Area and Rupee Payment Area

6.12 Exports to the General Currency Area (GCA) which have a direct bearing on the foreign exchange reserves, however, exhibited resilience. The growth of GCA exports was evident from the beginning of the year up to October 1992; it decelerated in the following two months and veered away from the seasonal pattern (measured in terms of monthly averages of those exports over the preceding three years). By January 1993, however, GCA exports resumed the seasonal uptrend which reached a peak in the closing month of the year. The growth of GCA exports at 10.4 per cent in US dollar terms during 1992-93 was satisfactory, against the back-ground of a volume growth in world trade of 4.2 per cent in 1992. Given the continuing sluggishness in the international prices of tradeables, the volume growth of GCA exports may be placed in the range of 7-8 per cent.

6.13 Exports to the Rupee Payment Area (RPA) fell over the year by US \$ 1,118 million or by 62.2 per cent in US dollar terms and continued to be a drag on the overall export growth. The deterioration in these exports was evident for the third year in succession. The collapse of trade with the erstwhile USSR, one of India's principal markets, led to a marked shift in the destination of exports and sources of imports as between GCA and the RPA (Graph 8).

6.14 The rebound in imports from the compression of 1990-91 and 1991-92 was strong in the first half of the year with import growth at 22.3 per cent in US dollar terms during April-September 1992; in the second half of the year, there was a perceptible slowdown in imports. As a result, the overall import growth for the year as a whole was only 11.9 per cent in US dollar terms, considerably lower than the expected revival from the retrenched level of imports in 1991-92. Non-POL, imports rose by 11.2 per cent in US dollar terms after declining by 22.2 per cent in the preceding year. The impact of extraneous developments and postponement of some imports in the latter half of the year due to expectations about changes in tariffs altered the seasonal pattern of non-POL, imports during the year and resulted in a contra-seasonal downward drift between September 1992 and January 1993 (Graph 9).

6.15 Imports of petroleum, oil and lubricants (POL) rose to US \$ 6.1 billion during 1992-93 from US \$ 5.4 billion in the preceding year. A step up in the quantity of imports of crude petroleum from 24.0 million tonnes in 1991-92 to 29.2 million tonnes in 1992-93 was necessitated by the continuing shortfall in domestic production. Imports of petroleum products also increased from 9.4 million tonnes in 1991-92 to 11.1 million tonnes in 1992-93 as a result of the shut-down of some refinery facilities for maintenance. The stability in international prices of crude oil during the year was a potential saving in the POL import bill, though the import prices of petroleum products rose moderately.

6.16 The trade deficit at US \$ 3,305 million on a customs basis during 1992-93 was lower than anticipated earlier (Appendix Table VI. 5). The measures taken to hold down imports during 1990-91 and 1991-92 vitiate any comparability of the trade balance during these years with that of the year under review. For the second year in succession, the non-POL balance registered a surplus entirely reflecting the subdued growth in non-POL imports. The POL deficit, however, widened over the year by US \$ 675 million.

6.17 The developments over the past two years have resulted in a shift in the direction of trade. While the shares of major markets for India's exports such as the European Economic Community (EEC), the USA, Japan and the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) remained stable between 1989-90 and 1992-93, the precipitous fall in the share of the RPA was absorbed by other countries. A similar trend was evident as regards sources of imports, although the share of OPEC in India's imports rose over the three-year period (Graph 10).

External Assistance

6.18 The inflow of external assistance declined substantially during 1992-93. Gross utilisation of loans and grants at US \$ 3,737 million (Rs. 11,454 crore) was lower by US

\$ 952 million (Rs. 161 crore) than that of US \$ 4,689 million (Rs. 11,615 crore) during 1991-92. The amortisation payments at US \$ 1,581 million (Rs. 4,846 crore) during 1992-93 were broadly the same as those in 1991-92. Net inflow of external aid declined by US \$ 1,059 million (Rs. 1,357 crore) to US \$ 2,156 million (Rs. 6,608 crore) during 1992-93 (Appendix Table VI.9). The impact of structural adjustment in her external sector was cushioned by the support provided by exceptional financing from multi-lateral and bilateral donors. Such exceptional financing amounted to US \$ 826 million in 1992-93 comprising US \$ 452 million from the World Bank, US \$ 150 million from the Asian Development Bank (ADB), US \$ 134 million from Japan, US \$ 62 million from Germany and US \$ 28 million from others. For 1993-94, the Aid India Consortium pledged assistance to India of US \$ 7.4 billion with a fast-disbursing component of US \$ 2.2 billion.

Accretions to Non-Resident Deposits

6.19 Under the Non-Resident (External) Rupee Accounts [NR(E)RA] Scheme, provisional data for 1992-93 indicate an accretion of US \$ 39 million (Rs. 111 crore) (excluding the estimated interest element) as compared with a withdrawal of US \$ 27 million (Rs. 44 crore) in 1991-92. There was an inflow of US \$ 86 million (Rs. 223 crore) under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (FCNRA) in 1992-93 as against a sizeable outflow of US \$ 1,611 million (Rs. 3,605 crore) in 1991-92 (Appendix Table VI. 10). At the end of March 1993, outstanding deposits under NR(E)R and FCNR accounts stood as US \$ 8,171 million or Rs. 25,634 crore with US \$ 2,884 million (Rs. 9,062 crore) under NR(E)RA and US \$ 5,287 million (Rs. 16,572 crore) under FCNRA. At the end of June 1993, outstanding balance amounted to US \$ 5,167 million or Rs. 16,136 crore and US \$ 2,900 million or Rs. 9,099 crore under FCNRA and NR(E)RA, respectively. Under the Foreign Currency (Ordinary Non-Repatriable) Scheme, there was an inflow of US \$ 1 million in 1992-93 as compared with that of US \$ 5 million in 1991-92. Under the Non-Resident (Non-Repatriable) Deposit [NR(NR)D] Scheme, there are indications of a sizeable inflow. Partial information available indicates an inflow of nearly US \$ 600 million (Rs. 1,912 crore) under the NR(NR)D Scheme during 1992-93. A full picture of the performance of the newly instituted genre of non-resident schemes is yet to emerge particularly, the FCNR (Banks) Scheme, since it was introduced very recently, i.e., from May 15, 1993.

6.20 The FC(B&O)D Scheme was suspended with effect from July 31, 1992. At that time, the outstanding deposits under the Scheme stood at US \$ 2,232 million. Following the suspension of the Scheme, there were sizeable withdrawals in succeeding months. The outstanding deposits under the Scheme stood at US \$ 1,044 million at the end of March 1993 and US \$ 932 million at the end of June 1993.

Interest Rates Non-Resident Deposits

6.21 Keeping in view the downward movement in interest rates in international markets, interest rates on deposits under FCNRA were revised five times in 1992-93 and thrice during the current financial year (up to end-July 1993) for all designated currencies (Appendix Table VI.11). Interest rates on NR(E)RA were revised effective October 9, 1992, for all term deposits of maturities ranging between 46 days and 3 years and a cap interest of 13 per cent was prescribed. The cap was lowered to 12 per cent with effect from April 8, 1993 in order to rationalise interest rates on NR(E)RA in accordance with domestic deposit rates.

External Debt

6.22 As mentioned in the previous year's Report, the Policy Group and Task Force on External Debt Statistics of India recommended a new definition and classification of external debt. The new classification is exhaustive and includes, in addition to the components covered at present, the interest credited to the accounts under the FCNRA scheme, convertible debentures, revalued balances under IBRD pooled loans and exchange adjustments in respect of pre-1971 IDA credits.* It would exclude lease transactions and rupee-rouble credits from the main debt statistics (the latter appear as memo items). Under short-term debt, all credits up to six-month maturity are excluded. The Group also recommended that the data on non-civilian debt be disclosed in view of the need for greater transparency of the debt statistics. Appendix Table VI.12 presents India's external debt based on the new definition and classification. India's long-term debt rose from US \$ 56 billion (Rs. 96,439 crore) at the end of March 1990 to US \$ 69 billion (Rs. 2,13,508 crore) as at the end of March 1993. The short-term debt declined from US \$ 5.5 billion (Rs. 9,465 crore) to US \$ 4.5 billion (Rs. 13,909 crore) during this period. The total debt including those given as memo items amounted to US \$ 85 billion (Rs. 2,66,167 crore) as at the end of March 1993.

6.23 In relation to GDP at current market prices, the total debt excluding that under memo items rose from 23.3 per cent at end-March 1990 to 32.4 per cent as at end-March 1993. If the memo items are included, the debt stock as per cent of GDP would show a rise from 28.3 per cent as at end-March 1990 to 37.9 per cent as on March 31, 1993. The debt-service ratio (i.e. ratio of debt service payments exclusive of defence-related debt service payments to export of goods and services excluding official transfers) is estimated to have declined fractionally from 26.2 per cent in 1991-92 to 26.1 per cent in 1992-93. Inclusive of defence-related debt service payments, the debt-service ratio would have shown a decline from 31.6 per cent in 1991-92 to 30.8 per cent in 1992-93.

* However, revaluation of balances under IBRD pooled loans and exchange adjustments in respect of pre-1971 IDA credits have not been done, in view of technical problems.

Rupee-Rouble Debt

6.24 According to the agreement reached in the beginning of 1993, the amount of principal debt outstanding as on April 1, 1992 is to be converted into Indian rupees and repaid in Indian rupees as set out below :

- (i) The outstanding debt as on April 1, 1992 will be converted into rupees as per the rupee-rouble rate of exchange (in accordance with the provisions of the Protocol dated November 25, 1978) prevailing as on January 1, 1990 (Rs. 19.9 per rouble).
- (ii) The debt will also be converted into rupees as per the exchange rate as on April 1, 1992 (Rs. 31.8 per rouble).

6.25 The difference between the two amounts will be repaid with no interest in equal annual instalments over a period of 45 years starting from April 1, 1993. There is no protection against any fluctuation in the value of the rupee for five years from April 1, 1992. Thereafter, this will be reviewed once every five years and if there is more than three per cent depreciation of the rupee per year on an annual average basis vis-a-vis the SDR, the payment due on this account could be indexed to the rupee value of the SDR for the next five-year period.

6.26 The debt, as converted at the rate of exchange prevailing as on January 1, 1990, will be repaid with interest in accordance with the payment schedule in force for each loan agreement. In case the value of the rupee vis-a-vis the SDR changes on any day after April 1, 1992 by more than three per cent either way as compared to the base value of the rupee which is Rs. 3,53,637 on April 1, 1992, the amount of principal and interest repaid on any day after April 1, 1992 will be readjusted proportionately to the change.

6.27 With this agreement, the advantage to the country is that the increase in debt between January 1, 1990 to April 1, 1992 due to variation in the exchange rate of the rupee vis-a-vis the rouble as per the Protocol would be repaid in 45 years without any interest.

Exchange Rate of the Rupee

6.28 The dual exchange rate arrangement instituted on March 1, 1992 under the Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) enabled an orderly transition from a managed floating regime to a market-determined system. During the twelve-month period of the operation of the LERMS, the officially determined exchange rate held steady except for a downward adjustment of 1.12 per cent effected on December 4, 1992. The official exchange rate equilibrated between 40 per cent of current receipts surrendered to autho-

rised dealers (ADs) and in turn to the Reserve Bank and payments for purposes designated under the LERMS. An even volume of transactions passed through market operators and as a result, the market-determined exchange rate was stable. The spread between the official and market rates moved in a narrow range, except in the month of February 1993, when speculative activity resulted in some turbulence in the inter-bank exchange market (Table 6.4 and Graphs 11 and 12).

Table 6.4 : Spread between Official & Market Exchange Rates

(Rupees per US Dollar)				
Month	Official Rate	Market Rate	Spread	Weighted Rate
1	2	3	4	5
March 92	25.8901	29.4551	13.77	28.0291
April 92	25.8900	30.9253	19.45	28.9112
May 92	25.8900	30.3407	17.19	28.5604
June 92	25.8900	30.2361	16.79	28.4977
July 92	25.8900	30.2524	16.85	28.5074
August 92	25.8900	30.0885	16.22	28.4091
September 92	25.8900	30.0584	16.10	28.3910
October 92	25.8900	30.0471	16.06	28.3843
November 92	25.8900	30.0824	16.19	28.4054
December 92	26.1540	30.7005	17.38	28.8819
January 93	26.1986	30.8833	17.88	29.0094
February 93	26.1986	32.6456	24.61	30.0668

6.29 The LERMS as a system in transition performed well in terms of creating the conditions for transferring an augmented volume of foreign exchange transactions on to the market. The stability imparted by it, the significant deceleration in the rate of inflation and a healthy build-up in the level of foreign exchange reserves enabled a smooth change-over to a regime under which the exchange rates were unified (effective March 1, 1993) and the external value of the rupee is determined by market forces. The unification of the dual rate system into a single, floating exchange rate imparted a significant degree of flexibility to the exchange rate regime in balance of payments adjustment.

6.30 The unified exchange rate arrangement operates within the overall framework of exchange control. All foreign exchange transactions are put through ADs who have no obligation to surrender to the Reserve Bank. While foreign exchange transactions are effected at market rates, the Reserve Bank's own rate of exchange reflects market conditions and could move within a margin of 5 per cent on either side of the market rates. It would, at its discretion, buy US dollars spot and sell the currency for approved purposes and as such, Bank is no longer required to necessarily buy or sell foreign exchange; at the present time, however, the Reserve Bank sells foreign exchange for debt service payments of the Government of India and as a transitional arrange-

ment, for the full value of Eximscrips and 40 per cent of the value of other licences issued to exporters. It would also undertake, at its discretion, intervention purchases/sales of foreign currencies in the market. Besides its buying and selling rates for transactions with ADs, the Reserve Bank announces its Reference Rate on a daily basis which is based on noon rates of a few select banks in Bombay. The SDR-Rupee exchange rate and the exchange rate applicable to transactions through Asian Clearing Union are based on this Reference Rate. The Bank also enters into swap transactions in dollars with ADs for periods ranging from 2 to 6 months.

6.31 The experience with the freely floating market-determined exchange rate system has been satisfactory. Contrary to expectations, there has been a remarkable stability in the exchange rate of the rupee. The rupee has, in fact, strengthened on several occasions since the unification of exchange rates on March 1, 1993 (Table 6.5 and Graph 13).

International Economic Developments

6.32 The international economic situation, as reflected in output and trade volume growth, has shown improvement in 1992. World output growth which was less than 1 per cent in 1991 recovered to reach 1.8 per cent in 1992. The recovery was contributed by both the industrial and the developing countries. Growth rate in the industrial countries went up from 0.2 per cent in 1991 to 1.5 per cent in 1992 and in the developing countries (excluding the countries of Central Europe and the former Soviet Union) from 4.2 per cent to 6.1 per cent. The contribution to the developing countries growth came from countries in Asia, Middle East and Europe. The economies of Central Europe and the former Soviet Union, together faced a decline in output for the third successive year, the decline being more severe at 15.5 per cent as compared with 10.1 per cent in 1991.

6.33 World Trade (excluding trade among the states of the former USSR) grew in volume terms by 4.2 per cent in 1992 as against 2.3 per cent in 1991. However, it is widely recognised that the future growth of world trade would depend on the success of the Uruguay Round negotiations.

6.34 Developments in foreign exchange and financial markets have been influenced to a considerable extent by the crisis in the Exchange Rate Mechanism (ERM) of the European Monetary System (EMS) since September 1992. The crisis in the EMS witnessed the suspension from the ERM of two major currencies, viz., Pound Sterling and the Italian Lira. The turmoil resulted in a number of realignments and the floating of three Nordic currencies that were pegged to ECU, giving rise to shifts in currency and capital movements and trade and trade-related flows.

6.35 One of the significant developments of the year relates to the Ninth General Review of Quotas and the Third Amendment to the Articles of Agreement of the IMF which came into effect from November 11, 1992. With this total IMF Quotas increased from SDR 90.1 billion under the Eighth Review to SDR 135.2 billion under the Ninth Review. In view of the subsequent membership in the IMF, total Quotas increased to about SDR 145 billion. India's Quota has increased by 38.4 per cent from SDR 2,207.7 million to SDR 3,055.5 million. The IMF also announced new limits under its access policy which imply an increase in absolute access for India under various facilities of the Fund.

Table 6.5 : FEDAI* (Indicative) Exchange Rates—Weekly Average (March 1992 to June 1993)

			(Rupees per US Dollar)		
Week ended		Rupees/US \$ (average)	Week ended		Rupees/US \$ (average)
1	2	3	4	5	6
1992					
March	6	29,1996	October	30	30,0955
March	13	29,1783	November	6	30,0680
March	20	30,5031	November	13	30,1024
March	27	31,2645	November	20	30,0969
April	3	31,3251	November	27	30,0590
April	10	31,1614	December	4	30,4113
April	17	31,0768	December	11	30,7930
April	24	30,7611	December	18	30,7286
May	1	30,6185	December	25	30,7588
May	8	30,1646	1993		

1	2	3	4	5	6
May 15		30.1963	January 1		30.8072
May 22		30.0617	January 8		30.7901
May 29		30.6775	January 15		30.7626
June 5		30.5022	January 22		30.8139
June 12		30.2587	January 29		31.2650
June 19		30.0239	February 5		31.8733
June 26		29.9792	February 12		32.9878
July 3		30.4159	February 19		32.8364
July 10		30.4110	February 26		32.9244
July 17		30.3472	March 5		31.8706 (31.86)
July 24		30.1708	March 12		31.5610 (31.56)
July 31		30.1097	March 19		31.4634 (31.46)
August 7		30.0327	March 26		31.4482 (31.45)
August 14		30.0417	April 2		31.2257 (31.23)
August 21		30.0580	April 9		31.2256 (31.23)
August 28		30.2231	April 16		31.3211 (31.32)
September 4		30.1092	April 23		31.3195 (31.32)
September 11		30.0436	April 30		31.3687 (31.37)
September 18		30.0571	May 7		31.3190 (31.32)
September 25		30.0454	May 14		31.3034 (31.32)
October 2		30.0312	May 21		31.3209 (31.32)
October 9		30.0098	May 28		31.3382 (31.34)
October 16		30.0264	June 4		31.3714 (31.37)
October 23		30.0364	June 11		31.4209 (31.42)
			June 18		31.4643 (31.56)
			June 25		31.3854 (31.39)

Figures in purchases are RBI Reference Rates.

* Foreign Exchange Dealers Association of India.

6.36 Yet another important development which has an effect on the low income countries is the decision of the IMF made in July 1992 to extend the deadline for commitments of resources under the Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF), by one year to the end of November 1993. The ESAF, it may be recalled, is a concessional facility to assist low-income countries. The decision reflects the growing realisation of the fact that the external environment for the low-income countries continues to remain uncertain. The Fund is currently examining the options and operational modalities of a possible successor to the ESAF which is expected to come into effect after November 1993.

6.37 The formerly centrally planned economies of Central Europe and the former Soviet Union are now in different stages of transition towards becoming market economies. The IMF has set up a new facility, called the Systemic Transformation Facility, to help members respond to systemic disruptions in their economies.

VII. ASSESSMENT AND PROSPECTS

7.1 The important positive features of the economy during 1992-93, the strong growth of agriculture, the moderation in monetary expansion, the marked reduction in the inflation rate and the improvement of the foreign currency assets—are encouraging signs and provide the basis for continuing and intensifying policy efforts aimed at ensuring macro-economic stability and improved efficiency of the system. A number of critical issues have however surfaced in the process of adjustment requiring coherent and strong policy responses.

Agricultural Prospects

7.2 In the recent period the overall growth of the economy has been built around a strong agricultural performance, which still hinges largely on weather conditions. The fall in investment in agriculture during the eighties has affected the longer-term growth of agricultural productivity. In the last two years, however, there has been a growing recognition, which has been well-reflected in the Eighth Five-Year Plan document, that investment in agriculture and other rural development activities together with improvements in

rural infrastructure are crucial for increasing productivity and employment. The draft Agricultural Policy Resolution introduced in the Parliament in early 1993, the Budget for 1993-94, the modifications to the trade policy brought into effect from April 1993 and the increases in procurement prices of foodgrains—all provide measures to enable a strong thrust to agricultural growth. The favourable weather conditions in 1993-94, point to continued agricultural growth. The South-West monsoon during the current year has been favourable and out of the 35 Meteorological sub-divisions, the cumulative rainfall up to August 11, 1993 was normal/excess in 26 sub-divisions as against 25 sub-divisions of the corresponding period of last year. Public sector foodgrains stocks at around 26 million tonnes at the end of June 1993 are well above the norms and with the comfortable supply situation vis-a-vis demand, the system is now in a position to ensure that any supply shocks do not result in a sudden inflationary upsurge.

Industry

7.3 Despite relaxations in import restrictions and credit curbs and lowering of interest rates, the recovery of industrial output during 1992-93 was disappointing, though the growth would have been somewhat higher but for the disturbances in the last quarter of 1992-93. The sluggish industrial growth essentially reflected slack real domestic demand and the less than expected export pick up. It must be recognised that some segments of the industrial sector will, however, face certain problems in the process of transition. The attempt to reduce gross fiscal deficit which implies reduction in Government expenditure would adversely affect the demand for certain goods and these sectors will have to adjust themselves to the change in the demand pattern. The domestic capital goods sector may also come under some pressure, since imports of these goods are placed under OGL and there have been sizeable downward revision in the import tariff on these goods. The extent to which the capital goods sector can adjust itself to the new situation will also depend on the relative rates of tariff on imported raw materials and components and the final goods.

7.4 The encouraging factor in the overall economic scenario with respect to industrial production is the likely positive impact of the improved agricultural output. Rural income

will pick up, thus spurring the domestic final demand for industrial consumption goods. Thus as agricultural sector leads the strengthening of the revival in 1993-94 and with a reorientation in Government's expenditure policies, real gross investment as also real domestic demand should show a considerable rise. Private corporate sector investment in 1993-94 is expected to be higher by about 13.3 per cent in real terms (21.6 per cent in nominal terms). The Union Budget for 1993-94 also announced a step-up in the Central Plan outlays for 1993-94. The increase in Plan outlay of as much as 28 per cent in nominal terms is the highest rate of growth for any one year since the 'eighties. Critical sectors such as energy and rural development have been given special focus in the allocation of outlay. Besides, the rate of inflation which has been contained within single-digit in the last fiscal year and the flexibility with which exchange rate and foreign investment policies are being pursued would improve the competitiveness of Indian exports. The import-intensity of output is expected to be lower as a result of the structural adjustment being undertaken in the economy. The industrial sector spurred thus by both supply and demand factors can, therefore, be expected to record a real growth of around 4.5 per cent in 1993-94. However, industrial growth in 1993-94 will be well below the trend rate in the 'eighties of 8 per cent for the third successive year.

Overall GDP Growth

7.5 The prospects for 1993-94 thus appear distinctly better, with a noticeable improvement in the overall economic situation. With the sustained growth in agriculture and improvement in industry, real GDP growth in 1993-94 would be around 5 per cent.

Saving Rate and Productivity

7.6 Over the decade of the 'eighties, real aggregate investment-GDP ratio was around 21 per cent while the average real growth rate was 5.8 per cent thus yielding an incremental capital-output ratio (ICOR) of 3.6. In the three-year period 1990-91 to 1992-93, the aggregate investment-GDP ratio was about 23 per cent while real growth hovered at only 3.5 per cent, yielding an ICOR of 6.6. While a high ICOR in a single year of low real income growth is understandable, a continuing high incremental capital-output ratio over a number of years is worrisome. This underscores the need for a concrete plan for increasing productivity in the economy. While there is scope for increasing the saving-investment ratio, incentives to improve productivity and efficiency of the system are paramount. The emergence of a more competitive environment in the economy must help in this regard. Another important element that may eventually have an impact on productivity is the moderation of the gross fiscal deficit relative to GDP. This would imply that corporate entities, both in the public and private sectors, would be beneficiaries of the 'crowding in' phenomenon, so long as the effective rates of return on investments, adjusted for risk are perceived to be adequate. This should benefit the corporate sector and help finance its investment plans. Funds flow, however, to individual units will be determined by a unit's competitive efficiency and credibility in the pursuit of its business strategies.

Fiscal Evolution: Issues

7.7 In 1992-93, the improvement in the fiscal position turned out to be somewhat smaller than what was initially planned. As against the budgeted gross fiscal deficit of 5 per cent of GDP, the actual outturn was 5.7 per cent. Although the monetised deficit was lower than envisaged, its containment was only temporary as very short-term Repos operations had only a transient effect on monetary expansion. During the early months of 1993-94, there has been an alarming increase in the Centre's budget deficit which by August 20, 1993, stood at Rs. 21,065 crore. The conventional budget deficit, however, overstates the extent of primary money expansion, since it includes the 91-day auctioned Treasury bills which are predominantly held outside the Reserve Bank and are becoming increasingly a significant proportion of the total 91-day Treasury bills. The net Reserve Bank credit to the Centre which is lower than the conventional budget deficit was nonetheless still high at Rs. 16,245 crore on August 20, 1993. These trends need to be reversed quickly, otherwise there would be

a large monetary expansion which could result in sharp increase in prices and undermine the programme of restoration of stabilisation and consolidation of the structural reform in the financial sector, which has been assiduously pursued during the past two years.

7.8 The fiscal operations of the Centre will have to focus on reductions in non-obligatory revenue expenditures, such as subsidies and administrative services, improvement in non-interest non-tax revenue receipts as well as tax revenue. Besides, the Government would need to improve the share of capital outlay in total expenditure in order to bring about a high growth potential. Credible fiscal actions on the part of the Central Government are vital not only to correct its own deficit but also to set an example to States whose finances are also showing disturbing trends. The revenue accounts of State Governments have been in deficit since 1987-88. It would therefore be necessary for the States to reduce non-plan expenditure particularly on administrative services, enhance non-tax revenue through upward revisions of user charges on social and economic services and ensure the profitable working of the State-level public enterprises.

Reform of the Financial System

7.9. Several measures were taken to bring about a fundamental change in the working of the financial system. Commercial banks particularly, are in the process of undergoing a time-bound structural transformation. The reform programme is primarily designed to make the financial sector more viable, efficient and responsive. The thrust of policy is to improve the operational and allocative efficiency of the financial system as a whole. This is sought to be achieved by correcting many of the external and structural factors affecting its performance. Banks and financial institutions are being encouraged to act as autonomous business units, fully responsible for their performance. The structural reforms in the financial sector focus on easing external constraints, prescribing appropriate prudential norms relating to provisioning against loan losses and capital adequacy, introducing transparency in the accounting and reporting procedures, restructuring and recapitalising banks, and increasing the competitive element of the market through entry of private participants. Legislative changes are also being contemplated to strengthen the legal framework supporting the financial sector.

7.10. A range of important measures have already been taken to introduce greater transparency in the accounts of the commercial banks. This is an essential precondition for increasing their financial strength and overall accountability. The new rules are being applied by banks to their accounts for 1992-93 and these serve to provide a more accurate picture of the financial position of each bank. The norms have been designed to become progressively more stringent over a period of two to three years. While the norms will be applicable from the accounting year ended March 31, 1993, banks have been permitted to make up the required provisions by March 31, 1994. It is expected that for the year ended March 31, 1993, about 13 banks will show an aggregate loss of about Rs. 3,500 crore after making provisions as per the new norms. In addition, they will have to meet the prescribed capital adequacy norms. It is against this background that a scheme of infusing additional capital has been drawn up. Accordingly, the Government has, in the Budget for 1993-94, made provision for subscribing capital amounting to Rs. 5,700 crore to recapitalise the nationalised banks. This amount will be allocated among the banks in such a way as to ensure that all nationalised banks meet the minimum capital-to-risk-assets ratio (CRAR) of 4 per cent as at the end of March 1993 and also maintain their capital unimpaired. The recipient banks will be required to invest the Government's capital subscription in Government bonds. The banks will also have to give specific time-bound commitments, relating to profitability and earnings ratios, loan quality and recoveries, computerisation, customer service, liquidity and investment management, so as to ensure that the recapitalisation and strengthening of banks is carried out on a durable basis. Apart from strengthening the financial position, the cleaned-up balance sheets will enable some banks to approach the capital market for raising additional equity as and when the appropriate legislative changes come into force.

7.11. One of the underlying principles of the risk-weighted approach to the capital adequacy is that institutions with a higher risk profile should maintain higher levels of capital funds. Such an approach which incorporates both off-balance

sheet and on-balance sheet credit risks of a bank in the determination of minimum capital will encourage banks to be more risk sensitive and to structure their balance sheet in a more prudent manner. This will require individual bank management to adopt appropriate risk management strategies particularly with reference to raising of resources as also for deployment of funds in various categories taking into account the risk sensitiveness of different categories of assets and exposures.

7.12. One of the features of the Indian banks over the years has been the low level of profitability. As a result, reserves build-up has been at very low levels and consequently owned funds have had to be strengthened by repeated infusion of additional capital. The Government has contributed Rs. 4,000 crore up to March 31, 1993. This capital infusion programme was more in the nature of a passive covering of losses rather than part of a programme of restoring the viability of public sector banks.

7.13. The recapitalisation scheme now being adopted is only an initial step in making the banking system financially sound and viable. The subscription of additional capital by Govt. in the current financial year is only one part of what will be a medium-term, multi-faceted process for modernisation of the banking system. As accounting standards tighten and the minimum capital-level is raised, the capital shortfall of the nationalised banks as a group will remain significant till 1994-95. In order to reach the minimum capital requirements, banks will need to obtain additional resources from either the Government or the capital markets. The sustained growth in the size of the balance sheet will, however, only be possible on the basis of retained earnings which are a function of the overall earnings. Equality, prospective private investors will look for an assurance that earnings and dividend growth will be sufficiently attractive. Increased profitability, as measured by the new accounting standards, will therefore become imperative. Such increased profitability will involve greater generation of non-fund based income, reduction in costs (particularly, overhead costs), and improvement in loan recovery. The reduction in preemption of funds below-market by Government should allow banks to reduce the margin between their deposit and general lending rates, and increase their competitiveness in lending to prime clients. The non-performing assets (NPA) of public sector banks are at uncomfortably high levels. The NPA which are considered realisable in view of the security held in such advances and/or guarantees, will constitute a fairly sizeable portion of the total non-performing assets. Bank management will, therefore, have to adopt a two-point strategy; first, to make efforts for speedy recovery of such realisable NPAs and secondly, to ensure that incremental NPAs are kept at a reasonably low level. In this context, a new Act for the creation of Special Recovery Tribunals for banks and financial institutions has been passed by the Parliament. The expeditious setting up of such Tribunals should assist banks in speedy recovery of debts due to them.

7.14. Even after the increase in minimum provisions in 1992-93 and 1993-94, the banks will be left with the non-performing assets. As long as these sterile assets remain on the books, it will be difficult for banks to raise their profitability to the desired level. The perceived drawbacks of a centralised nationwide Asset Reconstruction Fund (ARF) in the Indian environment are lack of geographic reach for a new institution in a large country such as India, as well as concerns that releasing commercial banks from their recovery obligations might weaken their resolve to collect from their healthy accounts, and encourage such healthy accounts themselves to go sick. In addition, there is the issue of how to finance the capital shortfall created by writing down an even greater part of the assets portfolio than is required by the minimum provisioning requirements. No single solution can resolve the problem of NPA. Instead, a range of initiatives, taking into account to the circumstances of individual banks is likely to be required.

7.15. While the resource requirements of banks to meet capital adequacy and provisioning for bad debts would be very large, it needs to be stressed that greater transparency by itself in no way results in a deterioration in the solvency of banks; if at all, a sharper focus on these issues would work towards an improvement in the banks' overall position. In other words, the move towards implementing stricter pruden-

tial norms should in no way cause anxiety to depositors as to the safety of their deposits, on the contrary all these measures would protect depositors' interests.

7.16. Banks would also need to strengthen the asset management strategies particularly with reference to credit management and investment management. Appropriate changes in credit appraisal, credit monitoring and policies towards management of risk assets/exposures, in addition to appropriate pricing techniques, will have to be adopted. Strategies will have to be worked out for management of interest rate risk, maturity risk and exchange risk which will assume greater significance in the ensuing period. Liability management will need much greater attention than hitherto. In addition, a closer look will have to be given to the different types of business and services which they undertake, particularly from the point of view of cost-effectiveness, shedding activities which are not profitable. Technological innovations, including extensive use of computer and communication technologies, improved processing of operations, etc., will have to be thought out in order to improve productivity and efficiency. Rationalisation of branch network, including closing down of unremunerative branches, relocation of branches, business mix, will also need greater attention. It is a fact that certain banks do have significantly higher level of staff compared to the volume of business undertaken by them and rationalisation of the staff levels will be a prerequisite for restoration of the viability of such banks.

Setting up of Private Sector Banks

7.17. Guidelines for the entry of private sector banks were set out in January 1993. While the importance and role of public sector banks was recognised, there was also an increasing need to introduce greater competition which could lead to higher productivity and efficiency in the banking system. The guidelines, therefore, aimed at ensuring that the new entrants would be financially viable and technologically strong and that there was no concentration of credit, monopolisation of economic power, crossholding with industrial groups, etc. While a number of proposals have been received it has been found feasible to first decide on applications received from the financial institutions taking into account the past track record of these institutions. 'In principle' approval has been given to three institutions for starting new banking companies, which are expected to be widely held, subject to certain terms and conditions. These banks will set up branches in rural, semi-urban and urban areas, fulfil the requirements for priority sector and meet the capital adequacy of 8 per cent of the risk-weighted assets from the inception.

7.18. Among the other possible entrants, non-bank financial companies are the closest in their operations to banking activity and would have an edge over others in setting up private sector banks. There is, however, a need to evolve well-defined guidelines to establish arms length relationship between the parent and its subsidiary. As this is an emerging area, it is desirable to set out well-accepted ground rules at the outset.

Reform of Non-Bank Financial Companies

7.19. While non-bank financial companies have played an useful role in meeting diverse financial needs, these companies need to undergo a considerable degree of adjustment to integrate into the mainstream of the organised financial system. This will require greater transparency of operations and fuller disclosing. What is required is the formulation of a well-integrated, regulatory framework consisting of (i) an appropriate legal structure to deal specially with property rights, bankruptcy law, disclosure of accounting information, etc., and a mechanism for the enforcement of contractual legal obligations; and (ii) prudential guidelines and a surveillance mechanism which provides a safeguard against a possible systemic crisis.

7.20. The Reserve Bank has accepted, in principle, the recommendations of the Shah Working Group. Some of the recommendations, however, would have to be modified to fit into the overall policy framework, while a few others may require legislative changes. Accordingly, it has been decided to implement the measures in a phased manner so that the companies will have adequate time to comply with the directions at each stage thereby minimising the difficulties in the transition. The recommendations relating to capital adequacy, income recognition and provisioning, are being devised and

would be put in place shortly. At the present time there is excessive categorisation of financial companies with vastly different regulatory framework. The present framework which varies for different groups of financial companies could be purposefully unified into a single effective framework. The role of Self Regulatory Organisations (SROs), as envisaged by the Shah Working Group, is also an idea which should be pursued further. With the hastening of the pace of financial liberalisation, and the further deepening and expansion of the financial market, SROs will have an important role to play to see that individual members observe the guidelines of the regulatory authorities and function on prudential basis. The present regulatory approach is based primarily on limiting the quantum of deposits and determining the terms and conditions of acceptance of deposits. The Shah Working Group has correctly suggested a shift in this regulatory approach from the liability to the asset side. This fits with the standards of capital adequacy being applied to banks and their applicability to non-bank financial companies. In fact, the Shah Working Group recommendation for compulsory credit rating for all registered non-bank financial companies should be considered within a shorter time-frame than envisaged by the Working Group. This would be one of the effective ways of ensuring investor protection. These shifts along with an effective and enforceable set of regulations and supervision should encourage the healthy and orderly growth of non-bank financial companies and also ensure the solvency and safety of the financial system.

7.21. In the recent period the Reserve Bank has introduced certain prudential norms for inter-corporate deposits. The absence of such norms was clearly a serious lacuna as there were systematic problems from companies taking imprudent risks. It is erroneous to argue that because these inter-corporate deposits are placements by corporates, there is no need for the observance of prudential norms. It is precisely the imprudent practices of a few companies that can produce large systemic risks. Besides, the regulation of inter-corporate deposits has been undertaken after a comprehensive survey and only a few companies need to undertake a large adjustment and even here the Reserve Bank is providing for a generous phased programme of adjustment.

7.22. A system of registration by the end of July 1993 has been introduced for all financial companies with net owned funds above Rs. 50 lakh. Satisfactory completion of registration procedures would be of distinct advantage to financial companies while expanding business. It would, therefore, be in the interest of all these companies to expeditiously fulfil the registration requirements.

7.23 At the present time both non-bank financial and non-bank non-financial companies interest rates on deposits are regulated. These interest rates would need to continue to be regulated so long as banks' deposit rates are regulated. Furthermore, until a system of credit rating is made mandatory, these company deposits would need to be administered. To the extent that the deposit rates of companies are administered, it is necessary that the financial and non-financial companies are subject to the same administered interest rate regime.

Rural Credit Delivery System

7.24. Yet another dilemma being faced in policy-making is in respect of the rural credit delivery system. In large parts of the country, co-operative credit institutions have suffered from financial inadequacy and managerial weaknesses. Commercial banks, including regional rural banks, have sustained large financial losses in rural lending, mainly because of large administrative costs, heavy overdues and an interest structure which is not viable. However, given the need for securing an efficient agricultural base, it is essential that the flow of rural credit is maintained at an appropriate level to support productive activity. This is particularly important, as in recent years, the overall growth rate of the economy has been sustained essentially by agricultural growth. The institutional apparatus required to provide such a delivery system would have to be evolved quickly, along with complementary support from legal provisions for loan recoveries. The past losses of banks involved in agricultural and rural lending would have to be taken care of, by strong recapitalisation of the existing institutions and by removing the constraints on their lending policies.

7.25. While agricultural loans are relatively smaller than loans to other sectors, the purveyors of credit and such loans to be unattractive as there is an inadequate margin between the cost of funds and the rate of interest fixed for such lending. As part of the rationalisation of lending rates it has been recognised that there is a need for moving over to a two-slab structure with one rate being freely determined by the market and one concessional rate which could be say 2 to 3 percentage points below the rate charged to prime borrowers. While this may imply some increase in the rate of interest for small loans, what is important is not keeping the interest rate low for small borrowers but the provision of adequate and timely credit to these borrowers, albeit at a slightly higher rate. The essential objective should be to increase the effective flow of credit to the rural sector at a somewhat higher interest rate, as an alternative to the small borrower's large recourse to informal sources at extremely high rates of interest. The interest rates presently prescribed for the co-operative credit structure are quite clearly not viable as the cost of funds is way above the return on funds. One thought has been that, the co-operative credit structure should be totally freed from deposit/lending rate control so that these interest rates could settle at realistic levels.

7.26. In widening the credit delivery system, banks could extend credit to self-help groups, non-Government Organisations (NGOs) and other intermediaries. Such organisations, in turn, could help in identifying and meeting the genuine credit requirements of the rural poor. Attempts at rationalising the system of credit delivery must be supplemented by a revamped system of credit recovery without which the rural credit system cannot be sustained. While improving their recovery mechanisms commercial banks, regional rural banks and co-operatives could consider appointing 'recovery facilitators', drawn locally, to help improve loan collections.

Computerisation and Information Systems in Banks

7.27. There are already some areas of banking in which computerisation has made significant progress. The Subsidiary General Ledger (SGL) system in most major centres of the Reserve Bank has already been placed under computerisation. Almost all the cheque clearing operations at the metropolitan centres are being handled by computers. The BANKNET system of communications has provided a route for sending messages, including fund transfer instructions between places, connected by BANKNET. The network, however, needs further strengthening. India has also joined the group of countries who are members of the international SWIFT network. At the individual office level, commercial banks have been increasingly installing computers for back-office work, accounting and other house-keeping operations, but these actions are confined to a small number of relatively large-sized branches in metropolitan and major urban centres. The progress thus made far falls short of providing the banking industry with the foundation required to fully avail of the benefits of computerisation.

7.28 Computerisation in banks must proceed at a pace adequate enough to improve the existing levels of customer service, decision making, productivity and profitability of banks. Banking industry, therefore, needs to take stock of the situation and evolve a well defined and timebound programme of computerisation. As part of a comprehensive programme of improving efficiency and customer service, 400 branches of public sector banks at the minimum are to be fully computerised over the next two to three years. As the economy is progressively deregulated and the financial sector reform improves the competitiveness of the market place, computerisation would be necessary to ensure optimal planning of resource management. Need for effective market intelligence and modern internal control system, has clearly been brought out by the securities irregularities which revealed large information gaps and lags.

Trading in PSU Bonds

7.29 In the aftermath of the securities irregularities there has been a cessation of secondary market activity in PSU bonds. A point of view has been forcefully expressed that restoration of the Repos facility would provide the impetus for the revival of the secondary market in PSU bonds. The manner in which the placements of public sector bonds were done and the virtual exclusive dependence on rolling over of short-term funds to finance these bonds together with the highly irregular practices that developed inevitably led to the total collapse of the public sector bonds market. It is, therefore, essential that the lessons of this experience are

learnt while attempting to reconstruct a viable and enduring market in PSU bonds. In this context, it would be hazardous to resume Repos in PSU bonds without an adequate clearance and settlement system; a mere collateralised Repos system without a proper recording/payments systems in place could give rise precisely to the kind of problems which resulted in the breakdown of the system. Moreover, once PSU bonds are freely traded on the National Stock Exchange, Repos would be redundant. Apart from ensuring that there are proper clearance and settlement procedures, there is a need to ensure that the initial subscription is accessed over a large number of institutions so as to avoid unhealthy concentration with one or two holders. The PSUs, in turn, need to raise only that amount which would meet their requirements over a 12-24 month period. Thought may also have to be given to shortening the maturity of the bonds. To ensure that there is adequate liquidity for these bonds in the secondary market, market-makers need to be encouraged. While institutions like DFHI and the proposed Securities Trading Corporation of India could possibly develop market making activity, for a market with some depth there is a need for a number of market-makers. The PSUs raising bonds could place at the disposal of the market makers a part of the amount issued, say 10 to 15 per cent to enable the market makers to offer two-way quotes on PSU bonds. While the Nadkarni Committee had recommended the establishment of an Electronic Clearing Settlement and Depository (ECSD) system for secondary market trading in PSU bonds, indications are that such a system of trading would take time to be operational. The Reserve Bank is actively considering the possibility of extending the Subsidiary General Ledger (SGL) system for Government securities to trading in PSU bonds by bulk institutional investors (such as banks, financial institutions, mutual funds etc.) who have SGL facilities. This scheme is expected to be made operational in the ensuing few months. Initially, only the new issues of PSU bonds will be taken into the SGL system. Moreover, efforts are being made to ensure that trade and payment settlements occur simultaneously, in order to eliminate risks to both the sellers and buyers of PSU bonds.

Implications of the Irregularities in the Securities Transactions

7.30 The Janakiraman Committee completed its task of investigating the irregularities in securities operations of banks and financial institutions. The six reports clearly bring out the magnitude of the irregularities, the mechanisms used, the various forms of arrangements between brokers/financial companies and banks (including some of their subsidiaries) and, the manner in which the Reserve Bank guidelines on funds management were grossly violated. While these revelations and subsequent investigations were the single most important development in the financial system in 1992-93, restoring normalcy in the functioning of the money and securities market and building back the overall credibility of the financial system has become the urgent need. The prevailing operating practices, regulatory framework and the market environment have come necessarily under critical review. Significant interlinkages among the various segments of the financial system, including the capital market, have come to light, and there were lessons, both, for individual managements as well as the regulatory authorities.

7.31 The irregularities brought to the fore the need for a strong and an alert system of surveillance. The mechanism of internal control and audit and the system of supervision, despite the best intents, had failed to detect financial operation of a collusive and fraudulent character. Co-ordinated monitoring of the on-going market developments was also found to be weak.

7.32 Questions have been raised about the appropriateness of the prevalent supervisory mechanism. The fact that despite guidelines, bank officials and others extensively violated them indicates that strong deterrent action is required the moment any violation emerges. The need for ensuring strict observance of supervisory guidelines through effective follow up and maintaining high professional standards has become imperative. Considerable attention has come to be focused on the role of regulator, with a strong public expectation that regulators pursue a system that is prompt and efficient and which ensures adherence to guidelines both in letter and spirit. While regulators have to maintain a

general vigil, the irregularities clearly brought out that it is not possible for regulators to completely eliminate violations of a regulations, although a proper framework will act as a powerful deterrent. Fixing of individual responsibility for the irregularities changes effected in the management and the proposed imposition of penalties on the erring institutions should help in bringing about a greater element of accountability in the system.

7.33 The irregularities also brought to the fore the need for legislative changes in order to strengthen the legal framework supporting the financial sector. The intricate system of contractual enforcement impeded efforts to bring about early and satisfactory resolution of disputes relating to the securities irregularities. An explicit legal framework and its enforcement is crucial to the emergence of a system where contractual obligations are honoured. An adequate legal infrastructure is thus acknowledged as an essential element in the proper development of the security market.

7.34 There is a felt need for a quick fraud detection mechanism, accompanied by a machinery for its proper enforcement. In this regard, a study has been conducted of the various institutional arrangements in other countries and their applicability to Indian conditions. A decision on the appropriate mechanism will be taken shortly.

7.35 Emphasis is being given to greater transparency in operations, through the introduction of a rigorous system of income recognition and accounting disclosure norms so as to eliminate concealment and window dressing of transactions. Standards for statutory external audits are also being tightened. System audit and analysis are to be conducted periodically in order to ensure that the business is being transacted as per the rules.

7.36 The Board for Financial Supervision (BFS) being set up by the RBI will develop a single integrated system of supervision so as to avoid segmentation of the supervisory function and the related problems of inadequate co-ordination between different authorities overseeing the financial system. The Board will also help to direct focus on the role of effective supervision as a means of ensuring banks compliance with the regulatory framework.

7.37 Another concern that arose in the context of the irregular securities transactions was the possibility of systemic disturbances in the financial system and the economy as a whole. Proper assessment of counter party risk and a well-functioning debt market have assumed significance. A major challenge which regulation has now to confront is, how to contain systemic risk. Regulatory attention has now been directed to investment operations of banks and the flow of funds, and guidelines have been issued, mandating that banks must have policy and operating guidelines duly approved by their boards. The need to strengthen market intelligence has been recognised and banks have been urged to evolve system which help exercise greater vigil and continuous monitoring critical portfolio operations.

7.38 It is in the interest of all that the uncertainty about the soundness of financial system and the intent to operate an efficient and objective system subserving the underlying social and economic goals of our development efforts, is dispelled. Individual banks need to initiate action even as the efforts of the regulators continue to put in place a more comprehensive supervisory system. Policy must also recognise that the market for funds is integrated and that artificial segmentations may not work.

External Sector Issues

7.39 There was a distinct improvement in the balance of payments during 1992-93 as evident in a sizeable accretion to the foreign exchange reserves for the second successive year. While the current account deficit in 1992-93 did widen in relation to the preceding year, the measures of import restriction which sharply compressed the current account deficit in 1991-92 vitiate any comparison with that year. When seen against 1989-90, the last 'normal' year, the current account deficit in 1992-93 was lower both in absolute terms as well as relative to GDP.

7.40 During 1993-94, the balance of payments situation will remain manageable. During the first quarter of the year, exports recorded a robust growth rate of 28 per cent in US dollar terms. While imports during April-June 1993 have declined by about 3 per cent over those in the first quarter of 1992, import demand is expected to rise as the economy expands. Nevertheless, the current account deficit for the year as a whole is expected to be of the same order as in 1992-93, or even somewhat lower depending on export performance.

7.41 There has been a build-up of foreign exchange assets during the first four months of 1993-94. At the end of July 1993 the foreign currency assets stood at US \$ 6.8 million. There has also occurred a healthy reorganisation of the composition of the foreign currency assets with volatile components such as swaps and deposits under the FCBOB Scheme having declined substantially from their levels at the end of July 1992. These positive developments would considerably strengthen the management of the balance of payments during 1993-94.

7.42 Over the medium-term, export growth of the order of 15 per cent per annum in US dollar terms can bring about a significant narrowing down of the trade deficit. Some improvement in invisible earnings can also be expected to occur, benefiting from the conducive policy environment. As a result, the current account deficit would follow the improvement in the trade balance. However, repayments to the IMF towards draws under the Compensatory and Contingency Financing Facility and the standby Arrangement would be large during 1994-95 to 1996-97 with a peak in 1995-96. Moreover, repayments of India Development Bonds along with compounded interest would occur at one go in 1996-97. The improvement in the current account could thus be more than offset by the debt-servicing requirement. While access to commercial markets could be renewed as international credit ratings improve in response to the strengthening of macro-economic fundamentals, the need for exceptional financing would persist over the medium-term.

7.43 A high export growth can only occur within the framework of a broad based policy framework which generalises the incentive structure, obviates infrastructural constraints and procedural impediments and exposes export industries to the invigorating effects of international competition in terms of technological and quality upgradation. Over the longer period, export incentives would need to move away from direct incentives to those that are conveyed as price signals. Simultaneously, interest rate and tariff reform as well as an active exchange rate policy would be needed to hone the sensitivity of export volumes to price effects. Over the longer run, exports would need to be seen as an expression of rising productivity and comparative advantage of domestic industry rather than being sustained by subsidies.

7.44 Import growth during 1992-93 was moderate at 11.9 per cent. But given the inherent import intensities, the need for a comprehensive programme in respect of bulk imports, such as POL and fertiliser, cannot be over-emphasised. Concerted efforts towards conservation, efficient utilisation and inter-fuel substitution in respect of POL are measures to which increased attention must be paid.

7.45 Invisible payments such as transportation payments, interest, royalties, technical know-how, professional fees, etc., have, in recent years assumed an inflexible character leading to a steady deterioration in the invisibles account. In augmenting earnings from this service sector, there is a need to shift away from labour intensive services to those with greater technological inputs. Services are particularly responsive to price signals and therefore the need for appropriate price-related policies assumes crucial relevance. The unified exchange rate system has helped to accelerate private transfers.

7.46 For a sustainable balance of payments over the medium-term, a restructuring of capital flows would also be crucial. The levels of debt that can be incurred in the years to come would need to be restricted to the quantitative dimensions of a current account balance as defined by the High Level Committee. Productivity in the use of foreign capital would have to be the guiding criterion in the incurring of liabilities.

7.47 The experience of recent years underscores the need to monitor the composition of capital flows besides their absolute quantum. External commercial borrowings, especially publicly guaranteed credits must be limited to levels declined by trade related needs. Besides, due attention would have to be paid to the maturity structure of commercial debt.

7.48 The large reliance on deposits by non-resident Indians (NRIs) has proved perilous, given their volatility and high costs of borrowings, both explicit and implicit. There is now a distinct policy slant towards reducing the volatile component of such borrowings by restructuring the maturities and reducing the costs of borrowing to levels determined by the profile of international interest rates. A 'cafeteria' approach has been adopted where the NRI has the choice of deposit schemes with varying features. It is essential that such a policy approach continues over the medium-term so as to minimise the destabilising effects that were earlier observed. The overall strategy for non-resident deposits should be to ensure that the volatility and costs of these schemes are reduced. The five schemes with varying features on repatriability, exchange risk and reserve requirements and interest rate prescriptions have been prepared with different target groups in mind and some of the new schemes such as Non-Resident (Non-Repatriable) Deposit Scheme has been very successful. It is expected that over the next two to three years a fundamental transformation would be achieved and the excessive reliance on exchange guarantees would be progressively reduced.

7.49 There is also a need to alter the composition of capital inflows in favour of non-debt creating flows, especially direct foreign investment. Foreign investment has had so far a limited role to play in India's industrial strategy and in providing balance of payments support. Direct foreign investment inflow into the country during the 'eighties' have averaged around US \$ 0.16 billion per annum, whereas the annual inflow is about US \$ 2 billion in Thailand, US \$ 1 billion in Indonesia, US \$ 2.7 billion in Malaysia and US \$ 3 billion in China. The relatively meagre inflow of foreign investment is reflection of our earlier policy stance. Certain technologies are closely held and are usually transferred only when accompanied by equity. It is necessary to recognise that foreign investment has several advantages vis-a-vis debt even when not functioning as a vehicle of technology transfer; it provides balance of payments support without adding to debt. As dividend repatriation is linked to performance, foreign investment leads to the upgradation of technology and serves to integrate domestic industry with the global economy. The medium-term BOP adjustment strategy has accordingly focussed on giving an augmented role to foreign investment. Major initiatives were therefore put in place. Amendments to the Foreign Exchange Regulation Act (FERA) have been effected. India has also signed the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) convention to assure protection to foreign investments, and has also expressed its willingness to provide bilateral guarantees in order to instill confidence among foreign investors. An important measure has been the issue of guidelines to Foreign Institutional Investors.

7.50 The lessons emerging out of the severe payments crisis of 1990-91 and 1991-92 and the concerted efforts towards stabilisation that dominated developments during 1992-93 have led to a reformulation of strategies that would secure a viable balance of payments over the medium-term. It is in this context that the High Level Committee on Balance of Payments has considered an atmosphere of liberal trade regime with a self-correcting exchange rate and a gradual movement towards international competitiveness to be the basic medium-term objective. In keeping with this vision of the evolving scenario and in order to allow the country to reap the gains of dynamic competitive efficiency and openness, the Committee sought to free the approach to self-reliance from the confines of the strategy of yesteryears based on static comparative advantage producing imports and insulating the economy from the international order. The medium-term strategy for the balance of payments should be evolved against the backdrop of the High Level Committee's assessment that a current account deficit of the order of 1.6 per cent of GDP could be met with normal capital flows.

Exchange Rate Policy

7.51 In the recent period there has been a fundamental change in the exchange rate policy and to enable an assessment of the policy it is necessary to first set out the essentials of the operation of the new policy. The dual exchange rate system which was in operation until March 2, 1993 worked reasonably well. During the period from July, 1992, the free market rate premium over the official exchange rate remained steady at around 17 per cent with the exception of February, 1993 when it spiked on account of speculative expectations. An analysis of the monthly evolution of the composite rate (average of the official and market exchange rates weighted by 40 per cent and 60 per cent factors) and official exchange rate shows that the premium of the composite rate over the official rate remained more or less unchanged at about 9-10 per cent. With effect from March 2, 1993, the dual exchange rate system was replaced by a unified exchange rate system whereunder the exchange rate came to be fully determined by market forces of relative demand and supply. The Unified Exchange Rate System was introduced to take care of the anomaly arising out of the dual exchange rate system under which exporters and other foreign exchange earners indirectly subsidised certain imports.

7.52 Under the new system, the Reserve Bank has been announcing its buying and selling rates (for transactions with authorised dealers in India) based on the going market rates unlike under the earlier system under which the Reserve Bank fixed its rate first and the market followed it. The Reserve Bank has been authorised to fix its buying and selling rates within 5 per cent of the going market rate, but thus far, the Reserve Bank has not used this flexibility and has generally been fixing the rates close to the going market rate. Since the market rates go on changing throughout the business hours of banks, as the standard exchange rate of the rupee on a day, the Reserve Bank announces what is called a "Reference Rate" in terms of rupees per US dollar (there has been a switch over to a system of direct quotes with effect from August 2, 1993). The reference rate is based on 12 noon rates of a few select banks in Bombay. The SDR rupee rate and rates for exchange for Asian Clearing Union currencies are based on this rate.

7.53 Under the new system, the Reserve Bank's selling rate is not effectively applicable. The Bank has been buying foreign exchange offered by authorised dealers. The Reserve Bank's buying rate is, however, not necessarily attractive as compared with the market buying rate. On days, when there is excess supply of dollars in the market, the market sells the surplus to the Reserve Bank at its buying rate. This can at best be called passive intervention. The Reserve has purchased a net amount of over US \$ 2 billion during the 4-month period, March-July 1993. The Bank's Reference Rate on March 2, 1993 was Rs. 32.06 per US dollar. The average of the Reference Rates on the rupee during the month was Rs. 31.53 per dollar. The rupee has strengthened since then and moved between Rs. 31.20 and Rs. 31.50 per US dollar. The direction of the movement in the exchange rate during 1993-94 critically hinges on the gap in the current account and the availability of finance, both normal and exceptional. International oil prices, domestic and global economic developments have different implications depending upon the degree of synchronization of the cycles. If domestic recovery is more than projected, the imports may surge. But if the domestic recovery synchronises with that in the leading industrial countries, both exports and imports will rise with the possibility of a stable exchange rate well into the next year. Indeed, according to the latest estimates, the USA, Canada and the UK have already emerged out of the trough and are on a growth trajectory. In view of the foregoing, on balance, the rupee would continue to remain stable at the present level during the year.

7.54 The exchange rate policy followed till the introduction of Liberalised Exchange Rate Management System was oriented essentially towards maintenance of competitiveness of India's exports. This was done by the Reserve Bank fixing the nominal exchange rate of the rupee in such a manner that in real terms (i.e., after taking into account the inflation differential between India and its major trading partners), the rupee did not at least appreciate. Under the unified exchange rate system, the rate of exchange is determined by the forces

of demand and supply of (of foreign exchange) in the market. In such a situation, if the rupee strengthens because supply of foreign exchange exceeds demand temporarily, it would be possible for the Reserve Bank to intervene in the market by buying foreign exchange to avoid volatile movements in the value of the rupee. In a contrary situation, however, if the rupee depreciates because of fundamentals, it would not be prudent to defend the value of the rupee by losing reserves. The experience the world over is that it is futile to resist fundamental and enduring changes in the exchange value of a currency. It may, however, be possible to smoothen short-term volatility in the country's foreign exchange market. With trade and exchange control restrictions being reduced almost to the minimum, presently the rupee could be said to be more or less convertible on current account.

7.55 The maintenance of a stable exchange rate over time in India would greatly depend on the achievement of a sustainable balance between exports of goods and services and imports. In this the exchange rate itself will play an equilibrating role. However, there will be an increasing link between exchange rate and the stance of monetary policy and the overall price situation. Maintenance of a reasonably stable exchange rate would call for a stable domestic price situation.

Monetary Policy

7.56 Monetary policy as an arm of economic policy is particularly effective in certain areas. For instance, the lag between the time when action is needed and when action is actually taken is shorter in the case of monetary policy than in the case of fiscal policy as, unlike in the case of fiscal policy, monetary policy changes can be conveniently undertaken at any time during a year. The lag between the change in the variables immediately under the instrument of monetary control, and the impact on real variables such as output and employment is, however, much longer in the case of monetary policy, since it does not directly influence the income and expenditure flows. Monetary policy acts through influencing the cost and availability of credit and money and its effectiveness depends on the institutional framework that is available for transmitting the impulses released by the central bank. In the 'eighties, net Reserve Bank credit to Government had been a major contributor to the expansion in reserve money and monetary policy, therefore, had to address itself to the difficult task of neutralising, to the extent possible, the expansionary impact of deficits after taking into account the short-term movements in its holdings of net foreign exchange assets. The increasing liquidity of the banking sector consequent on large increases in reserve money has had to be continually mopped up. Given the administered interest rate structure, the task of absorbing excess liquidity in the system was undertaken mainly by increasing the cash reserve ratio. With the borrowing requirements of the Government remaining at a high level, the statutory liquidity ratio had also to be progressively increased to meet these requirements.

7.57 Containment of inflationary pressures and supporting productive activities with adequate credit have remained the cornerstone of the Reserve Bank's monetary and credit policies. The Reserve Bank came to bear more than its normal share of responsibility in mid-1990-91 when the balance of payments situation acquired crisis dimension. It had to respond swiftly through monetary and credit policy measures aimed at import compression and demand containment. The stance of monetary policy has, however, undergone some change since then. While keeping in mind the primary of the objective of inflation control, measures have also been introduced to revive industrial and agricultural production. The minimum lending rate which was raised to 20 per cent in October 1991 has been brought down to 16 per cent in four stages. Correspondingly, the maximum deposits rate has been brought down from 13 per cent to 11 per cent. Any adjustment of the lending rate has to be accompanied by a similar change in deposits rate. Otherwise the viability of the banking system will be severely affected. In determining the deposits rate, one has to take into account the perceptions of depositors as well as the returns available on alternative financial assets. Interest rates are, however, kept under continuing review and it is not the intention of policy to keep real lending rates at very high levels over a long period. Interest rate policy must be used as a flexible instrument, raising and lowering interest rates as the circumstances demand.

7.58 Apart from the level of interest rate, which will be determined by the stance of monetary policy, there are certain issues connected with the structure of interest rates. The last few years have seen some important reform's relation to the administered structure of interest rates. These are: (i) considerable rationalisation has been effected in banks' lending rates with a reduction in the number of concessional slabs and enhancement in some of the rates, thereby reducing the element of cross-subsidisation; (ii) the regulated deposits rate structure has been replaced by a single prescription setting a maximum rate for maturities of 46 days and above; (iii) rates of interest on Government securities have been raised while the maturities have been reduced thereby substantially raising the effective rates of interest on comparable maturities; and (iv) for several instruments, such as Certificates of Deposit, the interest rates are freely determined by banks. On the deposits side, there is a need to give depositors a positive real rate of interest and in the absence of adequate rates of return on deposits, funds may move out of the organised financial system into the unorganised system. There is considerable controversy whether the rate of interest is an important variable in determining overall savings. Notwithstanding this debate, there is no doubt that transferable savings are influenced by interest rates. It is, however, the element of cross-subsidisation that keeps the rates of interest for the large borrowers at a relatively high level. The Reserve Bank is actively working towards a two-lab lending rate structure as recommended by the Chakravarty Committee. Banks will inevitably have to learn to live with a more flexible interest rate system. The spread available to banks between cost of funds and return on funds has to be adequate to provide for the cost of mobilising deposits and servicing the deployment of assets. Until reserve requirements are lowered substantially and the element of interest rate concessionality reduced, there would inevitably be a wedge between deposit and lending rates. In this context, the spread of around 3 per cent presently available to banks is reasonable, given that the banking system is characterised by a large number of borrowal and deposit accounts. While there is a link between the lending rate and the deposit rate, it is necessary at the same time to ensure that administrative and other costs are kept to the minimum so that the spread is not widened. Artificially low interest rates on Government securities have become a thing of the past. Interest rates on Government securities are now close to the realm of substitutability: the maximum rate on securities is 3.5 per cent, while the weighted average lending rate on advances is around 15-16 per cent. Given the risk perception, it is conceivable that the banks' choice of asset holdings will be determined not by statutory prescription but by the risk-reward perception on securities and bank lending. Strengthening the efforts aimed at placing the Government's financing needs at market-related rates and development of a secondary market for Government securities remain an integral part of the financial sector reform agenda. The freeing of interest rates, however, is best undertaken in phases. Interest rate is a variable which is significantly influenced by central banking actions. So long as certain rates of interest are administered, it is necessary to ensure that these rates are close to market perceptions.

7.59 The objective of policy, at appropriate points of time in the ensuring period, would be to further reduce the element of prescription of interest rates by the Reserve Bank. Thus, the prescription of a minimum lending rate for categories of advances of over Rs. 2 lakh could be discontinued and banks could fix their own prime rate. Again, the prescription of a ceiling rate of interest on bank deposits could be discontinued and banks could be free to fix their own deposit rates. The need for a signal on interest rates from the Reserve Bank would continue to be a vital aspect of interest rate policy and the Bank could declare one of its interest rates as the reference rate. A convention could develop whereby banks could take cognisance of this reference rate and fix their deposits rate at an appropriate differential below the reference rate while the lending rate could be an appropriate differential above the reference rate. Such a system, once it becomes operative, would transmit influences throughout the organised segments of economic activity.

7.60 As part of the financial sector reforms, a start has been made to reduce reserve requirements. While the Reserve Bank is committed to a reduction in the levels of preemptions

in the form of CRR and SLR, the pace of reduction would depend on the fiscal outcome. While the reduction in the CRR would depend critically upon reduction in the monetised deficit, reduction in the SLR would depend on the reduction in the overall borrowings of the Government and the extent to which Government borrow at market related rate of interest. In effect, as the gross fiscal deficit comes down and as there is a move away from automatic monetisation of the deficit, monetary policy will come into its own. The regulation of money and credit will be determined by the overall perception of the central monetary authority on what the appropriate level of expansion of money and credit should be, depending on how the real factors in the economy are evolving.

7.61 One of the major objectives of the financial sector reform is to reduce the effective tax on the banking system of heavy reserve requirements. Cash reserve requirements have for many years been internationally used as powerful instruments of monetary control and this instrument is seen as a tool for putting an upper limit on monetary expansion. In recent years, in a number of countries, cash reserve requirements have been reduced significantly. In the Indian context, the medium-term plan is to reduce the CRR from an effective ratio of about 16.5 per cent in 1992 to 10 per cent by 1997; however, if the primary money creation is excessive at any time during the adjustment period, the Reserve Bank would not hesitate to deviate temporarily from the medium-term objective and raise the CRR to neutralise excessive primary money creation. While the objectives are quite clear, the time path of the adjustment has to be carefully modulated. To the extent that the Reserve Bank relies on the direct approach of a link between reserves and monetary growth, a decline in reserve requirements would result in an attenuation of monetary control. If loss of monetary control is to be avoided, the Reserve Bank would need to have much greater interest rate manoeuvrability and the security market needs to be sufficiently developed.

7.62 As an integral part of the financial sector it is envisaged that the SLR prescribed for banks will be reduced to 25 per cent over a three-year period ending March 1996. This would imply that the captive market for securities will shrink sharply in the next few years. As part of the adjustment process the Centre has moved over to an auction system with flexible interest rates on securities and in the ensuing period the Centre would need to move fully to market determined rates of interest for raising its borrowing requirement. The states would, however, need more time to move over to market related rates of interest; however, this problem should not inhibit the pace of reform. Consideration could be given to setting up a States Funding Corporation which would raise funds at market related rates of interest and pass on the funds at fixed rates to the States. Before such an institution is set up it would be necessary to examine the full implications of the burden of the subsidy as between the Centre and the States and between States. The modalities of such an arrangement need to be fully worked out between the Centre and the States before it is implemented. Again, with the shortening of the maturity structure of Government borrowing, the repayment schedules can give discomfort and, therefore, the restoration of the erstwhile system of a consolidated sinking fund for redeeming the debt has been long overdue. While there is merit in the move to market determined rates of interest on Government securities, the adjustment can be successful only if the Government's borrowing requirement is moderated. If the borrowing requirement is excessive, under a market determined interest rate system, the rate of interest would move up to such high levels that the entire programme of reform becomes counter productive as there could emerge a vicious spiral of rising interest rates and growing fiscal imbalances. It is, therefore, imperative that the borrowing requirements are kept within reasonable limits.

7.63 A phased programme of reduction of SLR to 25 per cent in three years should be dovetailed into a programme to phase out the automatic monetisation of the budget deficit in a three-year period. Accordingly, the proportion of auctioned bills in the total creation of 91-day Treasury bills should be raised, in a phased manner, so that by 1996-97 the system of ad hoc Treasury bills should be totally discontinued. The Central Government could then be provided

a Ways and Means Advance limit from the Reserve Bank for meeting temporary requirements and the limit could be required to be liquidated by the end of the financial year. Such a reform of the system would establish the independence of monetary policy action.

7.64 Quite often, monetary policy and exchange rate policy are discussed as separate and distinct segments of overall financial policy. These two segments are inevitably intertwined and as a market-based system develops, it would no longer be meaningful to view these as separate segments of policy. If these two segments are not made mutually consistent one or the other segment of policy could be greatly attenuated.

7.65 Since 1992-93 there has been a conscious attempt to reduce the use of instruments of direct monetary control and to give greater attention to the development of indirect instruments of monetary control over the money and securities markets. It is here that there is a need to coordinate monetary and internal public debt management policies so that the two segments are mutually supportive. The Government securities operations are a key element in the evolution of a well-developed system of monetary control. For open market operation to be really effective, it is necessary to have an active secondary market for Government securities. If such a secondary market is to develop, it is essential that there should be investors other than captive investors. It is only when non-captive investors become predominant that the secondary market can develop depth and it is only under these conditions that it is possible to develop a system of primary dealers who would underwrite the entire issue at the auctions and thereafter access these securities to final investors. An important feature of a well developed securities market is that the Reserve Bank should not take up any part of a primary issue of a Government security but it should buy and sell securities as part of its open market operations, depending on its assessment of the liquidity of the system. An active secondary market in securities requires that there must be institutions dedicated to foster the secondary market. The Securities Trading Corporation of India (STCI), which is proposed to be set up in the current financial year, would endeavour to play the role of market maker by providing two-way quotes for securities. The objective of the STCI would not merely be that of a passive repository for these securities but it would actively buy and sell these securities at market prices. The STCI would encourage the turnover of securities, thereby imparting liquidity to these securities. The pace of development a secondary market in securities will depend on interest rates being fully market determined and the emergence of a more efficient clearing and settlement system. At the present time, the auctions of Government securities are of two types: first, where the amount is preannounced and the Reserve Bank participates at the cut-off price and second, where the amount is not preannounced and the Reserve Bank does not participate in the auctions. To move away from this system to a truly market determined system, primary dealers are required to take up the entire issue and they would have an incentive to undertake financial intermediation between the Reserve Bank's intervention rates and the rates in the secondary market. The Reserve Bank proposes to develop an active market in Government securities over a two to three-year period. In this connection, it is necessary to undertake action simultaneously to undertake institutional development, instrument development and an appropriate structure of market determined interest rates on Government securities. Above all, it would be necessary to moderate the Government's borrowing requirements to a level consistent with the size and depth of the Government securities market.

7.66 In the recent period, the inflation rate in India on a year-on-year basis has come down to around 6 per cent as against twice the level a year ago. This decline in the inflation rate is very welcome. There is, however, a need to sound a word of caution. The growth of primary liquidity in the economy in the recent period has been at an unprecedented level and unless the gross fiscal deficit is drastically reduced in the ensuing few months the continuing excess primary liquidity would fuel inflationary pressures later in the year and this could destabilise the reform process. While the Reserve Bank must stand ready to expeditiously reduce excess primary liquidity in the system by using all available instruments of control, fiscal corrective actions are needed to keep the deficit at the targeted levels.

PART TWO—THE WORKING AND OPERATIONS OF THE RESERVE BANK OF INDIA

VIII. INTRODUCTION

8.1 The role of the Reserve Bank during the accounting year 1992-93, was essentially to further reinforce the reform measures in the financial and external sectors. The Bank also took initiatives to support the revival of the economy, keeping in view the prime objective of maintaining price stability. The first Part of this Report has presented in detail the important economic developments and perspectives.

8.2 In the first half of 1992-93, the Janakiraman Committee had submitted its first three reports, and later in the year, the Committee submitted its three subsequent reports and completed its deliberation. In the light of the findings of the Janakiraman Committee and its recommendations, the Bank undertook several corrective measures to restore financial credibility, and to plug existing loopholes and to bring about overall qualitative improvement in the entire financial sector. The Committee recommended that the Reserve Bank should strengthen its market intelligence to supplement its own information. The Reserve Bank has set up recently a Market Intelligence Cell (MIC) within the Bank on overall developments and banking intelligence in the supervisory wing is also being strengthened. The other important step is in respect of mechanisation and computerisation in the entire financial system wherein the Reserve Bank has a major role to play. The Janakiraman Committee had commented that the major lacuna for not detecting sufficiently early the irregularities in securities transactions by banks and financial institutions was the absence of electronic data processing (EDP) system in the operations that deal with recording, clearing, settlement and, finally, payments connected with the related securities. In November 1992, the Bank introduced a system of Electronic Clearance Settlement and Depository (ECS/D) for the purpose. A Group was also set up to guide and coordinate the work of establishing electronic system for clearance and settlement of trading in PSU bonds units by the Stock Holding Corporation of India Limited/UTI. In consultation with the Government of India, it has been decided to constitute an Inter-Disciplinary Group headed by the Reserve Bank (Chairperson: Mr. V. Visvanathan). The Group which will have the representatives of Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate and Income-tax (Investigation) Department as members, will decide on the parameters of coordinated action relating to further investigations regarding tracing of the funds involved in the problem exposure identified by the Janakiraman Committee.

8.3 The year 1992-93 was characterised by a number of changes in the Bank's operations as well as policies. A beginning was made to move from direct to indirect instruments of monetary control with the launching of an active internal debt management policy. For strengthening the internal debt management policies and operations, the Bank created an Internal Debt Management Cell (IDMC) as an Independent unit with effect from October 1, 1992. A decision has been taken to set up a new institution to be called the Securities Trading Corporation of India, dedicated to the development of a secondary market for Government securities. Direct instruments such as, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio have been relaxed and the effective ratios have been brought down mainly with a view to improving the competitive efficiency of the banking system.

8.4 Another important event during the year was the setting up of the Gold Management Division within the Bank essentially to explore the possible use of gold in economic adjustment and growth by mobilising gold from the public and shoring up the international reserves position of the country.

8.5 Two Committees set up by the Bank, viz., on the Structure of Export Credit (Chairman: Dr. G. Sundaram) and the Committee to Examine the Adequacy of Institutional Credit to the Small Scale Industries Sector and Related Aspects (Chairman: Shri P. R. Nayak) submitted their reports and action has already been taken on their recommendations. The Working Group on Financial Companies (Chairman: Dr. A. C. Shah) submitted its report and the action is being taken on the recommendations.

8.6 The Reserve Bank has also set up during the year a few Committees to examine afresh and in a comprehensive manner the present system of credit delivery. Giving due recognition to the difficulties faced by trade and industry in complying with the present norms and procedures relating to working capital finance, a Committee (Chairman: Shri Rashid Jilani) is reviewing the cash credit system of lending while another Committee (Chairman: Shri J. V. Shetty) was set up to relook the extant guidelines on lending under consortium arrangement. The Shetty Committee has since submitted the Report and its recommendations are under examination by the Bank. An In-House Group within the Bank (Chairperson: Ms. J. T. Vaz) has been constituted to examine and recommend the necessity of fixing norms and lending discipline by the Reserve Bank as also the necessity of fixing the extent of bank credit (maximum permissible bank finance).

8.7 As regards computerisation in the banking industry, the guidelines issued by the two Reserve Bank Committees on Computerisation of Banking Industry of 1983 and 1989 have offered a workable framework for a well-defined and time-bound programme on the nature and extent of computerisation. These have been reiterated as banks in India, both in the traditional commercial and co-operative sectors, have to prepare themselves to adopt higher technology in the field of computers and communications with a view to improving the customer service, house-keeping and decision making.

8.8 It was mentioned in the previous year's Report, about setting up of an Internal Task Force to formulate the Bank's corporate plan and that M/s. A. F. Ferguson & Co., an external consultant, was selected in March 1992 to assist the Task Force. The Internal Task Force with the guidance of M/s. A. F. Ferguson & Co. and support of officers and staff of various departments of the Bank undertook a review of the critical functional areas of the Bank and has prepared a Strategic Action Plan (1993-2002). It has suggested, inter alia, restructuring of the Reserve Bank's organisation in the context of the evolving economic policies in general and monetary and credit policies in particular.

IX. DEVELOPMENTS CONCERNING COMMERCIAL BANKS

9.1 Developments in the banking sector during the year 1992-93 have to be viewed in the light of the overall financial sector reforms. Banks are rapidly adapting themselves to functioning in a more competitive environment and preparing to meet new challenges and accept opportunities.

Guidelines for Entry of Private Banks

9.2 As referred to in Section I, the Reserve Bank has formulated guidelines in January 1993 for establishment of new banks in the private sector. The important guidelines in respect of the entry of new banks in the private sector apart from the required minimum paid-up capital of Rs. 100 crore and the prudential norms and the capital adequacy, etc., are: (i) listing of their shares in stock exchanges; (ii) their management set-up, liquidity requirements, etc., to be governed by the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934, and the Banking Regulation Act, 1949, and also the directives, instructions/guidelines and advice given by the Reserve Bank; (iii) observance of directions in regard to priority sector lending with modification allowed in the composition of such lending for an initial period of three years; (iv) voting rights of an individual share holder shall be governed by the ceiling of one per cent of total voting rights as stipulated by the Banking Regulation Act, 1949 (exemption, however, may be granted under Section 53 of the said Act, to public financial institutions); (v) the new bank shall not be allowed to set up a subsidiary or mutual fund for at least three years after its establishment; and (vi) the bank is to make use of modern infrastructural facilities to provide good customer service as also institute a high powered customer grievances cell to handle customer complaints.

Branch Expansion of Commercial Banks

9.3 In April 1992, the branch licensing policy of commercial banks was liberalised. In October 1992, the policy was further liberalised. Banks were given authority to shift offices and spin-off business, etc. Banks are now permitted

to shift their existing branches within the same locality, open specialised branches, such as, industrial finance/SSI/NRI/Treasury branches, open extension counters, provide safe deposit lockers at these counters, and convert the existing rural branches into satellite offices if the existing branches are found non-viable after complying with certain minimum formalities. Moreover, banks have been given freedom to spin-off business of a branch, such as, Government business, to provide better customer service. Besides, future branch expansion and licensing in rural and semi-urban centres would depend upon proposals of the concerned State Governments, while Working Groups at the regions have identified unbanked/underbanked localities in urban, port town and metropolitan centres with future potential for new branches.

Inspection of Banks

9.4 Inspection of banks by the Reserve Bank has assumed a critical role in the light of the large scale irregularities of banks in the securities transactions. The Working Group (Chairman: Shri S. Padmanabhan) which looked into the scope and content of the present system of Reserve Bank's inspection of commercial banks has suggested a new system of inspection and supervision in the light of the changing environment. The Reserve Bank accepted the recommendations of the Group. Under the new system, on-site supervisory process of the Reserve Bank will comprise: (i) Annual Financial Inspection (AFI), (ii) Audit of select items by statutory auditors, (iii) Management Audit to be conducted by the Reserve Bank's senior and experienced executives once in two years, (iv) Scrutiny of social lending, developmental aspects, etc., by the Reserve Bank's staff, independent of the main inspection, i.e., AFI, and (v) Special Inspections and investigations as and when needed. The salient feature of the main inspection, i.e., the Annual Financial Inspection would be an examination of the aspects crucial to a bank's financial soundness and methods of operations. The scheme is applicable to all scheduled commercial banks including those of private sector and foreign banks. It has been decided to assign to the statutory auditors specific areas in some select banks for examination during the current year after completion of balance sheet audit work. The Bank during the financial year 1992-93 conducted Annual Financial Inspections in respect of 27 public sector banks and 13 Local Head Offices of State Bank of India. In respect of financial inspections, the Bank inspected nine each of the private sector banks and foreign banks; during the first three months of the financial year 1993-94, financial inspections were completed in three private sector and two foreign banks.

9.5 The Reserve Bank addressed the issue of large arrears in reconciliation of inter-branch accounts in banks, in the light of the recommendations of the Working Group set up by the Bank in March 1992. Accordingly, the Bank in April 1993, has advised the banks to adjust all large value items within a period of two months, bring about computerisation in central and local main offices, decentralise the clearing process and reconcile entries at monthly intervals. Time bound targets have been set for clearing all these arrears by March 31, 1994, whereby from 1993-94 onwards banks would not be allowed to keep entries unadjusted for more than six months.

9.6 To expedite decision making in respect of disposal of cases involving writing-off of bad debts/losses and compromise proposals, and also to assist banks in identification of loss items and in complying with the Reserve Bank's instructions in respect of prudential norms, the Reserve Bank has permitted the Boards of Directors of individual banks to delegate suitable powers for write-off of bad debts/losses and to approve compromise proposals to various functionaries subject to such safeguards/conditions and reporting as the Boards may prescribe.

9.7 The Reserve Bank has decided to implement the bulk of the recommendations made by the Committee on Frauds and Malpractices in Banks (Chairman: Shri A. Ghosh). The recommendations, inter alia, exhort all banks to review their instruction manuals based on the observations made in the Report, and evolve adequate systems and procedures to strengthen internal control, monitoring and vigilance mechanism, particularly in the area of preventive vigilance with a view to ensuring strict compliance of the various systems. An informal group of bankers and auditor professionals has also been set up by the Bank for setting out the modalities

of the system of concurrent audit to cover major portion of the business operations of banks designed to ensure the prevention of irregularities in securities transactions.

Moratorium, Amalgamation and Liquidation

9.8 In February 1993, the Grand Court of Cayman Islands approved the terms and conditions of sale of the business of the Bombay Branch of the Bank of Credit and Commerce International (Overseas) [BCCI(O)] Ltd. to the State Bank of India (SBI). The SBI offered to purchase the business of the Bombay branch for a consideration of Rs. 40 crore. As per the offer, the business of BCCI (O) Ltd., Bombay, is to be acquired by SBI Commercial International Bank Ltd. (SBICI), a wholly-owned subsidiary of SBI to be constituted for the purpose. In the event of the subsidiary not coming up for any reasons, the business will be acquired by SBI itself. The Reserve Bank has considered the offer and filed an application in the High Court of Bombay for approval of this proposal. The sale has since been approved by the Court at its final hearing on August 3, 1993.

9.9 Three banks had indicated their intention to take over certain assets and staff of the Bank of Karad Ltd. The Reserve Bank's petition for winding up the bank is receiving the attention of the Bombay High Court.

9.10 As on March 31, 1990, nine banks had unsatisfactory financial position, of which, one bank, viz., Purbanchal Bank Ltd., was amalgamated with a public sector bank, viz., Central Bank of India on August 29, 1990. Three banks viz., Karnataka Bank Ltd., Bank of Madura Ltd., and Sangli Bank Ltd., were found to have improved their position on the basis of their inspections conducted by the Reserve Bank during 1991, as there was no erosion in their deposits, i.e., the realisable value of their assets was adequate to pay deposit liabilities. However, there was erosion in their provisions, part of reserves (Karnataka Bank Ltd.) and provisions, reserves and part of paid-up capital (Sangli Bank Ltd., and Bank of Madura Ltd.). The remaining five banks, viz., Benares State Bank Ltd., Kashi Nath Seth Bank Ltd., Punjab Co-operative Bank Ltd., Lord Krishna Bank Ltd., and Dhana-lakshmi Bank Ltd., continued to have unsatisfactory financial position, as per the inspections carried out by the Reserve Bank on various dates during 1991. There was erosion in these banks' provisions, reserves, paid-up capital and part of deposits. Their working is being watched by Reserve Bank through directions issued to them, periodical statements obtained from them and through Bank's nominee directors. These banks have been inspected again during the last quarter of 1992 and the inspection reports in respect of six banks have been finalised. While Kashi Nath Seth Bank Ltd., Punjab Co-operative Bank Ltd., and Lord Krishna Bank Ltd., continued to have unsatisfactory financial position, that of Bank of Madura Ltd., Karnataka Bank Ltd., and Sangli Bank Ltd., have improved and shown satisfactory financial positions. The inspection reports of two banks, viz., Benares State Bank Ltd., and Dhana-lakshmi Bank Ltd., are in the process of finalisation.

Advances against the Security of Gold Bonds, 1998 and 10 per cent Relief Bonds, 1993

9.11 Consequent upon launching of the Gold Bonds Scheme 1993, from March 15, 1993, and introduction of 10 per cent Relief Bonds 1993 by the Government of India, all commercial banks have been permitted to grant advances against the security of the above mentioned bonds on the basis of the terms and conditions stipulated by the Reserve Bank for the purpose.

Industrial Credit

9.12 A number of changes have been effected in the Credit Monitoring Arrangement (CMA) with the objective of imparting more flexibility to banks in meeting the demand of industrial credit expeditiously. Thus, commercial banks were permitted to deviate from the norms for inventory and receivables for assessing the maximum permissible bank finance. The Reserve Bank also raised the cut-off limit for reporting sanction of industrial credit for post sanction scrutiny under the CMA.

Committee/Working Group Relating to Industrial Credit

9.13 In accordance with the demand made by trade and industry and keeping in view the changes to be made in the banking sector policies in line with the process of liberalisation of the economy, the Reserve Bank decided to examine the whole gamut of industrial credit policy as also guidelines, norms, etc., for delivery of credit by the banking system. First, at the instance of the Reserve Bank, the Indian Banks' Association constituted a Committee (Chairman: Shri Rashid Jilani) to review the present cash credit system of lending followed by banks in extending working capital facilities and to recommend modifications, if necessary, including introduction of any new system of lending. Second, another Committee was constituted to review the extant guidelines on lending under consortium arrangement (Chairman: Shri J. V. Shetty). The Committee has submitted its Report on August 21, 1993, and its recommendations are under examination. Finally, an In-House Group (Chairperson: Ms. I. T. Vaz) was set up to review the role of the Reserve Bank in laying down norms, guidelines, etc., for lending by commercial banks for working capital purposes.

9.14 The Committee on the Structure of Export Credit (Chairman: Dr. G. Sundaram) was set up by the Reserve Bank in September 1992 to look into the structure of export credit. The committee looked into complaints regarding interest rate structure on report finance taking into account the cost of funds and incidence of cost of interest on pricing of exported goods. Since the submission of the report, the interest rates on export credit were lowered by one percentage point across the board with effect from March 1, 1993, and the tax on interest in case of export credit was withdrawn. Furthermore, as recommended by the Committee, it was decided to introduce a scheme of rediscounting of export bills abroad.

State Level Export Promotion Committee

9.15 With a view to sort out expeditiously the infrastructural and operational problems with the help and cooperation of the State Governments and other organisations and offices, it has been decided to set up a State Level Export Promotion Committee (SLEPC) which will exclusively deal with all matters relating to exports. The lead bank of the State shall be the convenor of the meetings and members among others include officials of State Governments, the Reserve Bank local Chambers of Commerce, Export Associations, Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Customs, Exim Bank and FEDAI (Local), etc. The SLEPC will closely monitor the growth of export in the State. The Committee shall sort out the operational problems relating to export credit, exchange control regulations, insurance, etc. It shall also discuss and consider the problems of exporters relating to infrastructural facilities such as availability of power, transport, etc., and shall generally co-ordinate the efforts of export promotion in the State. The committee will meet at half-yearly intervals.

Sick Industrial Undertakings

9.16 Growing industrial sickness has become a major problem for the banking system. The Reserve Bank has continued to lay emphasis on a systematic approach to the formulation of workable rehabilitation packages in respect of those units which have the potential of being commercially viable. As a follow-up, the Bank has been monitoring the performance of each bank by way of scrutiny of periodical returns from the banks. From March 1993, submission of performance reports by banks has been made half-yearly instead of quarterly to coincide with the statistical returns on sick/weak industrial units for the relative half-year.

9.17 An In-house Group held discussions with select banks and financial institutions to evolve measures for minimising sickness. To study the problems of sick/weak leather units and suggest measures, a Committee has been set up in December 1992 (Chairman: Shri N. G. Balasubramanian).

9.18 The latest data at the end of March 1992 on SSI sick units place the number of such units substantially higher at 2,45,575 units. The number of SSI units added to the sick list was 24,103 during the year ending March 1992 and the outstanding scheduled commercial banks' credit against

the SSI sick units as a whole was Rs. 3,101 crore. Of the sick SSI units viability studies in respect of 2,42,546 units were completed and 19,210 units were considered viable, of which 13,289 units were put under nursing programme. Non-SSI sick units increased by 75 to 1,536 and the amount of bank credit outstanding increased to Rs. 5,787 crore from Rs. 5,106 crore in the previous year. Of the non-SSI sick units, viability studies in respect of 1,301 units were completed and 577 units were considered viable, of which 401 units were put under nursing programme.

9.19 The non-SSI weak units declined by 63 units bringing down the number to 813 with an outstanding bank credit at Rs. 2,646 crore. Out of these, viability studies in respect of 623 units were completed and 361 units were considered viable. Of the units considered potentially viable, 218 units were put under nursing programme by banks.

Reserve Bank's Assistance to Financial Institutions

9.20 During 1992-93, the Reserve Bank did not extend any assistance to financial institutions out of its Statutory Funds. The only support given was the sanction of Rs. 155 crore to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) at an interest rate of 8 per cent per annum for 15 years out of the repayment by Industrial Development Bank of India (IDBI) to the National Industrial Credit (Long-Term) Operations Fund. Besides, a special refinance facility of Rs. 400 crore was sanctioned to IDBI to stimulate investment in capital and intermediate goods industries at an interest rate of 14 per cent per annum repayable in ten half-yearly equal instalments. However, for 1993-94, the Bank has contributed Rs. one crore to the National Industrial Credit (LTO) Fund, the details of which are given in Section XV.

9.21 The quarterly information system introduced in respect of 11 major all-India financial institutions was made more comprehensive and the data are analysed from the point of view of policy making. It is felt necessary to bring about better coordination between banks and financial institutions. Overall policy measures introduced by the Reserve Bank having relevance to the operations of the financial institutions are immediately brought to their notice for action wherever necessary. The recent instructions which were intimated to the financial institutions for taking appropriate action relate to (i) discounting/re-discounting bills by banks, (ii) portfolio management on behalf of clients and (iii) fixation of aggregate upper contract limit for business to be transacted through approved brokers. Following the recommendations of the Committee on Trading in Public Sector Bonds and Units of Mutual Funds (Chairman: Shri S. S. Nadkarni), an important recommendation on which action has already been initiated relates to the setting up of a system of Electronic Clearance Settlements and Depository (ECSD) and a Working Group chaired by Shri W. S. Saraf is working out the modalities of operationalising such a facility.

Housing Finance

9.22 Scheduled commercial banks were advised to continue computing their respective shares of housing finance allocation at 1.5 per cent of their incremental deposits accrued in the preceding year. Considering the larger accrual of aggregate deposits with the banks during 1991-92, the overall housing finance target on this basis worked out higher at Rs. 569 crore as against the overall quantum of Rs. 365 crore earmarked during 1990-91. Bank have been permitted to exceed their housing finance target if their resource position is found to be comfortable. Restrictions imposed during 1991-92 on real estate loans do not apply to the extent such credit is included in the definition of housing finance for purposes of the target.

9.23 The paid-up capital of the National Housing Bank (NHB), which is fully subscribed by the Reserve Bank, remained unaltered at Rs. 250 crore. As mentioned in the previous report, no allocation was made to NHB by the Reserve Bank out of its National Housing Credit (LTO) Fund during 1992-93. In 1993-94, the Bank has allocated Rs. one crore to the Fund reference to which has been made later in Section XV.

Service Area Approach

9.24 On a review of the working of the Service Area Approach (SAA), certain deficiencies in its implementation were observed, such as, failure (i) to update village profiles, (ii) to prepare credit plans in a realistic manner on the basis of potential reflected in the village profiles, and (iii) of conscious efforts on the part of branch managers to achieve the stipulated targets. The Reserve Bank issued fresh guidelines in November 1992 to all commercial banks to rectify the deficiencies/loopholes in the implementation of the SAA.

Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990

9.25 According to the provisional data, debt relief to the extent of Rs. 7,829 crore has been provided under the Scheme, of which public sector commercial banks provided Rs. 2,334 crore, regional rural banks Rs. 795 crore, and co-operatives Rs. 4,200 crore. The Government of India had released Rs. 1,500 crore, Rs. 1,425 crore and Rs. 1,500 crore out of its budgetary allocation, respectively, in the last three years ended March 1993. A further sum of Rs. 80 crore has been released out of the 1993-94 allocation of Rs. 500 crore for meeting the claims of implementing agencies. The amount utilised was of the order of Rs. 2,158.04 crore by public sector commercial banks, Rs. 672 crore by regional rural banks (RRBs) and Rs. 1,674.16 crore by co-operatives. The Reserve Bank has also provided loans of Rs. 1,674.16 crore through NABARD to State Governments for meeting their share of 50 per cent in implementation of the Scheme for borrowers of co-operatives.

Exemption of RRBs from Sub Sections 1 and 1(a), of Section 42 of RBI Act, 1934

9.26 The Reserve Bank exempted all RRBs from the proviso to Sub-Section 1 and Sub-Section 1(A) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, for a further period of two years up to December 31, 1994, which, in other words, would mean that the cash reserves to be maintained by RRBs will continue to be three per cent of their demand and time liabilities. The major considerations for exemption are that most of the RRBs are weak and have been incurring losses and they are extending credit to the target group comprising weaker section though they have recently been permitted to deploy 40 per cent of their incremental advances to non-target group as well. The question of restructuring of RRBs is under active consideration of both the Government of India and the Reserve Bank.

Committee on Customer Service in Banks

8.27 Ensuring qualitative customer services in banks assumes considerable importance at this point of time when banking sector reforms have to be a part of the overall financial sector reforms. After examination of the recommendations of the Committee on Customer Service in Banks, the Bank initiated speedy action and issued guidelines to the banks, relating to (i) advancing of working hours, (ii) extension of business hours, (iii) introduction of bank orders in various denominations, (iv) acceptance of small denomination notes, (v) exchange of mutilated and soiled notes, (vi) publication of the full text of interest rate directives or of amendments thereto in the news papers, (vii) immediate credit of local cheques up to Rs. 5,000 and (viii) payment of interest at enhanced rate on delayed collection of outstation instruments and at minimum lending rate when the proceeds of instruments are to be credited to Cash Credit, Overdraft or Loan account with a view to compensating such customers equitably.

Committee to Examine the Adequacy of Institutional Credit to the Small-Scale Industries Sector and Related Aspects

9.28 The Committee on Small Scale Industrial (SSI) Units (Chairman: Shri P. R. Nayak), in its report submitted in September 1992, has observed that the SSI sector as a whole received a level of working capital which was only 8.1 per cent of its output, and the village industries and the smaller tiny industries among them could get working capital finance to the extent of only about 2.7 per cent of their output. The Committee, therefore, suggested that small units with credit limits of not more than rupees one lakh should have the first claim on the priority sector credit to SSI. The Reserve Bank, on the basis of the Committee's recommen-

dations, introduced, in its monetary policy for the first half of 1992-93, a special package for SSI sector and the salient features are as follows :

- (a) The banks should step up the credit flow to meet the legitimate requirements of the SSI sector in full during the Eighth Five-Year Plan. For this purpose, the banks should draw annual credit budgets on bottom up basis and should reflect consolidated position of the budgets prepared by each bank at the branch level in consultation with the SSI units and also taking into account other relevant factors.
- (b) Working capital limits up to Rs. 50 lakh computed on the basis of a minimum of 20 per cent of their projected annual turnover would be provided for new as well as existing limits.
- (c) To arrest the problem of sickness in the SSI sector, the definition of a sick SSI unit was modified so that potentially viable SSI units could be helped in their rehabilitation efforts at an early stage.
- (d) Banks should set up an institutional frame-work for redressal of grievances of SSI units. An 'Ombudsman' type of authority may be set up for this purpose.

9.29 Action has already been initiated on these recommendations as set out in Section I of the Report.

X. CO-OPERATIVE BANKS

Licensing of New Urban Co-operative Banks

10.1 The recommendations of the Committee on Licensing of New Urban Co-operative Banks (Chairman: Shri S. S. Marathe), were set out in the previous year's Annual Report. The Reserve Bank has since accepted the recommendations of the Committee with certain modifications. Fresh entry point and viability norms have accordingly been stipulated. The thrust of the new policy is towards a need based and healthy growth of such banks. The revised viability norms will have to be attained within a time-frame of three years. However, certain relaxations have been made in the entry point norms for new urban co-operative banks in the least developed, tribal and desert areas and less developed States as also for banks organised by women and scheduled castes/scheduled tribes. Banks operating in metropolitan/urban/semi-urban centres will be allowed to extend their area of operation to the respective peripheral rural areas for the purpose of meeting the non-agricultural financial needs of their members. Norms for issue of licenses to the existing unlicensed urban co-operative banks have also been relaxed and those for inclusion of urban banks in the second schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, are proposed to be revised.

10.2 Weak and non-viable banks would be sought to be weeded out by merger/amalgamation with stronger units and/or liquidation. State Governments have been advised to initiate measures in co-ordination with the Reserve Bank in this regard. State Governments are also being advised to promote appropriate amendments to State Co-operative Societies' Law to impart true democracy and autonomy in the functioning of the co-operatives alongside self-regulation and responsible action. Suitable legislative amendments to the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies), would be suggested to facilitate merger/amalgamation of weak urban banks.

Branch Licensing Programme

10.3 Under the Branch Expansion Programme for the urban co-operative banks covering the three-year period 1991-94, permission for opening of branches is being issued to those licensed banks which meet the following requirements: (i) the banks are financially viable, (ii) the banks have deployed the stipulated level of credit to priority sector, (iii) the banks have overdue within the prescribed limit, (iv) the banks have submitted proper compliance to the findings of the inspection reports, and (v) violations of directives, which are pointed

out are duly complied. Accordingly, during the Branch Plan Period 1991-94, of the proposals from 660 urban co-operative banks, those of 363 banks have been approved and these banks have been allotted 446 centres by the Reserve Bank for opening of branches, as at end-June 1993.

10.4 On June 9, 1993, the Reserve Bank introduced relaxations in the existing guidelines regarding the opening of extension counters, shifting of offices and closure of branches. The decisions in regard to opening of extension counters, shifting of offices and splitting of branches, however, should be approved by Boards of Directors of respective banks under intimation to the Reserve Bank, obtaining post facto approval within one month of their implementation.

Rehabilitation of Weak Primary Urban Co-operative Banks

10.5 As on March 31, 1993, there were 211 non-viable/weak banks and also those which had failed to comply with the minimum capital requirements. Action has been initiated to set right the deterioration in their financial position/operational deficiencies.

10.6 The Reserve Bank issued directions to four primary urban co-operative banks under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies), placing restrictions, among others, on the maximum amounts of withdrawal of deposits, on the grant/renewals of loans and advances and incurring expenditure beyond specified amounts. Besides, show cause notices were issued to two banks for unsatisfactory working to the detriment of the interest of the depositors under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and for cancellation of license to carry on banking business in India. In respect of six urban co-operative banks, the Managements, i.e., the Boards of Directors, have been superseded. On the recommendation of the Reserve Bank, six banks were placed under order of moratorium by the Government of India during the year 1992-93, and all these banks were amalgamated/cleared for amalgamation with other strong units.

Reforms in the Co-operative Sector

10.7 Apart from prescribing entry point, viability norms and the guidelines relating to their operations, the Reserve Bank also placed on urban co-operative banks stipulations in respect of income recognition, classification of assets and provisioning on the lines stipulated for scheduled commercial banks, with suitable modifications which may be implemented in a phased manner over a period of three years commencing with the accounting year beginning April 1, 1992. Accordingly, the Reserve Bank issued detailed guidelines on February 9, 1993, advising all primary co-operative banks to ensure that necessary provisions against substandard assets, doubtful assets and loss assets, are reflected in their profit and loss accounts and balance sheets from the accounting year ending March 31, 1993.

Refinance to Urban Co-operative Banks

10.8 The Reserve Bank continued to extend refinance facilities to eligible urban co-operative banks in respect of their advances to small and tiny industrial units at the Bank Rate. During the financial year 1992-93, 20 primary co-operative banks were sanctioned credit limits aggregating Rs. 10.64 crore. The outstanding amount against these limits stood at Rs. 7.19 crore as on March 31, 1993.

Co-operative Development Fund

10.9 To help improve the management systems and skills in co-operative banks, as contemplated in the Union Budget 1993-94, a Co-operative Development Fund under the aegis of NABARD has been set up with an initial corpus of Rs. 10 crore.

Computerisation in Urban Co-operative Banks

10.10 While accepting the recommendation made in the Marathe Committee Report with regard to computerisation in urban co-operative banks, the Reserve Bank, on June 24,

1993, advised all urban co-operative banks, particularly those having working capital of Rs. 5 crore and above, to take appropriate measures for computerisation of their operations so as to render better customer services, enhance profitability and improve their overall efficiency.

Advances against Security of Gold Bonds, 1998 and 10 per cent Relief Bonds, 1993

10.11 The Reserve Bank, on June 2, 1993, permitted urban co-operative banks to sanction advances against the security of Gold Bonds, 1998, and 10 per cent Relief Bonds, 1993. While the interest rate on such advances would depend on the directives on advances issued by the Reserve Bank from time to time, the banks should also satisfy themselves about the genuineness of the credit needs of the borrower and proper end use of the funds lent.

Exemption of SCBs from Sub-Sections 1 and 1A of Section 42 of the RBI Act, 1934

10.12 The Reserve Bank has exempted all scheduled state co-operative banks (SCBs) from the provisions of the proviso to sub-sections 1 and 1A of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, for a further period of two years up to December 31, 1994. Accordingly, cash reserves to be maintained by such banks will continue to be 3.0 per cent of their demand and time liabilities.

XI. DEPOSIT ACCEPTANCE BY NON-BANKING FINANCIAL AND NON-FINANCIAL COMPANIES

Working Group on Financial Companies

11.1 The Narasimham Committee had recognised that non-banking financial companies would necessarily have to be integrated within the mainstream of the overall financial sector reform. The Committee observed that prudential norms and guidelines in respect of conduct of business should also be laid down for these companies and a system of off-site supervision based on periodic returns should be instituted within the purview of the agency which is proposed to be set up to supervise the entire financial system. In order to prepare a programme of reform for the financial companies, the Reserve Bank constituted a Working Group in May 1992 under the Chairmanship of Dr. A. C. Shah and the Group submitted its report in September 1992. The Working Group has provided a comprehensive framework of reform of the financial companies and has sought to strengthen the companies by laying down prudential norms. The major recommendations of the Group are set out below:

- (i) Categoricwise classification of financial companies may be abolished and uniform regulations may be applied to all financial companies.
- (ii) Regulatory attention by the Reserve Bank may be confined to companies with net owned funds of Rs. 50 lakh and above.
- (iii) As regards new financial companies, entry norms, viz., minimum net owned funds of Rs. 50 lakh and a cooling period before accepting deposits, have been proposed by the Group.
- (iv) The regulations should be on the asset side, such as, limit on credit concentration, prohibiting investments in undesirable activities, etc.
- (v) Capital adequacy standards may be laid down based on risk assessment of assets and credit conversion factors for off-balance sheet items.
- (vi) The 'exempted' category of deposits should be removed and all deposits should be brought under regulatory framework. A clear distinction should be made between deposits and borrowings from banks/institutions.
- (vii) Non-banking financial companies may be allowed to accept deposits for a period ranging between 12

months and 84 months. Furthermore, so long as interest rates on bank deposits are regulated, interest rates on deposits accepted by non-banking financial companies should be 2 or 3 percentage points more than those offered by commercial banks.

(viii) Prudential norms for income recognition, transparency of accounts and provisions for bad and doubtful debts, may be prescribed.

11.2 There are also a few other recommendations, such as, formation of a self-regulating organisation, compulsory credit rating after five years, initiating public awareness programme for educating the depositors, etc.

11.3 The Reserve Bank has, in principle, accepted the recommendations of the Shah Working Group with some modifications. As the reform process is likely to require adjustment by the financial companies, the measures were proposed for implementation in a phased manner. Accordingly, the Bank introduced a number of changes in the Directions with effect from April 12, 1993, the main gist of which is set out below.

11.4 As part of the measures in the first phase, the Bank made certain changes in the Directions issued to the non-banking financial companies in April 1993 and amended thereafter in May 1993. The duration of deposits of all non-banking financial companies (NBFCs) has been uniformly stipulated at a minimum of 12 months and a maximum of 84 months; this has implied that the maximum for residuary non-banking companies has been reduced from 120 months to 84 months while the minimum for all other financial companies has been reduced from 'over 24 months' to 12 months. The rules regarding premature deposits has been revised in tune with the bringing down of the minimum period of deposits. Thus, this brings into alignment the maturity range of deposits of different types of companies. Inter-corporate deposits/borrowings, monies received from directors and shareholders of private limited companies and monies raised through issue of debentures or bonds secured by mortgage of immovable property, which were hitherto in the exempted category of deposits, have been brought under the purview of the Bank's Directions. However, inter-corporate deposits accepted by the financial companies up to a period of 12 months to the extent of two times their net owned funds will not be subjected to the stipulations regarding interest rate and minimum period. Hire purchase finance and equipment leasing companies will be required to maintain liquid assets at 10 per cent of deposits. Loan and investment companies, in respect of which no liquid assets requirements were stipulated earlier, will be required to maintain liquid assets to the extent of 5 per cent of their deposits. Half of the liquid assets, i.e., 5 per cent of the deposits in the case of equipment leasing and hire purchase finance companies and 2.5 per cent of the deposits in the case of loan and investment companies are required to be maintained in the form of Government securities and/or Government guaranteed bonds. The residuary non-banking companies will also have to maintain a minimum investment in Government securities and/or Government guaranteed bonds to the extent of 10 per cent of their deposit liabilities, within the limit of 70 per cent investment in approved securities. The non-banking financial companies and residuary non-banking companies which have not attained the prescribed liquidity ratios have been allowed time up to the end of March 1994 to attain these stipulations. All financial companies including residuary non-banking companies which have net owned funds of Rs. 50 lakh and over, have been required to register themselves with the Reserve Bank. The registration would, in due course, be vital for companies expanding their operations.

11.5 The other recommendations of the Working Group will be implemented in a phased manner, and legislative changes as required will be suggested to the Government.

Directions Issued to Residuary Non-Banking Companies

11.6 Residuary non-banking companies, which generally accept deposits under certain schemes, are governed by a set of Directions known as Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987. As most of the residuary non-banking companies do not have adequate net owned

funds (vis-a-vis the quantum of their deposits), unlike the Directions issued to financial and miscellaneous non-banking companies, these Directions stipulate that at least 10 per cent of their deposit liabilities should be kept in fixed deposits with public sector banks and another 70 per cent of the deposit liabilities should be held in the form of approved securities. The constitutional validity of these Directions had been challenged by some of the residuary non-banking companies. Some of these companies also were not showing their entire liability to the depositors and were transferring a portion of the deposits to their profit and loss account for the purpose of meeting their revenue expenditure. The Supreme Court in its judgment dated January 30, 1992, upheld the validity of the Directions. The Court also ruled that the residuary non-banking companies cannot use any portion of the deposits for meeting their working capital expenses. Even after this judgment, it was found that some companies have started the practice of collecting substantial amounts from their depositors in the name of processing/maintenance charges. The Bank has amended the Directions issued to the residuary non-banking companies prohibiting these companies from collecting such charges. One of the companies has challenged these amendments and the matter is presently being heard in the Calcutta High Court.

Chit Funds Act, 1982

11.7 As mentioned in the previous Report, the Act has so far been brought into force in 19 States/Union Territories. The other States and Union Territories are being urged to frame rules for bringing the provisions of the Act into force. Here again, the validity of the Chit Funds Act was challenged in different courts and the Supreme Court; the case was heard in the Supreme Court in November 1992 and the Court has, in its judgement dated July 13, 1993, upheld the validity of the Act in its entirety.

Acceptance of Deposits by Unincorporated Bodies

11.8 The number of States/Union Territories which had issued notifications authorising suitable officers to take action against unincorporated bodies as envisaged in Sections 45F and 58E of the Reserve Bank of India Act, 1934, remained unaltered at 30. The total number of unincorporated bodies which had to pay fines was six; one case has been quashed by the concerned High Court.

11.9 The constitutional validity of the stipulations regarding the ceiling on the number of deposit accounts to be accepted by individuals, firms and other unincorporated bodies as governed by Chapter III-C of the Reserve Bank of India Act, 1934, was challenged, but the Supreme Court, in its judgment dated February 5, 1993, has upheld the constitutional validity of Chapter III-C of the Act.

XII. DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION AND REFORM OF THE INSURANCE SECTOR

12.1 A substantial enhancement of the insurance cover per depositor in an insured bank from Rs. 30,000 in vogue since July 1980 to Rs. one lakh effective May 1, 1993, was the significant development of the year under review. This was in response to the demands for increasing the then existing insurance cover and the need for maintaining the confidence of the public in the banking system in the context of prudential norms that are being put in place. The rate of insurance premium has been raised from 4 paise to 5 paise per annum per Rs. 100 with effect from July 1, 1993. The total number of insured banks stood at 1,931 as on March 31, 1993, consisting of 80 commercial banks, 196 regional rural banks and 1,655 co-operative banks. As against the insurance premium of Rs. 105.97 crore received during the year ended March 1993, the Corporation paid Rs. 38.99 crore towards settlement of claims/as 'on account' payment in respect of one commercial bank and two co-operative banks.

12.2 As indicated in the previous year's Report, the Corporation terminated three out of its guarantee six credit schemes with effect from April 1, 1992, as there were nil/negligible guaranteed advances, persistent defaults in payment of guarantee fees by participating institutions, etc. Thus, only

three schemes are in operation, viz., Small Loans Guarantee Scheme, 1971, Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981. The priority sector advances guaranteed under these three schemes amounted to Rs. 43,605.50 crore as on March 31, 1992. During the current year, the guarantee claims receipt at Rs. 1,143.27 crore far outstripped the guarantee fee receipt at Rs. 702.78 crore thereby leaving a shortfall of the order of Rs. 440.49 crore. The guarantee fee receipts fell short of the guarantee claims receipts for the third consecutive year. Since this had been adversely affecting the operational viability of the existing guarantee schemes, the Corporation had to enhance the guarantee fee rate for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 from 1.5 per cent to 2.5 per cent per annum with effect from April 1, 1993. The rate for the two other schemes however, has been left unchanged at 1.5 per cent per annum.

12.3 As discussed earlier, a number of initiatives in the area of financial sector reforms covering the banking sector and the capital market have been taken, aiming at creating a more efficient and competitive financial system moulded for the economy consistent with ongoing structural changes. Insurance is an important segment of the overall financial system and it has been felt necessary to address the need for similar reforms in this sector. The Government has, therefore, appointed a 'Committee on Reforms in the Insurance Sector' (Chairman: Shri R. N. Malhotra) on April 2, 1993, to go into these issues in-depth and make suitable recommendations with the following terms of reference.

- (i) To examine the structure of the insurance industry as it has evolved within the existing framework and to assess its strengths and weaknesses in terms of the objective of creating an efficient and viable insurance industry providing a wide reach of insurance services and a variety of insurance products with a high quality of service to the public and serving as an effective instrument for mobilisation of financial resources for development.
- (ii) To make recommendations for changes in the structure of the insurance industry, as well as the general framework of policy keeping in mind the structural changes currently underway in other parts of the financial system and in the economy.
- (iii) To make specific suggestions regarding Life Insurance Corporation of India and General Insurance Corporation of India, which would help to improve the functioning of these organisations in the changing economic environment and to make recommendations for strengthening and modernising the regulatory system in tune with changing requirements.
- (iv) To review and make recommendations on the role and functioning of surveyors, intermediaries and other ancillaries of the insurance sector.
- (v) To make recommendations of such other matters as the Committee consider relevant for the health and long-term development of the insurance sector or which are consequential on other recommendations made by the Committee, including changes in legislation where necessary.

12.4 The Committee is expected to submit its report within six months.

XIII. EXCHANGE MANAGEMENT AND EXCHANGE CONTROL

13.1 During 1992-93, there were two major developments of importance in the area of exchange management and control. First, the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 was amended, initially through an Ordinance promulgated in January 1993 which was subsequently repealed and replaced by the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act of 1993 on April 2, 1993. The Amendment Act, however, is deemed to have come into force from the date on which the Ordinance was issued, viz., January 8, 1993. Second,

a market-based unified exchange rate system was introduced with effect from March 1, 1993, which has been dealt with in detail in Part I of the Report.

Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act of 1993

13.2 Mention was made in the previous year's Report about the Government's intention to undertake a comprehensive review of the Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1973 to simplify and remove regulations hindering free flow of foreign capital into India as also investments by Indian companies in joint ventures overseas. Accordingly, comprehensive amendments have been effected to the FERA 1973, under the following broad categories:

- (i) Amendments were made to some of the provisions governing the operations of 'FERA companies' in India, with the result the restrictions placed on these companies under FERA, 1973 have been removed. FERA companies thus have been placed on par with domestic companies that do not have any foreign equity participation or have foreign equity participation up to a level of 40 per cent and do not attract the restrictive provisions of FERA, 1973.
- (ii) A number of provisions imposing restrictions which were considered repugnant in the context of the move towards convertibility of the rupee were amended or deleted. The deletions, of the provision relating to payment of hotel bills in India by foreigners compulsorily in foreign currency, the provision backing the restrictions on payment in rupee for travel to/from India on behalf of non-residents are some of the important developments in this regard.
- (iii) Certain provisions relating to the enforcement of the Act were amended with a view to preventing harassment of persons suspected of having committed violations of the provisions of the Act.
- (iv) Two new provisions, viz., Sections 18A and 73A, were introduced with a view to providing better regulation of export of goods on lease or hire and ensuring better compliance, by authorised dealers (ADs), in the matter of submission of returns to the Reserve Bank and in the matter of compliance with directions issued by the Reserve Bank, respectively. The latter Section empowered the Reserve Bank to impose penalty on ADs without prejudice to the powers and jurisdiction of the Enforcement Directorate.

Simplification of Procedures under FERA

13.3 Yet another important step facilitating the amendments was the simplification of procedures and documentation and delegation of greater authority to ADs in several areas of remittances such as, (i) surplus collections of foreign airline companies operating in India, (ii) remuneration payable to foreign technicians engaged by Indian companies, (iii) advance remittances for import of goods, and (iv) remittances for various sundry purposes like advertisements, membership fees, examination fees, and legal expenses. The regulations relating to the provision of forward exchange cover by ADs were further liberalised and ADs have been empowered to provide forward exchange cover to foreign investors for their direct investments in Indian companies, in respect of dividends due to them on their shareholdings and to residents in respect of balances held in bank accounts, with ADs in India, denominated in foreign currencies. Remittances of dividend to the foreign investors in respect of their shareholdings in FERA companies, which earlier required authorisation of the Reserve Bank, are now permitted to be effected directly by the ADs.

13.4 The regulations relating to travel abroad for business visit including travel abroad of delegations sponsored by trade bodies such as, Associated Chambers of Commerce and Industry of India, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, etc., for participation in conferences/seminars, undertaking study tour, training higher studies and

for the purpose of medical treatment were further liberalised and the procedure and documentation were simultaneously simplified. ADs have been empowered to deal with all these applications directly, without seeking the approval of the Reserve Bank.

General Permission in Select Areas

13.5 Reserve Bank has granted general permission to NRIs/overseas corporate bodies (OCBs) to make investment in India on non-repatriation basis subject to certain considerably liberalised conditions. In order to reduce specific reference to the Control in respect of matters relating to the liberalisation of the opening and maintenance of ordinary non-resident rupee accounts (NRO accounts) with banks in India, these accounts have also been permitted in the names of all non-residents (and not merely NRIs). The regulations relating to these accounts have been greatly simplified, eliminating totally the process of references to the Control. The earlier guidelines for opening branch offices in India by foreign companies have been substantially liberalised, along with widening of areas of operation.

13.6 Government has granted general permission to residents to hold foreign currency/currencies up to a total value equivalent of US dollar 500 for numismatic purposes.

Exemption from Declaration/Surrender of Foreign Currency Assets by Returning Indians

13.7 Indian nationals and foreign nationals of Indian origin were required to declare to the Reserve Bank all their foreign currency assets, acquired while they were non-residents, on their return to the country permanently. They were also required to close down their bank accounts abroad and were permitted to hold other forms of foreign currency assets only with the permission of the Reserve Bank subject to its terms and conditions. Where such persons desired to continue to maintain foreign currency accounts abroad, had to obtain permission from the Bank. Non-residents with a minimum stay abroad for a period of one year have now been exempted from declaring their foreign currency assets to the Reserve Bank even after their return to the country permanently and have been permitted to utilise them without any restrictions. The facility includes switching of their foreign investments, investing abroad of the income earned on their legitimately acquired foreign assets. As an incentive, such persons bringing their foreign currency funds into the country have also been permitted to maintain foreign currency accounts with banks in India (Resident Foreign Currency Accounts), and utilise the funds in such accounts freely without any exchange control restrictions.

Liberalised Baggage Rules

13.8 The Government has reduced the rate of customs duty applicable to 35 specified baggage items from 255 per cent prevailing earlier to 150 per cent ad valorem. There is no prescribed condition relating to minimum stay abroad for available the concessional rates and the total value of goods which will be eligible for these rates has been fixed at Rs. 1.50 lakh.

Developments in the Domestic Foreign Exchange Market

13.9 There have also been a number of developments in the domestic foreign exchange market. As already mentioned, the regulations relating to the provision of forward exchange cover by ADs have been relaxed. They are now permitted, (i) to provide forward cover for all genuine transactions; (ii) to provide cover for longer periods, i.e., even beyond 180 days, on outright basis without going in for periodic rollovers after obtaining Reserve Bank's approval; (iii) to undertake fully covered swaps in any convertible currency, against one of the FCNR currencies, with NRI depositors; and (iv) to do such swaps between two FCNR currencies.

13.10 In order to ease the pressure on the rupee, banks have been advised that the overnight oversold position in the Rupee should not exceed US \$ one million or its equivalent as at the close of business each day. For the purpose of

this limit, however, customer purchases and foreign currency purchases for vostro funding are excluded.

Foreign Investment

13.11 During the year, foreign investment proposals in high priority areas were freed of non-tariff restrictions embodied in export obligations to balance dividend repatriation (except for 22 consumer goods industries). Keeping in view the ever-expanding frontiers of global technological progress in the field of computers, an Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Scheme was introduced which provides for 100 per cent foreign equity participation, duty-free import of capital goods and a five-year tax holiday relating to corporate and income tax. One hundred per cent foreign equity participation in power generation was also permitted. Indian firms/companies are now free to engage the services of foreign technicians without seeking permission of the Reserve Bank provided, the terms of their engagement conform to certain specific guidelines. ADs are now permitted to offer forward cover to their resident corporate clients in respect of amount of dividend due to their overseas investors on account of direct foreign investment in India, subject to certain conditions. Reservations for the public sector in the area of mining and mineral extraction were done away with. The new National Mineral Policy envisages foreign equity participation up to 50 per cent in Indian companies engaged in mining activities and even beyond in the case of non-captive mines, on a case-by-case basis.

13.12 The foreign collaborations approved during the second year of the post-liberalisation period especially those approved by Reserve Bank and the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) registered manifold increases. Such approvals by all the institutions increased to 1,520 in 1992 from 950 in 1991. Of these, the break-up of the total number of foreign collaborations approvals involving foreign equity are: Reserve Bank (251 for foreign equity worth Rs. 7.8 billion); Secretariat for Industrial Approvals (243 for foreign equity worth Rs. 4.2 billion) and FIPB (198 for foreign equity worth Rs. 26.9 billion). During 1993 (up to end-June 1993), total number of foreign collaborations approved by all agencies referred to above stood at 673, of which 333 foreign collaborations involved foreign investment worth Rs. 39.5 billion.

13.13 To attract substantial foreign investment and also to guarantee protection and repatriability thereof, the Government of India signed the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) convention. The Government has indicated willingness to enter into bilateral negotiations on this issue.

Guidelines for Investments in Primary and Secondary Markets for Foreign Institutional Investors

13.14 As part of the ongoing process of developing a market-friendly environment for foreign investment, guidelines have been set out for foreign institutional investors (FIIs), i.e. pension funds, mutual funds, asset management companies, investment trusts, nominee companies and corporate or institutional portfolio managers. The main guidelines are the following: FIIs have been allowed to invest in all the securities traded in the primary and secondary markets. FIIs would be required to obtain an initial registration with SEBI before any investment is made by them in the securities of companies listed on the Stock Exchanges in India which are defined to include the OTC Exchange of India. Since there are foreign exchange controls in force, FIIs along with their application for initial registration with SEBI file another application addressed to Reserve Bank for seeking various permissions under FERA in a specified format. Reserve Bank's general permission would be obtained by SEBI before granting initial registration, both under a single window. FIIs seeking initial registration with SEBI shall be required to hold a registration from the Securities and Exchange Commission or the regulatory organisation for the stock market in the country of domicile/incorporation of the FII. SEBI's initial registration would be valid for five years and could be renewed.

13.15 The general permission from Reserve Bank, as per the guidelines, would enable the FII to (i) open foreign

currency denominated accounts in a designated bank; (ii) open a special non-resident rupee account to which would be credited all receipts; (iii) transfer sums from the foreign currency accounts to the rupee account and vice versa; (iv) make investments in the securities in India out of the balances in the rupee account; (v) transfer repatriable (after tax) proceeds from the rupee account to the foreign currency account; (vi) repatriate the capital, capital gains, dividends, interest income, etc., and (vii) register FIIs' holdings without any further clearance under FERA.

13.16 The guidelines also state that there would be no restriction on the volume of investment for the purpose of entry of FIIs in the primary/secondary market. Also, there would be no lock-in period prescribed for the purposes of such investments made by FIIs. Portfolio investments of FIIs in primary or secondary markets will, however, be subject to a ceiling of 24 per cent of issued share capital for the total holdings of all registered FIIs, in any one company. The holding of a single FII in any company would also be subject to a ceiling of 5 per cent of total issued capital, and for this purpose, the holdings of an FII group will be counted as holdings of a single FII.

13.17 According to the guidelines; disinvestment will be allowed only through stock exchanges in India. All secondary market operations of FIIs would be conducted only through the recognised intermediaries on the Indian Stock Exchanges. A registered FII can appoint as custodian an agency approved by SEBI to act as a custodian of securities and for confirmation of transactions in securities, settlement of purchase and sale and for information reporting.

13.18 FIIs have to pay at present a concessional tax rate of 10 per cent on long-term (more than one year) capital gains and 30 per cent on short-term capital gains. A tax rate of 20 per cent on dividend and interest income also compares well with similar tax rates in other countries.

Introduction of Stock invest Facility in Primary Capital Market for NRIs/OCBs

13.19 Stock invest facility has hitherto been provided by ADs to residents. ADs have now been allowed to issue Stock invest with certain conditions to non-residents of Indian nationality/origin and overseas corporate bodies predominantly owned by such persons. NRIs and OCBs could thus avail of the facility to apply for shares/debentures with repatriation benefits.

Investments Abroad by Authorised Dealers

13.20 It was mentioned in the previous year's Report that ADs were permitted to maintain a few new foreign currency/external deposits such as, Exchange Earners Foreign Currency (EEFC) Resident Foreign Currency (RFC) Accounts and that they were allowed to maintain such accounts in foreign currencies and manage the foreign currency funds with prudential norms. However, they were not permitted to invest the foreign currency balances abroad. The Reserve Bank has since permitted the ADs with effect from August 16, 1993 to invest their funds held in all foreign currency accounts in their books, in treasury bills and with banks abroad rated for short-term obligations as A1+ by Standard and Poor or P1 by Moody's. They have also been allowed to lend the foreign currency amounts standing in their EEFC and RFC accounts to residents towards their genuine foreign exchange requirements as in the case of funds mobilised under FCNR (Bank) Scheme. However, the ADs have been advised to ensure that the maturities of such deposits and placements are taken into account alongwith the maturities of foreign exchange transactions for computing gaps and that the aggregate gap limits are not exceeded. They have to ensure that investments are made in such a manner that the deposit liabilities are promptly met on maturity/demand. The details of investment in treasury bills and deposits placed abroad as well as the total balances held by customers in their foreign currency accounts are required to be reported periodically.

Foreign Exchange Rate Quotations—Switchgear to Direct Quotation System

13.21 Reserve Bank and ADs have for been using the indirect quotation system for their sale/purchase transactions in foreign exchange. In exercise of the powers conferred by Section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934, Government vide their Order F. No. 4(4) FEB-1193 dated May 28, 1993, have decided to switchover to direct system of quotation of exchange rates. Accordingly, with effect from August 2, 1993, the Reserve Bank expresses its exchange rates in terms of rupees per US dollar instead of US dollar per rupees 100. Simultaneously, the inter-bank and merchant quotations of the ADs are also changed to direct quotation system.

General Permission to Include a Non-Resident Holder

13.22 With a view to simplifying the procedural formalities, general permission has been granted by the Reserve Bank to Indian companies to enter in its register/books overseas address of holder of any securities consequent on his becoming a non resident, provided the holder will not seek repatriation of income/dividend or sale proceeds of the securities.

13.23 NRIs can now convert their shareholdings into joint holding by adding therein the names of another NRI or resident Indian and add the names of NRIs in securities held by them without Reserve Bank's approval. General permission has also been granted for transfer of shares by NRIs to their close relatives in India subject to certain conditions.

Extension of Facility to Open NRE/FCNR Account

13.24 In view of the recent relaxations brought about in the policies relating to exchange control and with a view to attracting more foreign investments to the country, it has been decided to extend the facility of opening NRE/FCNR accounts as well as making investments in shares and debentures of Indian companies under various investment schemes, available to NRIs, to the foreign born spouses of NRIs. Accordingly, a spouse (not being a national of Pakistan and Bangladesh) of a citizen of India or of a person of Indian origin will henceforth be deemed to be person of Indian origin.

Export and Import of Indian Currency

13.25 It has been decided that any resident in India can take outside India (other than to Nepal) and bring back into India, Indian currency up to an amount not exceeding Rs. 1,000 as against the earlier limit of Rs. 250.

Investment by Non residents of Indian Nationality/Origin in Housing and Real Estate Development

13.26 (i) With a view to further encouraging NRI investment, it has been decided to allow existing or new private or public limited companies engaged or proposing to engage in development of plots and construction of residential and commercial premises including business centres and offices, development of townships, urban infrastructural facilities, manufacturing of building materials, etc., to issue equity shares and convertible debentures to non-resident of Indian nationality/origin up to 100 per cent of the new issue with repatriation benefits. OCBs are, however, not eligible for this facility.

(ii) Persons of Indian nationality/origin who were permitted to acquire residential properties only on non-repatriation basis are now allowed repatriation of original investment in equivalent foreign exchange in residential properties subject to a maximum of two houses provided the properties have been purchased on or after May 26, 1993, and the properties are not transferred or disposed of by way of sale for a period of three years from the date of purchase.

(iii) General permission has been granted to foreign citizens of Indian origin, whether resident in India or not, and non-resident Indians to acquire by way of purchase, inheritance

and transfer or dispose of by sale of commercial immovable property in India. Repatriation of original investment in equivalent foreign exchange is also allowed subject to certain conditions.

(iv) General permission has also been granted under Section 31(1) of FERA, 1973 to foreign citizens of Indian origin, whether resident in India or not, to acquire, transfer or dispose of residential properties (upto 2 houses) situated in India by way of gift from or to a relative who may be an Indian citizen or a person of Indian origin whether resident in India or not subject to the condition that gift tax, if any, will be paid. The above general permission, however, is not available for acquisition of agricultural land/farm house/plantation property situate in India.

Silver Imports

13.27 The Government of India notified on February 8, 1993, a scheme to allow import of silver into the country on the lines similar to that of gold imports. The NRIs and Returnee Indian (after a stay of six months abroad) were allowed to bring in 100 kilograms of silver as personal baggage after paying, in foreign currency, a duty of Rs 500 per kilogram.

XIV. ORGANISATIONAL MATTERS OF THE BANK

Currency Chests

14.1 The number of currency chests functioning in the country at the end of June 1993 stood at 4,016. The number of currency chests with State Bank of India and its Associates increased by 26 to 2,837. With 24 more currency chests, the number of chests with nationalised bank rose to 715. The chests maintained by treasuries and sub-treasuries were 436 and those with the Reserve Bank and the Jammu and Kashmir Bank Ltd. remained unchanged at 17 and 5, respectively. It was mentioned in the previous year's Report that two private sector banks have already established currency chests and with an addition of four more chests, six chests with the private sector banks have started operating during they year 1992-93. Four hundred and ninety four repositories maintained by the public sector banks were also functioning along with these chests.

Currency Management

14.2 There was a marginal improvement in the availability of fresh notes from the existing note printing presses at Nasik and Dewas. The banks had to salvage maximum number of reissuable notes and effect diversion from surplus chests. Measures such as, further coinisation of lower denomination notes of Rupee one, Rupees two, and Rupees five, creation of additional capacities in the presses and introduction of a new family of notes of reduced sizes in the denomination of Rupees ten and above would augment the availability of fresh notes. The two new note press projects at Mysore and Salboni are getting into the finishing stages in respect of civil construction for the first line of production.

Gold Management Division

14.3 The role that gold played in the management of external payments crisis in early 1991 has underscored the need to mobilise domestic gold for external adjustment as well as to evolve policies that improve the availability of gold within the country through legal channels. It is in this context measures such as, the liberalisation of gold and silver imports and issues like market regulation, augmentation of assaying and refining capacity in the country, and orientation of jewellery exports to international markets need to be viewed. In response to the considerations underlying the importance of gold in Indian economy and possibilities of utilising it for external adjustment, the Gold Management Division has been formed in the Department of External Investments and Operations. The Division would, (i) keep track of the developments in the local and international bullion markets by collecting relevant data; (ii) examine the policy and developmental issues relating to bullion market in India and to make suitable recommendations; and (iii) devise schemes for mobilising idle gold from the public.

Internal Debt Management Cell

14.4 As monetary policy has to adapt itself to the evolving economic environment by exercising influence on economic activity through indirect methods, the need for strengthening internal debt management policies and operations has become imminent. It is in response to this need, that the Internal Debt Management Cell (IDMC) was constituted as an independent unit in the Reserve Bank with effect from October 1, 1992. Its main objectives are: (i) to evolve appropriate policies relating to internal debt management as a part of the overall monetary policy and, in pursuance of this, to manage internal debt operations such as, open market operations, market borrowings, Ways and Means advances to State Governments and other related matters; and (ii) promote an active and efficient Government securities market.

14.5 As part of a move towards an active internal debt management policy, in 1992-93, the Central Government as part of its market borrowing raised resources through auctions of dated securities and 91 and 364-day Treasury bills. As mentioned in Section I, in a move towards developing an institution dedicated to developing the secondary market in Government securities and public sector bonds, it has been decided to set up a Securities Trading Corporation of India.

Market Intelligence Cell

14.6 The Janakiraman Committee on irregularities in Government securities' transactions recommended that the Bank should strengthen its market intelligence organisation so that early action can be initiated whenever warranted. Pursuance to its recommendations, a Market Intelligence Cell (MIC) has been set up in the Bank. The main objective of MIC is to keep itself abreast of market developments. MIC will gather information on areas of concern to the Bank. This unit will be in addition to the banking intelligence which would be handled by the Department of Banking Operations and Development.

Surveys Conducted by the Reserve Bank

14.7 As referred to in the previous Report, the Survey of Foreign Currency (Non-Resident) and Non-Resident (External) Rupee Accounts was repeated for the period July 1988 to June 1991, whereby based on 453 sample branches, the estimates have been generated. The results are expected to be released shortly. The Reserve Bank also launched in July 1992, the Census of India's Foreign Liabilities and Assets with March 31, 1992, as the reference date. The Census covered official sector comprising the Government of India and the Reserve Bank and non-official sector including private corporate enterprises including public sector undertakings, banks and insurance companies.

Progress of Computerisation

14.8 Use of computers and communication technology will have a major role to play in bringing about efficiency in customer services and operations and enhancing the profitability and viability of the banking industry. Significant progress has already been achieved in computerisation of certain areas of banking.

14.9 In respect of Reserve Bank, the Internal Accounting and Currency Chest Accounting Modules were computerised already in the Issue Department at eight centres. As regards computerisation of payroll module, apart from five centres already operationalised, at other offices it is at various stages of operationalising. The pilot project for development of legal software on mini-computers installed in the Legal Department has been completed. Personal computers (PCs) have been installed in the Regional Offices of Department of Economic Analysis and Policy at New Delhi, Calcutta, Jaipur, Ahmedabad and Madras, Regional Offices of Department of Banking Operations and Development at New Delhi, Calcutta, Madras, Thiruvananthapuram, Bangalore, Hyderabad and Bombay, Department of Financial Companies (Central Office Cell), Bombay and Press Relations Division, Bombay. Besides, three personal computers have been provided to Top Management of the Bank. Two personal computers are being linked to the mini-computer in Issue Department, New Delhi for payroll processing. ALPMs (with LAN) have been installed in Madras, Bombay, New Delhi and Hyderabad offices.

Software is ported and training has been imparted. Test/parallel runs have started. The application has since gone live at Madras. ALPMs (with LAN) will be soon operational in the Deposit Accounts Department, Bangalore. Computerisation of SGL transactions has been made operational in Bombay and the SGL transactions including interest calculation for both Central and State Government loans at Bombay, Madras, Calcutta, New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Kanpur. Software packages have been developed and made operational for processing of auctions of 91-day Treasury bills and open market operations of Internal Debt Management Cell. A software package is being developed for processing transactions in the Dealing Room of Department of External Investments and Operations. The replacement of the present Cii-Honeywell Bull Mainframe Computer System in the Department of Statistical Analysis and Computer Services by a State-of-the-Art Computer System is expected to be completed by March 31, 1994.

Computerisation of Cheque Clearance

14.10 As cheque clearing is a critical activity, the Bank has been taking vigorous steps in the recent years to bring it increasingly under computerisation. The MICR clearing has already been in operation at all the four metropolitan centres since 1989. At seven other clearing houses managed by the Bank, the settlement work has been computerised. Settlement operations at Baroda and Pune clearing houses, which are managed by the State Bank of India, have also been computerised.

14.11 For speedy collection of outstation cheques from specified centres, the Reserve Bank has interconnected the four metropolitan cities of Bombay, Calcutta, Delhi and Madras in two-way clearing. It has also connected four more centres, viz., Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Nagpur to the four metropolitan centres for one-way clearing. The concept of Regional Grid clearing, whereby commercially important centres in the region are connected to the nearest metropolitan centre in one-way clearing is being implemented in a phased manner. Kanpur has been connected to New Delhi and Thiruvananthapuram to Bombay and Madras. Baroda has been connected to all the four metropolises and Pune to Bombay. In the State of Tamil Nadu, as many as 11 centres have been connected to Madras and there is a plan to connect all district headquarters in the State to Madras.

Telecommunication Network

14.12 BANKNET, a dedicated communication network for the banking industry, has expanded to include 248 ports at seven centres, viz., Bombay, Delhi, Madras, Calcutta, Hyderabad, Bangalore and Nagpur. Consequent upon receipt of permission from the Department of Telecommunications (DOT), Government of India, to extend the network to Pune and Ahmedabad, BANKNET is poised to increase its coverage. The network is being used for transmission of transfer responding advices pertaining to inter-city clearing, funds transfer, etc.

14.13 While the BANKNET is playing a useful role, it has certain limitations such as, (i) free format messages beyond 400 bytes size cannot be sent across the network; (ii) absence of versatile file transfer system; (iii) vendor dependence for software development process, creation of new templates; and (iv) absence of batch output utility. A network called RBInet is being developed to overcome the limitations of BANKNET and enhance its utility. It is expected to be operational in the next six months. This network will initially connect all Bank's offices and will facilitate exchange of data, documents, etc., of fairly large size among the Bank's offices with required security features and will co-exist with BANKNET. In the first phase, UNIX Server for RBInet will be installed in Bombay and Madras.

14.14 During the year under review, three more banks in India joined the SWIFT network, taking the total number of live users of the network in India to 41. Due to the persistent and sustained efforts of the Bank, DOT accorded approval to the SWIFT user banks to link their important forex branches in Bombay and remote centres through PSTN and telex lines. The Reserve Bank has been monitoring the quick implementation of the approval of DOT to optimise the use of the network to offer better and faster customer service to the

clientele of the banks. Within the Bank, the user department of SWIFT is the Department of External Investments and Operations. Attempts are being made to provide connectivity to Deposit Accounts Department, Bombay, to enable them to send all their forex messages through SWIFT which would substantially improve the present system of handling of forex messages at Deposit Accounts Department.

Office Automation

14.15 Fax machines have been installed in all Offices/ Training Colleges of the Bank except in Srinagar Office. Fax modern cards have been installed in PCs at National Clearing Cell at Central Office and Bombay Regional Office, Public Debt Office, Bombay and Department of Statistical Analysis and Computer Services.

Strategic Plan for Reserve Bank

14.16 As referred to in the previous Annual Report, the Reserve Bank has undertaken a Strategic Planning Exercise during the year. The Internal Task Force with the guidance of the external consultants, M/s. A F. Ferguson prepared a draft plan document which outlines the strategic actions focussing on certain key thrust areas.

Expert Committee on HRD

14.17 The Expert Committee on Human Resources Development (HRD) in Reserve Bank of India, (Chairman: Shri S. S. Marathe, Director of the Central Board of the Bank) has made extensive recommendations covering all important aspects of HRD, viz, (i) direct recruitment of officers (ii) placement, (iii) promotion, (iv) training and (v) performing appraisal. The recommendations are under active consideration of the Bank's Management Committee. To begin with, the Bank have accepted for implementation one of the recommendations relating to direct recruitment of officers and have decided to relax the age ceiling and waive the requirement of minimum period of service for staff members who wish to apply for the post of direct recruit in Grade 'B'.

L. K. Jha Memorial Lecture

14.18 The second L. K. Jha Memorial Lecture on 'The Strategy of Economic Adjustment' was delivered by Dr. Jacob A. Frenkel, Governor, Bank of Israel, on November 30, 1992 in Bombay.

History of the Reserve Bank

14.19 The compilation of the History of Reserve Bank of India covering the developments during the period 1951 to 1967 is in progress under the guidance of the Committee of Direction.

Development Research Group

14.20 Mention was made in the previous year's Report of the setting up of the Development Research Group (DRG) with a view to providing a forum for collaborative research effort between the Bank's professional staff and the academic and professional experts from outside the Bank. Six DRG studies have so far been published and five studies are currently under preparation.

Indira Gandhi Institute of Development Research

14.21 During the year under review, the Indira Gandhi Institute of Development Research conducted conferences and workshops on topics of policy options for economic reforms environment and economic development, global environment facility, innovation and growth. The Institute which is conducting a four-year Ph.D. Programme in Development Policy since August 1990 enrolled the third batch of research scholars in August 1992.

Training

14.22 Training and update of knowledge and adaptation to the new information technology and developments in both domestic and international fields, have assumed greater importance now than ever before. Realising this, the Bank's training institutions introduced a variety of new programmes during the year which bring into focus the implications of the emerging economic policies and reforms measures.

Bankers Training College, Bombay

14.23 The College conducted 104 programmes (including eleven programmes in Hindi) benefiting 2,098 participants. The total number of participants trained since its inception in 1954 rose to 45,872.

14.24 The new programmes introduced by the College during the year were in seven different areas such as, Bank Profitability, Liberalised Exchange Control Policies, Management of Balance of Payments, Costing in Banks, Inspection in Computerised Environment, Management of Public Issues of Company Shares/Debentures and Role of Operating Agencies in Preparation of Rehabilitation Packages. All these programmes took into account the changes being effected in macro and micro-economic policies. The College also arranged seminars on Transparency of Balance Sheets of Commercial Banks, Security Aspects in Banks and Banking Law and Practice.

Reserve Bank Staff College, Madras

14.25 The College conducted 83 programmes during the year, benefiting 1,855 employees. The total number of officers trained since its inception in 1963 increased to 30,345.

14.26 The College introduced a few new programmes, viz., Computer Orientation Programmes for Members of Faculty and Programmes for newly-promoted Assistant Treasurers, Computerisation of SGL Accounts in PDO, and Financing of Small Scale Industrial Units.

College of Agricultural Banking, Pune

14.27 During the year, the College conducted 117 programmes (including 21 programmes exclusively in Hindi) imparting training to 2,572 officers. The total number of officers trained by the College since its inception in 1969 was 43,050.

14.28 During the year, the College conducted new programmes on Monitoring and Evaluation of Projects, Financing of Agro-Exports, Rural Finacing, Synthesising Development Potential with Rural Credit, and Functional Programmes on Plantation and Horticulture, Financing of Fisheries Development, Animal Husbandry, Financing of Non-Farm Sector, Minor Irrigation and Rain-fed Agriculture. The College also conducted seminars on Credit Support for Sericulture Development, Bank Finance on Bio Technology Projects and Self-Help Groups. A programme on Management of Financing of Small Scale Projects' was conducted by the College during the year on behalf of the Asian and Pacific Regional Agricultural Credit Association.

Zonal Training Centres

14.29 During 1992-93, the four Zonal Training Centres of the Bank conducted 113 programmes in all, including programme on Computer Appreciation for Class III staff. The number of employees trained during the year was 1,839 in Class III and 184 in Class IV raising the total number of employees trained so far to 41,841 and 3,168, respectively.

Training in Commercial Banks

14.30 Under the scheme of training of the Bank's officers in Grades A, B and C in commercial banks, 124 officers, in all, completed the training since its introduction in 1986. At present 31 officers are undergoing training under the

scheme. During the year, one senior officer completed a six-month attachment to a commercial bank.

Deputation Officers for Training in India and Abroad

14.31 The Bank deputed, in all, 349 officers during 1992-93 to training programmes, seminars and conferences organised by various management/banking institutes in India.

14.32 The Bank also deputed 38 officers for training/study to banking and financial institutions in 14 countries, the USA, UK, Switzerland, Germany, Japan, Thailand, France, South Korea, Philippines, Zimbabwe, Malaysia, Austria, Singapore and Maldives.

14.33 With four more officers selected for pursuing higher studies abroad, the number of officers availing the benefit under the Golden Jubilee Scheme for award of scholarships to the Bank's officers for higher studies abroad, since its inception in 1983, rose to 28.

Training Facilities to Foreign Bank Officers

14.34 During 1992-93, altogether 95 officials from ten different countries viz., 36 from Sri Lanka, 7 from Kenya, 12 from Uganda, 7 from Tanzania, 6 from Nepal, 4 from Ghana, 8 from Afghanistan, 1 from Zambia, 11 from Uzbekistan and 3 from Mauritius participated in the training/study facilities extended by the Bank. The total number of officers of foreign central/commercial banks trained since 1981 was 908.

Schemes of Sponsorship for Ph.D.

14.35 Under the Bank's scheme of sponsoring officers from the Department of Economic Analysis and Policy for M. Phil Ph.D. programmes during the year under review, three officers were sponsored for the Ph.D. programme at the Indian Institute of Technology, Bombay and two officers at the Indira Gandhi Institute of Development Research, Bombay.

Training Computer Technology

14.36 The Bank's scheme of incentives for acquiring qualification in the field of computers was continued during the year. Since inception of the scheme in 1987, 128 officers and 537 clerical staff have joined the courses at various institutions in the country.

Scheme of Incentives for Acquiring Professional Qualifications

14.37 The scheme offering incentives to employees who successfully complete the Chartered Financial Analysis Programme conducted by the Institute of Chartered Financial Analysis of India, Hyderabad, continued to be in operation. So far, 171 employees have been granted permission to join the programme.

Employer-Employee Relations

14.38 The industrial relations climate in the Bank during the period under review was relatively peaceful.

14.39. It was mentioned in the previous Annual Report about the setting up of a Joint study Team comprising representatives of All India Reserve Bank Workers' Federation (AIRBWF) and the Bank to look into the question of recruitment to base cadres, regulation of part-time employees, etc. The Team submitted its report in November 1992 and the major recommendations of the Team have been accepted by the Bank in principle. The Bank has since entered into a settlement with the AIRBWF in this matter and steps are being taken towards implementation of the settlement.

14.40 The Bank has set up a Committee under the Chairmanship of Shri M. S. Patwardhan, Director of the Central Board of the Bank, to review the existing policy relating to transfer of officers and to frame fresh guidelines.

Staff Welfare

14.41 The benefits under the Reserve Bank of India Medical Assistance Fund Scheme which were hitherto available to spouses of members only during the lifetime of the member have been extended with effect from January 1, 1993 to the spouse even after demise of the member. An 'Advisory Committee' headed by the Chief Manager and consisting of a representative each of the four recognised associations of officers and workmen employees has been set up with effect from January 1, 1993, to suggest ways and means for bringing about improvements in the Scheme.

14.42 During the year, the bank decided to grant ex-gratia payment at the rate of Rs. 150 per month to the widow/widower/eligible child of deceased employees who had retired from Bank's service/died while in service prior to January, 1, 1986. Dearness relief is also payable on the ex-gratia payment at the rate as is admissible for family pension. The ex-gratia amount is payable as from January 1, 1986.

Employment to Reserved Categories: SCs/STs

14.43 In the recruitment in the Bank during the year 1992, the representation to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in different categories was as under:

Category	Total number of candidates recruited	Of Which		Percentage	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	18	3	1	16.7	5.6
Class III	95	26	8	27.1	8.4
Class IV	116	50	13	43.1	11.2
of whom :					
(a) Sweepers	24	21	1	87.5	4.2
(b) Other	92	29	12	31.5	13.0

14.44 With this, the total number, of SC and ST employees in the Bank as on December 31, 1992, rose to 563 and 124, respectively, in Class I. However, the total number of SC and ST employees registered a marginal decline to 2,417 and 1,177, respectively, in Class III and to 2,467 and 707, respectively, in Class IV on account of factors like retirements, resignations, etc. The Liaison Officer for Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees conducted inspection of reservation rosters maintained at the Bank's Bhopal, Bicculla, Cochin, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Nagpur, New Delhi and Thiruvananthapuram Offices. The dialogues between the Management and the representatives of the All-India Reserve Bank Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Buddhist Employees' Federation were held on three occasions during the year to discuss issues relating to implementing action on the reservation policy by the Bank.

Ex-servicemen

14.45 During the calendar year 1992, as against the prescribed rates of reservation of 14.5 per cent for Class III and 24.5 per cent for Class IV, four vacancies in Class III and 14 in Class IV could be filled up by recruitment of ex-servicemen out of the required number of posts of 14 and 28, respectively. However, the total strength of ex-servicemen in the Bank at the end of 1992 registered a marginal decline, as compared to the previous calendar year to 734 in Class III and 1,001 in Class IV owing to retirements, resignations, etc.

Physically-Handicapped Persons

14.46 During the calendar year 1992, two physically-handicapped persons were recruited in Class III and six in Class IV raising the total number of physically-handicapped employees recruited to 431.

Promotion of Hindi

14.47 The Bank, besides attending to its normal functions under the statutory provisions of official language, intensified the awareness amongst the staff members regarding the importance of official language by introducing various new measures, viz., Hindi training programmes for employees at various levels, originating Hindi correspondence, displaying Hindi terms and sentences at strategic points of the Bank's premises and keeping ordinary translations from Hindi to English to the minimum.

14.48 A scheme for writing original books in Hindi on banking subjects has been introduced for the employees of the Bank which has also been extended to retired employees of the Bank.

14.49 In keeping with the tradition of awarding the best work done in various areas of official language, both in public sector banks and in the Bank as well, two Rajbhasha Shield Award functions were held in August 1992 and October 1992, respectively. A House Journal Prize Distribution function was also held. This prize is given for quality contribution and quality production etc., in Hindi of House Journals of public sector banks. As regards training in Hindi typewriting to English typists, the capacity of Bank's Training Centre has been augmented from 14 to 30 seats. The Bank continued to ensure the use of Hindi software in computerisation of banking operations.

14.50 Besides bringing out Hindi version of Bank's Annual Report Report on Trend and Progress of Banking in India, Annual Report of Reserve Bank Services Board, and compendium of circulars brought out by the Urban Banks Department, a number of important committees have also been translated into Hindi.

14.51 The Bank has finalised the manuscript of the Banking Paribhasha Kosh, an interpretative glossary of banking terms and the same will be published shortly.

14.52 Hindi Diwas, on September 14, was observed by the Bank to commemorate the adoption of Hindi as official language by the Constituent Assembly. On this occasion, various competitions were held and cultural programmes were conducted by the Central Office Departments and Regional Offices.

Office Building and Residential Accommodation

14.53 During the year 1992-93, a sum of Rs. 17.26 crore was spent on capital account towards construction of office buildings, residential quarters, additions/alterations to the properties. In respect of residential accommodation, those nearing completion are 102 officers' flats at Vasna, Ahmedabad, 28 officers' flats at Napean Sea Road, Bombay and 132 staff quarters at Malviyanagar, Jaipur. An office building at Jammu is nearing completion. The construction work of Bankers Training College at Masab Tank, Hyderabad is in an advanced stage. Construction of a coin note vault at Calcutta has been taken up while one more at Hyderabad is under planning. Construction works in respect

of 42 flats for officers at Bombay and 120 flats for Class III and IV staff at Thiruvananthapuram are in progress. Contracts for construction of 80 flats for officers and 360 flats for class III and IV staff at Belapur, New Bombay have recently been awarded. Plans are under preparation for constructing residential flats for officers at Trikuta Nagar, Jammu, Cunningham Road, Bangalore and for staff quarters at Charkop, Kandivli, Bombay.

14.54 As against the satisfaction norms set up for residential quarters at 75 per cent for officers and 50 per cent each for classes III and IV staff, the Bank has nearly achieved the norms in respect of residential quarters for officers at most of the centres. Out of 21 centres, the required satisfaction level has been achieved at 14 centres for Class III and at 12 centres for Class IV staff.

Housing Loan

14.55 The Bank raised, with effect from July 20, 1992 the aggregate ceiling of housing loan and provident fund advance/withdrawal together for acquisition/construction of houses/flats to employees in Class I and Class III/IV from Rs. 4,00,000 to Rs. 6,00,000 and Rs. 3,00,000 to Rs. 4,00,000, respectively, with a further discretion to the extent of 25 per cent of the aggregate ceiling to the sanctioning authority.

14.56 It has been decided to permit a subscriber to avail himself of Provident Fund withdrawal after completion of 10 years' service (instead of the present 15 years), provided it is for the purpose of acquisition of a new house or new flat.

14.57 As directed by the Committee of the Central Board, an In-house Group has been constituted which will attempt without liberalising the existing monetary parameters of the Scheme, to redraft the existing Housing Loan Rules to simplify them so as to make the framework concise and to study the procedural requirements in Reserve Bank vis-a-vis other banks and to suggest measures which will encourage employees to avail of the housing loan facility.

14.58 During 1992-93 (July-June) the Bank sanctioned a total amount of Rs. 9.98 crore towards housing loan to employees (societies/Individuals). The details are given below:

Category	No. of Societies	No. of Employees	Amount of Loans (Rupees)
1	2	3	4
A. Co-op. Housing Societies	18**	60**	34,64,270**
(i) Fresh Loans	—	—	—
(ii) Additional Loans	18**	60**	34,64,270**
B. Individual Loans sanctioned by Central Office	—	181**	1,71,91,250**
(i) Fresh Loans	—	105**	1,53,98,150**
(ii) Additional Loans	—	76**	17,93,100**
C. Individual Loans sanctioned by Regional Offices	—	840*	7,91,34,565*
(i) Fresh Loans	—	544*	6,71,20,145*
(ii) Additional Loans	—	296*	1,20,14,420*
Total of A+B+C	18	1081	9,98,90,085

Note : Provisional Figures

(i) * Housing Loans sanctioned upto March 31, 1992 in respect of Bangalore, Calcutta (Banking), Calcutta (Reserve), New Delhi, Hyderabad, and Jammu Offices.

(ii) * Data from July 1, 1992 to June 30, 1993.

Central Board

14.59 Shri S. Venkitaramanan relinquished charge of the office of the Governor of the Bank as at the close of business on December 21, 1992. Dr. C. Rangarajan, Member of the Planning Commission, succeeded him as Governor of the Bank with effect from December 22, 1992. Dr. Rangarajan's appointment is for a period of three years.

14.60 Shri D. R. Mehta, Director General of Foreign Trade, Government of India, was appointed as Deputy Governor of the Bank with effect from November 11, 1992 for a period up to June 30, 1995.

Local Board

14.61 The Bank regrets to report the sad demise on January 6, 1993 of Shri R.M. Gupta, a member of the Northern Area Local Board of the Bank from August 25, 1984 till his demise. The Board wishes to place on record its deep sympathy to the members of his family in their bereavement.

14.62 There was no change in the constitution of any of the Local Boards during the year.

Appointment of Executives

14.63 Sarvashri A.P. Aiyer and P.B. Kulkarni were appointed as Executive Directors with effect from September 14, 1992.

Inspection and Audit Sub-Committee of the Central Board

14.64 With a view to giving sharper focus to the internal audit and inspection exercises and tailoring these towards the objectives of maximising productivity and efficiency of operations, an Inspection and Audit Sub-Committee of the Central Board was formed to November 1992 under the Chairmanship of Shri S.S. Marathe, Director of the Central Board of the Bank.

Sub-Committee of the Central Board on the Board of Financial Supervision

14.65 A Sub-Committee of the Central Board was set up in March 1993 under the Chairmanship of Shri S.S. Marathe, Director, Central Board to work out organisational and structural details of the proposed Board for Financial Supervision (BFS); the Sub-Committee submitted its report to the Board on May 13, 1993 and the BFS is expected to be operational shortly.

XV. THE BANK'S ACCOUNTS FOR THE YEAR 1992-93**(JULY-JUNE)****1. INCOME**

15.1 During the accounting year ended June 30, 1993, the Bank's income, after making adjustments for various

provisions, was marginally less by Rs. 67.44 crore (or 1.18 per cent) at Rs. 5,632.12 crore as compared with Rs. 5,699.56 crore in the previous year. The sources of income are given below :

(Rupees crore)

Item	Year ended June 30, 1993	Year ended June 30, 1992
1	2	3
(a) Interest on securities, loans and advances to banks, financial institutions, State Governments, etc., (including interest on foreign securities, deposits, etc.)	4,588.69	4,527.84
(b) Discount on rupee and foreign Treasury bills	993.11	819.65
(c) Exchange on remittances, TT's purchased etc. (including foreign transactions)	0.94	307.91
(d) Commission on management of public debt and other miscellaneous income	49.38	44.16
Total Income :	5,632.12	5,699.56

15.2 There was an increase of Rs. 60.85 crore in interest earnings during 1992-93. Discount earned showed an increase of Rs. 173.46 crore mainly on account of a rise in the discount earnings on Rupee Treasury bills.

2. EXPENDITURE

15.3 Total expenditure which was Rs. 4,199.56 crore during 1991-92 (July-June) decreased marginally by Rs. 71.44 crore to Rs. 4,128.12 crore in 1992-93 (July-June). The decrease was mainly due to less interest paid to scheduled banks on their additional eligible balances for CRR purposes. Of the interest payments of Rs. 3,057.77 crore, interest payments to scheduled banks during the year on their eligible additional balances (i.e. above the 3 per cent statutory ratio) maintained with the Reserve Bank for CRR purposes alone amounted to Rs. 2,339.96 crore and constituted 56.68 per cent of total expenditure (Table 15.1).

Table 15.1 : Reserve Bank of India : Income and Expenditure—1982-83 to 1992-93

(Rupees crore)

Sr. No.	Particulars	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Total Income (Gross)	1343.61	1645.13	1886.28	2209.67	2896.85	3741.23	4920.25	4426.73	4624.97	5699.56	5632.12
2.	Appropriations to :											
(a)	NIC (LTO) Fund	315.00	315.00	350.00	400.00	430.00	490.00	450.00	525.00	525.00	—	1.00
(b)	NRC (LTO) Fund	225.00	275.00	300.00	350.00	300.00	330.00	330.00	375.00	400.00	—	1.00
(c)	NRC (Stabilisation) Fund	75.00	80.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	—	1.00
(d)	NHC (LTO) Fund	—	—	—	—	—	50.00	25.00	50.00	50.00	—	1.00
3.	Total (a + b + c + d)	615.00	670.00	675.00	760.00	740.00	840.00	815.00	960.00	995.00	—	4.00
4.	Net Income (1-3)	728.61	975.13	1211.28	1449.67	2156.85	2701.23	3215.25	3466.73	3629.97	5699.56	5628.12
5.	Expenditure :											
(a)	Interest paid to Scheduled Comm. Banks	303.19	503.28	625.00	810.04	1042.99	1521.59	1829.82	2137.33	2431.02	2683.68	2339.96
(b)	Agency Charges	82.28	93.93	132.85	150.70	163.64	173.88	259.46	261.25	265.62	302.34	386.68
(c)	Security Printing	35.94	43.42	58.28	107.08	173.05	206.81	187.02	143.71	162.27	238.30	295.65
(d)	Int. on Extended Funds Facility (EFF)	—	—	—	—	368.00	357.03	445.18	388.89	62.00	540.42	616.75
(e)	Other Exp. @	97.20	124.50	185.15	179.58	199.13	231.81	283.64	325.43	359.06	434.82	489.08
6.	Total Expenditure (a + b + c + d + e)	518.61	765.13	1001.28	1239.67	1946.81	2491.12	3005.12	3256.61	3279.97	4199.56	4128.12
7.	Amount Transferred to Government (4-6)	210.00	210.00	210.00	210.00	210.04	210.11	210.13	210.12	350.00	1500.00	1500.00

@ 1.11% expenditure on establishment, interest on funds and other expenditure.

15.4 Establishment cost went up by Rs. 25.79 crore to Rs. 303.08 crore and formed 7.34 per cent of the total expenditure mainly on account of periodic increase in dearness allowance to staff in all categories and annual increments in the time scales of pay.

15.5 Security printing and incidental costs, which constituted 7.16 per cent of total expenditure, amounted to Rs. 295.65 crore and were higher by Rs. 57.35 crore than that in the preceding year, on account of general increase in the rates of charges for printing of note forms and cheque forms and in the supply of note pieces.

15.6 The higher turnover in Government transactions handled by agency banks resulted in agency charges registering a rise of Rs. 84.34 crore to Rs. 386.68 crore and formed 9.37 per cent of the total expenditure.

15.7 In the Notes to Accounts and Significant Accounting Policies annexed to the preceding year's accounts, it was mentioned against item 1(h) under "Retirement benefits" that the actuarial valuation for the pension scheme for the employees was to be obtained. Based on the actuarial valuation, the liability in respect of Pension Fund as on March 31, 1992 has been fully funded during 1992-93.

15.8 A policy decision was taken during the last year to discontinue the practice of appropriating large amounts from the profit of the Bank for credit to various Statutory Funds for loans and advances for agricultural development, industrial and housing financial institutions before transferring the surplus to the Government. Pending amendment to the Reserve Bank of India Act, 1934, to give effect to the above decision, a contribution of Rs. one crore each has been made to each of the four Statutory Funds from out of the profit for the year 1992-93 and the surplus at Rs. 1,500 crore for 1992-93 (July-June) was transferred by the Reserve Bank to the Government, the same as from the surplus for the previous year 1991-92 (Table 15.1).

3. BALANCE SHEET

Deposits-Banks

15.9 The aggregate deposits of scheduled commercial banks with the Reserve Bank rose by Rs. 2,176.25 crore from the previous year's level of Rs. 43,448.11 crore to Rs. 45,624.36 crore, whereas aggregate deposits of scheduled state co-operative banks, other scheduled co-operative banks, non-scheduled state co-operative banks and other banks increased by Rs. 138.53 crore from the previous year's level of Rs. 448.37 crore to Rs. 586.90 crore during 1992-93 (July-June).

Deposits-Others

15.10 The rise of Rs. 5,048.86 crore in other deposits from the previous year's level of Rs. 7,690.07 crore to

Rs. 12,738.93 crore was mainly on account of an increase of Rs. 4,360 crore in the balance in IMF Account No. 1.

Foreign Exchange Assets

15.11 Foreign exchange reserves include foreign securities in the Issue Department, balances held abroad and a part of Investments in the Banking Department. Such assets which stood at Rs. 16,124.93 crore as on June 30, 1992, increased by Rs. 4,358.44 crore to Rs. 20,483.37 crore as on June 30, 1993.

Government of India Rupee Securities and Investments

15.12 Investments in Government of India Rupee Securities and shares of financial institutions which were Rs. 94,028.76 crore as on June 30, 1992, increased by Rs. 17,258.96 crore to Rs. 1,11,287.72 crore on account of increase in investments in Government of India Rupee Securities during the year.

Loans and Advances

15.13 Credit extended to scheduled banks and financial institutions registered a sharp decline of Rs. 5,860.77 crore from Rs. 12,583.54 crore as at the end of June 1992 to Rs. 6,722.77 crore as at the end of June 1993 mainly owing to lower outstandings under export refinance to scheduled commercial banks.

Other Assets

15.14 Other assets increased by Rs. 380.01 crore from Rs. 4,348.18 crore as on June 30, 1992 to Rs. 4,728.19 crore mainly on account of profit in Banking Department (Rs. 1,545.29 crore).

Exchange Risk for Foreign Currency Deposit Schemes

15.15 During the year ended June 30, 1993, the exchange loss borne by the Reserve Bank on FCNR Account with-drawals/renewals was lower at Rs. 2,569.57 crore as against Rs. 5,531.91 crore borne during the year ended June 30, 1992. This was owing to smaller outflows and lower impact of rupee's depreciation in 1992-93. Government of India has agreed to take over the exchange risk liabilities related to FCNR deposits on annual outflows with effect from July 1, 1993. The Bank will endeavour to transfer additional profits and funds out of existing provisions to Government of India to facilitate takeover of such liabilities.

Auditors

15.16 The Accounts of the Bank have been audited by M/s. Brahmayya & Co., Madras, M/s N.M. Rajji & Co., Bombay, M/s Goel Garg & Co., New Delhi, M/s J. N. Sharma & Co., Kanpur, M/s M. Anandam & Co., Hyderabad and M/s Mitra Kundu & Basu, Calcutta. While the first four auditors were reappointed by the Government of India for 1992-93, the other two auditors have been newly appointed. All the offices of the Bank, divided into six zones, were allocated for audit by the Statutory Auditors.

RESERVE BANK OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1993

ISSUE DEPARTMENT			(Rs. Thousands)		
Liabilities	1992-93 Rs.	1991-92 Rs.	Assets	1992-93 Rs.	1991-92 Rs.
Notes held in the Banking Department	5,53,91	13,45,21	Gold Coin and Bullion		
Notes in circulation	75078,23,23	64550,25,75	(a) Held in India	9743,19,77	7275,91,94
			(b) Held outside India	557,91,84	467,50,24
Total Notes issued	75083,77,14	64563,70,96	Foreign Securities	200,00,00	200,00,00
			Total	10501,11,61	7943,42,18

1	2	3	4	5	6
			Rupce Coin	117,32,34	96,01,23
			Government of India Rupe		
			Securities	64465,33,19	56524,27,55
			Internal Bill of Exchange		
			and other Commercial Paper	—	—
Total Liabilities	75083,77,14	64563,70,96	Total Assets	75083,77,14	64563,70,96

BANKING DEPARTMENT

Liabilities	1992-93	1991-92	Assets	1992-93	1991-92
Capital paid-up	5,00,00	5,00,00	Notes	5,53,91	13,45,21
Reserve Fund	6500,00,00	6500,00,00	Rupce Coin	7,73	7,57
National Industrial Credit (LTO) Fund	5676,00,00	5675,00,00	Small Coin	5,98	1,101
National Housing Credit (LTO) Fund	176,00,00	175,00,00	Bills Purchased and Discounted		
Deposits			(a) Internal	—	—
(a) Government			(b) External	—	—
(i) Central Government	53,02,33	47,30,04	(c) Government Treasury Bills	2460,14,37	1827,77,18
(ii) State Governments	92,02,98	39,16,17	Balances Held Abroad	16600,14,57	14690,06,84
(b) Banks			Investments	50505,60,84	38739,34,93
(i) Scheduled Commercial Banks	45624,35,95	43448,10,84	Loans and Advances to		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	280,09,18	250,01,04	(i) Central Government	—	—
(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	237,99,66	135,16,23	(ii) State Governments	74,35,00	170,73,00
(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks	9,84,95	10,55,21	Loans and Advances to		
(v) Other Banks	58,96,13	52,65,07	(i) Scheduled Commercial Banks	3110,31,27	7471,98,19
(c) Others	12738,92,68	7690,07,35	(ii) Scheduled State Co-operative Banks	8,36,20	12,68,58
Bills Payable	18,46,28	126,06,92	(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	23,47,00	—
Other Liabilities	15264,92,20	13857,74,23	(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks	—	—
			(v) NABARD	3225,16,12	3582,27,17
			(vi) Others	355,46,81	1516,59,75
			Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (LTO) Fund		
			(a) Loans and Advances to		
			(i) Industrial Development Bank of India	3421,74,03	3576,55,41
			(ii) Export Import Bank of India	877,00,00	877,00,00
			(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	170,00,00	170,00,00
			(iv) Others	995,00,00	840,00,00
			(b) Investments in Bonds/Debentures issued by		
			(i) Industrial Development Bank of India	—	—
			(ii) Export Import Bank of India	—	—
			(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	—	—

1	2	3	4	5	6
			(iv) Others		
			Loans, Advances and Investments from National Housing Credit (LTO) Fund		
			(a) Loans and Advances to National Housing Bank	175,00,00	175,00,00
			(b) Investments in Bonds/Debentures issued by National Housing Bank	—	—
			Other Assets	4728,18,51	4348,18,26
Total Liabilities	86735,62,34	78011,83,10	Total Assets	86735,62,34	78011,83,10

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies as per Annexure.

(Rs. Thousands)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE 1993

	1992-93 Rs.	1991-92 Rs.
INCOME		
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc. ¹	5632,12,13	5699,56,44
Total	5632,12,13	5699,56,44
EXPENDITURE		
Interest	3057,76,54	3311,57,46
Establishment	303,08,13	277,29,02
Directors' and Local Board Members' Fees & Expenses	10,48	8,26
Remittance of Treasure	18,61,93	5,59,14
Agency Charges	386,68,50	302,34,10
Security Printing (Cheque, Note forms, etc.)	295,64,84	238,29,63
Printing and Stationery	2,84,96	3,00,97
Postage and Telecommunication Charges	5,64,97	5,31,53
Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	17,35,92	15,83,94
Auditors' Fees and Expenses	11,67	8,32
Law Charges	31,02	45,89
Depreciation and Repairs to Bank Property	20,41,25	20,47,81
Miscellaneous Expenses	19,51,92	19,30,37
Total	4128,12,13	4199,56,44
Available Balance	1504,00,00	1500,00,00
LESS : Contributions to :		
National Industrial Credit (LTO) Fund	1,00,00	—
National Rural Credit (LTO) Fund ²	1,00,00	—
National Rural Credit (Stabilisation) Fund ²	1,00,00	—
National Housing Credit (LTO) Fund	1,00,00	—
	4,00,00	
Surplus Payable to Central Government	1500,00,00	1500,00,00

1. After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934.
2. These funds are maintained by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

(P.Y. Padhye)
Chief Accountant

(D.R. Mehta)
Deputy Governor

(S.S. Tarapore)
Deputy Governor

(C. Rangarajan)
Governor

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet of the Bank as at 30th June 1993 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date.

We have examined the above Balance Sheet of the Reserve Bank of India as at 30th June 1993 and the Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date and report that where we have called for explanations and information from the Bank, such information and explanations have been given and have been satisfactory.

In our opinion and according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of accounts of the Bank, the Balance Sheet read with Notes to Accounts and Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs.

M/s Brahmayya & Co.
Auditors

M/s Goel Garg & Co.
Auditors

M/s N.M. Rajji & Co.
Auditors

M/s Mitra Kundu & Basu
Auditors

M/s J.N. Sharma & Co.
Auditors

M/s M. Anandam & Co.
Auditors

Dated 26th August 1993

RESERVE BANK OF INDIA

ANNEXURE

NOTES TO ACCOUNTS AND SIGNIFICANT POLICIES

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1 GOLD HOLDINGS

Gold held in Issue and Banking Departments is valued at 90 per cent of the monthly average London price of gold which is converted into Rupees at the Reserve Bank's Reference Rate for dollar prevailing at the end of the year.

1.2 INVESTMENT IN FOREIGN SECURITIES

Foreign securities are valued at the lower of cost or market price prevailing on the last business day of each month and are converted into Rupee equivalent at the Reserve Bank's rates (based on Reference Rate) prevailing on that date. While depreciation is charged to the Profit and Loss Account, no credit is taken for appreciation in the value of securities.

1.3 INVESTMENT IN GOVERNMENT OF INDIA RUPEE SECURITIES

Securities are valued at the lower of cost or on rates based on current yield curve prevailing at the end of the year. The sale proceeds of Rupee securities are credited to the Investment Account. Profit/Loss is booked only at the time of redemption except where sale proceeds of part of securities are more than the book value of the securities held under that category.

1.4 GOVERNMENT TREASURY BILLS

Treasury Bills are valued at cost.

1.5 BANK'S INVESTMENTS

Bank's investments in shares of State Bank of India, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Housing Bank and Discount and Finance House of India Ltd., are valued at cost.

1.6 Assets and Liabilities in foreign currencies are translated into rupees at the Reserve Bank's rates (based on Reference Rate) prevailing on the balance sheet date except in cases where rates have been contractually fixed. Income and Expenditure are translated into rupees at the holding rates for the month in which the transactions take place.

1.7 PROFIT AND LOSS ACCOUNT

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis. Accounting for accrued income and provision for outstanding expenses are made only for individual items of Rs. 1 lakh and above.

1.8 RETIREMENT BENEFITS

Based on actuarial valuation, contributions to the Gratuity Fund are made every year and in respect of Pension Fund one in two years.

1.9 DEPRECIATION

Depreciation on assets such as premises, fixtures and electrical installations is charged on written down value method and in the case of computers, motor vehicles, etc., depreciation is charged on straight line method. However, in respect of assets acquired during the second half of the year, not depreciation is charged.

2. RESERVE FUND

Represents initial contribution of Rs. 5 crore made by Government of India in the form of Government securities and appreciation of Rs. 6,495 crore on account of revaluation of gold.

3. DEPOSITS—OTHERS

Include mainly deposits from foreign central banks, financial institutions, IMF balances, staff pension, provident fund and gratuity contributions.

4. OTHER LIABILITIES

Include mainly reserves for exchange fluctuation and other contingency accounts.

5. INVESTMENTS

(i) Investment in Banking Department include Rs. 3,683.22 crore (previous year Rs. 1,234.87 crore) held abroad in foreign currencies.

(ii) Foreign Investments include bonds of value of Rs. 87.98 crore (face value Rs. 88.38 crore) loaned under Bond Lending Scheme on fee sharing basis. The same are covered by adequate security.

6. OTHER ASSETS

Include mainly gold [valued at Rs. 1,645.29 crore (previous year Rs. 1,188.65 crore) which is held outside India] fixed assets, capital works in progress, receivables balances in inter-office accounts, staff loans and advances and Asian Clearing Union Accounts. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation.

INDEX OF APPENDIX TABLES

Table No.	Title
I. POLICY DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES	
I.1	Interest Rate Structure for Advances of Scheduled Commercial Banks
I.2	Interest Rates on Commercial Advances of Scheduled Commercial Banks
I.3	Interest Rates on Deposits of Scheduled Commercial Banks
I.4	Interest Rates on Export Credit of Scheduled Commercial Banks
I.5	Minimum Margins and Level of credit Ceiling on Bank Advances Against Commodities Subject to Selective Credit Controls
II. THE REAL ECONOMY : PERFORMANCE AND PROBLEMS	
II.1	Sectoral Composition and Growth Rates of Real Gross Domestic Product
II.2	Estimates of Domestic Saving and Investment Ratios
II.3	Agricultural Production
II.4	Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains
II.5	Trends in Index of Industrial Production
II.6	Growth in Index of Seventeen Major Groups of Manufacturing Sector
II.7	Trends in Production of Infrastructure Industries
III. GOVERNMENT FINANCES	
III.1	Measures of Deficit of the Central Government
III.2	Fortnightly Levels of the Centre's Budget Deficit and Net RBI Credit to Central Government
III.3	Financing of Gross Fiscal Deficit
III.4	Total Outstanding Liabilities of Government of India
III.5	Budgetary Position of the Central Government
III.6	Measures of Deficit of the State Governments
III.7	Financing of States' Gross Fiscal Deficit
III.8	Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments
III.9	Developmental and Non-developmental Expenditure of Centre and States
III.10	Direct and Indirect Tax Revenues of the Centre and States
III.11	Market Borrowings of Central and State Governments, Local Authorities and Institutions Sponsored by the Central and State Governments
III.12	Coupon Rates on Central and State Governments Securities
IV. MONETARY AND PRICE TRENDS	
IV.1	Variations in Money Stock (M ₃)—Components and Sources
IV.2	Reserve Money—Components and Sources
IV.3	Trends in Income Velocity of Currency, Aggregate Deposits, M ₁ and M ₂
IV.4	Monetary Ratios
IV.5	Important Banking Indicators—Scheduled Commercial Banks
IV.6	Variations in Selected items of Scheduled Commercial Banks ; Last Week of March
IV.7	Scheduled Commercial Banks' Non-deposit Resources
IV.8	Sectoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors

Table No.	Title	Page No.
IV.9	Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit	
IV.10	Reserve Bank's Accommodation to Scheduled Commercial Banks	
IV.11	Reserve Bank's Refinance to Discount and Finance House of India Ltd.	
IV.12	Cumulative Turnover of the Discount and Finance House of India Ltd., in Money Market Instruments	
IV.13	Interest Rates for Reserve Bank Refinance to Discount and Finance House of India Ltd.	
IV.14	Call Money Lending Rates of Discount and Finance House of India Ltd.	
IV.15	Issue of Certificates of Deposit (CDs) by Schedule Commercial Banks	
IV.16	Auctions of 364-Day Government of India Treasury Bills	
IV.17	Auctions of 91-Day Government of India Treasury Bills	
IV.18	Auctions of Central Governments' Securities	
IV.19	Auctions of Repos by the Reserve Bank	
IV.20	Variations in Index Numbers of Wholesale Prices	
IV.21	Weighted Contribution of Groups/Commodities to the Increase in the General Index of Wholesale Prices	
IV.22	Annual and Quarterly Rates of Price Increases as Reflected in Wholesale Price Index and Consumer Price Index Numbers	
IV.23	Gold and Silver Ratio in Terms of Grammes	
IV.24	Gold and Silver Prices in Domestic and International Markets	
IV.25	Gold and Silver Price—Monthly Averages and Spread between Domestic and International Price	
	V. CAPITAL MARKET DEVELOPMENTS	
V.1	Assistance Sanctioned and Disbursed by all Financial Institutions	
V.2	Approvals for New Issues by the CCI and Clearance by SEBI for Raising Capital	
V.3	New Capital Issues by Non-Government Public Limited Companies	
V.4	Reserve Bank of India All-India Index Numbers of Ordinary Share Prices (Weekly)	
V.5	Deposits with Non-Banking Corporate Sector	
	VI. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR	
VI.1	India's Overall Balance of Payments	
VI.2	Financing Need and Sources of Financing	
VI.3	India's Foreign Exchange Reserves	
VI.4	Transactions with the IMF	
VI.5	India's Foreign Trade	
VI.6	India's Exports of Principal Commodities	
VI.7	India's Imports of Principal Commodities	
VI.8	India's Trade with Rupee Payment Area (RPA) and General Currency Area (GCA)	
VI.9	External Assistance	
VI.10	Deposit Liabilities under NR(E)RA and FCNRA Schemes	
VI.11	Interest Rates on FCNRA Deposits	
VI.12	India's External Debt	
VI.13	Rupee Exchange Rates	

APPENDIX TABLE 1.1 : INTEREST RATE STRUCTURE FOR ADVANCES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(per cent per annum)

Category of Account	Rates Effective					
	October 9, 1991	April 22, 1992	October 9, 1992	March 1, 1993	April 8, 1993	June 24, 1993
1	2	3	4	5	6	7
I. Size of credit limit	G G G G					
1. Upto and inclusive of Rs. 7,500	11.5	11.5	11.5	11.5	12.0	12.0
2. Over Rs. 7,500 and upto Rs. 15,000	13.0	13.5	13.5	13.5		
3. Over Rs. 15,000 and upto Rs. 25,000	13.5					
4. Over Rs. 25,000 and up to Rs. 50,000	15.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.0
5. Over Rs. 50,000 and upto Rs. 2 lakh	16.5					
6. Over Rs. 2 lakhs@ (minimum)	20.0*	19.0*	18.0*	17.0*	17.0*	16.0*
II. Specific categories of advances						
1. DRI advances		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2. Term loans to agriculture, SSI, and transport operators owning up to two vehicles						
Size of credit limit						
(i) Over Rs. 25,000 and up to Rs. 50,000	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
(ii) Over Rs. 50,000 and up to Rs. 2 lakh	15.0					
(iii) Over Rs. 2 lakh (minimum)	15.0					
3. (i) Loans for purchase of consumer durables		Banks are free to determine the rate.				
(ii) Loans to individuals against shares and debentures/bonds						
(iii) Other non-priority sector personal loans						
4. Lending rate for commodities coming within the purview of selective credit control (SCC)						
Loans/advances/cash credit/overdrafts against commodities subject to SCC (minimum)		20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

† Excluding interest tax.

* The effective interest rate on bills discounting facilities to this category of borrowers is one percentage point below the lending rate charged.

⊗ The changes in this rate since September 1990 are set out below:

16.0 (minimum) effective September 22, 1990

17.0 (minimum) effective April 13, 1991

18.5 (minimum) effective July 4, 1991

20.0 (minimum) effective October 9, 1991

19.0 (minimum) effective March 2, 1992

18.0 (minimum) effective October 9, 1992

17.0 (minimum) effective March 1, 1993

16.0 (minimum) effective June 24, 1993

- Notes: 1. Where short-term loans are routed through PACS/LAMPS/FSS, the rates to be charged by banks to the PACS/LAMPS/FSS shall be 2.5 percentage points lower than the rates to the ultimate borrowers indicated in item I above for the respective size of the limit.
2. In the case of term loans routed through PACS/LAMPS/FSS, the rate of interest charged by banks to the PACS/LAMPS/FSS shall be 1.5 percentage points lower than the rate stipulated for the respective size of the limit for term loans at items I and II (2) above.
3. In the case of finance granted to intermediary agencies (including those for housing) for onlending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support, the rate should be a fixed rate of three percentage points below the minimum rate applicable for credit limits in the category of over Rs. 2 lakh.

APPENDIX TABLE 1.2 : INTEREST RATES ON COMMERCIAL ADVANCES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

		(per cent per annum)
Effective Date	Rate of Interest	
1	2	
March 1, 1978	15.0	
September 13, 1979	18.0	
July 1, 1980	19.4	
March 2, 1981	Not exceeding	19.5*
April 1, 1983	Not exceeding	18.0
April 1, 1985	Not exceeding	17.5
April 1, 1987	16.5	
October 10, 1988	16.0 (minimum)	
April 13, 1991	17.0 (minimum)	
July 4, 1991	18.5 (minimum)	
October 9, 1991	20.0 (minimum)	
March 2, 1992	19.0 (minimum)	
October 9, 1992	18.0 (minimum)	
March 1, 1993	17.0 (minimum)	
June 24, 1993	16.0 (minimum)	

* Inclusive of interest tax.

APPENDIX TABLE 1.3 : INTEREST RATES ON DEPOSITS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(per cent per annum)					
Category of Account	Rates Effective				
	October 9, 1991	April 24, 1992	October 9, 1992	March 1, 1993	July 1, 1993
1	2	3	4	5	6
Current	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Savings	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0
<u>Term Deposits</u>					
46 days to three years and over	11.0*	Not exceeding 13.0@	Not exceeding 12.0	Not exceeding 11.0	Not exceeding 11.0

* This was the fixed rate for 3 years and over and lower fixed rates were prescribed for shorter maturities,

@ Effective April 22, 1992.

APPENDIX TABLE 1.4: INTEREST RATES ON EXPORT CREDIT OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

Export Credit	(percent per annum)				
	Rates Effective				
	January 1, 1992††	March 2, 1992††	October 9, 1992††	March 1, 1993††	June 24 1993††
1	2	3	4	5	6
1. Pre-shipment credit					
(i) (a) Upto 180 days	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(b) Beyond 180 days and upto 270 days*	17.0	17.0	16.0	15.0	15.0
(ii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC guarantee upto 90 days	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
2. Post-shipment credit					
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(ii) Usance bills (for period comprising usance period of export bills, transit period, as specified by FEDAI, and grace period, wherever applicable)					
(a) Upto 90 days	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(b) Beyond 90 days upto six months from date of shipment	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
(c) Beyond six months from date of shipment	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0
(iii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(iv) Against undrawn balance (upto 90 days)	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
3. Deferred credit					
Deferred credit for the period beyond 180 days	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0
4. Export credit not otherwise specified (minimum)	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
5. Post-shipment export credit denominated in foreign currency (PSCFC)					
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	8.5	6.5	6.5	6.5	6.5
(ii) Usance bills (for total period comprising usance period of export bills, transit period, as specified by FEDAI, and grace period, wherever applicable, upto six months from date of shipment)	8.5	6.5	6.5	6.5	6.5
(iii) Export credit not otherwise specified for PSCFC@@				8.5	8.5

††Excluding Interest Tax.

* With effect from March 12, 1992, prior approval of the Reserve Bank was dispensed with.

@Effective October 13, 1992.

APPENDIX TABLE I.5 : MINIMUM MARGINS AND LEVEL OF CREDIT CEILING ON BANK ADVANCES AGAINST COMMODITIES SUBJECT TO SELECTIVE CREDIT CONTROLS

Commodities	Minimum margins (effective June 24, 1993)			(Per cent)	
	Mills/processing units	Others	Warehouse receipts	Level of credit ceiling (Base Year : Three Years ending 1991-92) (Nov.-Oct.)	
				1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6
1. Paddy/Rice	45	60	45	85	
2. Wheat	30	45	30	100	
3. Pulses	45	60	45	100	
4. Other foodgrains	45	60	45	100	
5. Oilseeds (viz., groundnut, rapeseed/mustard, cottonseed, linseed castorseed and all imported oilseeds)	30	45	30	100	
6. Vegetable oils (viz., groundnut oil, rapeseed/mustard oil, cottonseed oil, linseed oil, castor oil, vanaspati and all imported vegetable oils)	30@	45	30	100	
7. Sugar					
(a) Buffer stock	0	—	—	—	
(b) Unreleased stock	20	—	—	—	
(c) Released stock	75	75	60	—	
8. Gur and khandasari	45	75	60	—	
9. Cotton & kapas	x	45	30	115+	

@ Applicable to registered oil mills and vanaspati manufacturers.

x Exempt from the selective credit control stipulations.

+ Applicable to other than mills/processing units.

— Not applicable.

APPENDIX TABLE II.1 : SECTORAL COMPOSITION AND GROWTH RATES OF REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

Sector	Share in real GDP			Growth rate				
	1991-92*	1990-91	1980-81	1992-93†	1991-92*	1990-91	Seventh Plan (1985-86 to 1989-90)	Decade (1980-81 to 1989-90)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Agriculture and Allied Activities of which :	30.8	31.6	38.1	+5.1	+1.4	+4.8	+3.4	+2.9
Agriculture	28.4	29.3	34.7	+5.1	+1.8	+4.9	+3.9	+3.1
2. Industry of which :	24.7	25.2	20.9	+1.5	+0.9	+7.2	+7.5	+7.3
Manufacturing	20.3	21.0	17.7	+0.9	+2.3	+7.5	+7.1	+7.2
3. Services@	44.5	43.2	41.0	+5.0	+4.5	+4.3	+7.0	+6.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	+4.2	+1.2	+5.2	+5.8	+5.4

* Quick Estimate (January 1993), Central Statistical Organisation

† Reserve Bank Estimates.

@ Inclusive of construction.

APPENDIX TABLE II.2 : ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT RATIOS

Sectors/ Fiscal Year	Gross Saving and Investment as percentage of GDP at current market prices			Net Saving and Investment as percentage of NDP at current market prices		
	1992-93#	1991-92@	1990-91@	1992-93#	1991-92@	1990-91@
1	2	3	4	5	6	7
1 Household Sector Saving: of which:	17.7	19.4	19.9	16.2	17.5	18.0
Saving financial assets*	7.7	9.1	8.6	8.5	10.2	9.5
2 Public Sector	2.0	1.7	1.1	-3.0	-3.3	-3.8
3 Domestic Private Corporate Sector	2.8	2.7	2.7	1.0	1.0	1.0
4 Total Domestic Saving (1+2+3)	22.5	23.8	23.7	14.2	15.2	15.2
5 Net Inflow of Foreign Resources	2.2	1.0	3.5	2.5	1.1	3.9
6 Aggregate Investment (4+5)	24.8	24.8	27.1	16.3	16.3	19.1
GDP/NDP at Current Market Prices (Rupees crore)	7,03,000	6,09,500\$	5,30,865	6,34,506	5,47,691\$	4,78,981

@Provisional Estimates

\$ Quick Estimates

Reserve Bank Estimates.

* These are adjusted for financial liabilities. As saving in financial assets do not involve capital consumption for fixed assets net ratios work out higher than gross ratios; like-wise in net inflow of foreign resources.

Notes: 1. The ratios for 1990-91 and 1991-92 differ from those given in the previous year's Annual Report of the Bank and those published in the CSO's Quick Estimates for 1991-92, because of the revision in the estimates of national income and those of saving and investment consequent on the availability of fresh data.

2. Figures may not add up to the totals due to rounding off.

APPENDIX TABLE II.3 : AGRICULTURAL PRODUCTION

(Million tonnes)

Crop	1992-93 (Estimated)	1991-92 (Final)	1990-91	1989-90
1	2	3	4	5
1. ALL CROPS\$	5.1*	-2.5	2.7	2.1
2. FOODGRAINS	18.12	167.1	176.4	171.0
Rice	72.6	73.7	74.3	73.6
Wheat	57.0	55.1	55.1	49.8
Coarse grains	36.9	26.3	32.7	34.8
Pulses	14.7	12.0	14.3	12.8
(a) KHARIF	103.2	91.4	99.4	101.0
Rice	64.6	64.8	66.3	65.9
Coarse grains	32.3	22.2	27.7	29.6
Pulses	6.3	4.4	5.4	5.5
(b) RABI	78.0	75.6	77.0	70.0
Rice	8.0	8.8	8.0	7.7
Wheat	57.0	55.1	55.1	49.8
Coarse grains	4.6	4.1	5.0	5.2
Pulses	8.4	7.6	8.9	7.3
3. OIL SEEDS	20.6	18.3	18.6	16.9
4. SUGARCANE	238.0	249.3	241.1	225.6
5. COTTON**	11.7	9.8	9.8	11.4
6. JUTE & MESTA@	7.6	10.2	9.2	8.3

Total may not tally because of rounding off.

* Anticipated.

\$ Growth rates (in per cent) based on Index of Agricultural Production (Triennium ending 1969-70=100)

** Million bales—one bale = 170 Kgs.

@ Million bales—one bale = 180 Kgs.

Source : Ministry of Agriculture, Government of India.

APPENDIX TABLE II.4 : PROCUREMENT, OFF-TAKE AND STOCKS OF FOODGRAINS

(Million tonnes)

Fiscal year	Procurement			Off-take			Stocks*		
	Rice	Wheat	Total	Rice	Wheat	Total ^(a)	Rice	Wheat	Total ^(a)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1990-91	12.8	11.1	23.9	7.9	8.2	16.1	11.2	5.8	17.3
1991-92	10.4	7.8	18.2	10.1	9.1	19.2	9.8	2.4	12.2
1992-93\$	12.6	6.4	19.0	9.4	7.7	17.1	11.0	3.0	14.7
First quarter (April—June)									
1992-93	1.1	6.3	7.4	2.3	1.9	4.2	8.4	6.7	15.1
1993-94\$	1.5	12.7	14.2	2.1	1.0	3.1	10.4	15.2	26.4

* Stocks are as at end-March for fiscal year period.

^(a) Includes coarse grains.

\$ Provisional.

Source : Ministry of Food & Civil Supplies, Government of India.

APPENDIX TABLE II.5 : TRENDS IN INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION

(Base : 1980-81 = 100)

Sector	Mining & Quarrying		Manufacturing		Electricity		General	
	Weight		11.46		77.11		11.43	
	Index	Growth rate (per cent)	Index	Growth rate (per cent)	Index	Growth rate (per cent)	Index	Growth rate (per cent)
Year	2	3	4	5	6	7	8	9
1988-89	199.1	7.9	175.6	8.7	198.2	9.5	180.9	8.7
1989-90	211.6	6.3	190.7	8.6	219.7	10.9	196.4	8.6
1990-91	221.2	4.5	207.8	8.9	236.8	7.8	212.6	8.2
1991-92	221.5	0.1	204.6	-1.5	257.0	8.5	212.5	0.0
Apr-Jun	203.4	-3.6	187.7	-3.7	243.4	6.7	195.9	-2.3
Jul-Sep	193.1	-1.8	193.9	-1.2	252.5	10.0	200.5	0.2
Oct-Dec	228.1	6.0	197.6	-2.7	262.2	10.4	208.4	0.05
Jan-Mar	261.4	-0.3	239.3	1.0	269.7	7.1	245.4	1.6
1992-93	225.8	1.9	206.1	0.7	269.7	4.9	215.6	1.5
Apr-Jun	220.1	8.2	195.8	4.3	258.0	6.0	205.7	5.0
Jul-Sep	195.4	1.2	199.6	2.9	259.0	2.5	205.8	2.7
Oct-Dec	223.8	1.9	205.8	4.2	276.5	5.5	215.9	3.6
Jan-Mar	263.9	1.0	223.1	-6.8	285.4	5.8	234.9	-4.3

Source : Central Statistical Organisation.

APPENDIX TABLE II.6 : GROWTH IN INDEX OF SEVENTEEN MAJOR GROUPS OF MANUFACTURING SECTOR

(Base : 1980-81=100)

Industry Group	Weight	Index			Per cent variation		Relative Contribution (in per cent)	
		1992-93	1991-92	1990-91	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. POSITIVE								
ACCELERATION (During 1992-93)								
1. Food and food products	5.33	175.7	166.2	169.8	5.7	-2.1	45.2	-7.9
2. Chemicals and chemical products	12.51	276.2	262.8	254.1	5.1	3.4	149.9	44.9
3. Transport Equipment	6.39	198.5	191.5	192.5	3.7	-0.5	40.0	-2.6
4. Wood and wood products	0.45	190.5	185.0	197.2	3.0	-6.2	2.2	-2.3
5. Rubber, plastic and petroleum products	4.00	176.8	172.4	174.0	2.6	-0.9	15.7	-2.6
6. Leather and leather and fur products	0.49	200.9	196.6	194.3	2.2	1.2	1.9	0.5
7. Cotton textiles	12.31	128.3	126.2	126.6	1.7	-0.3	23.1	-2.0
8. Other Manfg. Industries	0.90	271.0	269.8	321.8	0.4	-16.2	1.0	-19.3
DECELERATION (During 1992-93)								
9. Non-metallic mineral products	3.00	207.2	205.2	193.1	1.0	6.3	5.4	15.3
II. NEGATIVE (During 1992-93)								
10. Textile Products (including wearing apparel)	0.82	78.7	97.2	103.2	-19.0	-5.8	-13.5	2.0
11. Metal products	2.29	126.3	139.9	143.1	-9.7	-2.2	-27.8	-3.00
12. Beverages, tobacco and tobacco products	1.57	113.6	119.1	104.8	-4.6	13.6	-7.7	9.3
13. Jute, hemp and mesta textiles	2.00	87.2	90.4	101.6	-3.5	-11.0	-5.7	-9.2
14. Electric all machinery	5.78	476.4	493.6	563.6	-3.5	-12.4	-88.8	-166.7
15. Machinery and machine tools	6.24	178.2	184.4	186.9	-3.4	-1.3	-34.6	-6.4
16. Paper and paper products	3.23	208.7	209.6	198.0	-0.4	5.9	-2.6	15.4
17. Basic metal and alloys industries	9.80	168.1	168.5	158.8	-0.2	6.1	-3.5	39.2
MANUFACTURING	77.11	206.1	204.6	207.8	0.7	-1.5	100.0	-100.0

Source : Central Statistical Organisation,

APPENDIX TABLE II.7 : TRENDS IN PRODUCTION OF INFRASTRUCTURE INDUSTRIES

Industry	Weight	Unit	Fiscal Year			
			Output		Growth Rate (per cent)	
			1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6	7
Electricity	11.43	Billion Units	300.99	286.71	4.9	8.5
Coal	6.61	Million Tonnes	238.22	229.29	3.9	8.3
Saleable Steel	5.21	..	10.45	10.07	3.9	8.1
Cement	1.60	..	54.14	54.01	0.2	10.9
Petroleum Crude	2.41	..	26.95	30.35	-11.2	-8.1
Petroleum Refinery Products*	1.52	..	49.74	47.82	4.0	-0.7
Composite Index of Infrastructure Industries (Base : 1980-81 = 100)	28.77		233.9	228.2	2.5	6.8

* This represents 93 per cent of the refinery throughput.

Source : Ministry of Planning & Programme Implementation, Government of India.

APPENDIX TABLE III.1 : MEASURES OF DEFICIT OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(Rupees crore)

Year	Gross Fiscal Deficit (a)	Net Fiscal Deficit (a)	Net Primary Deficit	Monetised Deficit	Conventional Deficit	Revenue Deficit	GDP at Current Market Prices
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	8,299	5,110	4,301	3,551	2,477	2,037	1,36,013
1981-82	8,666	4,591	3,611	3,207	1,400	392	1,59,760
1982-83	10,627*	5,973	4,887	3,368	1,656*	1,308	1,78,132
1983-84	13,030*	8,171	6,044	3,949	1,417*	2,540	2,07,589
1984-85	17,416	10,972	8,961	6,055	3,745	4,225	2,31,343
1985-86	21,857*	13,543	10,626	6,190	5,315*	5,889	2,62,243
1986-87	26,342	17,036	13,143	7,091	8,261	7,777	2,92,949
1987-88	27,044	18,431	12,935	6,559	5,816	9,137	3,33,201
1988-89	30,923	20,770	13,473	6,503	5,642	10,515	3,96,593
1989-90	35,632	23,722	14,439	13,813	10,592	11,914	4,53,986
1990-91	44,632	30,692	17,651	14,746	11,347	18,562	5,30,865
1991-92	36,325	24,623	8,982	5,508	6,855	61,261	6,09,500
1992-93(RE)	36,722	26,037	5,974	5,400\$	7,202+	16,700	7,03,000‡
1993-94(BE)	36,959	26,926	3,457	4,314	4,314	17,630	7,85,000++

As Percentage to GDP at Current Market Prices

1980-81	6.10	3.76	3.16	2.61	1.82	1.50
1981-82	5.42	2.87	2.26	2.01	0.88	0.25
1982-83	5.97	3.35	2.74	1.89	0.93	0.73
1983-84	6.28	3.94	2.91	1.90	0.68	1.22
1984-85	7.53	4.74	3.87	2.62	1.62	1.83
1985-86	8.33	5.16	4.05	2.36	2.03	2.25
1986-87	8.99	5.82	4.49	2.42	2.82	2.65
1987-88	8.12	5.53	3.88	1.97	1.75	2.74
1988-89	7.80	5.24	3.40	1.64	1.42	2.65
1989-90	7.85	5.23	3.18	3.04	2.33	2.62
1990-91	8.41	5.78	3.32	2.78	2.14	3.50
1991-92	5.96	4.04	1.47	0.90	1.12	2.67
1992-93	5.22	3.70	0.85	0.77	1.02	0.38
1993-94++	4.71	3.43	0.44	0.55	0.55	2.25

RE : Revised Estimates.

BE : Budget Estimates

‡RBI Estimates.

++ Rough Estimates.

① These data differ from those published earlier on account of certain adjustments of contra entries on the capital account.

* Excluding medium-term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given to States to clear their overdrafts with the RBI.

\$ As per RBI Records, after the closure of Government accounts, monetised deficit was Rs. 4,257 crore.

+ The deficit according to RBI Records after closure of Government account as on March 31, 1993 was Rs. 12,757 crore.

Note : The conventional deficit is the difference between all receipts and expenditure (both revenue and capital). The revenue deficit denotes the difference between revenue receipts and revenue expenditure. The monetised deficit is the increase in the net RBI credit to the Central Government which is the sum of net increase in the holdings of 91-day Treasury bills of the RBI and its contribution to the market borrowings of the Central Government. The gross fiscal deficit is the excess of total expenditure including loans net of recovery over revenue receipts (including external grants) and non-debt capital receipts. Net fiscal deficit is the difference between gross fiscal deficit and net lending. The net primary deficit denotes net fiscal deficit minus net interest payments.

Source : Central Government Budget document and Economic Survey, 1992-93.

APPENDIX TABLE III.2 : FORTNIGHTLY LEVELS OF THE CENTRE'S BUDGET DEFICIT AND NET RBI CREDIT TO CENTRAL GOVERNMENT@

(Rupees crore)

Period		Centre's Budget Deficit				Net RBI Credit to Centre			
		1993-94	1992-93	1991-92	1990-91	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Budget Estimates		4,314	5,389	7,719	7,206	4,314	5,389	7,719	7,206
(Fortnight Actuals)	Date \$								
1	3-4-92	887	4,774	2,271	2,679	2,413	3,847	2,427	2,712
2	17-4-92	4,057	6,115	3,716	3,204	9,476	6,522	3,269	4,050
3	1-5-92	8,186	6,604	5,508	5,754	12,101	5,229	3,962	4,994
4	15-5-92	11,964	8,924	8,409	6,638	13,694	7,218	6,764	7,058
5	29-5-92	13,046	10,414	8,925	8,228	13,726	7,985	7,534	6,907
6	12-6-92	16,201	10,854	11,029	7,698	10,065	7,192	9,607	7,463
7	26-6-92	16,053	8,886	11,503	9,107	9,201	3,912	9,168	7,703
8	10-7-92	20,718	14,102	12,747	9,996	18,889	9,193	11,165	9,883
9	24-7-92	20,750	14,949	11,873	10,128	16,498	8,113	10,580	8,185
10	7-8-92	21,727	13,935	12,793	10,976	16,444	7,872	10,759	9,018
11	21-8-92	21,065	11,792	11,571	8,729	16,245	5,657	10,303	6,543
12	4-9-92		13,007	13,442	10,290		7,236	11,029	8,209
13	18-9-92		11,159	10,393	10,289		5,512	8,890	7,269
14	2-10-92		10,169	12,406	11,971		4,723	10,445	9,245
15	16-10-92		9,868	13,097	10,755		6,424	11,866	10,241
16	30-10-92		9,986	11,409	11,830		7,111	9,564	12,438
17	13-11-92		12,609	14,245	13,636		9,110	12,418	12,476
18	27-11-92		13,261	15,272	13,001		9,549	13,117	12,978
19	11-12-92		15,440	17,419	15,330		10,744	15,830	15,159
20	25-12-92		11,511	11,503	13,097		1,450	9,812	13,029
21	8-1-93		14,134	16,177	15,093		8,725	14,979	15,055
22	22-1-93		14,637	14,138	15,123		9,065	13,961	14,621
23	5-2-93		15,166	15,726	15,442		9,441	15,305	15,447
24	19-2-93		15,658	15,024	14,627		8,773	14,454	15,107
25	5-3-93		14,327	13,011	15,072		4,254	10,485	16,064
26	19-3-93		13,960	10,606	11,969		2,262	10,452	14,486
27	31-3-93		12,757	6,492	11,430		4,257	5,508	14,746
Quarterly Averages									
First Quarter		10,056	8,082	7,337	6,187	10,097	5,986	6,104	5,841
Second Quarter		21,065 ≠	13,157	12,137	10,068	17,019 ≠	7,264	10,454	8,185
Third Quarter			11,835	13,622	12,803		7,016	11,865	11,938
Fourth Quarter			14,647	14,114	14,554		7,087	13,606	15,130
Financial Year Average			11,811	11,508	10,818		6,718	10,209	10,337

@ Based on RBI Records.

≠ Up to August 20, 1993.

\$ The relevant dates of fortnights for 1992-93 have been specified; the dates for other years pertain to corresponding fortnights.

Note : As per budgetary data. Centre's deficit was Rs. 11,347 crore in 1990-91 (Accounts) and Rs. 6,855 crore in 1991-92 (Accounts).

APPENDIX TABLE III.3 : FINANCING OF GROSS FISCAL DEFICIT

						(Rupees crore)
Year	External Finance	Internal Finance			Total Finance/ Gross Fiscal deficit (2+6)	
		Market Borrowings	other Liabilities	Conventional deficit		
1	2	3	4	5	6	
7						
1980-81	1,281 (15.4)	2,679 (32.3)	1,862 (22.4)	2,477 (29.9)	7,018 (84.6)	8,299 (100.0)
1981-82	964 (11.1)	2,913 (33.6)	3,389 (39.1)	1,400 (16.2)	7,702 (88.9)	8,666 (100.0)
1982-83	1,258 (11.8)	3,771 (35.5)	3,942 (37.1)	1,656* (15.6)	9,369 (88.2)	10,627 (100.0)
1983-84	1,338 (10.3)	4,038 (31.0)	6,237 (47.8)	1,417* (10.9)	11,692 (89.7)	13,030 (100.0)
1984-85	1,452 (8.3)	4,095 (23.5)	8,124 (46.7)	3,745 (21.5)	15,964 (91.7)	17,416 (100.0)
1985-86	1,449 (6.6)	4,884 (22.4)	10,209 (46.7)	5,315* (24.3)	20,408 (93.4)	21,857 (100.0)
1986-87	2024 (7.7)	5,532 (21.0)	10,525 (39.9)	8,261 (31.4)	24,318 (92.3)	26,342 (100.0)
1987-88	2,893 (10.7)	5,862 (21.7)	12,473 (46.1)	5,816 (21.5)	24,151 (89.3)	27,044 (100.0)
1988-89	2460 (8.0)	8,418 (27.2)	14,403 (46.6)	5,642 (18.2)	28,463 (92.0)	30,923 (100.0)
1989-90	2,595 (7.3)	7,404 (20.8)	15,041 (42.2)	10,592 (29.7)	33,037 (92.7)	35,632 (100.0)
1990-91	3,181 (7.1)	8,001 (17.9)	22,103 (49.5)	11,347 (25.5)	41,451 (92.9)	44,632 (100.0)
1991-92	5,421 (14.9)	7,510 (20.7)	16,539 (45.5)	6,855 (18.9)	30,904 (85.1)	36,325 (100.0)
1992-93(RE)	4,430 (12.1)	3,670 (10.0)	21,420++ (58.3)	7,202 (19.6)	32,292 (87.9)	36,722 (100.0)
1993-94(BE)	5,454 (14.8)	3,700 (10.0)	23,491** (63.5)	4,314 (11.7)	31,505 (85.2)	36,959 (100.0)

Figures in brackets represent percentages to total finance/gross fiscal deficit.

* Excluding medium-term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given to States to clear their overdrafts with RBI.

†† Other liabilities comprise small savings, provident funds, special deposits, reserve funds, 364-day Treasury bills, etc.

§ Defined as variation in 91-day Treasury bills issued net of changes in cash balances with RBI.

+· Includes Rs. 5,300 crore in respect of the receipts from sale of 182-day/364-day Treasury bills net of repayment of 182-day Treasury bills.

** Includes Rs. 6,000 crore in respect of net receipts from sale of 364-day Treasury bills.

RE : Revised Estimates.

BE : Budget Estimates.

Source : Budget Documents of Government of India.

APPENDIX TABLE III.4 : TOTAL OUTSTANDING LIABILITIES OF GOVERNMENT OF INDIA

(Rupees crore)

Year	Internal Debt	Small Savings	Provident Fund & other Accounts	Reserve Fund & Deposits	Total Internal Liabilities (2+3+4+5)	External Liabilities	Total Liabilities (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	30,864 (22.7)	7,976 (5.9)	5,977 (4.4)	3,634 (2.6)	48,451 (35.6)	11,298 (8.3)	59,749 (43.9)
1981-82	35,653 (22.3)	9,375 (5.9)	7,203 (4.5)	3,627 (2.3)	55,858 (35.0)	12,328 (7.7)	68,186 (42.7)
1982-83	46,939 (26.4)	11,098 (6.2)	8,789 (5.0)	4,364 (2.4)	71,190 (40.0)	13,680 (7.7)	84,872 (47.7)
1983-84	50,263 (24.2)	13,506 (6.5)	10,368 (5.0)	6,004 (2.9)	80,141 (38.6)	15,120 (7.3)	95,061 (45.9)
1984-85	58,537 (25.3)	17,157 (7.4)	12,547 (5.4)	8,563 (3.7)	96,804 (41.8)	16,637 (7.2)	1,13,441 (49.0)
1985-86	71,039 (27.1)	21,449 (8.2)	15,410 (5.9)	11,433 (4.3)	1,19,331 (45.5)	18,153 (6.9)	1,37,484 (52.4)
1986-87	86,312 (29.5)	24,725 (8.4)	20,204 (6.9)	15,006 (5.1)	1,46,247 (49.9)	20,299 (6.9)	1,66,546 (56.8)
1987-88	98,646 (29.6)	28,358 (8.5)	26,170 (7.8)	19,164 (5.8)	1,72,338 (51.7)	23,223 (7.0)	1,95,561 (58.7)
1988-89	1,14,498 (28.9)	33,833 (8.5)	34,702 (8.7)	20,992 (5.3)	2,04,025 (51.4)	25,746 (6.5)	2,29,771 (57.9)
1989-90	1,33,193 (29.3)	41,791 (9.2)	45,273 (10.0)	19,592 (4.3)	2,39,849 (52.8)	28,343 (6.2)	2,68,192 (59.0)
1990-91	1,54,004 (29.0)	50,100 (9.4)	57,007 (10.8)	21,922 (4.1)	2,83,033 (53.3)	31,525 (5.9)	3,14,558 (59.0)
1991-92	1,72,750 (28.3)	55,755 (9.2)	65,745 (10.8)	23,464 (3.8)	3,17,714 (52.1)	36,948 (6.1)	3,54,662 (58.2)
1992-93(RE)	1,93,035 (27.4)	59,955 (8.5)	77,191 (11.0)	25,083 (3.6)	3,55,264 (50.5)	41,218 (5.9)	3,96,482 (56.4)
1993-94(BE)	2,04,690 (26.1)	63,855 (8.1)	94,685 (12.1)	26,777 (3.4)	3,90,007 (49.7)	46,453 (5.9)	4,36,460 (55.6)

Note : Figures in brackets represent percentages to GDP at current market prices.

RE : Revised Estimates

BE : Budget Estimates.

Source : Budget Documents of Government of India.

APPENDIX TABLE III.5 : BUDGETARY POSITION OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(Rupees crore)

Item	1993-94 (BE)	1992-93 (RE)	1992-93 (BE)	1991-92 (Accounts)
1	2	3	4	5
1. Revenue Account				
(i) Receipts (a)	84,209	78,279	75,688	66,047
(ii) Expenditure (a)	1,01,839	94,979	89,570	82,308
(iii) Surplus (+)/Deficit(—)	—17,630	—16,700	—13,882	—16,261
2. Capital Account				
(i) Receipts	42,800	39,245	38,010	38,528
(ii) Disbursements	29,484	29,747	29,517	29,122
(iii) Surplus(+)/Deficit(—)	+13,316	+9,498	+8,493	+9,406
3. Total Receipts [1(i)+2(i)]	1,27,009	1,17,524	1,13,698	1,04,575
4. Total Expenditure [1(ii)+2(ii)]	1,31,323	1,24,726	1,19,087	1,11,430
5. Overall Surplus(+)/Deficit(—)	—4,314	—7,202	—5,389	—6,855
6. Net Market Loans	3,700 (4,848)	3,670 (4,821)	5,000 (6,151)	7,510 (8,921)

(a) Exclude Commercial Departments in respect of Revenue Account.

Figures in brackets represent gross market loans.

RE : Revised Estimates.

BE : Budget Estimates.

Source : Budget Documents of Government of India.

APPENDIX TABLE III.6 : MEASURES OF DEFICIT OF THE STATE GOVERNMENTS

(Rupees crore)

Year	Gross Fiscal Deficit	Net Fiscal Deficit	Monetised Deficit*	Conventional Deficit	Revenue Deficit	Gross Fiscal Deficits as percentage of GDP at current Market Prices
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	3,712	1,714	487	897	+1,486	2.7
1981-82	4,062	2,209	789	1,020	+1,379	2.5
1982-83	4,986	2,830	+860	820	+888	2.8
1983-84	6,359	4,067	38	561	+211	3.1
1984-85	8,199	5,834	1,486	1,438	924	3.5
1985-86	7,520	4,799	+1,862	+1,688	+654	2.9
1986-87	9,269	6,107	516	667	+169	3.2
1987-88	11,219	7,742	+157	66	1,088	3.4
1988-89	11,672	8,884	425	+380	1,807	3.0
1989-90	15,433	11,645	255	161	3,682	3.4
1990-91	18,787	14,532	420	+72	5,309	3.5
1991-92	18,900	15,746	+340	96	5,650	3.1
1992-93(RE)	19,988	15,249	176	1,256	4,117	2.8
1993-94(BE)	23,707	17,298	N.A.	2,640	4,524	3.0

+ Indicates surplus.

* Data pertain to 23 States having accounts with Reserve Bank. The monetised deficit of States refers to loans and advances to State Governments by the RBI net of their deposits with the RBI.

N.A. : Not Available

RE : Revised Estimates

BE : Budget Estimates.

Source : Budget Documents of State Governments.

APPENDIX TABLE III.7 : FINANCING OF STATES, GROSS FISCAL DEFICIT

(Rupees crore)

Year	Loans from the Central Government (net)	Market Borrowings (net)	Others ++	Gross Fiscal Deficit (2+3+4)	States' Outstanding Liabilities (end -March)		
					Total *	Loans and Advances from the Centre	Market Loans
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	1,564 (42.1)	184 (5.0)	1,964 (52.9)	3,712 (100.0)	23,977	17,071	2,973
1981-82	2,000 (49.2)	339 (8.4)	1,723 (42.4)	4,062 (100.0)	27,729	19,080	3,328
1982-83	2,735 (54.8)	393 (7.9)	1,858 (37.3)	4,986 (100.0)	29,457	20,425@	3,735
1983-84	3,031 (47.7)	563 (8.8)	2,765 (43.5)	6,559 (100.0)	38,493	27,539@	4,408
1984-85	3,580 (43.7)	693 (8.4)	3,926 (47.9)	8,199 (100.0)	44,394	31,226@	5,100
1985-86	5,757 (76.6)	1,010 (13.4)	753 (10.0)	7,520 (100.0)	52,474	38,682@	6,104
1986-87	4,786 (51.6)	1,147 (12.4)	3,336 (36.0)	9,269 (100.0)	59,373	43,468@	7,257
1987-88	5,832 (52.0)	1,523 (13.6)	3,864 (34.4)	11,219 (100.0)	68,523	49,300@	8,779
1988-89	6,688 (57.3)	1,973 (16.9)	3,011 (25.8)	11,672 (100.0)	79,496	55,985@	10,712

1	2	3	4	5	6	7	8
1989-90	7,917 (51.3)	2,298 (14.9)	5,218 (33.8)	15,433 (100.0)	97,300	69,903 ^(a)	12,919
1990-91	9,978 (53.1)	2,556 (13.6)	6,253 (33.3)	18,787 (100.0)	1,08,203	73,852 ^(a)	15,474
1991-92	9,374 (49.6)	1,864 (9.9)	7,662 (40.5)	28,900 (100.0)	1,24,099	83,226 ^(a)	17,338
1992-93(RE)	9,118	2,214	8,656	19,988	1,40,079	92,344 ^(a)	19,452
	(45.6)	(11.1)	(43.3)	(100.0)			
1993-94(BE)	10,707 (43.1)	2,188 (9.2)	11,312 (47.7)	23,707 (100.0)	1,58,144	1,02,551 ^(a)	21,740

Figures in brackets are percentages to the Gross Fiscal Deficit.

†† Include reserve funds, deposits and advances, provident funds, loans from banks and financial institutions, etc.

* These include internal debt, loans and advances from the Central Government and provident funds etc.

@ Includes medium-term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given by the Centre to States to clear their overdraft.

RE : Revised Estimates. BE : Budget Estimates

Source : Budget Documents of State Governments.

APPENDIX TABLE III 8 : COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(Rupees crore)						
Item	1993-94 ^a (BE)	1992-93 (RE)	1992-93 (BE)	1991-92 (Accounts)	Percentage (3)/(5)	Variation (2)/(3)
1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts	2,22,066	2,06,019	2,00,475	1,88,505	9.3	7.8
A. Revenue Receipts	1,59,872	1,47,655	1,45,148	1,27,405	15.9	8.3
of which :						
Tax Receipts (a + b)	1,30,956	1,18,703	1,16,612	1,02,674	15.6	10.3
(a) Direct Taxes	26,000	23,086	21,404	19,040	21.3	12.4
(b) Indirect Taxes	1,04,956	95,617	95,208	83,634	14.3	9.8
B. Capital Receipts	62,194	58,364	55,327	61,000	—4.5	6.6
II. Total Disbursements (A + B + C)	2,29,920	2,14,477	2,05,776	1,95,456	9.7	6.8
A. Developmental Expenditure (a + b + c)	1,21,080	1,17,378	1,11,253	1,08,766	7.9	3.1
(a) Revenue	89,618	87,924	82,293	81,013	8.5	1.9
(b) Capital Outlay	19,363	18,269	18,008	16,221	12.6	6.0
(c) Loans and Advances	12,099	11,185	10,952	11,532	—3.0	8.0
B. Non-Developmental Expenditure (a + b + c)	98,069	85,720	85,640	72,956	17.5	14.4
(a) Revenue	91,339	79,525	79,262	67,333	18.2	14.9
(b) Capital	6,207	5,699	5,912	—	8.0	8.9
(c) Loans and Advances	523	496	466	378	31.2	8.3
C. Others	9,871	11,379	8,883	13,734	—17.1	—13.3
III. Overall Surplus (+)/Deficit(—)	—6,954	—8,458	—5,301	—6,951	21.7	—17.8

@ Includes Commercial Departments in respect of the Central Government's Revenue Account.

* Includes effect of Budget proposals.

Notes : 1. Regarding State Governments, data relate to 25 States, of which, 11 are from Vote-on-Account Budget.

2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and Panchayati Raj Institutions, appropriation to contingency funds and net remittances and are adjusted for difference in figures of repayments of loans by States to the Central Government given in their respective budgets.

RE : Revised Estimates. BE : Budget Estimates.

Source : Budget Documents of Government of India and State Governments.

APPENDIX TABLE U1.9 : DEVELOPMENTAL AND NON-DEVELOPMENTAL EXPENDITURE OF CENTRE AND STATES

(Rupees crore)

Year	Centre††			States				Centre and States Combined			
	Develop- mental Expendi- ture	Non- Develop- mental Expendi- ture	Total@	Develop- mental Expendi- ture	Non- Develop- mental Expendi- ture	Others*	Total	Develop- mental Expendi- ture	Non- Develop- mental Expendi- ture	Others**	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1980-81	13,932 (57.6)	10,245 (42.4)	24,177 (100.0)	15,961 (70.1)	4,289 (18.8)	2,520 (11.1)	22,770 (100.0)	25,845 (66.0)	11,977 (30.6)	1,338 (3.4)	39,160 (100.0)
1981-82	16,084 (60.9)	10,331 (39.1)	26,415 (100.0)	17,969 (70.2)	4,996 (19.6)	2,615 (10.2)	25,571 (100.0)	28,796 (64.7)	13,609 (30.6)	2,074 (4.7)	44,479 (100.0)
1982-83	17,557 (60.7)	12,673 (39.3)	32,230 (100.0)	20,649 (71.0)	5,883 (20.2)	2,565 (8.8)	29,097 (100.0)	33,643 (64.6)	16,473 (31.7)	1,941 (3.7)	52,057 (100.0)
1983-84	22,207 (58.8)	15,564 (41.2)	37,771 (100.0)	23,972 (71.2)	6,882 (20.4)	2,814 (8.4)	33,668 (100.0)	38,352 (63.9)	19,936 (33.3)	1,701 (2.8)	59,989 (100.0)
1984-85	27,375 (59.6)	18,525 (40.4)	45,900 (100.0)	27,958 (70.3)	8,340 (21.0)	3,443 (8.7)	39,746 (100.0)	46,265 (64.6)	23,390 (32.6)	1,999 (2.8)	71,654 (100.0)
1985-86	29,979 (58.9)	20,927 (41.1)	50,906 (100.0)	31,733 (70.7)	9,617 (21.4)	3,519 (7.9)	44,869 (100.0)	55,032 (65.1)	27,332 (32.4)	2,106 (2.5)	84,470 (100.0)
1986-87	35,498 (57.7)	26,060 (42.3)	61,558 (100.0)	35,827 (70.6)	11,220 (21.5)	4,149 (7.9)	52,196 (100.0)	64,441 (63.4)	33,682 (33.2)	3,479 (3.4)	1,01,602 (100.0)
1987-88	36,573 (54.7)	30,261 (45.3)	66,834 (100.0)	42,141 (70.2)	13,751 (22.9)	4,104 (6.9)	59,999 (100.0)	69,087 (62.2)	39,460 (35.5)	2,614 (2.3)	1,11,161 (100.0)
1988-89	41,536 (53.9)	35,579 (46.1)	77,115 (100.0)	47,064 (69.8)	15,803 (23.4)	4,599 (6.8)	67,466 (100.0)	78,983 (1.66)	45,940 (35.8)	3,322 (2.6)	1,28,745 (100.0)
1989-90	54,204 (56.9)	41,020 (43.1)	95,224 (100.0)	53,150 (69.2)	19,253 (25.1)	4,496 (5.7)	76,899 (100.0)	89,386 (60.5)	54,300 (36.8)	3,939 (2.7)	1,47,725 (100.0)
1990-91	58,645 (54.3)	49,367 (45.7)	1,08,012 (100.0)	62,831 (68.8)	23,162 (25.4)	5,295 (5.8)	91,288 (100.0)	98,151 (58.8)	63,973 (38.3)	4,759 (2.9)	1,66,883 (100.0)
1991-92	61,807 (54.0)	52,693 (45.0)	1,14,500 (100.0)	73,932 (64.3)	27,814 (24.2)	13,235 (11.5)	1,14,981 (100.0)	1,08,766 (55.7)	72,956 (37.3)	13,734 (7.0)	1,95,456 (100.0)
1992-93 (RE)	65,877 (51.2)	62,814 (48.8)	1,28,691 (100.0)	79,948 (65.2)	32,729 (26.7)	9,918 (8.1)	1,22,595 (100.0)	1,17,378 (54.7)	85,720 (40.0)	11,379 (5.3)	2,14,477 (100.0)
1993-94 (BE)	65,245 (48.0)	70,554 (52.0)	1,35,799 (100.0)	85,430 (64.0)	39,073 (29.3)	9,021 (6.7)	1,33,524 (100.0)	1,21,080 (52.9)	98,069 (42.8)	9,871 (4.3)	2,29,020 (100.0)

†† Includes Commercial Departments in respect of Central Government's Revenue Account.

@ Exclude discharge of internal and external debt.

* Comprise discharge of internal debts, repayment of loans to the Centre, appropriation for contingency and fund and remittances (net), compensation and assignments to Local Bodies and Panchayati Raj institutions.

** Comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignment to Local Bodies and Panchayat Raj institutions, appropriation for contingency funds, net remittances of State Governments and are adjusted for differences in the figures of repayments of loans by the State Governments to the Central Government given in their respective budgets.

† Regarding State Governments, data relate to 25 States, of which, 11 are from Vote-on-Account Budgets.

RE : Revised Estimates. BE : Budget Estimates.

Notes : 1. Figures in brackets represent percentages to respective total expenditure.

2. Figures for the Centre and States do not add up to the combined position due to inter-Governmental adjustments.

3. The figures for Centre's expenditure prior to 1989-90 do not take into account capital expenditure on railways and loans to States against small savings collections.

Source : Budget Documents of Government of India and State Governments.

APPENDIX TABLE III.10 : DIRECT AND INDIRECT TAX REVENUES OF THE CENTRE AND STATES

(Rupees crore)

Year	Centre (Gross)			States			Centre & States Combined			
	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2,907	10,242	13,149	686	5,929	6,615	3,593	16,171	19,764	
(a)	22.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	13.2	81.8	100.0	
(b)	2.1	7.6	9.7	0.5	4.4	4.9	2.7	11.9	14.6	
1984-85	4,626	18,802	23,428	1,230	11,108	12,338	5,856	29,910	35,766	
(a)	19.7	80.3	100.0	10.0	90.0	100.0	16.4	83.6	100.0	
(b)	20.0	8.2	10.2	0.6	4.8	5.4	2.5	13.0	15.5	
1985-86	5,563	23,109	28,672	1,401	12,919	14,320	6,964	36,028	42,992	
(a)	19.4	80.6	100.0	9.8	90.2	100.0	16.2	83.8	100.0	
(b)	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4	
1986-87	6,234	26,559	32,793	1,685	14,934	16,619	7,919	41,493	49,412	
(a)	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0	
(b)	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	14.1	16.8	
1987-88	6,751	30,861	37,612	1,969	17,438	19,407	8,711	48,299	57,010	
(a)	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0	
(b)	2.0	9.3	11.3	0.6	5.2	5.8	2.6	14.5	17.1	
1988-89	8,824	35,596	44,420	2,413	19,988	22,401	11,237	55,584	66,821	
(a)	19.9	80.1	100.0	10.8	89.2	100.0	16.8	83.2	100.0	
(b)	2.2	9.0	11.2	0.6	5.1	5.7	2.8	14.1	16.9	
1989-90	10,003	41,578	51,581	3,006	22,989	25,995	13,009	64,567	77,576	
(a)	19.4	80.6	100.0	11.6	88.4	100.0	16.8	83.2	100.0	
(b)	2.2	9.2	11.4	0.7	5.1	5.8	2.9	14.3	17.2	
1990-91	11,024	46,489	57,513	3,244	26,804	30,048	14,368	73,293	87,561	
(a)	19.2	80.8	100.0	10.8	89.2	100.0	16.3	83.7	100.0	
(b)	2.5	8.8	11.0	0.6	5.1	5.7	2.7	13.9	16.6	
1991-92*	15,100	52,066	67,266	3,840	31,567	35,407	19,040	83,633	1,02,673	
(a)	22.6	77.4	100.0	10.8	89.2	100.0	18.5	81.5	100.0	
(b)	2.5	8.5	11.0	0.6	5.2	5.8	3.1	13.7	16.8	
1992-93(RE)*	18,877	59,827	78,704	4,209	35,790	39,999	23,086	95,617	1,18,703	
(a)	24.0	76.0	100.0	10.5	89.5	100.0	19.4	80.6	100.0	
(b)	2.7	8.5	11.2	0.6	5.1	5.7	3.3	13.6	16.9	
1993-94(BE)*	21,261	63,527	84,788	4,739	41,429	46,168	26,000	1,04,956	1,30,956	
(a)	25.1	74.9	100.0	10.3	89.7	100.0	19.9	80.1	100.0	
(b)	2.7	8.1	10.8	0.6	5.3	5.9	3.3	13.4	16.7	

† Excluding State's share in Central taxes as reported in Centre's Budget Documents.

* Regarding State Governments, data relates to 25 States, of which, eleven are from Vote-on-Account Budgets.

Note : (a) Represents percentage to total tax revenue and (b) indicates tax to GDP ratio in percentages.

Source : Budget Documents of Government of India and State Governments.

APPENDIX TABLE III.11 : MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS, LOCAL AUTHORITIES AND INSTITUTIONS SPONSORED BY THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(Rupees crore)

Government/Authority	Gross Market Borrowings		Repayments		Net Market Borrowings	
	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
	1	2	3	4	5	6
1. Central Government	4,821	8,919	1,151	1,418	3,670	7,501
2. State Governments	3,805	3,364	334	..	3,471	3,364
3. Institutions Sponsored by Central Government	2,248	2,702	198	14	1,750	2,688
4. Institutions Sponsored by State Governments (including Local Authorities and State Land Development Banks)	1,223	1,200	102	104	1,120	1,096
5. Aggregate Market Borrowings	12,097	16,185	2,086	1,536	10,011	14,649

Source : Reserve Bank of India Records.

APPENDIX TABLE III.12 : COUPON RATES ON CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS SECURITIES

YEAR	Maturity Period in years	Central Government													State Governments			
		3	5	6	7	8	9	10	15	18	20	23	28	30	10	13	15	20
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1984-85			7.75	8.00				8.50			9.50		10.25	10.50			9.00	
1985-86			9.00		9.25			9.50			10.50	10.80		11.50		9.75		
1986-87			10.00		10.20			10.50		11.30	11.50						11.00	
1987-88								10.50	11.00		11.50						11.00	
1988-89			10.00			10.30		10.50	11.00		11.50							11.50
1989-90								10.50	11.00		11.50							11.50
1990-91			10.50					10.75	11.25		11.50							11.50
1991-92			10.50					10.75	11.25		11.50							11.50
			10.75					11.00	11.50		12.00							12.00\$
									12.50									12.50\$
1992-93			12.00	12.30	12.60	12.70		12.75										
1993-94		12.75+	13.00		13.25		13.40								13.50			

S Coupon rate raised to 12.00 and 12.50 per cent on October 3, 1991 and March 26, 1992, respectively.

+ Pre-announced.

Source : Reserve Bank of India Records.

[Table III.12 (ii)]

संकेत को संदर्भित : वर्ष 2019-20, 1994/अप्रैल 1, 1916

APPENDIX TABLE IV.1 : VARIATIONS IN MONEY STOCK (M3)—COMPONENTS AND SOURCES

(Rupees crores)

Item	Outstand- ing as on March 31, 1993*	Variations during**							
		1992-93*		1991-92		April-June			
						1993-94*		1992-93*	
		Amount	Perce- tage	Amount	Perce- tage	Amount	Perce- tage	Amount	Perce- tage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Broad Money (M3) (A+B+C)	3,62,665	45,184	14.2	51,653	19.4	18,391	5.1	19,452	6.1
A. Currency with the Public	68,512	7,414	12.1	8,050	15.2	6,088	8.9	2,763	4.
B. Aggregate Deposit with Banks (1+2)	2,92,650	37,152	14.5	43,392	20.5	9,171	3.1	11,690	4.6
C/W External deposits \neq	34,116	5,843	20.7	5,632	24.8	1,124	3.3	5,069	17.9
(i) All foreign currency deposits	23,500	5,061	24.8	4,824	30.9	499	2.0	4,291	21.0
(ii) NRE deposits	8,616	782	10.0	808	11.5	625	7.3	778	9.9
1. Demand Deposits	53,263	408	0.8	13,685	34.9	-873	-1.6	-711	-1.3
2. Time Deposits	2,39,387	36,744	18.1	29,707	17.2	10,044	4.2	12,401	6.1
C. 'Other' Deposits with the RBI	1,503	618	69.8	211	31.3	3,132	208.4	4,999	564.9
II. Narrow Money (M1) [A+B(1)+C]	1,23,278	8,440	7.3	21,946	23.6	8,347	6.8	7,051	6.1
III. SOURCES OF MONEY STOCK (M3) (1+2+3+4+5)									
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	1,76,089	17,826	11.3	18,070	12.9	13,654	7.8	6,442	1.1
A. RBI's net credit to Government (i)-(ii)	98,449	4,433	4.7	5,168	5.8	7,303	7.4	2,320	2.5
(i) Net claims on Central Government (a)-(b) \neq	96,523	4,257	4.6	5,508	6.3	9,201	9.5	3,913	4.2
(a) Claims on Central Government	97,621	3,273	3.5	5,904	6.7	8,158	8.4	1,906	2.0
(b) Deposits of Central Government	1,098	-984	-47.3	396	23.5	-1,043	-95.0	-2,067	-96.4
(ii) Net claims on State Governments (a)-(b)	1,926	176	10.1	-340	-16.3	-1,898	-98.5	-1,593	-91.0
(a) Claims on State Governments	1,926	176	10.1	-340	-16.3	-1,880	-97.6	-1,577	-90.1
(b) Deposits of State Governments	0	0	..	0	..	18	..	16	..
B. Other banks' credit to Government	77,640	13,393	20.8	12,902	25.1	6,351	8.2	4,122	6.4
2. Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	2,16,374	28,380	15.1	16,225	9.4	3,916	1.8	8,811	4.7
A. RBI's credit to commercial sector \neq	6,220	-1,040	-14.3	913	14.5	179	2.9	93	13
B. Other banks' credit to commercial sector	2,10,154	29,420	16.3	15,367	9.3	3,737	1.8	8,718	4.8
3. Net Foreign Exchange Assets of Banking Sector (A+B)*	25,681	3,809	17.4	11,291	106.7	1,681	6.5	849	3.9
		(2,369)	(10.8)	(9,577)	(90.5)	(462)	(1.8)	(1,649)	(4.8)
A. RBI's net foreign exchange assets	22,647	3,809	20.2	10,855	136.0	1,681	7.4	849	4.5
B. Other banks' net foreign exchange assets	3,034	0	0.0	436	16.8
4. Governments' Currency Liabilities to the Public	1,798	94	5.5	83	5.1	15	0.8	31	1.8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Banking Sector's Net Non-monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)		57,277	4,925	9.4	-5,934	-10.3	875	1.5	-3,319	-6.3
A. Net non-monetary liabilities of RBI +		28,056	641	2.3	393	1.5	-270	-1.0	-2,205	-8.0
B. Net non-monetary liabilities of other banks (residual)		29,221	4,284	17.2	-6,377	-20.4	1,145	3.9	-1,114	-4.5

* Provisional. —Includes special securities and for March 31, 1993, it includes an amount of Rs. 752 crore (equivalent of SDR 211.95 million) incurred on account of Reserve Assets Subscription made to the IMF towards Quota increase.

** Figures relate to scheduled commercial banks.

** Based on data pertaining to March 31 in respect of the Reserve Bank and the last reporting Friday of March in respect of scheduled commercial banks.

@ Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

—Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market price effective October 17, 1990. Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank's net non-monetary liabilities. Figures within brackets are net of such revaluation.

Note : Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

APPENDIX TABLE IV.2 : RESERVE MONEY—COMPONENTS AND SOURCES

(Rupees crore)

Item	Outstand- ing as on March 31, 1993*	Variations during*							
		1992-93*		1991-92		1993-94*		1992-93*	
		Amount	Perce- ntage	Amount	Perce- ntage	Amount	Perce- ntage	Amount	Perce- ntage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RESERVE MONEY (1+2+3+4)	1,10,943	11,438	11.5	11,726	13.4	3,833	3.5	6,008	6.1
1. Currency with the Public	68,512	7,414	12.1	8,050	15.2	6,088	8.9	2,763	4.5
2. 'Other' Deposits with RBI	1,503	618	69.8	211	31.3	3,132	208.4	4,999	564.9
3. Cash with Banks	2,788	148	5.6	406	18.2	107	3.8	305	11.6
4. Bankers' Deposits with RBI	38,140	3,258	9.3	3,059	9.6	-5,494	-14.4	-1,999	-5.7
SOURCES OF RESERVE MONEY (1+2+3+4+5+6)									
1. Net RBI credit to Government									
of which:	98,449	4,433	4.7	5,168	5.8	7,303	7.4	2,320	2.5
To Central Government +	96,523	4,257	4.6	5,508	6.3	9,201	9.5	3,913	4.2
2. RBI's claims on commercial and co-operative banks@	9,885	4,783	93.7	-4,905	-49.0	-5,615	-56.8	570	11.2
3. RBI's credit to commercial sector	6,220	-1,040	-14.3	918	14.5	179	2.9	93	1.3
4. Net foreign exchange assets of RBI**	22,647	3,809 (2,369)	20.2 (12.6)	10,855 (9,141)	136.0 (114.5)	1,681 (462)	7.4 (2.0)	849 (1,049)	4.5 (5.6)
5. Government's currency liabilities to the public	1,798	94	5.5	83	5.1	15	0.8	31	1.8
6. Net non-monetary liabilities of RBI**	28,056	641	2.3	393	1.5	-270	-1.0	-2,025	-8.0
Net Domestic Assets of the RBI	88,296	7,629	9.5	871	1.1	2,152	2.4	5,219	6.5

*Provisional. @Including NABARD. S—Based on data pertaining to March 31. —Includes special securities and for March 31, 1993 it includes an amount of Rs. 752 crore (equivalent of SDR 211.95 million) incurred on account of Reserve Assets subscription made to the IMF towards Quota increase.

** Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market prices effective October 17, 1990. Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank's net non-monetary liabilities. Figures within brackets are exclusive of such revaluation.

APPENDIX IV.3 : TRENDS IN INCOME VELOCITY OF CURRENCY, AGGREGATE

DEPOSITS, M1 AND M3

Year	Averages* (Rupees crore)				Income Velocity Ratios			
	Currency (C)	Aggregate (Deposits (AD))	M1	M3	GDP/C	GDP/AD	GDP/M1	GDP/M3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987-88	31,490	1,21,744	53,039	1,53,546	10.563	2.732	6.155	2.166
1988-89	35,934	1,43,556	61,877	1,79,884	10.992	2.751	63.84	2.196
1989-90	42,678	1,70,554	74,370	2,13,807	10.558	2.642	6.059	2.108
1990-91	50,046	1,98,066	87,375	2,49,282	10.581	2.674	6.061	2.124
1991-92	57,675	2,33,125	1,04,194	2,92,260	10.568	2.614	5.850	2.085
1992-93 @	64,802	2,76,512	1,20,407	3,45,376	10.848	2.542	5.839	2.035

@ Provisional

*Average of reporting Fridays of the year.

APPENDIX TABLE IV.4 : MONETARY RATIOS

Item	1992-93 @	1991-92	1990-91	1989-90	1988-89	1987-88
1	2	3	4	5	6	7
Point-to-point basis						
(Incremental Ratios)						
(a) Currency /Aggregate Deposits (C/AD)	0.234	0.239	0.241	0.269	0.198	0.298
(b) Currency/M3 (C/M3)	0.189	0.192	0.193	0.213	0.163	0.229
(c) Aggregate Deposits/M3 (AD/MC)	0.807	0.805	0.804	0.790	0.827	0.768
(d) Broad Money Multiplier (MC/RM)	3.269	3.191	3.423	2.560	3.086	2.608
(e) Narrow Money Multiplier (M1/RM)	1.111	1.154	1.161	0.975	0.869	0.811
(f) Bank Reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.140	0.147	0.120	0.228	0.182	0.197
Average basis						
(Incremental Ratios)						
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.234	0.262	0.268	0.250	0.204	0.244
(b) Currency/M3 (C/M3)	0.188	0.209	0.208	0.199	0.169	0.196
(c) Aggregate Deposits/M3 (AD/M3)	0.801	0.798	0.776	0.796	0.828	0.802
(d) Broad Money Multiplier (M3/RM)	3.200	3.109	3.026	3.150	3.127	2.482
(e) Narrow Money Multiplier (M1/RM)	1.116	1.108	1.109	1.163	0.930	0.772
(f) Bank Reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.141	0.150	0.116	0.138	0.179	0.255

@ Provisional.

- Note : 1. On a point-to-point basis, the ratios are based on March 31 data while on an average basis, the ratios have been worked out on the basis of average of reporting Fridays of the year. All ratios in this table are incremental ratios.
2. On a point-to-point basis, the ratios presented here differ from those given in the earlier Reports as the basis for them was the last reporting Friday of March.

APPENDIX TABLE IV.5 : IMPORTANT BANKING INDICATORS—SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Rupees crore)

Item	Outstanding as on March 1993	Variations during				
		1992-93	1991-92	1990-91	April-Jun	
					1993-94*	1992-93
1	2	3	4	5	6	7
1. Total Demand and Time Liabilities (excluding borrowings from RBI/IDBI/NABARD)	2,97,709	45,914	39,709	26,241	10,428	16,389
2. Aggregate Deposits (a + b)	2,68,572	37,814	38,216	25,583	8,664	12,256
(a) Demand Deposits	46,461	1,373	11,895	4,337	-744	159
(b) Time Deposits	2,22,111	36,441	26,321	21,246	9,407	12,097
3. Borrowings from RBI	1,619	1,042	-2,891	-1,069	-1,020	1,039
4. Bank Credit (a + b)	1,51,982	26,390	9,291	14,848	3,534	8,052
(a) Food Credit	6,743	2,073	164	2,500	2,833	431
(b) Non-food Credit	1,45,239	24,317	9,127	12,348	701	7,621
5. Investments (a + b)	1,05,656	15,460	15,131	10,696	6,137	4,291
(a) Government Securities	75,945	13,218	12,729	7,706	6,233	4,076
(b) Other Approved Securities	29,711	2,242	2,402	2,990	-97	215
6. Cash in hand	2,293	285	204	155	114	370
7. Balances with RBI	28,535	-5,644	10,318	398	3,052	-2,226
8. Credit-Deposit Ratio (%) ^(a)	56.6	56.6	54.4	60.4	56.1	55.0
9. Non-food Credit-Deposit Ratio (%) ^(b)	54.1	54.1	52.4	58.1	52.6	56.1

* Provisional.

(a) Ratios relate to outstandings as on respective last reporting Fridays.

Notes : 1. Figures in parentheses are percentage variations.

2. Constituent items may not add up to the totals due to rounding off.

3. No sign is indicated for positive variations.

APPENDIX TABLE IV.6 : VARIATIONS IN SELECTED ITEMS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS—LAST WEEK OF MARCH

(Rupees crore)

Item	Outstanding as on							Variations						
	March 20 1992	March 19 1993	March 26 1993	March 31 1993	April 2 1993	April 16 1993	April 30 1993	March 19 1993 over March 20, 1992	March 26 1993 over March 19, 1993	March 31 1993 over March 26, 1993	March 31 1993 over March 19, 1993	April 2 1993 over March 31, 1993	April 16 1993 over April 2, 1993	April 30, 1993 over April 16, 1993
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Aggregate Deposits (a + b)	2,30,758	2,68,572	2,74,938	2,81,085	2,79,860	2,75,539	2,75,502	37,814 (16.4)	6,366 (2.4) [16.8]	6,147 (2.2) [16.3]	12,513 (4.7) [33.1]	—1,225 (0.4) [3.2]	—4,321 (—1.5) [11.4]	—37 (0.0) [0.1]
(a) Demand Deposits	45,088	46,461	49,541	53,908	52,761	48,655	47,455	1,373 (3.0)	30.80 (6.6) [224.3]	4,367 (8.8) [318.1]	7,447 (16.0) [542.4]	—1,147 (—2.1) [83.5]	—4,106 (—7.8) [229.1]	—1,200 (—2.5) [87.4]
(b) Time Deposits	1,85,670	2,22,111	2,25,397	2,27,177	2,27,099	2,26,884	2,28,047	36,441 (19.6)	3,286 (1.5) [9.0]	1,780 (0.8) [4.9]	5,066 (2.3) [13.9]	—78 (0.0) [0.2]	—215 (—0.1) [0.6]	1,163 (0.5) [3.3]
2. Bank Credit (a + b)	1,25,592	1,51,982	1,54,838	1,59,356	1,58,763	1,57,832	1,55,819	26,390 (21.0)	2,856 (1.9) [10.8]	4,518 (2.9) [17.1]	7,374 (4.9) [27.9]	—593 (—0.4) [2.2]	—931 (—0.6) [3.5]	—2,013 (—1.5) [7.6]
(a) Food Credit	4,670	6,743	6,788	7,010	7,010	6,588	7,412	2,073 (44.4)	45 (0.7) [2.2]	222 (3.3) [10.7]	267 (4.0) [12.9]	0 (0.0) [0.0]	—422 (—6.0) [20.4]	824 (12.5) [39.7]
(b) Non-Food Credit	1,20,922	1,45,239	1,48,050	1,52,346	1,51,753	1,51,244	1,48,407	24,317 (20.1)	2,811 (1.9) [11.6]	4,296 (2.9) [17.7]	7,107 (4.9) [29.2]	—593 (0.4) [2.4]	—509 (—0.3) [2.1]	—2,837 (—1.9) [—11.7]

Notes : 1. Figures in parentheses indicate percentage variations.

2. Figures in square brackets indicate absolute variation as percentage of financial year variation.

3. No sign is indicated for positive variations.

APPENDIX TABLE IV.7 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' NON-DEPOSIT RESOURCES

(Rupees crore)

Item	Outstanding as on last Reporting Friday of March			Variations	
	1993	1992	1991	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6
1. Aggregate Deposits	2,68,572	2,30,758	1,92,542	37,814 (16.4)	38,216 (19.8)
2. Gross Demand and Time Liabilities (DTL)	2,97,709	2,51,795	2,12,086	45,914 (18.2)	39,709 (18.7)
3. Assets with the Banking System	11,043	7,927	5,582	3,116 (39.3)	2,345 (42.0)
4. Gross DTL excluding inter-bank assets (2-3)	2,86,666	2,43,868	2,06,504	42,798 (17.5)	37,364 (18.1)
5. Difference (4-1)	18,094	13,110	13,962	4,984 (38.0)	-852 (-6.1)
6. Other Borrowings	112	362	470	-250 (-69.1)	-108 (-23.0)
7. Bills Rediscounted with Financial Institutions	779	3,874	3,479	-3,095 (-79.9)	395 (11.4)
8. Non-Deposit Resources (5+7)	18,873	16,984	17,441	1,889 (11.1)	-457 (-2.6)
Memorandum Item: Call Money Borrowings from UTI, LIC, DFI, HFC	8,203	1,212	2,275	6,991 (576.8)	-1,063 (-46.7)

Figures in parentheses are percentage variations.

① Figures for March 1991, March 1992 and March 1993 include borrowings from IDBI, NABARD and 'Others'.

APPENDIX TABLE IV.8 : SECTORAL DEVELOPMENT OF GROSS BANK CREDIT BY MAJOR SECTORS

(Rupees crore)

Sector	Outstanding as on			Variations during	
	Mar. 19 1993	Mar. 20 1992	Mar. 22 1991	April-March 1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6
I. Gross Bank Credit (1+2)	1,47,071	1,26,005	1,18,019	21,066	7,986
1. Public Food Procurement Credit	6,743	4,670	4,506	2,073	164
2. Non-food Gross Bank Credit	1,40,328	1,21,335	1,13,513	18,993 (100.0)	7,822 (100.0)
(A) Priority Sectors	49,758 [35.0]	45,425 [38.7]	42,915 [39.3]	4,383 (22.8)	2,510 (32.1)
(i) Agriculture	19,884 [14.0]	18,157 [15.5]	16,750 [15.3]	1,727 (9.1)	1,407 (18.0)
(ii) Small Scale Industries	20,027	18,150	17,181	1,877 (9.9)	969 (12.4)
(iii) Other Priority Sectors	9,847	9,118	8,984	729 (3.8)	134 (1.7)
(B) Industry (Medium and Large)	58,627	47,090	44,508	11,537 (60.7)	2,582 (33.0)
(C) Wholesale Trade (other than food procurement)	6,909	6,154	5,910	755 (4.0)	244 (3.1)
(i) Cotton Corpn. of India	224	208	91	16 (0.1)	117 (1.5)
(ii) Food Corpn. of India (for fertiliser distribution)	24①	21	212	3 (0.0)	-191 (-2.4)
(iii) Jute Corpn. of India	122	70	62	52 (0.3)	8 (0.1)
(iv) Other Trade	6,539	5,855	5,545	684 (3.6)	310 (4.0)
(D) Other Sectors	25,034	22,666	20,180	2,368 (12.5)	2,486 (31.8)
II. Export Credit [included under item 1(2)]	15,348	10,294	9,186	5,054 (26.6)	1,108 (14.2)
III. Net Bank Credit (including inter-bank participations)	1,42,149	1,17,443	1,09,298	24,706	8,145

① Represents penal interest charged by banks pending waiver.

Notes : 1. Data are provisional and relate to 48 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of bank credit of all scheduled commercial banks. Gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank and other approved financial institutions and inter-bank participations. Net bank credit data are exclusive of bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank and other approved financial institutions.

2. Figures in parentheses are proportions to incremental non-food bank credit.

3. Figures in square brackets are proportions to net bank credit (including inter-bank participations) given in item III.

APPENDIX TABLE IV.9 : INDUSTRY-WISE DEVELOPMENT OF GROSS BANK CREDIT^(a)

(Rupees crore)

Industry	Outstanding as on			Variations during	
	Mar. 19	Mar. 20	Mar. 26	April-March	
	1993	1992	1991	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5	6
Industry (Total of Small, Medium and Large Scale)	78,654	65,240	61,689	13,414	3,551
1. Coal	341	246	229	95	17
2. Iron and Steel	5,691	3,692	3,292	1,999	400
3. Other Metals and Metal Products	2,691	2,312	2,227	379	85
4. All Engineering	17,065	14,842	13,931	2,223	911
Of which : Electronics	2,308	2,092	1,874	216	218
5. Electricity generation and transmission	1,405	1,298	1,152	107	146
6. Cotton Textiles	4,665	4,278	4,073	387	205
7. Jute Textiles	349	330	339	19	-9
8. Other Textiles	4,647	3,970	3,761	677	209
9. Sugar	1,254	899	639	355	260
10. Tea	791	658	608	133	50
11. Food Processing	1,423	1,241	1,216	182	25
12. Vegetable Oil (including Vanaspati)	1,015	898	865	117	33
13. Tobacco and Tobacco Products	741	550	391	191	159
14. Paper and Paper Products	1,590	1,501	1,482	89	19
15. Rubber and Rubber Products	1,186	1,077	989	109	88
16. Chemicals, Dyes, Paints, etc.	10,114	8,280	7,743	1,834	537
Of which :					
(i) Fertilizers	1,715	1,357	1,309	358	48
(ii) Petro-chemicals	943	614	680	329	-66
(iii) Drugs & Pharmaceuticals	1,316	1,127	987	189	140
17. Cement	1,099	986	899	113	87
18. Leather and Leather Products	1,092	1,086	998	6	88
19. Gems and Jewellery	1,601	1,300	1,236	301	64
20. Construction	1,566	1,344	1,321	222	23
21. Petroleum	436	19	54	417	-35
22. SAFAUNS*	46	68	87	-22	-19
23. Other Industries	17,846	14,365	14,157	3,481	208

^(a) Provisional. *Ships acquired from abroad under new scheme.APPENDIX TABLE IV.10 : RESERVE BANK'S ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS^(a)

(Rupees crore)

As on last Reporting Friday of	Export Credit Refinance						Government Securities Refinance		Grand Total	
	Rupee Denominated		Dollar Denominated		Total		Limit	Out- standing	Limit	Out- standing
	Limit	Out- standing	Limit	Out- standing	Limit	Out- standing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1992										
March	5,564.21	494.30	30.10	0.57	5,594.31	494.87	5,594.31	494.87
June	6,939.32	1,467.05	224.02	64.78	7,163.34	1,531.83	7,163.34	1,531.83
July	7,136.22	1,405.32	519.39	157.04	7,655.61	1,562.36	7,655.61	1,562.36
September	5,561.06	722.69	1,993.23	363.64	7,554.29	1,086.33	7,554.29	1,086.33
December	4,797.66	2,295.36	3,347.45	1,371.78	8,145.11	3,667.14	1,027.79	..	9,172.90	3,667.14
1993										
March	5,834.15	994.19	4,567.64	556.01	10,401.79	1,550.20	1,027.79	..	11,429.58	1,550.20
June	6,548.36	194.34	4,679.09	343.24	11,227.45	537.58	1,027.79	..	12,255.24	537.58
July	6,743.28	316.34	4,818.95	690.40	11,562.23	1,006.74	1,027.79	..	12,590.02	1,006.74

^(a) : Excluding special refinance against shipping loans, duty drawback, etc.

APPENDIX TABLE IV.11 : RESERVE BANK'S REFINANCE TO DISCOUNT AND FINANCE HOUSE OF INDIA LTD.

As on the last day of	(Rupees crore)											
	Refinance Against the Collaterals of Treasury Bills Sold Through Auctions				Refinance Against Short-Term Commercial Bills				Refinance Against Dated Securities of the Central Government			
	Limit	Outstand- ing	Peak level utilisation during the month	Limit corres- ponding to the peak utilisation as in col. 4	Limit	Outstand- ing	Peak level utilisation during the month	Limit corres- ponding to the peak utilisation as in col. 8	Limit	Outstand- ing	Peak level utilisation during the month	Limit corres- ponding to the peak utilisation as in col. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1992 March	600.00	Nil	580.48 (28-3-92)	600.00	50.00	Nil	50.00 (27-3-92)	50.00
June	100.00	26.55	87.75 (19-5-92)	100.00	200.00	151.20	200.00 (22-6-92)	200.00	100.00	28.00	100.00 (27-6-92)	100.00
September	100.00	3.15	100.00 (7-9-92)	100.00	100.00	Nil	..	100.00	100.00	Nil	..	100.00
December	100.00	57.69	57.69 (30-12-92)	100.00	100.00	Nil	..	100.00	100.00	Nil	100.00 (3-12-92)	100.00
1993 March	300.00	Nil	288.91 (22-3-93)	300.00	100.00	Nil	100.00 (27-3-93)	100.00	100.00	Nil	41.85 (30-3-93)	100.00
June	100.00	Nil	Nil	100.00	100.00	Nil	Nil	100.00	100.00	Nil	Nil	100.00
July	100.00	Nil	Nil	100.00	100.00	Nil	Nil	100.00	100.00	Nil	Nil	100.00

APPENDIX TABLE IV.12 : CUMULATIVE TURNOVER OF THE DISCOUNT AND FINANCE HOUSE OF INDIA LTD. IN MONEY MARKET INSTRUMENTS

Instrument	Fiscal Year		During the year 1993-94 (up to August 13, 1993)	During the year 1992-93 up to August 14, 1992
	1992-93	1991-92		
1	2	3	4	5
1. Call Funds (including Notice Funds)	4,57,013	2,94,373	1,93,258	1,78,528
2. Treasury Bills	16,019	23,413	3,532	10,325
3. Commercial Bills	786	6,995	16	563
4. Certificates of Deposit	33	22	119	6
5. Commercial Paper	—	42	—	—
6. Term Deposits	3,797	5,959	991	2,341
7. Dated Central Government Securities	18,645	—	12,534	3,583

APPENDIX TABLE IV.13 : INTEREST RATES FOR RESERVE BANK REFINANCE TO DISCOUNT AND FINANCE HOUSE OF INDIA LTD.

(per cent per annum)					
Refinance Against Holdings of Treasury bills sold through Auctions		Refinance Against Commercial Bills		Refinance Against Dated Securities	
Effective Date	Rate of Interest	Effective Date	Rate of Interest	Effective Date	Rate of Interest
1	2	3	4	5	6
1992		1992		1992	
July	1 10.00	July	1 17.00	July	1 12.00
		July	11 15.00		
September	19 11.00				
	21 10.00				
1993					
February	12 11.00				
	13 10.00				
March	15 11.00				
	16 10.00				
	20 11.00				
	22 12.00				
April	3 10.00				

APPENDIX TABLE IV.14 : CALL MONEY LENDING RATES OF DISCOUNT AND FINANCE HOUSE OF INDIA LTD.

For the fortnight ended	Lending rate			For the fortnight ended	Lending rate		
	Trough	Peak	Average of middle rate*		Trough	Peak	Average of middle rate*
1	2	3	4	5	6	7	8
1991				1992			
July	12 10.25	38.50	23.40	July	10 3.00	18.50	12.70
	26 5.00	27.00	14.05		24 1.25	16.50	8.70
August	9 5.00	17.50	12.60	August	7 3.50	12.50	9.20
	23 9.00	15.00	13.40		21 3.00	12.50	8.65
September	6 3.50	15.00	10.95	September	4 3.00	12.50	9.10
	20 3.00	14.50	10.85		18 3.00	12.00	10.15
October	4 5.00	50.00	18.60	October	2 2.00	14.00	10.10
	18 4.00	35.25	19.65		16 3.50	13.00	10.55
					30 3.00	13.25	8.40

1	2	3	4	5	6	7	8
November 1	10.00	24.50	14.90				
15	15.00	36.00	23.25	November 13	4.50	11.75	10.20
29	3.00	36.00	20.55	27	1.50	12.75	8.45
December 13	2.00	21.00	9.35	December 11	5.00	10.75	8.40
27	3.50	16.25	9.60	25	9.00	11.75	10.05
1992				1993			
January 10	3.25	16.25	9.95	January 8	10.25	13.00	11.25
24	4.00	10.75	9.25	22	5.00	11.75	10.65
February 7	2.75	10.00	8.40	February 5	3.00	11.50	9.80
21	3.00	10.00	8.30	19	5.00	12.25	10.70
March 6	4.50	9.75	8.75	March 5	10.50	12.50	11.30
20	2.00	20.25	10.30	19	5.00	13.50	11.85
April 3	6.00	15.00	26.70	April 2	5.00	25.00	16.55
17	4.00	36.50	18.00	16	2.00	20.00	10.00
				30	4.00	10.75	8.30
May 1	20.00	86.00	42.05				
15	6.00	51.00	34.15	May 14	2.50	10.50	6.65
29	3.50	36.00	17.05	28	3.25	10.25	6.50
June 12	4.50	16.50	11.45	June 11	5.00	9.25	6.40
26	5.00	22.00	15.00	25	3.00	8.25	5.45
July 10	3.00	18.50	12.70	July 9	4.25	8.00	5.55
24	1.25	16.50	8.70	23	3.50	6.75	5.30
August 7	3.50	12.50	9.20	August 6	1.25	6.50	4.30
21	3.00	12.50	8.65	20	2.00	6.00	5.20

*This is a simple average of daily middle rates.

APPENDIX TABLE IV.15 : ISSUE OF CERTIFICATES OF DEPOSIT (CDs)
BY SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

Fortnight ended	Number of banks which issued CDs	Total Outstanding (Rupees crore)	Effective interest rate (range) of CDs (per cent per annum)
1	2	3	4
1992			
July 10	53	7,308	13.50—17.75
24	52	7,800	13.00—19.76
August 7	52	8,160	13.00—17.30
21	52	8,145	13.50—17.30
September 4	51	8,187	13.50—17.30
18	51	8,249	13.00—20.00
October 2	51	8,469	13.50—17.24
16	50	8,520	13.00—17.50
30	49	8,458	13.00—17.30
November 13	49	9,044	13.00—17.30
27	49	9,332	13.00—17.19
December 11	49	9,380	13.00—17.19
25	48	9,955	12.25—17.50
1993			
January 8	51	10,016	13.50—17.50
22	51	9,962	13.50—16.50
February 5	50	10,261	13.00—17.20
19	50	10,106	13.06—17.19
March 5	51	10,163	12.50—17.19
19	51	9,803	12.50—16.50
April 2	51	9,885	13.00—18.00
16	51	10,319	12.50—17.25
30	50	10,648	11.50—17.00
May 14	50	10,797	12.00—17.00
28	49	11,267	12.00—16.00
June 11	50	11,744	12.00—16.50

APPENDIX TABLE IV.16 : AUCTIONS OF 364-DAY GOVERNMENT OF INDIA TREASURY BILLS

(Rupees crore)

Date of Auction		Date of Issue		Bids Tendered		Bids Accepted		Cut-off price (per cent)	Implicit yield at cut-off price (per cent)	Amount outstanding as on the date of issue +	
				No.	Total Face Value	No.	Total Face value			Before Funding	After Funding
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1992											
April	28	April	30	75	1,128.65	53	666.15	89.75	11.4206	666.15	3,43
May	13	May	15	57	1,396.48	44	961.48	89.75	11.4206	1,627.63	176.76
	27		29	60	1,087.23	41	797.75	89.75	11.4206	2,425.38	333.01
June	9	June	11	43	537.64	33	412.64	89.75	11.4206	2,838.02	378.11
	24		26	85	1,756.16	66	1,474.16	89.75	11.4206	4,312.18	755.76
July	7	July	10	26	589.00	10	387.00	89.80	11.3586	4,699.18	786.26
	22		24	56	1,979.65	16	854.60	89.87	11.2718	5,553.78	860.86
August	5	August	7	67	1,623.35	21	795.85	89.93	11.1976	6,349.63	1,009.36
	19		21	55	997.80	35	810.00	89.95	11.1729	7,159.63	1,255.36
September	2	September	4	17	163.00	12	139.50	89.95	11.1729	7,299.13	1,262.85
	16		18	25	318.00	15	43.00	89.95	11.1729	7,342.13	1,274.86
	29	October	1	13	165.60	10	130.60	89.85	11.2966	7,472.73	1,291.46
October	13		16	16	337.00	10	264.00	89.85	11.2966	7,736.73	1,305.46
	28		30	18	1162.80	10	69.80	89.85	11.2966	7,806.53	1,306.93
November	11	November	13	26	265.00	3	20.00	89.86	11.2842	7,826.53	1,306.93
	25		27	49	485.11	9	75.11	89.88	11.2595	7,901.64	1,326.93
December	8	December	11	5	40.00	2	20.00	89.91	11.2223	7,921.64	1,346.93
	22		24	35	591.60	19	451.60	89.91	11.2223	8,373.24	1,470.43
1993											
January	6	January	8	32	340.00	4	45.00	89.95	11.1729	8,418.24	1,510.43
	19		22	22	131.02	2	6.00	90.00	11.1111	8,424.24	1,510.43
February	3	February	5	24	426.00	2	53.00	90.12	10.9632	8,477.24	1,513.43
	17		18	18	151.00	14	134.00	90.08	11.0124	8,611.24	1,577.43
March	3	March	5	10	42.50	9	41.50	90.05	11.0494	8,652.74	1,613.93
	17		19	29	363.50	21	124.00	90.00	11.1111	8,776.74	1,653.93
	31	April	2	17	77.00	4	20.00	90.01	11.0988	8,796.74	1,673.93
April	13		16	61	1,132.00	22	585.00	90.10	10.9878	9,381.74	2,258.93
	28		30	15	219.85	12	204.85	90.10	10.9878	8,920.44	2,460.35
May	13	May	14	28	223.75	23	156.75	90.05	11.0494	8,115.71	2,443.77
	26		28	26	229.20	26	229.20	89.90	11.2347	7,547.16	2,516.72
June	9	June	11	24	258.20	19	219.20	89.87	11.2718	7,353.72	2,690.82
	23		25	53	539.00	50	509.00	89.80	11.3586	6,358.56	2,822.17
July	7	July	9	31	448.00	23	367.00	89.80	11.3586	6,358.56	3,158.67
	21		23	54	1,313.00	46	1,052.00	89.80	11.3586	6,565.96	4,136.07
August	4	August	6	60	1,154.00	54	1,044.00	89.80	11.3586	6,814.11	5,031.57
	18		20	59	1,572.50	35	902.25	89.82	11.3338	6,906.36	5,687.82

+ As on April 19, 1993, bills for an aggregate face value of Rs. 7,122.81 crore maturing in 1993-94 were converted into 12.75 per cent Government Stock, 1996.

APPENDIX TABLE IV.17 : AUCTIONS OF 91-DAY GOVERNMENT OF INDIA TREASURY BILLS

											(Rupees crore)		
Date of Auction		Date of Issue	Notified Amount	Bids Tendered No.	Total face Value	Bids Accepted No.	Total face Value	Subscription by RBI	Cut-off price (per cent)	Implicit yield at cut-off price (per cent)	Amount outstanding as on the date of issue		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1993													
January	8	January	9	250	10	226.00	4	50.50	199.50	97.80	8.9980	250.00	199.50
	15		16	100	4	11.00	3	6.00	94.00	97.78	9.0816	350.00	293.40
	22		23	100	6	86.00	4	6.00	94.00	97.65	9.6262	450.00	387.50
	29		30	100	4	31.00	4	31.00	69.00	97.62	9.7521	550.00	456.50
February	5	February	6	100	5	7.85	4	7.35	92.65	97.60	9.8361	650.00	549.15
	12		13	100	27	93.25	19	66.75	33.25	97.55	10.0461	750.00	582.40
	18		20	100	4	1.00	0	0.00	100.00	97.60	9.8361	850.00	682.40
	26		27	100	6	8.00	6	8.00	92.00	97.50	10.2564	950.00	774.40
March	5	March	6	100	6	2.50	6	2.50	97.50	97.45	10.4669	1,050.00	871.90
	12		13	100	9	7.00	6	4.50	95.50	97.40	10.6776	1,150.00	967.40
	19		20	100	2	10.50	2	10.50	89.50	97.35	10.8885	1,250.00	1,056.90
	26		27	100	3	10.00	3	10.00	90.00	97.33	10.9730	1,350.00	1,146.90
April	2	April	3	100	11	73.50	10	73.00	27.00	97.30	11.0997	1,450.00	1,173.90
	8		10	150	18	220.00	8	150.00	0.00	97.38	10.7620	1,350.00	974.40
	16		17	200	47	770.00	8	200.00	0.00	97.68	9.5004	1,450.00	880.40
	22		23	150	11	180.00	5	140.00	10.00	97.68	9.5004	1,500.00	796.40
May	29	May	30	125	4	20.00	4	20.00	105.00	97.60	9.8361	1,525.00	832.40
	7		8	50	10	121.00	5	50.00	0.00	97.62	9.7521	1,475.00	739.75
	14		15	50	16	120.00	3	50.00	0.00	97.65	9.6262	1,425.00	706.50
	21		22	50	9	50.00	8	45.00	5.00	97.63	9.7101	1,375.00	611.50
June	28	June	29	75	16	123.00	9	74.50	0.50	97.62	9.7521	1,350.00	520.00
	4		5	100	12	87.00	12	87.00	13.00	97.58	9.9201	1,350.00	435.50
	11		12	100	20	245.00	8	100.00	0.00	97.57	9.9621	1,350.00	340.00
	18		19	100	18	185.00	12	100.00	0.00	97.55	10.0461	1,350.00	250.50
July	25	July	26	100	30	219.00	11	87.00	13.00	97.54	10.0882	1,350.00	173.50
	2		3	100	32	312.00	15	100.00	0.00	97.55	10.0461	1,350.00	1203.50
	9		10	100	26	351.00	9	100.00	0.00	97.56	10.0041	1,300.00	1153.50
	16		17	150	34	526.00	5	150.00	0.00	97.60	9.8361	1,250.00	1103.50
August	23	August	24	250	48	756.00	24	250.00	0.00	97.60	9.8361	1,350.00	1213.50
	30		31	250	49	1,043.00	23	250.00	0.00	97.62	9.7521	1,475.00	1,443.50
	6		7	350	60	1,260.40	4	350.00	0.00	97.69	9.4585	1,775.00	1,743.50
	13		14	450	65	1,627.00	33	450.00	0.00	97.72	9.3328	2,175.00	2,143.50
August	20	August	21	500	36	1,879.00	18	500.00	0.00	97.74	9.2490	2,625.00	2,598.50
													26.53

APPENDIX TABLE IV.18 : AUCTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES

(Rupees crore)

Date of Auction		Date of Subscription		Notified Amount	Maturity Period (years)	Bids Tendered		Bids Accepted		Subscription by RBI	Cut-off price/yield (per cent)
						Number	Amount	Number	Amount		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1992											
June	3	June	5	1,000.00	5	100	1,479.05	21	713.25	286.75	12.00
August	3	August	5	1,000.00	10	80	1,390.50	56	646.30	353.50	12.75
December	1	December	3	1,000.00	6	82	660.50	26	261.25	738.75	12.30
1993											
February	1	February	3	1,000.00	7	76	770.56	59	628.56	371.44	12.60
	26	February	27	820.85*	8	59@	575.00@	20@	357.29\$	463.56**	12.70
June	3	June	4	1,000.00	5	62	1,212.00	41	1,000.00	0.00	13.00
	15	June	16	1,000.00	9	74	1,037.00	22	565.20	434.80	13.40
July	27	July	28	1,000.00	7	86	1,393.00	52	1,000.00	0.00	13.25

* The total amount subscribed by cash is Rs. 675.40 crore and that by conversion is Rs. 145.45 crore.

@ These figures represent competitive bids.

\$ This amount includes Rs. 18.29 crore by conversion and the remaining by cash.

** This amount includes Rs. 127.16 crore by conversion and the remaining by cash.

APPENDIX TABLE IV.19 : AUCTIONS OF REPOS BY THE RESERVE BANK

(Rupees crore)

Date of Auction		Date of Sale		Repo Period (No. of days)	Bids Tendered		Bids Accepted		Cut-off Repo rate (per cent)
					No.	Total Face Value	No.	Total Face Value	
1		2		3	4	5	6	7	8
1992									
December	10	December	11	1	13	2,120	13	2,120	6.00
	17		18	1	66	10,595	29	6,075	9.25
	23		24	2	49	8,295	49	8,295	12.50
	31	January	1993	1	56	11,519	26	3,130	11.50
1993									
January	7	January	8	1	54	7,163	19	2,743	8.00
	14		15	1	25	2,587	3	402	10.50
	19		22	1	36	4,285	16	2,645	6.00
	28		29	1	11	1,175	2	250	9.50
February	4	February	5	1	28	4,063	9	2,935	5.00
	11		12	1	13	2,335	2	890	10.50
	17		18	2	25	4,162	19	3,787	5.50
	25		26	1	18	2,705	2	930	10.50
March	4	March	5	1	82	9,749	58	8,374	10.50
	11		12	1	52	8,397	34	6,650	12.50
	17		19	1	70	9,837	63	9,570	11.75
	23		26	1	50	6,847	13	4,730	14.50
	30		31	2	22	5,160	21	5,110	19.50
April	1	April	2	1	38	3,817	22	3,077	7.00
	7		8	2	32	4,430	2	400	11.50
	8		10	7	34	2,891	5	450	10.00
	22		23	10	47	2,571	7	515	7.75

1		2		3	4	5	6	7	8
May	4	May	5	10	28	1,761	12	1,008	7.50
	12		13	2	16	1,649	15	1,648	5.00
	19		20	9	24	1,887	16	1,775	7.00
	22		24	5	22	2,557	9	1,550	5.75
	28		29	14	44	4,370	15	1,543	7.75
June	3	June	4	1	24	3,117	23	3,116	7.75
	10		11	1	49	9,349	45	8,249	8.75
	17		18	1	77	10,201	75	9,801	9.50
	24		25	1	109	14,247	73	10,817	8.50
	25		26	14	51	2,682	32	1,475	8.50
	30	July	2	8	74	4,733	19	2,967	7.00
July	13		14	10	81	7,795	37	4,703	6.50
	16		17	7	66	3,930	14	737	6.50
	23		24	14	63	6,389	22	4,130	6.50
	29		30	8	60	5,116	20	1,041	6.00
August	6	August	7	14	59	6,887	20	5,398	6.00
	20		21	14	43	6,037	8	4,368	6.00

APPENDIX TABLE IV.20 : VARIATIONS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

(Base : 1981-82 = 100)

Major Groups/Groups/Sub-Groups/ Commodities	Weight	(Per cent)					
		Financial year		First quarter			
		Point-to-point basis		Average basis		Point-to-point basis	
		1992-93	1991-92	1992-93	1991-92	1993-94*	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8
ALL COMMODITIES	100.000	7.0	13.6	10.0	13.7	2.4	3.2
I. PRIMARY ARTICLES	32.295	3.0	15.3	7.3	18.2	2.6	4.1
1. Food Articles	17.386	5.4	20.9	12.3	20.2	2.6	7.1
(a) Cereals	6.824	-2.7	26.9	13.5	23.2	0.2	1.2
(i) Rice	3.685	-0.2	30.7	14.5	21.7	0.5	2.3
(ii) Wheat	2.248	2.7	12.3	11.4	18.3	0.6	-3.1
(b) Pulses	1.093	2.7	9.4	3.5	9.3	2.2	-0.1
(c) Fruits and vegetables	4.089	9.7	19.0	7.5	24.1	6.2	10.3
(d) Milk	1.961	9.6	13.7	12.0	12.9	2.6	18.5
(e) Eggs, fish & meat	1.783	17.1	16.3	16.4	14.6	-3.8	2.8
(f) Condiments & spices	0.947	3.0	41.3	22.9	46.7	6.8	14.1
(g) Other food articles@	0.689	27.9	-5.0	10.0	-8.9	9.3	20.7
(i) Tea	0.564	30.8	0.4	13.5	-9.6	11.5	26.6
(ii) Coffee	0.125	15.8	-22.2	-4.6	-5.5	-0.7	-4.2
2. Non-Food Articles	10.081	-1.4	8.1	-0.2	17.8	3.0	-0.8
(a) Fibres	1.791	-10.5	14.4	-10.7	38.8	3.3	0.3
(i) Raw cotton	1.335	-10.9	24.7	-8.6	63.4	3.1	3.0
(b) Oilseeds	3.861	-8.7	4.7	-1.9	20.3	6.0	2.3
3. Minerals	4.828	2.8	5.2	2.3	4.1	0.0	0.0
(i) Petroleum crude & natural gas	4.274	1.9	1.9	1.7	1.4	0.0	0.0
II. FUEL, POWER, LIGHT AND LUBRICANTS	10.663	15.2	13.2	14.1	13.1	3.4	0.3
(a) Coking coal	0.353	14.9	26.1	20.0	7.0	4.8	0.0
(b) Mineral oils	6.666	18.8	9.2	13.6	16.1	0.1	0.1
(c) Electricity	2.741	9.8	13.7	11.8	10.8	9.4	0.9
III. MANUFACTURED PRODUCTS	57.042	7.9	12.6	10.9	11.3	2.0	3.2
(a) Sugar, khandsari & gur	4.059	27.9	5.5	12.1	5.3	20.7	11.8
(i) Sugar	2.013	13.9	18.9	13.1	10.6	2.8	3.2
(ii) Khandsari	0.300	26.9	-6.9	5.1	3.1	14.7	14.2
(iii) Gur	1.746	47.4	-6.9	12.1	0.4	40.3	23.2
(b) Edible oils	2.445	-7.1	1.9	-0.5	19.1	3.1	5.3
(c) Cotton textiles	6.093	5.5	16.0	8.9	14.4	0.0	0.6
(d) Chemicals & chemical products	7.355	12.8	15.5	14.3	13.9	1.5	3.0
(e) Cement	0.860	-3.5	17.4	6.4	13.9	1.5	-1.8
(f) Iron & Steel	2.441	12.2	4.5	9.5	5.5	0.9	8.8

*Provisional.

@Comprise tea and coffee.

APPENDIX TABLE IV.21 : WEIGHTED CONTRIBUTION OF GROUPS/COMMODITIES TO THE INCREASE IN THE GENERAL INDEX OF WHOLESALE PRICES (Base : 1981-82=100)

Major Groups/Groups/Sub-groups/ Commodities	Weight	Financial year				(Per cent)	
		Point-to-point basis		Average basis		First quarter	
						Point-to-point basis	
		1992-93	1991-92	1992-93	1991-92	1993-94*	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8
ALL COMMODITIES	100.000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
I. PRIMARY ARTICLES	32.295	14.4	37.1	24.9	42.2	35.2	42.4
1. Food Articles	17.386	15.6	29.4	24.8	28.9	22.4	45.2
(a) Cereals	6.824	-2.9	13.4	9.4	10.8	0.5	2.8
(i) Rice	3.685	-0.1	8.2	5.6	5.7	0.8	3.0
(ii) Wheat	2.248	0.9	2.2	2.5	2.8	0.6	-2.4
(b) Pulses	1.093	0.5	0.9	0.5	0.9	1.2	0.0
(c) Fruits and vegetables	4.089	6.3	6.1	3.8	8.0	12.3	26.5
(d) Milk	1.961	3.1	2.3	2.7	2.1	2.5	0.6
(e) Eggs, fish & meat	1.783	4.6	2.2	3.1	2.0	-3.3	1.7
(f) Condiments & spices	0.947	0.8	4.8	4.4	5.0	5.4	8.6
(g) Other food articles @	0.689	3.2	-0.3	0.9	-0.7	3.8	5.1
(i) Tea	0.564	2.8	0.0	1.0	-0.6	3.8	5.3
(ii) Coffee	0.125	0.3	-0.4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2
2. Non-Food Articles	10.081	-2.1	6.6	-0.2	13.9	12.5	-2.6
(a) Fibres	1.791	-2.8	2.0	-2.2	4.8	2.2	0.2
(i) Raw cotton	1.335	-2.2	2.4	-1.3	4.9	1.6	1.3
(b) Oilseeds	3.861	-4.9	1.5	-0.8	6.1	8.5	2.9
3. Minerals	4.828	1.0	1.1	0.6	0.9	0.0	0.0
(i) Petroleum crude & natural gas	4.274	0.5	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0
II. FUEL, POWER, LIGHT AND LUBRICANTS	10.663	22.6	10.2	14.4	9.8	16.3	0.9
(a) Coking coal	0.353	1.1	0.9	0.9	0.3	1.1	0.0
(b) Mineral oils	6.666	15.2	4.0	7.9	6.6	0.2	0.1
(c) Electricity	2.741	4.3	3.1	3.5	2.4	12.5	0.8
III. MANUFACTURED PRODUCTS	57.042	63.0	52.7	60.6	47.0	48.7	56.2
(a) Sugar, khandsari & gur	4.059	11.5	1.3	3.8	1.3	30.3	10.6
(i) Sugar	2.013	3.1	2.1	2.0	1.2	2.0	1.6
(ii) Khandsari	0.300	0.7	-0.1	0.1	0.1	1.3	0.8
(iii) Gur	1.746	7.7	-0.7	1.7	0.0	27.0	8.3
(b) Edible oils	2.445	-2.9	0.5	-0.1	4.1	3.3	4.8
(c) Cotton textiles	6.093	4.6	6.8	5.2	6.0	-0.1	1.1
(d) Chemicals & chemical products	7.355	10.9	6.7	8.5	6.0	4.1	5.6
(e) Cement	0.860	-0.4	1.1	0.5	0.8	0.5	-0.5
(f) Iron & steel	2.441	4.2	0.9	2.4	1.1	1.0	6.6

* Provisional.

@ Comprise tea and coffee.

APPENDIX TABLE IV.22 : ANNUAL AND QUARTERLY RATES OF PRICE INCREASES AS REFLECTED IN WHOLESALE PRICE INDEX AND CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS (Point-to-Point basis)

Item	1992-93					1991-92					(Per cent)	
	Quarters				Annual Variation	Quarters				Annual Variation	Quarter	
	April-June	July-Sept.	Oct.-Dec.	Jan.-March		April-June	July-Sept.	Oct.-Dec.	Jan.-March			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wholesale Price Index@	3.2	3.0	0.3	0.4	7.0	4.3	5.0	2.0	1.7	13.6	2.4	
Consumer Price Index for Industrial Workers	3.1	3.0	0.0	0.0	6.1	4.0	5.7	1.8	1.8	13.9	2.9	
Consumer Price Index for Urban Non-manual Employees	2.6	3.6	0.5	0.0	6.8	3.0	5.7	1.6	2.7	13.6	N.A.	
Consumer Price Index for Agricultural Labourers*	2.1	4.1	-4.0	-1.3	0.7	2.1	11.3	3.4	3.8	21.9	0.4	

@ Base : 1981-82=100

S Base : 1982=100

S Base 1984-85=100

* Base : 1960-61=100

N.A.—Not available.

APPENDIX TABLE IV.23 : GOLD AND SILVER RATIO IN TERMS OF GRAMS†

Year	In Bombay Market*		In International Markets‡	
	On average price basis	On year-end price basis	On average price basis	On year-end price basis
1	2	3	4	5
1980-81	59	63	37	43
1981-82	66	61	46	45
1982-83	62	58	44	39
1983-84	53	55	38	40
1984-85	55	53	46	49
1985-86	55	54	54	65
1986-87	55	54	71	67
1987-88	56	51	64	68
1988-89	50	46	66	66
1989-90	47	49	72	75
	51	53	83	92
1991-92	59	54	87	83
1992-93	58	75	89	87

† Grams of silver available per one gram gold.

* Based on quotations of Bombay Bullion Association.

‡ Based on quotations received from Press Trust of India for London and New York markets.

APPENDIX TABLE IV.24 : GOLD AND SILVER PRICES IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL MARKETS

Year	Gold		Silver		Spread between Bombay and London prices (Average in percentages)	Spread between Bombay and New York prices (percentages)
	Bombay Market (Rs. per 10 grams for standard gold)		Bombay Market (Rs. per Kg. for 0.999 fineness)			
	Year-end	Average	Year-end	Average	Gold*	Silver**
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1,700 (27.8)	1,522 (31.3)	2,720 (2.4)	2,617 (13.9)	2.5	-34.9
1981-82	1,645 (-3.2)	1,719 (12.9)	2,680 (-1.5)	2,636 (0.7)	42.1	0.3
1982-83	1,800 (9.4)	1,723 (0.2)	3,105 (15.9)	2,798 (6.2)	37.8	-1.1
1983-84	1,975 (9.7)	1,859 (7.8)	3,570 (15.0)	3,506 (25.3)	38.5	-0.3
1984-85	2,130 (7.8)	1,984 (6.8)	3,955 (10.8)	3,594 (2.5)	53.3	27.9
1985-86	2,140 (0.5)	2,126 (7.1)	4,015 (1.5)	3,918 (9.0)	64.8	63.5
1986-87	2,570 (20.1)	2,324 (9.3)	4,794 (19.4)	4,247 (8.4)	47.3	91.3
1987-88	3,130 (21.8)	3,082 (32.7)	6,066 (26.5)	5,539 (30.4)	61.2	83.6
1988-89	3,140 (0.3)	3,175 (3.0)	6,755 (11.4)	6,367 (14.9)	62.0	114.3
1989-90	3,200 (1.9)	3,229 (1.7)	6,463 (-4.3)	6,842 (7.5)	56.5	140.4
1990-91	3,466 (8.3)	3,452 (6.9)	6,646 (2.8)	6,761 (-1.2)	59.5	162.1

1	2	3	4	5	6	7
1991-92	4,334 (25.0)	4,298 (24.5)	8,040 (21.0)	7,392 (8.5)	51.3	124.2
1992-93	4,140 (-4.5)	4,104 (-4.5)	5,489 (-31.7)	7,078 (-3.5)	23.2	88.7

Figures in brackets are percentage variations over the previous year.

*Till February, 1992, the spread has been worked out after converting the quotations in dollars per troy ounce in London market into rupees per 10 grams at the cross rates based on daily average of spot buying and selling rates of U.S. dollars in London and average of Reserve Bank's spot buying and selling rates of sterling. Since March, 1992, the quotations have been converted at the daily average of FEDAI's spot buying and selling rate of U.S. dollars in Bombay.

**Till February, 1992, the spread has been worked out after converting the quotations in cents per troy ounce in New York market into rupees per Kg. at the cross rates based on the daily average of spot buying and selling rates of US dollars in London and average of Reserve Bank's spot buying and selling rates of sterling. Since March, 1992, the quotations have been converted at the daily average of FEDAI's spot buying and selling rate of US dollars in Bombay.

Source : 1. Bombay Bullion Association 2. Press Trust of India.

APPENDIX TABLE IV.25 : GOLD AND SILVER PRICE—MONTHLY AVERAGES AND SPREAD BETWEEN DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRICE

Month/Year	Gold (Rupees per 10 grams)			Silver (Rupees per kilogram)		
	Bombay-London			Bombay-New York		
	Bombay	London	Spread	Bombay	New York	Spread
1	2	3	4	5	6	7
1992						
April	4,497.18	3,365.70	1,131.48 (33.6)	8,395.41	3,998.67	4,396.74 (110.0)
May	4,176.77	3,287.43	889.34 (27.1)	7,973.09	3,976.31	3,996.78 (100.5)
June	4,110.15	3,313.26	796.89 (24.1)	7,255.88	3,942.41	3,313.47 (84.0)
July	4,136.55	3,428.00	708.55 (20.7)	7,537.00	3,686.19	3,850.81 (104.5)
August	4,094.00	3,323.88	770.12 (23.2)	7,626.14	3,660.16	3,965.98 (108.4)
September	4,086.13	3,336.85	749.28 (22.5)	7,351.50	3,638.57	3,712.93 (102.0)
October	4,079.00	3,320.23	758.77 (22.9)	7,196.33	3,608.26	3,588.07 (99.4)
November	3,998.61	3,241.48	757.13 (23.4)	6,539.35	3,645.50	2,893.85 (79.4)
December	3,966.81	3,305.05	661.76 (20.0)	6,644.71	3,663.73	2,980.98 (81.4)
1993						
January	3,977.24	3,271.32	705.92 (21.6)	6,810.35	3,654.02	3,156.33 (86.4)
February	4,027.10	3,457.45	569.65 (16.5)	6,056.71	3,820.80	2,235.91 (58.5)
March	4,094.39	3,344.74	749.65 (22.4)	5,554.22	3,703.81	1,850.41 (50.0)
April	4,331.27	3,446.90	884.37 (25.7)	5,809.41	3,999.53	1,809.88 (45.3)
May	4,518.50	3,697.13	821.37 (22.2)	6,187.13	4,479.20	1,707.93 (38.1)
June	4,468.20	3,752.33	715.87 (19.1)	6,009.88	4,407.98	1,601.90 (36.3)
July	4,564.59	3,957.87	606.73 (15.3)	6,481.48	5,080.34	1,401.14 (27.6)

Note : Figures in brackets indicate percentage spread.

Source : 1. Bombay Bullion Association.

2. Press Trust of India.

APPENDIX TABLE V.1 : ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY ALL FINANCIAL INSTITUTIONS

(Rupees crore)

Institutions	Fiscal Year						Variations in			
	1992-93		1991-92		1990-91		Sanctions		Disbursements	
	S	D	S	D	S	D	1992-93 over 1991-92	1991-92 over 1990-91	1992-93 over 1991-92	1991-92 over 1990-91
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. All India @ Development Banks (1 to 5) @@	20,898.7	13,907.4	16,759.7	11,447.7	14,896.4	9,551.7	4,139.30 (24.7)	1,863.3 (12.5)	2,459.7 (21.5)	1,896.0 (19.8)
1. IDBI @	18,906.5	12,574.5	14,543.3	10,082.5	12,872.7	8,278.5	4,363.2 (30.0)	1,670.6 (13.0)	2,492.0 (24.7)	1,804.0 (21.8)
@	9,459.4	6,668.5	7,590.0	5,762.8	6,431.2	4,459.4	1,869.4 (24.6)	1,158.8 (18.0)	905.7 (15.7)	1,103.4 (29.2)
@@	9,320.5	6,529.5	7,106.2	5,279.0	5,985.0	4,016.9	2,214.3 (31.2)	1,121.2 (18.7)	1,250.5 (23.7)	1,262.1 (31.4)
2. FCI	8,701.9	6,042.1	6,414.1	4,760.8	5,156.3	3,487.6	2,287.8 (35.7)	1,257.6 (24.4)	1,281.3 (26.9)	1,273.2 (36.5)
3. ICICI	2,492.8	1,733.0	2,435.0	1,604.8	2,523.9	1,574.8	57.8 (2.4)	-88.9 (-3.5)	128.2 (8.0)	30.0 (1.9)
4. SIDBI @	5,882.7	3,315.2	4,094.9	2,351.3	3,744.0	1,967.6	1,787.8 (43.7)	350.9 (9.4)	963.9 (41.0)	383.7 (19.5)
@@	2,908.4	2,145.8	2,845.9	2,027.4	2,408.8	1,838.5	62.5 (2.2)	437.1 (18.1)	118.4 (5.8)	188.9 (10.3)
5. IRBI	1,534.8	1,300.3	1,321.6	1,180.4	1,213.6	1,094.6	213.2 (16.1)	108.0 (8.9)	119.9 (10.2)	85.8 (7.8)
B. Specialised F- Financial Institutions (6 to 9)	294.3	183.9	277.7	185.2	234.7	153.9	16.6 (6.0)	43.0 (18.3)	-1.3 (-0.7)	31.3 (20.3)
6. RCTC	929.3	579.6	542.2	245.4	438.6	224.9	387.1 (71.4)	103.6 (23.6)	334.2 (136.2)	20.5 (9.1)
7. TDICI	14.8	10.4	11.1	8.4	11.0	7.3	3.7 (33.3)	0.1 (0.9)	2.0 (23.8)	1.1 (15.1)
8. SCICI	28.6	23.2	18.6	17.8	11.0	11.4	10.0 (53.8)	7.6 (69.1)	5.4 (30.3)	6.4 (56.1)
9. TFCI	760.9	486.3	409.0	170.9	331.6	167.0	351.9 (86.0)	77.4 (23.3)	315.4 (184.6)	3.9 (2.3)
C. Investment Institutions (10+11+12) @	125.0	59.7	103.5	48.3	85.0	39.2	21.5 (20.8)	18.5 (21.8)	11.4 (23.6)	9.1 (23.2)
10. UTI	9,293.1	6,963.6	5,843.4	3,910.8	2,924.7	1,929.0	3,449.7 (59.0)	2,918.7 (99.8)	3,0528.8 (78.1)	1,981.8 (102.7)
@	7,981.0	5,801.5	4,793.4	3,360.8	2,414.7	1,404.0	3,187.6 (66.5)	2,378.7 (98.5)	2,440.7 (72.6)	1,956.8 (139.4)
11. LIC	7,089.2	5,123.1	3,670.9	2,646.5	1,923.7	1,355.2	3,418.3 (93.1)	1,747.2 (90.8)	2,476.6 (93.6)	1,291.3 (95.3)
@	6,427.1	4,411.0	3,020.9	2,146.5	1,413.7	830.2	3,406.2 (112.8)	1,607.2 (113.7)	2,246.5 (105.5)	1,316.3 (158.6)
12. GIC	1,739.8	1,395.4	1,515.3	1,022.5	688.1	427.4	224.5 (14.8)	827.2 (120.2)	372.9 (36.5)	595.1 (139.2)
D. Total Assistance by All-India Financial Institutions (A@+B+C@)	1,089.8	945.4	1,115.3	972.5	688.1	427.4	-25.5 (-2.3)	427.2 (62.1)	-27.1 (-2.8)	545.1 (127.5)
	464.1	445.1	657.2	241.8	312.9	146.4	-193.1 (-29.4)	344.3 (110.0)	203.3 (84.1)	95.4 (65.2)
	29,809.0	20,288.5	22,095.3	15,053.9	17,749.7	11,180.6	7,713.7 (34.9)	4,345.6 (24.5)	5,234.6 (34.8)	3,873.3 (34.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E State-level Institution (13 and 14)	3,291.3	2,349.8	3,002.0	2,220.1	2,687.6	1,869.1	289.3 (9.6)	314.4 (11.7)	129.7 (5.8)	351.0 (18.8)
13 SFCs	2,151.7	1,652.8	1,988.4	1,540.1	1,863.9	1,270.8	163.3 (8.2)	124.5 (6.7)	112.7 (7.3)	269.3 (21.2)
14 SIDCs	1,139.6	697.0	1,013.6	680.0	823.7	598.3	126.0 (12.4)	189.9 (23.1)	17.0 (2.5)	81.7 (13.7)
F Total Assistance by All Financial Institutions (A@@+B+C@+E)	31,108.1	21,305.4	22,880.9	15,908.8	18,413.6	11,776.5	8,227.2 (36.0)	4,467.3 (24.3)	5,396.6 (33.9)	4,132.3 (35.1)

S—Sanctions D—Disbursements

IDBI—Industrial Development Bank of India, IFCI—Industrial Finance Corporation of India (changed to Industrial Finance Corporation of India Ltd. with effect from 1-7-93), ICICI—Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd., SIDBI—Small Industries Development Bank of India, IRBI—Industrial Reconstruction Bank of India, RCTC—Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd., TDICI—Technology Development and Information Company of India Ltd., SCICI—Shipping Credit & Investment Company of India Ltd. (name changed to SCICI Ltd. from October 20, 1992), TFCI—Tourism Finance Corporation of India Ltd., UTI—Unit Trust of India, LIC—Life Insurance Corporation of India, GIC—General Insurance Corporation of India, SFCs—State Financial Corporations and SIDCs—State Industrial Development Corporations.

@ Data are adjusted for inter-institutional (all-India) flows.

@@ Data are adjusted for inter-institutional (all-India and state-level) flows.

Notes : 1. Data for 1992-93 are provisional for all institutions and estimated for SFCs and SIDCs.

2. Data have been adjusted for inter-institutional flows. This involves adjustment in regard to loans to and investments in shares and bonds of financial institutions by IDBI, IDBI/SIDBI's refinance assistance to SFCs and SIDCs and seed capital assistance, term loans given by LIC to IFCI and ICICI, and special deposits by UTI to IDBI, IFCI and ICICI.

3. Figures in parentheses are percentage variation over the corresponding figure of the previous year.

4. SIDBI commenced its operations from April, 2, 1990.

Source : IDBI and Respective Financial Institutions.

APPENDIX TABLE V.2 : APPROVALS FOR NEW ISSUES BY THE CCI AND CLEARANCE BY SEBI FOR RAISING CAPITAL

(Rupees crore)										
Types of Issues	1992-93						1991-92		1990-91	
	(April-May)*		(June-March)**		Total(A+April-March)		(April-March)		(April-March)	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Non-Government Companies of which	329	2,245	999	18,596	1,328	20,841	1,243	12,341	1,074	6,423
(i) Equities@	272	1,187	845	8,996	1,117	10,183	868	4,291	841	2,853
(ii) Debentures/Bonds	57	1,058	154	9,600	211	10,658	375	8,050	233	3,570
B. Government Companies of which	2	60	1	320	3	380	20	7,061	31	6,208
(i) Equities @	1	10	1	320	2	330	3	76	14	201
(ii) Public Sector Bonds	1	50	1	50	17	6,985	17	6,007
Grand Total (A + B)	331	2,305	1,000	18,916	1,331	21,221	1,263	19,402	1,105	12,631

* Consents/Acknowledgements granted by Controller of Capital Issues (April-May 1992).

** Clearance by Securities and Exchange Board of India (June 1992—March 1993). Data relating to bonds issue by IDBI and excluded.

@ Including premium and bonus shares, and excludes bonus shares from June 1992 onwards.

£ Provisional.

Sources : 1. Controller of Capital Issues.

2. Securities and Exchange Board of India.

APPENDIX TABLE V.3 : NEW CAPITAL ISSUES BY NON-GOVERNMENT PUBLIC LIMITED COMPANIES

(Rupees crore)

I	Fiscal Year					
	1992-93		1991-92		1990-91	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
2	3	4	5	6	7	
1. Equity Shares (a + b)	867	9,981.0	368	1,731.3	246	1,284.3
	(324)	(5,184.1)	(58)	(227.5)	(40)	(127.9)
(a) Prospectus	484	3,846.0	158	1,043.3	105	995.0
	(105)	(876.8)	(16)	(26.7)	(15)	(74.1)
(b) Rights	383	6,135.0	210	688.0	141	289.3
	(219)	(4,307.3)	(42)	(200.8)	(25)	(53.8)
2. Preference Shares (a + b)	1	0.5	3	1.5	3	13.1
(Including CCPS)						
(a) Prospectus	1	0.5	2	13.0
(b) Rights	1	0.5	2	1.0	1	0.1
3. Debentures (a + b)	169	9,844.1	146	4,024.0	115	3,014.8
(a) Prospectus	47	3,187.6	50	867.9	45	1,040.1
(b) Rights	122	6,656.5	96	3,156.1	70	1,974.7
Of which :						
(i) Convertible (a + b)	150	7,864.9	133	3,496.9	94	2,356.6
(a) Prospectus	44	2,567.1	47	856.1	38	877.0
(b) Rights	106	5,297.8	86	2,640.8	56	1,479.6
(ii) Non-convertible (a + b)	19	1,979.2	13	527.1	21	658.2
(a) Prospectus	3	620.5	3	11.8	7	163.1
(b) Rights	16	1,358.7	10	515.3	14	495.1
4. Total (1 + 2 + 3)	1,037	19,825.6	517	5,756.8	364	4,312.2
(a) Prospectus	531	7,033.6	209	1,911.7	152	2,048.1
(b) Rights	506	12,792.0	308	3,845.1	212	2,264.1

- Notes :
1. Data are provisional.
 2. Equity shares exclude bonus issues.
 3. Figures in brackets indicate data in respect of premium on capital issues which are included in respective totals.
 4. Data exclude issues privately placed with financial institutions, etc., and includes amounts raised by ICICI, HDFC, SCICI and issues through OTCEI.
 5. Convertible debentures include partly convertible debentures.
 6. Non-Convertible debenture includes secured premium notes.
 7. Data include amount of over-subscriptions retained and under subscriptions in cases where specific information was available.
 8. Debentures include bonds.
 9. Data are compiled from Prospectus/Circulars/Advertisements issued by companies, replies given by the companies to the Reserve Bank's questionnaires, information received from Stock Exchanges, Press Reports, etc.

APPENDIX TABLE V.4 : RESERVE BANK OF INDIA ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF ORDINARY SHARE PRICES (WEEKLY)

(Base : 1980-81 = 100)

Year/Month	Average :-	High	Low	Last week-end of the month/year
1	2	3	4	5
1991-92	776.2	1485.4	536.9	1485.4
(April-March)	(+ 55.1)			(+18.14)
1992-93	1142.1	1656.9	892.1	892.1
(April-March)	(+47.1)			(+39.9)

April 1992	1620.2	1656.9	1597.3	1622.0
May	1345.5	1519.3	1206.8	1206.8
June	1161.6	1174.3	1148.9	1157.5
July	1141.7	1159.2	1108.8	1108.8
August „	1077.2	1134.2	1032.3	1134.2
September „	1214.7	1243.5	1168.4	1234.1
October „	1181.9	1227.5	1122.8	1122.8
November „	1045.6	1102.1	1010.8	1010.8
December „	1003.1	1022.4	979.2	998.2
January 1993	985.9	1002.2	966.1	1002.2
February „	1009.0	1024.6	993.4	1007.8
March „	912.9	955.7	892.1	892.1

Memorandum Items :	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	Average for (1988-89 to 1992-93)
Co-efficient of	16.20	5.90	14.66	27.04	16.21	16.00
Variation (in percentage)+ Dispersion	121.10	93.70	258.60	948.50	764.80	437.34
(The Range)						

Figures in brackets are percentage variation over the previous year.

+ Based on weekly indices.

APPENDIX TABLE V.5 : DEPOSITS WITH NON-BANKING CORPORATE SECTOR

(Rupees crore)

Category	1991-92*				1990-91				
	No. of reporting Companies	Regula- ted deposits	Exempted deposits	Total	No. of reporting companies	Regula- ted deposits	Exemp- ted deposits	Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aggregate Deposits of which, held by :		12,817	9,269	44,290	53,559	10,166	7,907	37,354	45,261
(i) Non-Financial Companies		2,393 (18.7)	4,608 (49.7)	23,673 (53.4)	28,281 (5.28)	2,367 (23.3)	4,618 (58.4)	21,829 (58.4)	26,447 (58.4)
(ii) Financial Companies		8,656 (67.5)	2,904 (31.3)	19,311 (43.6)	22,215 (41.5)	6,663 (65.5)	2,013 (25.5)	14,589 (39.1)	16,602 (36.7)
(iii) Miscellaneous Non-Banking Companies and Residuary Non-Banking Companies		1,768 (13.8)	1,757 (19.0)	1,306 (3.0)	3,063 (5.7)	1,136 (11.2)	1,276 (16.1)	936 (2.5)	2,212 (4.9)

* Provisional.

†As at the end of March.

Note : Figures in parentheses are percentages to total number of reporting companies/regulated/exempted/aggregate deposits as the case may be.

APPENDIX TABLE VI-1—INDIA'S OVERALL BALANCE OF PAYMENTS

Item	Rupees crore			US Dollar million		
	1992-93 (QE)	1991-92 (PE)	1990-91 (Preliminary)	1992-93 (QE)	1991-92 (PE)	1990-91 (Preliminary)
1	2	3	4	5	6	7
A. Current Account						
1. Exports, f.o.b.	54,418	44,923	33,153	18,789	18,223	18,477
2. Imports, c.i.f.	65,945	50,159	50,086	22,895	20,347	27,914
3. Trade Balance	-11,527	-5,236	-16,933	-4,106	-2,124	-9,437
4. Officials Transfers, net	1,091	1,050	828	356	426	461
5. Other Invisibles, net	-4,195	-1,000	-1,261	-1,171	-437	-703
6. Current Account Balance	-14,631	-5,186	-17,366	-4,921	-2,135	-9,679
B. Capital Account						
1. External Assistance, net	5,645	7,188	3,965	1,842	2,916	2,210
Disbursements	10,362	10,644	6095	3,381	4,318	3,397
Amortisation	-4,717	-3,456	-2,130	-1,539	-1,402	-1,187
2. Commercial Borrowings, net*	-1,461	4,060@	4,588	-451	1,647@	2,558
Disbursements	3,562	7,457@	8,183	1,188	3,025@	4,562
Amortisation	-5,023	-3,397	-3,595	-1,639	-1,378	-2,004
4. NRI Deposits, net	5,419	-1,111	2,756	1,949	-454	1,536
4. Rupee Debt Service	-2,994	-3,260	-2,140	-977	-1,332	-1,192
5. Other Capital, net	6,124	6,077	4,046	1,998	2,152	2,253
6. Total Capital Account	12,733	12,954	13,215	4,361	4,929	7,365
C. IMF, net	3,363	2,077	2,178	1,288	781	1,214
D. SDR Allocation
E. Total Capital Account, IMF and SDR Allocation	16,096	15,031	15,393	5,649	5,710	8,579
F. Total Current Account, Capital Account, IMF and SDR Allocation	1,465	9,845	-1,973	728	3,575	-1,100
G. Errors & Omissions	1,098**	..	-320	-178
H. Reserves and Monetary Gold (Increase—1/Decrease+)	-2,563	-9,845	2,293	-728	-3,575	1,278

@ Include India Development Bonds.

* Excluding refinancing credits.

** Errors and Omissions for 1992-93 arise due to different exchange rates applied to receipts and payments as per the provisions of LERMS.

QE Quick Estimates. PE—Provisional Estimates.

- Notes :
- For features of the formal in which the balance of payments have been presented here, please refer to the text (paragraph 6.3).
 - Data on 'Non-Monetary Gold' have been adjusted under merchandise or official miscellaneous capital depending upon the nature of the transaction.
 - Balance of payments for 1992-93 exclude gold and silver brought in by returning Indians under the liberalised baggage rules.

APPENDIX TABLE VI. 2—FINANCING NEED AND SOURCES OF FINANCING

Item	Rupees crore				US Dollar million			
	1992-93 (QE)	1991-92@ (PE)	1990-91@	Total Seventh Five-Year Plan*	1992-93 (QE)	1991-92@ (PE)	1990-91@	Total Seventh Five-Year Plan*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Current Account Deficit including errors & omissions	13,533	5,186	17,686	39,285	4,921	2,135	9,857	27,999
2. Repayment to IMF	868	1,127	1,156	5,153	335	459	644	3,610
3. Rupee Debt Service	2,994	3,260	2,140	NA	977	1,322	1,192	NA
4. Financing Need (2+3)	17,395	9,573	20,982	44,438	6,233	3,926	11,693	31,609
Financed by								
5. External Assistance	5,645 (32.4)	7,188 (75.1)	3,965 (18.9)	12,728 (28.6)	1,842 (29.6)	2,916 (74.2)	2,210 (18.9)	9,115 (28.8)
6. Commercial Borrowings	-1,461 (-8.4)	4,060 (42.4)	4,588 (21.9)	10,647 (24.0)	-451 (-72)	1,647 (42.0)	2,558 (21.9)	7,548 (23.9)
7. Non-Resident Deposits	5,419 (31.2)	-1,111 (11.6)	2,756 (13.1)	10,164 (22.9)	1,949 (31.3)	-454 (-11.5)	1,536 (13.1)	7,324 (23.2)
8. Drawals from IMF	4,231 (24.3)	3,204 (33.5)	3,334 (15.9)	..	1,623 (26.0)	1,240 (31.6)	1,858 (15.9)	..
9. Other Capital	6,124 (35.2)	6,077 (63.4)	4,046 (19.3)	5,823 (13.1)	1,998 (32.0)	2,152 (54.8)	2,255 (19.3)	3,995 (12.6)
10. Use of Reserves	-2,563 (-14.7)	-9,845 (-102.8)	2,293 (10.9)	5,076 (11.4)	-728 (-11.4)	-3,575 (-91.1)	1,278 (10.9)	3,627 (11.5)

@ Please see note under Appendix Table VI.1.

* Excludes accrued interest on NRI deposits.

QE — Quick Estimate PE—Provisional Estimate. NA : Not Available.

- Note :
- Figures in brackets indicate proportions to financing need (item 3) conversions to US \$ has been made at respective annual average rates (Except transactions with the IMF in 1991-92).
 - Figures of commercial borrowing for 1991-92 include India Development Bond of US \$ 1627 million (SDR's 1192 million).
 - Figures for the Seventh Five Year Plan are not strictly comparable with those for recent years.

APPENDIX TABLE VI.3 : INDIA'S FOREIGN EXCHANGE RESERVES

End of Month	Foreign Exchange Reserves (Rupees crore)				Foreign Exchange Reserves (US Dollar million)				Total Foreign Exchange Reserves@ (SDR million)	Movement in Foreign Exchange Reserves (SDR million)*	Reserve Position in the Fund (SDR million)
	SDRs†	Gold@	Foreign Currency Assets	Total (2+3+4)	SDRs	Gold@	Foreign Currency Assets	Total (6+7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
March 1991	200	6,828	4,388	11,416	102	3,496	2,236	5,834	4,329 (2,111)	—1284 (—934)	—
June 1991	133	7,411	2,382	9,926	63	3,524	1,124	4,711	3,564 (1,278)	—765 (—833)	..
September 1991	476	8,658	4,442	13,576	184	3,353	1,722	5,259	3,838 (1,766)	—491 (—345)	..
December 1991	120	9,489	9,287	18,896	46	3,675	3,580	7,301**	5,095 (2,930)	766 (819)	..
March 1992	233	9,039	14,578	23,850	90	3,499	5,631	9,220	6,716 (4,566)	2387 (2,455)	..
June 1992	297	8,932	16,125	25,354	115	3,459	6,221	9,795	6,838 (4,822)	122 (256)	..
September 1992	88	9,053	14,937	24,078	34	3,505	5,777	9,316	6,319 (4,340)	—397 (—226)	..
December 1992	10	8,937	14,297	23,244	4	3,420	5,461	8,885	6,456 (4,372)	—260 (—194)	212
March 1993	55	10,549	20,140	30,744	18	3,380	6,434	9,832	7,033 (5,015)	317 (449)	212
June 1993	586	11,946	20,483	33,015	187	3,807	6,553	10,547	7,518 (5,201)	485 (186)	212

† At Rupee-SDR exchange rate at the end of the respective month.

* Variations over the previous March.

@ Gold has been valued close to international market price.

** Includes acquisition of gold worth US \$ 191 million from the Government.

Notes : 1. Conversion of foreign currency assets and SDRs into US dollar is done at exchange rates supplied by the IMF.
2. Figures in parentheses indicate levels of/movements in foreign exchange reserves excluding revaluation of gold.

APPENDIX TABLE VI.4—TRANSACTIONS WITH THE IMF

(SDR million)

End of March	Gross Drawings	Cumulative Repurchases	Outstanding Net drawing (2)—(3)	Net Draws (-) /Repayments (+) of IMF Credit*
1	2	3	4	5
March 1991	5,169	3,221	1,948	800
June 1991	5,169	3,300	1,869	—79
September 1991	5,804	3,396	2,408	460
December 1991	5,889	3,463	2,426	478
March 1992	6,074	3,558	2,516	568
June 1992	6,074	3,612	2,462	—54
September 1992	6,536	3,696	2,840	324
December 1992	6,998	3,738	3,260	744
March 1993	7,229	3,796	3,433	917
June 1993	7,460	3,825	3,635	202

* Variations over the previous March.

Note : Gross drawings, repurchases and outstanding liabilities to the IMF relate to transactions in respect of Extended Fund Facility, Stand by Credit Arrangement and Compensatory and Contingency Financing Facility and exclude those relating to Trust Fund Loans.

APPENDIX TABLE VI.5 : INDIA'S FOREIGN TRADE

		Rupees crore			US Dollar million			SDR million		
Item		1992-93*	1991-92	1990-91	1992-93*	1991-92	1990-91	1992-93*	1991-92	1990-91
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Exports	53,551 (21.1)	44,042 (35.3)	32,553 (17.6)	18,421 (3.1)	17,866 (-1.5)	18,143 (9.1)	14,364 (9.0)	13,173 (0.6)	13,100 (1.1)
	POL	1,379 (34.9)	1,022 (9.0)	938 (34.6)	476 (14.8)	415 (-20.7)	523 (24.9)	371 (21.4)	306 (-19.0)	377 (15.8)
	Non-oil	51,972 (20.8)	43,620 (36.1)	31,615 (17.2)	17,945 (2.8)	17,451 (-1.0)	17,620 (8.7)	13,993 (8.7)	12,867 (1.1)	12,723 (0.7)
II.	Imports	62,923 (31.5)	47,851 (10.8)	43,193 (22.0)	21,726 (11.9)	19,411 (-19.4)	24,073 (13.2)	16,941 (18.4)	14,313 (-17.7)	17,382 (4.9)
	POL	17,153 (30.7)	13,127 (21.4)	10,816 (72.4)	6,100 (13.7)	5,364 (-11.0)	6,028 (60.0)	4,618 (17.6)	3,926 (-9.8)	4,353 (48.2)
	Non-oil	45,770 (31.8)	34,724 (7.3)	32,377 (11.1)	15,626 (11.2)	14,047 (-22.0)	18,045 (3.1)	12,323 (18.6)	10,387 (-20.3)	13,029 (-4.5)
III.	Trade Balance	-9,572	-3,809	-10,640	-3,305	-1,545	-5,930	-2,577	-1,140	-4,282
	Oil Balance	-15,774	-12,105	-9,878	-5,624	-4,949	-5,505	-4,247	-3,620	-3,975
	Non-oil Balance	+6,202	+8,296	-762	+1,231	+3,404	-425	+1,670	+2,480	-306

* Provisional.

Note : Figures in brackets relate to percentage variation over the previous year.

Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

APPENDIX TABLE VI.6 : INDIA'S EXPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES

Commodity Group	Rupees crore			Percentage variation		US Dollar million			Percentage variation	
	1992-93*	1991-92	1990-91	(2)/(3)	(3)/(4)	1992-93*	1991-92	1990-91	(7)/(8)	(8)/(9)
	1	2	3			7	8	9		
A. Primary products	10,937	10,187	7,754	7.4	31.4	3,776	4,132	4,322	-8.6	-4.4
	(20.5)	(23.1)	(23.8)			(20.5)	(23.1)	(23.8)		
(a) Agriculture and allied products	8,791	7,895	6,019	11.4	31.2	3,035	3,203	3,354	-5.2	-4.5
	(16.5)	(17.9)	(18.5)			(16.5)	(17.9)	(18.5)		
(b) Ores and minerals	2,146	2,292	1,735	-6.4	32.1	741	930	967	-20.3	-3.9
	(4.0)	(5.2)	(5.3)			(4.0)	(5.2)	(5.3)		
B. Manufactured goods	40,375	32,413	23,310	24.6	39.1	13,941	13,149	12,991	6.0	1.2
	(75.7)	(73.6)	(71.6)			(75.7)	(73.6)	(71.6)		
Of which :										
(a) Leather and manufactures thereof	3,692	3,128	2,600	18.1	20.3	1,275	1,269	1,449	0.5	-12.4
	(6.9)	(7.1)	(8.0)			(6.9)	(7.1)	(8.0)		
(b) Chemicals and related products	3,615	3,648	2,344	-0.9	55.6	1,248	1,480	1,307	-15.6	13.2
	(6.8)	(8.3)	(7.2)			(6.8)	(8.3)	(7.2)		
(c) Engineering goods@	7,140	5,554	4,038	28.6	37.5	2,465	2,253	2,250	9.4	0.1
	(13.4)	(12.6)	(12.4)			(13.4)	(12.6)	(12.4)		
(d) Textile fabrics and manufactures	12,423	9,872	6,775	25.8	45.7	4,289	4,005	3,776	7.1	6.1
	(23.3)	(22.4)	(20.8)			(23.3)	(22.4)	(20.8)		
Of which :										
(i) Cotton yarn, fabrics, made-ups	3,929	3,204	2,100	22.6	52.6	1,355	1,300	1,170	44.4	11.1
	(7.4)	(7.3)	(5.5)			(7.4)	(7.3)	(6.5)		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(i) Ready-made garments		6,918 (13.0)	5,422 (12.3)	4,012 (12.3)	27.6	35.1	2,389 (13.0)	2,399 (12.3)	2,236 (12.3)	8.6	-1.6
(c) Handicrafts		10,848 (20.3)	8,349 (19.0)	6,167 (18.9)	29.9	35.4	3,746 (20.3)	3,387 (19.0)	3,437 (18.9)	10.6	-1.5
Of which :											
(i) Gems and jewellery		8,839 (16.6)	6,750 (15.3)	5,247 (16.1)	31.0	28.6	3,052 (16.6)	2,738 (15.3)	2,924 (16.1)	11.5	-6.4
C. Minerals and lubricants*		1,379 (2.6)	1,022 (2.3)	938 (2.9)	34.9	9.0	476 (2.6)	41.5 (2.3)	523 (2.9)	14.8	-20.7
D. Others		659 (1.2)	419 (1.0)	551 (1.7)	57.2	-23.9	228 (1.2)	170 (1.0)	307 (1.7)	33.8	-44.6
Total Exports (A+B+C+D)		53,351	44,042	32,553	21.1	35.3	18,421	17,866	18,143	3.1	-1.5

Figures in parentheses represent percentage to total exports.

* Provisional.

*Relates to petroleum crude and petroleum products.

@ Relates to machinery, transport equipments, metal manufactures including iron and steel, electronic goods, computer software and project goods.

Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

APPENDIX TABLE VI.7 : INDIA'S IMPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES

Commodity Group	Rupees crores			Percentage variation		US Dollar million			Percentage variation	
	1992-93*	1991-92	1990-91	(2)/(3)	(3)/(4)	1992-93*	1991-92	1990-91	(7)/(8)	(8)/(9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Bulk imports	27,736 (44.1)	21,337 (44.6)	19,685 (45.6)	30.0	8.4	9,754 (44.9)	8,694 (44.8)	10,97 (45.6)	12.2	-20.8
(A) Petroleum, petroleum products & related material	17,153 (27.3)	13,217 (27.4)	10,816 (25.0)	30.7	21.4	6,100 (28.1)	5,304 (27.6)	6,028 (25.0)	13.7	-11.0
(B) Bulk consumption goods	1,413 (2.2)	687 (1.4)	999 (2.3)	108.5	-32.2	488 (2.2)	274 (1.4)	55.7 (2.3)	77.7	50.7
(a) Cereals & cereal preparations	924	173	182	432.9	-4.9	319	70	102	353.6	-30.8
(b) Edible oils	172	248	326	-30.4	-23.9	60	101	182	-40.8	-44.6
(c) Pulses	316	255	481	23.8	-46.9	109	104	268	5.3	-61.4
(d) Sugar	..	1	9	—	-9.1	—	—	5	—	—
(C) Other bulk items	9,170 (14.6)	7,532 (15.7)	7,870 (18.2)	21.7	-4.3	3,166 (14.6)	3,056 (15.7)	4,386 (18.2)	3.6	-30.3
(a) Fertilizers	2,827	2,352	1,766	20.2	33.2	976	954	984	2.3	-3.1
(i) Crude	458	455	347	0.6	31.3	158	181	193	-14.4	-4.5
(ii) Sulphur & unroasted iron pyrite	350	307	278	14.1	10.2	121	124	15.5	-2.9	-19.8
(iii) Manufactured	2,020	1,591	1,141	27.0	39.4	697	645	636	8.1	1.5
(b) Non-ferrous metals	1,119	840	1,102	33.3	-23.8	386	341	614	13.4	-41.5
(c) Paper, paper board & manufactures thereof (incl. newsprint)	483	488	456	-1.1	7.0	167	198	204	-15.8	-22.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(d) Crude rubber	258	182	226	41.8	—19.6	89	74	126	20.7	—41.5	
(e) Pulp & waste paper	400	299	458	34.0	—34.8	138	121	255	14.1	—52.5	
(f) Metalliferous ores & metal scrap	1,792	1,175	1,528	52.5	—23.1	619	477	852	29.8	—44.1	
(g) Iron & Steel	2,291	2,197	2,334	4.3	—5.9	791	891	1,301	—11.2	—31.5	
II. Non-bulk imports	35,187	26,514	23,508	32.7	12.8	11,972	10,717	13,102	11.7	—18.2	
Of which:	(55.9)	(55.4)	(54.4)			(55.1)	(55.2)	(54.4)			
(A) Capital goods	12,926	10,436	10,471	23.9	—0.3	4,463	4,233	5,836	5.4	—27.5	
	(20.5)	(21.8)	(24.2)			(20.5)	(21.8)	(24.2)			
(B) Mainly export-related items	12,030	8,828	6,603	36.3	33.7	4,154	3,581	3,680	16.0	—2.7	
	(19.1)	(18.4)	(15.3)			(19.1)	(18.4)	(15.3)			
(a) Pearls, precious & semi-precious stones	7,011	4,825	3,738	45.3	29.1	2,421	1,957	2,083	23.7	—6.0	
(b) Chemicals, organic & inorganic	4,242	3,399	2,289	24.8	48.5	1,465	1,379	1,276	6.2	8.1	
(c) Textile yarn, fabrics, etc.	417	338	443	23.5	—23.7	144	137	247	5.1	—44.4	
(d) Cashew nuts, raw	360	267	134	35.1	90.0	124	108	75	15.0	44.9	
(C) Others	10,231	7,252	6,434	41.1	12.7	3,355	2,903	3,586	15.6	—19.0	
Of which:	(16.3)	(15.2)	(14.9)			(15.4)	(15.0)	(14.9)			
(a) Artificial resins & plastic materials	1,206	1,402	1,095	—13.9	28.1	417	569	610	—26.8	—6.8	
(b) Professional, scientific & optical goods, etc.	1,484	1,004	1,060	47.8	—5.3	512	407	591	25.8	—31.0	
(c) Coal, coke & briquettes, etc.	1,379	1,036	789	33.1	31.3	476	420	440	13.3	—4.4	
(d) Medicinal & pharmaceutical products	713	559	468	27.7	19.2	246	227	261	8.7	—13.2	
(e) Chemical material & products	450	338	286	33.0	18.2	155	137	159	13.2	—14.0	
(f) Non-metallic mineral manufactures	250	219	203	14.0	7.9	86	89	113	—2.9	—21.4	
Total Imports (I+II)	62,923	47,851	43,193	31.5	10.8	21,726	19,411	24,073	11.9	—19.4	

* Provisional.

Note : Figures in brackets represent percentages to total imports.

Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

APPENDIX TABLE VI 8: INDIA'S TRADE WITH RUPEE PAYMENT AREA (RPA) AND GENERAL CURRENCY AREA (GCA)

Fiscal Year	RPA			GCA			Total		
	Exports	Imports	Trade balance	Exports	Imports	Trade balance	Exports	Imports	Trade balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rupees crore									
1985-86	2,310	2,071	239	8,585	17,587	-9,002	10,895	19,658	-8,763
1986-87	2,231 (-3.4)	1,359 (-34.4)	872	10,221 (19.1)	18,737 (6.5)	8,516	12,452 (14.3)	20,096 (2.2)	-7,644
1987-88	2,444 (9.5)	1,885 (38.7)	559	13,230 (29.4)	20,359 (8.7)	-7,129	15,674 (25.9)	22,244 (10.7)	-6,570
1988-89	3,162 (29.4)	1,655 (-12.2)	1,507	17,070 (29.0)	26,580 (30.6)	-9,510	20,232 (29.1)	28,235 (26.9)	-8,003
1989-90*	5,173 (63.6)	2,679 (61.9)	2,494	22,508 (31.9)	32,737 (23.2)	-10,229	27,481 (36.8)	35,416 (25.4)	-7,935
1990-91	5,507 (6.5)	2,869 (7.1)	2,638	27,046 (20.2)	40,324 (23.2)	-13,278	32,553 (17.9)	43,153 (22.0)	-10,600
1991-92	4,433 (-19.5)	1,970 (-31.3)	2,463	39,609 (46.5)	45,881 (13.8)	-6,272	44,42 (35.3)	47,851 (10.8)	-3,869
1992-93*	1,970 (-55.6)	1,076 (-45.4)	894	51,381 (29.7)	61,847 (34.8)	-10,466	53,351 (21.1)	62,973 (31.5)	-9,572
US Dollar million									
1985-86	1,888	1,693	195	7,017	14,374	-7,358	8,905	16,467	-7,162
1986-87	1,746 (-7.5)	1,064 (-37.2)	682	7,998 (14.0)	14,662 (2.0)	-6,664	9,756 (9.4)	15,726 (-2.1)	-5,982
1987-88	1,885 (8.0)	1,454 (36.7)	431	10,204 (27.6)	15,702 (7.1)	-5,498	12,489 (24.1)	17,156 (9.1)	-4,667
1988-89	2,183 (15.8)	1,143 (-21.4)	1,041	11,787 (15.5)	18,354 (16.9)	-6,567	13,971 (15.6)	19,497 (13.6)	-5,526
1989-90*	3,107 (42.3)	1,609 (40.8)	1,498	13,519 (14.7)	19,663 (7.1)	-6,144	16,626 (19.0)	21,772 (9.1)	-4,646
1990-91	3,069 (-1.2)	1,599 (-0.6)	1,470	15,073 (11.5)	22,474 (14.3)	-7,400	18,143 (9.1)	24,073 (13.2)	-5,93
1991-92	1,798 (-41.4)	799 (-50.0)	999	16,668 (6.6)	18,612 (-17.2)	-1,944	17,806 (-1.5)	19,411 (-19.4)	-1,54
1992-93*	680 (-62.2)	372 (-53.5)	308	17,741 (10.4)	21,54 (14.7)	-3,613	18,421 (3.1)	21,726 (11.9)	-3,305

* Provisional.

Note : 1. Figures in brackets represent percentage variation over the previous year.

2. Till 1989-90, five countries are included in RPA, namely, USSR, Romania, Czechoslovakia, GDR and Poland. Since 1990-91, the first three of the countries mentioned above are included.

Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

APPENDIX TABLE VI.9 : EXTERNAL ASSISTANCE

Item	Rupees crore							US Dollar million						
	1992-93P	1991-92R	1990-91	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87	1992-93P	1991-92R	1990-91	1989-90	1988-89	1987-88	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Loans	10,363	10,696	6,170	5,138	4,738	4,574	3,176	3,381	4,318	3,438	3,086	3,272	3,528	2,485
2. Grants	1,091	919	534	665	566	478	429	356	371	298	399	391	368	336
3. Gross Utilisation	11,454	11,615	6,704	5,803	5,304	5,052	3,605	3,737	4,689	3,736	3,485	3,663	3,896	2,821
4. Repayments	4,846	3,650	2,329	1,987	1,646	1,581	1,176	1,581	1,474	1,298	1,193	1,137	1,219	920
5. Net (3-4)	6,608	7,965	4,375	3,816	3,658	3,471	2,429	2,156	3,215	2,438	2,292	2,526	2,677	19,01

R—Revised

P—Provisional

Notes : 1. Loans are inclusive of non-Government loans but exclusive of suppliers' credits and commercial borrowings.

2. Grants are exclusive of PL 480-II grants.

3. Figures in U.S. Dollar are converted at annual average rates.

Source : Controller of Aid, Accounts & Audit, Government of India.

APPENDIX TABLE VI. 10 : DEPOSIT LIABILITIES UNDER NR (E)RA AND FCNRA SCHEMES

(Rupees crore)

Non-Resident (External) Rupee Accounts					Foreign Currency Non-Resident Accounts@ (a)								Grand Total			
As at	Inflow during the year@		Total outstanding*		Inflow during the year@		Outstanding						Inflow		Outstanding	
end-March	Rupees crore	US \$ mn.	Rupees crore	US \$ mn.	Rupees crore	US \$ mn.	US Dollar	Pound Sterling	DM	Yen	Total (8 to 11)		Rupees crore (2+6)	US \$ mn. (3+7)	Rupees crore (4+12)	US \$ mn. (5+13)
											Rupees crore	US \$ mn.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1988	477	368	5,107	3,942	1,363	1,051	4,406 (3,410)	541 (222)	—	—	4,947	3,827	1,840	1,419	10,054	7,769
1989	235	162	5,899	3,774	2,230	1,540	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,255	5,275	2,465	1,702	14,154	9,049
1990	277	166	6,507	3,777	2,165	1,309	9,304 (5,409)	337 (119)	1,028 (1,013)	655 (60,327)	11,324	6,586	2,442	1,475	17,831	10,363
1991	156	84	7,349	3,746	255	168	11,270 (5,754)	305 (89)	1,005 (874)	825 (59,403)	13,405	6,838	411	252	20,754	10,584
1992	—44	—27	8,071	2,591	—3,605	—1,611	10,300 (3,978)	2,002 (445)	447 (284)	859 (44,028)	13,608	5,256	—3,649	—1,638	21,679	7,847
1993	111	39	9,062	2,884	223	86	10,107 (3,236)	3,557 (752)	431 (222)	2,477 (91,020)	16,572	5,287	334	125	25,634	8,171
1993 (April-June)	—191	—60	9,099	2,900	—592	—189	9,364 (2,988)	3,621 (774)	474 (258)	2,677 (91,577)	16,136	5,167	—783	—249	25,235	8,067

@Excluding estimated accrued interest.

*Inclusive of accrued interest.

@@Do not include accrued interest.

Notes : 1. Figures in brackets are outstanding deposits in the relevant currencies in million.

2. Conversion to US dollar has been done at annual average rate in case of inflows and at year-end rate in case of outstanding balances.

3. Non-Resident (External) Rupee Account data for the year 1993 are provisional.

APPENDIX TABLE VI.11 : INTEREST RATES ON FCNRA DEPOSITS

(per cent per annum)

Effective Dates	US Dollar				Pound Sterling				DM				Yen			
	6 months	1 year	2 years	3 years	6 months	1 year	2 years	3 years	6 months	1 year	2 years	3 years	6 months	1 year	2 years	3 years
	&	&	&	only	&	&	&	only	&	&	&	only	&	&	&	only
	above to less than 1 year	above to less than 2 years	above to less than 3 years		above to less than 1 year	above to less than 2 years	above to less than 3 years		above to less than 1 year	above to less than 2 years	above to less than 3 years		above to less than 1 year	above to less than 2 years	above to less than 3 years	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
January 27, 1992	5.50	5.75	6.75	7.50	12.00	12.00	12.00	12.00	10.25	10.25	10.50	10.50	7.00	7.00	7.00	7.00
March 27, 1992	5.75	6.25	7.50	8.25	12.00	12.00	12.00	12.00	10.50	10.50	10.50	10.50	6.00	6.00	6.50	7.00
July 13, 1992	4.75	5.25	6.25	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.50	10.50	10.50	10.50	5.75	6.00	6.00	6.50
October 12, 1992	4.00	4.50	5.50	6.25	9.75	10.00	10.00	10.25	9.75	9.75	9.75	9.75	4.75	5.00	5.25	5.75
November 2, 1992	4.50	5.00	6.00	6.75	8.00	8.00	8.75	9.25	9.00	9.00	9.00	9.00	4.75	5.00	5.25	5.75
February 22, 1993	4.25	4.75	5.75	6.50	7.00	7.00	7.50	8.00	8.75	8.50	8.25	8.25	4.25	4.50	4.75	5.25
March 15, 1993	4.00	4.25	5.25	5.75	6.75	6.75	7.25	7.75	8.00	8.00	8.00	8.00	4.25	4.50	4.50	5.00
May 10, 1993	4.00	4.25	5.00	5.50	6.75	7.00	7.75	8.25	8.00	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00
June 8, 1993	4.25	4.50	5.50	6.00	6.75	7.00	7.75	8.25	8.00	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00
July 29, 1993	4.25	4.75	5.50	6.00	6.75	7.00	7.50	8.00	7.75	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00

APPENDIX TABLE VI.12 : INDIA'S EXTERNAL DEBT††

(Rupees crores)

Item	As at the end of March			
	1993p	1992	1991	1990
I. MULTILATERAL	77,398 (24,898)	68,263 (23,089)	40,386 (20,900)	32,886 (19,164)
A. Government Borrowing	71,950 (23,139)	63,787 (21,651)	38,429 (19,887)	31,575 (18,399)
(i) Concessional	48,117 (15,474)	40,990 (14,320)	25,849 (13,377)	21,760 (12,672)
(a) IDA	47,078 (15,140)	40,017 (13,974)	25,221 (13,052)	21,055 (22,261)
(b) Others	1,039 (334)	973 (346)	628 (325)	705 (411)
(ii) Non-concessional	23,833 (7,665)	22,797 (7,331)	12,580 (6,510)	9,815 (5,727)
(a) IBRD	21,355 (6,868)	21,134 (6,796)	12,161 (6,293)	9,752 (5,690)
(b) Others	2,478 (797)	1,663 (535)	419 (217)	63 (37)
B. Non-Government Borrowing	5,448 (1,759)	4,476 (1,438)	1,957 (1,013)	1,311 (765)
(i) Concessional	0	0	0	0
(ii) Non-concessional	5,448 (1,759)	4,476 (1,438)	1,957 (1,013)	1,311 (765)
(a) Public Sector	1,789 (578)	1,424 (458)	303 (157)	158 (92)
(i) IBRD	1,312 (424)	962 (308)	303 (157)	158 (92)
(ii) Others	477 (154)	462 (150)	0	0
(b) Financial institutions	2,869 (926)	2,349 (754)	1,270 (657)	799 (465)
(i) IBRD	1,777 (574)	1,720 (553)	872 (451)	503 (292)
(ii) Others	1,092 (352)	629 (201)	398 (206)	296 (173)
(c) Private sector	790 (255)	703 (226)	384 (199)	354 (208)
(i) IBRD	687 (222)	625 (201)	330 (171)	313 (184)
(ii) Others	103 (33)	78 (25)	54 (28)	41 (24)
II. BILATERAL	48,623 (15,629)	47,603 (15,466)	27,378 (14,168)	22,993 (13,564)
A. Government Borrowing	40,575 (13,050)	40,371 (13,099)	23,065 (11,936)	19,444 (11,489)
(i) Concessional	40,575 (13,050)	40,371 (13,099)	23,065 (11,936)	19,444 (11,489)
(ii) Non-concessional	0	0	0	0

APPENDIX TABLE VI 12 : INDIA'S EXTERNAL DEBT†† (Contd.)

(Rupees crore)

Item	As at the end of March			
	1993p	1992	1991	1990
B. Non-Government Borrowing	8,048 (2,579)	7,232 (2,367)	4,313 (2,232)	3,549 (2,075)
(i) Concessional	1,253 (403)	928 (348)	514 (266)	441 (261)
(a) Public Sector	0	0	0	7 (4)
(b) Financial institutions	1,253 (403)	928 (348)	514 (266)	431 (255)
(c) Private sector	0	0	0	3 (2)
(ii) Non-concessional	6,795 (2,176)	6,304 (2,019)	3,799 (1,966)	3,108 (1,814)
(a) Public Sector	4,726 (1,513)	4,472 (1,432)	2,957 (1,530)	2,581 (1,507)
(b) Financial institutions	1,571 (503)	1,236 (396)	527 (273)	271 (158)
(c) Private sector	498 (160)	596 (191)	315 (163)	256 (149)
III. International Monetary Fund	14,985 (4,799)	8,934 (3,451)	5,132 (2,623)	2,572 (1,493)
IV. EXPORT CREDIT	13,127 (4,206)	12,418 (3,990)	8,374 (4,301)	8,002 (4,655)
(a) Buyers credit	3,989 (1,277)	3,566 (1,142)	2,230 (1,154)	1,877 (1,096)
(b) Suppliers' credit	2,050 (656)	1,380 (442)	933 (483)	950 (555)
(c) Export credit component of bilateral credit	3,314 (1,065)	2,428 (791)	1,390 (719)	1,340 (790)
(d) Defence related export credit	3,774 (1,208)	5,044 (1,615)	3,821 (1,945)	3,835 (2,214)
V. COMMERCIAL BORROWING	36,251 (11,606)	35,664 (11,700)	19,727 (10,209)	15,988 (9,335)
(a) Commercial bank loans	20,156 (6,453)	20,933 (6,704)	13,200 (6,831)	11,453 (6,687)
(b) Securitised borrowings (inclu. IDBs)	13,990 (4,479)	13,219 (4,512)	5,840 (3,022)	4,227 (2,468)
(c) Loans/securitised borrowings etc. with multilateral/bilateral guarantee and IFC(W)	2,105 (674)	1,512 (484)	687 (356)	308 (180)
VI. NRI & FC (B&C) Deposits (above one-year maturity)	23,124 (7,403)	19,581 (7,056)	16,418 (8,319)	13,998 (8,135)
(a) NRI deposits	22,296 (7,138)	18,934 (6,806)	16,231 (8,224)	13,998 (8,135)
of which				
Accrued interest (interest credited)	4,474	3,749	2,379	1,729
on the FCNR deposits	(1,432)	(1,448)	(1,212)	(1,004)
(b) FC (B&O) deposits	828 (265)	647 (250)	187 (95)	0
VII. TOTAL LONG-TERM DEBT (I to VI)	2,13,508 (68,541)	1,92,463 (64,753)	1,17,415 (60,520)	96,439 (56,346)

APPENDIX TABLE VI.12 : INDIA'S EXTERNAL DEBT†† (Contd.)

(Rupees crore)

Item	As at the end of March			
	1993 P	1992	1991	1990
VIII. SHORT-TERM DEBT	13,907	15,881	11,683	9,465
	(4,453)	(5,556)	(6,006)	(5,485)
(a) NRI deposits (less than one year maturity)	7,837	6,494	6,902	5,562
	(2,509)	(2,439)	(3,572)	(3,232)
(b) FC (B&O) deposits	2,433	924	328	0
	(779)	(357)	(167)	
(c) Others (above 6 months)	3,637	8,463	4,453	3,903
	(1,165)	(2,710)	(2,267)	(2,253)
IX. GROSS TOTAL (VII+VIII)	2,27,417	2,08,344	1,29,098	1,05,904
	(72,994)	(70,309)	(66,526)	(61,831)
Memorandum items :				
Short-term debt of 6 months	5,601	4,738	4,976	3,472
	(1,793)	(1,517)	(2,533)	(2,004)
Rupees suppliers' credit	67	72	65	58
	(21)	(20)	(33)	(33)
Civilian Rouble debt	2,905	3,088	2,259	1,741
	(934)	(1,178)	(1,164)	(1,016)
Non-civilian Rouble debt	30,177	28,796	22,875	17,276
	(9,661)	(7,222)	(11,645)	(9,972)
X. Total (Including Memo items)	2,66,167	2,45,038	1,59,273	1,28,451
	(85,403)	(82,246)	(81,901)	(74,856)
Debt Indicators :				
Debt Stock-GDP Ratio (in per cent) (excluding Memo items)	32.4	34.2	24.3	23.3
Debt Stock-GDP Ratio (in per cent) (Including Mem items)	37.9	40.2	30.0	28.3
Debt-Service Ratio* (For fiscal year) (in per cent) (Excluding debt servicing on non-civilian credits)	26.1	26.2	25.2	24.9
(including debt servicing on non-civilian credits)	30.8	31.6	30.5	29.9

* Includes accrued interest on NRI deposits.

†† Revised classification.

P Provisional.

N.A. : Not Available.

Note : Figures in parentheses indicate US dollar million.

APPENDIX TABLE VI.13 : RUPEE EXCHANGE RATES

(Rupees per unit of SDR/Foreign currency)

Period	SDR	US Dollar	Pound Sterling	Deutsche Mark	Japanese Yen
1	2	3	4	5	6
A. Annual Average Rates*					
(April-March)					
1988-89	19.2619	14.4817	25.5959	8.0494	0.1130
1989-90	21.3684	16.6492	26.9179	9.0922	0.1166
	(-9.9)	(-13.0)	(-4.9)	(-11.5)	(-3.1)
1990-91	24.8491	17.9428	33.1930	11.4351	0.1279
	(-14.0)	(-7.2)	(-18.9)	(-20.5)	(-8.8)
1991-92	33.4325	24.4737	42.5152	14.6248	0.1845
	(-25.7)	(-26.7)	(-21.9)	(-21.8)	(-30.7)
(April-February)					
1991-92	33.2584	24.3419	42.3183	14.4449	0.1835
1992-93	36.5615	25.9701	48.0532	16.7031	0.2072
	(-9.0)	(-6.3)	(-11.9)	(-13.5)	(-11.4)
B. Monthly Average Rates					
March 1992*	35.3472	25.8901	44.6775	15.6033	0.1949
March 1992 (FEDAI)**	—	29.4551	51.9588	18.1909	0.2270
March 1993 (FEDAI)**	—	31.5256	45.9520	19.1156	0.2695
% Appreciation (+)/ Depreciation (—) of March 1993** over March 1992**	—	-6.6	13.1	-4.9	-15.8
June 1992*	36.5507	25.8900	47.7889	16.4646	0.2043
June 1992 (FEDAI)**	—	30.2361	55.9065	19.1931	0.2383
June 1993 (FEDAI)**	—	31.4068	47.4174	19.0123	0.2929
% Appropriation (+)/ Depreciation (—) of June 1993** over June 1992**	—	-3.7	17.9	1.0	-18.6
C. Exchange Rates on :					
March 31, 1992*	35.5143	25.8900	44.9490	15.7294	0.1948
March 31, 1992 (FEDAI)**	—	31.2256	53.6913	18.8501	0.2328
March 31, 1993 (FEDAI)**	—	31.2354	46.6200	19.2864	0.2699
June 30, 1992*	37.0530	25.8900	47.2789	17.0182	0.2061
June 30, 1992 (FEDAI)**	—	30.6607	58.4795	20.2429	0.2460
June 30, 1993 (FEDAI)**	—	31.3381	47.3373	18.5701	0.2937

* Represents RBI official rate.

** Represents Foreign Exchange Dealers' Association of India, indicative rates.

Note : Figures in brackets indicate % appreciation (+)/depreciation (—) of Rupee.

[F. No. 19/16/93-BO-1]

M.S. SEETHARAMAN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 1994

का.आ. 1417 :—मैसर्स एशियन होटल्स लि. (हयात रीजेन्सी, दिल्ली) को पंजीगत माल (डिस्कोथेक उपस्कर, रसोईघर उपस्कर आदि) के आयात के लिये रुपये 48,08,361 (अड़तालीस लाख, आठ हजार तीन सौ एकसठ रुपये मात्र) का आयात लाइसेंस सं. पी/सीजी/2134907 दिनांक 30-12-93 प्रदान किया गया था।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिये इन आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति गुम हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति सीमाशुल्क कार्यालय, नई दिल्ली के पास दर्ज कराई गई थी और इसके निम्न 42,02,683.90 रुपये की शेष अप्रयुक्त राशि की छोड़कर 6,05,677 रु. का इस्तेमाल किया जा चुका है।

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, नई दिल्ली के समक्ष रसीदी कागज पर विधिवत शपथ लेकर एक हलफनामा दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस सं. पी/सीजी/2134907 दिनांक 30-12-93 की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति फर्म से खो गई है। अतः यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा-9 (गग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एशियन होटल्स लि. (हयात रीजेन्सी, दिल्ली) को जारी की गई मूल विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति सं. पी/सीजी/2134907 दिनांक 30-12-93 एतद्वारा रद्द की जाती है।

4. उक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[का.सं. 18/1197/एम/94/ईपीसीजी-3/686]

एम.डी. केम, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of Director General of Foreign Trade)

ORDER

New Delhi, the 6th June, 1994

S.O. 1417.—M/s. Asian Hotels Ltd. (Hyat Regency, Delhi) was granted an import licence No. P/GC/2134907 dated 30-12-93 Rs. 48,08,361 (Rupees forty eight lakhs eight thousand three hundred and sixty one only) for import of capital goods (Discotheque equipments, kitchen equipments etc.).

2. The firm has applied for issue of duplicate copy of Exchange control purpose of the above mentioned licence on the ground that the original Exchange Control purpose copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Exchange Control Purpose copy of the licence was registered with Customs House, New Delhi and has been utilised for a sum of Rs. 6,05,677/- leaving an utilised balance of Rs. 42,02,683.90.

3. In support of their contention, the licensee has filed an Affidavit on stamped paper duly sworn in before Notary Public, New Delhi. I am accordingly satisfied that the Exchange Control purpose copy of import licence No. P/CG/2134907 dated 30-12-93 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Exchange Control purpose copy No. P/CG/2134907 dated 30-12-93 issued to M/s, Asian Hotels Ltd. (Hyat Regency, Delhi) is hereby cancelled.

4. The duplicate Exchange Control purpose copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 18/1197/AM/94/EPCG-III/686]

M. D. KEM, Dy. Director General

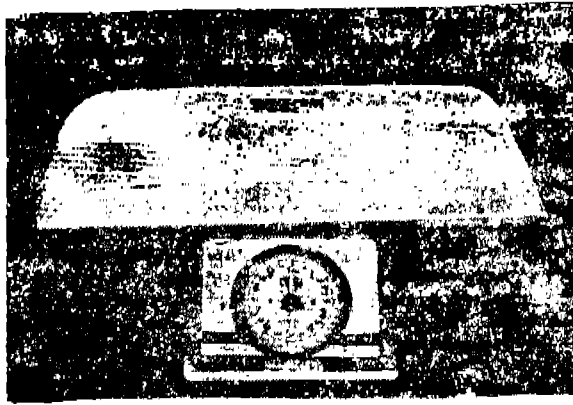
नागरिक प्रति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 1994

का. आ. 1418.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'फाउन' ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, गैर स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) जो मैसर्स रैमन रजिक्व कम्पनी, सी-12, ओल्ड गुप्ता कालोनी, पोली रोड, दिल्ली-110009 द्वारा विनिर्मित है, जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन डी. 409/94/09

समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है।



[आकृति 1]

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक सामान्य शुद्धता (शुद्धता वर्ग III) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 500 ग्राम है। स्थापन मापमान अंतर (ड०) 50 ग्राम है। इसमें आरम्भिक शून्य सैटिंग युक्ति है। मारग्राही पैत आयातकार आकृति की है जिसकी विमाण, 165 मिलीमीटर × 145 मिलीमीटर है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21(8)/93]

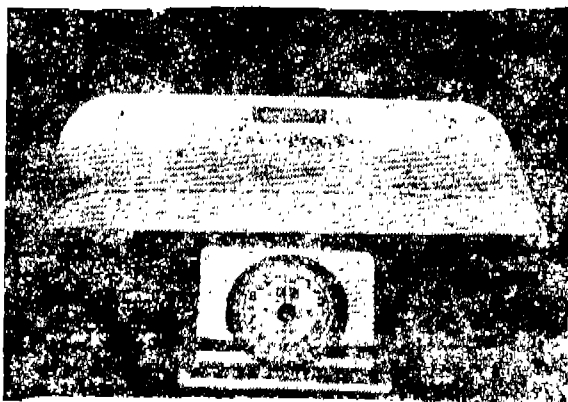
सती नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS
AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 7th June, 1994

S.O. 1413.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provision of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (61 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes, the certificate of approval of the model of the self indicating, non-automatic weighing instrument with the brand name "Crown" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s. Ramon Surgical Company, D-12, Old Gupta Colony, Polo Road, Delhi-110009, which is assigned the approval Mark IND/09/94/09.



[Figure 1]

The Model (see figure 1) is an ordinary accuracy (Accuracy Class-III) weighing instrument with a maximum capacity of 10 kilogram and a minimum capacity of 500 gram. The verification interval (e) is 50 gram. It has initial zero setting device. The load receptor Pan is of rectangular shape with dimension 165 millimetre × 145 millimetre.

[F. No. WM-21(8)]93]

SATHI NAIR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 1994

का. ग्रा. 1419 —केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारी चन्द्र ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

1. क्षेत्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र,
18, मिर्गना रोड, सेवक सभा अस्पताल के पास,
हियाग-125001 (हरियाणा)
2. राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ सयादित,
66, तुगलकाबाद इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
महरोली बदरपुर रोड,
नई दिल्ली-110062.
3. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ,
3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
हौज खास,
खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली-110016.
4. राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र,
सी. जी. ओ. काम्प्लेक्स,
कमला सहकर नगर,
गजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।
5. नेशनल फीडरिंग आफ अरबन कोऑपरेटिव बैक एण्ड
क्रेडिट सोसाइटीज, लि.,
बी-14, "ए" ब्लॉक शांति सेंटर,
नारायणा विहार,
नई दिल्ली-110028
6. क्षेत्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, आधाराताल,
जवाहरपुर (मध्य प्रदेश)।
7. राष्ट्रीय निपहन एवं वनस्पति जल विकास बोर्ड,
फाट नं. -86, सैक्टर -18
गुडगांव-122001 (हरियाणा)।

[सं. 3/15/93-हिन्दी निति]

अनुज सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

S.O. 1419.—In pursuance of Sub-Rule 14 of Rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the Department of Agriculture & Cooperation (Ministry of Agriculture) the staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Regional Bio-Fertilizer Development Centre, 18, Sirsa Road, Near Sewak Sabha Hospital, HISSAR-125001 (HARYANA).
2. National Federation of Fishermen's Cooperatives, 66, Tughlakabad Institutional Area, Mehrauli Badarpur Road, New Delhi-110062.
3. National Cooperative Union of India, 3, Siri Institutional Area, Hauz Khas, Khel Gaon Marg, New Delhi-110016.
4. National Bio-Fertilizer Development Centre, C.G.O. Complex, Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad (Uttar Pradesh).
5. National Federation of Urban Cooperative Banks & Credit Societies Ltd., B-14, 'A' Block Shopping Centre Naraina Vihar, New Delhi-110028.
6. Regional Bio-Fertilizer Development Centre, Adhartal, Jabalpur (Madhya Pradesh).
7. National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board, Plot No. 86, Sector-18, Gurgaon-122001 (HARYANA)

[No. 3-15/93-Hindi Neeti]

ATUL SINHA, Jt. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 4 मई, 1994

का. आ. 1420.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी को जिसके 80% कर्मचारियों ने उक्त नियम के प्रयोजनों के लिए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं. ई-11012/1/94-हिन्दी]

राजीव भूषण सिन्हा, उप सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 4th May, 1994

S.O. 1420.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) the Central Government hereby notifies the Indian National Science Academy the 80 per cent staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi for the purposes of said rule.

[No. E-11012/1/94-Hindi]

R. B. SINHA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई, 1994

का. आ. 1421.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 12 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में "नाईजीरिया" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

नेपाल

त्रिभुवन विश्वविद्यालय एम बी बी एस

बैचलर आफ मेडिसिन और बैचलर आफ सर्जरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय

टिप्पण — यह अर्हता आयुर्विज्ञान महाविद्यालय काठमांडु में प्रशिक्षित उन छात्रों की बावत, जिन्होंने विज्ञान विषयों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, तब मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब वह 27 अप्रैल, 1985 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो।

[संख्या बी-11015/37/90/एम ई (पी) एम ई यू जी]

एस. के. मिश्र, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th May, 1994

S.O. 1421.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 12 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule after the entry NIGERIA, following entry shall be added namely :

"NEPAL			Tribhuvan
Tribhuvan	M.B.B.S.	Bachelor of	University
University		Medicine and	
		Bachelor of	
		Surgery	

Note.—This qualification shall be recognised Medical qualification when granted on or after 27th April 1985 in respect of students trained at Medical College, Kathmandu, who have joined the M.B.B.S. Course after passing the 10+2 examination with Science Subjects."

[No. V. 11015/37/90, ME(P)/ME(UG)]

S. K. MISHRA, Desk Officer

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली 2 जून, 1994

का. आ. 1422.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के

नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसार में, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इंडियन एयरलाइन्स के उत्तरी क्षेत्र के जम्मू, अमृतसर तथा चंडीगढ़ स्टेशनों को, जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[संख्या ई — 11011/6/88-हिन्दी]

रघुनाथ सहाय, उप निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 2nd June, 1994

S.O. 1422.—In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Offices of Jammu, Amritsar & Chandigarh Stations of Indian Airlines Northern Region, under the administrative control of Ministry of Civil Aviation and Tourism (Department of Civil Aviation), the staff of which have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E. 11011/6/88-Hindi]

RAGHUNATH SAHAI, Dy. Director (O.L.)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली 26 मई, 1994

का. ग्रा. 1423.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद सं० 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/18/93-आईआर (बी-2)]

बी के शर्मा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th May, 1994

S.O. 1423.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad No. 2 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 26-5-1994.

[No. L-12012/18/93-IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL

TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947
Reference No. 50 of 1993

PARTIES :

Employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri B. Prasad, State Secretary.

On behalf of the employers : Shri K. K. Mukherjee, Dy. Chief Officer (Law).

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Banking.

Dated, Dhanbad, the 18th May, 1994

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012/18/93-IR.B.II dated, the 17th May, 1993 :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Zonal Office, Uco Bank, Patna in not regularising the service of Sri Vijay Kumar, working as Peon w.e.f. 18-5-87 in the Exhibition Road Branch, Patna is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The terms of reference speaks of non-regularisation of the service of Shri Vijay Kumar who alleged to have been working as Peon with effect from 18-5-87 in the Exhibition Road, Branch of the Uco Bank, Patna.

3. The concerned workman filed W.S. and submitted that joined the services of Uco Bank (hereinafter referred to as Bank) at Exhibition Road Branch on daily wage basis on 18-5-87. He claims to have been attending the duties in the branch of Uco Bank from 10 A.M. to 6 P.M. everyday. He also stated to have been discharging the duties like (1) carrying out token scroll/register from accounts department to cash department, (2) taking out ledgers/registers from Almirah and keeping them on the counter/tables, (3) cleaning the tables, (4) serving water and tea to the members of the staff of the Bank and customers etc.

4. The concerned workman claims to have worked 240 days attendance in every calendar year right from 1988 to 1991. In spite of that he was not being paid his wages at par with the regular employees in the subordinate cadre. The concerned workman in order to get his services regularised and permanently absorbed in the Bank's services approached the Bank management times without number and also through the Uco Bank employees association but the management did not listen. Ultimately on 12-10-89 the management entered into settlement with the workmen's union and agreed to absorb the casuals as permanent employees who had been engaged for full days work for 240 days or more without interruption during the period of 3 years immediately preceding the aforesaid settlement.

5. In pursuance of above settlement the concerned workman applied to the Bank management in the prescribed application on 22-11-89 for his absorption in the Bank's services. The Chief Manager of the Exhibition Road also forwarded application to the Zonal Office for his onwards transmission to the head office at Calcutta. The Chief Manager adjudged the eligibility of the concerned workman for his absorption in the Bank's services but the management did not regularise the services of the concerned workman and finding no solution the association raised industrial dispute. The conciliation also failed giving rise to the present reference. The concerned workman has claimed his regularisation/absorption in the Bank's services with effect from 18-5-87 also for payment of salary at par with regularly employed workmen with similar condition of service in the minimum scale of pay of the subordinate employee of the Bank.

6. The management admitted that the concerned workman started working in the Bank with effect from 18-5-87 as casual water boy on daily wage basis at Exhibition Road Branch Patna Bank. It was stated that the main function of the concerned workman was to serve water and tea to the staff of the Bank and customers as and when required. Most of the period the concerned workman remained idle when there was no order for supply of water and tea. Considering the nature of duty performed by him he used to be paid minimum wages on daily rated basis.

7. Admittedly, there was a settlement dated 12-10-1989 whereby the management of the Bank issued a circular dated 19-10-1989 containing salient features of the settlement. In the aforesaid circular it was stipulated that the casual workers working as water boy on daily rated basis would not be allowed for consideration for regularisation as permanent subordinate staff. That taking into consideration the kinds of job and nature of the employment the union agreed that the water boy will not be allowed for regularisation on permanent post. Since the concerned workman was working as Water Boy he cannot claim for his regularisation in view of the aforesaid settlement and the circular. In the circumstances it was stated that the concerned workman has got no claim and the reference be answered in favour of the management.

8. The question for consideration would be as to whether the concerned workman can be regularised in the Bank's services or not.

9. Shri Vijay Kumar the concerned workman is demanding regularisation in the Bank services with effect from 18-5-87 on the ground that he has been serving as Peon and doing all the job of regular Peon of the subordinate staff every day right from 10 A.M. to 6 P.M. in Exhibition Road Branch of the UCO Bank. He also claims to have completed 240 days attendance in a calendar year. The management on the other hand claims that the concerned workman was engaged as casual water boy on daily wage basis and his main function was to serve tea and water, to the staff and the customers as and when required. Since it was not a regular job it was wrong to suggest that he had been doing every day from 10 A.M. to 6 P.M. It was also denied that he had been doing as regular Peon.

10. First of all I will decide as to whether the concerned workman was doing as casual water boy or the Peon. Engagement of the concerned workman with effect from 18-5-87 is not denied. MW-1 Shri L. S. Gopalkrishnan, the Senior Manager, UCO Bank, Patna has stated that the concerned workman was initially engaged as Water Boy. He denied that he was engaged as Peon. He also denied that the concerned workman was working as Peon against permanent vacancy. However, in cross-examination the witness stated that the concerned workman worked from 10.15 A.M. to 5.30 P.M. every day. He also added that he was discharging all the duties of Peon. In this connection I may refer to Ext. W-3 which is the photocopy of the check list in respect of the concerned workman prepared by this witness. At this stage it may be pertinent to mention that the management of UCO Bank had entered into an agreement on 12-10-89 with workmen's union whereby the casual workers were to be absorbed in the Bank's services, as permanent employees who fulfilled the criteria for eligibility as laid down thereunder. A circular dated 19-10-89 to that effect was also issued for information to all concerned. The photocopy of the settlement is Ext. M-1.

11. The concerned workman in pursuance of that settlement and circular applied for his absorption in the Bank's services on permanent basis giving out his bio-data. Clause 2(a) of the saving clause of agreement provides that persons entitled for being absorbed in terms of the settlement shall apply to the competent authority in the prescribed manner on or before 30-11-89. It further provides that on receipt of such applications the particulars will be verified to satisfy that he meets the necessary eligibility criteria. Shri Vijay Kumar the concerned workman applied within time i.e. 22-11-89 and the particulars were verified vide Ext. W-3. Under clause 2 of the Check list (Ext. W-3) it has been stated as under :—

"Initial appointment was as Water Boy for 3 months and since then doing Peon's job."

This verification was done and endorsement was made by MW-1, the Sr. Manager of the Bank. In view of this oral and documentary evidence it is well established that the concerned workman was doing as Peon. In the check list it is further stated that he was doing full days job as casual worker in subordinate cadre.

12. The concerned workman examined himself as WW-1 and stated that he had been doing the job of a regular Peon from the very day of his engagement. He also stated to have applied for absorption on permanent basis in the Bank's service. The photo copy of the application is Ext. W-2. Besides other details it also states about the yearwise days worked by the concerned workman showing that he worked for more than 240 days in each calendar year. Here I may state the eligibility criteria as enumerated under Ext. M-1, as filed under Ref. No. 48/93. That document may also be read in the present reference. The eligibility criteria reads as follows :—

2. Eligibility criteria :

- (a) Only persons who have been engaged as casual workers for full day's work and who have been discharging any of the normal duties in the Bank in the subordinate cadre as casual workers for a period of 240 days or more with or without interruption during the period of 3 years immediately preceding this settlement. However, those who have been engaged as water boy on daily wage would not be eligible for being considered for absorption under this settlement."

13. As per criteria the concerned workman was required to have worked for 240 days as casual worker which he has already proved by oral and documentary evidence. As per stipulation those who have been engaged as water boy on daily wage would not be eligible for being considered for absorption under the settlement. As discussed above the concerned workman never worked as Water Boy. In the Check list it is stated in Col. 5 that the applicant completed minimum of 240 days of work in 3 years period i.e. from 12-10-86 to 11-10-89. MW-1 Shri Krishnan recommended the case of the concerned workman holding him eligible for subordinate cadre.

14. The concerned workman also proved document to show that he had been doing as Peon and not as Water Boy. Ext. W-5 is the photocopy of the notes addressed to the Manager, Regional Bank of India Patna by the Manager, UCO Bank for sending some documents as per bearers sub-staff. The bearer sub-staff who carried that letter was none else but Shri Vijay Kumar, the concerned workman. This means according to the Manager, UCO Bank the concerned workman was working as sub-staff. Ext. W-6 is the photocopy of the entry slip granted to the concerned workman as sub-staff for his entry into the office of the Reserve Bank of India, Patna.

15. It is the case of the concerned workman that the management did not consider his case for absorption and instead of he was issued show cause (Ext. W-4) for disengagement from the work of casual labour. The main ground taken was that the concerned workman was not engaged on daily wage basis by the appropriate appointing authority and was engaged without any advertisement or without calling for names from the employment exchange office which is in the teeth of Constitutional provision. The second ground was that the concerned workman did not fulfil eligibility criteria.

16. It has already been discussed that the concerned workman had fulfilled all the eligibility criteria and his application was favourably considered and recommended for absorption by an official of the rank of Sr. Manager, UCO Bank, Patna. The concerned workman had replied to show cause notice asserting that he had fulfilled all the eligibility criteria for being considered for absorption in the Bank's services. It was stated that he was not engaged or appointed by a competent authority. Even supposing for the sake of argument he was not engaged by a competent authority even then the management in order to make the things clear and in order had entered into a settlement with the workmen's union for absorption of casual workmen. The concerned workman, as discussed above had been working as Peon and not as Water Boy and he served the department for years together completing more than 240 days attendance in each calendar year. In the circumstances of the case as discussed above the manage-

ment is directed to empanel the concerned workman as subordinate staff within the two months from the date of publication of the Award. The management is further directed to regularise the services of the concerned workman and to absorb him in the Bank's services as and when vacancy arises.

This is my Award.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 मई, 1994

का. आ. 1424—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केनारा बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 12012/171/90/आई आर (बी-2)]

बी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th May, 1994

S.O. 1424.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CANARA BANK and their workmen, which was received by the Central Government on 26-5-94.

[No. L-12012/171/90-IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL: NEW DELHI

I. D. No. 111/90

In the matter of dispute between :

Shri R. P. Singh Grover, through Chairman, Canara Bank Employees Congress, (Reg.) 127, Engineers Enclave, Pitampura, Delhi-110034.

Versus

Assistant General Manager, Canara Bank Delhi Circle, Marshal House, Hanuman Road, Sansad Marg, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri L. C. Sareen for the workman.

Shri N. C. Sikri for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/171/90-I.R.B.II dated 1-10-90 has referred the following industrial dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Canara Bank New Delhi in stopping One increment with cumulative effect of Shri R. P. Singh Grover was justified ? If not to what relief the workman is entitled?"

2. In the statement of claim it was alleged that the workman was originally recruited by the Laxmi Commercial Bank Limited which was later on amalgamated with the Canara Bank on 24-8-85. The workman was an active member of the Canara Bank Employees Congress and was taking interest in strengthening the Union at branch level. This activity of the workman was not liked by the management. He was involved in a case and placed under suspension w.e.f. 8-8-86.

An enquiry was conducted and punishment of stoppage of three increments with cumulative effect was imposed upon the workman. On an appeal the Appellate Authority reduced the punishment to one increment with cumulative effect. The stoppage of increment with cumulative effect was not covered either in the Settlement or Desai Award or Canara Bank Service Code. The workman in his statement has claimed thus urged that the order passed against him was too harsh.

3. The Management in its reply alleged that the Service Code formulated by the management had the contractual force and was applicable to the workman. The amalgamation of Laxmi Commercial Bank with the Canara Bank was not disputed. The Management further alleged that the punishment awarded to the workman was correct and not at all harsh and the enquiry was conducted in a very fair or impartial manner. The leniency was shown by the highest authority and reducing the increments from three to one with cumulative effect.

4. The management examined Shri Rajindera, MW1 while the workman himself appeared as his own witness as MW1. I have heard representatives for the parties and have gone through the record.

5. The representative for the workman and the workman himself have made statement that he has nothing to say about the fairness or otherwise of the enquiry but request for changing of the stoppage of increment for a fixed period. Statement was made in the presence of the representative for the management. After having gone through the points urged by the representative for both the parties, I am of the opinion that since the workman has come with clean hands at this stage and has only prayed for mercy I, therefore, think that the stoppage of one increment for a period of 10 years would satisfy the ends of justice instead of stoppage of increment with cumulative effect. I, therefore, order that the increment be stopped for a period of ten years and whereafter he would be entitled to all benefits. Party shall bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

28th April, 1994.

नई दिल्ली, 30 मई, 1994

का. आ. 1425—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे कोटा के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था ?

[संख्या एल-41011/11/89-डी 2-(बी)आई आर(बी-I)]

बी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th May, 1994

S.O. 1425.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Paschim Railway, Kōla and their workmen, which was received by the Central Government on the 30-5-94.

[No. L-41011/11/89-D.2(B)/IR.B.I]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING
OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL:
NEW DELHI

I. D. No. 123/89

In the matter of dispute between :

1. Shri Anzar s/o Shri Tala
2. Sh. Mumtaz s/o Nazira
3. Shri Ram Kishore s/o Kajod
4. Shri Sabraddin s/o Deena
5. Shri Islamddin s/o Habila
6. Shri Sagir s/o Gafura
7. Shri Amrood s/o Ganshia
8. Shri Nassiruddin s/o Bedraddin
9. Shri Shabbir Hussena
through Divisional Secretary,
Paschini Railway Karamchari Patishad,
Bhimganj Mandi-Kota 324001.

Versus

Executive Engineer (Survey & Construction) Paschim
Railway, Kota, 324001.

APPEARANCES :

Shri A. D. Grover for the workman.
None for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-41011/11/89-D-2(B) dated nil has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of Executive Engineer (Survey and Construction), Western Railway, Kota is justified in not giving the temporary status to the workmen (details are given below) ? If not, what relief these workmen are entitled to ?"

S. No.	Name of workman	Date of engagement
1.	Sh. Anzar s/o Sh. Tala	8-7-83
2.	Sh. Mumtaz s/o Nazira	8-7-83
3.	Sh. Ram Kishore s/o Kajod	8-7-83
4.	Sh. Subraddin s/o Deena	8-7-83
5.	Sh. Islamddin s/o Habila	27-7-83
6.	Sh. Sagir s/o Gafura	27-7-83
7.	Sh. Amrood s/o Ganshia	8-7-83
8.	Sh. Nassiruddin s/o Badraddin	8-7-83
9.	Sh. Shabbir Hussena	8-7-83

2. In the statement of claim the workmen alleged that they had already completed more than 360 days continuous service and were entitled to grant of temporary status with retrospective effect, as per judgment of the Hon'ble Supreme Court. The Management was deliberately deprived of their legitimate rights like annual increments, leave entitlement House rent allowance and other fringe benefits by not issuing formal orders for grant of temporary status.

3. The Management in its reply denied the right of the workman and alleged that the workmen were not entitled as their claim was not justified.

4. Today the representative for the workman made statement that since the workmen involved in this dispute had been transferred to other units and their whereabouts was not known nor the workmen had contacted the representative for the last three years. He further stated that the case may be closed and no dispute award may be given.

5. In view of the above statement of the representative for the workmen I pass no dispute award in this case leaving the parties to bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

13th May, 1994.

नई दिल्ली 30 मई, 1994

का. आ. 1426.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि-करण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 27-5-94 का प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/277/88 डी-III(ए)/आई आर(बी-1)]

बी० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th May, 1994

S.O 1426.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-5-94.

[No. L-12012/277/88-D.III(A)/IR.B.I.]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 104/89

Jagat Singh Vs. State Bank of Patiala.

For the workman : None.

For the management : Shri N. K. Zakhmi.

AWARD

Central Govt. vide gazette notification No. L-12012/277/88-D-3(A) dated 2nd June 1989 issued U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of Patiala in not giving an opportunity to Shri Jagat Singh, temporary Peon/Farash, employed in the Mall Road Branch Patiala as required U/S 25-II of the I. D. Act is justified ? If not, to what relief, the workman concerned is entitled to ?"

2. Brief facts of the case that the petitioner has stated to have worked at the Mall Road Branch of the respondent bank as follow :

20-6-1983 to 19-8-1983

24-8-1983 to 16-9-1983

05-05-1986 to 04-07-1986

09-07-1986 to 12-08-1986

His work and conduct was to the entire satisfaction of the respondent bank. He was not charge sheeted during his employment. No notice or pay in lieu of notice was ever given to him. The petitioner has alleged that the management had employed large number of persons after termi-

nating his services but he was not given employment despite his requests. According to him the management had held interview of temporary employees for absorption in the bank's permanent service. The bank with mala fide intention employed number of persons who are appointed late to the initial appointment of the petitioner and they absorbed permanently. However he has been ignored despite right for appointment in the bank. The management has violated the provisions of Section 25-G and 25-H of the Industrial Disputes Act 1947 and mandatory provisions of Sastri Award, Desai Award and Bipartite Settlement. He has thus sought reinstatement with continuity of service with full back wages and other attended benefits.

3. The management in their written statement has taken the preliminary objection that the petitioner was engaged only for specific period and his contract of employment was not renewed after the expiry of said period. Non-renewal of contract of service does not fall within the ambit of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act 1947, therefore, reference is not maintainable. The management has also raised the objection that the petitioner had worked only for 181 days intermittently. Since he has not completed 240 days, he is not legally entitled to claim employment in the respondent bank. On merits the plea of the management that the petitioner had not completed 240 days of service in 12 calendar months, therefore, his case does not fall within the ambit of Section 25-F of the Industrial Disputes Act. He was engaged temporarily for the specific period. After the expiry of term of employment his contract of service was not renewed, therefore, giving any charge sheet notice or pay in lieu of notice does not arise. The management has further pleaded that in order to give an opportunity for re-employment of ex-temporary peons who has worked in the bank up to September 1985, applications were invited from them through leading newspapers and also through bank's circular. About 2200 persons who had earlier worked as temporary peons had applied to the bank. They were interviewed in February 1986. Various factors like academic qualifications, percentage of marks, job knowledge and performance in interview were seen by the interview committee while awarding the marks to the persons. The panel was prepared in order of merits and persons were put on the waiting list. Out of 2200 persons about more than 260 persons have already been given job and others will also be offered appointment as and when vacancies arise in future. The petitioner Jagat Singh also appeared in the interview and availed the opportunity U/S 25-H of the Industrial Disputes Act 1947 and has been on the waiting list. Therefore, he will also be given appointment as and when his turn comes in the order of merits. The management thus has not violated any provisions of Section 25-G and H of the Industrial Disputes Act 1947 and sought the dismissal of this reference.

4. Replication was also filed reasserting the same facts as in the statement of claim and challenge the provisions of Section 2(oo)(bb) of the Industrial Disputes Act, 1947.

5. The petitioner despite registered notice did not appear to depose and to authenticate his affidavit. The management was asked to lead evidence MW1 Paramjit Singh Deputy Manager is the management's witness. He filed his affidavit Ex. M1. The management closed their evidence.

6. I have heard the counsel for the management, gone through the evidence and record.

7. The plea of the petitioner in the present case is violation of Section 25-H of the Industrial Disputes Act 1947 having the management employed large number of persons the termination of his services. Appointment of the petitioner in his own showing in the statement of claim was for a fixed period from 20-6-1983 to 19-8-1983, 24-8-1983 to 16-9-1983, 5-5-1986 to 4-7-1986 and 9-7-86 to 12-8-1986. The provisions of Bipartite Settlement are applicable to the Banking industry. Para 20.8 of the said Bipartite Settlement dated 19-10-1966 which is relevant to the present case is reproduced below :

"20.8. A temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed a period of three months during which the bank shall make arrangements for filling up the vacancy permanently. If

such temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy the period as such temporary employment will be taken into account as part of his probationary period."

8. It is therefore, apparent that the management is within its competence to appoint temporary workman to fill the permanent vacancy provided that such temporary employee does not exceed three months during which period the bank was required to make arrangement to fill the vacancy permanently. It appears that this provision for appointment of temporary workman has been made keeping in view of the peculiar nature of the functions of the bank which are customer oriented and there could be wide fluctuation in the volume of work on day to day basis. The joining of the petitioner itself for said specified period amounts to giving acceptance.

9. The last tenure on which the petitioner had worked with the respondent management is from 5-5-86 to 4-7-1986 and 9-7-1986 to 12-8-1986. Thus on all the occasions his employment was for a fixed tenure. Clause (bb) of Sub-Section (oo) of Section 2 of the Industrial Disputes Act is effective from 18-8-1984. It is remedial provision prospective in nature and apply only to those terminations which takes place after the provision was brought to statute book. It provides that the termination of service of the workmen as a result of non-renewal of contract being terminated in terms of a stipulation, shall not constitute retrenchment. Therefore, being the petitioner having worked for specified period as said above and the termination had taken effect after 18-8-1984 it has to be held that termination of the services of the petitioner squarely covered by the exclusion clause of Section 2(oo)(bb) of the Industrial Disputes Act 1947 and the management has not violated the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act 1947. The clause (bb) of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act 1947 has held to be valid and constitutional in the case of Terminated Full Time L.I.C. Employees and Vs. Sr. Divisional Manager reported in 1993 (2) S.C.T. page 581 (F.B.) and Raj Bahadur Vs. General Manager Food Specialities Ltd. Moga reported in 1991 (1) PLR page 631. It has also been held in K. Rajan and other Vs. Kerala State Electricity Board reported in 1992 Lab. I. C. page 1208 the workman can claim violation of Section 25-H only if validly retrenched. Further under subsection (bb) thereof retrenchment does not include termination of service of a workman as a result of non-renewal of contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry of said contract being terminated in terms of stipulation on that behalf contained therein. Therefore, he can not claim any benefit U/s 25-H of the Industrial Disputes Act 1947. Similarly the case of the petitioner fallen u/s 2(oo)(bb) of the Industrial Disputes Act 1947 which does not include termination of service of a workman as a result of non-renewal of contract of workman obviously provisions of Section 25-H would not attract.

10. Even factually the petitioner has no case in relation to violation of Section 25-H of the Industrial Disputes Act 1947. It is quite evident from the evidence of the management that in order to give one time opportunity for re-employment to all ex-temporary peons, the bank had invited application from all such temporary employees through advertisement in leading Newspapers and the circular of the Bank to its branches. Those who had applied to the bank in response to the newspapers advertisement and circular were interviewed and the candidates found suitable by interview committee were offered appointments in the bank. The petitioner in his own showing in the claim statement admits to this effect. The stand of the management in the written statement and also in evidence of MW1 Paramjit Singh the management's witness. The petitioner had also appeared in the interview and has been put in waiting list and he will be given appointment as and when his turn comes in the order of merit. This certainly establishes that action of the management inviting the applications of the ex-temporary peons for permanent absorption through advertisement wherein the petitioner was also one of the candidate and had been put in the waiting list is sufficient compliance of Section 25-H of the Industrial Disputes Act 1947. Therefore, the plea that the management has violated the provisions of Section 25-H of the Industrial Disputes Act 1947 is rejected.

11. Hence nothing survive in the proceedings initiated by the petitioner and he is not entitled to any relief what-so-ever. In a way reference is answered accordingly.

Chandigarh.

20-5-1994.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का. आ. 1427.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार केनारा बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक-विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012 108 88 डी-2 (ए) आई आर (बी-II)]

वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1427.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 31-5-1994.

[No. L-12012/108/88-D.II-A/IR (B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 101/88

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Rajeshwar Singh S/o Shri Tej Bahadur, L-46, Laxmi Nagar, New Delhi-92.

Versus

The General Manager, Canara Bank, Marshall House, Parliament Street, New Delhi.

APPEARANCES :

Workman in person.

Shri Ravi Kumar—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/108/88-D.II (A) dated 22-9-88 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of Canara Bank in terminating the services of Shri Rajeshwar Singh from June, 1987 even though leave vacancies existed was justified ? If not to what relief is the workman entitled ?"

2. The case was fixed today for filing arguments when the workman made statement that the management has

already given him permanent job and he did not want to continue with this dispute. He further stated that no dispute award may be given in this case.

3. In view of the statement of the workman No dispute exist between the parties now. A No dispute award is given/passed leaving the parties to bear the own costs.

Dated : 19th May, 1994

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का.आ. 1428.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कैरिज एवं बैगन सुपरि. (लोडिंग), नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/67/92-आई आर (डी-यु)/आई आर बी-I)]

वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1428.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Carriages and Wagon Suptd. (Loading) New Delhi Railway Station and their workmen, which was received by the Central Government on 31-5-1994.

[No. L-41012/67/92 IR (DU)/IR (B-I)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 73/93

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri Deep Chand through Shri Shiv Nath, Assistant General Secretary, N.R.L.U., Railway Colony, Punjabi Lane, Gaziabad (UP) 201001.

Versus

Carriage and Wagon Suptd. (Loading) New Delhi Railway Station, New Delhi-110001.

APPEARANCES :

None.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-41012/67/92-IR(DU) dated 4-9-93 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether AME/CW-II, NDLS was justified in removing Shri Deep Chand, S/o Shri Vishnoo, Sweeper from service w.e.f. 15-9-89 ? If not, what relief he is entitled to ?"

2. Registered notice was sent to the parties and served on both the parties but no body appeared. Notices had been sent earlier also but parties has not appeared. It

appears that the parties are not interested in pursuing this case. I, therefore, pass a No dispute award in this case leaving the parties to bear their own costs.

Dated : 20th May, 1994.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का.आ. 1429.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/275/89-आईआर (बी-III)/आईआर बी-1]

बी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1429.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad (A.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-1994.

[No. L-12012/275/89-IR (B-III)/IR (B-I)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatchalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated, 9th day of May, 1994

Industrial Dispute No. 28 of 1991

BETWEEN

The General Secretary, State Bank Employees Union, Peddibhotlavuri Street, Vijayawada-520002

—Petitioner.

AND

The Regional Manager State Bank of India, Region-

III, Regional Office, Visakhapatnam-530020.

—Respondent.

APPEARANCES :

M/s. C. Suryanarayana and P. Bhaskar, Advocates—for the Petitioner.

M/s. K. Srinivas Murthy, G. Sudha and M. Ananthasena Rao, S. Suresh, Advocates—for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-12012/275/89-IR (B-III), dated 10-7-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d) (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of State Bank of India, Visakhapatnam and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India, in dismissing Sri Yedla Mallaiiah, Temporary Watchman-cum-Messenger, Samlkot Branch, vide their order No. (3-0) (DPC) VSP/R-3/No. 55 dated 21st July, 1987 is justified? If not, to what

relief the workman is entitled to and from which date?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 28 of 1991 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner-workman read as follows :—

The workman Sri Yedla Mallaiiah joined the service of the State Bank of India as "Temporary Godown Watchman" at its Eluru Branch in January 1970. While working as such he has allegedly retrenched in December, 1976 and was reinstated under I. D. Act on 23-4-1980 and posted to Ramachandrapuram Branch and was later transferred to Samalkot Branch. Just four months before the date of retirement, he was served with charge sheet dated 23-3-1987 for allegedly giving "falsified statement producing falsified document" at the time of joining the Bank "in 1980" and allegedly concealing his "real age". A domestic enquiry was ordered by the Disciplinary Authority and it was held on 23-5-1987 and 26-5-1987. Following the enquiry show cause notice dated 20-6-1987 was served held the workman "guilty" of the charge and proposing the punishment of dismissal without notice. The date of personal hearing was 20-7-1987 and the letter confirming the punishment of dismissal was dated 21-7-1987 and it was served on 22-7-1987 i.e. the date on which he was to retire from service. The charge sheet and the proceedings in pursuit thereof were in violation of the standing instructions per Bank's Staff Circular No. 49 dated 25-3-1982 the provisions of the 3rd Bipartite Settlement and the principles of natural justice. The punishment was illegal, mala fide and unsustainable and is liable to be set aside.

3. The brief averments of the Respondent Management is read as follows :—

It is not correct that the workman illegally retrenched but as the provisions of Section 25-F were not followed he was directed to be reinstated and the bank duly complied with the same. It is true that a domestic enquiry was conducted and as the charges were proved the workman is held guilty of the charges. It may be true that the Bank is in possession of xerox copy of the Ministry Discharge Certificate of the workman wherein his date of birth was shown as 23-7-1927 and the bank believed the same to be true and gave him employment. While so, the workman is protected category employees, in order to regularise his service in the bank he was interviewed on 27-8-84 at Kakinada and at that time also he submitted a xerox copy of Military Discharge Certificate for the purpose of regularising the service. However, the original was called for verification which he did not produce for a long time and later in the year 1986 he produced it which on close scrutiny revealed that the date of birth and date of enrolment were altered. In order to find out the truth, the Bank referred to Military Authorities who advised that the workmen was 20 years of age when he was enrolled in the military services in the year 1941. As per the Military Regimental Centre (Records) letter dated 14-10-1986 the date of birth of the workmen should be 15-9-1921 and not 23-7-1927 as mentioned in the xerox copy. Thus it was discovered for the first time in the year 1986 that the workman was guilty of producing false certificate to obtain employment in the bank and but for the false certificate he would not have been given the employment and thus he deprived another eligible candidate for the post. The procedure required by law in case of domestic enquiry was scrupulously followed and adequate opportunity was given to the workman to submit his case and only thereafter the order are passed. It is also submitted that except for raising the unsubstantial technical pleas both at the time of domestic enquiry and even now the workman is not able to make out a case or disproved that what is apparent from the available evidence is not true. There are no merits in the petition and the same may therefore be dismissed with costs.

4. The point for determination is whether the action of the Respondent in dismissing Sri Yedla Mallalah is justified or not ?

5. No oral or documentary evidence has been adduced by both the parties.

6. In this case the only point to be adjudicated is with regard to the age discrimination. It is seen that at the time of employment of the petitioner, the Respondent Bank was in possession of xerox copy of the Military Discharge Certificate of the Petitioner herein his date of birth was shown as 23-7-1927 and that the Bank believed the same to be correct and appointed him. It is also seen that the petitioner is a protected category employee and that in order to regularise his services in the Bank, the Bank interviewed him on 27-8-1984 at Kakinada, the petitioner submitted Military Discharge Certificate which was a xerox copy. Doubting the bonafide of the certificate, the original was called for verification which the petitioner did not produce for a long time and later in the year 1985 the petitioner produced it which on close scrutiny revealed that the date of birth and date of enrolment were altered. To find out the truth, the Respondent Bank referred to Military Authorities who advised that the petitioner was 20 years of age when he was enrolled in the Military Services in the year 1941. It is pertinent to note that as per the Military Regimental Centre (Records) letter dated 14-10-1986 the date of birth of the Petitioner should be 15-9-1921 and not 23-7-1927 as mentioned in the xerox copy. Thus it is seen that when it was discovered for the first time in the year 1986 that the petitioner was guilty of producing false certificate to obtain employment in the Respondent Bank. It is also seen that a show cause notice was issued to the workman and charges were framed as soon as the fraud was discovered and the date of joining of the petitioner in duty is irrelevant since he joined on the basis of a fraudulent document which could not be discovered immediately. I find that the act is certainly misconduct and the workman was rightly charge sheeted. I am of the firm opinion that when once petitioner was found guilty of a grave misconduct in submitting a false certificate, the extreme penalty of dismissal imposed is apparently correct and rightly done. Hence I find that there is no merits in the allegation of the petitioner made in the claim statement.

7. In the result, the action of the Management of State Bank of India in dismissing Sri Yedla Mallalah, Temporary Watchman-cum-Messenger, Samalkot Branch vide their Order No. (3-0) (DPC)/VSP/R-3/No. 55 dated 21st July, 1986 is justified. The workmen in dispute is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 9th day of May, 1994.

V. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence

NH

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का.आ. 1430.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यूको बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद सं० 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[(संख्या एल-12012/17/93-आई.आर. (बी-2)]

वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd May, 1994

S.O. 1430.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad No. 2 as shown in the Annexure to the industrial dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-1994.

[No. L-12012/17-93-IR (B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 48 of 1993

PARTIES :

Employers in relation to the management of UCO Bank, Patna and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri B. Prasad, State Secretary.

On behalf of the employers—Shri K. K. Mukherjee, Dy. Chief Officer.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Banking

Dhanbad, the 20th May, 1994

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012/17/93-IR (B-II) dated, the 17th May, 1993.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Zonal Office, UCO Bank Patna in not regularising the service of Sri Bablu, working as Peon w.e.f. 28-11-86 in the main branch Patna is justified ? If not, to what relief is he entitled to ?"

2. As per schedule of the reference the action of the management has to be considered as to whether it is justified in not regularising the services of Shri Babloo working as Peon with effect from 28-11-86 in the main branch Patna of the UCO Bank.

3. The workmen submitted W.S. stating that he joined the services of UCO Bank (hereinafter referred to as Bank) at Exhibition Road, Patna main branch as Peon on daily wages basis on 1-1-84 and since then he has been continuously working in the aforesaid branch every day right from 10.00 A.M. to 6 P.M. He stated that his main function is to carry out token, scroll register from Accounts Deptt. to Cash department, taking out register/ledgers from the Almirah and keeping them on counters/tables. He had also been cleaning the tables and serving water and tea to the members of the staff of the Bank and customers. In this way he claims to have worked for more than 240 days in every calendar year.

4. He approach the management for his regularisation and absorption in the Bank's services but the management is not listen. In the mean time on 12-10-89 the Bank management entered into a settlement with the workmen's union whereby and whereunder it was agreed to absorb casuals as permanent employees who had worked for 240 days or more during the period of 3 years immediately preceding the aforesaid settlement. The concerned workman claim to have worked 285 days in the year 1989 and details of the working days have been given out in para 14 of the W.S.

5. The concerned workman in pursuance of the above settlement applied to the Bank management on 22-11-89 for his absorption in the Bank's services. His application was duly forwarded to the Zonal Office after due verification, while submitting the check list the Chief Manager of the main branch adjudged that eligibility of the concerned workman for his absorption in the Bank's services. But even then the management did not consider the case of the concerned workman. Ultimately the association raised an industrial dispute giving rise to the present reference. The concerned workman has claimed for his regularisation in the Bank's services with effect from 28-11-86.

6. The management also filed W.S. denying the claim of the concerned workman. It was stated that the concerned workman was engaged as casual water boy on 28-11-86 on daily wage basis at Patna main branch of the Bank. The main duty of the concerned workman according to the management was to serve water and tea to the members of the staff of the Bank and the customers as and when required. It was added that the work was for short period and it was not required to be done for the whole day.

7. Admittedly, a settlement was arrived at between the management and all the union operating in the Bank on 12-10-89 whereunder the casual workmen were to be regularised provided they fulfilled the eligibility criteria. It was stated that as per stipulation of the settlement the casual workmen working as Water Boy on daily rated basis would not be allowed for consideration for regularisation as permanent subordinate staff. In the circumstances, it was stated that the demand of the union for regularisation of the concerned workman as Peon was without any justification and he is not entitled to any relief.

8. While giving parawise reply the management denied that the concerned workman joined the services in UCO Bank as Peon with effect from 1-1-84. It was stated that he was neither appointed as Peon nor was engaged on the job of Peon at any point of time. It was also stated that the duty hours of the concerned workman spread over from 10.00 A.M. to 6 P.M. but his performance of duty was limited to few hours only as and when required.

9. The question for consideration would be as to whether the concerned workman was engaged as Peon and he should be regularised in the Bank's services.

10. Shri Babloo the concerned workman is demanding his regularisation in the Bank's services with effect from 28-11-86 on the ground that he has been serving as Peon and doing the jobs of regular Peon everyday from 10.00 A.M. to 6 P.M. He also claimed to have completed 240 days attendance in a calendar year. The management on the other hand claim that he was engaged as casual water boy and his main functions was to serve water and tea as and when required.

11. In view of the pleadings of the parties first of all I would like to discuss whether the concerned workman was doing as Peon as contended by him.

12. He claimed to have joined the services of UCO Bank at Exhibition Road main branch on 1-1-84 but he had no engagement or appointment letter showing his appointment with effect from 1-1-84. However, the management admitted that he was engaged as water boy with effect from 28-11-86. Now let us see if he was doing as Water Boy or the Peon with effect from 28-11-86.

13. MW-1 Shri S. Gopal Krishnan has denied that the concerned workman was doing as Peon against permanent vacancy. He further stated that he had heard that he was engaged as casual water boy. It appears that lastly the truth fell from his lips when he stated that the main function of the concerned workman was to carry out the token scroll register and also to take out ledgers from the almirah. He was also cleaning tables and serving tea and water to the staff and the customers. The witness further stated that the concerned workman was doing everyday from 10.15 A.M. to 5.30 P.M. By making such statement the management virtually admitted that the concerned workman was doing as Peon like other sub-staff.

14. Admittedly, the Bank Management had entered into an agreement on 12-10-89 with the workmen's union whereby it was agreed to absorb casual as permanent employees who had been engaged for 240 days or more with or without interruption during the period of 3 years immediately preceding the aforesaid settlement. The settlement also states the eligibility criteria which are follows :—

"only persons who have been engaged as casual worker for full day's work and who have been discharging any of the normal duties in the Bank in the subordinate cadre as casual workers for a period of 240 days or more with or without interruption during the period of 3 years immediately preceding this settlement. However, those who have been engaged as water boy on daily wage would not be eligible for being considered for absorption under this settlement."

15. The concerned workman in pursuance of the aforesaid settlement applied in the prescribed proforma on 22-11-89 for his absorption in the Bank's services giving out every details including the days worked by him during the year 1986, 1987, 1988 and 1989. In the year 1989 he was shown to have worked for 285 days. At the foot of the application there is a certificate by the Manager of the Bank whereby it has been certified that the information furnished in the application including the number of days worked by the casual labour were found to be true and borne out of the facts and records with branch office. By giving this certificate the management admitted that the concerned workman completed 240 days attendance in a calendar year.

16. A check list was also prepared by MW-1. In clause 2 he stated that the initial engagement of the concerned workman was as Water for 3 months and afterwards doing the job of a Peon. It was also confirmed that he was doing full days job as casual worker in subordinate cadre. It was further confirmed that the applicant completed minimum of 240 days work in three years period i.e. from 12-10-86 to 11-10-89 (both days inclusive). Thus the management by its own document proved that the concerned workman fulfilled all the eligibility criteria for his absorption in the Bank's services as laid down in the settlement in Ext. M-1.

17. The management issued show cause notice (Ex. W-4) for disengagement from work of casual water boy. In the show cause it was stated that it has come to the notice of the management that the concerned workman was not engaged on daily wage basis by appropriate appointing authority and without any advertisement or calling for names from the Employment Exchange office. It was also stated that the concerned workman did not fulfill one or two conditions of eligibility and thereby there was no chance of his absorption in the services of the Bank. The concerned workman replied to the show cause notice stating that he fulfilled every criteria as laid down in the settlement for his empanelment.

18. I have discussed that the concerned workman was working as a regular Peon and he was not solely engaged for the purpose of providing water and tea to the staff of the Bank and the customers. He was doing the job of regular subordinate staff as stated above. The management by its own statement made it clear that he was doing as Peon. By the document of the management it has also been well proved that the concerned workman completed 240 days attendance within 3 years time immediately preceding the date of settlement. In this way it is quite clear that he fulfilled all the eligibility criteria for his absorption in the Bank's services. There is a question that he was not engaged by the appropriate appointing authority. This is very vague question. At this stage I may refer to the settlement dated 19-10-89 (Ext. M-1). It does not state as to whether a workman was engaged by authorised or unauthorised person. It simply states that the branch office of the Bank engaged certain persons on daily wage basis as casual workers continuously for prolonged period notwithstanding the general instruction not to engage casual worker. It further states that such engagement was mostly unauthorised for meeting only temporary needs which will not confer any right of permanent employment. Thus it is clear that in spite of the fact that engagement was made by unauthorised authority and still the management entered into settlement for regularisation of those casuals. The moment the management settled down the eligibility criteria the question of engagement by regular procedure and by the appropriate authority does not arise at all.

19. As per discussion made above I am to hold the view that the concerned workman had fulfilled all the eligibility criteria for his regularisation in the Bank's services. In the circumstances of the case he deserved to be empanelled and accordingly the management is directed to empanel the concerned workman for his absorption in the Bank's services within two months time from the date of publication of the Award. The management is further directed to regularise the services of the concerned workman when permanent vacancy occurs.

This is my Award.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 मई, 1994

का.आ. 1431.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यूको बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/87/93-आई.आर(बी-2)]

बी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 1431.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-1994.

[No. L-12012/87/93-IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU
MADRAS

Thursday, the 21st day of April, 1994

PRESENT :

Thiru K. Sampath Kumaran, B.A., B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 80. 93

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of UCO Bank, Madras).

BETWEEN

The Workman represented by

The Secretary,
UCO Bank Employees Association,
115, Angappan Street,
Madras-600001.

AND

The Zonal Manager,
UCO Bank,
169, Thambu Chetty Street,
Madras-600001.

REFERENCE :

Order No. L-12012/87/93 IR (B-II), dated 16-8-93, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Tvl. A. Muni and P. Kandhan, Advocates appearing for the workman and of Tvl. R. Aravugham and B. Hari-

babu for Tvl. Aiyar and Dolla, Advocates appearing for the Management upon perusing the reference and other connected papers on record and the claim statement having not been filed, this Tribunal passed the following :

AWARD

This dispute between the workman and the Management of UCO Bank, arises out of a reference under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the management of UCO Bank in not considering the request of Smt. Thiruppammal, Sweeper for transfer on the ground that the guidelines contained in the circular No. 4/80 dated 7-3-80 are not applicable to her is justified ? If not to what relief she is entitled ?"

Claim statement not filed. Further time refused. Passed over. When taken up after lunch the claim statement is not filed. There is no representation for petitioner. Petitioner called absent. Industrial dispute dismissed for default. No costs.

Dated, this the 21st day of April, 1994.

THIRU K. SAMPATH KUMARAN, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 30 मई, 1994

का.आ. 1432.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/461/एफ/91-आई आर(सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th May, 1994

S.O. 1432.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government (Industrial Tribunal), New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on the 30-5-94.

[No. L-22012/461/F/91 IR(C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,
NEW DELHI

I.D. No. 5/93

In the matter of dispute between :

Shri Bishan Pal Singh,
through the General Secretary,
F.C.I. Executive Employees Union,
2337, Dharampura, O.P. Chipiwara,
Chawari Bazar, Delhi.

Versus

Managing Director,
Food Corporation of India,
16-20 Barakhamba Lane,
New Delhi-110001.

APPEARANCES :

Shri Vinod Kumar—for the workman.
Shri A. K. Raina with Shri A. S. Sukhija—for the
Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/461/F/91-IR(C-II) dated 6-1-93 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, New Delhi, in terminating the services of Shri Bishan Pal Singh w.e.f. 3-6-86 or thereafter was legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. After the filing of the statement of claim and the written statement by the parties, case was fixed for rejoinder. The parties made statement that consent award in this case may be given to which both the parties have agreed. The following terms and conditions have been settled as per para 3 of Ex. M-1.

- "(a) Shri Bishan Pal Singh will be appointed Khalasi as a fresh candidate in the pay scale of Rs. 1265-35-1440-45-1845 as laid down part IX Engg. cadre in the Staff Regulations, 1971 subject to medical fitness and verification of character and antecedents with effect from date he joins in pursuance of this settlement
- (b) That neither the Union nor the Workman will claim any kind of benefit for the past period, i.e. prior to his date of joining.
- (c) That the cost of the case will be borne by respective parties.
- (d) He will be governed by FCI Staff Regulations, 1971 amended from time to time."

3. In view of the settlement between the parties Consent Award in this case leaving the parties to bear their own costs is passed. Party shall remain bound by the statement/settlement Ex. M-1 which shall form part of this Award.

26th April, 1994.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

BEFORE PRESIDING OFFICER, CGIT ANSAL BHAWAN,
NEW DELHI

I.D. No. ६/93 Date of hearing
Sh. Bishan Pal Singh,
through the General Secretary,
FCI Executive Employees Union (NZ).....Workman

Vs.

The Zonal Manager (North),
Food Corporation of India,
Zonal Office, Ansal Bhawan,
K.G. Marg, New Delhi.....Management

Sub :—Application for consent Award between the parties in the above noted matter.

Respected Sir,

Most Respectfully sheweth :

1. That the G.O.I., Ministry of Labour vide their order No. L-22012/461/F/91-IR(C-II) dated 6-1-93 referred the dispute on the following terms to the Hon'ble Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the Management of Food Corporation of India in terminating the services of Sh. Bishan Pal Singh w.e.f. 3-6-86 or thereafter was

legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The FCI Exclusive Employees Union, North Zone has raised the dispute leading to the order of the adjudication by the GOI, Ministry of Labour, discussed the issue for amicable settlement.

3. That after detailed discussions, it has been agreed to by both parties to settle the dispute on the following terms and conditions:—

- (a) Sh. Bishan Pal Singh will be appointed Khalasi as a fresh candidate in the pay scale of Rs. 1265-35-1440-45-1845 as laid down part IX Engg. cadre in the Staff Regulations, 1971 subject to medical fitness and verification of character and antecedents with effect from the date he joins in pursuance of this settlement.
- (b) That neither the Union nor the Workman will claim any kind of benefit for the past period, i.e., prior to his date of joining.
- (c) That the cost of the case will be borne by respective parties.
- (d) He will be governed by FCI Staff Regulations, 1971 amended from time to time.

The Hon'ble Tribunal may be pleased to decide the reference in the form of Consent Award.

Management

FOOD CORPORATION OF INDIA
NEW DELHI

Sd/-
(Bishan Pal Singh)

WORKMAN
THROUGH
Its authorised
representative

Sd/-
(Vinod Kumar)

Sd/-(Illigible)
MANAGEMENT

THROUGH
Its authorised
representative

(A. K. RAINA)

General Secy.
Food Corporation of India
Executive Employees Union (NZ),
New Delhi.

Dated 25-4-1994.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का.आ. 1433.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसर्ग में, एस सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/327/89-आईआर (सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1433.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 31-5-1994.

[No. L-22012/327/89-IR(C.II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT:

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.
Dated, 3rd day of May, 1994
Industrial Dispute No. 19 of 1990

BETWEEN

The Workmen of S.C. Co. Ltd.,
Bellampalli, Adilabad Dist. (A.P.) ... Respondent.

AND

The Management of M/s. S.C. Co. Ltd.,
Bellampalli, Adilabad Dist. (A.P.) ... Respondent

APPEARANCES:

M/s. A. K. Jayaprakash Rao, V. N. Goud, and Ch.
Lakshminarayana, Advocates for the Petitioner.
M/s. K. Srinivasa Murthy, G. Sudha, Advocates for the
Respondent

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-22012(237)/89-IR(C.II), dated -3-1990 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli and their workmen to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the Management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., Bellampalli in not changing the designation of S/Sri M. Shanker and 11 others (Listed below) as Coal fillers is justified? If not, to what relief the workmen concerned are entitled?"

List of the Workmen:

1. S/Sri Muthe Shanker
2. " S. Kista Reddy
3. " Peddi Komaraiah
4. " P. Malliah
5. " Salapala Sammaiah
6. " Oruganti Kumaraswamy
7. " Lakkakula Kishan
8. " Gaja Lingaiah
9. " Nalla Sudhakar Reddy
10. " Chatla Narayana
11. " Pittala Shankar
12. " K. Venkata Rao."

This reference was registered as Industrial Dispute No. 19 of 1990 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner-workman read as follows: It is submitted that the workmen in the reference who were working as Badli workers at Morgans Pit Mine of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli were appointed as Coal Fillers vide office order dated 15-10-1987 and transferred to work at Boipalli Mine of the Respondent. Sri Edla Narasimha Reddy, who was working as Badli worker at Morgans Pit Mine where the above said 12 badli workers are working has been appointed as Coal Filler vide office order dated 15-10-1987 and transferred to work at Mahaveerkhani 3 Incline of the Respondent. The terms and conditions of those two office orders are one and similar. But difference is the Mine instead of Boipalli MVK-3 in case of Sri Edla Narasimha Reddy. As per the term of the office order, all the 12 plus 1 total 13 badli workers should report at the mine where posted. Whereas Sri Edla Narasimha Reddy, refused to go to MVK-3 Incline. The Management again transferred him to MVK-3 Incline vide office order dated 9/11-4-1988. He again refused to obey this office order. The management has detained him at Morgans Pit Mine as per order dated 29-4-1988 and 7-7-1988. The management had confirmed him with effect

from 1-7-1988 at M. Pit Mine. The 12 workmen S/Sri M. Shankar and 11 others have requested the management to give one more chance but the management refused to consider their request. Whereas Sri Edla Narasimha Reddy was given three changes and at last retained at Morgans Pit where he confirmed effective from 1-7-1988. Due to refusal of the management to consider the request of 12 workmen, they had to remain as Badli workers at Morgans Pit till their confirmation as per Memorandum of Settlement, effective from 26-3-1989 i.e. 7 months later than Sri Edla Narasimha Reddy, though all these 13 workers are appointed at the same time. On account of the above, their seniority and other benefits were badli affected for these 12 workers. Though it was due to mistake or by over sight of the management, injustice was done to the 12 workers. It is proper and genuine that all these 12 workmen should also be confirmed effective from 1-7-1988 on par with the confirmation of Sri Edla Narasimha Reddy. Because of the mistake of the management, these 12 workmen were badli affected in seniority wages other benefits etc. It is evident that the management had want only done this and confirmed Sri Edla Narasimha Reddy by allowing him to stay a Morgans Pit Mine itself for giving three changes. It is requested that Hon'ble Tribunal to order the Management to effect the confirmation of these 12 workmen also from 1-7-1988 instead of from 26-3-1989 on par with Sri Edla Narasimha Reddy.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent-Management read as follows:—When there are no vacancies in a mine where the Badlis are working and if there are vacancies in another mines, the badlies of a particular mine will be transferred to the mine where there are vacancies as permanent workers. Under those circumstances, whenever a badli worker is posted as a permanent workman, he will be the junior most in the seniority list of that particular category. All these workmen Sri Shankar and 11 others joined in the Respondent Company as badli workers, they are on the panel of badli workers and they worked at M. Pit of the Respondent at Bellampalli. It may be noticed in the year 1987 there were no permanent vacancies at M. Pit and there were vacancies available at Boipalli Mine. As such the 12 badli workers in this dispute have been posted to Boipalli Mine as permanent workers and they were made permanent on 15-10-1987 and as such they were transferred to Boipalli Mine is not correct. It is submitted that Sri Edla Narasimha Reddy was also working as Badli worker in M. Pit Mine but he was the senior to the 12 badli workers in dispute. He was appointed as Coal Filler w.e.f. 1-11-1987 and transferred to MVK-3 Incline Mine. The same type of terms and conditions were stipulated to Sri Edla Narasimha Reddy as well as to the 12 workmen in dispute. When the first appointment order dated 15-10-1987 was not received by Sri E. Narasimha Reddy, another office order was issued on 29-4-1988 giving him appointment as permanent worker w.e.f. 30-3-1988. Sri Edla Narasimha Reddy submitted a representation on 17-5-1988 and 17-6-1988 stating that he is the senior most badli worker in the Mine. In 1987 he was empanelled as Badli worker at M. Pit and thus he was senior to the 12 workmen in dispute. Basing on his representation, the management found that there is a clerical mistake in his case and he is the seniormost badli worker. The management looked into the matter and rectified and posted him in M. Pit Mine only as permanent workman. As such the workmen in dispute cannot compare their case with that of Sri E. Narasimha Reddy. It may be noticed that all the workmen in dispute were empanelled as Badli workers from 1-4-1986 to 17-7-1986. they are three years juniors to Sri E. Narasimha Reddy. It may be noticed that there were no 12 vacancies in M. Pit Mine to post them. That was the reason they were posted to Boipalli Mine. The allegations that Sri E. Narasimha Reddy was given three chances and at last he was retained at Morgans Pit and confirmed from 1-7-1988 is not correct. The 12 workmen in dispute cannot compare their case with that of Sri E. N. Reddy. A settlement on 3-3-1989 was entered by the management and from that date only their seniority and other benefits will be granted and not from the date when they refused to go to Boipalli Mine as Coal Filler. In view of the above mentioned facts this Hon'ble Court may be pleased to dismiss the claim petition as devoid of merits.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent in not changing the designation of 12 workmen as Coal Fillers is justified or not?

5. M.W.1 was examined on behalf of the Respondent Management and marked Exs. M1 to M7. No oral or documentary evidence have been adduced by the Petitioner-workman.

6. M.W.1 is C. Gopala Rao. In brief he deposed that he knows the facts of this case. Badlies will be engaged to overcome the absenteeism of regular coal fillers. Ex. M1 is the xerox copy of the Standing Orders. There is a procedure for badlies those who have put in 180/240 musters and among them senior most badlies will be regularised as coal filler. Depending upon the vacancies the badlies will be regularise will be posted either in the same mine or in some other mine. Sri M. Shanker and 11 others/petitioners in this case are regularised as Coal Fillers and posted to work at Boipalli Mine from Margon's Pit with the clause he should report for duty to the Colliery Manager, Boipalli on relief, this office order will be automatically cancelled if he do not report at Boipalli by 1-11-1987. Ex. M2 is the true copy of the office order dated 15-10-1987. When badlies made permanent and posted at a particular mine it is not called as transfer. These workmen have not reported at Boipalli Mine when these 12 badlies have not reported at Boipalli Mine, their status were not changed and they were retained at Morgans Pit. There were no permanent vacancies at M. Pit at that time. Because of that only they were posted at Boipalli. Afterwards there is a settlement dated 3-3-1989 under Section 12(3) for regularisation of badlies mentioned at Page No. 4 Item No. 4. The seniority of the 12 petitioners in this case will not be calculated from 1987 onwards as they have not reported at Boipalli Mine. Sri Edla Narasimha Reddy is the Senior most worker and he has represented to retain him at M. Pit and his representation are Exs. M5 and M6. There is no ambiguity in interpretation of settlement or implementation of settlement. All 12 workers involved in this I.D. were made permanent. The Union is not entitled to any relief.

7. In this case it is seen that S/Sri Mutha Shanker and 11 others were working as Badli workers at Morgans Pit of the Respondent Company were appointed as Coal Fillers by an office order dated 15-10-1987 and transferred to work at Boipalli Mine of the Respondent-Company. Similarly Sri Edla Narasimha Reddy who was working as Badli worker at Morgans Pit Mine has been appointed as Coal Filler by an office order dated 15-10-1987 and transferred to work at Mahaveerkhani 3 Incline of the Respondent-Company. The contention of the petitioner workmen is that these two office orders dated 15-10-1987 are one and the same terms and conditions imposed i.e. "You should report for duty to the Colliery Manager, Boipalli, on relief. This office order will be automatically cancelled, if you do not report at Boipalli by 1-11-1987. But there is a difference of Mine one is Boipalli Mine for 12 workmen in dispute and the other Mine is Mahaveerkhani 3 Incline for the one workman Sri Edla Narasimha Reddy. The contention of the workman that Sri Edla Narasimha Reddy refused to go to M.V.K. No. 3 Incline thrice and the Management has detained him at Morgans Pit Mine as per order dated 29-4-1988 and 7-7-1988 and finally Sri E. Narasimha Reddy was confirmed with effect from 1-7-1988 at Morgans Pit Mine. It is also seen that the 12 workmen in dispute have requested the Management to give one more chance but the Management refused to consider their request. I find that it is a clear case of discrimination shown to the 12 workmen in dispute. It is clear case of want on mistake of the Respondent Management, injustice was done to the 12 workmen in question. I find that it is proper and genuine that all these 12 workmen should also be confirmed with effect from 1-7-1988 on par with the confirmation of Sri Edla Narasimha Reddy.

8. In the result, the action of the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli in not changing the designation of S/Sri M. Shanker and 11 others as Coal Fillers is not justified. The Respondent-Management is directed to effect the confirmation of these 12 workmen in dispute also from 1-7-1988 instead of from 26-3-1989 on par with Sri Edla Narasimha Reddy.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 3rd day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal I

Appendix of Evidence

Witnesses Examined
for the Petitioner/
Workmen :

NIL

Witnesses Examined
for the Respondent/
Management :

M.W.1 C. Gopal Rao

Documents marked for the Petitioner/Workmen :

NIL

Documents marked for the Management :

Ex. M1—Xerox copy of the Standing Order.

Ex. M2/15-10-87—True Copy of the Office Order.

Ex. M3—Settlement copy entered on 3-3-89.

Ex. M4/15-10-87—Appointment order of Sri Edla Narasimha Reddy.

Ex. M5/17-5-88—Representation made by the Edla Narasimha Reddy.

Ex. M6/17-6-88—Representation made by the Edla Narasimha Reddy.

Ex. M7/26-3-89—Order making payment to the workmen involved in this I.D.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का.श्रा. 1134.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 17 के अनुसरण में, एस सी सी एन. के प्रबंधन के संबंध निराश्रितों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-22012/55/92-आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1434.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 31-5-1994.

[No. 1-22012/55/92-IR(C-II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L. Industrial Tribunal-I.

Dated : 9th day of May, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 33 OF 1992

BETWEEN

D. Raji Reddy rep. by
(the President, A.P.C.M. Sangh (INTUC))
Indira Bhavan, P.O. Bellampalli Dist.
Adilabad (A.P.)

.. Petitioner

AND

The General Manager, M/s. S.C. Co. Ltd.,

P.O. Mandamarri, Dist. Adilabad (A.P.)—Respondent

APPEARANCES :

M/s. G. Vidyasagar & V. Vishwanatham, N. Vinesh
Raj, G. Ravi Mohan, Advocate for the Petitioner.

M/s. K. Srinivasa Murthy & G. Sudha, P.V.K.K. Babu, Advocates for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/53/92-IR(C.II), dated 18-6-1992 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the section of the management of M/s. S.C.C. Ltd., Mandamarru in not referring Sri D. Raji Reddy, Coal Filler, SMGI Incline to Area Age Determination Committee in violation of Age Retirement Rules of the Company is legal and justified. If not, to what relief the workman entitled to?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 33 of 1992 and notices were issued to both the parties.

2. The claim statement was filed by the Petitioner on 9-11-1993 and the counter was filed by the Respondent on 5-1-1994. For enquiry it was posted to 4-2-1994, and then went on adjourning the matter till 12-4-1994. When the matter is called on 12-4-1994 the Advocate for the Petitioner and the petitioner are not present. There is no representation on their side. The Advocate on record for Respondent is not present. Their Junior Advocate did not argue the matter. Hence the arguments of both side are closed for Award.

3. From the above it is seen that the petitioner is not coming forward to pursue the case and inspite of giving several adjournments and fullest opportunity the Petitioner did not show keen interest in prosecuting the matter. Hence I find that there is no meaning in adjourning the case any further and I find it is just and reasonable to terminate the reference. Hence the reference is terminated.

Award passed.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal this the 9th day of May, 1994.

V. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal.

Appendix of Evidence

NIL

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का.आ. 1435.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, एस सी सी एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/138/82 आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1435.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 31-5-1994.

[No. L-22012/138/82 IR(C II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.
Dated : 2nd day of May, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 62 OF 1992

BETWEEN

The Vice President,
S.C.E. Council (INTUC)
P.O. Godavarikhani,
Karimnagar.

... Petitioner

AND

The General Manager, RGI
M/s. S.C. Co. Ltd.,
P.O. Godavarikhani,
Dist Karimnagar (A.P.)

.. Respondent.

APPEARANCES :

None—for the Petitioner.

M/s. K. Srinivasa Murthy, G. Sudha and P.V.K.K. Babu,
Advocates for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-22012/138/82-IR(C.II) dt. 4-9-1992 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, RG-I, Godavarikhani and their workmen to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of M/s. S.C. Co. Ltd. RG-I, Godavarikhani, in not confirming Sri D. Mallesh, temporary General Mazdoor who has been working in place of Sri T. Sattiah, ex-peon after his death since 1988 as peon is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

This reference is registered as Industrial Dispute No. 62 of 1992 and notice were issued to both the parties.

2. Notice were sent by this Tribunal to both the parties and both of them received the notice as per docket sheet. The petitioner was directed to appear before this Tribunal on 17th October, 1992. On 17-10-1992 petitioner did not turn and called absent despite service of notice. Respondent called absent but Sri K. S. Murthy and G. Sudha etc. Advocates filed vakalat on behalf of the Respondent. Adjournments were given from time to time till 2-4-1994. On 2-4-1994 the petitioner did not file claim statement. The petitioner is called absent. There is no representation on their side. Heard the Advocate for the Respondent. Since no claim statement was filed by the Petitioner and that the petitioner did not appear before this Tribunal to prosecute their case. Having seen that the Petitioner is not coming forward and having seen no interest in the case, there is no use of adjourning the case further. This Tribunal is left with no other alternative except to terminate the reference.

Award passed.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence.

NIL

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का.आ. 1436.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, एस सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार

औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-22012/261/91-आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1436.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 31-5-1994.

[No. L-22012/261/91-IR(C.II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated, 9th day of May, 1994

Industrial Dispute No. 75 of 1991

BETWEEN

The General Secretary, Coal Mines Employees Union, Room No. 8, R.T.C. Complex, Kothagudem Khammam District (A.P.)-507101.

...Petitioner.

AND

The Chairman and Managing Director, M/s. Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem, Khammam District (A.P.)-507101.

...Respondent.

APPEARANCES:

Sri B. Appa Rao, General Secretary for the Petitioner.

M/s. K. Srinivasa Murthy, G. Sudha and Smt. M. Meera, Advocates for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-22012/261/91-IR(C.II) dated Nil referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their workmen to this Tribunal for adjudication:

"Whether the gravity of punishment of dismissal of Sri G. Seshagiri Rao, Watchman, from service with effect from 9-9-1989 awarded by the Management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., Kothagudem is disproportionate to the charges levelled against him? If so, to what relief the workman is entitled to?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 75 of 1991 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner read as follows: The petitioner did splendid job of catching a lorry while it was transporting a stolen drill bits in 1980 and he also caught another lorry while transporting a stolen idol of Lord Anjaneya from the Central Workshop of the Company. In those two incidents an Engineer who happened to be the best friend of the Chief Security Officer was involved. The said C.S.O. developed grudge against the petitioner and made use of the incident of 18-2-1986. On 18-2-1986 he was not allowed for duty and was directed to

go to the C.S.O. to obtain permission and that he went to the C.S.O.'s room and there while talking the workman accepts that he insisted that he be allowed duty without uniform since he was not issued uniforms for the year 1985. But the C.S.O. utilised the opportunity and issue charge sheet alleging that the workman abused him and tried to assault him and that in the enquiry a Senior Inspector and a Jamedar who are subordinates to the CSO were examined as his witnesses and who deposed on the instruction of the C.S.O. and that the enquiry officer being the Company official gave proved report. The enquiry proceedings were closed on 2-3-1987 and no action was further initiated and that the workman was in the impression that no action was taken against him and his file was closed. But to the shock and surprise of the workman the order of dismissal was issued only in 1989 i.e. after two and half years which shows that the action is not taken for the misconduct but it may be either for the statistical purpose or to satisfy the C.S.O. The workman was dismissed from service by order dated 8-9-1989 without issuing the second show cause notice. Hence this dispute. The punishment of dismissal is shockingly disproportionate to the charges levelled against the workman even the same were held proved. The Company considered the case of the dismissal workers namely Sri K. Saraiah, P. Nandiah, B. Narayana, B. Lakshma Reddy but failed to consider the case of the concerned workman. It is prayed that this Hon'ble Court may be pleased to set aside the dismissal order dated 8-9-1989 of Sri C. Seshagiri Rao, Watchman and direct the Respondent to reinstate him with continuity of service with full back wages.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows:—

The allegation that an Engineer who was involved in the theft case is the best friend of Chief Security Officer and as such, the Chief Security Officer developed grudge against him and thus made use of the incident of 18-2-1986 is totally false. So the question of making an allegation that those incidents of 1980 have connection to the incident of 18-2-1986 is false, and made out only for the purpose of this case. The allegation that Uniforms were not issued for the year 1985 and the uniform which he was wearing was torn off and as such he wore civil dress on that day is not correct. For the purpose of identification of watch and ward (Security) staff they were given uniforms. The workman in dispute came for duty without wearing the Uniform and the Chief Security Officer asked him to go back if he was not coming in uniform. On 18-2-1986 Sri Seshagiri Rao came for duty in civil dress without uniform. As such, he was not allowed to attend duty and the concerned Security Staff directed him to go and see the Chief Security Officer and obtain his permission. Sri Seshagiri Rao met the Chief Security Officer and insisted him that he would come only in civil dress and he should be allowed for duty as such. The allegation that the Chief Security Officer utilised the opportunity and issued charge sheet alleging that the workman abused him and tried to assault him is not correct. That Seshagiri Rao did not report for duty the schedule time of 3.00 p.m. on 18-2-1986, that he came in civil dress at 3.30 p.m. and started arguing that he would not wear the uniform while coming to duty as the Company had not provided the same. Instead of complying with the instructions Sri Seshagiri Rao started shouting at the top of his voice and acted in a riotous and disorderly manner and lifted his hand over the C.S.O. to beat him and threatened him in abusive language. Because of the behaviour of Sri Seshagiri Rao a charge sheet was issued on 19-2-1986. As the management was not satisfied with the explanation, Enquiry Officer was appointed to conduct the enquiry. The Enquiry Officer submitted the report basing upon the material available. It is true that the enquiry proceedings were closed on 2-3-1987. The findings were forwarded to the concerned department. But unfortunately the files were misplaced which resulted management could not take action immediately. As soon as the file were traced, the order of dismissal was passed on 8-9-1989. It is submitted that in the Standing Orders there was no provision of issuing second show cause notice. So the second show cause notice is not given. In view of the above mentioned facts, it is submitted that there are no merits in the petitioner's case. As such the petitioner is not entitled for relief prayed for setting aside the dismissal order dated 8-9-1989 nor to reinstate him with continuity of service and back wages and this Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the claim petition.

4. The point for adjudication is whether the gravity of punishment of dismissal of Sri G. Seshagiri Rao from service w.e.f. 9-9-1989 is disproportionate to the charges levelled against him or not?

5. No evidence were let in by both the parties Exs. W1 to W10 is marked on behalf of the Petitioner and Exs. M1 to M21 is marked on behalf of the Respondent Management.

6. The facts of the case that Sri G. Seshagiri Rao, Watchman was appointed on 1-7-1977, that he was charge sheeted with an allegation of misbehaviour i.e. during arguments and conversation before the Chief Security Officer on 18-2-1986 he said "I will see you will be sent out of this place to Bombay" and questioned the authority "who are you to stop me from doing whatever I want". That it was in the year 1986 there was an altercation between the workman and his superior the Chief Security Officer in connection with about the wearing of the uniform and destroy of belt. Whenever there was non-supply of Uniforms in scheduled time there was the practice to attend the work in civil dress. The Superior Officers only waited for no occasion to take revenge against him, due to the grudge nourished against him for the fault of his honesty. The Official took an opportunity when the workman started above entered into a heated arguments with his boss about the wearing of the Uniforms. It is quite obvious the orders of his dismissal is quite disproportionate to the allegations made against him to have been committed. It is seen though the enquiry proceedings ended earlier in 1986 the dismissal orders were issued in the year 1989 nearly after 2-1/2 years, there was no adverse remarks whatsoever against the delinquent workman. Before issuing the final orders of dismissal the management did not communicate the provisional conclusions along with a copy of the enquiry report to facilitate the workman to submit his defence. Thus I find that he was deprived of his opportunity envisaged by the rules of proceedings which is against the principles of natural justice. In this context the Petitioner cited a few observations of their Lordships in 1983 Supreme Courts Case (L&S 26 (1982) 3 S.C.C. 346 of Civil Appeal No. 1531 of 1980 decided on October 21, 1982 which are relevant provided hereunder the perusal of this Hon'ble Court. In para six it is observed "The punishment must be for misconduct. To some extent misconduct is a civil crime which is visited with civil and pecuniary consequences. In this case it has resulted in dismissal from service. In order to avail the charge of vindictiveness, justice, equity and fair play demand that punishment must always be commensurate with the gravity of the offence charged". In para 7 it is observed that "these works indicate that even though misconduct is proved and a penalty has to be imposed, the extreme penalty of dismissal or discharge was not justified in the facts and circumstances of the case meaning thereby that the punishment was either disproportionately heavy or excessive. As stated earlier it is a well recognised principle of jurisprudence which permits penalty to be imposed for misconduct that the penalty must be commensurate with the gravity of the offence charged". So it is clear from the charge sheet issued by the Respondent dated 19-2-1986 that words uttered by the workman to his superior are "I will see, you will be sent out of this place to Bombay" and "who are you to stop me from doing whatever I want". In view of the nature of wording used by the workman which are not so grave, does not warrant the extreme punishment of dismissal, as opined by the Supreme Court in the above case. So in view of the Supreme Court's judgement cited above, the maximum and extreme penalty of dismissal of the workman for alleged offence of misconduct, it is certainly a disproportionate punishment and not maintainable, and the petitioner-workman is deserved for his reinstatement in his interest of natural justice.

7. In the result, the gravity of punishment of dismissal of Sri G. Seshagiri Rao, Watchman, from service with effect from 9-9-1989 awarded by the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem is disproportionate to the charges levelled against him. The Respondent-Management is directed to reinstate the concerned workman into service with continuity of service and with full back wages including all attendant benefits.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 9th day of May, 1994.

Y VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I
1397 GI/94—37

Appendix of Evidence

Witnesses Examined
for the Petitioner :
NIL

Witnesses Examined
for the Respondent :
NIL

Documents marked for the Petitioner (By Consent) :

- Ex. W1/8-9-89—Order of dismissal issued to the workman.
- Ex. W2/31-10-89—Appeal preferred for the workman against the workman dismissal order.
- Ex. W3/24-1-91—Letter issued to the B. Appa Rao by the Director Personal, S.C.C.
- Ex. W4—Letter issued by B. Appa Rao to Chairman and Managing Director, S. C. Company Limited, Kothagudem for reinstatement of G. Seshagiri Rao, Ex Security Guard.
- Ex. W5—Minutes of Conciliation Proceedings of A.L.C. (C) Vijayawada on 31-5-91.
- Ex. W6/31-5-91—Conciliation failure report.
- Ex. W7/5-8-91—Request for interview with card MD by the General Secretary.
- Ex. W8/16-8-91—Representation by G. Seshagiri Rao to the Chairman, and Managing Director, S. C. Company, Kothagudem.
- Ex. W9/20-5-89—Minutes of conciliation held on 7-1-90.
- Ex. W10—Minutes of Conciliation Proceedings held on 26th, 27th March, 1991.

Documents marked for the Management (By consent) :

- Ex. M1/19-2-86—Charge sheet issued to the workman G. Seshagiri Rao.
- Ex. M2/31-3-86—Explanation given by G. Seshagiri Rao.
- Ex. M3/25-4-86—Enquiry Notice.
- Ex. M4/15-5-86—Enquiry Notice.
- Ex. M5/4-6-86—Enquiry Notice.
- Ex. M6/26-6-86—Enquiry Notice.
- Ex. M7/30-6-86—Enquiry Notice.
- Ex. M8/10-7-86—Enquiry Notice.
- Ex. M9/7-8-86—Enquiry Notice.
- Ex. M10/20-2-86—Enquiry Notice.
- Ex. M11/3-9-86—Enquiry Notice.
- Ex. M12/26-12-86—Enquiry Notice.
- Ex. M13/30-12-86—Notice of enquiry.
- Ex. M14/5-1-87—Notice of enquiry.
- Ex. M15/19-1-87—Notice of enquiry.
- Ex. M16/20-2-87—Notice of enquiry.
- Ex. M17/ 2-87—Notice of enquiry.
- Ex. M18—Enquiry Proceedings.
- Ex. M19—Typed copy of enquiry proceedings.
- Ex. M20—Enquiry Report.
- Ex. M21/8-9-89—Dismissal Order.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का.आ. 1437.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकाम बरंगल (आ.प्र.) के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या गुल-40012/19/91-आई आर (डी यू) (भाग)]

के.वी.वी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1437.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Telecom Warangal (A.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on 30th May, 1994.

[No. L-40012/19/91-IR (DU)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.
Dated, 2nd day of May, 1994

Industrial Dispute No. 55 of 1991

BETWEEN

J. Sudhakar Reddy, S/o K. Butchi Reddi,
about 23 years Casual Mazdoor. ... Petitioner

AND

The Sub-Divisional Officer, Phones,
Warangal-506007. ... Respondent.

APPEARANCES:

M/s .C. Suryanarayana and P. Bhaskar, Advocates—for
the Petitioner.

M/s. M. Pandurangarao & B. G. Ravinder Reddy,
Advocates—for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/19/91-IR(DU), dated 4th October, 1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of M/s. Telecom, Warangal (A.P.) and their workmen to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of M/s. Telecom, Warangal (AP) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the service of Sri J. Sudhakar Reddy without complying with the provisions of the Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 55 of 1991 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the petitioner read as follows: The Petitioner claim for reinstatement in service is based on the fact that the SDI Telecom Warangal recruited and employed the petitioner as casual mazdoor initially. The petitioner was employed for 243 days during the period from September, 1986 to June, 1987 but retrenched thereafter on the ground that he was recruited after 30th March, 1985 contrary to the orders of the Director General, P&T, New Delhi prohibiting any fresh recruitment and employment of casual mazdoors. The petitioner was not given notice nor paid wages as per the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. Notwithstanding the aforesaid direction of the Supreme Court the petitioner was retrenched from service on the fallacious ground that he was recruited after 30th March, 1985 the date on which the Director General imposed ban on fresh recruitment/employment of casual mazdoors. The petitioner submits that after absorbing several mazdoors, the Telecom Department issued order dated 7th November, 1989 to grant temporary status to those who could not be absorbed in the regular establishment for want of vacancies. It is thus clear that continuous one year

service as Casual Labourers in the Telecom Department entitled them to temporary status pending their absorption in the regular establishment of the Department, according to their turn in the seniority list of Casual Mazdoors of a recruitment unit and for preparing the seniority list the Director General issues separate orders. The petitioner therefore prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold and declare that his retrenchment is illegal and to direct the respondents to reinstate him in service with full back wages, continuity of service, protection or his seniority and all other benefits which are consequential and/or incidental to such reinstatement and to pass the Award accordingly. The Petitioner relies on following documents in support of his case.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows: The reference itself is illegal for the reasons that the services of the petitioner were never terminated as he was only working on casual basis and the casual mazdoors were offered work and when the same is available. It is submitted that the Department engages casual mazdoors and when temporary works are taken up for laying ground cables and construction of overhead alignments are taken up. As soon as the work is over, the employment of the casual mazdoor comes to an end. Likewise if another work is taken up, and the casual mazdoor comes forward for employment, he will again be engaged till the work lasts. It is submitted in the case or casual mazdoors work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work. The petitioner was engaged as a casual mazdoor in the Sub-Division for 136 days. The petitioner was informed clearly at the time of his initial appointments as casual mazdoor that he was engaged for works of casual nature, and as and when such casual works are completed, he will be disengaged from the muster rolls. The petitioner has also signed a declaration to this effect. Disengagement will not amount to termination and such disengagement is automatic in the case of casual mazdoors. The contention of the petitioner that he is entitled for regularisation is not relevant for purpose of this case and the same is beyond the scope of reference made by the Government. It is therefore, prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award holding that the petitioner is not entitled to any relief.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent management in terminating the service of Sri J. Sudhakar Reddy is justified or not?

5. W.W1 is examined on behalf of the Petitioner and marked Exs. W1 to W6. M.W1 is examined on behalf of the Respondent and marked Ex. M1 on its side.

6. W.W1 is J. Sudhakar Reddy. In brief he deposed that he is recruited in the Telecom Department as casual mazdoor on 11th September, 1986. He worked up to 25th June, 1987 and retrenched from service on that day. He worked for 243 days. He worked in Sub-Division Telecom and Phones both at Warangal and under the same Divisional Engineer, Warangal. He did not absent from work but they stopped him to work on the ground that there was no work. No reasons were given to him for terminating his services, except that he was told that those who were recruited after March, 1985 should be restored. He was not given any notice. He was not given one month wage in lieu of notice. He was not paid any compensation. Even after his retrenchment, the works are going on but they have entrusted to the contractor. At the cost of mazdoors working in the department the works were given to the contractor who are engaging new workers. Several new workers are employed now in the department but he does not know whether they are his juniors or seniors. His name was not shown in any seniority list while he was in service. Atleast no such seniority list was circulated.

7. M.W1 is G. V. Narasimhachari. He deposed that he is working as Section Supervisor under the Respondent for the last one year. The casual mazdoors are engaged for temporary works of digging trenches, cables laying etc. and this work is not continuous in nature. They engaged casual mazdoors only when the work is available and they will not continue them, when the work is not available. The petitioner worked under the Respondent only for 141 days. Ex. M1 is the certified copy of the working days particulars and the works in which the petitioner has worked. The casual mazdoors are informed before the engagement that they would be engaged only when the work is available. In this particular case petitioner might have been informed the same. The petitioner was disengaged after 25th June, 1987 due to

non-availability of work. No junior was continued after disengagement of the petitioner. No contractor is being engaged now for the works done by the Petitioner.

8. The case of the petitioner workman that the Telecom Department recruited and employed the petitioner as Casual Mazdoor for 243 days during the period from September 1986 to June 1987 but retrenched thereafter on the ground that he was recruited after 30th March, 1985 contrary to the order of the Director-General, P&T New Delhi prohibiting any fresh recruitment, and employment of casual mazdoors, that the petitioner was not given notice nor paid wages as per the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act even though he has rendered 243 days service in the year proceeding June 1987 the date on which the petitioner was retrenched from service.

9. The contention of the Respondent that the Department engages casual mazdoors as and when temporary works are taken up for laying ground cables and construction of overhead alignments are taken up. As the work is over, the employment of the casual mazdoor comes to an end. Likewise if another work is taken up and the casual mazdoor comes forward for employment, he will again be engaged till the work lasts, the casual mazdoor work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work.

10. It is seen that the Respondent Department engages casual mazdoors as and when temporary works are taken up for laying ground cables and construction of overhead alignments are taken up. As soon as the work is over, the employment of the casual mazdoor comes to an end. It is seen that the casual mazdoor work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work. Whenever casual mazdoor are taken up for work, they are informed clearly at the time of their initial appointment that they are engaged for works of casual nature and as and when such casual works are completed, they will be disengaged from the muster rolls. So the case of the petitioner, he was engaged purely on temporary basis whenever the work is completed, the requirement of casual labour will not be there. It is clear that the services of casual mazdoor comes to an end as and when the work is completed. Here the work was completed and the requirement of the petitioner is not necessary and the disengagement is automatic in the case of casual mazdoors and such disengagement is not termination as contended by the petitioner-workman. Hence I find that there is no termination of service of the petitioner in this case and the question of regularisation of the petitioner does not arise. It is pertinent to note that the work undertaken is purely of casual nature. Hence I find that the petitioner is not entitled to any relief.

11. In the result, the action of the Management of M/s. Telecom, Warangal (AP) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the service of Sri J. Sudhakar Reddy without complying with the provisions of the Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 is justified. The workman concerned is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this 2nd day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Petitioner/Workman:

W.W1—J. Sudhakar Reddy.

Witnesses Examined for the Respondent/Management:

M.W1—G. V. R. Narasimhachari.

Documents marked for the Workman:

Ex. W1—Xerox copy of the working days particulars.

Ex. W2/4-4-89—Complaint given to RLC(C), Hyderabad.

Ex. W3—Parawise remarks submitted by the Management.

Ex. W4—Rejoinder to Ex. W3 submitted by the workman.

Ex. W5—Minutes of conciliation.

Ex. W6—Failure report of ALC(C), Hyderabad submitted to the Government of India.

Documents marked for the Management:

Ex. M1—Certified copy of the details of the working days particulars of the Petitioner/Workman.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का.अ. 1438.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पोस्ट एवं टेलीग्राफ, जमशेदपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/131/89-डी 2(बी) (भाग)]

के०बी०बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1438.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management Post & Telegraph, Jamshedpur and their workmen, which was received by the Central Government on 31-5-94.

[No. L-40012/131/89-D.II(B)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 155 of 1990

PARTIES:

Employers in relation to Post & Telegraph, Jamshedpur.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer.

APPEARANCES

For the Employers—Sri K. Patar, PRI (Postal), Jamshedpur (East).

For the Workmen—Sri Ajok Kr. Srivastava, Workman concerned.

STATE: Bihar.

INDUSTRY: Postal.

Dated, the 20th May, 1994

AWARD

By Order No. L-40012/131/89-D-2(B) dated 10-7-1990 the Central Government in the Ministry of Labour has, in

exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action taken by the management in terminating the service of Shri A. K. Srivastava, w.e.f. 1-9-89 without assigning any reason is justified? If not what relief the workman is entitled to?"

2. From the written statements and subsequent rejoinders filed by the parties, the case of the management appears to be that since Mail Motor Carriage situated in the compound of Post Office at Golmuri was without any shutter, hence need for a Night Watchman was felt. For this the concerned workmen filed an application and he was appointed at the daily rate of Rs. 10 on 3-7-86. Thereafter shutter was fixed and, as per order of the Post Master General dated 7-7-88, there was no need for a daily wage Night Guard, hence a direction was made to relieve the concerned workman from the job with effect from 1-9-1989 for which one month's wage was sanctioned to be paid to the concerned workman. Admittedly, the concerned workman could not be relieved on 1-9-89 as per the order, but was finally relieved on 4-9-89. The workman claimed that termination of his service was illegal, hence he should be regularised in Group 'D' service with back wages.

3. It may be mentioned that in the rejoinder petition received in the Tribunal on 18-3-1992, the concerned workman made various allegations but I am confining myself to the facts of the case since those allegations, such as, demand of gratification by Sr. Superintendent of Postal Service at Jamshedpur, have not even been substantiated because both the parties agreed to have the Reference adjudicated on the basis of documents on the record. Neither side has adduced oral evidence.

4. The workman has contended that he had put in a total number of 1159 days of service as Night Guard, hence he must be deemed to have continued in service in Group 'D' cadre.

5. There are some admitted facts in this case. Vide Ext. M-10 the concerned workman had moved against the other side in the Central Administrative Tribunal, Patna Bench, in O.A. No. 131/90 which application was finally disposed of by the learned Tribunal by order dated 18-9-90. From the judgement it will appear that the workman had taken the plea that he was working in the post of Night Guard from 3-7-86 and that his service was terminated with effect from 1-9-89. He prayed the Tribunal to quash the order dated 1-9-89 by which his services were terminated as well for a direction to the respondents for regularisation of his service claiming that he had the status of a casual labour and having worked for more than one year, he was entitled to regularisation of his service, and that his termination violated the provision of Industrial Disputes Act. The learned Tribunal, by a reasoned order, dismissed the application on merit.

6. It is also admitted fact that against that decision of The Central Administrative Tribunal, the workman moved in appeal to the Hon'ble Supreme Court by filing Special Leave Petition (Civil) No. 983/91 which would be clear from Ext. W-2, which also contains notice issued by the Hon'ble Supreme Court. This exhibit also contains copy of the order of Central Administrative Tribunal, Patna Bench and application filed before the Hon'ble Supreme Court with its annexures.

7. From Ext. W-3, which is an interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 8-7-91 it will appear that their Lordships ordered S.L.P. to come up after six weeks. While ordering this their Lordships also observed that in the meantime, the Counsel for the Union of India might explore the possibility of giving an alternative posting to the petitioner. Ext. W-5 is the order of the Hon'ble Supreme Court in the aforesaid petition dated 19-8-91 in which their Lordships had mentioned about their previous observation and were further pleased to observe in the order dated 19-8-91 that it was stated before their Lordships that the petitioner could be employed as an E.D. Agent by entering his name on the register and would be absorbed as such within a period of three months. The order further mentioned that in view of this statement at the Bar, the Counsel for the petitioner did not press that petition. Their Lordships ordered that the

petition would stand disposed of as not pressed. Their Lordships also observed that after the petitioner was admitted as an E. D. Agent, he would be entitled to all the benefits to which such employees were entitled under the relevant rules and orders issued from time to time.

8. Having stated these facts, the point that emerges to be decided by this Tribunal are as follows :

- (i) Whether or not the workman is entitled to a declaration that termination of his service with effect from 1-9-89 was not justified, and
- (ii) If it was not justified, then the second point would be about the relief or reliefs to which the workman then would be entitled.

9. Alongwith its written statement the management had filed photo copy of order dated 4-7-86 relating to the initial posting of the concerned workman. As per this letter he was directed to work as contingent paid Night Guard for guarding the Mail Motor in the campus of Golmuri Post Office on daily rated wage of Rs. 10/- with effect from 3-7-86.

10. The workman has brought nothing on the record to show that his engagement as Night Guard for guarding Mail Motor was on a regular or sanctioned post. The very fact that he was ordered to be paid from contingency fund at the flat rate of Rs. 10/- per day shows that this was not a regular appointment, nor on a sanctioned post.

11. In course of argument the workman had raised a point that earlier, in pursuant to general direction of Hon'ble Supreme Court dated 27-10-87 in a writ petition No. 573 (or 373 as this number is not clear from Ext. M-3) of 1986 to pay minimum of pay in the pay scale of regularly employed worker in the corresponding cadre to the casual labourer, he was paid the difference of the amount through Ext. W-1. The workman argued that therefore he would be deemed to have been absorbed in Group 'D' post since he was getting minimum of that pay scale. But this argument is not acceptable. Through Ext. M-3, the Postal Department had ordered direction in compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court that all casual labourers engaged on casual basis were to be paid wages worked out on the basis of the minimum pay in the pay scale of regularly employed workers in the corresponding cadre but without any increment. They were to be entitled to D.A. and A.D.A. on the minimum of the pay scale, but no other allowances were to be paid to them. It was ordered that the expression 'casual labour' would cover also part time casual labour and the workers engaged on contingency, and that they would be paid on pro-rata basis.

12. Ext. W-1 which is a voucher for payment of difference of wages mentioning the workman as contingent paid Night Guard. Therefore, even while paying difference in wages he was treated as the contingent paid Night Guard. Mere fact that he was placed at the minimum of corresponding pay scale would not make him a regularly employed employee of that scale because in that order it was clearly mentioned that he was not to get any increment or any other allowance except D.A. and A.D.A.

13. As part of Ext. W-2, the workman had also filed Annexures 'C' series. It was a circular from the Post Master General, Bihar Circle, inviting certain informations in the light of the judgement of the Hon'ble Supreme Court directing payment of wages and regularisation of service.

14. Ext. M-4 is the order dated 30-10-91 through which the workman was appointed as E.D.D.A. of Golmuri S.O. which was in pursuant to the assurance given on behalf of the Postal Department before the Hon'ble Supreme Court, as stated earlier.

15. It has been argued on behalf of the management that the service of the workman was terminated legally, in accordance with Rule 5 of the C.C.S. (Temporary Service) Rules which provided that the service of a temporary Government servant who is not in quasi-permanent service could be terminated forthwith but then the Government servant would be entitled to claim a sum equivalent to his pay and allowance for the period of notice which was one month. He

submitted that the service of the workman was terminated and he was paid one month's wages.

16. Since there is nothing before me to hold that the workman was appointed on any regular or sanctioned post, and since his appointment was for a specific purpose, the management could have terminated his service in accordance with rules when that specific purpose was no more available for continuing the workman in that job.

17. Here I may mention that the workman has raised a number of points, such as, that even after his employment as E.D.D.A. he was not being allowed to apply for other regular post for which departmental test was to be taken. The representative of the management submitted that the workman would definitely be allowed to sit in such test if he had completed the statutory period in the present post after which alone he would be entitled to sit in such test. The workman argued that for affording him such opportunity the period to be counted should be from the date on which he was appointed as Night Guard and not the date on which he joined as E.D.D.A. Agent. But in view of the observation of the Hon'ble Supreme Court in Ext. W-5 I do not find that this argument is available to the workman. Their Lordships had observed that after he was admitted as an E.D. Agent he would be entitled to all the benefits to which such employees were entitled under the relevant rules and orders issued from time to time. Therefore, this benefit was to be available to him after he was admitted as an E.D. Agent and, on such admittance he was put at par to get all the benefits to which other E.D. Agents were entitled to. The other E.D. Agents were entitled to compete after completing the statutory period counting from the date of their employment as E.D. Agent. Therefore, the workman would not be entitled to add the period of his working as Night Guard including the period when he had remained unemployed after he was stopped from working as Night Guard. In any case such prayer cannot be allowed in view of the fact that I do not find anything irregular in the termination of his service as Night Guard and secondly, strictly speaking, it is also beyond the scope of reference.

18. There is one technical point also by dint of which the workman would not be entitled to any relief from this Tribunal. It appears that on his termination the workman used two forums for redressal of the same grievance, i.e. the forum of Central Administrative Tribunal and the forum of this Tribunal. The Central Administrative Tribunal already had decided the application of the workman, on merit, by a speaking order dated 18-9-1990. It appears from the copy of the decision of the Central Administrative Tribunal that on the date the arguments were heard (14-9-90) there, this matter already stood referred to this Tribunal for adjudication. In this Tribunal also this was, for the first time, brought to my notice on 2-4-94 by the management's representative in course of arguments after which this Tribunal directed both the sides to file certain documents including the copy of the application filed by the workman before the Central Administrative Tribunal. Only thereafter the order of the Central Administrative Tribunal was filed.

19. The Central Administrative Tribunal was a competent authority to decide similar prayer of the workman which was raised before it. The Central Administrative Tribunal having already decided the same matter in issue, between the same parties, that would create bar of res-judicata. This is on the ground of public policy that the decision pronounced by the Court of competent jurisdiction should be final, unless they are modified or reversed by the Appellate Authority. If one is made to face the same kind of litigation more than once, it would be contrary to the considerations of fair play and justice. Their Lordships of Hon'ble Supreme Court, in a decision reported in AIR 1960 SC 1153 (Gulabchand Chhotalal Parikh Vs. State of Gujarat) had held that the provisions of Sec. 11 of the C.P.C. were not exhaustive with respect to an earlier decision operating as res-judicata between the same parties on the same matter in controversy in a subsequent regular suit, and that on the general principle of res-judicata, any previous decision on a matter in controversy, decided after full contest or after affording fair opportunity to the parties to prove their case by a Court competent to decide, it will operate as res-judicata in a subsequent regular suit. This principle was applied by their

Lordships in relation to the decision on merit in writ proceeding under Art. 226 or 32 of the Constitution.

20. In another decision reported in AIR 1960 SC 1150 (Devilal Modi Vs. Sales Tax Officer) the principle of res-judicata as well constructive res-judicata was held to be applicable in between writ applications even if in the subsequent writ application some new grounds were taken.

21. Therefore, a decision on merit by a competent authority i.e. Central Administrative Tribunal, on the same matter in issue, between the same parties, which was heard and finally decided would operate as res-judicata in deciding the same issue by this Tribunal.

22. Moreover, the decision of the Central Administrative Tribunal had become final and operative because on the assurance of the Postal Department for re-employment of the petitioner as E.D.D.A. Agent, the petitioner did not press the S.L.P. filed by him before Hon'ble Supreme Court. Because of the observation of the Hon'ble Supreme Court the petitioner was offered an alternative appointment which was accepted by him and he was so appointed. After his acceptance, Hon'ble Supreme Court also observed about the entitlements of the petitioner after he was so appointed. That order of the Hon'ble Supreme Court had put the final seal over the controversy between the two parties which now cannot be agitated before other authority.

23. Therefore, in any view of the matter, either on facts or in law, I do not find that the action of the management was unjustified or the workman is entitled to any relief other than what he already has got at the instance of the Hon'ble Supreme Court.

24. Therefore, the following award is rendered—

The action of the management in terminating the service of Sri A. K. Srivastava with effect from 1-9-1989 was justified. The workman is not entitled to any relief other than what he has already got under observation of the Hon'ble Supreme Court.

In the circumstances of the case there will be no order as to the cost.

P. K. SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

कां० 1439.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकम्यूनिकेशन, एलुरु के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40011/7/90-आई०आर० (डी०यू०) (भाग)]
के०वी०बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1439.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecommunications Eluru and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-94.

[No. L-40011/7/90-IR(DU)(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

Present :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.
Dated : 10th day of May, 1994

Industrial Dispute No. 49 of 1992

BETWEEN

The District Secretary, All India

Telecom Employees' Union, I.S. & Gr. 'D'
West Godavari Dist. Eluru .. Petitioner

AND

The Dy. General Manager, Telecom,
(The Telecom Dist. Manager),
Eluru-534050. .. Respondent

Appearances :

S/Sri C. Suryanarayana & P. Bhasker, Advocates for
the Petitioner.Sri P. Damodhar Reddy, Addl. Standing Counsel for
Central Government.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40011/7/90-IR(DU), dt. 31-1-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the management of Telecomunications, Eluru and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Telecom Department in terminating the services of S/Sri B. V. N. Prasada Rao, M. V. Ramakrishna and P. Sitaramanjaneyulu, Casual Mazdoors under the control of Sub-Divisional Officer, Telecom Palakol is justified? If not, to what relief the said workmen are entitled to?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 49 of 1992 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner read as follows :—The Petitioner Union submits at the outset that his claim is limited to Sri M. V. Ramakrishna as the other two workmen are not interested in pursuing the dispute. It is prayed that adjudication may be limited to Sri M. V. Ramakrishna alone without prejudice to the rights of the other if and when they turn up. The Sub-Divisional Officer, Telecom, Palakol recruited and employed Sri M. V. Ramakrishna w.e.f. 31-10-1985 vide SDOT's Memo dt. 31-10-1985 recruiting the said workman and another. After employing the workman initially on casual works during the period from 1-11-1985 to 4-1-1986 the SDOT, Palakol included the said workman's name in Muster Rolls w.e.f. 5-1-1986. He was employed continuously for 491 days upto and inclusive of 10-5-1987. The workman was properly recruited in accordance with the orders of the highest authority in the P&T Department, he was asked not to come for work w.e.f. 11-5-1987. Thus he was terminated by verbal orders. No reasons were furnished for termination of the workman's service nor was he paid either one month's wages in lieu of the notice period nor paid any other terminal benefits as per the said mandatory provisions of Section 25-F. The workman made a representation on 15-5-1987 to the S.D.O.T. Palakol praying for reinstatement in service. Hence this reference. This Hon'ble Tribunal may also be pleased to declare that in accordance with the orders of the Department of Telecom in their letter dt. 7-11-1989 the workman Sri M. V. Ramakrishna is entitled the conformer of temporary status pending his absorption into the Telecom Department on a regular basis. The Petitioner prays that the Award may kindly be passed accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent Telecom read as follows :—The casual mazdoors are normally engaged by the Department of Telecom as and when works

like laying of underground cables and construction of over head lines etc. are taken up and when even the projects works are completed and if there are no fresh works, the mazdoors are disengaged. Due to modernisation induction of high technology and progressive removal of over head lines by replacing them with underground cables there has been a reduction in the workload to be carried out by the casual mazdoors. The casual mazdoors who are engaged after 30-3-1985 the department has decided to disengage them as no work can be provided. Sri M. V. Ramakrishna was initially engaged w.e.f. 31-10-1985. One month wages were paid to the workmen subsequently on 29-7-1987 in lieu of the one month's notice. As explained in the earlier paras, the services of the workmen Sri M. V. Ramakrishna, were dispensed w.e.f. 11-5-1987 since there was no scope for giving one month notice he was paid one month wages on 29-7-1987. There are no merits in the claim of the petitioners. It is prayed that the Hon'ble Court may be pleased to hold that the claim of the petitioner is not justified and not to grant any relief to the petitioners in this case.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent in terminating the service of Sri M. V. Ramakrishna is justified or not?

5. W.W1 was examined on behalf of the Petitioner-workman and marked Exs. W1 to W7 on its side. No oral or documentary evidence has been let in by the Respondent.

6. W.W1 is M. V. Ramakrishna. He deposed that he was appointed as Casual Mazdoor on 31-10-1985. He registered his name in the Employment Exchange. He worked in the department till 10-5-1987. He worked for about 500 days during the above period. Thereafter he used to approach the Respondent for work. He was engaged for about one month from 15-2-1988 and for about 2 months from 1-10-1988. Ex. W4 is the notice dt. 20-6-87 proposing to terminate the services of the petitioner w.e.f. 11-5-1987. Thereafter he raised an Industrial Dispute through the Union. Ex. W9 is the xerox copy of the failure of conciliation report. He is not aware whether any of his juniors are employed in the department. He prays this Hon'ble Court to reinstate him into service and grant all other attendant benefits.

7. In this case, the claim of the petitioner Union is limited to Sri M. V. Ramakrishna only as the other two workmen are excluded from this case since they are not interested to pursue the case. There is no dispute about the employment of the petitioner workman under the respondent. After employing the workman concerned initially on casual works during the period from 1-11-1985 to 4-1-1986 the S.D.O.T. Palakol included the said workman's name in Muster Rolls w.e.f. 5-1-86, and worked till 10-5-1987. Finally on 11-5-1987 the workman was asked not to come for work. Hence he was terminated by verbal orders. The allegation of the Respondent Telecom that normally the casual mazdoors are engaged by the Department of Telecom, as and when works like laying of underground cables and construction of over head lines etc. are taken and whenever the project works are completed and if there are no fresh works, the mazdoors are disengaged. It is seen that due to modernisation, induction of high technology and progressive removal of overhead lines by replacing them with underground cables there has been a reduction in the workload to be carried out by the casual mazdoors. The casual mazdoors who were engaged after 30-3-1985 decided not to engage them as no work can be provided. One month wages were paid to Sri M. V. Ramakrishna subsequently on 29-7-1987 in lieu of one month's notice. The Asstt. Labour Commissioner submitted that whose continued engagement is not considered necessary shall be served notice of one month before terminating their services or alternatively one month's wages in lieu of will be paid to them. I find that accordingly the said casual mazdoors services were dispensed with by paying one month wages on 29-7-1987. Hence I find there is no gross violation committed by the Respondent in terminating the services of the workman, and there is no merits in the claim of the petitioner-workman.

8. In the result, the action of the Telecom Department in terminating the services of S/Sri B. V. N. Prasada Rao, M.V. Ramakrishna and P. Sitaramanjaneyulu, Casual Mazdoors under the control of Sub-Divisional Officer, Telecom Palakol is justified. The concerned workmen are not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 10th day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Petitioner/Workman :
W.W1 M. V. Ramakrishna

Witnesses Examined for the Respondent/Management :
—NIL—

Documents marked for the Petitioner/Workman :

- Ex. W1/31-10-85—Appointment Order to M. R. Ramakrishna.
- Ex. W2—Xerox copy of the working days particulars.
- Ex. W3/15-5-87—Complaint given to the Asstt. Commissioner of Labour, Eluru Xerox Copy.
- Ex. W4/20-6-87—Orders of termination of services of casual mazdoors—Reg.
- Ex. W5/31-10-90—Representation given by the Petitioner/Workman.
- Ex. W6—Complaint given to the ALC(C) raising the dispute on illegal retrenchment of Casual Mazdoors—Reg.
- Ex. W7—Parawise remarks submitted by the Management to Ex. W6 (xerox copy).
- Ex. W8—Minutes conciliation proceedings (Xerox copy).
- Ex. W9/22-2-90—Xerox copy of the conciliation failure report.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

कां०आ० 1440.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार टेलीकाम, अदिलाबाद के प्रबन्धन के संबंध नियोजनों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/204/91-आई०आर० (डी०यू०) (भाग)]
के०वी०बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1440.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom, Adilabad and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-1994.

[No. I-40012/204/91-IR (DU)(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated, the 2nd day of May, 1994
Industrial Dispute No. 42 of 1992

BETWEEN

Sri K. Narasa Reddy, S/o Shri Bhoja Reddy, H. No. 3-3-81 Nayaduwada, Nirmal-504106 ..Petitioner

AND

1. The Sub-Divisional Officer,
Telecom, Adilabad-504001.
2. The Dist. Engineer, Telecom,
Adilabad-504001.

Respondents.

APPEARANCES :

M/s. C. Suryanarayana and P. Bhaskar, Advocates—for the Petitioner.

M/s. M. Panduranga Rao and M. V. Rama Rao, Advocates—for the Respondents.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/204/91-IR (DU), dated 25-6-1992 referred the following dispute under Section 10(1)(d) (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the management of Telecom, Adilabad and their workmen for adjudication by this Tribunal.

"Whether the management of Sub-Divisional Office (Rural) Telecom, Adilabad is justified in terminating the services of Shri K. Narasa Reddy w.e.f. 31-8-89? If not, what relief he is entitled to?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 42 of 1992 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner workman read as follows :—

The petitioner submits that he was initially recruited and continuously employed from 4-9-1987 except for a few days each in some months due to cessation of work for departmental reasons. But he was discharged from service on the A/N of 31-8-1989 on the plea that under the orders of Dot, no fresh casual mazdoor can be recruited after 30-3-85 and if so recruited, such mazdoors as recruited after 30-3-85 should be discharged from service as they are not eligible for consideration for absorption in the Department. Thus the petitioner was discharged from service w.e.f. 1-9-1989 even though he was put in a total of 551 days of actual work including 284 days in the one year period preceding termination of his service i.e. during the period from 1-9-1988 to 31-8-1989. Notwithstanding the direction of the Supreme Court, the petitioner was retrenched from service on the fallacious ground that he was recruited after 30-3-85 the date on which the Director-General imposed ban on fresh recruitment/employment of casual mazdoors. The retrenchment was without complying with the mandatory provisions of Section 25-F of the I. D. Act. The petitioner submits that after absorbing several mazdoors, the Telecom Department issued orders dated 7-11-1989 to grant temporary status to those who would not be absorbed in the regular establishment for want of vacancies. It is thus clear that continuous one year service as casual labourers in the Telecom Department entitles them to temporary status pending their absorption in the regular establishment of the Department, according to their turn in the seniority list of casual mazdoors of a recruitment unit and for preparing the seniority list the Director General issued separate orders. The petitioner therefore prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold and declare that his retrenchment is illegal and to direct the Respondent herein to reinstate him in service with full back wages, continuity of service, and all other benefits which are incidental to such reinstatement and to pass the award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondents read as follows :

The reference itself is illegal for the reason that the services of the petitioner were never terminated as he was only working on casual basis and the casual mazdoors were offered work as and when the same available. That the Department engages casual

mazdoors as and when temporary works are taken up for laying ground cables, construction of overhead alignments are taken up. As soon as the work is over, the employment of the casual mazdoors comes to an end. Likewise if another work is taken up and the casual mazdoors comes forward for employment he will again be engaged till the work lasts. That in the case of casual mazdoors, work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work averment that the petitioner employed w.e.f. 4-4-1988 to 31-8-1989 continuously for 385 days is not true. The petitioner worked from March 1989 to August, 1989 only i.e. 160 days. The judgement cited in para 4 does not apply to the present facts as the petitioner worked for 6 months only. The petitioner was informed clearly at the time of his initial appointment as casual mazdoor that he has engaged for works of casual nature and as and when such casual works are completed, he will be disengaged from the Muster rolls. It is submitted that there is a procedure for recruitment of regular employees in the department and therefore the claim of the petitioner that he should be made a permanent employee is not maintainable. The services of casual mazdoor come to an end as and when the work is completed. Such disengagement will not amount to termination and such disengagement is automatic in the case of casual mazdoors. There is no termination of the services of the petitioner and the dispute itself is not maintainable. It is prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award holding that the petitioner is not entitled to any relief.

4. MW-1 was examined on behalf of the Respondent and no documents were marked on its side. Exs. W-1 to W-3 were marked on behalf of the Petitioner and no evidence has been adduced on behalf of the petitioner.

5. MW-1 is A. Satyanarayana. In brief he deposed that he is working as S.D.O. Telecom Adilabad from June 1989. Casual mazdoors are engaged for underground cable work, laying cable and distribution joint work and joint works etc. This work is not regular and continuous. They engage casual mazdoors only when the work is available and they would be disengaged as and when the work for which they were engaged is completed. The petitioner worked under the Respondent from March 1989 to August 1989 for a casual mazdoors that they would be engaged till the completion of the works for which they are engaged and they will not be continued after the work is over. The petitioner did not approach immediately after August 1989 but he is being engaged as casual mazdoor for the last 3 years whenever the work is available.

6. The case of the petitioner that he was continuously employed from 4-9-1987 but he was discharged from service on 31-8-1989 on the plea that under the orders of DOT, no fresh casual mazdoor can be recruited after 30-3-1985 and if so, recruited, such mazdoors as are recruited after 30-3-1985 should be discharged from service as they are not eligible for consideration for absorption in the Department. Hence the petitioner was discharged from service.

7. The allegation of the Respondent that the services of the petitioner were never terminated as he was only working on casual basis and the casual mazdoors were offered work as and when the same is available, that the Department engages casual mazdoors as and when temporary works are taken up for laying ground cables, construction of overhead alignments are taken up, that as soon as the work is over, the employment of the casual mazdoor comes to an end, that in the case of casual mazdoors, work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work averment that the petitioner employed w.e.f. 4-4-1988 to 31-8-1989 continuously for 385 days is not true. The petitioner worked for 160 days during the period from March, 1989 to August 1989. The judgement cited are not relevant and the petitioner is entitled for temporary status and regularisation are beyond the scope of reference.

8. It is seen that the Respondent management engages casual mazdoors as and when temporary works are taken up for laying ground cables, constructions of overhead alignments.

When the work gets over, the employment of the casual mazdoors ceases. If another work is taken up the casual mazdoors are taken up for employment and the petitioner will again be engaged till the work lasts. Here it is seen that the work is not a continuous process. Whenever there is work, casual employees are engaged for such work until it completes the process. Moreover it is seen that the petitioner worked only for 163 days during the period from March 1989 to August 1989 wherein he is not put in 240 days continuous work in a year. The judgement cited by the Petitioner is not relevant to the facts of this case. It is pertinent to note that the petitioner was informed clearly at the time of his initial appointment as casual mazdoor that he was engaged for works of casual nature and as and when such casual works are completed, he will be disengaged from the muster rolls. Moreover there is a procedure for recruitment of regular employees in the Department and that the question of being made permanent employee is not acceptable. When the work is completed, the petitioner was disengaged and such disengagement will not amount to termination and such disengagement is automatic in the case of casual mazdoor. Hence I find that the petitioner is not entitled to continue in service mechanically as a casual labour as there is no termination of the services of the petitioner and therefore the dispute itself is not maintainable. In addition, the petitioner also is not entitled for regularisation as claimed by the petitioner workman himself. Hence I find there is no merits to the facts of the case for the petitioner, and the petitioner is not entitled for any relief as prayed for.

9. In the result, the action of the Sub-Divisional Office (Rural) Telecom. Adilabad is justified in terminating the services of Sh. K. Narasa Reddy w.e.f. 31-8-1989 and the workman in dispute is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for
the Petitioner/Workman :

NIL

Witnesses Examined for
the Respondent/Management :
M.W1 A. Satyanarayana.

Documents marked for the Respondent/Management:

NIL

Documents marked for the Petitioner :

Ex. W1—Xerox copy of the Complaint given by the Petitioner to RLC.

Ex. W2—Xerox copy of the minutes of the Conciliation Proceedings.

Ex. W3—Working days particulars of K. Narasa Reddy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

कां०आ० 1441.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टी०बी० बोर्ड, टी०बी० डेम, बिलैरी के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-42012/70/91—आई०आर० (डी०यू०) (भाग)]

के०बी० बी०, उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1441.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of T. B. Board, T. B. Dam, Bellary and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-94.

[No. L-42012/70/91-IR(DU)(Pt.) to
L-42012/79/91-IR(DU)(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated, 2nd day of May, 1994

Industrial Dispute No. 80 of 1991

BETWEEN

Sri Bramaiah,
C/o President, Daily Wage
Employees Association,
Ananthapur Road,
Bellary 583101.

...Petitioner.

AND

(1) The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam, Via Hospet,
Bellary District 583225(R1).

(2) The Executive Engineer,
L.L.C. Division,
Cantonment, Bellary 583101.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 81 of 1991

BETWEEN

Chinna Urukundappa,
C/o The President,
Government Daily Wage Employees
Association, Ananthapur Road,
Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam-583225.

2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,
Bellary-583101.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 82 of 1991

BETWEEN

Sri Nagappa, C/o The President,
Government Daily Wage Employees
Association, Ananthapur Road,
Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam-583225.

2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,
Bellary-583101.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 83 of 1991

BETWEEN

Masthani,

C/o The President, Government
Daily Wage Employees Association,
Ananthapur Road, Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam-583225.

2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,

Bellary-583101.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 84 of 1991

BETWEEN

Gorentala, C/o The President,
Government Daily Wage Employees
Association, Ananthapur Road,
Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam.

2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,
Bellary-583101.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 85 of 1991

BETWEEN

Narasimhappa, C/o The President,
Government Daily Wage Employees
Association, Ananthapur Road,
Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam.

2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,
Bellary.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 86 of 1991

BETWEEN

Jannaiah, C/o The President,
Government Daily Wage Employees
Association, Ananthapur Road,
Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam.

2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,
Bellary-583101.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 87 of 1991

BETWEEN

Bhargav Reddy, C/o The President,
Government Daily Wage Employees
Association, Ananthapur Road,
Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam.

2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,
Bellary-583101.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 88 of 1991

BETWEEN

Narasappa, C/o The President,
Government Daily Wage Employees
Association, Ananthapur Road,
Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam.

2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,
Bellary-583101.

... Respondents.

Industrial Dispute No. 89 of 1991
BETWEEN

A. Venkateshulu, C/o The President,
Government Daily Wage Employees
Association, Ananthapur Road,
Bellary.

...Petitioner.

AND

1. The Secretary, T. B. Board,
T. B. Dam.
2. The Executive Engineer,
L.L.C. Division, Cantonment,
Bellary-583101.

...Respondents.

Sri N. Vivekananda Swamy, Representative for the Petitioners.

Sri R. Satya Murthy, Advocate for the Respondents.

COMMON AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Orders in (1) No. L-42012/70/91-IR. (DU) dt. 18-12-1991, (2) No. L-42012/71/91-IR(DU), dt. 18-12-1991, (3) No. L-42012/72/91-IR(DU), dt. 18-12-1991, (4) No. L-42012/73/91-IR(DU), dt. 18-12-1991, (5) No. L-42012/74/91-IR(DU), dt. 18-12-1991, (6) No. L-42012/75/91-IR(DU), dt. 18-12-1991, (7) No. L-42012/76/91-IR(DU), dt. 18-12-1991, (8) No. L-42012/77/91-IR(DU), dt. 18-12-1991, (9) No. L-42012/78/91-IR(DU), dt. 18-12-1991, (10) No. L-42012/79/91-IR(DU), dt. 18-12-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of T. B. Board, T. B. Dam, Bellary Dist. and their workmen to this Tribunal for adjudication respectively :—

"Whether the action of the Management of Tunga Bhadra Board, T. B. Dam, Hospet in terminating the services of Sri Bramaiah w.e.f. 1-6-1987, Sri Chinna Urkundappa w.e.f. 1-7-1988, Sri H. Nagappa w.e.f. 1-7-1988? Sri Mastani, w.e.f. 1-7-1988? Sri Gorantha w.e.f. 1-7-1988, Sri Narasimhappa w.e.f. 1-7-1988, Sri Janaiah w.e.f. 1-7-1988, Sri Bhargav Reddy w.e.f. 1-4-1987, Sri Narasappa w.e.f. 1-6-1987, and Sri A. Venkateshulu w.e.f. 1-7-1988 are justified? If not, to what relief are they entitled to?"

These reference were registered as Industrial Dispute Nos. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 and 89 of 1991 respectively and notices were issued to both the parties.

2. The Representative of the Workmen filed a Memo dated 24-3-1994 mentioning that the I.D. No. 80 of 1991 to I.D. No. 89 of 1991 are connected cases and they are raising out of one and the same cause of action as against the same party. It is prayed that this Tribunal be pleased to order clubbing of the above cases and common evidence of the representative of the petitioners may be recorded in I.D. No. 80 of 1991. Hence a common Award is being passed.

3. I.D. No. 80/91.—The Petitioner was appointed on 10-11-1985 as a Literate Mazdoor by the Second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Holgund, Kurnool District and that the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. The Petitioner has rendered his services sincerely and without any bad remarks and that to the satisfaction of the superiors. In brief he has put in 1 year and 7 months of continuous service under the Second Respondent since the date of his appointment. The Petitioner had been orally terminated by the Second Respondent on 1-6-1987 without giving any prior notice or reasons which is highly illegal and against the principles of natural justice. Though the petitioner has put in continuous and uninterrupted service without any blemish. The second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the petitioner w.e.f. 1-6-1987 which is highly unsustainable in the eye of law.

4. I.D. No. 81/91.—The petitioner was appointed in the month of July 1985 as a Man Mazdoor by the Second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Holgund, Kurnool District and that the petitioner was getting as sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. The petitioner has rendered his service sincerely and

without any bad remarks. In brief he has put in 2 years of continuous service under the second Respondent since the date of his appointment. The petitioner had been orally terminated by the Second Respondent on 1-7-1987 without giving any prior notice or reason which is highly illegal and against the principles of natural justice. The Second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the petitioner w.e.f. 1-7-1987 which is highly unsustainable in the eye of law.

5. I.D. No. 82/91.—The petitioner was appointed in the month of October 1984 as a Man Mazdoor by the Second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Holgunda, Kurnool District and that the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. In brief he has put in 3 years 10 months of continuous service under the Second Respondent since the date of his appointment. The Second Respondent has so arbitrarily terminated the services of the petitioner with effect from 1-7-1988 which is highly unsustainable in the eye of law.

6. I.D. No. 83/91.—The petitioner was appointed in the month of February, 1984 as a Man Mazdoor by the Second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Holgund, Kurnool District and that the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. In brief he has put in 4 years and 5 months of continuous service under the Second Respondent since the date of his appointment. The petitioner had been orally terminated by the Second Respondent on 1-7-1988 without giving any prior notice or reasons which is highly illegal and against the principles of natural justice. The Second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the petitioner w.e.f. 1-7-1988 which is highly unsustainable in the eye of law.

7. I.D. No. 84/91.—The Petitioner was appointed in the month of March 1984 as Man Mazdoor by the Second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Holgunda, Kurnool District and that the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. In brief he has put in 4 years and 4 months of continuous service under the Second Respondent since the date of his appointment. The petitioner had been orally terminated by the Second Respondent on 1-7-1988 without giving any prior notice or reasons which is highly illegal and against the principles of natural justice. The Second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the first party w.e.f. 1-7-1988 which is highly unsustainable in the eye of law.

8. I.D. No. 85/91.—The petitioner was appointed in the month of January 1984 as a Man Mazdoor by the second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Holgunda, Kurnool District and that the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. In brief he has put in 4 years and 7 months of continuous service under the second Respondent since the date of his appointment. The petitioner had been orally terminated by the second Respondent on 1st July, 1988 without giving any prior notice or reasons which is highly illegal and against the principles of natural justice. The second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the petitioner w.e.f. 1st July, 1988 which is highly unsustainable in the eye of law.

9. I.D. No. 86/91.—The petitioner was appointed in the month of January 1984 as a Man Mazdoor by the second respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division Holagunda, Kurnool District and the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. In brief he has put in 4 years and 7 months of continuous service under the second Respondent since the date of his appointment. The petitioner has been orally terminated by the second Respondent on 1st July 1988 without giving any prior notice or reasons which is highly illegal and against the principles of natural justice. The second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the petitioner w.e.f. 1st July, 1988 which is highly unsustainable in the eye of law.

10. I.D. No. 87 of 1991.—The petitioner was appointed in the month of July, 1985 as a Man Mazdoor by the second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Holgunda, Kurnool District and that

the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. In brief he has put in 3 years of continuous service under the second Respondent since the date of his appointment. The petitioner had been orally terminated by the second Respondent on 1st July, 1988 without giving any prior notice or reasons which is highly illegal and against the principles of natural justice. The second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the petitioner w.e.f. 1st July, 1988 which is highly unsustainable in the eye of law.

11. I.D. No. 88/91.—The Petitioner was appointed in the month of February, 1984 as a Man mazdoor by the second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Hologunda, Kurnool District and that the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. In brief he has put in 3 years and 4 months of continuous service under the second Respondent since the date of his appointment. The petitioner has been orally terminated by the second Respondent on 1st June, 1989 without giving any prior notice or reasons which is highly illegal and against the principles of natural justice. The second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the first party w.e.f. 1st June, 1987 which is highly unsustainable in the eye of law.

12. I.D. No. 89/91.—The petitioner was appointed in the month of January 1984 as a Man mazdoor by the second Respondent to look after the work of the canal in L.L.C. No. 4 Sub-Division Holagunda, Kurnool District and that the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily wages. In brief he has put in 4 years and 7 months of continuous service under the second Respondent since the date of his appointment. The petitioner has been orally terminated by the second Respondent on 1st July, 1988 without giving any prior notice or reasons which is highly illegal and against the principle of natural justice. The second Respondent has so arbitrarily terminated the service of the petitioner w.e.f. 1st July, 1988 which is highly unsustainable in the eye of law.

13. Soon after the termination of the service of the petitioners, they made number of requests and representations through the Association to the second Respondent for their reinstatement. But in vain. During the course of the conciliation proceedings, the second Respondent has taken a vague contention that the Management (T.B. Board) does not come under the purview of the definition of the "Industry". The oral termination of the petitioners by the second Respondent is against law. The second Respondent has not issued any prior notice nor has not conducted any enquiry prior to the impugned oral order of termination. It is thus in violation of the principles of natural justice. The Second Respondent ought to have considered the points shown in the letter No. 1516/6-10-1988 issued by the second respondent and could have provided reasonable justice to the aggrieved petitioners. The service of the petitioners could have been confirmed and regularised during the year 1986 at the time of preparing the list of the N.M.R. persons working in L.L.C. No. 4 Sub-Division Holagunda Kurnool District. But due to the negligent act and arbitrary administration of the concerned officers, the service of the petitioners have not included in the concerned list and book let. Due to the said laches on the part of the administration branch of the second Respondent, the petitioners have put to this sort of great hardship and injustice including the burning problem of unemployment. The impugned order of termination in the absence of valid order of dismissal falls under the category of retrenchment as defined under Section 2(cc) of the Act. Since the mandatory provisions of the Section of the Act has not been complied with the impugned order of termination tantamounts to the illegal termination as the second Respondent answers the description of an industry within the relevant section of the Act. The petitioners are entitled to invoke the jurisdiction of this Hon'ble Tribunal for relief under the shelter of the judgement of Hon'ble Supreme Court of India in the case of Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A. Rajappa (AIR 1978 SC-548). It is prayed that the Hon'ble Court may be pleased to set aside the impugned oral order of termination of the services of the petitioners, to order reinstatement of the petitioners into service with full back wages and consequential benefits and to grant such other reliefs as this Hon'ble Court deems fit.

14. The brief facts of the counter filed by both the Respondents read as follows : The claimants is put to strict proof

of the allegation that they are entitled to file the claim petitions before the Hon'ble Tribunal, maintain the same as against this Respondent at this stage and seek necessary reliefs on the facts and circumstances of the case. This Respondent specifically denies the same. The claimants are not entitled to any reliefs. The Budget of the Tungabhadra Board is incorporated in the State Budget of Andhra Pradesh passed by the Legislature of Andhra Pradesh and the expenditure incurred including the salaries of staff is later apportioned between the States of Andhra Pradesh and Karnataka. In view of these Tungabhadra Board cannot be considered as Industry and its employees are not covered under the provisions of "INDUSTRIAL DISPUTE ACT". Under Secretary to the Government of India, in fact specifically clarified that the Tungabhadra Board cannot be termed as an industry under the provisions of I.D. Act. The status of the Board has again been explained in para 1 of the Ministry of Water Resources Office Memorandum dated 21st April, 1987 addressed to the Ministry of Labour wherein it has been clarified that the Tungabhadra Board cannot be termed as an Industry. This interpretation has been upheld by the High Court of Karnataka in the case of Dr. Dasa Rao Vs. T.B. Board. The functioning of the Board, inter alia, include maintenance of the Tungabhadra Dam reservoir, Canal system, Horticulture and other functions identical to or connected therewith. The casual labour are employed by the Board depending on the exigencies of work. In short, the Board might have engaged number of workmen till completion of the construction of Dam. It may take years. After completion of the construction of Dam work, it is highly impossible for the Board to continue their and it is highly impossible for the Board to provide employment to all the workmen. Considering the nature of project work involved, considering the facts and circumstances of the case, under any scrol the claimants herein are not entitled to seek any reliefs as against the respondent. The claimants herein are relied upon citation reported in AIR 1990 SC 883 and AIR 1986 SC 584. The Respondents most humbly submit that the facts and circumstances of the case are quite different one and it has no bearing to the facts and circumstances of the case on hand. Since the petitioners are not within the directions of the Supreme Court (AIR 1990 SC 883) the request of the said ex-employees could not be considered and could not engage them under T.B. Board. Under these circumstances, the claimants are not entitled to take shelter the advantage of the writ petition also. Apart from it even in the case of construction project run by the State Government the Supreme Court has held that the workers engaged by the State Government are not covered by the Industrial Disputes Act, vide Civil Appeal No. 8/77 dated 16th October, 1979. Hence it is to be stated that the Hon'ble Court has no jurisdiction to entertain the case under Industrial Disputes Act. The allegation that the applicants were appointed as workers on N.M.R. basis in the year 1983 in L.L.C. Division under the control of the first Respondent and were paid the sum of Rs. 360.00 a month, are not correct and are specifically denied. The allegation that the applicants herein have completed their 240 days of service under this Respondent and that they are entitled to reinstatement is not correct. The ruling reported in AIR 1978 SC 548 are not applicable to the facts and circumstances of the case. The claimants may be called upon to prove that they joined the service under this Respondent, worked for 240 days under this Respondent, by producing all required documentary evidence to the satisfaction of the Hon'ble Court to maintain the claim petition, beyond all reasonable doubt. The claimants may be called upon to produce the appointment orders, service documents and etc. This Respondent specifically denies all allegations. In any evident the claimants are not entitled to seek set aside of alleged oral impugned order of termination not entitled to see reinstatement with full back wages and consequential benefits as alleged. This Respondent is not liable to pay any compensation much less than that is claimed. For the reasons stated above and for the reasons that would be urged at the time of adjudication of the claim, this Respondent prays that the Hon'ble Court may pleased to dismiss the petitions, with costs as against this Respondent in the interest of justice.

15. The point for adjudication is whether the action of the Respondents in terminating the services of the persons mentioned in the reference are justified or not?

16. W.W1 was examined on behalf of the Petitioners and marked Exs. W1 to W5. M.W1 was examined on behalf of the Respondents and marked Exs. M1 and M1(a) on its side.

17. W.W1 is N. V. Vivekananda Swamy. In brief he deposed that he has been appointed as President of the Government Daily Wage Workers Association District Unit Bellari by the President and Chairman of the State Federation. The main object of the District Unit is to look after the welfare and solve the other problems of daily wage workers. After the termination of the workers who were working in the T.B. Board were approached him for their redressal in the month of May 1987 after ascertaining their problems. He has issued a representation to the second Respondent on 20th May, 1987 with a request to reinstate the 10 workmen belongs to the No. 4 Hanwal Section and 1 worker in No. 1 Holagunda Section and 4 workers in No. 2 Hingaldan Section who were terminated by the second Respondent on 28th March, 1987. Ex. W1 is the letter dated 20th May, 1987 along with the list of workmen addressed to the second Respondent. Soon after the representation made by this District Unit the concerned authorities have considered the plea of the Union and provided temporary job to the terminated workers. But finally the second Respondent has orally terminated all the 10 workmen who were working at No. 4 Sub-Division under the control of Assistant Executive Engineer, Holagunda on 1st July, 1988 without giving any notice. As per the act of the concerned officer is illegal and arbitrary one, again the Union Office has made a representation to the Secretary T.B. Board at Hospet on 3-8-1988 with a request to reinstate all the terminated workers as they have put in continuous service of more than 240 days under the 2nd Respondent. Finally the concerned authority has submitted its failure report to the Central Government due to the non-cooperation of the second Respondent. The first Respondent has filed a Memo before the Conciliation Authority with the support document, Ex. W4 is the copy of the Memo dt. 27-8-1990. A notice has been issued to the Respondent's Advocate to produce the attendance register, muster roll and also Service Registers of the concerned workmen. Ex. W5 is the notice dt. 30-8-1993 by the petitioner's representative to the Respondent's Advocate. In response to the above notice, the management has supplied the statement of the concerned workmen by suppressing the true facts just avoiding their liability. The date of appointments of which individual are mentioned in Ex. W5, and all the workmen were terminated on similar date on 1-7-1988. They were not paid any terminal benefits. No domestic enquiry was conducted against any workman under Ex. W5. All the workmen have completed more than 240 days continuous service without any remarks. He requests that all the workmen referred in this petition may be reinstated with back wages and all other attendant benefits.

16. M.W1 is Shaik Shavali. He deposed that he is well conversant with the facts of the case. Ex. M1 was prepared by Holgunda Circle and it was certified by their Division. His initials are also there. He can identify his initial on Ex. M1. Ex. M1 A is his signature on Ex. M1. Ex. M1 was repared on the basis of N.M.R. Rolls. N.M.R. Rolls consists of names and basis of N.M.R. Rolls. N.M. R.Rolls consists of names and father's name of the worker, No. of days worked in the particular month, amount of wages paid also the signature of the person who received the wages. All the 10 workmen in I.Ds. 80/91 to 89/91 were working on canal. They do not have work throughout the year. As and when they require the services they will be called. No appointment letter was given to the workmen. They are not maintaining any service register or attendance registers. They are maintaining N.M.R. Rolls. According to their records, no workman completed 240 days complete service without break. They were paying Rs. 8.00 per day for each workman. The plea of the petitioners that they have completed 240 days worked in a calendar year is correct.

19. In this case this Tribunal has to see whether the Tungabhadra Board is an industry or not. Their contention of the petitioner workmen that according to Section 2(5) of the Industrial Dispute Act the term industry is very well applicable to the Tungabhadra Board and also relied upon the judgement of Hon'ble Supreme Court in the case of Bangalore Water Supply & Sewage Board vs. Rajappa reported in AIR 1978 S.C. page No. 548. The main object of the project is to provide Irrigation benefits to both the Karnataka

and Andhra Pradesh States. Electricity also is generated both at the Dam and on the canals and is being shared between the two States. The T.B. Board was established with powers to deal with all the matters relating to workers which are common to both States of Andhra Pradesh and Karnataka. Hence the very nature of work and establishment of the 2nd Respondent comes under the definition of "Industry".

20. The contention of the Respondents on the other hand contended that Tungabhadra Board which is a statutory Body under the administrative control of the Ministry was established under the Andhra Pradesh State Act to undertake operation of Tungabhadra Dam and deal with all matters relating to operation Dam which are common to both States of Karnataka and Andhra Pradesh. The budget of the T.B. Board is incorporated in the state budget of Andhra Pradesh passed by the Legislature of Andhra Pradesh and the expenditure incurred including the salaries of staff is later apportioned between including the Andhra Pradesh and Karnataka. Thus T.B. Board cannot be considered as 'Industry' and its employees are not covered under the provisions of Industrial Disputes Act.

21. The Petitioner workmen relied upon the decision of the Supreme Court in BANGALORE WATER SUPPLY v. A. RAJAPPA (AIR 1978 page 548 S.C.) read as follows :

"Industry as defined in Sec. 2(j) has a wide import.

Where there is (i) systematic activity (ii) organised by cooperation between employer and employee (the direct and substantial element is chimerical), (iii) for the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes (not spiritual or religious but inclusive of material things or services geared to celestial bliss e.g. making on a large scale, prasad or food) prima facie, there is an "industry" in that enterprise.

Absence of profit motive or gainful objective is irrelevant, be the venture in the public, joint, private or other sector.

The true focus is functional and the decisive test is the nature of the activity with special emphasis on the employer-employee relations."

In the light of the above decision, the T.B. Board does distribution of water through canals and it is a systematic activity, in the other words for distribution of goods i.e. water. Hence I find that it has a wider meaning and that the very nature of the work of T.B. Board comes under the term "Industry". Hence I am of the clear view that the T.B. Board do come under the purview of "Industry" as defined under Section 2(5) of the Industrial Disputes Act, 1947. So this case goes in favour of the petitioner-workmen.

22. The next point is to be seen whether the Petitioner workman have put in 240 days continuous service in a year without any break so as to regularise them in their services. The Petitioner-workman very much relied upon the document Ex. W3 wherein it clearly indicates that the motive of the second Respondent, the contents of the said document clearly speaks about the latches on part of the Administration of the T.B. Board (Irrigation Branch). The concerned officer very clearly admitted that the list of N.M.R. persons working in L.L.C. No. 4 Sub-Division, Holgunda could not be included in the booklet even though they were already in roll even before preparing the booklet during July 1986 for want of information from the Field Officers in time. Their services have since been dispenses consequent on receipt of instructions from the higher officers and further the second Respondent has admitted that the petitioner-workman have been represented several times for further reinstatement. they have taken back to service on casual labour basis only, when required for water and ward, giving preference to them in view of the past service put in by them in the department. I find that the document Ex. W3 is quite sufficient to prove the case of the petitioner-workman and there is some merits in the case of the petitioner-workmen. The petitioner-workmen

relied upon the decision reported in DAILY RATED CASUAL WORKERS v. POST & TELEGRAPHS DEPARTMENT (AIR 1987 Supreme Court page 2342) held as follows : That non-regularisation of temporary employees or casual labour for a long period is not a wise policy, also his Lordships direct the Respondents (P&T Department) to prepare a scheme on a rational basis for absorbing as far as possible the casual labourers who have been continuously working for more than one year. Here in this case the petitioner workman have put in more than 240 days of continuous service in a year. There is another judgement of the Supreme Court reported in DAILY WAGE WORKERS ASSOCIATIONS v. STATE OF KARNATAKA (AIR 1990 page 883). This case was filed by the daily wage employees Association with a prayer for equal pay for equal work. Whereas the Hon'ble Supreme Court of India has pleased to observe so many aspects pertaining to the service affairs of the casual daily rated workers. And in the meantime his Lordships observed that the casual/daily rated employees appointed on or before 1-7-1984 shall be treated as monthly rated establishment employees at the fixed pay of Rs. 780.00 per month. And also the Hon'ble Supreme Court has given directing to the State Government that the casual and daily rated employees who become entitled to absorption shall be absorbed/regularised in a phased manner. Hence I find that this above judgement is aptly applicable to the present case on hand. Finally I find that there is some merits in the case of the petitioner workman. Hence I find that the impugned oral order of termination in the absence of valid order of dismissal falls under the Category of retrenchment as defined under Section 2(oo) of the I.D. Act, the mandatory provisions of the Section of the I.D. Act has not been complied with the impugned oral order of termination tantamounts to illegal termination.

23. In the result, the action of the Management of Tunga-Bhadra Board, T.B. Dam Hospet in terminating the services of Sarvasri Brahmaiah, Chinna Urukundappa, Nagappa, Masthani, Gorantla, Narasinhappa, Janaiah, Bhargava Reddy Narasappa and Venkateshwarlu, w.e.f. 1-7-1988 are not justified. These persons are entitled to be reinstated into service with full back wages and consequential all attendant benefits.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Workmen :	Witnesses Examined for the Management:
W.W.1 N. V. Vivekananda Swamy	M.W.1 Shaik Shavali.

Documents marked for the Petitioner:

- Ex. W1 20-5-87—Xerox copy of the letter enclosing the list of the workmen.
- Ex. W2 3-8-88—Letter addressed to 1st Respondent.
- Ex. W3 6-10-88—Letter addressed to the D.C.L. Bellary.
- Ex. W4 27-8-90—Memo filed by the 1st Respondent before the conciliation authority.
- Ex. W5—Notice given by the Workmen Representative to the Advocate Sri R. Satyamurthy, Bellary.

Documents marked for the Respondent/Management:

- Ex. M1 30-8-93—Statement sent to the workman to the notice dt. 30-8-93 (Ex. W5).
- Ex. M1-A—Relevant portion of signature on the Ex. M1.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

कां.प्रा. 1442.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकाम, संगारेड्डी के प्रबन्धन के संयुक्त नियोजकों

और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संद्या एल-40012/135/89-आई.आर. (सी.यू.) (भाग)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1442.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom, Sangareddy and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-94.

[No. L-40012/135/89-IR(DU) (Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :—

Sri Y. VENKATACHALAM, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated : 2nd day of May, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. OF 1990

BETWEEN :

Syed Mobu.

... PETITIONER

AND

The Sub-Divisional Officer,

Telecom, Sangareddy & another. ... RESPONDENT

APPEARANCES :—

M/s. C. Suryanarayana & P. Bhasker, Advocates for the Petitioner.

M/s. M. Panduranga Rao, B. G. Ravinder Reddy, Advocates for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/135/89-II(DU), dt. 10-7-1990 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the management of Telecom Sangareddy (AP) and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of M/s. Telecom, Sangareddy (AP) represented by their Sub-Divisional Officer in terminating the services of Sri Syed Mabu, Casual Mazdoor is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 41 of 1990 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner read as follows :—

The Petitioner was admittedly employee as Casual Mazdoor under the Respondent w.e.f. 1-9-1986 for a period of one year (240 days to be as act) During October 1986 and February 1987 Camp of the working party in which the petitioner was employed was shifted to other places. On those two days, the petitioner was not marked present in the muster Rolls but but shown absent though he was engaged in the camp shifting work. Thus if those two days are added to the working days the petitioner has put in 242 days of work by the end of April 1987. On 30-4-1987 the petitioner was retrenched from service on the plea that he was recruited and employee after 30-3-1985, and that the Director General, P&T New Delhi prohibited any recruitment of casual mazdoors after that date. The petitioner was retrenched on 30-4-1987 and he was not given notice or notice period wages nor was he given any other terminate benefits as per the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. Thus the petitioner's retrenchment on 30-4-1987 was illegal and void. In view of the judgements of the Supreme Courts the Petitioner has acquired a right of consideration for absorption in to the regular establishment of the Telecom Department as he was rendered more than one year service before his (first) retrenchment and for grant of temporary status in accordance with the order dt. 7-11-1989 of the Director-General Telecommunications, New Delhi pending his absorption into the Telecom Department according to his turn in the seniority list. The petitioner submits that his retrenchment is illegal and void on both the occasions (i.e. the end of April, 1987 and in October 1988) and that he is entitled to full wages during the period from 1-5-1987 to 30-9-1988 as if he were in service all along. He also submits that since he was retrenched illegally, he is entitled to reinstatement in service with full back wages from the date of his retrenchment in October 1988 with protection of his seniority among the 'Casual Mazdoors of Sangareddy Division as the seniority is a determining factor for absorbing a Casual Mazdoor into the regular establishment of Telecom Department pending his absorption, the petitioner is entitled to conformant of Temporary status as per the Director General's order dt. 7-11-1989 mentioned above as the petitioner has rendered more than one year service before his retrenchment. The petitioner there pays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold accordingly and make an award directing that the petitioner be given all the benefits claimed by him in view of the above mentioned decisions and orders or instructions on the subject.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows :—The petitioner was engaged as casual mazdoor under the Respondent from the month of September, 1986 to April 1987 depending on the availability of work such as laying up of cables, erections of overhead lines, and maintenance works etc. As the works were over by the end of April 1987 the service of the petitioner was disengaged w.e.f. May, 1987. The petitioner has not completed 240 days as alleged by him. It was made clear to him at the time of his engagement that he will be disengaged whenever there is no work. From May, 1987 the petitioner has not approached the respondent for employment. It is submitted that he allegation that the termination is in violation of Sec. 25(F) of the I.D. Act is not correct. It is submitted that the disengagement of casual labour does not mean retrenchment and therefore the question of complying with Section 25(F) of the I.D. Act does not arise. The judgements cited by the petitioner are not at all applicable to the facts of the case. There are no merits in the case and therefore the same may be dismissed. It is prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an award that the petitioner is not entitled of any relief.

4. The point for adjudication is whether the action of the management in terminating the services of Sri Syed Mabu is justified or not.

5. W. W1 was examined on behalf of the Petitioner and marked Exs. W1 to W3. M. W1 was examined on behalf of the Respondent and no documents were marked on its side.

6. W. W1 is Syed Maboob. He deposed that he joined as Casual mazdoor on 1-9-1986. He worked for 240 days upto 30-4-1987. He did not stop from working but he was removed from the service. At the time of his removal, he was not given notice and he was given any reasons for removal. He was not paid one month's wages in lieu of notice. Even after his retrenchment the Department carried on several works. In the Telecom Department there is continuous work. Subsequently new mazdoors were engaged and the works carried on. They are all juniors to him. He does not remember the names. He does not know whether any contractors were engaged to carryout the works. After his retrenchment in April, 1988 the S.O. Tel. called him and employed for one month again in August, 1988. After one month he was again retrenched, without notice, without reasons without any compensation. He was not employed again. He is requesting that he should be reinstated into service with back wages continuity of service and protect his seniority.

7. M. W1 is V. Krishna Murthy. He deposed that he is working as Section Supervisor from 1980 in Sangareddy. The daily mazdoors are engaged for the purpose of doing of trenches, erection of poles, laying cables etc. This type of work is there throughout the year and this work will not be of the same volume though the year and some time there may not be work. The petitioner is not sponsored through the Employment Exchange as required by rules. They engaged casual mazdoors only when the work available. The petitioner was informed before his engage-

ment that he would be engaged as per the availability of work and he will be disengaged when there is no work. After 30-4-1987 as there was no work he was disengaged. The petitioner did not approach them after 30-4-1987 till September 1988, and he was engaged again in October 1988. As there is no work he was again disengaged after October 1988. Now this casual nature of work was given to the contractor for the last two years. No contractor was engaged during 1987-88 and 1989. No junior was continued after disengagement to the petitioner.

8. The case of the Petitioner workman that the petitioner workman was employed for 240 days from 1-9-1986 continuously, during October 1986 and February 1987 there was shift of camp of the working party for which the workman was employed but he was not paid wages for those two days, therefore the workman should be deemed to have been employed for 242 days but he was retrenched on the evening of 30-4-1987 without notice, without payment of the notice period wages or any compensation whatever and without furnishing any reasons whatever. None of the conditions laid in Section 25-F of the I.D. Act have been complied with therefore retrenchment is illegal and void.

9. The allegation of the Respondent-management is what the petitioner was engaged as casual mazdoor under the respondent from the month of September, 1986 to April 1987, that as the works were over by the end of April 1987 the service of the petitioner was disengaged with effect from May 1987. The petitioner has not completed 240 days are alleged by the petitioner and that from May 1987 the petitioner has not approached the Respondent for employment. He is not terminated or retrenched but was disengaged.

10. It is seen that the petitioner was engaged depending upon the availability of work such as laying of cables, erection of overhead lines, maintenance works etc. It is seen that the above works are not permanent and regular in nature, in nature. It is seen that at the time of engagement of the petitioner it was made clear that at the time of the engagement of the petitioner he will be disengaged whenever there is no work. Then the work was over by April 1987 the petitioner services were no longer required. The disengaged of casual labour does not mean that retrenchment and Section 25(F) of the I.D. Act does not apply to the case of the petitioner. The judgement cited by the Petitioner is not at all applicable to the facts of this case. Hence I am of the clear view that the disengagement of the petitioner from service is legal and justified. Hence no relief can be awarded to the petitioner workman in dispute. Moreover the casual nature of work has been given to the contractor for the last two years, the question of absorbing the petitioner workman does not arise Hence I find that the petitioner-workman has no merits and thus the petitioner workman is not entitled to reinstatement or any other relief.

11. In the result, the action of the management of M/s. Telecom. Sangareddy (A.P.) represented by their Sub-Divisional Officer in terminating the services of Sri Syed Mabu, Casual Mazdoor is justified. The workman in question is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence .

Witnesses Examined
for Workmen :

W.W1 Syed Mabu.

Witnesses Examined
for Management :

M.W1 V. Krishna Murthy

Documents marked for the Petitioner :

Ex. W1 Copy of the Complaint to R.L.C.(C),
10-4-89 Hyderabad.

Ex. W2 Copy of the parawise Report submitted by
the S.D.O.T. Sanga Reddy to R.L.C.(C),
Hyderabad.

Ex. W3 Copy of the Rejoinder.
31-8-89

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

को.आ. 1443.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम, संगारेड्डी के प्रबन्धन के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/136/89-आर्डीआर० (डी०यू०) (भाग)]

के०बी०बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1443.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom. Sangareddy and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-94.

[No. L-40012/136/89-IR (UD) (Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L.,
Industrial Tribunal-I.

Dated 10th day of May, 1994
Industrial Dispute No. 43 of 1990

BETWEEN

Miya Khan S/o Ismail, aged about
23 years Casual Madzdoor —Petitioner

AND

1. The Sub-Divisional Officer,
Telecom, Sangareddy-502001.
2. The Telecom District Engineer,
Sangareddy-502050.

APPEARANCES :

- Sri C. Suryanarayana, Advocate for the Petitioner.
- S/Sri M. Panduranga Rao and B. G. Ravinder Reddy, Advocates for the Respondents.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. 40012/136/89-IR(DU), dt. 10-7-1990 referred the following dispute under Section 10(1) (d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of Telecom, Sangareddy (AP) and the workman to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of M/s. Telecom, Sangareddy (AP) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the services of Sri Miya Khan, Casual Labour is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?”

This reference is registered as Industrial Dispute No. 43 of 1990 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement read as follows :—The petitioner was admittedly employee as Casual Mazdoor under the 1st Respondent w.e.f. 1-5-1986 and was employed continuously till the end of April 1987 and thus actually rendered 365 days of work. In spite of the same he was retrenched from the service without complying with the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act on the ground that he was recruited after 31-3-1985. The petitioner was retrenched on the afternoon of 30-4-87 and was not again employed till April 1988. During that month he was employed for 28 days and then again abruptly retrenched from service illegally. On both the occasions he was not given any notice or notice period wages nor did the Respondent comply with any other mandatory provisions of Sec. 25-F of the I.D. Act. That in view of the orders of the Department of Telecom in their letter dt. 7-11-1989 he is entitled to conferment of temporary status with all its attendant benefits pending his absorption and regularisation in the Department as per the mandate of the Supreme Court. In view of the foregoing facts and submission, that the retrenchment of the petitioner is illegal. He is therefore entitled to reinstatement in service with full back wages, protection of seniority and all other benefits incidental and consequential to such reinstatement including absorption and regularisation in service and pending the same he is entitled to conferment of temporary status as per the Department's Order dt. 7-11-1989.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows :—

The petitioner was engaged as casual labour under the Respondent S. D. from May 1986 to April 1987 depending upon the availability of work. The casual mazdoor are engaged by the department only for temporary works like construction of overhead lines, cable laying and maintenance works etc. There was no work for the casual mazdoor w.e.f. 1-5-1987 and therefore the services of the petitioner were disengaged. As the work that is being done by casual labour are purely casual nature, the question of their termination does not arise. Even if any disengagement of any labour for want of work is there, it can be taken as permanent disengagement it is always open for such casual labour to offer himself whenever the work is available. The allegation of the petitioner that his services were terminated in violation of Section 25-F of the I.D. Act does not arise. The petitioner was not terminated from service but was disengaged for want of work and as and when the work is available, the same will be offered to the petitioner. The disengagement of casual labour does not amount to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I. D. Act. There are no merits in the dispute raised by the petitioner. It is prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award that the petitioner is not entitled to any relief.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent in terminating the services of Mr. Miya Khan is justified or not ?

5. W.W1 was examined on behalf of the petitioner and marked Exs. W1 to W4. M.W1 was examined on behalf of the Respondent and no documents were marked on its side.

6. W.W1 is Miya Khan. He deposed that he worked in the Telephone Department from 1-5-1986 to 30-4-1987. Subsequently he was removed from service on the ground that some orders have come from the top to remove him and others. No reasons were given except that there is no work. He was turned out on the ground that there was no work. He was not given any notice before he was removed. He was not paid one months wages in lieu of notice. He was not given any other compensation. When they did not take him to work he raised an I.D. on 10-4-1989. Ex. W1 is the xerox copy of his complaint date 10-4-1989. The Regional Labour Commissioner called the S.D.O.T. Sangareddy for discussions and conciliation proceedings.

7. M.W1 is V. Krishna Murthy. He deposed that he is working at Sangareddy since 1980. The casual mazdoors are engaged for the temporary works, digging trenches, laying cable for new phone connection etc. It is not a continuous and regular work. The petitioner was engaged on different works during his engagement though the nature of work is same. The petitioner was engaged on different works due to completion of earlier works. The S.D.O.T. Sangareddy has informed the petitioner before his engagement no casual mazdoor that he would be engaged only when the work is available. The petitioner was disengaged after April, 1987 due to non-availability of work. After April 1987 no Junior to the petitioner was engaged. The temporary works of laying cables etc. is now being entrusted to contractor for the last one year.

8. In this case it is seen that the petitioner was employed as Casual Mazdoor under the Respondent w.c.f. 1-5-1986. He worked upto April 1987 and rendered 363 days of work. As per the records, it is seen that casual mazdoors are engaged by the Department only for temporary works like construction of overhead lines, cable laying and maintenance works etc. From 1-5-1987 there was no work for the casual mazdoor, hence the services of the petitioner was disengaged. It is for the casual labour to come and enquire about the availability of work and offer themselves for such work. They will be engaged as and when they are available. Even if any disengagement of any labour for want of work, it cannot be taken as permanent disengagement. It is seen that it is always open for such casual labour to offer himself whenever the work is available. I find that the petitioner was not terminated from service but was disengaged for want of work and as when the work is available, the same will be offered to the petitioner. I find that the termination is not in violation of Section 25-F of the I.D. Act. The disengagement of casual labour does not amount to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D. Act. Hence the question of not complying with Section 25-F of the I.D. Act does not arise. I find that the said Section is not at all applicable to the casual labour as the work is of casual in nature. It is also seen from the evidence of M.W1 in his deposition that S.D.O., Telecom Sangareddy has informed the Petitioner before his engagement as casual mazdoor that he would be engaged only when the work is available. That the work of laying cables, digging trenches and erection of poles are given to the contractor. Consideration of all the facts and circumstances, I am of the firm opinion that the petitioner workman is not entitled to reinstatement or any kind of compensation under the provisions of the I.D. Act.

9. In the result, the action of the Management of M/s. Telecom, Sangareddy (AP) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the services of Sri Miya Khan, Casual Labour is justified. The concerned workman is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 10th day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for Workmen :

W.W1 Miya Khan

Witnesses Examined for Management :

M.W1 V. Krishna Murthy

Documents marked for the Petitioner/Workmen :

Ex.W1 10-4-89 Xerox copy of the Complaint given to the RLC(C), Hyderabad-Reg-Illegal retrenchment.

Ex.W2 2-5-89 Xerox copy of the parawise remarks submitted by the Management before ALC(C).

Ex.W3 Written comments submitted by the counsel for the petition before ALC(C) Hyderabad Xerox copy.

Ex. W4 31-10-89 Xerox copy of failure report submitted by the ALC., Hyderabad.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

कांआा 1444.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकाम वारंगल (आं०प्र०) के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/18/91-आई०आर० (डी०यू०) (भाग)]
के०वी०वी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1444.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Telecom Warangal and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-94.

[No. L-40012/18/91-IR(DU)(Pt.)]
K. V.B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated : 2nd day of May, 1994

Industrial Dispute No. 54 of 1991

BETWEEN

M. A. Masood S/o. Hussain,
about 21 years Casual Mazdoor
retrenched by the Respondent
herein . . .Petitioner

AND

The Sub-Divisional Officer,
Phones, Warangal-506 007. . .Respondent

APPEARANCES :

M/s. C. Suryanarayana & P. Bhasker, Advocates
for the Petitioner.

M/s. M. Panduranga Rao & B. G. Ravinder
Reddy, Advocates for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/18/91-IR(DU), dated 4-10-91 referred the following dispute under Section 10(1)(d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of M/s. Telecom, Warangal and their workmen to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the Management of M/s. Telecom, Warangal (AP) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the service of Sri M. A. Mazced without complying with the provisions of the Section 25-F of the Industrial Dispute Act, 1947 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled ”

This reference was registered as Industrial Dispute No. 54 of 1991 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the petitioner reads as follows :—The Petitioner's claim for reinstatement in service is based on the fact that the respondent herein and other officers of the Telecom Department recruited and employed the petitioner as casual mazdoor for 383 days during the period from September 1985 to June 1987 but retrenched thereafter on the ground that he was recruited after 30-3-1985 contrary to the orders of the Director General, P&T New Delhi prohibiting any fresh recruitment and employment of Casual mazdoors. The petitioner was not given notice nor paid wages as per the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act even though he has rendered 272 days service in the year proceeding 24-6-1987 the date on which he was retrenched from service. Notwithstanding the aforesaid direction of the Supreme Court the petitioner was retrenched from service on the fallacious ground that he was recruited after 30-3-1985 the date on which the Director General imposed ban on fresh recruitment/employment of casual mazdoors. The petitioner submits that after absorbing several mazdoors, the Telecom Department issued orders dated 7-11-1989 to grant temporary status to those who could not be absorbed in the regular establishment for want of vacancies. It is thus clear that continuous one year service as casual labourers in the Telecom Department entitles them to temporary status pending their absorption in the regular establishment of the Department, according to their turn in the seniority list of Casual mazdoors of a recruitment unit and for preparing the seniority list the Director General issued separate orders. The petitioner prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold and declare that his retrenchment is illegal, null and void and consequently to direct the respondents to reinstate him in service with full back wages, continuity of service and all other benefits which are consequential and/or incidental to such reinstatement, and to pass the Award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows :—The reference itself is illegal for the reasons that the services of the petitioner were never terminated as he was only working on casual basis and the casual mazdoors were

offered work as and when the same is available. The department engages casual mazdoors as and when temporary works are taken up for laying ground cables and construction of over head alignments are taken up. As soon as the work is over, the employment of the casual mazdoor comes to an end. In the case of casual mazdoors work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work. The petitioner was engaged as casual mazdoor in the sub-division on the following dates viz., 13 days in February 1986, 29 days in March 1986, 20 days in April, 1986, 13 days in May 1986, 23 days in November 1986 and 29 days in December 1986. He again worked 29 days in January 1987, 28 days in February 1987, 30 days in March 1987, 23 days in June 1987 and 28 days in February 1989. It is submitted that the petitioner was informed clearly at the time of the initial appointment as casual mazdoor that he was engaged for works of casual nature, and as and when such casual works are completed, he will be dis-engaged from the muster rolls. The petitioner has also signed a declaration to this effect. As already submitted the service of casual mazdoor come to an end as and when the work is completed. Till fresh works are taken up, he will have to remain idle. Such dis-engagement will not amount to termination and such disengagement is automatic in the case of casual mazdoors. The petitioner is not entitled to continue in service mechanically as a casual labour. It is submitted that there is no termination of the service of the petitioner and therefore the dispute itself is not maintainable. The contention of the petitioner that he is entitled for regularisation is not relevant for purpose of this case and the same is beyond the scope of reference made by the Government. It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award holding that the Petitioner is not entitled to any relief.

4. The point for adjudication is whether the action of the management of M/s. Telecom, Warangal in terminating the service of Sri M. A. Mazced is justified or not?

5. W.W1 is examined on behalf of the petitioner and marked Exs. W1 to W7. M.W.1 was examined on behalf of the Respondent and marked Exs. M1 and M2.

6. W.W1 is Mohd. Abdul Mazdoor. In brief that he joined the respondent department on 7-9-1985 as casual mazdoor. He worked in the department till 24-6-1987. Thereafter he was retrenched from service on the ground that he was recruited after 30-3-1985. No notice was given at the time of retrenchment nor any wages were paid. Ex. W7 is the Xerox copy of D.G. Telecom's order dated 7-11-1989 conferring the temporary status to casual labourers pending regularisation. He prays this Hon'ble Tribunal to grant him relief of reinstatement with all other consequential benefits.

7. M.W1 is G. V. B. Krishnamachari. He deposed that the casual mazdoors are engaged for digging of trenches and erecting poles, laying of cables etc. and this work is of temporary nature and when this type of work is taken only when there is expansion of exchanges. Casual mazdoors are

engaged only when there is work. The petitioner was informed before his engagement that he would be engaged only when the work is available and he would automatically be disengaged when the work for which he was engaged is completed. The petitioner was not retrenched from service with effect from 24-6-1987. The work for which the petitioner was engaged was completed by 24-6-87, and as such he was disengaged. The petitioner did not approach them from June 1987 to February 1989 he approached the Respondent in February 1989 and as the work is available he was engaged upto 30-4-1989. The petitioner was not removed as per the alleged circular of D.G.T. and only he was disengaged as the work was not available. No junior of the petitioner is being engaged are continued as casual mazdoors.

8. The case of the petitioner workman that the Telecom Department recruited and employed the petitioner as Casual Mazdoor for 383 days during the period from September 1983 to June 1987 but retrenched thereafter on the ground that he was recruited after 30-3-1985 contrary to the order of the Director-General, P&T, New Delhi prohibiting any fresh recruitment and employment of casual mazdoors, that the petitioner was not given notice nor paid wages as per the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act even though he has rendered 272 days service in the year proceeding 24-6-1987 the date on which the petitioner was retrenched from service.

9. The contention of the Respondent that the Department engage casual mazdoors as and when temporary works are taken up for laying ground cables and construction of overhead alignments are taken up. As the work is over, the employment of the equal mazdoor comes to an end, likewise if another work is taken up and the casual mazdoor comes forward for employment, he will again be engaged till the work lasts, the casual mazdoor work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work.

10. It is seen that the Respondent Department engages casual mazdoors as and when temporary works are taken up or laying ground cables and construction of overhead alignments are taken up. As soon as the work is over, the employment of the casual mazdoor comes to an end. It is seen that the casual mazdoor work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work. Whenever casual mazdoor are taken up for work, they are informed clearly at the time of their initial appointment that they are engaged for works of casual nature and as and when such casual works are completed, they will be disengaged from the musterrolls. So the case of the petitioner, he was engaged purely on temporary basis whenever the work is completed, the requirement of casual labour will not be there. It is clear that the services of casual mazdoor comes to an end as and when the work is completed. Here the work was completed and the requirement of the petitioner is not necessary and the dis-engagement is automatic in the case of casual mazdoors and such disengagement is not termination as contended by the petitioner-workman. Hence I find that there is no

termination of service of the petitioner in this case, and the question of regularisation of the petitioner does not arise. It is pertinent to note that the work undertaken is purely of casual nature. Hence I find that the petitioner is not entitled to any relief.

11. In the result, the action of the Management of M/s. Telecom, Warangal (A.P.) represented by their Sub Divisional Officer, in terminating the service of Sri M. A. Maseed without complying with the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 is justified. The workman concerned is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for
the Workmen :

W.W1.—Mohd| Abdul Masood.

Witnesses Examined for
the Management :

M.W1.—G. V. R. Krishnamachari.

Documents marked for the Workmen

Ex. W1.—Xerox copy of the Working days particulars.

Ex. W2.—30-3-1985.—Xerox copy of the order dated 30-3-1985.

Ex. W3.—Complaint Made to the R.L.C.

Ex. W4.—Parawise remarks the deptt. to the Ex. W3.

Ex. W5.—Xerox copy of the rejoinder to Ex. W4.

Ex. W6.—Xerox copy of the failure of conciliation proceedings.

Ex. W7.—7-11-1989.—Xerox copy of the D.G. Telecom's Order dated 7-11-1989, with regard to the temporary status to the casual labours pending regularisation.

Documents marked for the Management :

Ex. M1.—Working days particulars of the Petitioner|Workmen typed copy.

Ex. M2.—Xerox copy of the undertaking given by the Petitioner—Workman.

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

कां०आ० 1445.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिप्टी जनरल इंजीनियर, टेलीकाम, हैदराबाद (रूरल) के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/45/91—आई०आर० (डी०यू०) (भाग)]

के०बी०बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1445.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Engineer, Telecom, Hyderabad (Rural) and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-1994.

[No. L-40012/45/91-IR(DU) (Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated : 9th day of May, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 59 OF 1991

BETWEEN

Sri C. Suryanarayana,
President,

All India Telegraph Engg. Employees Union,
Line Staff & Class-IV,

A.P. Circle, H. No. 1-2-593/50,
Sri Sri Margh, Gaganmahal,
Hyderabad-500029.

.. Petitioner

AND

The Divisional Engineer,
Telecom,
Hyderabad (Rural),
Hyderabad-500050.

.. Respondent

APPEARANCES :

Sri C. Suryanarayana, representative of the petitioner.

S/Sri M. Pandu Ranga Rao, and B. G. Ravindera Reddy, Advocates for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. 40012/45/91-IR(DU), dt. 23-10-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of Divisional Engineer, Telecom, Hyderabad (Rural) and their workmen to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the Management of Sub-Divisional Officer (Rural), Telecom, Hyderabad in terminating the services of Sh. Bhikshapathi, Sh. Pullaiah and Sh. K. Ettesar, ex-casual mazdoors are justified ?

If not, what relief the concerned workmen are entitled to ?”

This reference is registered as Industrial Dispute No. 59 of 1991 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner read as follows :—Sri S. Bikshapathi was recruited and employed as Casual Mazdoor from December, 1981 onwards. He was continuously employed from 1-12-1981 to 30-4-1984 except for a few days in each month and also for the entire month of October, 1983 due to cessation of work for departmental reasons but not due to any fault of his part. Consequently the workman was employed w.e.f. March 1990 and his name was again included in the M/Rs. As such he gained the impression that his absence on health grounds was condoned and that he was unconditionally reinstated in service. Unfortunately, however, the workman's service was terminated w.e.f. 26-8-1990 on the ground that after the break during the period from May, 1984 to July 1988 and in the later period, he has become a fresh recruit and such fresh recruitment being banned by the D.G., P&T he was not entitled to continue in service and therefore he was prohibited from attending to work. Under the provisions of Section 25-B of the I.D. Act defining “continuous service” the workman must be deemed to be in continuous service from the date of his initial appointment on 1-12-1981 till his termination on 26-8-1990 and hence he is entitled to reinstatement with back wages from the date of his termination and also for regularisation in service as per the directions of the Supreme Court in DAILY RATED CASUAL LABOUR IN P&T SERVICES v. UNION OF INDIA & OTHERS, AIR 1987 S.C. 2342. Sri P. Pullaiah was employed w.e.f. 1-12-1981 continuously upto 31-3-83. Due to cessation of work by the Department, not attributable to the workman, he was also not employed on some days in each month as well as in the months of April and May 1983. He was employed during June to August, 1983 kept idle from September 1983 to March 1985 but again employed in April 1985. From the beginning till he was terminated on 26-8-1990 the workman's name was included in the M/Rs. As such he was under the impression that the alleged break in service was condoned and that he was unconditionally reinstated in service. But unfortunately he was retrenched from service w.e.f. 26-8-1990 in violation of the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. Sri K. Ettesar was recruited and employed from 1-4-1982 but his recruitment was formalised by the S.D.O.'s order dt. 21-2-1984. He was employed continuously till July 1984 except for intermittent breaks in each month due to cessation of work and non-provision of paid weekly holidays besides non-employment during the month of September to November 1982 October to December 1983 and March 1984 either due to cessation of work or due to non-availability of work for juniors like this workman. On recovery the workman approached the SDI Telecom, Hyderabad and after submitting the medical certificate sought for reinstatement in service. The SDO Telecom did not provide him with employment immediately on the ground that there was ban on recruitment/employment of fresh casual labourers. The workman submitted to the SDO, Telecom, Hyderabad that he cannot be treated as a fresh recruit as he was initially recruited and employed from 1-4-1982 and his recruitment was formalised in February 1984. For the same reason as in the above cases this workman is also entitled to reinstatement with back wages w.e.f.

26-8-1990 absorption and regularisation in service in accordance with the Supreme Court's directions mentioned in the above two cases. The petitioner Union therefore prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold and declare that retrenchment of the three workmen mentioned about w.e.f. 26-8-1990 is illegal, null and void and that they are entitled to full back wages from that date, continuity of service, protection of their seniority and all other benefits which are incidental and consequential to such reinstatement and pass the Award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent Management read as follows:—In the case of Sri Pullaiah, he was engaged for the first time in the month of December, 1981 for 26 days. Thereafter he worked for 25 days in January 1982, 21 in February, 26 in March, 19 in April, 22 in May, 21 in June, 22 in July, 24 in August, 20 in September, 24 in October, 28 in November, 24 in December, 1982, 20 in January, 1983, 20 in February, 30 in March, 17 in June, 28 in July, 18 in August, 9 in September and thereafter he was engaged only for 30 days in April 1985. Thereafter he never came for employment and absconded from duty. Again after gap of six years, he came for duty only in March 1990 and worked for some days from April to August. In the case of Sri K. Ettesar, he was engaged in the month of April 1982 for 24 days, 9 in May, 26 in June, 29 in July, 30 in August, 31 in December. Again he worked for 27 in January 1983, 23 in February, 28 in March, 20 in April, 20 in May, 19 in June, 23 in July, 19 in August, 23 in September. In the year 1984, he worked for 24 days in January, 19 in February, 26 in May, 30 in June, 31 in July. It is submitted that thereafter he absconded from duty and he never came for duty. After gap of six years, he came for duty for 25 days in April 1990, 21 in May, 25 in June, 25 in July and 25 in August. In the case of Sri Bikshapathi he was engaged for the first time in the month of December 1981 for a period 26 days, 25 in January 1982, 21 in February, 26 in March, 19 day in April, 22nd in May, 21 days in June, 22 in July, 24 in August, 20 in September, 26 in October, 23 in November and 31 in December. Again in 1983 he worked for 23 days in January, 26 in February, 29 day in March, 29 in April, 22 in May, 30 in June, 26 in July, 18 in August 21 in September, 19 in November and 31 in December, 1983. Thereafter he never reported for duty and absconded from duty. Again after gap of 7 years, he came for duty and worked for 24 days in March 1990, 21 in May, 25 in June, 25 in July and 25 in August. It is submitted that they were being engaged as casual mazdoors depending upon the availability of work. As and when such work is available, casual mazdoors are engaged and as and when the work is over, their services will be discontinued. But these workmen did not come for duty for 5 to 7 years. That their service were never terminated, in the case of casual mazdoors, the question of termination of services does not arise. Though the work was available they did not choose to come regularly and absconded from duty. It is surprising how these three workmen can fall sick for over six years together continuously that too, approximately at the same time. In this case, firstly the workmen were never terminated and second their discontinuous and abandonment is not retrenchment within the meaning

of Section 2(oo) of the I.D. Act. The category of casual labour comes under exception Clause i.e. (bb) under Section 2(oo) of the I.D. Act. As it is not a case of retrenchment, the question of compliance with the provisions of Section 25-F of the I.D. Act does not arise. The Department is bound to follow procedure set in while recruiting permanent employees. The above workmen have no right of whatever for permanent employment under the Respondent in deviation of the procedure laid down in the rules. It is prayed that this Hon'ble Court may be pleased to pass an Award holding that the petitioners are not entitled for any benefit.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent Telecom in terminating the services of Sh. Bikshapathi, Sh. Pullaiah and Sh. K. Ettesar, ex-casual mazdoor are justified or not?

5. M.W1 was examined on behalf of the Respondent-Telecom and no documents were marked on its side. No oral or documentary evidence has been adduced on behalf of the petitioner-workman.

6. M.W1 is G. Sridhar Rao. He deposed that he is giving evidence on the basis of the records. The concerned workman Pullayya absented himself after April 1985 and turned up only in March 1990. He did not give any reason for his absence. He was engaged from March 1990 to August 1990 as a fresh casual mazdoor for temporary works. After August 1990 the petitioner was disengaged due to nonavailability of work. Another concerned workman Ettesar absented himself after July 1984 without giving any reasons and he came back in March 1990 asking for work. He was engaged as fresh casual mazdoor from April to August 1990. He was disengaged after August 1990 due to non-availability of work. Another concerned workman Bikshapathi absented himself after December 1983 and turned up only in March 1990 asking for work. He has not given any reasons for his absence from 1984 to February 1990. As the work was available during March 1990 he was engaged as fresh casual mazdoor upto August 1990. He was disengaged after August, 1990 due to non-availability of work. All the three workmen did not work for a period of 240 days during 1990.

7. The case of the Petitioner that S/Shri S. Bikshapathi, P. Pullaiah and Ettesar were employed as casual mazdoors in the Respondent Telecom. Their case is that they worked for some period in a month, that due to cessation of work for departmental reasons. For some time Sri Bikshapathi fell sick and he could not attend the work and again he was reinstated into service. Likewise Sri P. Pullaiah also had breaks in service due to cessation of work which cannot be attributed to the workman. Sri K. Ettesar also had intermittent breaks in each month due to cessation of work and non-provision of paid weekly holidays. This workman also fell sick during the period from August 1984 to July 1988. On recovery the workman approached the SDI Telecom, Hyderabad and later he was reinstated in service from 1-4-1990 but was retrenched from service w.e.f. 26-8-1990. The representative of the Union submitted that the termination of workman's service constitutes retrenchment in terms of Section 2(oo) of the I.D. Act and it is illegal null and void for non-compliance with the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D.

Act, in as much as the workman must be deemed to be in continuance employment ever since his initial recruitment in view of the provisions of Section 25-B ibid. Thus the three workmen are entitled to reinstatement within back wages, absorption and regularisation in service in accordance with the Supreme Court's directions mentioned above.

8. The contention of the Respondent-Telecom that Sri Pullaiah was engaged for the first time in the month of December 1981 thereafter he worked for some days in a month later he never came for employment and absconded from duty. After a gap of six years, the petitioner came for duty in the month of March 1990 and worked for some days till August 1990. Whereas in the case of K. Etteswar he was engaged in during 1982 for some days worked in a month and then thereafter he absconded from duty and never came for duty. Again after a gap of six years, he came for duty and worked for some days in a month during the year 1990. Then in the case of Bikshapathi he was engaged for first time in the month of December 1981 for a few days in a month during the year 1982, again in 1982 thereafter he never reported for duty and absconded from duty. Again after a gap of seven years, he came for duty and worked for some days in each month during the year 1990.

9. It is pertinent to note that all the three workmen worked in the Respondent Telecom during the years 1981, 1982 and 1983 and 1985. It is seen that after working for some days during each month and for three to four years and thereafter all of them never came and were absconded. It is seen that all of them were being engaged as casual mazdoors depending upon the availability of work. It is seen that casual mazdoors are engaged as and when the work is over. It is pertinent to note that these three workmen did not come for duty for a long gap i.e. five to seven years. In fact their services were never terminated and in fact in the case of casual mazdoors, the question of termination of services does not arise at all. It is also seen that all the workmen were on medical leave and the medical certificates produced by them for their absence for 6 to 7 years is somewhat ambiguous. I cannot believe that all the three were sick during the same period and all of them are working at the same place. I find that with a view to fill up the gap of such service, the certificates were created, they are trying to show the continuous service which I am not accepting. The allegation that their services were terminated and termination is in violation of Section 25-F of the I.D. Act which is not correct. It is seen that the workmen were never terminated and that their discontinuance and abandonment is not retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D. Act. The Department is Government of India and there is a set of procedure for recruitment of permanent employees. I find that all the three workmen have no right of whatever for permanent employed under the Respondent in deviation of the procedure laid down in the rules. Therefore I am of the firm opinion that the workmen in dispute are not entitled for reinstatement more so for permanent employment.

10. In the result, the action of the Management of Sub-Divisional Officer (Rural), Telecom, Hyderabad in terminating the services of Sh. Bikshapathi,

Sh. Pullaiah and Sh. K. Etteswar. Ex-Casual mazdoors are justified. The concerned workmen are not entitled to any relief.

Award passed accordingly

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 9th May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence :

Witness Examined for the
Petitioner/Workmen :

NIL

Witness Examined for the
Respondent/Management :
M. V. G. Srihar Rao

Documents marked for the both sides :
NIL

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का. आ. 1446.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस्. डी. ओ., टेलेकाम, कुरनूल के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/109/91-आई आर (डी यू) (भाग)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O 1446.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO, Telecom, Nagar Kurnool, and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-94.

[No.L-40012/109/91-IR(DU) (Pt.)]
K. V. B UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :—

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial
Tribunal-I.

Dated : 10th day of May, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 70 OF 1991

BETWEEN :

M. Venkateswarlu, S/o Beechupalli about 20
years Casual Mazdoor —Petitioner

AND

The Sub-Divisional Officer, Telecom, Nagar-kurnool-509 209. ... Respondent

APPEARANCES :

M/s. C. Suryanarayana and P. Bhaskar, Advocates for the Petitioner.

M/s. Panduranga Rao, B. G. Ravinder Reddy and M. V. Ramarao, Advocates for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order in No. L-40012/109/91-IRDU, dt. 19-11-1991 referred the following in dispute under Section 10(1) (d) (2A) of the I.D. Act between the management of Telcom and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Sub-Divisional Office (Rural) Telecom Nagar Kurnool, is justified in terminating the services of Sri M. Venkateswarlu with effect from 1-11-89? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

This reference is registered as Industrial Dispute No. 70 of 1991 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claims statement of the petitioner is read as follows :

The Respondent herein recruited and employed the petitioner as Casual mazdoor for 230 days during the period from March, 1989 to October, 1989 without weekly offs. The petitioner was not employed for a period of in 5 days in August, 1989, 9 days in September 1989 and one day in October 1989. Thus in a total of 245 days the Petitioner was kept idle for 15 days due to cessation of work-by the Department which is beyond in his control. He was retrenched thereafter on the ground that he was recruited after 30-3-1985 contrary to the orders of the Director General, P&T, New Delhi prohibition and fresh recruitment and employment of casual mazdoors. He was not given notice nor paid wages as per the provisions of Section 25-F of the I.D. Act. The petitioner submits that after absorbing several mazdoors the Telecom department issued order dt. 7-11-1989 to grant temporary status to those who could not be absorbed in the regular establishment for want of vacancies. It is thus clear that continuous one year service as casual labourers in the Telecom Department entitles them to temporary status pending their absorption in the regular establishment of the Department, according to their turn in the seniority list of casual mazdoors of a recruitment unit. Absorption in the regular establishment of the Department according to their turn in the seniority list and grant of temporary status are thus incidental to their service in the Telecom Department. The petitioner prays that this Hon'ble Tribunal may be

pleased to hold and declare that his retrenchment is illegal and to direct the Respondents herein to reinstate him in service with full back wages, continuity of service and all other benefits which are consequential and/or incidental to such reinstatement and to pass the Award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows:—The petitioner was engaged as casual mazdoor on daily wages depending upon the availability of work. The work of the casual mazdoor comes to an end as and when the work is over. The work of the casual mazdoor is not continues and purely depends upon the availability of work. The allegation that the petitioner worked continuously for 239 days during the period from March 1989 to October 1989 is not correct. He was engaged as and when the work was available and that there is no question of termination. Casual Mazdoor will be discontinued as and when the work is over. Therefore the allegation that the petitioner was terminated from service and that the termination is in violation of Section 25-F of the Industrial Disputes Act is not correct. There is no termination of service much less retrenchment of service. The Respondent is a Government of India Department and it has got procedure for engaging regular employees. The casual mazdoors are meant purely for discharging casual nature of work and they have not got any right of whatsoever nature to seek for absorption or for employment under the Respondent. The various judgements cited by the petitioner in the claim statement are not relevant and are not applicable to the facts of his case. The petitioner was not eligible for granting of temporary status as he was not engaged prior to 30-3-1985. It is prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award holding that the petitioner is not entitled to any relief.

4. The point for adjudication is whether the Respondent is justified in terminating the service of Sri M. Venkateswarlu w.e.f. 1-11-1989 or not?

5. W.W1 was examined on behalf of the Petitioner and marked Exs. W1 to W5. M.W1 was examined on behalf of the Respondent and no documents were marked on its side.

6. W.W1 is M. Venkateswarlu. In brief he deposed that he joined as casual mazdoor in Telecom Department on 1-3-1989. He worked upto 31-10-1989. Thereafter he was retrenched from service. He was not given any notice, nor reasons were given. He was not paid notice period wages nor any other compensation. During the above period his name was shown in the muster rolls. Subsequently also he was employed without showing his name in the muster roll and in wages were paid on ACG 17 receipts. After retrenching him from service the Department entrusted the work to the Contractors. While working as mazdoor he was employed for digging trenches, electric poles fixing brackets and insulators drawing the wire giving new phone connections etc. The work continues in nature after one work was over similar other work is taken by them. Therefore there is no dearth of work.

7. M.W1 is K. Paramdhamayya. He deposed that he is working at Nagarkurnool from August 1993. Casual mazdoors are engaged for temporary works like digging trenches erecting poles, laying cables etc. This is not a continuous work. The casual mazdoors are engaged only when the works are available. The petitioner worked for 230 days and even this period he was not engaged continuously. The breaks are due to completion of work for which the petitioner was engaged and upto starting of another work. They inform before this engagement of casual mazdoors that they would be engaged bill the works are undertaken are completed and they have to be idle until another work is taken. The petitioner was disengaged after October 1989 due to non-availability of work.

8. In this case it is seen that the petitioner was employed as Casual mazdoor under the Respondent w.e.f. March 1989 to October 1989. As per the records, it is seen that casual mazdoors are engaged by the Department only for temporary works like constructions of overhead lines, cable laying and maintenance works etc. from October 1989 there was no work for the casual mazdoors, hence the service of the petitioner was disengaged. It is for the casual labour to come and enquire about the availability of work and offer themselves for such work. They will be engaged as and when they are available. Even if any disengagement of any labour for want of work, it cannot be taken as permanent disengagement. It is seen that it is always open for such casual labour to offer himself whenever the work is available. I find that the petitioner was not terminated from service but was disengaged for want of work and as and when the work is available, the same will be offered to the petitioner. I find that the termination is not in violation of Section 25-F of the I.D. Act. The disengagement of casual labour does not amount to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D. Act. Hence the question of not complying with Section 25-F of the I.D. Act does not arise. I find that the said Section is not as all applicable to the casual labour as the work is of casual in nature. It is also seen from the evidence of M.W1 that the petitioner workmen as informed before their engagement as casual mazdoor that he would be engaged only when the work is available. On a consideration of all the facts and circumstances, I am of the firm opinion that the petitioner workman is not entitled to reinstatement or any kind of compensation under the provisions of the I.D. Act.

9. In the result, the management of Sub-Divisional Office (Rural) Telecom, Nagarkurnool, is justified in terminating the services of Sri Venkateswarlu with effect from 1-11-1989. The concerned workman is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 10th day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined
for the Petitioner-Workman
W.W1 M. Venkateswarlu.

Witnesses Examined for
the Respondent-Management :
M. W1 K. Paramdamaiah.

Documents marked for the Petitioner :

- Ex. W1 21-11-90.—Copy of the Complaint to RLC(C), Hyderabad.
- Ex. W2 26-12-90.—Respondent's parawise remarks (Xerox copy).
- Ex. W3 15-4-91.—Petitioner's Rejoinder (Xerox copy).
- Ex. W4 20-6-91.—Xerox copy of Minutes of conciliation.
- Ex. W5.—Xerox copy of the Muster Roll working days.

Documents marked for the Respondent/Management :

NIL

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का. आ. 1447.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम. डी. ओ. टेलेकॉम, कुर्नूल के प्रबन्धन के संवद्ध शिपों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-40012/106/91-आईआर (डी.यू.) (भा.भा.)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1447.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO, Telecom Nagar Kurnool and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-94.

[No. L-40012/106/91-IR(DU)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated : 9th day of May, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 68 OF 1991

BETWEEN :

D. Sankaraiah Goud, S/o Anjancylu Goud, about 21 years. Casual Mazdoor.

Petitioner

AND

1. The Sub-Divisional Officer,
Phones, Nagarkurnool-509 209.
2. The Telecom District Engineer,
Mahboobnagar-609050. Respondents

APPEARANCES :

S/Sri C. Suryanarayana & P. Bhaskar, Advocates
for the Petitioner.

S/Shri M. Pandu Ranga Rao & B. G. Ravinder
Reddy, Advocates for the Respondents.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. 40012/106/91-IR(DU), dt. 13/19-11-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of Telecom and their workmen to this Tribunal for adjudication :

“Whether the management of Sub-Divisional Office (Rural), Telecom, Nagar Kurnool is justified in terminating the services of Sri D. Shankaraiah Goud with effect from 16-10-1989? If not, to what relief the workman is entitled to?”

This reference is registered as Industrial Dispute No. 68 of 1991 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the petitioner read as follows :—The petitioner's claim for reinstatement in service is based on the fact that the Respondents herein recruited and employed the petitioner as casual mazdoor for 227 days without paid weekly offs during the period from 12-1-1989 to 15-10-1989 except in June and July, 1989 during which he was given paid weekly offs. For some days he was kept idle due to cessation of work, but thereafter he was retrenched on the ground that he was recruited after 30-3-1985 contrary to the orders of the Director-General, P. & T, New Delhi prohibiting any fresh recruitment and employment of casual mazdoors. The petitioner was not given notice nor paid wages as per the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. Notwithstanding the aforesaid direction of the Supreme Court, the petitioner was retrenched from service on the fallacious ground that he was recruited after 30-3-1985 the date on which the Director General imposed ban on fresh recruitment/employment of casual mazdoors. The retrenchment was without complying with the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. The petitioner submits that after absorbing several mazdoors, the Telecom Department issued orders dt. 7-11-1989 to grant temporary status to those who could not be absorbed in the regular establishment for want of vacancies. It is thus clear that continuous one year service as casual labourers in the Telecom Department entitles them to temporary status pending absorption in the regular establishment of the Department, according to their turn in the seniority list Casual Mazdoors of a recruitment unit and for preparing the seniority list the Director General issued separate orders. The petitioner therefore prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold and declare that his retrenchment is illegal, null and void and consequently to direct the Respondents herein to

reinstate him in service with full back wages, continuity of service, protection of his seniority and all other benefits which are consequential and/or incidental to such reinstatement and to pass Award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows :—It is submitted that the Petitioner was engaged as a Casual Mazdoor on daily wages depending upon the availability of work. The work of the casual mazdoors comes to an end as and when the work is over. The work of the casual mazdoor is not continuous and purely depends upon the availability of work. The allegation that the petitioner worked continuously for 227 days during the period from 12-1-1989 to 15-10-1989 is not correct. It is submitted that in case of casual mazdoors, there is no question of termination. Casual mazdoors will be discontinued as and when the work is over. Therefore the allegation that the petitioner was terminated from service and that the termination is in violation of Section 25-F of the I.D. Act is not correct. The Respondent is a Government of India Department and it has got procedure for engaging regular employees. Casual mazdoors are meant purely for discharging casual nature of work and they have to no right of whatsoever to seek for absorption or for employment under the Respondent. The fact that the petitioner is unable to give the date of retrenchment itself shows that there is no retrenchment. The petitioner was not eligible for granting of temporary status as he was not engaged prior to 30-3-1985. It is prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award holding that the petitioner is not entitled to any relief.

4. The point for adjudication is whether the management is justified in terminating the services of Sri D. Shankaraiah w.e.f. 16-10-1989?

5. W. W1 was examined on behalf of the Respondent. No documents were marked on its side. No oral or documentary evidence has been adduced by the Petitioner-workman.

6. M. W1 is K. Paramadhamayya. He deposed that he is working as S.D.O. Telecom at Nagarkurnool from August, 1993. He is giving the evidence on the basis of the records. The casual mazdoors are engaged for temporary works of laying cables, erection of poles and digging trenches. This is not regular nature of works. The petitioner was engaged from 12-1-1989 to 15-10-1989 and even during this period the petitioner was not engaged continuously and there are breaks in engagement due to non-availability of work during this period the petitioner worked only for 227 days. The petitioner was informed before his engagement and that this employment would automatically be ceased as soon as the work for which the petitioner was engaged was completed. No junior to the petitioner was continued after 15-10-1989.

7. It is seen in this case the petitioner was employed from 12-1-1989 to 15-10-1989 for 227 days except in June and July 1989. The contention of the petitioner that the period of their service from 12-1-1989 to 15-10-1989 constitutes continuous service as per the definition in Section 25-F of the I.D. Act, hence the petition should be deemed to be in

continuous service during all the 227 days between the above dates (12-1-1989 to 15-10-1989) which constitutes part of the year. The contention of the Respondent that the petitioner was engaged as a casual mazdoor on daily wages depending upon the availability of work, the work of the casual mazdoors comes to an end as and when the work is over, that the petitioner worked continuously for 227 days during the period from 12-1-1989 to 15-10-1989 is not correct, that the casual mazdoors will be discontinued as and when the work is over, the allegation that the petitioner was terminated from service and that the termination is in violation of Section 25-F of the I.D. Act is not correct.

8. In support of the contention of the Respondent-Management, M.W1 was examined on behalf of the Respondent and he deposed that casual mazdoors are engaged for temporary works of laying cables, erection of poles and digging trenches, this work is not regular in nature, that the petitioner was not engaged continuously and there are breaks in engagement and due to non-availability of work. It is seen that the petitioner was informed before his engagement and that his employment would automatically be ceased as soon as the work for which the petitioner was engaged was completed. From the above it is clear that the casual mazdoors are engaged for temporary works of laying cables, erection of poles and digging trenches. It is also seen that the work is not a regular in nature. It is also pertinent to note that the petitioner was informed before his engagement and that his employment would automatically be ceased as soon as the work for which the petitioner was engaged was completed. It is also found that the petitioner is unable to give the date of retrenchment hence this itself shows that there is no retrenchment. I find that the petitioner was not eligible for granting of temporary status as he was not engaged prior to 30-3-1985. On a consideration of the facts and circumstances, I am of the firm view that the Petitioner-workman is not entitled to be reinstated into service with full back wages, and the petitioner workman has no merits in his case.

9. In the result, the Management of Sub-Divisional Office (Rural), Telecom, Nagar Kurnool is justified in terminating the services of Sri D. Shankariah Goud with effect from 16-10-1989 and the concerned workman is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 9th day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I.

Appendix of Evidence.

Witnesses Examined for
the Petitioner/Workmen :

NIL

Witnesses Examined for
the Respondent/Management :

M.W1 K. Paramdamayya.

Documents marked for the Petitioner :

NIL

Documents marked for the Respondent :

NIL

नई दिल्ली, 1 जून, 1994

का. आ. 1448.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम, हैदराबाद के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-5-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/94/91-आई आर (डी यू) (भाग)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 1994

S.O. 1448.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on 30-5-94

[No. L-40012/94/91 IR(DU) (Pt)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L.
Industrial Tribunal-I.

Dated, 10th day of May, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 62 OF 1991

BETWEEN :

Sri N. Anjaiah, S/o. N. Venkataiah,
H. No. 1/111, Mogullavampu, Yacharam,
Ranga Reddy District, A.P. 501509

... PETITIONER

AND

1. The Sub-Divisional Officer,
Dept. of Telecommunication (Rural),
Hyderabad

2. The Divisional Engineer,
Telecom (Rural),
Hyderabad-500030. ... RESPONDENTS

APPEARANCES :

M/s. C. Suryanarayana and P. Bhaskar,
Advocates for the Petitioner.

M/s. M. Panduranga Rao and B. G. Ravinder

Reddy, Advocates for the Respondents.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/94/91-IR(DU), dt. 7-11-1991 referred the following dispute under Section 10(1) (d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of Telecom and their workman to this Tribunal for adjudication :

“Whether the management of Sub-Divisional Office (Rural) Telecom, Hyderabad is justified in terminating the services of Sri N. Anjaiah, Ex-Telecom Mazdoor w.e.f. 1-9-90? If not, to what relief the workman is entitled to?”

This reference was registered as Industrial Dispute No. 62 of 1991 and noticed were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the petitioner is read as follows :—The petitioner's claim for reinstatement in service is based on the fact that the Respondents have recruited and employed him from 19-7-1983 as indicated in his complaint to the Regional Labour Commissioner, Hyderabad dt. 14-1-1991 raising the industrial dispute. After his recruitment, the petitioner was kept idle, without any employment, due to cessation of work for departmental reasons not attributable to him. The petitioner was retrenched from service w.e.f. 1-9-1990 on the ground that he suffered from break in his service due to his prolonged absence from January 1986 to December 1989 (during which period he was sick and under treatment) and that on account of the break he became a fresh recruit in 1990. Not withstanding the direction of the Supreme Court, the petitioner was retrenched from service on the fallacious ground that he was recruited, after 30-3-1985 the date on which the Director-General imposed ban on fresh recruitment/employment of casual mazdoors. The retrenchment was without complying with the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. The petitioner therefore prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold and declare that his retrenchment is illegal, and consequently to direct the respondents herein to reinstate him in service with full back wages, continuity of service, protection of his seniority and all other benefits which are consequential and/or incidental to such reinstatement and to pass the Award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the respondent Telecom is read as follows :—There is no termination of the services of the petitioner as he was only a casual employee and therefore the reference is liable to be struck down. The casual mazdoors are engaged in the work of laying of cables, erection of poles etc. Whenever there is work, these casual mazdoors are engaged. That there is no question of terminating the services of a casual mazdoor as the very nature of the job indicates that the work is not continuous. It is submitted that the petitioner never completed 240 days in a year as alleged by him in his petition. The petitioner was absent from duty right from January 1986 to December 1989. He came for work only in the year 1990. That the provisions of Section 25F of the I.D. Act

are not applicable to the facts of the present case and the petitioner is not entitled to any relief.

4. The point for adjudication is whether the management is justified in terminating the services of Sri N. Anjaiah w.e.f. 1-9-1990.

5. W.W1 is examined on behalf of the Petitioner-workman and marked Exs. W1 to W10. M.W1 was examined on behalf of the Respondent and no documents were marked on its side.

6. W.W1 is N. Anjaiah, In brief he deposed that he joined the Telecom. Department on 19-7-1983 as casual mazdoor worked upto 30-8-1990. There was a break in his service from 1986 to 1989. Ex.W1 is the xerox copy of the working days particulars. Due to chest pain he was advised for rest by the Doctors. He intimated the Respondent that due to his ill-health he could not attend the work and after getting cured he attended to duty. He was taken back to duty after submitting his medical certificate from January 1990. He was retrenched from service from 1-9-1990 without assigning any reasons. No notice was given to him. Wages also in lieu of notice were not paid. After his retrenchment he approached the S.D.O.T. several times and requested for work. But S.D.O.T. refused to give him work on the plea that he was recruited after 30-4-1985 though he intimated him that he was recruited as long as in 1983. He prays this Hon'ble Tribunal to reinstate into service and grant all other incidental benefits.

7. M.W1 is G. Sridhar Rao. He deposed that he is working as S.D.O.T., Hyderabad from March 1990. He knows the facts of this case. He is giving evidence on the basis of records. The casual mazdoors are engaged for temporary works of laying cables, erection of poles etc. and the work is not regularly and continuously. The petitioner was engaged intermittently during the years 1982 to 1985. The petitioner lastly worked in October 1985 and after that he did not turn up and he has not intimated any reasons about his absence. After that the petitioner came in February 1990 and enquired about the work. As work was available, he was engaged from March 1990 to August 1990, as a fresh casual mazdoor. The petitioner did not ask to condone his absence nor did he submit Ex. W2 medical certificate. After August 1990 the petitioner was disengaged due to non-availability of work. No junior to the petitioner is being continued now.

8. The case of the petitioner that the Respondent employed the petitioner from 19-7-1983. After his recruitment he was, kept idle without any employment due to cessation of work for departmental reasons and he was retrenched from service w.e.f. 1-9-1990 on the ground that he suffered from break in his service due to his prolonged absence from January 1986 to December 1989 and that on account of the break he became a fresh recruit in 1990. That as per the judgement dt. 4-5-1988 in CA No. 529 of 1988 he should be deemed to be in continuous service till the date of his retrenchment, that as per direction of the Supreme Court the petitioner was retrenched from service on the fallacious ground that he was recruited after 30-3-1985, and that those that are recruited on or after that date and that all those who have rendered one year continuous ser-

vice are entitled to the benefits of the judgement in AIR 1987 SC 2342.

9. The contention of the Respondent Telecom is that the petitioner was engaged as a casual mazdoor that the casual mazdoors are engaged in the work of laying of cables, erection of poles etc., whenever there is work, these casual mazdoors are engaged, it is for the casual mazdoors to come and enquire for the work and as and when it is available, it will be allotted to him, that there is no question of terminating the services of a casual mazdoor as the very nature of the job indicates that the work is not continuous, that petitioner never completed 240 days in a year as alleged and that the various judgements cited by him are not applicable to the facts and circumstances of the case and finally Section 25-F of the I.D. Act are not applicable to this case and petitioner is not entitled to any relief.

10. In this case it is seen that the Petitioner was employed as Casual mazdoor under the Respondent w.e.f. 19-7-1983. He worked upto 1-9-1990. As per records, it is seen that casual mazdoors are engaged by the Department only for temporary works like construction of over head lines, cable laying and maintenance works etc. The petitioner was absent from duty right from January 1986 to December 1989. That he came for work only in the year 1990. It is for the casual labour to come and enquire about the availability of work and offer themselves for such work. There is no question of terminating the services of a casual mazdoor as they very nature of the job indicates that the work is not continuous. The various judgements cited by the petitioner are not applicable to the facts and circumstances of the case. It is also seen that the petitioner never completed 240 days in a year as alleged by the petitioner in his petition. So on a consideration of the facts and circumstances I am of the firm opinion that the petitioner workman is not entitled to reinstatement or any kind of compensation under the provisions of the I.D. Act.

11. In the result, the management of Sub-Divisional Office (Rural) Telecom, Hyderabad is justified in terminating the services of Sri N. Anjaiah, Ex-Telecom Mazdoor w.e.f. 1-9-1990 the concerned workman is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 10th day of May, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence :

Witnesses Examined for the
Petitioner/Workman :

W.W1 N. Anjaiah

Witnesses Examined for the
Respondent/Management :

M.W1 G. Sridhar Rao

Documents marked for the Petitioner/Workman :

Ex. W1 Xerox copy of working days particulars by the Petitioner.

Ex. W2 Medical Certificate Xerox copy.

Ex. W3 Xerox copy of the complaint given to the RLC (C). Hyd.

Ex. W4 Xerox copy of parawise comments on the above complaint.

Ex. W5 Rejoinder filed by the Petitioner to Ex.W4.

Ex. W6 Xerox copy of the failure of conciliation proceedings.

Ex. W7 Xerox copy of the Caste Certificate. 29-7-82.

Ex. W8 Copy of DGP&T No. 4-1/SCT Dt. 13-1-81.

Ex. W9 Xerox copy of letter from Asstt. Director General Reg—Regular absorption of Casual Mazdoor in Group D-Posts.

Ex. W10 Xerox copy of D.G.P. & T. Order dt. 30-3-85.

Documents marked for the Respondent :

NIL

नई दिल्ली, 3 जून, 1994

का. आ. 1449.—जबकि टेलिकाम विभाग, पेडापल्ली के प्रबन्धन तथा उनके कर्मकारों जिसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकाम कर्मकार संघ, लाइन स्टाफ और वर्ग घ, चारंगल क्षेत्र, जिला करीमनगर द्वारा किया जा रहा है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है :

और जबकि, उपरोक्त प्रबन्धन तथा उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकाम कर्मकार संघ लाइन स्टाफ और वर्ग घ, द्वारा किया जा रहा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उप धारा (1) के अन्तर्गत एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए भेजने पर सहमत हैं और उक्त विवाचन करार की एक प्रति केन्द्र सरकार को भेजी है,

अतः अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10-क की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्र सरकार उक्त करार को पत्रद्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अन्तर्गत)

इसके मध्य

पक्षकारों के नाम

नियोजक के प्रतिनिधि	कर्मकारों के प्रतिनिधि
टेलिकाम जिला अभियन्ता	श्री ए. राजामोती,
टेलिकाम विभाग	जैवीय सचिव,
करीम नगर,	अखिल भारतीय टेलिकाम
जिला करीमनगर	कर्मचारी संघ, लाइन स्टाफ
	और वर्ग घ (चारंगल क्षेत्र)
	करीम नगर जिला करीमनगर

पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित विवाद को विवाचन के लिए श्री जे. कन्कया, संयुक्त मध्य अमायुक्त (क.) नई दिल्ली के पास भेजने की सहमति हो गई है।

- (i) विवाद के विशिष्ट मामले श्री एन. सत्यनारायण, भूत-पूर्व नैमित्तिक मजदूर की सेवाओं की तथाकथित अवैध छंटनी । में देगा। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है तो विवाचन के लिए भेजा गया विषय स्वतः निरस्त हो जाएगा और हम नए विवाचन के लिए वार्ता करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (ii) अन्तर्ग्रस्त प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के नाम व पते सहित विवादों से संबंधित पक्षकारों के व्यौरे । प्रबन्धन के प्रतिनिधि टेलिकाम जिला अभियंता, टेलिकाम विभाग, करीमनगर, जिला—करीमनगर प्रबंधन की ओर से संघ की ओर से
- (iii) कर्मकार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त है या संघ का नाम, यदि कोई हो, जो संबंधित कर्मकारों या कर्मकार का प्रतिनिधित्व करता हो । कर्मकार के प्रतिनिधि श्री ए. राजामीली, क्षेत्रीय सचिव, अखिल भारतीय टेलिकाम कर्मकार संघ, लाइन स्टाफ और वर्ग "ब" (वारंगल क्षेत्र), करीमनगर, जिला— करीमनगर ह. /- (जी. कृष्णामूर्ति) क. ट. अ. टेलिकाम विभाग, पेडापल्ली, जिला करीमनगर ह. /- (ए. राजामीली) क्षेत्रीय सचिव अखिल भारतीय टेलिकाम कर्मचारी संघ, लाइन स्टाफ और वर्ग "ब", (वारंगल क्षेत्र) करीमनगर
- (iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या एक
- (v) विवाद से प्रभावित अथवा प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या एक

विवाचक की सहमति

मैं, श्री एन. सत्यनारायण, भूतपूर्व नैमित्तिक मजदूर की सेवाओं की तथाकथित अवैध छंटनी के मामले में, टेलिकाम विभाग, पेडापल्ली, जिला करीमनगर के प्रबंधन और उनके कर्मकार जिसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकाम कर्मचारी संघ, लाइन स्टाफ और वर्ग "ब", वारंगल क्षेत्र, जिला करीमनगर द्वारा किया जा रहा है, के मध्य औद्योगिक विवाद में विवाचन करने के लिए सहमत हूँ।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि इस मामले में श्री जे. कनकय्या, संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त (के.), नई दिल्ली विवाचक होंगे और विवाचक का निर्णय हम दोनों पर बाध्यकारी होगा।

ह. /-
(जे. कनकय्या)
संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त

विवाचक अपना पंचाट तीन माह के भीतर अथवा हमारे मध्य हुए परस्पर लिखित करार द्वारा आगे बढ़ाए गए समय

[सं. एल—40013/2/94-आई आर (डी यू)]

के. बी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd June, 1994

S.O. 1449:—Whereas an industrial dispute exists between the management of Telecom Deptt., Peddapalli and their workman represented by the All India Telecom Employees Union, Line Staff and Group D, Warangal Area, District Karimnagar :

And whereas, the said management and their workman represented by All India Telecom Employees Union, Line Staff and Group 'D' have by written agreement under sub-section (i) of Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Between

NAMES OF THE PARTIES

Representing Employer
Telecom District Engineer Telecom Department,
Karimnagar, Distt. Karimnagar

Representing workman
Shri A. Rajamouli
Area Secretary,
All India Telecom Employees Union,
Line Staff & Group D
(Warangal Area)
Karimnagar, Distt. Karimnagar.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri J. Kanakiah, Jt. CLC(C), New Delhi.

- | | |
|--|--|
| (i) Specific matters in dispute : | Alleged illegal retrenchment of services of
Shri N. Satyanarayana, Ex-Casal mazdoor |
| (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved. | Representing the management
Telecom District Engineer,
Telecom Department,
Karimnagar, Distt. Karimnagar. |
| (iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workmen or workman in question. | Representing the workman
Shri A. Rajamouli,
Area Secretary
All India Telecom Employees Union,
Linestaff and Group D
(Warangal Area)
Karimnagar, Distt. Karimnagar. |
| (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected | One |
| (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute | One |

We further agree that Shri J. Kanakiah, Jt. CLC(C), New Delhi will be the Arbitrator in the present case and the decision of the arbitrator is binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

On behalf of the management
Sd/-

(G. KRISHNAMURTHY)
J.T.O., Telecom Deptt.,
Peddapalli
Distt. Karimnagar.

On behalf of the Union
Sd/-

(A. RAJAMOULI)
Area Secretary,
All India Telecom Employees Union,
Line Staff & Group D.
(Warangal Area)
Karimnagar.

CONSENT OF THE ARBITRATOR

I am willing to accept the arbitration in the I.D. between the management of Telecom Deptt., Peddapalli District Karimnagar and their workman represented by All India Telecom Employees Union, Line Staff and Group D, Warangal Area, District Karimnagar over alleged illegal retrenchment of the services of Shri N. Satyanarayana, Ex-Casual Labour.

Sd/-

(J. KANAKIAH)

Jt. Chief Labour Commissioner
[No. L-40013/2/94-IR(DU)]
K.V.B. UNNY, Desk Officer.

नई दिल्ली, 14 जून, 1994

का. आ. 1450.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, आयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, (केन्द्रीय) वादोदरा के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-6-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-30025/1/91-आईआर (विविध)/आईआर (कोल-I)]

सी. गंगाधरन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th June, 1994

S.O. 1450.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal (Central) Vadodara as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employees in relation to the management of Oil and Natural Gas Commission which was received by the Central Government on 10-6-94.

[No. L-30025/1/91-IR (Vividh)/R(Coal-I)
C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI A. B. MARATHE, INDUSTRIAL
TRIBUNAL (CENTRAL) AT VADODARA
Reference (ITC) No. 6 of 91

Regional Director, Oil and Natural Gas Commission, (Now named as Oil and Natural Gas Corporation Limited), Makarpura Road, Vadodara-390009—First Party.

V/s

Engineering Mazdoor Sangh Shastri Pole, Kothi Char Rasta, Raopura, Vadodara-390001.—Second Party.

Shri I. K. Ramrakhiani—Officer of the Association of Industrial Employers for the first Party.

Shri Sudhirbhai J. Shah—Office bearer of the registered trade union, namely, Engineering Mazdoor Sangh—the second party.

AWARD

(1) Oil and Natural Gas Commission which has since converted itself into "Oil and Natural Gas Corporation Limited" and which will be hereinafter referred to as "ONGC" for the sake of convenience, is a public sector undertaking constituted by the Indian Parliament under the Oil and Natural Gas Commission Act to provide for production and sale of petroleum and petroleum products. With these objects in view the ONGC carries out geological and

geophysical surveys for the exploration of petroleum. As such the work of surveying is seasonal, in that the ONGC works in full swing during the field season ordinarily commencing from November each year and ending sometimes in April or May each year. The other months of the year are known as off-season. In other words, the work-load is much less during the monsoon. Every year when the field season begins, the ONGC recruits casual/contingent/temporary workmen for specified period and their services are terminated at the end of the field season. It appears this practice has continued from the inception of the ONGC some times in the year 1956. In the year 1956 the ONGC had a staff strength of about 450 employees and in the course of time it increased to a massive figure of 25,000 employees in the year 1979. Today in the year 1994 the strength of labour force might have multiplied still further.

(2) Since field season and off-season are a recurring phenomena, the Engineering Mazdoor Sangh on behalf of their members who were recruited by the ONGC as casual/contingent/temporary workmen raised an industrial dispute in the form of a demand for regularisation of these workmen. Therefore, the Ministry of Labour, Government of India by their order No. L-30025/1/91-I.R. (Vividh) dated 18-7-91 referred the following issue for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the demand of Engineering Mazdoor Sangh, Vadodara that the employees employed in the ONGC, Western Region, Vadodara who have completed 240 days or more in the Commission as casual/contingent/temporary be regularised as permanent workmen from the date of their engagement in ONGC, with other consequential benefits, is justified? If yes, to what reliefs the said workmen are entitled?"

(3) When the notices were issued to the ONGC and the casual/contingent/temporary workmen employed by them, the Engineering Mazdoor Sangh on behalf of such workmen filed their statement of claim at Ex. 3. They pointed out that several field parties on behalf of the ONGC start work during the field season and recruit casual/contingent/temporary workmen on a large-scale—say, each field party recruits about 200 such workmen. The work is reduced during the off-season and, therefore, the services of casual-contingent/temporary workmen are terminated. They alleged that a matter of an unfair labour practice, the workmen are required to change their names and are threatened with criminal proceedings if such changing of names comes to light. Relying on the rules and regulations framed by the ONGC they claimed that those workmen who have completed 240 days of work as casual/contingent/temporary workmen should be regularised. They enclosed a list of eight workmen as a sample who have completed 240 days in the ONGC.

(4) The ONGC filed their written statement at Ex. 9. They pointed out that for the purpose of carrying out the seismic survey and other prospective operations and for carrying out geological and geophysical surveys for the exploration of petroleum, 13 field parties work in western region of the Commission. They pointed out that these field parties

carry out seismic investigations at different areas in the western region for the purpose of recording seismic reflections corresponding to sub-surface horizons and to study their extension in the neighbouring areas. They pointed out that these field parties work normally during winter and summer approximately for nine months. When the monsoon is in the offing, the field parties close their work. They pointed out that each field party needs about 150 to 200 casual-contingent/temporary workmen during the field season. They pointed out that each party chief is authorised to recruit such casual workmen for specified periods only and no more. They pointed out that the casual workmen have no right to regular posts. They pointed out that the ONGC has framed "ONGC (Recruitment and Promotions) Regulations, 1980 for making appointments to the regular posts. Moreover, there are certified Standing Orders which also govern the recruitment procedure. They further pointed out that all vacancies to the regular posts are required to be notified to the Employment Exchange under the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and it is not permissible for the ONGC to overlook the names of those who are recommended for recruitment by the Employment Exchange. They pointed out that the party chiefs make recruitment without regard to the age requirements and educational qualifications led down in the rules. Therefore, if such persons are to be considered for recruitment to the regular posts, then that cannot be done without violating the rules and, therefore, such casual workmen had no right to be considered for the regular posts. They pointed out that if these who have completed 240 days as casual-contingent/temporary workmen are made permanent as a matter of course, then that would amount to violation of Articles 14 and 16 of the Constitution inasmuch as the candidates coming through Employment Exchange and those offering their services from the open market would be discriminated against. They pointed out that the contract of employment of the casual workmen came to an end when the term for which they were appointed expired and they could not claim any benefit of Sec. 25F of the Industrial Disputes Act, hereinafter referred to as 'the Act'. They further pointed out that unless it is established that regular posts are vacant on which such casual temporary workmen could be appointed, their regularisation was out of consideration. They pointed out that the Commission takes only unskilled, menial work from casual/temporary workmen and pays them minimum wages as provided for by the Minimum Wages Act and also 25 per cent extra and, therefore, there is no exploitation of labour by them. They, therefore, prayed for dismissal of the reference.

(5) On 21-7-92 the Union gave an application Ex. 14 enclosing therewith a list of 269 workmen who are their members and have completed 240 days of work in the ONGC as casual-contingent/temporary workmen.

(6) During the pendency of this reference the Union on 28-4-93 filed a complaint u/s 33A of the Act being Complaint (ITC) No. 5/93 alleging that the ONGC had started giving work to contractors in preference to the casual-contingent/temporary work-

men and had thus altered the term of service of the workmen and committed breach of Sec. 33 of the Act. That complaint was tried and this Tribunal by award dated 30-10-93 held that it was not permissible for this Tribunal to examine whether the work of the ONGC was seasonal or not and that the ONGC had breached the term of service of the workmen by giving work to contractors in preference to the casual-contingent/temporary workmen. By this order the ONGC was also directed to follow the principle of "Last come—First go" in case it wanted to terminate the services of casual/temporary workmen on the ground that they had no work and that in that case the ONGC must obtain prior permission of this Tribunal u/s 33(1)(a) of the Act.

(7) Therefore, the ONGC gave an application on 25-4-94 seeking permission to terminate the services of the casual/temporary workmen mentioned in the list enclosed with the application. That application was given Ex. 32 in Complaint (ITC) No. 5/93. On 27-4-94 the ONGC gave a corrected list of workmen whom it wanted to terminate and it appears that the ONGC wanted to terminate the services of 2217 workmen. Due notice of this application was served on the Engineering Mazdoor Sangh and after hearing both the sides by order dated 30-5-94 on Ex. 32 this Tribunal permitted the ONGC to terminate the services of casual-contingent/temporary workmen except 189 out of 269 workmen who were shown by the Union in the list along with Ex. 14. This figure of 189 workmen is arrived at because 74 workmen had not responded to the call of the ONGC to come for work and six workmen had already been regularised. This Tribunal gave an option to the ONGC to examine witnesses to show that actually they had no work which these 189 workmen were capable of doing and that work is in progress.

(8) In the Complaint (ITC) No. 5/93 the Union had examined four Workmen to prove that the ONGC were resorting to certain unfair labour practices and had started giving work to contractors in preference to the casual-contingent/temporary workmen. The ONGC did not lead any oral evidence in the said complaint.

(9) In the main reference itself neither party has led any oral evidence. ONGC (Recruitment & Promotion) Regulations, 1980 is an important document and is to be found at Ex. 17 in the Complaint (ITC) No. 5/93 and another important document, namely, certified Standing Orders of the ONGC is to be found at M. 10/1 in the said complaint. Several lists of workmen have been filed by both the sides at different stages of the proceedings in the complaint as well as in the reference.

(10) I have heard the arguments of Shri Sudhirbhai Shah, the learned office bearer of the Union and Shri I. K. Ramrakhiani, the learned Officer of the Association of Industrial Employers of the ONGC, Shri Sudhirbhai Shah has submitted a gist of his argument at Ex. 53 in the reference.

(11) The following issues arise :—

- (i) Who are eligible to be considered for appointment to the regular posts and whether the present workmen can be included in such workman ?

- (ii) Whether the present reference should be restricted to those workmen who are members of the Engineering Mazdoor Sangh and whose names appear in the list along with Ex. 14 ?
- (iii) What relief can be granted and what final order ?

My findings are as under :—

- (i) Only a temporary workman who has put in not less than 240 days of attendance in any period of 12 consecutive months is entitled to be considered for conversion as regular employee. But the temporary workmen as shown in the list mentioned in the Schedule to the affidavit Ex. 42 in the Complaint (ITC) No. 5/93 have been wronged for the reasons discussed below. Therefore, they should be considered for conversion as regular employees as per the principles indicated below.
- (ii) In the affirmative.
- (iii) As per order below.

REASONS

Issue No. (i)

(12) Though in the award dated 30-10-93 in Complaint (ITC) No. 5/93 this Tribunal held that it was not permissible for this Tribunal to examine whether the work of the ONGC was seasonal or not, in the order on Ex. 32 in the said complaint which was application by the ONGC to terminate the services of 2217 casual/temporary workmen, this Tribunal held that it was a fact admitted by both the sides that the work of the ONGC is seasonal. Thus, the ONGC recruiting casual workmen in the beginning of November every year and terminating their services in April or May every year is a recurring phenomenon. But keeping workmen casual, Badli or temporary over long spells to time amounts to an unfair labour practice. Therefore, there has to be some scheme of regularising such workmen. An answer is to be found in the certified Standing Orders which govern the parties and copy whereof is produced at M. 10/1 in the Complaint (ITC) No. 5/93. Rule 2 of these certified Standing Orders which is relevant reads as under :—

“2.(1) Classification of Workmen

The contingent employees if the Commission shall hereafter be classified as under :—

- (a) Temporary, and
- (b) Casual.

(ii) A workman who has been on the rolls of the Commission and has put in not less than 180 days of attendance in any period of 12 consecutive months shall be a temporary workman, provided that a temporary workman who has put in not less than 240 days of attendance in any period of 12 consecutive months and who possesses the minimum qualifications prescribed by the Commission may be considered for conversion as regular employee.

(iii) A workman who is neither temporary nor regular shall be considered as casual workman”

That means a casual workman who puts in attendance of 180 or more days in 12 consecutive months automatically becomes a temporary workman. The Union in the beginning had produced a list of only eight workmen as a sample. However, in course of time they produced a list along with Ex. 14 showing 269 workmen saying that all of them had completed 240 days. Whether this was acceptable to the ONGC as correct generated many difficulties and in the meanwhile several lists were produced by both the sides and attempts at verification were made several times. But a really satisfactory list acceptable to both the sides could not be settled till the final arguments were heard. It is only when the ONGC gave application Ex. 32 in Complaint (ITC) No. 5/93, they enclosed along with affidavit of Shri Gautam Sen, Chief Geophysicist (S) Ex. 48 a Schedule showing about 189 workmen arranged in descending order as per number of days put in by each workman. These 189 workmen are out of 269 workmen shown by the Union in the list along with Ex. 14 who, according to the Union, had completed 240 days. The say of the ONGC is that when the field season commenced in November 1993 they summoned all 269 workmen to report for work. But 74 workmen did not respond and about six workmen had been already regularised. Therefore, these 80 workmen are not shown in this Schedule. At the bottom of this Schedule there are ten workmen beginning with the name of Mathurbhai Bijabhai Patel who have not completed 240 days according to the ONGC. It is true that the Union could not get the opportunity to check the correctness of this Schedule. But at the same time the Union itself has not proved the list of 269 workmen along with Ex. 14 as correct. Since the burden of maintaining the workmen is on the ONGC it is safe to presume that the Schedule enclosed with the affidavit Ex. 48 is correct. So, I proceed on the assumption that the workmen shown in this Schedule, except the last ten workmen, have completed 240 days in the Commission. The ONGC has shown in this Schedule the number of days put in by each workman in the years 1989-90, 1990-91, 1991-92 and 1992-93. It is important to note that not a single workman could complete 240 days in any single lot of 12 consecutive months in these four years. Then the ONGC has shown number of days put in by each workman during the span of about eight years i.e. 1981 to 1989. The maximum number of days put in by one workman for this span of time is 869 days. Dividing this by eight, it is clear that even this workman could not complete 240 days in consecutive 12 months. Thus, though at the beginning of every field season the ONGC recruits about 2,000 to 2,500 workmen as casual and terminates them some times in April or May every year, not a single workman could complete 240 days in consecutive 12 months over a span of about 12 years. Therefore, strictly applying the above test mentioned in Rule 2 of the certified Standing Orders not a single casual workman has become “temporary” workman eligible to be considered for conversion as regular employee. This itself is the root cause of simmering discontent and has given rise to the present reference. Naturally a question would be asked why this has so happened? The ONGC has nowhere tried to explain this phenomenon by leading evidence. But the work-

men have tried to do so and let us examine with what consequence?

(13) The Union has examined four workmen as witnesses in the complaint (ITC) No. 5/93. Bapu Laxman Jadhav, witness No. 1 Ex. has said that he joined the service of ONGC as a contingent labour in the year 1986 and he was given employment intermittently. On 1-3-1988 his controlling officer told him that a contingent workman could not be kept in employment for more than 180 days and, therefore, he was forced to assume a false name "Sanjay" from 1-3-1988 to 20-6-1988. He has also said that he was also obliged to assume another name "Mukhesh" for some time. In cross-examination para (23) this witness admitted that whether his name is "Bapu", "Sanjay", or "Mukesh" the wages are received by one and the same man. But nowhere it is challenged in the cross-examination that the workman assumed different names. Second witness of the Union Prabhunath Ramnarayan Mishra Ex. 12 has also said that occasionally he was required to change his name such as "Birendrakumar Harshnarayan Mishra", "Ramakant Ramnarayan Mishra", "Shivsagar" etc. He is also cross-examined at length; but nowhere it is suggested that he did not assume such different names. Witness No. 3 Prashant Amrutrao Pawar has not complained that he was forced to change his name. But witness No. 4 Avadeshkumar Ramvilas Upadhyay Ex. 24 has said in para (6) of his examination-in-chief that he had to change his name at the instance of Party Chief K. S. Kalyan. He has also said that another Party Chief K. N. Rao also required him to change his name. This witness is not cross-examined at all. Therefore, there is no reason to disbelieve his word. The photographs of witness Bapu Laxman Jadhav on his applications for employment which bear different names it is clear that this workman did assume different names. Now, is it likely that a man would change his name on a frolic of his own? Ordinarily not. Unless there is a strong motivation like fear of losing a job, a man would not change his name. The story of the workmen is that if a workman completes 180 days in 12 consecutive months, then he ceases to be casual and becomes "temporary" and if a temporary workman completes 240 days in 12 consecutive months, then he is eligible to be considered for conversion as regular employee and the implied suggestion is that the powers that be in the ONGC in order to bestow favour on their favourites and deny the present workmen—who are not as fortunate as they should be—the right to be considered for becoming regular, have elected to treat the present workmen in such a manner that not a single one out of them can complete 240 days in 12 consecutive months. The device adopted by the powers that be is that "Oblige the workmen to change their names on the pain that if they do not do so, they would not get work". The result would be that a workman cannot complete 180 days and cannot become temporary and in turn cannot complete 240 days and does not acquire the right to be considered for becoming regular. This is the only plausible explanation which explains why not a single workman could complete 240 days in 12 consecutive months. The fact of changing of names is not challenged in the cross-examination

and the ONGC has not led any rebuttal evidence. Therefore, my apprehension is confirmed and I give it as a fact found that the Officers of the ONGC resorted to the unfair labour practice of requiring the casual workmen to change their names often with a view to depriving them of the right to become temporary and in course of time to be eligible to be considered for becoming regular employees.

(14) I have deliberately used the adjective "temporary" to describe the workmen mentioned in the Schedule to the affidavit Ex. 48 in the Complaint (ITC) No. 5/93. Some of them have completed 180 days in 12 consecutive months and some of them have not. But looking to the sharp practice practised on them by the ONGC, I order that all of them except the ten workmen mentioned at the bottom should be treated as "temporary". A copy of the said Schedule to the affidavit Ex. 48 is enclosed with this award for the sake of convenience.

(15) Now the question is whether these temporary workmen should be regularised as a matter of course? The ONGC says that they have been recruited by the Party Chiefs without regard to the age and educational qualifications. As far as educational qualifications are concerned, there cannot be any relaxation. But as far as the question of "age" is concerned, the matter requires some consideration. Some of the workmen are at the door of the ONGC for now more than 12 years. This is palpable injustice to them especially in view of the fact that ONGC, being State, is expected to be a model employer. Therefore, a fair scheme appears to be that for every 240 days of work, age relaxation of one year should be given to the workman. As and when vacancy to the regular post arises, the ONGC can be directed to allow the workmen in the Schedule to the affidavit Ex. 48 in Complaint (ITC) No. 5/93 to compete with other workmen seeking employment directly, say through employment Exchange, and if they otherwise fulfill the standard of educational qualifications, then each workman should be given relaxation of one year in age for every 240 days of work put in by him. I hold issue No. (i) accordingly.

Issue No. (iii)

(16) I am conscious of the fact that in this entire discussion a vast majority of casual workmen are kept out of consideration because they have not participated in the proceedings may be because of their poverty, ignorance, or lack of unity. But in any case the present workmen have given concrete evidence about unfair labour practice practised upon them by the ONGC and they are getting judgment in their favour because of their success in the attempt. As long as the other workmen who are kept out of consideration do not give such concrete evidence about unfair labour practice, they cannot get any benefit out of this award. I, therefore, hold that the present reference must be restricted to those workmen who are members of the Engineering Mazdoor Sangh who have sponsored their cause and whose names appear in the list in the Schedule appended to this award. I hold issue No. (iii) accordingly.

Issue No. (iii)

(17) In the circumstances the following final order is passed :—

ORDER

The present reference is ordered to be restricted to the workmen whose names appear in the Schedule to the affidavit Ex. 48 in the Complaint (ITC) No. 5/93 a copy of which is appended to this award for the sake of convenience. The ONGC is directed that as and when vacancies to the regular posts arise, they shall consider the names of those workmen in the same descending order in which they are mentioned in the Schedule and shall regularise them provided they satisfy the prescribed educational qualifications and for each 240 days of work put in by each workman, the ONGC shall give him age relaxation of one year. Ten workmen mentioned at

the bottom of this Schedule are not entitled to any relief. It is made that the workmen shall have to compete with other workmen seeking employment through Employment Exchange or similar lawful manner. The ONGC is warned to ensure that no officer in their employment resorts to the unfair labour practice of inducing any casual workman to change his name. Similarly no workman shall hereafter change his own name to conceal his previous employment with the ONGC.

Lastly, the ONGC is directed to pay a sum of Rs. 5,000 (Rupees Five thousand only) as special cost to the Engineering Mazdoor Sangh, Vadodara.
Dated : 6th June, 1994.

A. B. MARATHE, Presiding Officer.

